



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 2018/आषाढ़ 25, 1940

No. 243]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 2018/ASHADHA 25, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2018

विषय: भारत में "सोलर सेल्स चाहे वे मॉड्यूल्स या पैनल्स में जोड़े गए हों अथवा नहीं" के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच के संबंध में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क (रक्षोपाय शुल्कों की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के अंतर्गत अंतिम जांच परिणाम संबंधी कार्रवाई।

फा. सं. 22/1/2018-डीजीटीआर.- (क) प्रस्तावना

1. इनके बढ़ते हुए आयातों के कारण उत्पन्न गंभीर क्षति/गंभीर क्षति के जोखिम से घरेलू उद्योग के समान अथवा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्द्धात्मक उत्पादों की रक्षा के लिए भारत में "सोलर सेल्स चाहे वे मॉड्यूल्स या पैनल्स में जोड़े गए हों अथवा नहीं" (जिसे यहां "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लागू करने की मांग करते हुए पांच भारतीय उत्पादकों अर्थात् (i) मैसर्स मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड, अडानी हाउस, मीठा खाली 6 रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009, गुजरात; (ii) मैसर्स इंडोसोलर लिमिटेड, 3सी/1, इकोटेक-II, उद्योग विहार, जिला गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा-201306, उत्तर प्रदेश; (iii) मैसर्स जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड, गांव काथा, डाक घर बड्डी, तेहसील नागागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-173205; (iv) मैसर्स वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, फालटा सेज सेक्टर-II, फाल्टा, जिला 24 दक्षिण परगना, पश्चिम बंगाल-743504; और (v) मैसर्स हेलियोस फोटो वोल्टेक लिमिटेड, 43बी, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020 द्वारा मैसर्स एथेना लॉ एसोसिएट्स, 808, एलएंडटी बिल्डिंग, सेक्टर-18बी, द्वारका, नई दिल्ली-110075 की ओर से भारतीय सोलर विनिर्माताओं द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्कों की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे यहां "उक्त नियमावली" भी कहा गया है) के नियम 5 के तहत दिनांक 05.12.2017 को मेरे समक्ष दिनांक 28.11.2017 का एक आवेदन दायर किया गया है। आवेदकों का दावा है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में तेजी के कारण बहुत से घरेलू उत्पादकों ने अपनी उत्पादन सुविधाएं लगभग निष्क्रिय रखी हुई हैं और भारी हानि ने घरेलू उद्योग को अशक्त बना दिया है। इस कारण, आवेदकों ने अपनी क्षति को कम करने के उपाय के रूप में अनंतिम रक्षोपाय शुल्क को लागू करने के लिए अनुरोध किया।

2. उक्त नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदन तथा साक्ष्य/विवरणों/दस्तावेजों की जांच की गई। उसके बाद, भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के विरुद्ध जांच आरंभ नोटिस (एनओआई) दिनांक 19.12.2017 के अनुसार एक रक्षोपाय जांच आरंभ की गई। एनओआई को जीएसआर संख्या 1522(5) के अनुसार दिनांक 19.12.2017 के भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया।
3. उक्त नियमावली के नियम 6 के उप नियम (2) और (3) के अनुसरण में, एनओआई दिनांक 19.12.2017 की एक प्रति और घरेलू उद्योग द्वारा दायर दिनांक 28.11.2017 की एक प्रति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में केंद्रीय सरकार को भारत में उनके दूतावासों के जरिए प्रमुख निर्यातक देशों की सरकारों और उक्त आवेदन में उल्लिखित हितबद्ध पक्षकारों को अग्रेषित की गई थी। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों/आयातकों/घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्तर दी जाने वाली प्रश्नावली, जैसा कि उक्त नियमावली के नियम 6(4) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, इस अनुरोध के साथ ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अग्रेषित की गई कि वे एनओआई को जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से ज्ञात कराएं।
4. दिनांक 20.12.2017 को घरेलू सोलर सेल्स उत्पादकों के दो संघों अर्थात् (i) मैसर्स इंडियन सोलर मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (आईएसएमए) और (ii) मैसर्स सोलर पावर डेवलेपर्स एसोसिएशन (एसपीडीए) के द्वारा दिनांक 19.12.2017 के एनओआई, दिनांक 28.11.2017 के आवेदन के एनसीवी और निर्यातक/आयातक/घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्तर दी जाने वाली प्रश्नावली की एक प्रति भेजी।
5. अंतिम रक्षोपाय शुल्क को लागू करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध की जांच की गई और प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि ऐसी आलोच्य परिस्थितियां विद्यमान हैं जो अपूरणीय क्षति, जिसकी प्रतिपूर्ति करना कठिन हो सकता है, झेलने से घरेलू उद्योग को अंतरिम राहत उपलब्ध कराने की दृष्टि से अंतिम रक्षोपाय शुल्क को लागू किए जाने के लिए औचित्यपूर्ण हैं।
6. तदनुसार, अंतिम रक्षोपाय शुल्क के लिए प्रारंभिक जांच परिणाम को 05 जनवरी, 2018 को सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन), 1997 के नियम 9(2) के अंतर्गत जारी किया गया और उसी दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। हालांकि, अंतिम रक्षोपाय शुल्क को माननीय चेन्नई उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किए जाने के कारण कार्यान्वित नहीं किया गया जिसे लगभग 3 महीने की अवधि के पश्चात रद्द कर दिया गया।
7. निम्नलिखित पक्षकारों से या तो एक हितबद्ध पक्षकारों के रूप में विचार किए जाने का अनुरोध अथवा निवेदन प्राप्त हुए:

1.	इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (आईएसएमए)
2.	मैसर्स मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड
3.	मैसर्स इंडोसोलर लिमिटेड
4.	मैसर्स जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड
5.	मैसर्स वेबसोलर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड
6.	मैसर्स हिलियोस फोटो वोल्टेक लिमिटेड
7.	इंडियन सोलर एसोसिएशन
8.	इंडियन सोलर पावर प्रोड्यूसर्स एलियांस
9.	यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम
10.	इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन
11.	गिनटेक, 9 एफ नं. 295 टिडिंग ब्लिब्ड, सेक्टर 2 तैपई, ताइवान 11493 आर. ओ. सी.
12.	स्टर्लिंग एंड विल्सन प्रा. लि.
13.	सेल्स ओटी थालहीम, सोन्नेनल्ले 17-21, 06766 बिटरफेल्ड-वोल्फन, जर्मनी
14.	जेए सोलर नं. 36, जियांग चांग सन रोड, झबेई, शंघाई 200436, चीन
15.	डेलसोलर, 6 केबेई दूसरा रोड, झुनान, साइंस पार्क, झुनान टाउनशिप, मियोली काउंटी 35053 ताइवान, आरओसी
16.	सुनेनजाइन कारपोरेशन लि., सं. 10, वेनहुआ रोड, हुकोऊ टाउनशिप, हिंसिचु काउंटी 30352, ताइवान
17.	टीएसआई (टोपसेल सोलर इंटरनेशनल कं. लि., नं. 1560, सेक्टर 1, झोंगशान रोड, गॉनन टाउनशिप, टायोयुआन काउंटी 328, तेयान आरओसी
18.	ई टोन सोलर, नं. 498 सेक्टर 2, बेंटियन स्टे., तेनान, 709, ताइवान आरओसी
19.	बिग सन एनर्जी टेक्नोलॉजी इंक. नं. 458-9 सिंसिंग रोड, हुकोऊ टाउनशिप, हिंसिचु काउंटी 30353, ताइवान
20.	गोल्डपोली, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट जोन, जिन जियांग 363300, फुजियन, चीन
21.	केपीई, 1985-12 यिओनसन - डोंग, यिओनजी-जू, बूसन-611832 कोरिया, 23-2 पल्योंग-डोंग, चांगवान,

	ग्योंगसंगनम-डो 6410847, कोरिया
22.	शार्प कारपोरेशन, 3, स्टोकली पार्क, उक्सब्रिज, मिडिलसेक्स, यूके (यूरोप)
23.	क्यू-सेल्स, बिटरफील्ड-वोल्फेन, जर्मनी
24.	टीएसईसी, 9 एफ, नं. 10, सेक्टर 3, मिनशेंग ई. रोड, जोंगशन जिला तैपई सिटी, 10480 ताइवान आरओसी
25.	सोलर टेक एनर्जी, नं. 51, दिंगू पहली गली, चौथा इंडस्ट्रियल पार्क, गुएलसन, ताओयुआन 333, ताइवान आरओ चीन
26.	शिन संग, 404-1 बेखियों-डोंग, बुनडंग-गु सियोंगनम-एसआई, गियोंगी-डो, कोरिया: 463420
27.	एनएसपी (नियो सोलर कारपोरेशन), 7, लि-हिसन तीसरा रोड, हिंसिचु साइंस पार्क, हिंसिचु, 30078, ताइवान
28.	टीजीए (टॉप ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी), 9 एफ, नं. 246 लीन चैन रोड, चंग हो सिटी, तैपई हिंसिन ताइवान आरओसी
29.	टेनर्जी (थाई सोलर एनर्जी कारपोरेशन लि.), 3199 मलीनोट टावर, 16वां तल, रामा IV रोड, क्लोंगटन, क्लोंगटोई, बैंकॉक 10110
30.	यूनिटेक सोलर कारपो., स्रो. 16, सेक्टर 2, ल्कीगोंग, पहला रोड, बुजियू टाउनशिप, यिलन काउंटी 26841, ताइवान
31.	मोटेक, साउदर्न ताइवान साइंस पार्क, नं. 2, दशुन 9वां रोड, जिंसी जिला, तैनन सिटी 74145, ताइवान
32.	स्कॉच, हट्टेनबर्गस्टर 1055122 मैज
33.	हन्वा सोलर वन, 1199 मिनशेंग रोड बिल्डिंग 1, रूम 1801, शंघाई, चीन 200135
34.	रिन्यूबल एनर्जी कारपोरेशन (आरईसी), सेंडविका, नॉर्वे
35.	एई सोलर जीएमबीएच, मेसरकिमट्रिंग 54, 86343 कोंइंग्रन, जर्मनी
36.	निंगबो रिनेल्ड न्यू एनर्जी कं. लि.
37.	पोनासोनिक एनर्जी मलेशिया एसडीएन, बीएचडी
38.	झेजियांग बियोंडसन पीवी कं. लि.
39.	झेजियांग ट्रनसन सोलर कं. लि.
40.	बुक्सी सेजियांग सोलर कं. लि.
41.	अनहुई थिंक्सिन न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि.
42.	बिन बिन प्रेसिसन टेक्नोलॉजी कं. लि.
43.	झेजियांग ट्रनसन सोलर कं. लि.
44.	टोंगवी सोलर (हेफेई) कं. लि. टोंगवी सोलर (चेंगडु) कं. लि.
45.	गिनटेक एनर्जी कारपोरेशन
46.	टेनर्जी टेक. कं. लि. विटनर्जी कं. लि.
47.	सुझोऊ टालेसन सोलर टेक्नोलॉजीस कं. लि.
48.	एयू ऑप्ट्रोनिक्स कारपोरेशन
49.	चाइना सनएनर्जी (ननजिंग) कं. लि.
50.	जियांक्सी रिसुन ग्रीन एनर्जी कं. लि.
51.	रेनेसोला जियांगसू लि.
52.	मिंग हेवेई एनर्जी कं. लि.
53.	निंगबो ओसडा सोलर कं. लि.
54.	एलओएफ सोलर कारपो.
55.	हरयोन सोलर टेक्नोलॉजी कं. लि. हरयोन (बुक्सी) न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि. हरयोन सोलर इक्विपमेंट सेल्स कं. लि. हरयोन सोलर कं. लि.

	हरयोन इंटरनेशनल कं. लि. हेफेई सोलर टेक्नोलॉजी कं. लि. जियांगिन हरयोन पावर कं. लि. तेचंग हरयोन सोलर कं. लि. अलटुसविया एनर्जी (तेचंग) कं. लि. जियांगिन जिनहुई सोलर एनर्जी कं. लि.
56.	सोलरटेक एनर्जी कारपो.
57.	ट्रिना सोलर कं. लि. ट्रिना सोलर (वियतनाम) साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं. लि. ट्रिना सोलर साइट एंड टेक्नोलॉजी (थाइलैंड) लि.
58.	जियांग्सू शनफेंड फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी कं. लि.
59.	जेटियोन सोलर (चीन) कं. लि.
60.	एसयूएमईसी हांग कांग कं. लि.
61.	निंगबो रिनेल्ड न्यू एनर्जी कं. लि.
62.	लाइटवे ग्रीन न्यू एनर्जी कं. लि.
63.	अंजी डसोल सोलर एनर्जी एसएंडटी कं. लि.
64.	जियांग्सू एडुओ फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी कं. लि.
65.	कनाडियन सोलर मैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) कं. लि. सीएसआई सोलर पावर ग्रुप कं. लि.
66.	यिंगली सोलर
67.	अल्टरनेटिव एनर्जी (आई) सोलर कं. लि.
68.	जियांग्सू ग्रीन पावर पीवी कं. लि.
69.	हेंगदियान ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कं. लि.
70.	चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग बुक्स कं. लि.
71.	ई-टोन सोलर टेक. कं. लि.
72.	टीएसईसी कारपोरेशन
73.	निंगबो किक्सन सोलर इलेक्ट्रिकल एप्लियांस कं. लि.
74.	लॉगी सोलर टेक्नोलॉजी कं. लि.
75.	सिनो-अमेरिकन सिलिकॉन प्रोडक्ट्स इंक.
76.	फोनो सोलर टेक्नोलॉजी कं. लि.
77.	झेजियांग ऐको सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि.
78.	सीसीसीएमई
79.	अनहुई यिंगफा रिनेंग टेक्नोलॉजी कं. लि.
80.	लेवो सोलर टेक्नोलॉजी कं. लि.
81.	झेजियांग सनफलोवर लाइट एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड
82.	जिनेंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी लि.
83.	जीसीएल सिस्टम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी कं. लि.
84.	रिसेन एनर्जी कं. लि.
85.	जिनशाइन पीवी-टेक कं. लि.
86.	चांगझोऊ जीएस एनर्जी एंड टेक्. कं. लि.
87.	पेनासोनिक कारपोरेशन/सनयो इलेक्ट्रिक
88.	फर्स्ट सोलर एफई होल्डिंग पीटीई. लि. (सिंगापुर) और फर्स्ट सोलर इंक (यूएसए)

89.	मैसर्स झेजियांग सनफ्लोवर लाइट एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एलएलबी
90.	पैनासोनिक एनर्जी मलेशिया एसडीएन बीएचडी
91.	नाइस सन पीवी कं. लि.
92.	जियांगसू सेरपहिम सोलर सिस्टम कं. लि.
93.	एसीएमई सोलर होल्लिंग्स लि.
94.	नियो सोलर पावर कारपोरेशन
95.	मोटेक इंडस्ट्रीज इंक.
96.	जेए सोलर पीवी टेक्नोलॉजी कं. लि.
97.	एक्सेस सोलर लि. प्लॉट #5, फेज-II, टीआईई, बालानगर, हैदराबाद, 500037-तेलंगाना
98.	जैन इरीगेशन सिस्टम्स लि. जैन प्लास्टिक पीक, जलगांव 425001
99.	कोटक ऊर्जा प्रा. लि., 378, 10वां क्रॉस, चौथा फेज, पीनया इंडस्ट्रियल एरिया, बैंगलोर, 560058, कर्नाटक
100.	पीएलजी पावर लिमिटेड 139, ए-1 शाह एंड नागर इंड. इस्ट. लोअर परेल (डब्ल्यू) मुंबई
101.	एवर ग्रीन सोलर सिस्टम इंडिया प्रा. लि. सुलोचना मिल्स मेट्टूपलयम रोड कोयंबटूर, तमिलनाडु
102.	अम्मिनी ग्रुप प्लॉट नं. 33-37, किनफ्रा स्मॉल इंडस्ट्रीज पार्क सेंट जेवियर्स कॉलेज पीओ, त्रिवेंद्रम 695582
103.	केएल सोलर कंपनी प्रा. लि. 1/482-बी ट्रांसपोर्ट नगर, नीलमबुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु
104.	फोटोनिकस सोलर प्राइवेट लिमिटेड, 38/ए, सहकार वृंद सोसायटी,, पॉड रोड, वनाज फैक्ट्री के सामने, कोथरूड, पुणे 411038 महाराष्ट्र
105.	जेजे पीवी सोलर प्रा. लि., सर्वे नं. 237,238 प्लॉट नं. 2,3 एनएच 8बी गांव वेरावल शापर, जिला राजकोट, 360024 गुजरात
106.	एलएंडटी कंस्ट्रक्शन, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आईएफसीआई टावर, चौदहवां तल, 61, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली-110019.
107.	एम्प्लस एनर्जी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लि.
108.	क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी सॉल्यूशन्स प्रा. लि.
109.	ग्रीन एनर्जी एसोसिएशन
110.	नॉर्थ इंडिया मॉड्यूल मैनुफैक्चरर एसोसिएशन
111.	एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशन्स प्रा. लि.
112.	विक्रम सोलर लिमिटेड
113.	माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
114.	आदित्य बिरला रिन्यूबल्स लिमिटेड
115.	सोलर पावर डेवलेपर्स एसोसिएशन
116.	कृषिराज रिन्यूबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
117.	विराज सोलर महाराष्ट्र
118.	अवादा पावर प्राइवेट लिमिटेड
119.	कोरिया गणराज्य दूतावास
120.	संयुक्त राष्ट्र दूतावास/उच्चायोग
121.	सिंगापुर दूतावास/उच्चायोग
122.	मलेशिया दूतावास/उच्चायोग
123.	इटली दूतावास
124.	जर्मनी दूतावास
125.	ताइवान दूतावास

126.	जापान दूतावास
127.	चीन जनवादी गणराज्य दूतावास
128.	नॉर्वे दूतावास
129.	रॉयल थाई दूतावास
130.	ताइवान इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर
131.	मैक्सिको दूतावास
132.	संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग
133.	मैसर्स चाइना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलैक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स
134.	ताइवान फोटोवोल्टेक इंडस्ट्री एसोसिएशन
135.	यूरोपीय आयोग
136.	डीजीएफटी, इंडोनेशिया सरकार
137.	स्टर्लिंग एंड विल्सन प्रा. लि.
138.	गुआंगडोंग एको सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लि.
139.	स्कचन सोलर एनर्जी कं. लि.
140.	इकोनीज एनर्जी कं. लि.
141.	जेए शंघाई, जेए हेफेई, जेए जिंग्ताई, जेए यांगझोऊ, जिंगएओ सोलर और जेए सोलर मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. सहित जेएस सोलर
142.	यिंगली एनर्जी (चाइना) कं. लि.
143.	यिक्सिंग जेएस सोलर कं. लि.
144.	युहुआन सिनोसोला साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं. लि.
145.	अनहुई दहेंग एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि.
146.	जियांग्सू इको ग्रीन एनर्जी कं. लि.
147.	ब्रिग सन एनर्जी टेक्नोलॉजी इंक., ताइवान
148.	झेजियांग इसोला न्यू एनर्जी कं. लि.
149.	सिमाक्स (सुझोऊ) ग्रीन न्यू एनर्जी कं. लि.
150.	अनहुई टेक्नोलॉजी इम्पॉ. एंड एक्सपो. कं. लि.
151.	निंगबो फुक्सिंग इलैक्ट्रिक कं. लि.
152.	बुक्सी सनटेक पावर कं. लि.
153.	झेजियांग जीएंडपी न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि.
154.	चांगझोऊ इंजी. फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी कं. लि.
155.	शेनजेन टोपरे सोलर कं. लि.
156.	यैरो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
157.	रत्न इंडिया सोलर 2 प्रा. लि.
158.	लीपटोन सोलर (चांगशू) कं. लि.
159.	सीईसीईपी सोलर एनर्जी (झेजियांग) कं. लि.
160.	सेपसेट कंस्ट्रक्शन्स लि.
161.	झेजियांग किंगडम सोलर एनर्जी टेक्नीक कं. लि.
162.	अनहुई स्कचन सोलर एनर्जी कं. लि.
163.	हाई होप इंटरनेशनल ग्रुप जियांग्सू फूडस्टफ्स इम्पॉ. एंड एक्सपो. लि.
164.	ईईपीवी कारपो., ताइवान

165.	सिचुआन थिंगफा सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि.
166.	वारबर्ग पिक्स इंडिया प्रा. लि.
167.	हर्ष अवाकस सोलर प्राइवेट लिमिटेड
168.	सोलर एनर्जी इन्फ्रिपमेंट मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना (सीमेट)
169.	अंकोर इलैक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
170.	क्लोराइड पावर सिस्टम एंड सॉल्यूशन्स लिमिटेड
171.	अदवेता लीगल, मैसर्स रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स सोलर ऐज पावर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स शपूर्जी पल्लोनजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर रही है
172.	हिल्ड एनर्जी प्रा. लि. ईगल प्रेस प्रा. लि.
173.	एसवाईएस ग्रुप एशिया पीटीई. लि.
174.	हनवा क्यू सेल्स कारपो. इंडिया
175.	नियोसोल टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.
176.	वारी एनर्जीस लिमिटेड
177.	सोलसिस कांसेप्ट्स एलएलपी
178.	मित्रा एनर्जी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
179.	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड
180.	आरईसी सोलर पीटीई. लि., सिंगापुर
181.	मेहर सोलर टेक्नोलॉजी प्रा. लि.
182.	जर्मनी ट्रेड एंड इन्वेस्ट
183.	मैक्सॉप रिसर्च एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट प्रा. लि.
184.	टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड
185.	एंका सोलर पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
186.	अजूरे पावर
187.	हीरस फोटोवोलेटिक्स
188.	महिंद्रा ससटेन प्रा. लि.
189.	रिन्यूसिस इंडिया प्रा. लि.
190.	ऊर्जा, पर्यावरण और जल (सीईईडब्ल्यू) संबंधी परिषद
191.	भारत लाइट एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
192.	जिनको सोलर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
193.	ई. आई. डुपोंट इंडिया प्रा. लि.
194.	एप्लाइड मैटेरियल्स इंडिया प्रा. लि.
195.	कनाडियन सोलर मैनुफैक्चरिंग इंक.
196.	गोदरेज एंड बॉइसी मैनु. कं. लि.
197.	एलएनवी टेक्नोलॉजी प्रा. लि.
198.	नेक्सटेक इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
199.	यूएल इंडिया प्रा. लि.
200.	उराटोम सोलर (इंडिया) प्रा. लि.
201.	टाटा पावर कंपनी
202.	सेम्बकॉर्प ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड

203.	भेल
204.	रिह्त सोलर लिमिटेड
205.	हीरो फ्यूचर एनर्जीस

8. सार्वजनिक सुनवाई में अथवा अन्यथा सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की उचित रूप से जांच की गई है और उनका निदान संबद्ध पैराओं में किया गया है। चूंकि अधिकतर मुद्दे दोहराए गए हैं, इसलिए उनका निदान सामूहिक रूप से किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की जांच यथासंभव स्थल पर/डेस्क के अध्ययन में की गई है तथा उन पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

9. इसके अतिरिक्त, मै. श्री सीमेंट्स लिमिटेड और प्राइसवाटर हाउस कॉर्पस (पीडब्ल्यूसी) सहित कुछेक हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे दिनांक 26 जून, 2018 को होने वाली सार्वजनिक सुनवाई में भाग लें। प्राधिकारी ने उसके लिए उन्हें अनुमति प्रदान कर दी है।

10. सार्वजनिक सुनवाई 26 जून, 2018 को हुई थी। इस सार्वजनिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक निवेदन प्रस्तुत किए थे। सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और मूल्यांकन) नियम 1997 के नियम 6 के उप नियम (6) के अनुसार सार्वजनिक सुनवाई में जिन सभी हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया था उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें।

11. एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित निवेदनों की प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करा दी गई थी। साथ ही, हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान किया गया था कि वे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित निवेदनों पर यदि कोई प्रत्युत्तर देना चाहते हों तो दें।

12. 26 जून, 2018 को हुई सार्वजनिक सुनवाई के अनुसरण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने लिखित निवेदनों में व्यक्त किए गए सभी विचारों की जांच की गई थी और उन्हें उपयुक्त निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा गया है। प्राप्त अथवा अपेक्षित सूचना का अगोपनीय वृत्तांत सार्वजनिक फाइल में रखा गया है।

13. हितबद्ध पक्षकारों और प्रत्युत्तर देने वाले हितबद्ध पक्षकारों की सूची सभी संबंधितों की सूचना डीजीटीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

ग. जांच की शुरुआत के पश्चात के निवेदन

14. जांच शुरुआत नोटिस की प्रतिक्रिया में किंतु सार्वजनिक सुनवाई से पूर्व प्राप्त निवेदनों को यहां नीचे संक्षिप्त रूप में दिया गया है:

(i) मैसर्स ग्रीन एनर्जी एसोसिएशन

- क. याचिकाकर्ता की हानियों का मुख्य कारण विचाराधीन उत्पाद का बढ़ा हुआ आयात नहीं है बल्कि त्रुटिपूर्ण व्यापार निर्णय, विश्वव्यापी हलचल, यूरोपीय वित्तीय गिरावट आदि हैं। वर्ष 2012-13 तक, याचिकाकर्ता, विशेष रूप से इंडो सोलर, वेबसोल, जुपिटर और मोजर अधिकतम निर्यात करने में लगी हुई थी और घरेलू बाजार पर उनका ध्यान कम था।
- ख. इंडो सोलर यूरोपियन बाजार को निर्यातों पर केंद्रित था और उन्होंने 100 प्रतिशत ईओयू कंपनी में परिवर्तित किए जाने के लिए आवेदन भी दिया था। दिनांक 15 सितंबर, 2008 को लेहमन ब्रदर्स की समाप्ति के कारण यूरोप में आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप सोलर उद्योग की समाप्ति और कीमतों में गिरावट आई।
- ग. 2011 में, इटली और जर्मनी में मांग गिर गई और असली वेफर कीमतों ने गहरी गिरावट की प्रवृत्ति दर्शानी आरंभ कर दी। इंडो सोलर ने वचनबद्ध कीमतों पर एक दीर्घावधिक करार पर हस्ताक्षर किए और उल्लेखनीय वित्तीय हानियां वहन कीं।
- घ. इसी प्रकार, मोजर बियर को भी इटालियन सरकार द्वारा सौर नीति को रद्द करने के कारण हानियां झेलनी पड़ी हैं जिसके परिणामस्वरूप मांग में आपूर्ति की तुलना में अत्यधिक गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, सोलर पैनलों की कीमतें 50 प्रतिशत तक कम हुई हैं।
- ङ. मोजर बियर को देश में आयात आरंभ होने से पहले, राष्ट्रीय सौर मिशन आरंभ होने से पहले और मुख्य रूप से असरदार सिलिकॉन प्रौद्योगिकी में जोखिम और वेफर/सेल आपूर्तिकर्ताओं को अदा किए गए अग्रिमों में हानि, जिन्होंने कंपनी को वसूली की अनुमति नहीं दी, के कारण हानि झेलनी पड़ी।

- च. वेबसोल, एक्सएल एनर्जी आदि को बाजारों में इकट्ठा हो रही भारी मालसूचियों के कारण, जिनमें गिरावट आई, जैसे कि यूरोपी, हानियों का सामना करना पड़ा। अतः वित्तीय हानि, जिसने उन्हें भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने से प्रतिबंधित कर दिया है, वह खराब निर्यात निष्पादन के कारण है न कि विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों के कारण।
- छ. याचिकाकर्ताओं ने कुल अनुमानित उत्पादन, उनकी आयातों से तुलना करते हुए को दर्शाया है, जबकि उन्होंने यह नहीं दर्शाया है कि उनकी कुल विनिर्माण क्षमता से उन्होंने कितना उत्पादन और बिक्री की है। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिशतांक वृद्धि की शर्तों में चीन की विनिर्माण क्षमता में भी वृद्धि दर्शाई है जबकि देश में विनिर्माण क्षमता को नहीं दर्शाया है।
- ज. जब जोड़ा गया तो मुंद्रा सोलर की प्रचालनात्मक क्षमता ने याचिकाकर्ताओं की क्षमता को और 1200 मेगावाट बढ़ा दिया। राष्ट्रीय सौर मिशन के परिणामस्वरूप भी क्षमता में वृद्धि हुई है। यदि रक्षोपाय शुल्क लागू किया जाता है तो अन्य सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माताओं को हानि होनी आरंभ हो जाएगी।

(ii) मैसर्स ईस्टमैन और ऑटो पावर लिमिटेड

- क. एसजीडी के लागू होने के परिणामस्वरूप परियोजना में वृद्धि होगी, सौर परियोजनाओं के घरेलू डेबलेपर्स पर बोझ पड़ेगा, टैरिफ में वृद्धि होगी और राज्य डिस्कॉमों को प्रभावित करेगा तथा अंत में उपभोक्ता समाप्त हो जाएंगे।
- ख. किसी नए शुल्क को निर्णायक अवधि में लागू किया जाना चाहिए और इस राजकोषीय वर्ष में लागू नहीं किया जाना चाहिए। शुल्क, यदि कोई हो, स्वरूप में भावी होना चाहिए और उसे जारी सौर परियोजनाओं को प्रभावित नहीं करना चाहिए।
- ग. पेरिस शिखर सम्मेलन के अनुसार, एसजीडी को लागू करने के वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 35 प्रतिशत तक कम करने के भारत के मिशन पर दूरगामी परिणाम होंगे।
- घ. घरेलू उद्योग खराब निष्पादन कर रहा है क्योंकि देश में पोली सिलिकॉन, इनगोट्स और वेफर्स अर्थात् सोलर पीवी, विनिर्माण श्रृंखला की अपस्ट्रीम चरणों के लिए एक विनिर्माण आधार नहीं है, ढांचे प्रतिकूल अर्थव्यवस्था है और आधुनिक प्रौद्योगिकी की कमी है और पूर्वगामी कारणों के लिए घरेलू विनिर्माताओं को उपलब्ध सुनिश्चित बाजार का पूरी तरह से अन्वेषण नहीं किया गया है।
- ङ. रक्षोपाय शुल्कों का क्रियान्वयन एक संरक्षणवादी उपाय है और मध्यम से दीर्घ अवधि में घरेलू उद्योग की सहायता नहीं करेगा, बल्कि मांग आपूर्ति में वृद्ध अंतर सृजित करेगा।
- च. एसजीडी को लागू करना भारतीय सौर मिशन की सफलता के लिए हानिकारक होगा।

(iii) मैसर्स विंडसर एक्सपोर्ट

- क. स्वदेशी विनिर्माता, जो सेज के बाहर प्रचालन कर रहे हैं, किसी प्रकार के आवृत्त रक्षोपाय शुल्कों से विपरीत रूप से प्रभावित होंगे। परिणामस्वरूप एसजीडी को लागू करना उत्पादन के विपरीत होगा।
- ख. शुल्कों के कारण विद्युत की उच्च लागतें समग्र उद्योग को निरुत्साहित करेंगी और इस कारण मांग में कमी आएगी जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सौर मिशन को भारी धक्का लगेगा।
- ग. एसजीडी को लागू किया जाना निर्णायक समीक्षा के पश्चात् होना चाहिए और यह इस राजकोषीय वर्ष में लागू नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) मैसर्स विक्रम सोलर

- क. सेज में स्थित सौर विद्युत उत्पादन सुविधाओं का वृद्ध समानुपात, सोलर सेल्स का 60 प्रतिशत से अधिक और मॉड्यूल विनिर्माता सुविधाओं का 40 प्रतिशत सेज में स्थित हैं और इसलिए रक्षोपाय शुल्क को लागू किया जाना घरेलू उद्योग को हानिकारक होगा।
- ख. प्रारंभिक रिपोर्ट भी सेज यूनिटों से आने वाली वस्तुओं को रक्षोपाय शुल्कों के लागू किए जाने से छूट प्रदान करने का सुझाव देती है।
- ग. वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट के सरकारी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सेज यूनिटों के बिना प्रतिस्पर्द्धा के और किसी अतिरिक्त भार को डाले बिना पूर्ण क्षमता से कार्य करना जरूरी होगा। डीटीए में सौर यूनिटें 10573 मेगावाट की सालाना मांग का केवल 1164 मेगावाट पूरा कर सकती हैं जो कि मांग का केवल 11 प्रतिशत है।

- घ. आयातों पर एसजीडी लागू करने से, जिनके द्वारा घरेलू मांग को पूरा किया जाना अपेक्षित है, केवल सौर परियोजनाओं की नियोजित लागत में वृद्धि का कारण बनेगी। इसलिए शुल्कों को लागू किया जाना सार्वजनिक हित के विपरीत भी होगा।

(v) भारत में आर्थिक प्रभाग, तैपई आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र

- क. याचिकाकर्ताओं के पास रक्षोपायों पर करार के अनुच्छेद 4.1(ग) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में पर्याप्त आधार नहीं है क्योंकि जहां नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में सोलर सेल्स के 20 विनिर्माता हैं, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ये अन्य भारतीय विनिर्माता आयातक हैं, दावे को प्रमाणित करने के किसी साक्ष्य को उपलब्ध कराए बिना।
- ख. याचिकाकर्ता ने दिनांक 28 अगस्त, 2017 की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सारणी में कोई उल्लेख नहीं पाया। इस संबंध में स्पष्टता होनी चाहिए कि क्या यह याचिकाकर्ता सोलर सेल्स का उत्पादक है या मॉड्यूलस का अथवा दोनों का।
- ग. याचिकाकर्ताओं के आधार का सोलर सेल्स साथ ही सोलर मॉड्यूलस के लिए मूल्यांकन होना चाहिए। हेलियोस के लिए प्रस्तुत आंकड़ों के अतिरिक्त, भारत में कुल क्षमता में से सोलर मॉड्यूलस के लिए स्थापित क्षमता का याचिकाकर्ताओं के पास केवल 15 प्रतिशत हिस्सा है।
- घ. यहां तक कि, सोलर मॉड्यूलस की क्षमता का संयुक्त हिस्सा केवल 26.5 प्रतिशत है। याचिकाकर्ताओं के पास, इसलिए घरेलू उद्योग का आधार नहीं है और तदनुसार जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- ङ. कथित रूप से अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण आयातों में वृद्धि नहीं हुई, जैसा कि जीएटीटी के अनुच्छेद XIX:1(क) के तहत जरूरी है किंतु वर्ष 2022 तक सोलर विद्युत ग्रिड का 100 गीगावाट स्थापित करते हुए भारत में सौर विद्युत को प्रोत्त करने का भारत सरकार के लक्ष्य हैं, इस बात से पूरी तरह से परिचित होते हुए कि विनिर्माता वार्षिक मांग का केवल 10 प्रतिशत पूरा कर सकते हैं। आयातों में ऐसी वृद्धि का यह एकमात्र कारण है।
- च. याचिकाकर्ता यह दर्शाने में भी असफल रहे हैं कि विचाराधीन अवधि से काफी पहले, 2005 में आईटीए 1 के अनुसरण में वचनबद्धताओं ने प्रवेश किया, जो आयातों में अचानक, तीव्र उल्लेखनीय और हाल ही में हुई वृद्धि का कारण हो सकता है। याचिकाकर्ता आयातों में वृद्धि के लिए एक कारण के रूप में अप्रत्याशित उतार-चढ़ावों और जीएटीटी बाध्यताओं को दर्शाने में असफल रहे हैं।
- छ. जांच की अवधि के दौरान, 3 याचिकाकर्ताओं की स्थिति में सुधार हुआ है, आंतरिक समस्याओं के कारण केवल 2 याचिकाकर्ताओं को हानि सामना करना पड़ा है। जहां मुंद्रा सोलर पीवी ने 2017 में वाणिज्यिक विनिर्माण आरंभ कर दिया है और क्षमताओं को स्थापित करने के लिए उन्हें अधिक समय की आवश्यकता है, आदि इंडो सोलर, वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड साथ ही जुपिटर सोलर में या तो हानियों में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाई है या लाभप्रदता में वृद्धि दर्शाई है। हेलियोस निगमित ऋण पुनर्गठन से गुजर रहा है जो कंपनी को होने वाली भारी हानियों का कारण है।
- ज. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता अप्रचलित प्रौद्योगिकी के कारण क्षति उठा रहे हैं न कि आयातों के कारण, जैसा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कहा गया है।
- झ. याचिकाकर्ताओं को क्षति का मुख्य कारण निर्यातों में 2014-15 में 100 सूचकांक बिंदुओं से गिरकर उनका 2017-18 में 13 सूचकांकों तक पहुँचना है। इन कारकों के कारण हुई क्षति को विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।
- ञ. याचिकाकर्ताओं के लिए तेजी से बढ़ती हुई क्षमताओं को स्थापित करना कठिन हो रहा है जो व्याज और मूल्यहास के कारण बढ़ती हुई हानियों का कारण है।
- ट. क्षति की अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं के कर्मचारियों की संख्या 5 गुना बढ़ी है जिसके कारण उनके द्वारा उपगत वेतन लागतों में 4 गुना वृद्धि हुई है।
- ठ. ऐसी कोई गंभीर परिस्थितियां नहीं हैं जो अनंतिम शुल्कों को लागू किए जाने के लिए औचित्यपूर्ण हो क्योंकि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक सुनिश्चित डीसीआर संघटक वाली 12000 मेगावाट की एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना का प्रस्ताव किया है। यह घरेलू उद्योग को एक सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराएगा।
- ड. याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई समायोजन योजना पश्चगामी एकीकरण की योजनाओं की ओर संकेत करती है। तथापि, एक पश्चगामी एकीकरण केवल अगले कुछ वर्षों में उच्चतर लागतों का कारण बनेगा और याचिकाकर्ता आयातों को समायोजित करने में सक्षम नहीं होंगे।

(vi) मैसर्स चाइना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स

- क. डीजी ने जांच शुरुआत नोटिस के 30 दिनों के भीतर पक्षकारों द्वारा उनके मत प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा नहीं की तथा एक अविचारित तरीके में जांच के आरंभ होने के 18 दिनों के भीतर अपना प्रारंभिक जांच परिणाम जारी कर दिया।

- ख. एसजीडी केवल जांच के बाद लागू किया जा सकता है। हितवद्ध पक्षकारों को उनका मत प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना, जांच पूरी नहीं हो सकती।
- ग. तत्कालीन जांच में की गई संपूर्ण कार्रवाई अमान्य है क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर की गई थी। जांच के विभिन्न चरणों पर की गई त्रुटियों को अब डीजी के किसी भी कार्य द्वारा परिशोधित नहीं किया जा सकता।
- घ. इस समय वृहत घरेलू मांग है जिसे ऐसा करने में घरेलू उद्योग की असमर्थता को देखते हुए पूरा किए जाने की आवश्यकता है। एसजीडी को लागू करने से उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी। इसी कारण से एडीडी पर किए गए सकारात्मक निष्कर्ष किए गए, किंतु लोक हित में शुल्क नहीं लगाया गया। यहां समान कारणों को परिचालित करना चाहिए।
- ङ. भारत को जेएनएनएसएम के तहत संशोधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, उच्च गुणवत्ता वाले आयातित पीवी उत्पादों, विशेष रूप से चीन से करने की आवश्यकता है।
- च. भारत को पीवी सेल्स की लगातार आपूर्ति की जरूरत है। एसजीडी का अनुप्रवाह उद्योगों, सोलर सेल उद्योग के स्वस्थ विकास और सरकार द्वारा आरंभ की गई ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं पर विपरीत प्रवाह होगा।
- छ. यह सामान्य है कि व्यापार उपचार के कारण चीन से ईयू और यूएसए को निर्यातों में गिरावट आई है। तथापि, चीन से भारत को निर्यातों में वृद्धि का इस मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। यह एक मुक्त बाजार है जहां बिक्री की मात्रा का बाजार उन्मुख है। आईटीए-1, जीएटीटी अथवा पेरिस करार को हस्ताक्षरित करने का कोई परिणाम नहीं हुआ है क्योंकि यह बाजार का प्राकृतिक कानून है कि बढ़ती हुई मांग आयातों में वृद्धि करती है।
- ज. कीमतों का गिरना एक प्रवृत्ति है, इसलिए इसे अप्रत्याशित के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता।
- झ. आयातों में वृद्धि भारतीय उद्योग की मांग में वृद्धि के साथ-साथ है।
- ञ. घरेलू उद्योग का विचार है कि आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही महत्वपूर्ण क्षति को प्रमाणित नहीं कर सकते, अन्यथा यह अंतिम स्तर में पाटनरोधी जांच को समाप्त करने का अनुरोध करना के निर्णय नहीं करता।
- ट. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े महत्वपूर्ण क्षति को भी प्रमाणित नहीं कर सकते, तब यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि गंभीर क्षति का निर्धारण नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा प्रत्येक वर्ष क्षमता को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक वर्ष क्षमता को बढ़ाने के ऐसे अनुचित निर्णयों से आवेदकों को क्षति पहुँच सकती है, संबद्ध देशों से आयातों से नहीं।
- ठ. घरेलू उद्योग के लिए उतरान कीमत और निवल बिक्री वसूली के बीच कोई सह संबंध नहीं है।
- ड. सर्वप्रथम घरेलू उत्पादकों को यह स्थापित करना चाहिए कि देश में बढ़े हुए आयात विद्यमान हैं और घरेलू उत्पादकों को ऐसे बढ़े हुए आयातों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं को अनुकूल बनाने हेतु समय और योजना की आवश्यकता है।
- ढ. आवेदक का दावा दोषपूर्ण और भ्रामक है क्योंकि दोनों प्रौद्योगिकियों से विनिर्मित उत्पादों के बीच का अंतर कई पहलुओं से महत्वपूर्ण है, जैसे कच्ची सामग्री, उत्पादन प्रक्रियाएं, कार्यकुशलता, लचीलापन और कीमतें आदि।
- ण. सीसीसीएमई तथा अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा बहुत बार लिखित में निवेदनों में और पाटनरोधी जांच के लिए पेशी के समय जनहितों पर व्यापार उपचार उपायों के नकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया गया है।
- त. विचाराधीन उत्पाद से निम्नलिखित को हटा दिया गया: (i) "पीईआरसी" (निष्क्रिय उत्सर्जक रियर सेल) आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले सेल, (ii) थिन फिल्म और बाई-फेशियल एन-टाइप सोलर सेल्स, (iii) 5 और 6 बस बार उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उच्च कार्यकुशलता वाले सोलर सेल्स, और (iv) मोनो क्रिस्टल प्रौद्योगिकी के सोलर मॉड्यूलस क्योंकि समायोजन योजना बताती है कि डीआईपीईआरसी प्रकार के सेल्स का उत्पादन करेगा।
- थ. याचिकाकर्ता हेलियस फोटो वोल्टेक लिमिटेड का दिनांक 28 अगस्त, 2017 की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सूची में उल्लेख नहीं मिलता है। डीजीटीआर को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या हेलियस सेल्स के उत्पादक हैं या मॉड्यूलस के अथवा दोनों।
- द. याचिकाकर्ताओं की प्रतिष्ठा की सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूलस के लिए पृथक-पृथक जांच होनी चाहिए। यह अनुरोध किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपनी स्थापित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए और सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूलस के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रतिष्ठा की अलग-अलग जांच करनी चाहिए।
- ध. भारत यह प्रदर्शन किए बिना रक्षोपाय शुल्क को लागू करने के द्वारा एओएस के तहत अपनी बाध्यताओं के बिल्कुल विपरीत कार्य करने के लिए दृढ़ है कि वर्तमान मामले में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव विद्यमान हैं।

- न. आयातों में वृद्धि भारत में मांग-आपूर्ति अंतर के कारण है। मांग राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सृजित की गई है। घरेलू उत्पादक और निर्यातक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में राष्ट्र को सक्षम बना रहे हैं।
- प. न तो याचिका न ही प्रारंभिक जांच परिणामों ने भारत द्वारा उपगत विशिष्ट जीएटीडी बाध्यताओं की यथार्थ रूप में पहचान की है जो संबद्ध वस्तुओं के आयातों में हुए अचानक, तीव्र, उल्लेखनीय और नवीन वृद्धि का कारण है।
- फ. जीएटीडी के अनुच्छेद XIX(1)(क) की शर्तों में ऊपर चिन्हित की गई जीएटीडी बाध्यताओं में से किसी के भी कारण संबद्ध वस्तुओं के आयातों में नवीन, अचानक, तीव्र और उल्लेखनीय महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।
- ब. संबद्ध वस्तुओं के लिए भारत की आईटीए-1 वचनबद्धता और आयातों में कथित नवीन और अचानक हुए वृद्धि के बीच कोई संबंध नहीं है। क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में क्रमशः 253 प्रतिशत और 305 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह वृद्धि महत्वपूर्ण है।
- भ. भारतीय उद्योग द्वारा भारतीय मांग का केवल 10-15 प्रतिशत ही पूरा कर सकता है। बाकी मांग को राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत लक्ष्य को पूरा करने के लिए आयातों द्वारा पूरा किया जाना है।
- म. निर्यात बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में तीव्र गिरावट आने से यह 2014-15 में 100 सूचकांक बिंदुओं से गिरकर 2017-18 में 56 सूचकांक बिंदु रह गया। सामना की गई क्षति का आयातों के साथ कोई संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग को क्षति का वास्तविक कारण अन्य भारतीय उत्पादकों की आक्रामक मूल्य निर्धारण प्रथाएं हैं न कि आयात। इस तरीके में पिछले एकीकरण के कारण अगले कुछ वर्षों में कीमत उच्च हो जाएगी। याचिकाकर्ता आयातों के साथ समायोजन करने में समर्थ नहीं होंगे यदि समायोजन योजना में कीमत में कमी करने के स्थान पर अधिक कीमत उपगत करना अनिवार्य हो।

(vii) सोलर पावर डेवलेपर्स एसोसिएशन

- क. घरेलू उद्योग "पीईआरसी" (पेसिवेटेड एमिटर रियर सेल) आधारित प्रौद्योगिकी; थिन फिल्म एंड बाय-फेसियल एन-टाइप सोलर सेल; 5 एवं 6 बस बार उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उच्च दक्षता सोलर सेल; तथा एकल क्रिस्टलीन के सोलर मॉड्यूल की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उत्पादन नहीं करता।
- ख. सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल के लिए घरेलू उद्योग के मत की पृथक-पृथक जांच की जानी चाहिए।
- ग. एमएनआई के नई, 2017 के लिए आंकड़ों का आश्रय लेते हुए कहा गया है कि सोलर सेल्स के लिए हिस्सा 56 प्रतिशत है और मॉड्यूल के लिए यह केवल 15 प्रतिशत है। यह तर्क दिया गया है कि कुल संस्थापित क्षमता 26.5 प्रतिशत है। घरेलू उद्योग स्थापित करने के लिए ये आंकड़े पर्याप्त हैं।
- घ. ये हस्तियां सेज यूनिट हैं और इन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे निर्यात बाजार का मुख्य भाग वहन करते हैं। रिलायंस इलैक्ट्रिक इंस्तेलर पर स्थित है।
- ङ. आंकड़े दर्शाते हैं कि केवल 2015-16 में उत्कर्ष दिखाई दिया था (228 प्रतिशत), अन्य वृद्धियां नाम मात्र की हैं (तदवर्ती वर्षों में 52 प्रतिशत और 49 प्रतिशत)। 2016-17 और 2017-18 में कोई नवीन, तीव्र, अचानक और यथेष्ट पर्याप्त आयात नहीं हुए हैं।
- च. भारी मांग और घरेलू उद्योग मांग का केवल 15 प्रतिशत पूरा कर सकता है। उत्पादन और बिक्रियों में क्रमशः 253 प्रतिशत और 305 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उपयोग में गिरावट अस्थायी है और इसमें सुधार तभी होगा जब उत्पादन स्थिर होगा। मुंद्रा ने अपना उत्पादन आरंभ किया है, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अच्छा कार्य कर रहा है। वेतनों में वृद्धि के कारण उद्योग के लाभों में गिरावट आई। बिक्री कीमत 2017-18 में बिक्रियों की लागतों के अनुरूप है, इसलिए कोई कीमत ह्रास या कीमत न्यूनीकरण नहीं है। इंडो सोलर के राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई है जिस कारण हानियों में 8322.91 लाख रुपए की कमी हुई है। वेबसोल ने अपने निष्पादन में सुधार किया है और 2016-17 में 8594.36 लाख रुपए का भारी लाभ उपगत किया है। वेबसोल ने अपने प्रचालन में भी विस्तार किया है। जुपिटर ने भी 3,999 लाख रुपए का लाभ दर्ज किया है।
- छ. स्थापित क्षमता में वृद्धि, निवल स्थिर परिसंपत्तियां और ब्याज लागत के कारण लाभप्रदता में गिरावट आई है। संबद्ध वस्तुओं के आयातों के खराब होते निर्यात निष्पादन के साथ कोई संबंध नहीं है। अप्रचलित प्रौद्योगिकी का प्रयोग अडानी द्वारा आक्रामक मूल्य निर्धारण के कारण भेल, टाटा पावर और सेंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स पैनल्स की 30 सेंटर/केडब्ल्यूएच क्षमता की रिकार्ड मंदा पर बिक्री की है।
- ज. चीन की क्षमता अप्रत्याशित नहीं है क्योंकि यह बाजार वास्तविक का परिणाम है। वस्तुओं के लिए मांग जेएनएनएसएम के तहत सृजित की गई है जिसका उद्देश्य 2022 तक 100 गीगावाट सौर विद्युत नियोजित करना है। उचित रूप से यह आशा की जाती है कि पाटित या अनुचित रूप से सहायता प्राप्त उत्पाद व्यापार उपचार कार्रवाई का सामना करें। उत्पाद चीन से आए हैं क्योंकि राज्य सरकारें या सार्वजनिक निकाय निविदाएं जारी की हैं। भारत ने डब्ल्यूटीओ में शामिल होने से पहले नवंबर, 1993 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन की अभिपुष्टि की थी। पेरिस करार यूएनएफसीसीसी के भीतर किया गया करार है। पेरिस में की गई वचनबद्धता यूएनएफसीसीसी के तहत की गई वचनबद्धताओं का परिणाम है।

- झ. आईटीए-1 के तहत की गई भारत की वचनबद्धताओं के परिणामस्वरूप ही 2005 में शुल्क शून्य हो गए थे। 2010 के पश्चात (जेएनएनएसएम) आयातों में वृद्धि हुई। यह दर्शाने के लिए किसी भी आंकड़ों का प्रदर्शन नहीं किया गया है कि सोलर सेल्स मामले ने आयातों को प्रभावित किया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सुनिश्चित डीसीआर के साथ 12000 मेगावाट की एक सीपीएसयू योजना लाने का प्रस्ताव किया है।
- ञ. भारत के सौर विद्युत ग्रिड संयोजकता के 100 गीगावाट तक पहुँचने की संभावना है। भारत की वर्तमान सौर क्षमता 20 गीगावाट है। सौर मिशन के लक्ष्य को पाने के लिए यह अपर्याप्त है। रक्षोपाय शुल्क को लागू करने से राष्ट्रीय सौर मिशन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे भविष्य की सौर परियोजनाओं के लिए टैरिफ उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकते हैं। रक्षोपाय शुल्क 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सौर विद्युत परियोजनाओं को जोखिम में डाल देगा।
- ट. डिस्कॉमों ने संकेत दिया है कि वे सौर विद्युत केवल तभी क्रय करेंगे यदि लागत लगभग 3 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच हो। प्रति वर्ष लगभग 12-15 सेंट की रेंज में रक्षोपाय शुल्क में 4 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच तक की वृद्धि करेगा। लगभग 9000 मेगावाट की क्षमता के साथ डिस्कॉम और परियोजना डेवलपर्स के बीच बड़ी संख्या में विद्युत क्रय करार निष्पन्न किए गए हैं। रक्षोपाय शुल्क को लागू करने से ऐसी वस्तुओं के आयात हानिकारक रूप से प्रभावित होंगे।
- ठ. सोलर सेलों के लिए रक्षा जांच बड़ी जल्दी से शुरू की गई है। डीजीएडी द्वारा पाटन एवं क्षति मार्जिन की जांच तब भी चलती रही जब रक्षा संबंधी जांच शुरू की गई।
- ड. हितवद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणी मांग बिना 70 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क लगाए गए थे। यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो यह संपूर्ण बाजार को विकृत कर देगा। डिस्कॉम सौर विद्युत विकासकर्ताओं से क्रय नहीं करेंगे क्योंकि टैरिफ बढ़ जाएंगे।
- ढ. एलडीडीजी द्वारा उल्लिखित अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव आयातों में वृद्धि का कारण नहीं है। आयातों में वृद्धि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को प्रोत्साहित करने के सरकार के दृष्टिकोण के कारण हुई है। भारत सरकार ने यह ध्यान में रखते हुए निविदाएं जारी कीं कि भारतीय विनिर्माता केवल मांग के 10 प्रतिशत से कम ही पूरा कर सकते हैं।
- ण. इसके अतिरिक्त, घरेलू विनिर्माण क्षमता का 70 प्रतिशत सेज क्षेत्र में स्थित हैं, जिनका लक्ष्य मुख्य रूप से निर्यात बाजार है। इसलिए, ऐसे आयात अप्रत्याशित उतार-चढ़ावों का परिणाम नहीं है, इसके बजाए मांग राष्ट्रीय सौर मिशन के कारण सृजित हुई।
- त. समान अवधि के लिए घरेलू उद्योग के आंकड़े पाटनरोधी जांच में लाभों को दर्शाते हैं। नवीन सुविधा, मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को घाटे दर्शाए गए हैं।
- थ. वेबसोल एनर्जी सिस्टम और जुपिटर सोलर विद्युत की उपलब्ध वार्षिक रिपोर्टें दर्शाती हैं कि हानियों अथवा उच्च लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। हेलियोस को हानि का कारण चल रहा निगमित ऋण गठन है।
- द. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी प्रस्ताव किया है कि प्रौद्योगिकीय सुविधा अप्रचलित है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होगी क्योंकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विद्युत के उत्पादन के 12000 मेगावाट में डीसीआर को शामिल करने की योजना बना रहा है।
- ध. टैरिफ में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होगी और यह प्रति यूनिट 4 रुपये तक पहुँच जाएगी जो सस्ती विद्युत की आपूर्ति के प्रयोजन को समाप्त कर देगा। सभी परियोजनाओं को "विधि में परिवर्तन" खंड के तहत राहत पाने के लिए न्यायालयों में चुनौती दी जाएगी।

(viii) मैसर्स रिन्यू सोलर पावर प्रा. लि. और मै. सोलर एज पावर एंड एनर्जी प्रा.लि.

- क. घरेलू उद्योग ने इस तथ्य पर बल दिया है कि सी-एसआई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विनिर्मित सोलर सेल्स और मॉड्यूलस तथा थिन फिल्मस प्रौद्योगिकी समान वस्तुएं हैं और इन्हें विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के रूप में माना जाना चाहिए। विचाराधीन उत्पाद को गलत रूप से परिभाषित किया गया है क्योंकि सी-एसआई से विनिर्मित सोलर सेल और थिन फिल्म प्रौद्योगिकी को पृथक् उत्पाद हैं और उन्हें समान वस्तु नहीं माना जा सकता और एकल जांच का भाग नहीं बनाया जा सकता। दोनों उत्पादों में भौतिक विशेषताओं, कच्ची सामग्री, उत्पादन प्रक्रिया, बेटेज आउटपुट प्रयोग और परस्पर विनिमेयता के आधार पर विभेदन किया गया है।
- (i) सी-एसआई प्रौद्योगिकी से विनिर्मित सोलर सेल्स और थिन फिल्मस प्रौद्योगिकी को एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि थिन फिल्मस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विनिर्मित किए गए सोलर सेल में सी-एसआई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विनिर्मित सोलर सेल की तुलना में निम्न रुपांतरण क्षमता और भिन्न बेटेज आउटपुट होती है।
- (ii) परियोजना को स्वीकार करने के स्तर पर, विकासकर्ता के पास भौगोलिक संकेतकों, प्राप्त की जाने वाली कार्यकुशलता और वित्तीय क्षतिपूर्ति के आधार पर दोनों में से किसी भी प्रौद्योगिकी को चुनने का विकल्प होता है। एक बार किसी विशिष्ट प्रौद्योगिकी को चुनने के पश्चात बदलकर भिन्न प्रौद्योगिकी के सोलर सेल को अपनाना व्यवहार्य नहीं है।

- (iii) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी निविदाओं में, सरकार ने दो भिन्न उत्पादों के रूप में उन्हें मानते हुए दो प्रौद्योगिकियों के सोलर सेल के लिए प्रभेद उत्तीर्ण किया है।
- (iv) प्रतिस्थापन के स्तर पर, थिन फिल्म प्रौद्योगिकी की संबद्ध वस्तुओं को क्रिस्टलीन प्रौद्योगिकी की संबद्ध वस्तुओं के साथ प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।
- (v) स्थापना के पश्चात, अंतिम प्रयोक्ता किसी थिन फिल्म प्रौद्योगिकी को किसी सी-एसआई प्रौद्योगिकी के मॉड्यूल के साथ प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। सी-एसआई प्रौद्योगिकी से थिन फिल्म प्रौद्योगिकी अथवा विपरीततः परिवर्तित करने का एकमात्र तरीका है कि यदि किसी एक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सम्पूर्ण संस्थापना को किसी एक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सम्पूर्ण संस्थापना को बदल दिया जाए जो इसे अत्यधिक लागत अक्षम और अव्यावहारिक बनाता है।
- ख. घरेलू उद्योग थिन फिल्म प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सोलर सेल का विनिर्माण नहीं करता और दोनों उत्पाद अर्थात् थिन फिल्म और सी-एसआई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं और थिन फिल्म प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं को वर्तमान जांच का भाग नहीं माना जा सकता।
- ग. सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल को किसी एकल जांच का भाग नहीं माना जा सकता जब तक कि वे समान वस्तु के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते। मॉड्यूल एक मूल्यवर्धित उत्पाद है जो सोलर सेल को एक कच्ची सामग्री/इनपुट के रूप में शामिल करता है। बिजली उत्पन्न करने के लिए एक सोलर सेल की क्षमता सीमित होती है, एक मॉड्यूल के विपरीत जो स्वतंत्र आधार पर अकेले वांछनीय और उपयोग योग्य बिजली उत्पन्न कर सकता है। एक सोलर सेल विद्युत के उत्पादन के प्रयोजनार्थ किसी सोलर मॉड्यूल के साथ विनिर्देशित प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।
- घ. घरेलू उद्योग में घरेलू उत्पादक शामिल हैं जो भारत में समान वस्तु के विनिर्माण में संलग्न हैं अथवा वे उत्पादक, जिनका संग्रहित आउटपुट कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख समानुपात ठहरता है। कुछ विशिष्ट आवेदक घरेलू उत्पादक सोलर सेल का आयातक हैं और सोलर सेल को मॉड्यूल में जोड़ने में संलग्न हैं और उन्हें घरेलू उद्योग नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे संबद्ध वस्तुओं के आयात में संलग्न हैं और समान वस्तु के उत्पादक नहीं हैं।
- ङ. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नोटिस के अनुसार, भारत में 117 सोलर मॉड्यूल 20 सोलर सेल विनिर्माता हैं। आवेदन आईएसएमए द्वारा दायर किया गया है जिसमें 23 सदस्य शामिल हैं। आवेदक उत्पादक समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे हैं कि बाकी उत्पादक को आईएसएमए का भाग नहीं है, संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण नहीं करते।
- च. ईओयू और सेज यूनिट में स्थित आवेदक उत्पादक जांच शुरूआत अधिसूचना और प्रारंभिक जांच परिणाम नोटिस के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग नहीं ठहरते क्योंकि किसी सेज के प्राधिकृत प्रचालनों से प्रयोजनार्थ भारत की सीमा शुल्क सीमा क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त, ईओयू यूनिट से डीटीए को हटाई गई कोई वस्तु पर रक्षोपाय शुल्कों सहित सीमा शुल्क प्रभाव्य होगा जहां भी ऐसी वस्तुओं पर प्रयोज्य हो जब उनका आयात किया जाता है। अतः, सेज और ईओयू में स्थापित यूनिटें भारत के घरेलू सीमा क्षेत्र से बाहर की यूनिटें हैं और उन्हें घरेलू उद्योग नहीं समझा जा सकता क्योंकि वे उन्हें प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों और लाभों के कारण एक पृथक् वाणिज्यिक स्थिति पर हैं तथा सेज/ईओयू यूनिटों के उत्पादन और बिक्रियां घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियों द्वारा प्रभावित नहीं होतीं।
- छ. डीजीएस की शक्तियां गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के जोखिम की विद्यमानता की जांच, वस्तु की पहचान, अंतिम और अंतिम जांच परिणाम को प्रस्तुत करने, शुल्क की राशि और अवधि की सिफारिश करने और रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की पुनरीक्षा करने तक सीमित है। सेज यूनिटों से घरेलू बाजार में वस्तुओं पर रक्षोपाय शुल्क की छूट के लिए डीजी की सिफारिश को स्वीकृत किया गया क्योंकि कुछ विशिष्ट आवेदक, जो सेज में प्रचालन कर रहे हैं, को प्राधिकार प्राप्त नहीं है।
- ज. कारक जैसे कि चीनी अधिशेष क्षमता, घरेलू सामग्री को कम करना, पेरिस 2015 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, वेफर, सेल्स, सिलिकॉन आदि जैसे इनपुट की विश्वव्यापी कीमतों में गिरावट के कारण आयातों की गिरती हुई उतरान कीमतें, जीएटीटी के अंतर्गत भारत की बाध्यताएं और आईटीए जो विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर इसके सीमा शुल्क टैरिफ को समाप्त करने का कारण हैं, अप्रत्याशित और असंभावित नहीं कहा जा सकता।
- झ. जबकि, आधार वर्ष से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, वहीं वर्षानुवर्ष आधार पर आयातों की प्रतिशतांक मात्रा में कमी आई है। जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। आयातों की मात्रा में वृद्धि के साथ, घरेलू बिक्रियों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। यह साक्ष्य है कि घरेलू बिक्रियों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। यह साक्ष्य है कि घरेलू बिक्रियों की मात्रा और मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, थिन फिल्मों के आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है और ऐसे निम्न आयात उसे गंभीर क्षति अथवा जोखिम उत्पन्न नहीं कर सकते।
- ञ. आवेदक घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण में संलग्न घरेलू उद्योग की क्षमताओं और देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए वास्तविक मांग के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। इससे यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में लगातार वृद्धि हुई है किंतु ऐसी बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए आवेदक घरेलू उत्पादकों की स्थापित

क्षमता समानुपातिक तरीके में नहीं बढ़ी है। इसलिए, बढ़ी हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

- द. आवेदक घरेलू उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ उचित रूप से प्रतिस्पर्द्धा किए बिना अपने बाजार हिस्से को बढ़ाने के उनके स्वयं के उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए रक्षोपाय शुल्क के कवच के नीचे आश्रय की मांग करते हैं।
- ठ. आर्थिक पैरामीटर जैसे कि कुल उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों और श्रमिक बल का नियोजन क्षति का स्तर निर्धारित करने में आलोचनात्मक है। ये पैरामीटर स्थापित करते हैं कि घरेलू उद्योग वास्तव में बढ़ रहा है जो स्थापित करता है कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण किसी क्षति का सामना नहीं कर रहा है।
- ड. डीसीआर को कम करने के साथ, विकासकर्ताओं के पास विकल्प है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें या आयातित वस्तुओं का। कुशलता, वेटेज आउटपुट बिक्री के पश्चात की सेवा आदि जैसे कारकों के साथ संबद्ध वस्तुओं की कीमत ऐसे मॉड्यूल के प्रकार का निर्धारण करती है जिसे कोई विकासकर्ता अपनी परियोजनाओं के लिए प्रयोग करेगा। यदि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुएं भारत में आयातित संबद्ध वस्तुओं की तुलना में इन कारकों को त्याग दिया जाता है तो डीसीआर को कम करने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की कोई उचित संभावना नहीं हो सकती। अतः घरेलू उद्योग को डीसीआर में कमी के कारण क्षति होना अनुचित है।
- ढ. कथित क्षति और कथित बड़े हुए आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि क्षति अन्य कारणों की वजह से है, जैसे कि संबद्ध वस्तुओं की विश्वव्यापी मांग में गिरावट, आवेदक उत्पादकों द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं की घटी हुई मांग, सुविधाएं जैसे कि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध न कराई जा रही 25 वर्ष की वारंटियों, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स की गुणवत्ता में नए प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों को नियोजित करने में अक्षमता। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में उतार-चढ़ाव और विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्द्धा के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को संबद्ध वस्तुओं के आयातों के साथ संबद्ध नहीं किया जा सकता।
- ण. डीजीएस द्वारा जारी किया गया प्रारंभिक जांच परिणाम नोटिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवज्ञा करता है क्योंकि यह हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है और हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई समयावधि के समाप्त होने से पहले ही 70 प्रतिशत यथा मूल्य शुल्क का प्रारंभिक निर्धारण किया गया है।
- त. प्रारंभिक निर्धारण करने के लिए आलोच्य परिस्थितियां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अवलोकन करती है जहां तक गंभीर परिस्थितियों के लिए स्पष्ट साक्ष्य की आवश्यकता है और साक्ष्य की स्पष्टता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती और साक्ष्य की स्पष्टता पर तब तक नहीं पहुँचा जा सकता, जब तक कि अन्य पक्ष के प्रतिवेदनों का संज्ञान न लिया जाए। आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य स्पष्ट साक्ष्य नहीं हो सकते क्योंकि यह अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा खंडन के लिए खुला है। इसलिए, जब तक इस साक्ष्य का कोई सत्यापन और प्रति प्रश्नों के अध्यधीन न हो, जो उसे सुस्पष्ट और सुव्यक्त बनाते हैं, इसे सुनिश्चित साक्ष्य नहीं माना जा सकता।
- थ. डीजीएस द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम दर्ज कराने के लिए अपूरणीय क्षति एक अपरिहार्य शर्त है। शुल्क लागू किए जाने की सिफारिश अपूरणीय क्षति को औचित्य सिद्ध करने/उसे स्पष्ट करने में असमर्थ है जो क्षति प्रारंभिक जांच निर्धारण को न्यायसंगत सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग को हो सकती है। घरेलू उद्योग को और "अधिक हानि" शब्द को "अपूरणीय क्षति" के साथ उद्धरित नहीं किया जा सकता।

(ix) मैसर्स एसीएमई सोलर होल्डिंग्स लि.

- क. वे 12 राज्यों में 874 मेगावाट प्रचालनात्मक क्षमता वाले 2 गीगावाट से अधिक के कार्य क्षेत्र वाले सबसे बड़े सौर विद्युत विकासकर्ता हैं। सौर मॉड्यूल में सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए अपेक्षित 50 प्रतिशत से अधिक घटक होते हैं और इसीलिए कंपनी के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
- ख. 60 प्रतिशत याचिकाकर्ता कंपनियां विशेष आर्थिक क्षेत्र में हैं और वे सरकार द्वारा दी गई कई राजकोषीय एवं गैर-राजकोषीय लाभ लेते हैं तथा रक्षोपाय शुल्क के लिए उन्हें घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता। इन याचिकाकर्ताओं से संबंधित आंकड़े भारतीय घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने तथा उसका परिकलन करने के लिए अलग नहीं किए जा सकते।
- ग. जांच रिपोर्ट में घरेलू उद्योग के उत्पादन के आंकड़ों में पूरा अंतर है जो कि 7,173 मेगावाट के सरकारी स्रोतों के आंकड़ों के विपरीत 544 मेगावाट है। इन दो संख्याओं में भारी अंतर है और जांच रिपोर्ट में इस संख्या पर विश्वास करने से रक्षोपाय शुल्क लगाने की गलत सिफारिश हुई है।
- घ. घरेलू उद्योग की क्षमता गलत बताई गई है क्योंकि घरेलू उद्योग का 2016 में उद्योग के 10.5 प्रतिशत की तुलना में 2017 में घरेलू सौर विनिर्माण उद्योग में 72 प्रतिशत से कम का हिस्सा है।

- ड. पेरिस करार अथवा राष्ट्रीय सौर मिशन के प्रति प्रतिबद्धता के कारण कोई परिस्थिति नहीं दिखाई थी क्योंकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट सोलर 2016-17 में स्वीकार किया है कि इस मिशन में 2022 तक ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर का 20,000 मेगावाट का विकास का लक्ष्य शामिल है। घरेलू उद्योग 2022 तक 100 गीगावाट के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के कारण सौर मॉड्यूलों और पैनलों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अभी भी तैयार नहीं था। इससे सौर विद्युत विकासकर्ता बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मॉड्यूलों और पैनलों का आयात करने के लिए मजबूर हो गए।
- च. आईटीए-1 के लिए बीसीडी की छूट प्रदान करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी करार के तहत डीजीएस भारत की प्रतिबद्धता को जोड़ने वाले डीजीएस 1996 में किया गया था और विचाराधीन उत्पाद के आयात में कोई हाल की वृद्धि बहुत दूर की बात है तथा उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।
- छ. आयातों में वृद्धि की इन परिस्थितियों को पहले से नहीं देखा जा सकता और प्रशुल्क छूटों सहित जीएटीटी के तहत दायित्वों का प्रभाव नहीं है। अतः जीएटीटी के अनुच्छेद XIX के तहत आवश्यकता पूरी नहीं है।
- ज. सोलर सेल की लागत मॉड्यूल की कुल लागत का 50 से 60 प्रतिशत है। भारतीय मॉडलों की कीमतें 2014-15 से 2017-18 की अवधि में रिपोर्ट में दर्शाई गई कमी के विपरीत 27 से 30 प्रतिशत के मार्जिन तक नीचे गई है। सेल की लागत 2014-15 की तुलना में 2017 में 38 प्रतिशत तक नीचे गई है जबकि मॉड्यूल की लागत केवल 8 प्रतिशत तक नीचे गई है। यह तर्क के विपरीत है क्योंकि सेल मॉड्यूल की लागत के लगभग 60 प्रतिशत हैं। अतः सेल की कीमत में गिरावट का प्रभाव मॉड्यूल की कीमत पर काफी अधिक होना चाहिए। अतः घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली की विकृत अवधारणा रही है।
- झ. सौर विद्युत क्षेत्र की वृद्धि से अर्धकुशल रोजगारों की काफी संख्या बनी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को अवसर प्रदान कर रहा है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि डिस्कॉमों को उपलब्ध कराई जाने वाली सस्ती विद्युत पर निर्भर है।
- ञ. घरेलू उद्योग पिछले दो वर्षों में अपने मार्जिन और इकट्टी के भाग में उल्लेखनीय लाभ कमा रहा है जो कंपनी रजिस्ट्रार से प्राप्त तुलन पत्र के अनुसार उनके काफी हानि के दावों के विपरीत है।
- ट. घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन की वृद्धि 473 से बढ़कर 838 हुई है जो उत्पादन में 100 प्रतिशत की वृद्धि के आसपास है। अतः आयात आंकड़ों को तब अलग से देखना उपयुक्त नहीं है जब सौर व्यापार की पूरी पारि-प्रणाली वर्ष 2016-17 में 100 प्रतिशत तक बढ़ी।
- ठ. रक्षोपाय शुल्क लगाने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है क्योंकि डीजीएस ने जांच की शुरुआत के विरुद्ध निर्यातकों अथवा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनकी आपूर्तियां उठाने का अवसर नहीं दिया।
- ड. डीजीएस ने दी गई किसी सूचना की प्राधिकारिता का सत्यापन किए बिना घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों पर पूरी तरह से विश्वास किया है। केवल आयात आंकड़ों के संबंध में वे डीजीसीआईएंडएस, वाणिज्य विभाग से जून, 2017 तक जांच की अवधि के लिए प्राप्त किए गए हैं और उसके बाद जांच की अवधि की शेष अवधि के लिए इनफोड्रिव मीडिया से प्राप्त किए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा बड़े हुए आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को भारी क्षति दर्शाने के लिए अलग से कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं। लाभ/हानि, रोजगार तथा उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए अधिकतर आंकड़े गलत और भ्रामक हैं, जैसा कि प्राधिकृत स्रोत से अलग-अलग आंकड़े दर्शाते गए हैं।
- ढ. कोई भी शुल्क लगाया जाना आंकड़ों और कारण से समर्थ होना चाहिए तथा शुल्क लगाए जाने और उसके उद्देश्य के बीच ऐसे शुल्क के लिए सीधा संबंध होना चाहिए। ऐसा कोई कारण डीजीएस के प्राथमिक जांच परिणाम में नहीं है।
- ण. सरकार ने 28 जनवरी, 2016 को संशोधित शुल्क नीति अधिसूचित की थी जिसमें नीति में उपयुक्त दरों पर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और नाभिकों के जीवन स्तर में तेजी से आर्थिक वृद्धि तथा सुधार प्राप्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र में पर्याप्त निवेश आकर्षित करने की आवश्यकता मानी गई थी। घरेलू खरीद को मानने वालों को छोड़कर सभी तृतीय सोलर सेल और मॉड्यूल के आयात की लागत में कारक थे। सोलर सेलों और मॉड्यूलों के आयात की लागत में वृद्धि का सौर विद्युत विकास उद्योग पर सीधा एवं वास्तविक प्रभाव पड़ेगा।
- त. स्वदेशी मॉड्यूल विनिर्माण उद्योग केवल पूरी मूल्य श्रृंखला में लगभग 10-13 प्रतिशत रोजगार देता है। बीओएस नामक सहायक क्षेत्र में 60 उद्योग हैं जिसमें कुल रोजगार सृजन 70-90 प्रतिशत है। दबाव में आए हुए विकासकर्ता से ये पूरी मात्रा लड़खड़ा जाएगी।
- थ. प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के कारण विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रयुक्त सोलर मॉड्यूलों के संबंध में सौर विद्युत विकासकर्ता सीमा शुल्क को ध्यान में रखते हैं। सौर विद्युत विकासकर्ताओं द्वारा उल्लिखित दर पीपीए में कानून की धारा में परिवर्तन के अध्यधीन 25 वर्षों के लिए बनाए रखी जानी अपेक्षित है। बोली के समय कंपनी ने यूनिट कीमत का उल्लेख करने के लिए रक्षोपाय शुल्क को ध्यान में नहीं रखा और कोई रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से विद्युत की लागत में वृद्धि होगी जिससे पूरी

परियोजना गैर-अर्थक्षम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, पहले ही दी गई संविदाओं के संबंध में कंपनी ने सोलर सेलों और मॉड्यूलों के आयात के लिए आदेश दे दिए। अतः शुल्क लगाए जाने से उस समय भारी नकद प्रवाह का मुद्दा बनेगा जब ऐसे शुल्क के भुगतान के संबंध में आयातों को सीमा शुल्क विभाग से छुड़ाया जाए। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने को शामिल करने के लिए पीपीए में कानून की धारा में परिवर्तन करने के लिए आयोग के समक्ष याचिका दायर करने का कार्य एक लंबी प्रक्रिया होगी और संशोधित प्रशुल्क प्राप्त करने में विलंब से व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा।

- द. विलंब के कारण अधिकतर परियोजनाएं शुरू नहीं हो पाएंगी और रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से अनिश्चितता के आलोक में बैंक निधियां लगाने में उदासीन होंगी।
- ध. भारत में आयात महानिदेशक के इस विचार के विपरीत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के लिए सरकार के इस उद्देश्य के कारण बड़े हैं कि चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा व्यापार उपचार उपायों के कारण अपने आयात भारत की ओर किए और भारत ज्यादा देर तक घरेलू उद्योग की घरेलू मात्रा की आवश्यकता का सुरक्षित परिवेश प्रदान नहीं कर सकता। चीन और अन्य देशों से आयात भारत में मांग और आपूर्ति के अंतराल को पूरा करते हैं जहां भारतीय विनिर्माता केवल 10 प्रतिशत से कम मांग को पूरा कर सकते हैं।
- न. घरेलू उद्योग 2017 में नई विनिर्माण सुविधा वाली एक कंपनी के जुड़ने के कारण हानियों की तस्वीर बनाता है। नई सुविधाओं में ब्याज एवं मूल्यहास की अत्यधिक लागत शामिल है जिसका लाभप्रदता पर हानिकारक प्रभाव है। इन कंपनियों को क्षति आयातों के कारण नहीं है बल्कि अत्यधिक ब्याज लागत एवं मूल्यहास लागत के कारण है।
- प. तीन याचिकाकर्ताओं की स्थिति में उन दो याचिकाकर्ताओं की स्थिति के विपरीत क्षति की अवधि में सुधार हुआ है जिनको नई विनिर्माण सुविधा, पुनर्गठन और अप्रयोज्य प्रौद्योगिकी जैसी अंतर्निहित समस्याओं के कारण हानियां हुई हैं। अतः आयातों में वृद्धि से क्षतियां नहीं हुई हैं।
- फ. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 12000 मेगावाट की एक सीपीएसयू योजना का प्रस्ताव किया है जिसमें एक सुनिश्चित डीसीआर घटक होगा जो घरेलू उद्योग को एक आश्वस्त बाजार देगा। महानिदेशक का यह निष्कर्ष कि यदि अनंतिम रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाता है तो गंभीर क्षति होगी, सही नहीं है।

(x) मैसर्स एमप्लस एनर्जी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

- क. "मॉडलों अथवा पैनेलों में असेंबल किए गए अथवा असेंबल न किए गए सोलर सेल" के आयातों पर प्रस्तावित 70 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से कंपनी की 100 प्रतिशत की इक्विटी बट्टे खाते में डाले जाने से तत्काल शुल्क लगाये जाने का भुगतान करने में कंपनी की अर्थक्षमता तथा निर्माणाधीन सौर परियोजनाओं के शुरू न होने के कारण परियोजनाओं में 700 करोड़ भारतीय रुपए का एनपीए होगा।
- ख. शुल्क लगाए जाने से 1000 करोड़ भारतीय रुपए के एफडीआई निवेश के कारण भारत के "व्यापार करने की आसानी" और "निवेशक अनुकूल नीति" को प्रतिष्ठा की हानि होगी।
- ग. शुल्क लगाए जाने से प्रमुख वैश्विक कंपनियों के साथ विद्युत क्रय करारों में प्रशुल्क संविदा पर आपूर्ति करने के लिए कंपनी की अर्थक्षमता होगी तथा भारतीय नीतिगत व्यवस्था में उनका विश्वास हिल जाएगा और अब आगे के विस्तार में बाधा पड़ेगी।
- घ. कंपनी की वित्तीय दुर्दशा 2700 लोगों के लिए रोजगार की हानि के परिणाम में होगी जो घरेलू सेल उद्योग में रोजगार से अधिक है।
- ङ. रोजगार का प्रभाव काफी सौर विकासकर्ताओं और ईपीसी उद्योग में 10,000 कर्मचारियों के रोजगार के कारण और बदतर होगा। अतः, अधिक समय देकर शुल्क लगाये जाने से घरेलू सोलर ईपीसी उद्योगों को पर्याप्त अवधि मिल जाएगी।

(xi) मैसर्स क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशन्स प्रा. लि.

- क. वे भारत में सबसे बड़े "रूफटॉप सोलर डेवलेपर", जिनका पिछले तीन वर्षों में औसतन 22 प्रतिशत बाजार हिस्सा है।
- ख. कंपनी को 350 करोड़ भारतीय रुपए का रक्षोपाय शुल्क देना होगा जो कि एक हानि है क्योंकि यह कर्नाटक में 166 मेगावाट एसी क्षमता का सोलर विकसित करने के लिए परियोजना में 260 करोड़ भारतीय रुपए के कुल इक्विटी निवेश से अधिक है। इससे कंपनी को दिवालिया घोषित करना होगा।
- ग. शुल्क के प्रपाती प्रभाव से कंपनी की 100 प्रतिशत की इक्विटी बट्टे खाते में डाले जाने से तत्काल शुल्क लगाये जाने का भुगतान करने में कंपनी की अर्थक्षमता तथा निर्माणाधीन सौर परियोजनाओं के शुरू न होने के कारण 660 करोड़ भारतीय रुपए तक बैंकिंग एनपीए में वृद्धि होगी।

- घ. कंपनी की वित्तीय दुरावस्था से 2165 लोगों के रोजगार की हानि होगी जो घरेलू सेल उद्योग में रोजगार से अधिक है।
- ङ. रोजगार का प्रभाव काफी सौर विकासकर्ताओं और ईपीसी उद्योग में 10,000 कर्मचारियों के रोजगार के कारण और बदतर होगा। अतः, अधिक समय देकर शुल्क लगाये जाने से घरेलू सोलर ईपीसी उद्योगों को पर्याप्त अवधि मिल जाएगी।
- च. शुल्क लगाए जाने से 250 करोड़ भारतीय रुपए के एफडीआई निवेश के कारण विश्व बैंक की "व्यापार करने की आसानी" रैंकिंग में और "निवेशक अनुकूल नीति" को प्रतिष्ठा की हानि होगी।
- छ. उन उप संविदाकारों की वित्तीय स्थिति प्रभावित होगी जो कंपनी की वित्तीय दुरावस्था के कारण छोटे पैमाने के व्यापार में हैं।

(xii) मैक्सिको सरकार/दूतावास

- क. 01 जनवरी, 2014 से 30 सितंबर, 2017 तक की अवधि में भारत द्वारा किए गए मैक्सिको के उत्पाद के आयात उसी अवधि में भारत द्वारा किए गए कुल आयातों के 3 प्रतिशत से कम हैं। मैक्सिको एक विकासशील देश है और मैक्सिको के निर्यात रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 की दृष्टि से रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से अलग रखे जाने चाहिए।

(xiii) यूरोपीय आयोग

- क. विचाराधीन उत्पाद की प्रमुख मात्रा चीन से आयातित की जाती है। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता का औचित्य बनाने के लिए प्रयुक्त पूरा तर्क चीन से लगभग आयातों से बनता है। केवल एक देश से आयातों में वृद्धि अधिक और काफी होने पर भी रक्षोपाय के प्रयोग का औचित्य बनाने के लिए काफी नहीं है जो सभी आयातों पर समान रूप से लागू होता है। चीनी आयात इस समय पाटनरोधी के अधीन हैं और यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने से पूर्व चल रही पाटनरोधी जांच के निष्कर्ष की प्रतीक्षा की जाए।
- ख. उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 2016-17 में आयातों की तुलना में 74 प्रतिशत तक 2017-18 के पहले 6 माह के दौरान आयात मात्रा में उछाल का निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सतत तुलना करने के लिए 2017-18 के पहले 6 माह की तुलना पूर्व वर्ष में उसी अवधि से की जानी चाहिए। तथाकथित 76 प्रतिशत का उछाल अस्पष्ट है जिसमें इसके विपरीत 26 प्रतिशत की गिरावट थी। जांचकर्ता प्राधिकारियों को इन आंकड़ों को स्पष्ट करना चाहिए और संगत आंकड़े देने चाहिए।
- ग. चीन से उसी उत्पाद के आयात के संबंध में तथा भारत में डीसीआर का कचरा बनाने के संबंध में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा व्यापार उपचार उपाय लगाना पूर्वपक्षित घटनाओं के रूप में देखा जाता है। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाटनरोधी और सीवीडी उपाय लगाने के बाद भारत को डीसीआर के कारण बड़े हुए आयातों से तत्काल नुकसान नहीं हुआ। वर्ष 2013 में चुनौती के बाद डब्ल्यूटीओ ने डीसीआर को असंगत घोषित किया और भारत ने उसे छोड़ दिया था। यह वर्ष 2013 में हुआ और 2017 में आयातों की वृद्धि के लिए अप्रत्याशित घटना नहीं हो सकती।
- घ. कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धताओं से सौर ऊर्जा के लिए भारतीय मांग में वृद्धि हुई है। यदि मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के पास बड़ी हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी क्षमता नहीं है।
- ङ. सुरक्षा जांच में गंभीर क्षति पाटनरोधी/सीवीडी जांचों में अपेक्षित वास्तविक क्षति से अधिक है। घरेलू उद्योग की कुल बिक्री पांच गुना से अधिक बढ़ी और उत्पादन संबंधित अवधि में तीन गुना से अधिक बढ़ा। घरेलू उद्योग ने उस समय 2017-18 में 1000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता संस्थापित की जब उसके पास 22 प्रतिशत अनुपयुक्त क्षमता थी। क्षमता उपयोग में गिरावट अतिरिक्त क्षमता में निवेश के परिणामस्वरूप है।
- च. घरेलू बाजारों में एक नई कंपनी आई जिससे कर्मचारियों की कुल संख्या में समग्र वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि नई कंपनी द्वारा सृजित रोजगार में गिरावट को देखने के लिए आंकड़ों से अलग किए जाने चाहिए। इस प्रकार, इन्हें अलग करना कृत्रिम है और रोजगार के मूल्यांकन में संगत तथ्यों को छिपाने का इरादा है।
- छ. घरेलू उद्योग को आयातों में तथाकथित वृद्धि से पूर्व मानी गई पूरी अवधि के दौरान लगातार हानियां हुईं। इसका अर्थ यह है कि आयातों के सिवाय और भी कई कारण हैं जिनकी हानियों के कारण के रूप में जांच की जानी चाहिए।
- ज. अतिरिक्त क्षमता में निवेश के लिए निर्णय, मांग में वृद्धि की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने नकारात्मक निष्पादन से युक्त निर्यात बाजारों में भारी हानियां घरेलू बाजार के प्रमुख एवं स्थिर हिस्से में आयात, जो प्रश्रुत कारणों से संपर्क बनाते हैं, जैसे कारकों पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- झ. कोई भी रक्षोपाय सभी स्रोतों से आयातों को समान रूप से प्रभावित करेंगे जो कि भारतीय बाजार में कम मात्रा में आते हैं और जो घरेलू उद्योग को होने वाली किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है।
- ञ. मानी गई अवधि में 600 प्रतिशत से अधिक की घरेलू मांग में भारी वृद्धि का अर्थ है कि यहां तक कि यदि घरेलू उद्योग अपनी 100 प्रतिशत क्षमता पर उत्पादन करे तो वह कुल भारतीय मांग का केवल 16 प्रतिशत ही हो जाएगा। अतः कोई भी रक्षोपाय बाजार के लगभग 85 प्रतिशत पर लागू होगा जिससे भारतीय आयातकों और निचले उत्पादकों के लिए कीमतों में अनुचित वृद्धि होगी, उत्पाद विकल्प सीमित होगा और घरेलू बाजार में भारी कमी होगी जिससे भारत में अतिरिक्त रूप से पेरिस करार के तहत अपनी उपलब्धताएं पूरी करने में मदद नहीं मिलेगी।

(xiv) ताइवान फोटो वोलेक इंडस्ट्री एसोसिएशन

- क. पांच आवेदक घरेलू उत्पादकों में तीन उत्पादक विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित हैं और उन्हें घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत से बाहर के क्षेत्र में माना जाता है और आयात अथवा निर्यात सामानों के लिए सभी शासी कानून उन पर लागू होंगे। किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट द्वारा उत्पादित सामान घरेलू रूप से विनिर्मित नहीं किए जा सकते।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता के कारण मान्य योग्य नहीं है क्योंकि वे हितवद्ध पक्षकारों की रक्षा के अधिकारों को प्रभावित करते हैं, कीमतों को गिराते हैं, घरेलू उद्योग को संधारणीय क्षति के लिए औचित्य वाले आधार के लिए अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, राष्ट्रीय सौर मिशन को प्रभावित करने वाले काफी शुल्क लगते हैं, आयात में वृद्धि अप्रत्याशित नहीं होती और शुल्क लगाने के लिए वे काफी नहीं होते।
- ग. संबद्ध सामानों के लिए बढ़ती हुई मांग घरेलू उद्योग की मांग को पूरा करने की क्षमता के अभाव के कारण घरेलू उद्योग और आयातों, दोनों द्वारा पूरी की जाती हैं। घरेलू मांग, घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता से कहीं अधिक है।
- घ. डीजीएडी ने सोलर सेलों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जांच शुरू की है, वे सेल चाहे चीन, ताइवान और मलेशिया से असेंबल हो अथवा नहीं हों। घरेलू उद्योग के हितों की बड़े हुए पाटित आयातों के कारण हुई संभावित वास्तविक क्षति से पाटनरोधी जांचों द्वारा संरक्षित की जा रही हैं, यदि डीजीएडी द्वारा जांच परिणाम किए जाते हैं। पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क, दोनों को लगाने से दोगुना खतरा हो जाता है।
- ङ. इंडो सोलर, वेबसोल और जुपिटर सोलर नामक घरेलू उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए याचिका दायर की और अंतिम जांच परिणाम के द्वारा डीजीएडी ने प्रशुल्क लगाया। तथापि, केंद्र सरकार ने वह शुल्क लगाए जाने को अधिसूचित नहीं किया है। घरेलू उद्योग तब से ही संबद्ध सामानों के आयात से प्रतिस्पर्द्धा समाप्त करने की प्रक्रिया में है। घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय के तहत लाभ लेने के लिए और उचित प्रतिस्पर्द्धा समाप्त करने के लिए मंच खरीदारी तथा एक उत्पादक संघ बनाने की पद्धति के रूप में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए दूसरा आवेदन दायर किया है।

(xv) फस्ट सोलर एफई होल्डिंग्स पीटीई. लि. (यूएसए, सिंगापुर)

- क. थिन फिल्म उत्पाद और सी-एसआई पीवी भौतिक तथा तकनीकी गुणधर्मों, उत्पादन प्रौद्योगिकी आदि जैसे मानदंडों के आधार पर समान वस्तु अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धा वस्तु नहीं है। दोनों में से कोई भी उत्पाद प्रणाली के संतुलन के बिना उपयोग योग्य बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते। यह केवल प्रणाली के संतुलन के एकीकरण के बाद ही हो सकता है कि दोनों उत्पाद प्रयोग योग्य बिजली का उत्पादन करें। इससे उनके लिए दो विकल्प बनते हैं न कि दो समान वस्तु। थिन फिल्म उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान जांच एक जांच में दो वैकल्पिक उत्पादों की जांच करने के लिए समान है।
- ख. विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटें स्थापित करने का मूलभूत उद्देश्य निर्यातों का संवर्धन है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के क्षेत्र घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की परिभाषा से अलग किए गए हैं और वहां से समाप्त करना सीमा शुल्क के अध्येधीन है। एसईजेड यूनिट द्वारा विनिर्मित सामानों की डीटीए बिक्री केवल आयात लाइसेंस प्रस्तुत करने पर ही की जा सकती है। एसईजेड यूनिट को घरेलू उद्योग का भाग मानने का तर्क स्वीकार्य नहीं है।
- ग. रक्षोपाय कानून में प्रयुक्त शब्द "भारत में उत्पादक" है और एसईजेड में स्थापित एसईजेड यूनिट भारत में अधिक उत्पादक नहीं है क्योंकि वह मानने योग्य नहीं है क्योंकि एसईजेड यूनिट भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र के रूप में माना जाता है। एसईजेड उत्पादक घरेलू उद्योग नहीं हो सकता और उसे घरेलू उद्योग के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए।
- घ. याचिकाकर्ताओं का वर्तमान याचिका में बने रहने का आधार नहीं है क्योंकि उनका उत्पादन भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात नहीं है तथा व्यापक रूप से निर्यात के लिए उत्पादन है।
- ङ. सेलों का आयात कच्ची सामग्री का आयात है और उसे आयातों में शामिल नहीं किया जा सकता। आयातों में कोई उछाल नहीं है क्योंकि अन्य उत्पादकों द्वारा भारत में मॉड्यूल उत्पादन को भारतीय उत्पादन में शामिल किया जाना चाहिए। थिन फिल्म को क्षति पहुँचाने वाले के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आयातों में उछाल प्रमुख रूप से सी-एसआई पीवी के कारण है।
- च. जांच की शुरुआत की सूचना में कोई अप्रत्याशित घटना की पहचान नहीं है और वह असंगत है। सेल के आयातों में उछाल भारत में उत्पादन करने वाले उद्योग के बजाए उद्योग द्वारा स्वयं सेलों का आयात करने के कारण है। अन्य उत्पादकों, जो इस याचिका के भाग नहीं हैं, के द्वारा आयातों को अप्रत्याशित वर्णित नहीं किया जा सकता।
- छ. घरेलू उद्योग के निष्पादन में वास्तविक रूप से सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग के उत्पाद और बिक्री में क्षति की अवधि में काफी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को भारत में आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। याचिकाकर्ताओं को आयातों में क्षति हुई है जो कि रक्षोपाय शुल्क द्वारा सुधारी नहीं जा सकती।
- ज. गंभीर क्षति मानदंडों का खतरा क्षति मानदंडों के रूप में नहीं हो सकता क्योंकि जांच की शुरुआत की सूचना में कोई अन्य आंकड़े अथवा विश्लेषण यह नहीं दर्शाते कि गंभीर क्षति का खतरा है।

- झ. घरेलू उद्योग के लिए निर्यात बाजार टूटने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हुई है। भारत में सौर विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए कई सरकारों की पहलों के परिणामस्वरूप घरेलू बाजार ने बेहतरी दर्शाई है। जो कंपनियां पिछले चार वर्षों के महत्वपूर्ण भाग के लिए क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं रही हैं, उन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन पुनः शुरू कर दिया है।
- ञ. डीजीएडी ने पूर्व में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जिसे आयातों से घरेलू उद्योग को भारित क्षति के अभाव में केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया गया था, रक्षोपाय शुल्क से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आयातित सामानों की कीमतों में वृद्धि हुई और कीमतें बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग हेतु एक साधन दिया जहां अंतिम पीड़ित व्यक्ति घरेलू उपभोक्ता है। यह सिद्ध करता है कि रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में नहीं है।

(xvi) फर्स्ट सोलर इंक.

- क. इस आधार पर प्राथमिक आपत्ति की एसईजेड यूनिट को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में माना गया है। एसईजेड यूनिट को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में नहीं माना जा सकता, जैसा कि महानिदेशक के विगत निर्णयों में विसंगति से सिद्ध भी है। इस मुद्दे पर इस मामले में आगे की कार्रवाई करने से पूर्व निर्णय लिया जाना चाहिए।

(xvii) सोलर एनर्जी इन्फ्रामेंट मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना

- क. देश में 1.6 गीगावाट की सोलर सेल विनिर्माण क्षमता और 5.5 गीगावाट की मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता है। सोलर सेल विनिर्माताओं के पास सोलर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा है जो उनके द्वारा उत्पादित सोलर सेलों की खपत करती है। सोलर सेलों में रक्षोपाय शुल्क लगाने से सोलर मॉड्यूल विनिर्माताओं द्वारा सोलर सेल खरीदने में समस्या होगी।
- ख. सोलर सेलों और मॉड्यूलों को आयात के लिए एक ही वस्तु माना जाता है, सोलर मॉड्यूल और सोलर सेलों पर शून्य शुल्क की अनुमति दी जाती है। सोलर सेलों ने सोलर मॉड्यूल की लागत का 60 प्रतिशत होता है और सोलर मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित सामग्री के 40 प्रतिशत की खरीद सोलर मॉड्यूल विनिर्माताओं द्वारा आयात शुल्क का भुगतान कर की जाती है, परंतु आयातित मॉड्यूलों पर शुल्क मुक्ति की अनुमति दी जाती है। एसएमई लगाने से सोलर मॉड्यूल विनिर्माताओं को सोलर सेल विनिर्माताओं की तुलना में भारी हानि होगी।
- ग. सोलर सेल भारत में उपलब्ध नहीं है क्योंकि अधिकतर सोलर सेल विनिर्माताओं के पास उनके सभी उत्पादन में प्रयोग के लिए मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता है। सोलर मॉड्यूल विनिर्माताओं, जो अधिकतर एसएमई हैं, के लिए विनिर्माण लागत उन विनिर्माताओं की तुलना में 42 प्रतिशत तक अधिक हो जाएगी जिनके पास सेल विनिर्माण क्षमता है क्योंकि वे 70 प्रतिशत शुल्क देकर सेलों का आयात करने के लिए मजबूर हैं।
- घ. सोलर सेलों और मॉड्यूलों के लिए भिन्न रक्षोपाय होने चाहिए। सोलर सेलों में काफी क्षमता नहीं है और क्षमता का निर्माण करना खर्चीला तथा समय लेने वाला है। अतः सोलर सेलों पर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाना चाहिए।

(xviii) वारबर्ग पिक्स इंडिया प्रा. लि.

- क. इस कंपनी ने क्लीन मेक्स सोलर में निवेश किया है जो पूरे भारत में लगभग 300 मेगावाट सोलर परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है, प्रमुख घरेलू एवं बहुराष्ट्रीय निगम तथा सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों को सेवा दे रही है। कंपनी की सतत परियोजनाओं और रक्षोपाय शुल्क से रोजगार की हानियां होंगी और निवेशक की पूंजी के लिए घातक होगी जिससे उसकी दीर्घवधि परियोजनाओं को क्षति पहुँचेगी।
- ख. भारतीय बैंकों द्वारा सतत परियोजनाओं के लिए दिया गया ऋण वित्तपोषण निष्पादन न करने वाली परिसंपत्तियों में बदलने के जोखिम पर होगा।

(xix) मैसर्स विक्रम सोलर लि.

- क. सोलर सेल सोलर पीवी प्रणाली की सबसे आधारभूत यूनिट है। एक पीवी मॉड्यूल में बहुत पीवी सेल्स होते हैं जो अधिक वोल्टता उत्पादन देने के लिए श्रृंखलाओं में घिरे होते हैं। मॉड्यूल मूल्यवर्द्धित उत्पाद हैं जो सोलर सेलों को इलैक्ट्रिक विद्युत के उत्पादन के लिए प्रयुक्त वाणिज्यिक रूप से उपयोगी वस्तु में बदलते हैं। सोलर सेलों के विनिर्माण के लिए सीमित घरेलू क्षमता के आलोक में विनिर्माताओं को आयातित सेलों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- ख. सोलर सेलों पर लगाए गए रक्षोपाय शुल्कों का डीटीए से हटाए जा रहे उसके सभी सोलर सेल मॉड्यूलों के लिए शुल्क देने वाली एसईजेड यूनिट का प्रभाव होगा। उस उपाय से एसईजेड यूनिटों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ग. सरकार की 2022 तक सौर ऊर्जा के 100 गीगावाट संस्थापित करने की योजना के लिए एसईजेड यूनिटों को उन पर कोई अतिरिक्त भार डाले बिना और उन्हें प्रतिस्पर्द्धाहीन बनाए बिना उनकी पूर्ण क्षमताओं को संचालित करने की अनुमति देने की आवश्यकता है। घरेलू सौर ऊर्जा की मांग काफी मात्रा तक एसईजेड यूनिटों में उत्पादन पर तथा आयातित सोलर सेलों पर निर्भर करती है। शुल्क लगाने से सौर परियोजनाएं लगाने की लागत में वृद्धि होगी।

- घ. घरेलू उत्पादकों द्वारा विनिर्मित सोलर मॉड्यूलों की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है। घरेलू उत्पादन के अधिकतर खंड एसईजेड में स्थित हैं और रक्षोपाय शुल्क लगाने से इन विनिर्माताओं पर ही प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि 2022 तक 100 गीगावाट सौर विद्युत का लक्ष्य प्राप्त करना भी असम्भव होगा क्योंकि 100 गीगावाट लक्ष्य का अधिकतर भाग आयात के माध्यम से पूरा किया जाना है। इससे कोयला और संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों जैसे पारंपरिक ईंधनों के माध्यम से विद्युत उत्पादन होगा। रक्षोपाय शुल्क इस प्रकार स्पष्ट रूप से जनहित के विरुद्ध है जो कि रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत है।
- ङ. यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो महानिदेशक को शुल्क की शून्य दर पर 5 गीगावाट के प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) निर्धारित करना चाहिए। टीआरक्यू से दावेदारों की अधिकतर चिंताएं दूर हो जाएंगी। यह एसईजेड में स्थापित घरेलू उत्पादन सुविधाओं को राहत देते हुए और टीआरक्यू व्यवस्था के तहत निर्धारित कोटे से अधिक आयातों पर रक्षोपाय शुल्क देकर डीटीए उत्पादकों का संरक्षण देते हुए सौर विद्युत उत्पादन की उत्पादन लागत पर अतिरिक्त कोई अतिरिक्त भार डाले बिना मांग एवं आपूर्ति के अंतराल को पूरा करेगा।
- च. भारत सरकार को एसईजेड से डीटीए में हटाए गए सोलर मॉड्यूलों पर रक्षोपाय शुल्क के भुगतान से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के तहत विशेष छूट प्रदान करनी चाहिए।
- छ. यूएसआईटीसी रक्षोपाय सिफारिशों पर विश्वास किया गया जिनमें उन्होंने मॉड्यूलों/पैनलों में असेंबल किए गए सोलर सेलों पर अधिक रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के अनुरोध करने के लिए सोलर सेलों की तुलना के रूप में मॉड्यूलों/पैनलों में असेंबल किए गए सोलर सेलों पर अधिक रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की थी।

(xx) विदेश व्यापार विभाग, रॉयल थाई सरकार

- क. किसी विकासशील देश के सदस्य के मूल के उत्पाद के विरुद्ध रक्षोपाय तब तक लागू नहीं किए जाएंगे जब तक आयातक सदस्य ने संबंधित उत्पाद के आयात का हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाता है। थाइलैंड से आयात पिछले तीन वर्षों में 3 प्रतिशत से कम है। अतः थाइलैंड को ये उपाय लगा जाने से अलग रखा जाना चाहिए।

(xxi) ग्रीन एनर्जी एसोसिएशन

- क. वर्तमान मामले में दो विचाराधीन उत्पाद हैं – (i) मॉड्यूलों अथवा पैनलों में असेंबल न किए गए सोलर सेल और (ii) मॉड्यूलों अथवा पैनलों में असेंबल किए गए सोलर सेल। याचिकाकर्ता दोनों विचाराधीन उत्पादों में घरेलू उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते।
- ख. दोनों विचाराधीन उत्पादों में याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के मानदंड को पूरा नहीं करते क्योंकि याचिकाकर्ताओं की प्रचालनात्मक सुविधा 50 प्रतिशत से कम है।
- ग. प्रचालनात्मक सुविधाओं वाले सेल विनिर्माताओं का उत्पादन वाई-ओ-वाई बढ़ गया है और समग्र उत्पादकता 90 प्रतिशत से अधिक रही है।
- घ. सरकार सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने के लिए उपलब्ध है। इसके लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की गई थी जिसमें समस्या के संधारणीय स्थानीय समाधान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय आमूल-चूल परिवर्तन एवं पुनरुद्धार का प्रावधान किया गया है।
- ङ. भारतीय मॉड्यूल एवं सेल विनिर्माताओं का व्यापार एवं लाभप्रदता बढ़ी है।

(xxii) महिंद्रा ससटेन प्रा. लि.

- क. भारत 2017 में वैश्विक रूप से तीसरा सबसे बड़ा सौर बाजार हो जाएगा। भारत के कई सौर विद्युत विकासकर्ताओं ने तदनुसार 1 गीगावाट से अधिक की परियोजनाओं का निर्माण किया। इससे सेलों और मॉड्यूलों की कीमतों में भारी गिरावट आई है जिससे बाद में भारत 2022 तक 100 गीगावाट सौर विद्युत प्राप्त कर लेगा।
- ख. यह दक्ष एवं कम लागत के सोलर मॉडलों के कारण संभव हुआ है। मॉडलों की कीमतें सौर परियोजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत हैं। चूंकि मॉडल के लेन-देन पूरी तरह बाजार एवं पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करते हैं। अतः कंपनियां केवल इन मानदंडों पर बोली लेती हैं। रक्षोपाय के तहत संरक्षण बोली के समय ध्यान में नहीं रखा गया है, अतः उत्पादों की कीमतें बाद में बढ़ेंगी जिससे प्रशुल्क की दर बढ़ जाएगी।
- ग. इससे भावी परियोजनाएं भी समाप्त हो जाएंगी क्योंकि निवेशक भविष्य में जांच के प्रति ज्यादा एहतियाती होंगे। इससे पूरी श्रृंखला टूट जाएगी और बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
- घ. एक सबसे बड़ा आघात बैंकों/वित्तीय संस्थाओं पर पड़ेगा जिन्होंने सोलर कंपनियों को ऋण दिए हैं। इन बैंकों की गैर-अर्थक्षम सौर परियोजनाओं के कारण अतिरिक्त गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का भाग होगा और नए एनपीए 12000 – 20000 करोड़ रुपए के बीच कहीं भी होने की उम्मीद है।

(xxiii) क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशन्स प्रा. लि.

- क. क्लीन मैक्स ने कर्नाटक में 166 मेगावाट एसी क्षमता, 40 मेगावाट रूफटॉप परियोजनाएं और 24 मेगावाट सोलर क्षमता का विकास भारतीय सौर ऊर्जा सहयोग रूफटॉप आबंटन कार्यक्रमों के तहत करने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया।
- ख. इसने 245 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी ले लिया है। उपर्युक्त मांग को पूरा करने के लिए उसने येस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आरबीएल लिमिटेड, आईडीएफसी और टाटा कैपिटल से विकास करने के लिए आवधिक ऋण लिया है।
- ग. प्रस्तावित शुल्क लगाने से दिवालियापन होगा और संविदागत कीमत वृद्धि के तहत कानूनी दावे भी होंगे।
- घ. कुल 350 करोड़ रुपए की हानि होगी जो कि आकलनों की तुलना में अधिक है। इससे 660 करोड़ रुपए का संभावित एनए बनेगा। 2000 से अधिक लोग अपना रोजगार खो देंगे जिनमें 165 प्रत्यक्ष और शेष आपूर्ति श्रृंखला में होंगे। भारत का व्यापारिक रैंक करने की आसानी भी कम हो जाएगी।

(xxiv) मैसर्स एसीएमई

- क. सोलर सेलों के लिए रक्षा जांच बड़ी जल्दी से शुरू की गई है। डीजीएडी द्वारा पाटन एवं क्षति मार्जिन की जांच तब भी चलती रही जब रक्षा संबंधी जांच शुरू की गई।
- ख. हितवद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणी मांग बिना 70 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क लगाए गए थे। यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो यह संपूर्ण बाजार को विकृत कर देगा। डिस्कॉम सौर विद्युत विकासकर्ताओं से क्रय नहीं करेंगे क्योंकि टैरिफ बढ़ जाएंगे।
- ग. एलडीडीजी द्वारा उल्लिखित अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव आयातों में वृद्धि का कारण नहीं है। आयातों में वृद्धि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को प्रोत्साहित करने के सरकार के दृष्टिकोण के कारण हुई है। भारत सरकार ने यह ध्यान में रखते हुए निविदाएं जारी कीं कि भारतीय विनिर्माता केवल मांग के 10 प्रतिशत से कम ही पूरा कर सकते हैं।
- घ. इसके अतिरिक्त, घरेलू विनिर्माण क्षमता का 70 प्रतिशत सेज क्षेत्र में स्थित हैं, जिनका लक्ष्य मुख्य रूप से निर्यात बाजार है। इसलिए, ऐसे आयात अप्रत्याशित उतार-चढ़ावों का परिणाम नहीं है, इसके बजाए मांग राष्ट्रीय सौर मिशन के कारण सृजित हुई।
- ङ. समान अवधि के लिए घरेलू उद्योग के आंकड़े पाटनरोधी जांच में लाभों को दर्शाते हैं। नवीन सुविधा, मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हानि दर्शाई गई है।
- च. वेबसोल एनर्जी सिस्टम और जुपिटर सोलर विद्युत की उपलब्ध वार्षिक रिपोर्टें दर्शाती हैं कि हानियों अथवा उच्च लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। हेलियोस को हानि का कारण चल रहा निगमित ऋण गठन है।
- छ. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी प्रस्ताव किया है कि प्रौद्योगिकीय सुविधा अप्रचलित है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होगी क्योंकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विद्युत के उत्पादन के 12000 मेगावाट में डीसीआर को शामिल करने की योजना बना रहा है।
- ज. टैरिफ में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होगी और यह प्रति यूनिट 4 रुपए तक पहुँच जाएगी जो सस्ती विद्युत की आपूर्ति के प्रयोजन को समाप्त कर देगा। सभी परियोजनाओं को "विधि में परिवर्तन" खंड के तहत राहत पाने के लिए न्यायालयों में चुनौती दी जाएगी।

(xxv) सोलर पावर डेवलेपर्स एसोसिएशन

- क. सोलर सेलों के लिए रक्षा जांच बड़ी जल्दी से शुरू की गई है। डीजीएडी द्वारा पाटन एवं क्षति मार्जिन की जांच तब भी चलती रही जब रक्षा संबंधी जांच शुरू की गई।
- ख. हितवद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणी मांग बिना 70 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क लगाए गए थे। यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो यह संपूर्ण बाजार को विकृत कर देगा। डिस्कॉम सौर विद्युत विकासकर्ताओं से क्रय नहीं करेंगे क्योंकि टैरिफ बढ़ जाएंगे।
- ग. एलडीडीजी द्वारा उल्लिखित अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव आयातों में वृद्धि का कारण नहीं है। आयातों में वृद्धि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को प्रोत्साहित करने के सरकार के दृष्टिकोण के कारण हुई है। भारत सरकार ने यह ध्यान में रखते हुए निविदाएं जारी कीं कि भारतीय विनिर्माता केवल मांग के 10 प्रतिशत से कम ही पूरा कर सकते हैं।
- घ. इसके अतिरिक्त, घरेलू विनिर्माण क्षमता का 70 प्रतिशत सेज क्षेत्र में स्थित हैं, जिनका लक्ष्य मुख्य रूप से निर्यात बाजार है। इसलिए, ऐसे आयात अप्रत्याशित उतार-चढ़ावों का परिणाम नहीं है, इसके बजाए मांग राष्ट्रीय सौर मिशन के कारण सृजित हुई।
- ङ. समान अवधि के लिए घरेलू उद्योग के आंकड़े पाटनरोधी जांच में लाभों को दर्शाते हैं। नवीन सुविधा, मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हानि दर्शाई गई है।
- च. वेबसोल एनर्जी सिस्टम और जुपिटर सोलर विद्युत की उपलब्ध वार्षिक रिपोर्टें दर्शाती हैं कि हानियों अथवा उच्च लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। हेलियोस को हानि का कारण चल रहा निगमित ऋण गठन है।

- छ. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी प्रस्ताव किया है कि प्रौद्योगिकीय सुविधा अप्रचलित है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होगी क्योंकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विद्युत के उत्पादन के 12000 मेगावाट में डीसीआर को शामिल करने की योजना बना रहा है।
- ज. टैरिफ में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होगी और यह प्रति यूनिट 4 रुपए तक पहुँच जाएगी जो सस्ती विद्युत की आपूर्ति के प्रयोजन को समाप्त कर देगा। सभी परियोजनाओं को "विधि में परिवर्तन" खंड के तहत राहत पाने के लिए न्यायालयों में चुनौती दी जाएगी।

- सोलर पावर डेवलेपर्स एसोसिएशन – सीबीईसी को पत्र

- क. घरेलू पीवी विनिर्माण क्षेत्र अप्रयोज्य प्रौद्योगिकी, भूमि/विद्युत की अधिक लागत, कम क्षमता उपयोग, वित्तपोषण की अधिक लागत और कुशल कार्यबल के अभाव के कारण 100 गीगावाट सोलर मिशन को सहायता देने की स्थिति में नहीं है।
- ख. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत के भीतर पीवी विनिर्माण क्षमता की मूल्य श्रृंखला सृजित करने और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि जैसे अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धी होने के लिए पर्याप्त सहायता हेतु एक संकल्पना के साथ आगे आया।
- ग. निवेशकों ने सरकार की नीतियों पर विश्वास किया और 2018 में सौर विद्युत क्षमता के 1.4 गीगावाट से बढ़ाकर 16 गीगावाट तक कर दी। देश की 80 प्रतिशत मॉड्यूल की आवश्यकता नवीनतम प्रौद्योगिकियों, उच्च दक्षताओं और प्रतिस्पर्द्धी कीमत पर विनिर्मित सोलर सेलों एवं मॉड्यूलों के आयात के माध्यम से पूरी की जाती हैं।
- घ. चूंकि, पाटनरोधी जांच का निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, अतः समानांतर रक्षोपाय जांच करने की कोई बात नहीं है। महानिदेशक, रक्षोपाय ने अनुरोधों की प्रतीक्षा किए बिना ही केवल 17 दिन के भीतर अनंतिम शुल्क लगा लिया है।
- ङ. शुल्क लगाने से देश सिलिकॉन और वेफर्स की लागत तुरंत बढ़ा देंगे जिससे बाद में मॉडलों की कीमतों में वृद्धि होगी।
- च. मॉडलों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं और विकासकर्ता मॉडल को आगे भेजने का कार्य रोककर रखे हुए हैं। कोयला माफिया भी नवीकरणीय क्षेत्र की वृद्धि को रोकने में लगे हुए हैं। वर्तमान घरेलू उत्पादन में राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए सभी कार्य रुक जाएंगे और सरकार तापीय ऊर्जा की ओर जाएगी। इसके परिणामस्वरूप कोयले के आयात में वृद्धि होगी।
- छ. सहायक क्षेत्र में कुल रोजगार सृजन 70 से 90 प्रतिशत है जबकि विनिर्माण क्षेत्र का योगदान केवल 10 से 13 प्रतिशत है। रक्षोपाय शुल्क लगाने से रोजगार सृजन प्रभावित होगा और भारतीय सौर क्षेत्र में निवेश भी रुक जाएगा। इसके अतिरिक्त, इससे कई कानूनी विवाद भी उत्पन्न होंगे।

- सोलर पावर डेवलेपर्स एसोसिएशन – रक्षोपाय महानिदेशक को पत्र

- क. देश का 100 गीगावाट विद्युत सृजन का उद्देश्य है। भारत ने वर्तमान में 12 गीगावाट से कुछ अधिक ही प्राप्त किया है। भारत की विद्युत की मांग घरेलू उत्पादकों से पूरी नहीं की जा सकती।
- ख. हाल ही में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रभावित हुआ है और 50 हजार से अधिक रोजगार विलंब से सृजित किए गए हैं। किसी भी शुल्क से इन परियोजनाओं की वित्तीय अर्थक्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी और बैंक के ऋण एनपीए हो जाएंगे।
- ग. चूंकि, पाटनरोधी जांच का निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, अतः समानांतर रक्षोपाय जांच करने की कोई बात नहीं है। महानिदेशक, रक्षोपाय ने केवल 17 दिन के भीतर अनंतिम शुल्क लगा लिया है।

(xxvi) आदित्य बिरला रिन्यूबल्स लिमिटेड

- क. सरकार डीसीआर श्रेणी के तहत निविदाओं के माध्यम से घरेलू सेल विनिर्माताओं को संरक्षण दे रही है।
- ख. भारत में पॉली-सिलिकॉन और वेफर विनिर्माण क्षमता नहीं है तथा दोनों मदों की कीमतें वैश्विक बाजार में पूरी तरह परिवर्तनशील हैं। ये सभी लागत से अधिक मॉडल पर काम करती हैं जो प्रशुल्क के आकलनों को नीलामियों में अत्यधिक चुनौतीपूर्ण बोली बना देते हैं। भारत में एकाधिकारिक स्थिति इन बोलियों को लेने में सक्षम नहीं होगी।
- ग. वर्तमान कीमत प्रतिस्पर्द्धी है क्योंकि उनका पूरी मूल्य श्रृंखला पर नियंत्रण है। विदेशी विनिर्माताओं को किफायत, कम ब्याज दर, कम विद्युत लागत, उच्च उत्पादकता, सामान्य बहिर्प्रवाह शोधन संयंत्र, मशीनरी में शामिल पूरी कार्य प्रणाली, सौर निर्माण के लिए कच्ची सामग्री तथा संचारिकी अवसंरचना के लाभ हैं। इन सबसे लागतों में कमी आती है।
- घ. रक्षोपाय शुल्क लगाने से विद्युत प्रशुल्क बढ़ जाएगा और उपभोक्ताओं को विद्युत प्रशुल्क देना होगा।

(xxvii) फर्स्ट सोलर इंक.

- क. थिन फिल्म प्रोडक्ट्स और सी-एसआई पीवी उत्पाद समान वस्तु अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धी उत्पाद नहीं है क्योंकि भौतिक एवं तकनीकी गुणधर्मों, उत्पादन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, संयंत्र एवं उपस्करों, कच्ची सामग्री, प्रणाली के

- संतुलन (बीओएस) में अंतर, लागत एवं कीमतों में भारी अंतर है। बीओएस के बिना दोनों उत्पाद दो विकल्प हैं और वे समान उत्पाद नहीं हो सकते।
- ख. बीओएस थिन फिल्म और सी-एसआई पीवी के लिए भिन्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जांच परिणाम में यह दिया गया है कि थिन फिल्म और क्रिस्टलीन मॉडल भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं।
- ग. अनरॉट एल्यूमीनियम के आधार पर फर्स्ट सोलर का अनुरोध है कि ऐसी एसईजेड यूनिटों को घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता। एसईजेड यूनिट भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में मानी जाती है और उसमें सभी उत्पाद भारत से बाहर उत्पादित माने जाते हैं।
- घ. इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के मामले में जांच परिणाम पर विश्वास किया जाता है और यह उल्लेख किया गया था कि ये एसईजेड यूनिटें अन्य घरेलू यूनिटों के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर रही हैं। अतः उसे घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता।
- ङ. याचिकाकर्ताओं का भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात नहीं है क्योंकि वह उत्पादन 25 प्रतिशत से कम है। मॉड्यूल बनाने के लिए प्रयुक्त आयातित सेल घरेलू उद्योग में शामिल नहीं किए जाने चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने वस्तुपरक तरीके से भारतीय उत्पादन की मात्रा नहीं बताई है।
- च. यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता 50 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन करते हैं, महानिदेशक, रक्षोपाय को घरेलू उद्योग निर्धारित करना है, जो कि वर्तमान मामले में नहीं हुआ और महानिदेशक, रक्षोपाय ने बिना किसी साक्ष्य के याचिकाकर्ताओं के दावे को स्वीकार किया।
- छ. सेलों का आयात शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह कच्ची सामग्री का आयात है। मॉड्यूलों के उत्पादन के लिए भारत में सेलों के आयात को आयातों से अलग किया जाना चाहिए। यह उद्घाल सी-एसआई पीवी के कारण है न कि थिन फिल्म के कारण।
- ज. जांच की शुरुआत में दर्शाई गई कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई है। भारत सरकार ने देश में सौर विद्युत के विकास के लिए योजना बनाई है। व्यापार उपाय भी हाल के नहीं हैं, और इसीलिए उन्हें अप्रत्याशित घटनाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता।
- झ. घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है। बिक्री और उत्पादन में इस अवधि में काफी वृद्धि हुई है। उत्पादकता और क्षमता उपयोग में अत्यधिक सुधार हुआ है।
- ञ. जांच की शुरुआत की सूचना में वस्तुपरकता का अभाव है क्योंकि घरेलू उद्योग को दो भागों में अलग करने के बाद कुछ मानदंड हैं, जबकि कुछ मानदंड नहीं रहे।
- ट. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत बाजार हिस्सा गलत दर्शाया गया है, क्योंकि उसमें अन्य पक्षकारों द्वारा मॉडलों का उत्पादन शामिल नहीं किया गया है, जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा उनके अपने दावे के अनुसार हाल की अवधि में बढ़ा।
- ठ. क्षमता उपयोग नए उत्पादक को जोड़ने के कारण कम हुआ है। रोजगार में काफी वृद्धि हुई है।
- ड. उत्पादों के निर्यात में काफी गिरावट आई है, परिणामस्वरूप उत्पादन लागत काफी बढ़ी है। याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित प्रति यूनिट लागत घरेलू एवं निर्यात बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा की गई वास्तविक बिक्री पर आधारित है। निर्यात निष्पादन वास्तविक रूप से कम हुआ है। इस प्रकार, घरेलू एवं निर्यात बाजार दोनों में ह्रास हुआ है।

(xxviii) हर्षा अबाकुस सोलर

- क. निर्माणाधीन परियोजनाओं पर शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि मॉडलों के लिए आदेश दिए गए हैं अथवा अभी दिए जाने हैं अथवा संचारिकी में हैं।

15. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोधों का संक्षिप्त सार निम्नलिखित है:

(i) यूरोपीय आयोग

- क. एसजीडी घटक का प्रयोग वर्तमान मामले के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह असाधारण मामलों के लिए प्रतिबंधित है क्योंकि वे सभी स्रोतों से आयातों पर लागू होते हैं। आयात मुख्य रूप से चीन से बढ़े हैं जो आयात मात्रा का 94 प्रतिशत और आयात मूल्य का 95 प्रतिशत है जबकि कम मात्रा में आयात अन्य देशों से हैं।
- ख. एक देश से ही आयातों में वृद्धि वैश्विक सुरक्षा उपाय लगाने का औचित्य बनाने के लिए काफी नहीं है। ऐसे व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय का प्रयोग चीन से आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच का निर्धारण किए जाने तक आस्थगित किया जाना चाहिए।
- ग. रक्षोपायों का प्रयोग उन देशों सहित सभी स्रोतों से आयातों को प्रभावित करेगा जिनका कुल आयात मूल्य 5 प्रतिशत से कम है जो घरेलू उद्योग को क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते।
- घ. जीएटीडी का अनुच्छेद XIX उन मामलों में रक्षोपाय शुल्क के उपायों का प्रयोग करने की अनुमति देता है जहां आयात अप्रत्याशित घटनाओं के परिणामस्वरूप बढ़ें।
- ङ. वर्ष 2012 और 2013 में अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा व्यापार सुधार उपाय मानी गई अवधि से काफी पूर्व लगाए गए थे।

- च. डब्ल्यूटीओ के अनुरूप न होने के बाद 2013 के डब्ल्यूटीओ नियम के रूप में घरेलू मात्रा की आवश्यकता को रद्द करना जीएटीडी के अनुच्छेद XIX के तहत निर्धारित किए गए अनुसार अप्रत्याशित घटनाओं का भार नहीं हो सकता, जैसा कि वह चार वर्ष पूर्व हुआ।
- छ. आयात बढ़ी हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बढ़ें क्योंकि घरेलू उद्योग पेरिस करार के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के बाद मांग में उछाल को पूरा करने में असमर्थ था।
- ज. कोई कारणात्मक संपर्क स्थापित नहीं किया गया है क्योंकि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के आरंभ में अर्थात् आयात बढ़ने से पूर्व से ही पहले ही हानियों का सामना कर रहा था; जबकि कुल बिक्री और उत्पादन जैसे प्रमुख संकेतक बढ़ रहे थे।
- झ. सुरक्षा संबंधी करार के अनुच्छेद 4.2(क) के तहत निर्धारित अन्य कारकों का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।
- ञ. हानि उठा रहे घरेलू उद्योग ने 22 प्रतिशत क्षमता, जो पहले ही अनुपयुक्त पड़ी है, का उपयोग करने की बजाए अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश किए हैं। परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग में गिरावट से यह सिद्ध हुआ है कि वह एक उपयुक्त व्यापारिक निर्णय नहीं था और घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है।
- ट. घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में काफी गिरावट आई है जिससे समग्र लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। नकारात्मक निर्यात निष्पादन के लिए अदक्षताओं और अन्य कारणों की पहचान बड़े हुए आयातों के कारण होने से पूर्व की जानी चाहिए।
- ठ. आयातों ने हमेशा यह बताते हुए घरेलू सौर बाजार के महत्वपूर्ण हिस्से को बनाए रखा है कि घरेलू उद्योग घरेलू मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं रहा है।
- ड. रक्षोपाय शुल्क के उपाय लगाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध है क्योंकि अंतिम रूप से बढ़ी हुई कीमत उत्पाद विकल्प को प्रतिबंधित करती है और उसे पूरा करने के लिए बढ़ी हुई मांग और घरेलू उद्योग की असमर्थता के आलोक में भारी कमियां आती हैं और वह पेरिस करार के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

(ii) भारत में चीन जन. गण. का दूतावास

- क. चीनी आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच किसी क्षति अथवा पाटन के अभाव में संभवतः 23 मार्च को रद्द की गई थी और अंतिम जांच परिणाम घरेलू उद्योग के अनुकूल नहीं होंगे। रक्षोपायों में सख्त शब्दों की आवश्यकता है और यदि पाटनरोधी जांच में कोई क्षति निर्धारित नहीं की गई तो फिर उससे कोई गंभीर क्षति अथवा खतरा नहीं हो सकता। अतः यह जांच किसी उपाय के बिना रद्द की जानी चाहिए।
- ख. आयातों के 80 प्रतिशत से आधा, जो प्राप्त किए जाने के लिए 100 गीगावाट कुल सोलर संस्थापन क्षमता है, चीन से आने का विश्वास किया जाता है। अतः रक्षोपाय लगाने से भारत की विद्युत उत्पादन लागत बढ़ सकती है और परिणामस्वरूप भारत का अवसंरचना निर्माण तथा अर्थव्यवस्था का विकास बढ़ सकता है।
- ग. जांच डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुसार उचित एवं वस्तुपरक तरीके से की जानी चाहिए। रक्षोपाय घरेलू उद्योग को अधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए एक ताकतवर हथियार है और वह भारत के सोलर फोटो वोल्टेक उद्योग के विकास के लिए अहितकर है।
- घ. चीन से भारत में आयात उचित एवं सामान्य शर्तों पर किए जाते हैं और घरेलू उद्योग को इससे कोई भारी क्षति अथवा खतरा नहीं हुआ है। चीनी उत्पादकों ने भारतीय कंपनियों के साथ अच्छी व्यापारिक प्रतिभागिता बनाए रखी है और निवेश, प्रौद्योगिकी अंतरण आदि के पहलुओं में भारत की संगत संस्थाओं के साथ प्रभावी सहयोग विकसित किया है। चीन और भारत के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोगी व्यापारिक अवसरों का सहयोग करने के लिए भारी संभावना है।

(iii) मैसर्स वारी एनर्जीस लि.

- क. पूर्व वित्तीय वर्ष में भारत में संस्थापित अनुमानित 10.7 गीगावाट मॉड्यूलों के 90 प्रतिशत के करीब चीनी मॉड्यूलों का प्रयोग करके लगभग सभी प्रमुख यूटिलिटी पैमाने की संस्थापनाओं के साथ विदेशी मॉडल विनिर्माताओं ने ले लिया था। यह बहु वीएनईएफ टियर-1 घरेलू विनिर्माताओं और पर्याप्त घरेलू क्षमता से अधिक के बावजूद संभव हुआ है।
- ख. चीनी मॉड्यूलों के लिए प्रमुख बाजारों में पाटनरोधी प्रतिबंध लगाए हैं और परिणामी बड़े हुए आयात घरेलू विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि का गला घोट रहे हैं।
- ग. उससे पूर्व की कीमतें बने रहने और मौजूदा बाजार शेयर बढ़ते रहने के संकेत हैं, जैसा कि एक उदाहरण में दर्शाया गया है जिसमें चीनी मॉड्यूल की कीमतें किसी भी प्रौद्योगिकीय सूचना अथवा परिवर्तनों के बिना तीन सप्ताह की अवधि में 21 प्रतिशत से अधिक नीचे गई है।

(iv) मैसर्स फर्स्ट सोलर इंक., फर्स्ट सोलर एफई होल्डिंग पीटीई. लि. और फर्स्ट सोलर मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.

- क. याचिकाकर्ता ने मंच खरीदारी की है, जैसा कि 05 जनवरी, 2018 को 70 प्रतिशत अंतिम एसजेवी लगाए जाने के बाद 27 फरवरी, 2018 को पाटनरोधी शुल्क लागू होने की वापसी से सिद्ध है। याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी शुल्क लागू होने को वापस लिया क्योंकि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन इतने अधिक शुल्क के लिए काफी अधिक नहीं हुए होते।

- ख. वस्तुएं तकनीकी गुणधर्म, उत्पादन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, संयंत्र एवं उपस्कर, कच्ची सामग्री, प्रणाली के संतुलन के बाद बीओएस में अंतर, लागत एवं कीमतों के आधार पर समान/प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धी नहीं है। थिन फिल्म उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल करने के पीछे एकमात्र तर्क यह प्रतीत होता है कि उनका प्रयोग समान प्रयोजन के लिए किया जाता है।
- ग. बीओएस में काफी निवेश एसी स्वरूप में बिजली को बदलने के लिए अपेक्षित था जो कि प्रयोज्य हो। थिन फिल्म और सी-एसआई सेलों के लिए प्रणालियों की लागत में कुल परियोजना लागत का 45-50 प्रतिशत होता है और वे काफी भिन्न होते हैं।
- घ. बीओएस में एकीकरण के बिना न तो सेल प्रयोज्य बिजली बना सकते हैं और इससे वे समान/प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धी उत्पाद के बजाए दो विकल्प बन जाते हैं। बीओएस थिन फिल्म उत्पादों और सी-एसआई पीवी उत्पादों के संबंध में पूरी तरह से अलग लागत संरचना में भिन्न हैं।
- ङ. याचिकाकर्ता ने यह विश्वास करने में प्राधिकारी को भ्रमित किया है कि उपभोक्ताओं ने थिन फिल्म उत्पादों और सी-एसआई सेलों तथा मॉडलों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया है। यद्यपि, उत्पादों के प्रयोग उपभोक्ताओं ने दोनों प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके संयंत्रों का संस्थापना की है। तथापि, यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि इन उपभोक्ताओं ने समान सी-एसआई फोटो वोल्टेक संयंत्र में थिन फिल्म उत्पादों और उसके बीओएस का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया है।
- च. जब कोई विकासकर्ता दो प्रौद्योगिकियों में से एक को चुन लेता है और परियोजना का कार्यान्वयन शुरू कर देता है तो विकासकर्ता दूसरी किस्म की प्रौद्योगिकी में जाने की स्थिति में नहीं होता है।
- छ. थिन फिल्म उत्पादों और सी-एसआई का प्रयोग समान प्रयोजन के लिए किया जाता है, यह कारण उन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के भीतर शामिल करने के लिए औचित्य नहीं बनाता। अन्य कई उत्पाद ऐसे भी हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और यदि वर्तमान में लागू कोई मानदंड उन्हें मानने के लिए अपनाया जाता है तो अन्य कई ऐसे उत्पाद भी हैं जो विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हो जाएंगे।
- ज. संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ में जांचकर्ता प्राधिकारियों ने निर्धारित किया कि सी-एसआई और थिन फिल्म उत्पाद की सीमित परस्पर परिवर्तनीयता है तथा दोनों उत्पाद पाटनरोधी शुल्क, एसजीवी और सीवीडी जांचों में जांच परिणामों के संदर्भ में समान नहीं हैं।
- झ. संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ में की गई जांचों में घरेलू उद्योग के उत्पादक दोनों उत्पादों का उत्पादन कर रहे थे, परंतु फिर भी जांचकर्ता प्राधिकारियों ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि थिन फिल्म उत्पाद और सी-एसआई उत्पाद अपनी प्रकृति और विशेषताओं में अत्यधिक भिन्न हैं तथा उन्हें एक जांच में नहीं मिलाया जा सकता।
- ञ. वर्तमान जांच एक भिन्न जांच है जिसका पूर्व पाटनरोधी शुल्क जांच से कोई संबंध नहीं है जहां शुल्क भारत सरकार द्वारा भी नहीं लगाया गया था। जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र कुछ पाटनरोधी शुल्क जांचों में बदल गया है, यथा – अमोनियम नाइट्रेट के रूप में विचाराधीन उत्पाद, विभिन्न जांचों के बीच भिन्न हो गया। अतः पूर्व पाटनरोधी शुल्क जांच में जब विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र बाद की जांच में बाध्यकारी नहीं माना गया था तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि संबद्ध सामानों की पूर्व पाटनरोधी शुल्क जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वर्तमान रक्षोपाय जांच पर बाध्यकारी है।
- ट. इसी प्रकार, समान उत्पाद के लिए पाटनरोधी शुल्क जांचों और एसजीवी जांचों के बीच विचाराधीन उत्पाद बदल गया, जैसे पाटनरोधी शुल्क जांच के तहत कास्टिक सोडा और एसजीवी जांचों के क्षेत्र के मामले में बदला है।
- ठ. चूंकि, याचिकाकर्ता उत्पादकों में से कोई भी उत्पादक अथवा संबद्ध सामानों का कोई भी अन्य घरेलू उत्पादक थिन फिल्म उत्पादों का उत्पादन और बिक्री नहीं कर रहा है तथा रक्षोपाय शुल्क के लिए उनका दावा इस निमित्त रखे जाने योग्य नहीं है।
- ड. तीन उत्पादक एसईजेड यूनिट हैं जिनका उद्देश्य निर्यात संवर्धन आदि है। डीटीए ने बिक्री के लिए सुविधा निर्यात बाजारों की अविस्तृता से निकलने के लिए दी गई छूट है। तथापि, डीटीए में इस प्रकार की बिक्री पर सीमा शुल्क लगता है। जब इन यूनिटों द्वारा घरेलू बाजार में बिक्री पर उदारता के रूप में छूट दी जाती है तो उन्हें घरेलू उद्योग के रूप में संरक्षण की मांग करने के लिए उन्हें हकदार बनाने हेतु उन यूनिटों द्वारा अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य के आधार पर कि उनकी आपूर्तियों पर डीटीए में सीमा शुल्क लग रहे हैं, यह माना जाता है कि वे घरेलू विनिर्माताओं के बराबर नहीं हैं।
- ढ. महानिदेशक की पूर्व जांचों में माना गया है कि एसईजेड यूनिटें घरेलू उद्योग का भाग नहीं हैं। "भारत में इलैक्ट्रिकल इंसुलेटरों के आयात संबंधी रक्षोपाय जांच" का संदर्भ दिया गया है जिसमें महानिदेशक, रक्षोपाय ने कानून के सिद्धांत पर स्पष्ट जांच परिणाम दिए कि एसईजेड के तहत प्रचालन करने वाली यूनिट को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जा सकता। इन जांच परिणामों ने अंतिम रूप ले लिया है और इसके विपरीत किसी न्यायिक निर्णय द्वारा नकारी नहीं गई हैं।

- ण. "भारत में अनरॉड एल्युमीनियम (अलॉय हील एल्युमीनियम और एल्युमीनियम अलॉय) के आयात संबंधी रक्षोपाय जांच" का संदर्भ दिया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व जांच परिणाम पैरा 25 और 26 से उद्धृत जांच परिणाम यह दर्शाते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एसईजेड के घरेलू उद्योग के भाग न होने के संदर्भ में कानून के सिद्धांत पर जांच परिणाम दिए हैं तथा उनका अनुपालन किया जाना चाहिए क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी एक अर्ध न्यायिक निकाय हैं और उन्हें निर्णय करने की प्रक्रिया में एकरूपता बनानी चाहिए।
- त. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) के अनुसार, घरेलू उद्योग बनाने की दोनों आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है।
- थ. याचिकाकर्ता उत्पादकों की भिन्न सूची को घरेलू उद्योग बनाने के रूप में दावा करने से रुक गया है जब 25 अन्य उत्पादकों (विक्रम सोलर एवर ग्रीन सोलर सिस्टम आदि सहित) ने खुद याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पाटनरोधी शुल्क आवेदन पत्र में उल्लेख पाया कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को वर्तमान आवेदन से हटा दिया गया है।
- द. याचिकाकर्ता इन उत्पादकों की संख्या के रूप में साथ-साथ नहीं आए हैं जो वस्तुतः एसोसिएशन के सदस्य हैं और उनके बारे में आवेदन में प्रकट नहीं किया है। यह मानना चाहिए कि एसोसिएशन की सदस्य संबद्ध सामानों के विनिर्माता हैं और यह कि इन सदस्यों को याचिकाकर्ता की अच्छी जानकारी थी। इस प्रकार, तथ्यों को गंभीर रूप से दबाया गया है जिसको माफ नहीं किया जाना चाहिए।
- ध. उन उत्पादकों, जो आयात करते हैं, को घरेलू उद्योग की परिभाषा से हटाने के लिए 8(ख) के तहत तदनुसारी पात्रता के अभाव में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) की अपेक्षा के अनुसार घरेलू उद्योग का हिस्सा तदनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।
- न. आयातित सोलर सेलों में से माँड्यूलों का उत्पादन करने वाले विनिर्माताओं का उत्पादन घरेलू उद्योग के भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और घरेलू उद्योग का उत्पादन हिस्सा उसके बाद परिकलित किया जाना चाहिए। यह निर्धारण दर्शाएगा कि याचिकाकर्ताओं का घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात नहीं है और तदनुसार, अधिनियम की धारा 8(ख) के तहत वे घरेलू उद्योग नहीं हैं।
- प. आयातों में वृद्धि को दूसरे कारकों से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए आयात बढ़े। विचाराधीन उत्पाद के लिए 9000 मेगावाट तक मांग में वृद्धि हुई, परंतु घरेलू उद्योग की क्षमता में तदनुसारी वृद्धि केवल 1200 मेगावाट थी। एमएसवीपीएल ने मई, 2017 में ही उत्पादन शुरू किया, और तत्काल उत्पादन का अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं कर पाया। भारतीय उद्योग बढ़ी हुई मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं था।
- फ. आयातों के बाजार हिस्से में संबंधित वृद्धि परिस्थितियों को देखते हुए 4 प्रतिशत की दर पर काफी नहीं है। उत्पादन के अनुपात में आयात बढ़े हैं क्योंकि उत्पादकों की क्षमताएं एसईजेड/ईओयू यूनिटें होने का नाते निर्यात बाजारों को सेवा देने के लिए स्थापित हुई हैं। याचिकाकर्ताओं के उत्पादन का निर्यात घटने के कारण न्यूनीकरण हुआ है। उत्पादन में वृद्धि, मांग में वृद्धि के अनुपात में नहीं है।
- ब. आयातों के बाजार हिस्से में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाया है क्योंकि घरेलू मांग में कई घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू मांग पूरी नहीं की जा रही थी। याचिकाकर्ताओं के पास एमएसवीपीएल की स्थापना से पूर्व घरेलू मांग की केवल 109 प्रतिशत क्षमता थी। घरेलू उद्योग का हिस्सा भी 3 प्रतिशत तक बढ़ा।
- भ. याचिकाकर्ताओं को क्षति नहीं हो रही है क्योंकि मात्रात्मक मानदंड अपवादात्मक निष्पादन दर्शा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की क्षमता, उत्पादन और बिक्री में क्षति की अवधि में काफी वृद्धि दर्शाई है। बिक्री चौगुनी हो गई है। एक नया उद्योग होने के बावजूद प्रतिभागी उत्पादकों ने इस अवधि के आरंभ की अपेक्षा चार गुना वृद्धि करके क्षमता में वृद्धि के अनुरूप अपनी घरेलू बिक्री बढ़ाने की व्यवस्था की है।
- म. जुपिटर सोलर को अपवाद मानते हुए सभी याचिकाकर्ता एसईजेड/ईओयू यूनिटें हैं। उनका प्रमुख जोर निर्यात बाजारों पर है। क्षमता उपयोग में गिरावट उत्पादकों की निर्यात बिक्री में कमी के कारण हुई है न कि घरेलू बाजार में उनके निष्पादन के कारण।
- य. एमएसवीपीएल ने हाल में प्रचालन आरंभ किए और याचिकाकर्ता उत्पादकों की क्षमता का एक प्रमुख भाग है जबकि समग्र कम क्षमता उपयोग दर्शाते हुए प्रत्याशित क्षमता उपयोग तक नहीं पहुँच पाए हैं जो कि स्थिति नहीं हो सकती।
- कक. प्रति कर्मचारी उत्पादकता के संबंध में आंकड़े एमएसवीपीएल के प्रवेश के कारण अनुचित रूप से बिगाड़े गए हैं जो कि उत्पादन के आरंभिक चरण में है।
- खख. याचिकाकर्ताओं को आयातों में वृद्धि से पहले भी हानियां होती रही हैं, अतः क्षति आयातों में अचानक वृद्धि के कारण नहीं है। याचिकाकर्ताओं को आधार वर्ष 2014-15 के दौरान भी हानियां हुई हैं जब आयातों की मात्रा कम थी। याचिकाकर्ता ने 2017-18 के संबंध में बढ़े हुए आयातों के कारण हानियों का दावा किया है। तथापि, उस वर्ष के दौरान हानियां आधार वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत कम हैं और 2015-16 की तुलना में 65 प्रतिशत कम हैं।

- गग. कम निर्यात निष्पादन के परिणामस्वरूप रोजगार में गिरावट एक संकेतक क्षति के लिए कारक नहीं माना जा सकता।
- घघ. कुछ आधारों पर एमएसवीपीएल को शामिल करने के संबंध में क्षति विश्लेषण के लिए आंकड़ों का चुनिंदा विश्लेषण किया गया है जिसमें वह याचिकाकर्ताओं के मामले में मदद करता है।
- ङङ. याचिकाकर्ता की सूचीबद्ध कंपनियां हैं जिन्होंने आयातों के परिणामस्वरूप प्रचालन बंद कर दिए थे। जब वस्तुतः वे एसईजेड यूनिटें थीं, जिनको कमजोर निर्यात निष्पादन के कारण हानि हुई।
- चच. याचिकाकर्ता ने भारित औसत कीमत कटौती नहीं दी है। यहां तक कि यदि कीमत कटौती सकारात्मक है तो उस पर कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा है। थिन फिल्म उत्पादों के लिए कोई कीमत कटौती परिकल्पित नहीं की गई है।
- छछ. बिक्री कीमत तथा लागत दोनों में आनुपातिक रूप से कमी आई है, प्रत्येक में जांच की अवधि के दौरान 16 सूचकांक तक गिरावट आई है। याचिकाकर्ता कीमत न्यूनीकरण का दावा नहीं कर सकते।
- जज. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में गिरावट माँझूलों की बढ़ी हुई दक्षता के कारण ही है जो 260 वाट की अधिकता से 330 वाट तक बढ़ी है; किफायतों का लाभ एवं सृजन पॉलीसिलिकन, वेफर और इंगट उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला में लिया गया है; प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में एकीकृत विनिर्माण क्षमताओं का सृजन और उसके बाद क्षमता उपयोग में सुधार तथा समग्र विनिर्माण लागत सीधे एकीकरण द्वारा लाई गई; और पीईआरसी जैसी नई प्रक्रियाओं को शामिल किया गया जो आगे दक्षता में सुधार लाते हैं जिनके कारण प्रति वाट कम लागत हासिल की जा सकती है।
- झझ. मालसूची में वृद्धि के कारण क्षति बढ़ी हुई घरेलू बिक्री के आलोक में मंद पड़ जाती है।
- ञञ. एसईजेड यूनिट/ईओयू न होने वाले एकमात्र उत्पादक जुपिटर्स सोलर का पूरा राजस्व सोलर सेलों की बिक्री से आया है और उसने लाभ कमाया। एसईजेड यूनिट/ईओयू होने वाले हानि उत्पादकों को कम निर्यात निष्पादन के कारण हानि हुई।
- टट. यद्यपि, निर्यात निष्पादन में वास्तविक रूप से गिरावट आई है, तथापि, उत्पादकों की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। वैश्विक घटोत्तरी के कारण क्षमता उपयोग के संबंध में निष्पादन प्रतिकूल रहा है। अतः यद्यपि, घरेलू बिक्री 304 प्रतिशत तक बढ़ी है, तथापि, निर्यात बिक्री 87 प्रतिशत तक घटी है।
- ठठ. इंडो सोलर की वार्षिक रिपोर्टों से उद्धरण यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उन्हें कमजोर निर्यात निष्पादन के कारण हानि हुई है।
- डड. कम लागत के वित्तपोषण में पहुँच का अभाव, अपर्याप्त अवसंरचना, कच्ची सामग्री का अभाव आदि जैसे कई कारक, जिनका आयात से कोई संबंध नहीं है, कमजोर निर्यात को निष्पादित कर रहे हैं।
- ढढ. वार्षिक विवरण में दर्शाए गए अनुसार हेलियोस और मोजर वेयर के संबंध में कमजोर निष्पादन के लिए प्रमुख कारण परिसमापन की कठिनाइयाँ हैं।
- णण. याचिकाकर्ता किसी पिछड़े एकीकरण के बिना कम मूल्यवर्धन में लगे हुए हैं। परिणामस्वरूप यदि एसजेवी लगाया भी जाए तो भी उद्योग गैर-प्रतिस्पर्द्धी रहेगा।
- तत. 2017-18 के दौरान क्षमता अभिवृद्धि में एमएनआरई द्वारा संशोधित लक्ष्यों के अनुसरण में भारी उछाल देखा गया, फिर बिक्री तथा आयात में वृद्धि कैसे हुई।
- थथ. रक्षोपाय कानूनों के तहत क्षति मार्जिन का मतलब वही है जो पाटनरोधी कानून के तहत है तथा एनआईपी के निर्धारण की अपेक्षा है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही एनआईपी के निर्धारण के लिए समान सिद्धांत लागू किए थे जो कि 2011 में दिए जाने से पूर्व थे।
- दद. रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए विशेष रूप से एनआईपी का निर्धारण किया गया क्योंकि उपचार प्रकृति में संरक्षण वाले हैं और शुल्क निर्यातकों के अनुचित कीमत व्यवहार को दबाने के लिए नहीं लगाया जाता है।
- धध. जीएटीटी और आईटीए पर हस्ताक्षर करना अप्रत्याशित घटनाएं नहीं हैं।
- नन. कोई ठोस समायोजन योजना नहीं दी गई है कि उत्पादक कैसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन रहे हैं। इस संबंध में पूर्णतः कोई मात्रा नहीं है कि क्या उपाय किए जाएंगे और उससे क्या लागत लाभ हासिल किए जाएंगे।
- पप. घरेलू उत्पादकों द्वारा किसी पिछड़े एकीकरण का प्रयास नहीं किया गया, जबकि घरेलू मात्रात्मक अपेक्षाओं के रूप में संरक्षण लागू था। यहां तक कि यदि ये कदम उठाए जाते तो उसे वास्तविक रूप देने के लिए वर्षों लग जाते और सरकार द्वारा निर्धारित स्वच्छ ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जाते।

पक्षकारों द्वारा अतिरिक्त अनुरोध

- फफ. याचिकाकर्ताओं के इन अनुरोधों के आलोक में कि सेल और मॉड्यूल अलग-अलग उत्पाद हैं, याचिकाकर्ताओं के मामले का कोई आधार नहीं है कि मॉड्यूल विनिर्माताओं को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में न माना जाए। प्राधिकारी को सेलों और मॉड्यूलों की अलग-अलग जांच करनी चाहिए।
- बब. याचिकाकर्ताओं का अधिक जोर इस पर रहा है कि घरेलू उत्पादक कैसे समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धी उत्पादों का उत्पादन करते हैं। याचिकाकर्ता अब इन मदों के भिन्न उत्पादों के रूप में शामिल करने की मांग करते हैं। तथापि, यह बात याचिका में नहीं दी गई है और अब याचिकाकर्ता दावा नहीं कर सकते कि वे एक वस्तु हैं।
- भभ. थिन फिल्म को शामिल करने के समर्थन के लिए कनाडियन प्राधिकारी के निर्णय पर याचिकाकर्ताओं का विश्वास गलत रखा गया है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने थिन फिल्म को घरेलू उत्पादन के बावजूद शामिल न करने का निर्णय लिया और जांचकर्ता प्राधिकारियों ने स्पष्ट रूप से माना कि थिन फिल्म उत्पाद सी-एसआई उत्पादों से भिन्न हैं।
- मम. महानिदेशक के पूर्व जांच परिणाम पर याचिकाकर्ता का विश्वास गलत रखा गया है क्योंकि उस जांच परिणाम के अनुसरण में शुल्क मंत्रालय द्वारा नहीं लगाया गया था और परिणामस्वरूप इस निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाना नहीं कहा जा सकता।
- यय. मॉड्यूल विनिर्माताओं को जांच के क्षेत्र से अलग नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं को निर्देश देने चाहिए कि वे उन विनिर्माताओं की सूची का ब्यौरा दें जो केवल मॉड्यूल का उत्पादन कर रहे हैं। एसईजेड यूनितों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जा सकता क्योंकि केवल यह तथ्य कि कंपनी विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक हो सकती है, यह मानने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है कि वह कंपनी घरेलू उद्योग का भाग है क्योंकि एसईजेड ने यह मान्य धारणा बनाई है कि ये कंपनियां विदेशी कंपनियां मानी जाएंगी।
- ककक. आयातों में उछाल के संदर्भ में अप्रत्याशित घटनाओं को देखा जाना चाहिए और घरेलू उद्योग को उस अवधि की पहचान करने की अपेक्षा है जब आयातों में उछाल आया और तदनुसार, अप्रत्याशित परिस्थितियों की पहचान करने की आवश्यकता है। जांच की अवधि अप्रैल, 2016 से सितंबर, 2017 निर्धारित होने पर अप्रत्याशित घटनाएं उस अवधि से संबंधित होनी चाहिए और ऐसी अवधि से पूर्व नहीं जो कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पहचानी जाए।
- खखख. याचिकाकर्ता ने एक सामान्य कारण से सितंबर, 2017 से आंकड़ों को अद्यतन नहीं किया है कि वे अद्यतन आंकड़े यह नहीं दर्शाएंगे कि उद्योग को निरंतर भारी क्षति हो रही है।
- गगग. पाटनरोधी जांचों में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाया कि क्षति मार्जिन नगण्य थे। ऐसी स्थिति में कीमतों में गिरावट रक्षोपाय उपचारों की आवश्यकता की स्थिति का संकेतक नहीं हो सकती।
- घघघ. चीन के निर्यात तीसरे देशों से बदलकर भारत में आना एक कारण नहीं है। कारण तो एक प्रभाव है और अप्रत्याशित घटनाओं को आयातों में उछाल के लिए कारण होना अपेक्षित है।
- ङङङ. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि यदि याचिकाकर्ता घरेलू मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं है तो प्राधिकारी रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाएंगे।
- चचच. रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव सौर विद्युत के विशिष्ट मामले में ही देखा जाना चाहिए न कि विद्युत के अन्य स्रोतों के मामले में। सौर विद्युत उत्पादन के एक पैसे की वृद्धि भी काफी वृद्धि होती है। मॉड्यूल की लागत का काफी अनुपात सोलर सेल होने के नाते आधारभूत कच्ची सामग्री के आधार पर ही है। अतः प्रस्तावित एसजीडी विदेशी मुद्रा को नहीं बचाएगा।
- छछछ. याचिकाकर्ता ने एक ओर यह समझाया है कि क्षति मार्जिन नकारात्मक अथवा कम था, जबकि दूसरी ओर यह तर्क दिया है कि उनके लिए 70 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क अपर्याप्त है। अतः यह सिद्ध है कि याचिकाकर्ता ने पूरी तरह से भ्रामक और गलत दावे किए हैं।

(v) मैसर्स पेनासोनिक एनर्जी मलेशिया एसडीएन, बीएचडी (पीईसीएमवाई)

- क. पीईसीएमवाई द्वारा निर्यातित उत्पाद संबद्ध सामानों से भिन्न हैं और उन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटाया जाना चाहिए।
- ख. सोलर सेलों और मॉड्यूलों को एक-दूसरे के "समान" नहीं माना जा सकता क्योंकि सोलर सेल और मॉड्यूल दोनों की लागत और कीमतें भिन्न हैं, अतः वे अलग-अलग उत्पाद हैं।
- ग. सिलिकन हीट्रोजंक्शन (एसएचजे) एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी है और वह 2016 तक पेनासोनिक कारपोरेशन, जापान के पेटेंट के तहत थी। एसजेएच प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विनिर्मित सोलर मॉड्यूल संबद्ध सामानों से भिन्न है।

- घ. तीन आवेदक यथा मैसर्स मुनरा सोलर पीवी लिमिटेड, मैसर्स वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड और मैसर्स हेलियोस फोटो वोल्टेक लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में आधारित हैं और वे घरेलू क्षमता के परिकलन में शामिल नहीं किए जा सकते।
- ड. एसईजेड संयंत्र केवल निर्यात के लिए हैं।
- च. आवेदक अनरॉट एल्युमीनियम (अलॉयहीन एल्युमीनियम और एल्युमीनियम अलॉय) में महानिदेशक, रक्षोपाय के पूर्व जांच परिणाम के मद्देनजर घरेलू उद्योग होने का दावा नहीं कर सकते।
- छ. जांच की शुरुआत विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (एसईजेड अधिनियम) की धारा 53 के मद्देनजर कानून में बुरी हैं जिसमें यह प्रावधान है कि एसईजेड भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र को माना जाता है।
- ज. एसईजेड अधिनियम की धारा 30 और विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.08 के अनुसार एसईजेड और ईओयू में स्थित यूनिटें भारत से बाहर स्थित मानी जाती हैं और इसीलिए उन्हें घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता।
- झ. पीईसीएमवाई ने जांच की अवधि के दौरान मैसर्स एंकर इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि. (एईपीएल) के लिए आयात किया है। दोनों पेनासोनिक जापान की 100 प्रतिशत सहायक कंपनियां हैं।
- ञ. पीईसीएमवाई द्वारा याचिकाकर्ताओं को कोई क्षति नहीं पहुँचाई गई क्योंकि उसके एसएचजे प्रौद्योगिकी आधारित सोलर सेलों और मॉड्यूलों के निर्यात पर भारत में पहुँच मूल्य अन्य भारतीय आयातकों द्वारा आयातों के भारत में पहुँच मूल्य से काफी अधिक (लगभग दोगुना) है।
- ट. आयात केवल भारत सरकार के नवीकरण ऊर्जा स्रोत का संवर्धन करने के लक्ष्य के कारण बढ़े हैं।
- ठ. भारतीय विनिर्माता भारत में मांग के 10 प्रतिशत से कम की ही पूर्ति कर पाए।
- ड. मलेशिया सहित अन्य देशों से आयात भारतीय विनिर्माताओं द्वारा सृजित मांग एवं आपूर्ति के अंतराल को पूरा करने के लिए ही हुए।
- ढ. संबद्ध सामानों की घरेलू मांग घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता से कहीं अधिक थी। इस प्रकार, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मांग व्यापक रूप से आयातों द्वारा पूरी की गई थी क्योंकि घरेलू उद्योग स्वदेशी ग्राहकों की मांग को पूरा करने में अक्षम था।
- ण. अतः ये आयात किसी अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप नहीं हैं बल्कि भारी मांग एवं आपूर्ति के कारण हैं।
- त. इस समय भारत की फोटो वोल्टेक उत्पादों की 80 प्रतिशत उत्पादन क्षमता आयातित सोलर सेलों पर आधारित है और सोलर उत्पादों के आयातों पर शुल्क से विद्युत केंद्र प्रचालक, निवेशक और आयातक जैसे भारत के निचले स्तर के प्रयोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुँचेगा।
- थ. इससे बाद में विद्युत उत्पादन लागत बढ़ सकती है जो भारत में अवसंरचना निर्माण तथा आर्थिक विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।
- द. प्राथमिक जांच परिणाम में आयातकों, अंतिम प्रयोक्ताओं के हित तथा समग्र सार्वजनिक हित का उल्लेख नहीं किया गया।
- ध. अतः रक्षोपाय लगाने से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास प्रभावित होगा।

(vi) मैसर्स नॉर्थ इंडिया मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन (एनआईएमएमए)

- क. सोलर मॉड्यूल सोलर सेलों से भिन्न है और रक्षोपाय शुल्क केवल मॉड्यूलों पर लगाया जाना चाहिए न कि सोलर सेलों पर क्योंकि सोलर सेलों के लिए मांग और आपूर्ति का भारी अंतराल है।
- ख. सोलर सेल विनिर्माता 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग कर केवल 15 प्रतिशत घरेलू मांग ही पूरा कर सकते हैं।
- ग. सोलर मॉड्यूल विनिर्माताओं के समक्ष आयातित मॉड्यूलों से कड़ी एवं बुरी प्रतिस्पर्धा है तथा वे विनिर्माण आधार की सुरक्षा के लिए नीचे से ऊपर तक चल रहे हैं।
- घ. ऐसी स्थिति में सोलर सेलों पर रक्षोपाय शुल्क, वह भी जब सोलर सेलों के लिए मांग एवं आपूर्ति का अंतराल भारी हो, लगाने से सोलर मॉड्यूलों के आयात में और अधिक वृद्धि होगी तथा भारत में सोलर सेलों की सीमित उपलब्धता सोलर मॉड्यूलों के भारतीय विनिर्माताओं की स्थिति को और कमजोर करेगी। सोलर मॉड्यूलों के प्रयोक्ता सोलर सेलों पर रक्षोपाय शुल्क के भार से बचने के लिए मॉडलों का आयात करने बेहतर समझेंगे और इससे भारत में सोलर पैनल विनिर्माण पूरी तरह से टूट जाएगा।
- ड. मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की असमर्थता के कारण घरेलू उद्योग को हुई कोई क्षति आयातों में उछाल के भ्रामक दावे के संबंध में रक्षोपाय शुल्क की मांग करने के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
- च. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग को क्षति तथा आयातों में वृद्धि के बीच कोई कारणात्मक संबंधित स्थापित नहीं कर पाए।

(vii) मैसर्स आरईसी सोलर पीटीई. लि.

- क. आरईसी सोलर पीटीई. लि. जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का केवल सिंगापुरी सीएसपीवी विनिर्माता रहा है और इससे सिंगापुर में विनिर्मित मॉड्यूलों अथवा पैनलों में असेंबल किए गए अथवा न किए गए किसी भी सोलर सेल पर कोई रक्षोपाय से छूट प्रदान की जाती है।
- ख. आरईसी सोलर पीटीई. लि. से आयात (सिंगापुर के प्रतिनिधि होने के मामले में) अलग-अलग 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- ग. जांच की पूरी अवधि में आरईसी सोलर पीटीई. लि. का भारत में लदान भारत में विचाराधीन उत्पाद की कुल मांग के 1.4 प्रतिशत से कम रहा है, जबकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के लिए कुल मांग की औसतन 10 प्रतिशत आपूर्ति की है।

(viii) मैसर्स चाइना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्ट्स

- क. महानिदेशक ने जांच शुरूआत नोटिस के 30 दिनों के भीतर पक्षकारों द्वारा उनके मत प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा नहीं की तथा जल्दबाजी में जांच के आरंभ होने के 18 दिनों के भीतर अपना प्रारंभिक जांच परिणाम जारी कर दिया।
- ख. एसजीडी केवल जांच के बाद लागू किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों को उनका मत प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना, जांच पूरी नहीं हो सकती।
- ग. वर्तमान जांच में की गई संपूर्ण कार्रवाई अमान्य है क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर की गई थी। जांच के विभिन्न चरणों पर की गई त्रुटियों को अब डीजी के किसी भी कार्य द्वारा परिशोधित नहीं किया जा सकता।
- घ. इस समय वृहत घरेलू मांग है जिसे ऐसा करने में घरेलू उद्योग की असमर्थता को देखते हुए पूरा किए जाने की आवश्यकता है। एसजीडी को लागू करने से विचाराधीन उत्पाद की लागत में वृद्धि होगी। इसी कारण से एडीडी पर किए गए सकारात्मक निष्कर्ष किए गए, किंतु लोक हित में शुल्क नहीं लगाया गया। यहां समान कारणों को परिचालित करना चाहिए।
- ड. भारत को जेएनएनएसएम के तहत संशोधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, उच्च गुणवत्ता वाले आयातित पीवी उत्पादों, विशेष रूप से चीन से करने की आवश्यकता है।
- च. भारत को पीवी सेल्स की लगातार आपूर्ति की जरूरत है। एसजीडी का अनुप्रवाह उद्योगों, सोलर सेल उद्योग के स्वस्थ विकास और सरकार द्वारा आरंभ की गई ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं पर विपरीत प्रवाह होगा।
- छ. यह सामान्य है कि व्यापार उपचार के कारण चीन से ईयू और यूएसए को निर्यातों में गिरावट आई है। तथापि, चीन से भारत को निर्यातों में वृद्धि का इस मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। यह एक मुक्त बाजार है जहां बिक्री की मात्रा का बाजार उन्मुख है। आईटीए-1, जीएटीडी अथवा पेरिस करार को हस्ताक्षरित करने का कोई परिणाम नहीं हुआ है क्योंकि यह बाजार का प्राकृतिक कानून है कि बढ़ती हुई मांग आयातों में वृद्धि करती है।
- ज. कीमतों का गिरना एक प्रवृत्ति है, इसलिए इसे अप्रत्याशित के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता।
- झ. आयातों में वृद्धि भारतीय उद्योग की मांग में वृद्धि के साथ-साथ है।
- ट. घरेलू उद्योग का विचार है कि आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही महत्वपूर्ण क्षति को प्रमाणित नहीं कर सकते, अन्यथा यह अंतिम स्तर में पाटनरोधी जांच को समाप्त करने का अनुरोध करना के निर्णय नहीं करता।
- ठ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े वस्तुगत क्षति को भी प्रमाणित नहीं कर सकते, तब यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि गंभीर क्षति का निर्धारण नहीं किया जाएगा।
- ड. आवेदक द्वारा प्रत्येक वर्ष क्षमता को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक वर्ष क्षमता को बढ़ाने के ऐसे अनुचित निर्णयों से आवेदकों को क्षति पहुँच सकती है, संबद्ध देशों से आयातों से नहीं।
- ढ. घरेलू उद्योग के लिए पहुंच कीमत और निवल बिक्री वसूली के बीच कोई सह संबंध नहीं है।
- ण. सर्वप्रथम घरेलू उत्पादकों को यह स्थापित करना चाहिए कि देश में बढ़े हुए आयात विद्यमान हैं और घरेलू उत्पादकों को ऐसे बढ़े हुए आयातों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं को अनुकूल बनाने हेतु समय और योजना की आवश्यकता है।
- त. आवेदक का दावा दोषपूर्ण और भ्रामक है क्योंकि दोनों प्रौद्योगिकियों से विनिर्मित उत्पादों के बीच का अंतर कई पहलुओं से महत्वपूर्ण है, जैसे कच्ची सामग्री, उत्पादन प्रक्रियाएं, कार्यकुशलता, लचीलापन और कीमतें आदि।
- थ. सीसीसीएमई तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बहुत बार लिखित में निवेदनों में और पाटनरोधी जांच के लिए पेशी के समय जनहितों पर व्यापार उपचार उपायों के नकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया गया है।
- द. विचाराधीन उत्पाद से निम्नलिखित को हटा दिया जाना चाहिए: (i) "पीईआरसी" (निष्क्रिय उत्सर्जक रियर सेल) आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले सेल, (ii) थिन फिल्म और बाई-फेशियल एन-टाइप सोलर सेल्स, (iii) 5 और 6 बस बार उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उच्च कार्यकुशलता वाले सोलर सेल्स, और (iv) मोनो क्रिस्टल प्रौद्योगिकी के सोलर मॉड्यूल्स क्योंकि समायोजन योजना बताती है कि डीआईपीईआरसी प्रकार के सेल्स का उत्पादन करेगा।
- ध. याचिकाकर्ता हेलियस फोटो वोल्टेक लिमिटेड का दिनांक 28 अगस्त, 2017 की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सूची में उल्लेख नहीं मिलता है। डीजीटीआर को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या हेलियस सेल्स के उत्पादक हैं या मॉड्यूल्स के अथवा दोनों।

- न. याचिकाकर्ताओं के आधार की सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल के लिए पृथक-पृथक जांच होनी चाहिए।
- प. यह अनुरोध किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपनी स्थापित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए और सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रतिष्ठा की अलग-अलग जांच करनी चाहिए।
- फ. भारत यह प्रदर्शन किए बिना रक्षोपाय शुल्क को लागू करने के द्वारा एओएस के तहत अपनी बाध्यताओं के बिल्कुल विपरीत कार्य करने के लिए दृढ़ है कि वर्तमान मामले में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव विद्यमान हैं।
- ब. आयातों में वृद्धि भारत में मांग-आपूर्ति अंतर के कारण है। मांग राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सृजित की गई है। घरेलू उत्पादक और निर्यातक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में राष्ट्र को सक्षम बना रहे हैं।
- भ. न तो याचिका न ही प्रारंभिक जांच परिणामों ने भारत द्वारा उपगत विशिष्ट जीएटीटी बाध्यताओं की यथार्थ रूप में पहचान की है जो संबद्ध वस्तुओं के आयातों में हुए अचानक, तीव्र, उल्लेखनीय और नवीन वृद्धि का कारण है।
- म. जीएटीटी के अनुच्छेद XIX(1)(क) की शर्तों में ऊपर चिन्हित की गई जीएटीटी बाध्यताओं में से किसी के भी कारण संबद्ध वस्तुओं के आयातों में नवीन, अचानक, तीव्र और उल्लेखनीय महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।
- य. संबद्ध वस्तुओं के लिए भारत की आईटीए-1 वचनबद्धता और आयातों में कथित नवीन और अचानक हुए वृद्धि के बीच कोई संबंध नहीं है।
- र. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में क्रमशः 253 और 305 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि अत्यधिक है।
- ल. भारतीय उद्योग भारतीय मांग का केवल 10-15 प्रतिशत ही पूरा कर सकता है। बाकी मांग को राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत लक्ष्य को पूरा करने के लिए आयातों द्वारा पूरा किया जाना है।
- श. निर्यात बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में तीव्र गिरावट आने से यह 2014-15 में 100 सूचकांक बिंदुओं से गिरकर 2017-18 में 56 सूचकांक बिंदु रह गया। इस संबंध में हुई क्षति का आयातों से कोई लेना-देना नहीं है।
- ष. घरेलू उद्योग को क्षति पूरी तरह से इन कारणों से है न कि तथाकथित पाटित आयातों से।
- स. घरेलू उद्योग की क्षति का वास्तविक कारण अन्य भारतीय उत्पादकों की उग्र कीमत निर्धारण पद्धतियां हैं और न कि आयात।
- ह. इस तरीके से पश्चगामी एकीकरण के फलस्वरूप आगामी कुछ वर्षों में लागत में अत्यधिक वृद्धि होगी।
- क्ष. यदि समायोजन योजना में लागत कम होने के बजाए अत्यधिक लागत आती है तो, याचिकादाता आयातों को समायोजित करने में समर्थ नहीं होंगे।

(ix) मैसर्स विक्रम सोलर लिमिटेड

- क. सोलर सेल सोलर पीवी प्रणाली की सबसे आधारभूत यूनिट है। एक पीवी मॉड्यूल में बहुत पीवी सेल्स होते हैं जो अधिक वोल्टता उत्पादन देने के लिए श्रृंखलाओं में घिरे होते हैं। मॉड्यूल मूल्यवर्द्धित उत्पाद हैं जो सोलर सेलों को इलैक्ट्रिक विद्युत के उत्पादन के लिए प्रयुक्त वाणिज्यिक रूप से उपयोगी वस्तु में बदलते हैं। सोलर सेलों के विनिर्माण के लिए सीमित घरेलू क्षमता के आलोक में विनिर्माताओं को आयातित सेलों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- ख. सोलर सेलों पर लगाए गए रक्षोपाय शुल्कों का डीटीए से हटाए जा रहे उसके सभी सोलर सेल मॉड्यूलों के लिए शुल्क देने वाली एसईजेड यूनिट का प्रभाव होगा। उस उपाय से एसईजेड यूनिटों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ग. घरेलू उत्पादकों द्वारा विनिर्मित सोलर मॉड्यूलों की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है। घरेलू उत्पादन के अधिकतर खंड एसईजेड में स्थित हैं और रक्षोपाय शुल्क लगाने से इन विनिर्माताओं पर ही प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि 2022 तक 100 गीगावाट सौर विद्युत का लक्ष्य प्राप्त करना भी असम्भव होगा क्योंकि 100 गीगावाट लक्ष्य का अधिकतर भाग आयात के माध्यम से पूरा किया जाना है। इससे कोयला और संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों जैसे पारंपरिक ईंधनों के माध्यम से विद्युत उत्पादन होगा। रक्षोपाय शुल्क इस प्रकार स्पष्ट रूप से जनहित के विरुद्ध है जो कि रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत है।
- घ. यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो महानिदेशक को शुल्क की शून्य दर पर 5 गीगावाट के प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) निर्धारित करना चाहिए। टीआरक्यू से दावेदारों की अधिकतर चिंताएं दूर हो जाएंगी। यह एसईजेड में स्थापित घरेलू उत्पादन सुविधाओं को राहत देते हुए और टीआरक्यू व्यवस्था के तहत निर्धारित कोटे से अधिक आयातों पर रक्षोपाय शुल्क देकर डीटीए उत्पादकों का संरक्षण देते हुए सौर विद्युत उत्पादन की उत्पादन लागत पर अतिरिक्त कोई अतिरिक्त भार डाले बिना मांग एवं आपूर्ति के अंतराल को पूरा करेगा।
- ड. भारत सरकार को एसईजेड से डीटीए में हटाए गए सोलर मॉड्यूलों पर रक्षोपाय शुल्क के भुगतान से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के तहत विशेष छूट प्रदान करनी चाहिए।

(x) मैसर्स एल एन वी टेक्नोलॉजी लिमिटेड

- क. तीन शिकायकर्ता (मुद्रा, वेसोल और हिलिय फोटो वोल्टेइक) विशेष आर्थिक क्षेत्र से कार्य करते हैं, को और से आपूर्ति करते हैं जिन्हें किसी शुल्कों अथवा करों के आरोपण से छूट मिली हुई है।

- ख. विशेष आर्थिक क्षेत्र में सभी आयातों को पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क लगाये जाने से बाहर रखा गया है। चूंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र को आयात और निर्यात के लिए अलग रूप में माना जाता है। अतः उसे घरेलू उद्योग के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।
- ग. आयातों में वृद्धि के फलस्वरूप विशेष आर्थिक क्षेत्र एककों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे अनेक मामले हैं जहां प्राधिकारी ने विशेष आर्थिक क्षेत्र को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना है। इसके फलस्वरूप इन तीन शिकायकर्ताओं को घरेलू उद्योग (डी आई) का हिस्सा नहीं माना जा सकता है और शेष शिकायकर्ता 'सामूहिक उत्पादन जो भारत में कुल वस्तु का एक बड़ा हिस्सा बनता हो', कि आरंभिक सीमा पार नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की स्थाई आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा रहा है।
- घ. रक्षोपाय की सीमा तक शुल्क में छूट का निदान जब विचारोधीन उत्पाद को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा घरेलू इकाई निपटाया जाता है, स्वयं घरेलू उद्योग के लिए व्यापक स्तर पर हानिकारक होगा।
- ङ. आयातों में वृद्धि के संबंध में निर्धारण सीमा शुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 के नियम 8 द्वारा यथाउल्लिखित वस्तुपरक एवं मात्रा योग्य आधार पर सभी संगत कारकों का मूल्यांकन नहीं करता है। यह विशेष रूप से तब होता है, जब घरेलू मांग और क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।
- च. दिए गए आंकड़ों के संदर्भ में, यह तर्क दिया गया है कि घरेलू मांग में 2014-15 से 2017-18 के बीच 7 गुणा वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग की क्षमता में केवल 4 गुणा वृद्धि हुई है। यह मानते हुए कि घरेलू उद्योग 70 प्रतिशत क्षमता पर कार्य करता था, घरेलू उत्पादन का योग और आयात में 2014-15, 2015-16 और 2017-18 में क्रमशः 5 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 1 प्रतिशत की वृद्धि मांग की तुलना में हुई है, जिसे घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातों के कारण उल्लेख किया जा सकता है।
- छ. एल एन वी सहित अनेक विकासकर्ताओं ने सोलर पार्क विकसित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ ठेका किया है और ऐसी धाराओं में वे कीमतें होती हैं जो इस प्रकार के शुल्क को लगाये जाने की स्थिति में भी परिवर्तन के लिए पूर्णरूप से समावित करने वाली तथा बिना किसी लचीलेपन के है।
- ज. चूंकि सोलर पेनल लागत का 60 प्रतिशत होता है, अतः विकासकर्ता आयातों को करने की स्थिति में नहीं होंगे और इसके फलस्वरूप इन परियोजनाओं में गतिरोध आ जायेगा। समाधान के रूप में, रक्षोपाय शुल्क केवल उन आयातों के लिए लगाया जाना चाहिए जिसमें भावी परियोजनाएं शामिल हों, जिन्हें नहीं लिया गया है।

(xi) ट्रिना सोलर (वियतनाम) साईस एंड टेक्नोलॉजी कं. लिमि.

- क. कोई अंतिम रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश वियतनाम के विरुद्ध नहीं की गई है क्योंकि संबंधित वस्तुओं का आयात अन्य विकासशील देशों (चीन और मलेशिया को छोड़कर) से आयातों के लिये जाने पर अलग अलग रूप में 3 प्रतिशत और सामूहिक रूप में 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।
- ख. यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी सकारात्मक अंतिम जांच परिणाम जारी करता है तब यह अनुरोध है कि कोई निश्चयात्मक रक्षोपाय शुल्क प्रारंभिक जांच परिणाम में की गई सिफारिशों के अनुरूप वियतनाम पर नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xii) ट्रिना सोलर (थाइलैंड) साईस एंड टेक्नोलॉजी कं. लिमि.

- क. कोई अंतिम रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश थाइलैंड के विरुद्ध नहीं की गई है क्योंकि संबंधित वस्तुओं का आयात अन्य विकासशील देशों (चीन और मलेशिया को छोड़कर) से आयातों के लिये जाने पर अलग अलग रूप में 3 प्रतिशत और सामूहिक रूप में 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।
- ख. यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी सकारात्मक अंतिम जांच परिणाम जारी करता है तब यह अनुरोध है कि कोई निश्चयात्मक रक्षोपाय शुल्क प्रारंभिक जांच परिणाम में की गई सिफारिशों के अनुरूप थाइलैंड पर नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xiii) आइकॉन सोलर – ईएन पावर टेक्नोलॉजिज प्रा. लिमि.

- क. हालांकि अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार 95 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क भारतीय सोलर उद्योग के विकास के लिए हानिकारक होगा और इसके फलस्वरूप अल्पाधिकारीवादी कार्टेल बनेगा।
- ख. भारत की नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों को लागतों के स्थिरीकरण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

ग. निर्मित मॉड्यूल के एक बड़े हिस्से का उपयोग “कृषि में सोलर पम्प” और “सौभाग्य होम लाइटिंग सिस्टम” जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए जाने में किया जा रहा है जिसका प्रत्यक्ष रूप से संबंध कृषि संबंधी आय और ग्रामीण न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देने से है।

घ. पी आर सी में शुल्कों के संशोधन के फलस्वरूप कीमतों में तेजी से गिरावट आई है और उसके कारण घरेलू उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

(xiv) विबग्योर एनर्जी/ सनबीम कोरपोरेशन

- क. एक विकल्प के रूप में सोलर रूफटॉप सॉल्यूशन का हालिया उद्भव जो 2022 तक 40 जी डब्ल्यू के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित वार्षिक वृद्धि के साथ साथ भी नहीं हुआ है।
- ख. सोलर सिस्टम पर जी एस टी की दर, लगाए जा रहे शुल्कों का सतत भय, खराब नेट मीट्रिंग कार्यान्वयन जैसे विनियामक अशपथताओं के हाने के कारण इन कंपनियों के लिए एक अस्थिर करने वाला वातावरण उत्पन्न हुआ है।
- ग. अपेक्षाकृत हालिया उद्भव के कारण, अधिकांश उपभोक्ताओं ने अब सोलर रूफटॉप सॉल्यूशन को अपनाना शुरू कर दिया है। इनके लिए अधिकांश ठेके या तो दे दिए गए हैं अथवा सौदेबाजी के अंतिम चरण में हैं। कंपनियों के पास उतनी क्षमता नहीं है जिससे वे इस समय ऐसे शुल्क को देने पर विचार कर सकें।
- घ. शुल्क लगाने के फलस्वरूप इन संविदाओं की पूर्ति खतरे में पड़ जायेगी, बहुत अधिक घाटा होगा और उन लक्ष्यों से विचलित भी होना पड़ेगा जो सरकार प्राप्त करना चाहती है।
- ङ. रक्षोपाय शुल्क का कोई लाभ नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्षमता नहीं है।
- च. यदि शुल्क लगाया भी गया होता तब एक उचित समय अवधि (6 महीने) पर विचार उसे लागू किए जाने के पूर्व किया जाना चाहिए। एक उचित और बिल्कुल सही समय पर शुल्क लगाने से भारत में सौर उर्जा का आर्थिक अंगीकरण बाधित नहीं होगा।
- छ. भारत को सहायक सेवा प्रदाताओं को समानांतर क्षति से बचाने के लिए घरेलू निर्यातों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए “नियोजित सहायता तंत्र” विकसित करने की योजना बनानी चाहिए।

(xv) सोलर पावर डेवेलपर्स एसोसिएशन

- क. हितबद्ध पक्षकारों को जांच आरंभन सूचना के अनुसार अपने विचारों से अवगत कराने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था परंतु प्रारंभिक जांच परिणाम हमारे द्वारा अपने विचारों को अवगत कराने के पूर्व जारी कर दिया गया था।
- ख. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की क्योंकि पाटनरोधी जांच अंतिम निर्णय के चरण में और अपुष्ट आधारों पर वापस लिया गया था। पाटनरोधी शुल्क समाप्ति आदेश के पैरा 18 और 21 के अनुसार, घरेलू उद्योग में जांच की अवधि के दौरान हुई क्षति में परिवर्तन होना अवश्यभावी है और यदि याचिकाओं को इस आधार पर वापस लेना शुरू हो जाता है, तब इसके फलस्वरूप अराजक की स्थिति पैदा हो जायेगी।
- ग. निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास पाटनरोधी शुल्क जांच और चालू रक्षोपाय याचिका और जांच अवधि अतिच्छादन से आंकड़े प्राप्त हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात की जांच करने के लिए इन दो आंकड़ों के समुच्चय की तुलना कर सकता है कि क्या रक्षोपाय याचिका में कोई विशेषता है।
- घ. 5 जनवरी, 2018 को 70 प्रतिशत अनंतिम रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश के कारण वास्तव में एक अराजक की स्थिति पैदा हो गई है। भारत की राज्य सरकार द्वारा अनेक सोलर निविदाओं को इन शुल्कों पर अनिश्चितता के कारण बोली लगाने वाले से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।
- ङ. चरण III में 2022 तक 80 जी डब्ल्यू का सोलर मिशन लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, प्रतिवर्ष 20 जी डब्ल्यू की औसत वार्षिक संस्थापना अवश्य होनी चाहिए। सोलर सैल (3164 एम डब्ल्यू/ प्रतिवर्ष) और सोलर मॉड्यूल (8398 एम डब्ल्यू/ प्रतिवर्ष) की वर्तमान घरेलू निर्माण क्षमता शपथ रूप से इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- च. वितरण कंपनियों जो सोलर उर्जा के अंतिम क्रेता हैं, में स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है यदि लागत प्रति के डब्ल्यू एक 3 रुपए के नीचे रहता है तभी वे सोलर उर्जा खरीदेंगे। आसन्न रक्षोपाय शुल्कों के आलोक में, यह विकासकर्ता के

लिए संभव नहीं होगा कि वे इस शुल्क को दें, जो प्रति के डब्ल्यू एच 3 रुपए से कम है और उससे यह वाणिज्यिक रूप से असंभव हो जाता है कि वे बोलियों और परियोजनाओं में भाग लें तथा इस प्रकार कम शुल्क दें।

यद्यपि निश्चयात्मक रक्षोपाय शुल्क 12-15 सेंट प्रति वाट है जो विनियम दर पर निर्भर करते हुए 8-11 भारतीय रुपए प्रति वाट के समतुल्य है, इसके फलस्वरूप प्रति के डब्ल्यू एच 80 पैसे से 1.30 भारतीय रुपए तक शुल्क में वृद्धि होगी और उससे यह शुल्क बढ़कर लगभग 4 रुपए प्रति के डब्ल्यू एच तक पहुंच जायेगा। इस दर से सोलर उर्जा अप्रतिस्पर्धी हो जायेगा और विकासकर्ता चालू परियोजनाओं को भी छोड़ देंगे। संलग्न रिपोर्ट इस बात को सिद्ध करती है कि सोलर पावर शुल्क प्रति के डब्ल्यू एच 3 भारतीय रुपए से कम है और इसमें ग्रिड समता प्राप्त कर ली है।

- छ. सोलर पावर ग्रिड की समता को अस्त व्यस्त करने से विकासकर्ताओं और अंतिम ग्राहकों दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ता की यह गणना कि 20 सेंट का मामूली शुल्क लगाने से बिजली के शुल्क में 70 पैसे प्रति वाट की वृद्धि होगी, सही नहीं है। 12 – 15 सेंट तक शुल्क से पर्याप्त रूप से प्रशुल्क में वृद्धि होगी, जिसे ऊपर दर्शाया गया है।
- ज. अनेक विद्युत खरीद करार परियोजना के विकासकर्ताओं और वितरण कंपनियों के बीच किया गया है और 9000 मेगावाट तथा 18000 मेगावाट की क्षमता वाली वितरण कंपनियों को आवंटन के लिए निविदा भी दे दी गई है। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए अपेक्षित आयात अभी शुरू होने हैं और लगान के अधीन हैं तथा रक्षोपाय शुल्क लगाने से इन आयातों पर प्रभाव पड़ेगा और उस से विद्युत प्रशुल्कों में वृद्धि होगी।
- झ. रक्षोपाय लगाना उत्पादना के प्रतिकूल होगा और इसका एन एस एम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि प्रशुल्कों में वृद्धि को कभी भी राज्य वितरण कंपनियों द्वारा खपाया नहीं जा सकेगा।
- ञ. अप्रैल 2018 में, एम एन आर ई ने सोलर परियोजनाओं के लिए बोली लगाने संबंधी मानदंडों में “कानून में परिवर्तन” के संदर्भ में इस धारा के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जिसके द्वारा उक्त धारा में शुल्कों और उपकर को शामिल किया गया है। यद्यपि विचार किए जाने के लिए रक्षोपाय शुल्क को पास-श्रू के रूप में लिया जाना है, उसकी अभी जांच की जानी है और विनियामक प्रक्रिया के अंतर्गत उसे सिद्ध किया जाना है। यह नोट किया जाना है कि कोई भी ओफ-टेकर पास-श्रू तंत्र के अंतर्गत इस प्रभाव को सहने नहीं जा रहा है और उसका संपूर्ण सोलर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पास-श्रू की प्रक्रिया भी बहुत अनिश्चित, लंबी और जटिल है और यदि शुल्क लगाया जाता है तब चालू परियोजनाओं का संरक्षण करने का कोई आश्वासन नहीं देता है। वर्तमान औसत प्रशुल्क 2.75 भारतीय रुपए प्रति के डब्ल्यू एच के साथ, इन प्रशुल्कों पर 35-40 प्रतिशत तक प्रभाव पड़ने की संभावना है, यदि शुल्क लगाया जाये और यह किसी डिस्कॉम को आगे आने और 3 भारतीय रुपए से अधिक पर विद्युत का बिक्री संबंधी करार करने के लिए आकर्षित नहीं कर पायेगा। इस प्रकार से संपूर्ण मिशन असफल हो जायेगा और सोलर उद्योग, एक दूसरे पर निर्भर एम एस एम ई, नौकरियां और बैंक के कर्जों का भुगतान न करने पर सौर उद्योग समाप्त हो जायेगा।
- ट. रक्षोपाय शुल्क 1,00,000 करोड़ भारतीय रुपए से अधिक की सोलर बिजली परियोजनाओं को खतरे में डाल देगा क्योंकि हमारे सदस्यों ने पहले ही लगभग 27 जी डब्ल्यू चालू परियोजनाओं के लिए करार किया है।
- ठ. रक्षोपाय के संबंध में अनिश्चितता के कारण, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हाल में लगाई गई बोलियों में प्रशुल्कों में लगभग 20-25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारा विश्लेषण यह दर्शाता है कि भावी सौर उर्जा परियोजनाओं के लिए प्रशुल्कों में 40 प्रतिशत से अधिक तक वृद्धि हो सकती है और यह गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित बोलियों में हाल में पाये गये 2.98 भारतीय रुपए प्रति यूनिट और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित बोलियों में पाये गये 2.71 भारतीय रुपए प्रति यूनिट के बजाय लगभग 4 भारतीय रुपए प्रति यूनिट तक हो जायेगा। इस वृद्धि का अंतिम उपभोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ड. घरेलू उद्योग आकार, प्रौद्योगिकी के उन्नयन में निवेशों की कमी के मामले में कमजोर है जिसके फलस्वरूप भारत में उत्पादित सोलर सैल और मॉड्यूल की कार्यक्षमता में कमी आती है। घरेलू उद्योग मॉड्यूल में सोलर सैल की एसेंबली मात्र तक सीमित है जो समग्र मूल्य श्रृंखला में अंतिम चरण है। चीन से सिलिकॉन इनगोट्स, वेफर्स और सैल्स को आयात करने पर निर्भरता भारत के निर्माण को सोलर निर्माण में अन्य एशियाई बड़ी कंपनियों से अप्रतिस्पर्धी रचना जारी रहेगी।
- ढ. भारत सरकार घरेलू उद्योग को अन्य प्रोत्साहन राशि जैसे कम व्याज पर ऋण देने पर विचार कर सकती है। रक्षोपाय लगाना परियोजना विकासकर्ताओं और अंतिम उपभोक्ताओं जिन्हें अपेक्षाकृत अधिक प्रशुल्कों का भुगतान करना होगा, पर इसके स्पिल ओवर प्रभाव पर विचार करते हुए सर्वोत्तम विकल्प नहीं हो सकता है।
- ण. निम्नलिखित उत्पादों उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए -

- (i) पी ई आर सी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सोलर सैल्स
 - (ii) थिन फिल्मस एंड बाई फेसियल एन प्रकार के सोलर सैल्स
 - (iii) 5 और 6 बस बार उत्पादन शब्दावली का उपयोग करते हुए अत्यधिक कार्यक्षम सोलर और
 - (iv) बोना सियस्टलाइंग प्रौद्योगिकी का सोलर मॉड्यूल
- त. याचिकाकर्ता ने याचिका में यह मान लिया है कि वे थिन फिल्म सोलर सैल्स और मॉड्यूल का निर्माण नहीं कर सकता है। इसके अलावा, उन्होंने समायोजन योजना में यह दावा किया है कि वे पी ई आर सी आधारित सैल्स का निर्माण करते रहेंगे। इस प्रकार से, स्वीकार्य रूप में, याचिकाकर्ता वर्तमान में इन सैलों का निर्माण नहीं कर सकता है। हमें मालूम है और यह सामान्य ज्ञान है कि याचिकाकर्ता 5 और 6 बस बार उत्पादन शब्दावली का उपयोग करते हुए और मोनो-क्रिस्टलाइन प्रौद्योगिकी पर सोलर सैल्स का निर्माण नहीं कर सकता है। किसी घरेलू उद्योग इन वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता है अतः उन्हें इस्पात के कार्यक्षेत्र से तत्काल बाहर किया जाना चाहिए।
- थ. याचिकाकर्ता कंपनियों के पास सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख (6) (ख) के साथ कथित रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.1 (ग) के संबंध में वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
- द. याचिकाकर्ता के आधार की जांच हिलियस पी वी लिमि. के लिए आंकड़ों पर विचार किए बिना सोलर सैलों और सोलर मॉड्यूल के लिए पृथक् रूप से की जानी चाहिए क्योंकि उनके आंकड़े एम एन आर ई के पास उपलब्ध नहीं हैं। सोलर मॉड्यूल के लिए याचिकाकर्ताओं की कुल संस्थापित क्षमता भारतीय उत्पादन क्षमता में से कुल का मात्र 15 प्रतिशत है। इस प्रकार से याचिकाकर्ताओं के पास सोलर मॉड्यूल में घरेलू उद्योग के रूप में कोई आधार नहीं है। इसके अलावा, सैल और मॉड्यूल की मिश्रित क्षमता भारत के कुल संस्थापित क्षमता में 26.5 प्रतिशत है। अतः सैल और मॉड्यूल दोनों के लिए घरेलू उद्योग के रूप में आधार मौजूद नहीं है।
- ध. याचिका में कुल भारतीय उत्पादन के आंकड़े सही नहीं हैं क्योंकि यह अपनी पूर्णता में अन्य उत्पादकों के उत्पादन पर विचार नहीं करता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि सभी अन्य उत्पादक संबद्ध वस्तुओं के आयातक हैं। इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है और इस प्रकार से इसमें कोई विशेषता नहीं है। एम एन आर ई के आंकड़ों पर इस मामले में घरेलू उद्योग के आधार की जांच करने के लिए विचार किया जाना चाहिए।
- न. इस जांच में दो वस्तु नामतः सोलर सैल और सोलर मॉड्यूल शामिल हैं। घरेलू उद्योग के आधार का आकलन करते समय डी जी टी आर से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उन सोलर सैल्स और मॉड्यूल के निर्माताओं, जिन्होंने क्षति की अवधि के दौरान क्रमशः सोलर सैल्स और मॉड्यूल का आयात किया था, को बाहर कर दें।
- प. जब दो उत्पाद एक ही जांच के अध्वधीन हों, तब निर्दिष्ट प्राधिकारी पृथक् रूप से घरेलू उद्योग के आधार की जांच करने की सतत् प्रथा का पालन करते हैं। ऐसा निम्नलिखित जांचों में किया गया है :
- (i) चीन जन. गण. और मेक्सिको से पेनेसिलिन-जी पोटेसियम और 6-ए पी ए का आयात। अंतिम जांच परिणाम दिनांक 20 जनवरी, 2011 के अधिसूचना संख्या 14/19/2009 – डी जी ए डी के द्वारा जारी किया गया है।
 - (ii) चीन जन. गण. से फ्रंट एक्सेल वीम्स और स्ट्रेयरिंग नकल्स का आयात। अंतिम जांच परिणाम दिनांक 05 मार्च, 2010 के अधिसूचना संख्या 14/19/2008 – डी जी ए डी के द्वारा जारी किया गया है।
- फ. इसके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित याचिकाकर्ताओं को आधार से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि उनका प्राथमिक लक्ष्य निर्यात बाजार की मांग को पूरा करना है। इलेक्ट्रिकल इंजुलेटर के मामले में दिनांक 27 सितंबर, 2012 के महानिदेशालय के रक्षोपायों के अंतिम जांच परिणामों में, डब्ल्यू एस आई उद्योग (विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित) को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। जैसे ही विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों को बाहर कर दिया गया हो, तब शेष याचिकाकर्ताओं की संख्या भारत में वार्षिक मांग की तुलना में बहुत कम (कुछ सैकड़ों मेगावाट) रह जायेगा।
- ब. गैट के अनुच्छेद XIX(1) (क) के अंतर्गत दायित्व के अनुसरण में, भारत तब तक रक्षोपाय शुल्क नहीं लगा सकता है जब तक निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार यह दर्शाया नहीं जा सके कि बड़ा हुआ आयात और परिणामी क्षति पूर्व में अनुमान न लगाये जाने वाले घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप तथा गैट के अंतर्गत भारत द्वारा लिये गये दायित्वों के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है।
- भ. डी एस 98 कोरिया – डेयरी में जिस व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को यह दर्शाना है कि किस प्रकार से सुलहकर्ताओं को कुछ घटनाक्रमों का पूर्व में अनुमान नहीं लगाया गया था, जब भारत ने गैट के

अंतर्गत दायित्वों का निर्वाह किया। जिसके फलस्वरूप जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि हुई थी। यदि याचिकाकर्ताओं उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं तब निर्दिष्ट प्राधिकारी पर यह दायित्व बना रहता है कि वे उपर्युक्त विश्लेषण करें। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तब संबद्ध जांच को समाप्त कर दिया जायेगा।

- म. याचिकाकर्ताओं द्वारा पहचान किए गए घटनाक्रम ऐसा नहीं है जिसका गैट के अनुच्छेद XIX (1) (क) के तात्पर्य से पूर्व में अनुमान नहीं लगाया गया है। चीन में क्षमता, उत्पादन और निर्यात में तीव्र गति से विस्तार भारत में नवीकरणीय उर्जा के लिए मांग में वृद्धि का परिणाम है। याचिकाकर्ताओं ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि किस प्रकार से चीन में उत्पादकों की क्षमता, उत्पादन और निर्यात उन्मुखीकरण में विस्तार जांच की अवधि के दौरान आयातों में साल में, अचानक, तीव्र और पर्याप्त वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग एन एस एम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सृजित की गई है। यही एकमात्र कारण है जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है।
- य. याचिकाकर्ता यह दर्शाने में असफल रहे हैं कि किस प्रकार से चीन पर व्यापार निदान उपायों को लगाने के फलस्वरूप चीन का निर्यात परिवर्तित होकर भारतीय बाजार में हुआ है। निर्यातक किसी एक दिवस को निर्णय नहीं ले सकते हैं कि वे भारत में अपने निर्यात को परिवर्तित करेंगे क्योंकि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को अवरुद्ध कर दिया गया है। यदि राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय कोई निविदा नहीं निकालते हैं तब कोई भी पक्षकार संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति कर सकता है और इस प्रकार से कृषि स्रोत से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं होगा।
- र. यह तर्क कि पेरिस करार के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धता का पूर्व में अनुमान नहीं लगाया गया है हास्यास्पद है। भारत कृषि व्यापार संगठन में योगदान करने के बहुत पहले नवंबर 1993 में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेम वर्क सम्मेलन (यू एन एफ सी सी) की पुष्टि की है। इसके अंतर्गत भारत में दो प्रोटोकॉल नामतः 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल और 2016 में पेरिस करार पर हस्ताक्षर किया है। विश्व व्यापार संगठन में योगदान करते समय, भारत को यू एन एफ सी सी के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं की जानकारी थी।
- ल. आयातों में कोई हाल में, अचानक, तीव्र और पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है जो गैट के अनुच्छेद XIX (1) (क) के अंतर्गत आवश्यकता को पूरा करता हो। संबद्ध वस्तुओं का पिछली बार किए गए आयातों में अचानक उछाल देखा गया था और वह 2015-16 में हुआ था जिसके दौरान आयात में 228 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। इसके बाद 2016-17 में आयातों में केवल 52 प्रतिशत और 2017-18 वार्षिकी में केवल 49 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। एन एस एम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सृजित मांग आपूर्ति अंतर के कारण वृद्धि हुई है।
- व. याचिका किसी ऐसे दायित्व की पहचान नहीं करती है जिसे भारत द्वारा गैट के अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं के लिए प्रशुल्क रियायतों सहित किया गया हो जिसके फलस्वरूप आयातों में अचानक उछाल आया हो।
- श. याचिका और आरंभिक जांच परिणाम दो कथित दायित्वों की पहचान करता है जो भारत ने आई टी ए-1 के अंतर्गत प्रतिबद्धता की हो, जिसके फलस्वरूप सीमा शुल्क समाप्त हो गया हो और भारत ने डी एस 456 – भारत – सोलर सैल्स ने विश्व व्यापार संगठन के निर्णय का आदर किया है। उपर्युक्त दायित्वों में से कोई भी दायित्व प्रथमतः 2005 में आयात शुल्क के शून्य होने के कारण आयातों में हाल में, अचानक, शीघ्र और पर्याप्त वृद्धि हुई। परंतु याचिका और आरंभिक जांच परिणाम इस बात की पहचान नहीं कर पाता है कि किस प्रकार से गैट का यह दायित्व जो 12 वर्ष पहले लागू हुआ, के फलस्वरूप क्षति की अवधि के दौरान आयातों में हाल में, अचानक, तीव्र और पर्याप्त वृद्धि हुई। आयातों में 2005 के बाद कई वर्षों तक पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई। आयातों में भारत सरकार द्वारा एन एस एम शुरू किए जाने के बाद वृद्धि हुई। संबद्ध वस्तुओं के आयातों में इस वृद्धि के पीछे एकमात्र कारण यह है कि भारत ने और अधिक निविदाओं को निकालकर और बोलियों को आमंत्रित कर संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग सृजित की थी। दूसरा, याचिका और आरंभिक जांच परिणाम इस तथ्य को दर्शाने के लिए कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं करते हैं कि जैसे ही डी सी आर को निविदाओं से निकाल दिया गया था, संबद्ध वस्तुओं के आयातों में अचानक रूप से वृद्धि हुई। किसी आंकड़ों के बिना याचिकाकर्ता का तर्क विशुद्ध रूप से शैक्षणिक है। एम एन आर ई सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय उपक्रम योजना, जो इस व्यापार संगठन के अनुकूल भी है, के अंतर्गत डी सी आर लागू कर भारतीय उद्योग को समर्थन जारी रखने की योजना बनाता है।
- प. याचिकाकर्ताओं को रक्षोपाय नियमावली के अनुबंध के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 8ख(6)(ग) और नियम 8 के संदर्भ में कोई गंभीर क्षति नहीं हुई थी क्योंकि आयातों में वृद्धि 2016-17 की तुलना में अधिकांश हाल की अवधि में केवल 49 प्रतिशत तक थी। भारत में बहुत अधिक मांग है और घरेलू उद्योग की क्षमता कुल मांग का मात्र 15 प्रतिशत है। घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान क्रमशः 253 प्रतिशत और 305 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 2014-15 में 60 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 78 प्रतिशत हो गया है।

- स. मुंद्रा ने 2017 में उत्पादन शुरू किया जिसके फलस्वरूप 2017-18 (वार्षिक) ने संस्थापित क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन बहुत अच्छा है और यह बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निवेश करने के लिए तैयार है। क्षमता के उपयोग में गिरावट केवल अस्थायी है और इसमें समय के क्रम में उत्पादन को स्थिर रखने के साथ सुधार आयेगा।
- ह. प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में क्षति की अवधि के दौरान कई गुणा वृद्धि हुई है। स्वतंत्र रूप में मजदूरी और प्रति किलोवाट मजदूरी में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप लाभ में गिरावट आई है और यह क्षति का कारण हो सकता है। अन्य कारणों में संस्थापित क्षमता, ब्याज लागत और मूल्यह्रास लागत में वृद्धि शामिल है।
- क्ष. बिक्री की लागत और बिक्री कीमत 2014-15 में 100 सूचीबद्ध बिंदुओं से गिरकर 2017-18 (वार्षिक) में प्रत्येक में 84 सूचीबद्ध बिंदु तक पहुंच गई। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री की लागत के अनुरूप है। कीमत पर कोई दबाव नहीं पड़ा है। अगर घरेलू उद्योग पर आयात का कोई दबाव पड़ता तब बिक्री कीमत बहुत कम हो गई होती। इस कारण से कीमत पर कोई मंदी नहीं हुई है। निर्यात बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 2014-15 में 100 सूचीबद्ध बिंदुओं से 2017-18 (वार्षिक) में 56 सूचीबद्ध बिंदुओं तक गिरावट आई। क्षति का यही कारण है।
- त्र. इंडोसोलर के कार्य निष्पादन में वित्तीय वर्ष 2016-17 में पर्याप्त रूप से सुधार आया है। इसका राजस्व वित्तीय वर्ष 2016-17 में शीघ्र रूप में 44,231.09 लाख रुपए तक पहुंच गया और उसी अवधि में इसका घाटा कम होकर 8,322.91 लाख रुपए हो गया। यह उस अवधि में बहुत बड़ा सुधार है, जिसके दौरान इंडोसोलर ने याचिका में आयातों के कारण क्षति का दावा किया है। स्पष्ट रूप से, इंडोसोलर के क्षति के दावे को इसके अपने आंकड़ों के द्वारा समर्थन नहीं मिला है। इसके अलावा, इंडोसोलर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बेहतर कार्य निष्पादन का अनुमान लगाया है क्योंकि यह आशा करता है कि सरकार कुछ अनुकूल नीतियां अपनायेगी।
- ज. वेबसोल की वित्तीय स्थिति में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है। वास्तव में, वित्तीय वर्ष 2015-17 में 647.48 लाख रुपए के घाटे से, वेबसोल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 8594.36 लाख रुपए का भारी मुनाफा कमाया है। इसने अपनी कार्यशील पूंजी और सावधिक ऋण का भी भुगतान कर दिया है। वेबसोल ने अपनी सैल क्षमता का विस्तार 100 से 200 मेगावाट तक किया है और इसका उद्देश्य अपनी सैल लाइन क्षमता का विस्तार 280-300 मेगावाट और मॉड्यूल लाइन क्षमता का विस्तार 100 मेगावाट से 300 मेगावाट तक करने की है। ऐसी मजबूत वित्तीय स्थिति को देखते हुए, हम यह नहीं समझ पाते हैं कि किस प्रकार से वेबसोल संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण क्षति का दावा करता है।
- कक. वित्तीय वर्ष 2016-17 में जूपिटर सोलर ने 3,999 लाख रुपए का लाख दर्ज किया। यह कंपनी द्वारा आपवादिक कार्य निष्पादन है।
- खख. मुंद्रा ने लगभग एक वर्ष पहले 2017 में अपना उत्पादन शुरू किया। जब नई निर्माण सुविधा स्थापित की जाती है तब ब्रेक इवन प्राप्त करने में काफी समय लगता है। इसके अलावा, आरंभिक अवधि में भी उच्च ब्याज और मूल्यह्रास लागत शामिल होता है जो क्षति का संभावित कारण है।
- गग. हिलिय पीवी लिमि. लंबे समय तक कोरपोरेट ऋण पुनर्संरचना कर रहा था और उसने तुलन पत्र में बहुत अधिक देयताएं जमा कर ली हैं। यह इस कंपनी के घाटे के लिए कारण हो सकता है।
- घघ. कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है क्योंकि 2015-16 और 2017-18 (वार्षिक) ने लाभप्रदता में गिरावट की प्रत्यक्ष रूप से इस अवधि के दौरान संस्थापित क्षमता, निवल स्थाई परिसंपत्तियां और ब्याज लागत में अचानक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को क्षति निर्यात बाजार में बिक्री कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। घरेलू उद्योग को क्षति इस तथ्य के कारण भी हुई है कि यह अभी भी अप्रचलित प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। 19 दिसंबर, 2017 को हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित एक आर्टिकल में, एम एन आर ई ने यह उल्लेख किया कि 'देश में सैल/ मॉड्यूल निर्माण क्षमता अप्रचलित है'। याचिकाकर्ता आई एस एम ए और इंडोसोलर ने स्वीकार किया है कि भारतीय निर्माता प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश नहीं कर सके क्योंकि बाजार की कोई निश्चितता नहीं थी।
- ङङ. घरेलू उद्योग का क्षति का वास्तविक कारण अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा आक्रामक मूल्य निर्धारण रिवाज और न की आयात है। इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि ये संलग्न न्यूज आर्टिकल का संदर्भ लें जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अदानी ग्रीन एनर्जी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, टाटा पावर सोलर और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे भारतीय उत्पादकों ने एक साथ 30 सेंट/ के डब्ल्यू एच क्षमता की रिकार्ड न्यूनतम कीमत (2.63

प्रति के डब्ल्यू एच) पर एनर्जी एफिसियेंसी सर्विस (ई ई एस एल) को 300 मेगावाट सोलर पैनल बेचा है जो अच्छी कोटि के चीन के सोलर पैनलों की दर की तुलना में सस्ता है। यह दर्शाता है कि याचिकाकर्त्ता और अन्य भारतीय उत्पादकों के बीच कीमत युद्ध घरेलू उद्योग को क्षति का वास्तविक कारण और न कि संबद्ध वस्तुओं का कथित आयात है।

- च. आवश्यकता के रूप में, घरेलू उद्योग को याचिका में यह दर्शाने के लिए एक समायोजन योजना उपलब्ध कराना है कि किस प्रकार से उनकी योजना रक्षोपाय की कार्य अवधि के दौरान समायोजित करने का है। याचिकाकर्त्ताओं ने अपनी अलग अलग समायोजन योजनाओं पर गोपनीयता का दावा किया है जो किसी सार्थक टिप्पणियां करने के लिए इसे कठिन बनाता है। इसके अलावा, याचिका का एन सी बी समायोजन योजना के संबंध में अस्पष्ट सूचना ही देता है। याचिकाकर्त्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे संरचनात्मक समायोजनाओं के संबंध में अपनी योजनाओं को लिखित अनुरोधों में स्पष्ट करें कि प्रत्येक याचिकाकर्त्ता का प्रयास रक्षोपाय नियमावली के नियम 11(3) के परंतु के साथ पथित एओएस के आर्टिकल 7.1 के संबंध में करने का है।
- छ. हालांकि, याचिका में उपलब्ध सूचना के आधार पर याचिकाकर्त्ता यह दावा करता है कि वे बैकवर्ड समेकन अर्थात् वेपरों और इनगोट्स का निर्माण करने के लिए संयंत्रों को स्थापित कर उत्पादन में किफायत को प्राप्त कर लेंगे। हालांकि, ऐसा तरीका अपनाने के फलस्वरूप अगले कुछ वर्षों में उसमें कटौती आयातों के प्रति समायोजन करने की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लागत हो जायेगी। इस कारण से इस प्रकार की समायोजन योजना संभव और व्यवहारिक नहीं है।
- ज. आयात जो हाल के बोलियों फलस्वरूप होता है, ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं अथवा लगभग 9000 मेगावाट की विद्युत खरीद करारों पर हस्ताक्षर रक्षोपाय शुल्क लगाने के पूर्व किया गया है, को शुल्क की परिधि छूट प्रदान की जाये।
- झ. एम एन आर ई ने 12000 मेगावाट की सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय उपक्रम योजना की एक अतिरिक्त योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। जिसमें एक आश्वस्त डी सी आर संघटक होता। यह घरेलू उद्योग को एक आश्वस्त बाजार उपलब्ध करायेगा। इस कारण से घरेलू उद्योग को भी गंभीर क्षति का भविष्य में कोई खतरा नहीं है।
- ञ. घरेलू उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता से 2017-18 (वार्षिक) के दौरान सोलर पावर के लिए भारतीय मांग का केवल 10 प्रतिशत पूरा कर सकता है। शेष को आयातों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।
- ट. जांच के अधीन अवधि में आयातों का हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन 86 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत तक हो गया – जिसे एक व्यापक विकास बमुश्किल कहा जा सकता है।
- ठ. कोई गंभीर क्षति और कारणात्मक संबंध नहीं है। क्योंकि घरेलू उद्योग की जांच के अधीन अवधि के लिए 16 प्रतिशत की दर से एबिटडा मार्जिन शीर्ष वैश्विक निर्माताओं के लिए एबिटडा मार्जिन की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत अधिक है। यह दर्शाता है कि उच्चतर पूंजी व्यय/ ब्याज लागतों के कारण उच्च ब्याज बोझ न कि आयात इसके लिए दोषी है।
- ड. याचिकाकर्त्ता एम एन आर ई आंकड़ों के अनुसार नियंत्रण अवधि के अधिकांश हिस्से तक घरेलू उद्योग का 51 प्रतिशत नहीं होता है। इसके अलावा, यदि घरेलू उद्योग में विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों को शामिल नहीं किया जाता है, जैसा कि 2016 और 2012 में महानिदेशालय के रक्षोपाय जांचों में माना गया है, तब याचिकाकर्त्ता आवश्यक 51 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है।
- ढ. आयातों के कारण उर्जा के इस नवीकरणीय स्रोत का संवर्द्धन करने के लिए भारत सरकार की दृष्टि के कारण और न कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य द्वारा व्यापार उपायों को लगाने तथा डी सी आर की संरक्षणवादी परिधि की हानि अथवा आई टी ए-1 के अंतर्गत भारत के दायित्व के घटनाक्रमों का पूर्व में अनुमान नहीं लगा सकने के कारण वृद्धि हुई। सरकार इस बात की पूरी जानकारी थी कि भारतीय निर्माता भारत में मांग का 10 प्रतिशत से कम को ही पूरा कर सकता है। यदि सरकार ने मांग सृजित नहीं की होती, तब आयात नहीं हुआ होता बल्कि एन एस एम में घरेलू और वैश्विक कंपनियों की भागीदारी पर विचार किया गया है ताकि सर्वोत्तम और सबसे उन्नत सोलर सैल और मॉड्यूल 2022 तक 175 गीगावाट सोलर ग्रिड संयोजकता के मिशन को पूरा करता है। विद्वान महानिदेशक ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग को हानि उठानी पड़ रही है। इसके विपरीत उस अवधि के लिए घरेलू उद्योग के आंकड़े चालू पाटनरोधी जांच में लाभ को दर्शाते हैं, यह एक गंभीर असंतुलन है। इसके अलावा, महानिदेशक (रक्षोपाय) (उपयोगिता 78 प्रतिशत से गिरकर 51 प्रतिशत हो गई) को उनकी अपनी वार्षिक रिपोर्टों में उनके विवरणों में उपलब्ध कराई गई सूचना में विसंगतियां हैं।

- ण. घरेलू उद्योग रक्षोपाय याचिका में मैसर्स मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड को जोड़े जाने के कारण घाटे की तस्वीर पेश कर सकता है। याचिकाकर्ता ने नई निर्माण सुविधा स्थापित की है और इस नई सुविधा के साथ उच्च ब्याज और मूल्यहास लागत आती है। इस कंपनी को क्षति आयातों के कारण नहीं बल्कि उच्च ब्याज और मूल्यहास लागत के कारण होती है।
- तत. 3 घरेलू उद्योगों ने वित्तीय वर्ष 2015 से 18.2 प्रतिशत के सी ए जी आर पर राजस्व की सूचना दी है और औसत एबिडटा मार्जिन में 2016 में 9.4 प्रतिशत से सुधार होकर 2017 में 22.3 प्रतिशत हो गया है।
- थथ. हिलिअस पी वी प्रा. लिमि. (पूर्व में मोजर बेयर) के लिए आंकड़ों को निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कंपनी सीडी, विद्युत में निवेश सहित विभिन्न उत्पादों के निर्माण में लगा हुआ है और 2008 से घाटे उठा रहा है। कंपनी का लंबे समय से कोरपोरेट ऋण पुनर्संरचना हो रही थी और तुलन पत्र में इसकी देयताएं बहुत अधिक हैं और इस कारण से इनके आंकड़ों पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- दद. यह स्पष्ट है कि सैल निर्माता को प्रचालन स्तर पर बहुत अधिक लाभ मार्जिन मिलता है जो इस बात का एक सांकेतिक है कि क्या आयातों के कारण घरेलू उद्योगों को क्षति हो रही है अथवा नहीं। उनके घाटे प्रति मेगावाट बहुत अधिक पूंजी लागत, उच्च ब्याज लागत और प्रबंधन की क्षमताओं के कारण है।
- धध. घरेलू उद्योग वर्ष 2017 में पूरी की गई पर्याप्त किस्तों के साथ कुल सैल क्षमता का 56 प्रतिशत की प्रचालनगत क्षमता है। वर्ष 2016 के दौरान घरेलू उद्योग 49.7 प्रतिशत की प्रचालन संबंधी सैल क्षमता का निर्माण करता है।
- नन. इसके अलावा, सोलर निर्माण में सैल और मॉड्यूल दोनों के निर्माण को शामिल किया जाना चाहिए। 2017 में घरेलू उद्योग का भारत की कुल सैल निर्माण क्षमता का 56 प्रतिशत था जबकि इसका 31 मई, 2017 को समाप्त अवधि के लिए भारत की कुल मॉड्यूल निर्माण क्षमता का केवल 2.6 प्रतिशत था।
- पप. इसके अलावा, दिसंबर 2017 में एम एन आर ई ने एक वक्तव्य दिया है कि भारतीय निर्माता की संस्थापित क्षमता अप्रचलित है और यह सरकारी सहायता के रूप में 11,000 करोड़ भारतीय रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव करता है।
- फफ. विद्वान महानिदेशक का यह निष्कर्ष की यदि अनंतिम रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाता है तब गंभीर क्षति होगी, सही नहीं है। एम एन आर ई की योजना 12,000 मेगावाट की सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम योजना के माध्यम डी सी आर सहायता जारी रखने की है। इस कारण से कोई नाजुक स्थितियां नहीं हैं।
- बब. महानिदेशक (रक्षोपाय) ने पूर्व में यह फैसला दिया है (2016 और 2012) की विशेष आर्थिक क्षेत्र एककों को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- भभ. विशेष आर्थिक क्षेत्र एककों को भारत से बाहर के रूप में माना जाना चाहिए जैसा कि "अनराउथ एल्मूनियम (वह एल्मूनियम जो एलॉड और एल्मूनियम एलॉय नहीं है)" के आयातों पर अप्रैल 2016 में रक्षोपाय शुल्क लगाने के मामले में माना गया था।

(xvi) मैसर्स अवादा लिमि.

- क. हितबद्ध पक्षकारों को जांच आरंभन सूचना के अनुसार अपने विचारों से अवगत कराने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था परंतु प्रारंभिक जांच परिणाम हमारे द्वारा अपने विचारों को अवगत कराने के पूर्व जारी कर दिया गया था।
- ख. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की क्योंकि पाटनरोधी जांच अंतिम निर्णय के चरण में और अपुष्ट आधारों पर वापस लिया गया था। पाटनरोधी शुल्क समाप्ति आदेश के पैरा 18 और 21 के अनुसार, घरेलू उद्योग में जांच की अवधि के दौरान हुई क्षति में परिवर्तन होना अवश्यभावी है और यदि याचिकाओं को इस आधार पर वापस लेना शुरू हो जाता है, तब इसके फलस्वरूप अराजक की स्थिति पैदा हो जायेगी।
- ग. निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास पाटनरोधी शुल्क जांच और चालू रक्षोपाय याचिका और जांच अवधि अतिच्छादन से आंकड़े प्राप्त हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात की जांच करने के लिए इन दो आंकड़ों के समुच्चय की तुलना कर सकता है कि क्या रक्षोपाय याचिका में कोई विशेषता है।
- घ. 5 जनवरी, 2018 को 70 प्रतिशत अनंतिम रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश के कारण वास्तव में एक अराजक की स्थिति पैदा हो गई है। भारत की राज्य सरकार द्वारा अनेक सोलर निविदाओं को इन शुल्कों पर अनिश्चितता के कारण बोली लगाने वाले से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

- ड. चरण III में 2022 तक 80 जी डब्ल्यू का सोलर मिशन लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, प्रतिवर्ष 20 जी डब्ल्यू की औसत वार्षिक संस्थापना अवश्य होनी चाहिए। सोलर सैल (3164 एम डब्ल्यू/ प्रतिवर्ष) और सोलर मॉड्यूल (8398 एम डब्ल्यू/ प्रतिवर्ष) की वर्तमान घरेलू निर्माण क्षमता शपथ रूप से इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- च. वितरण कंपनियों जो सोलर उर्जा के अंतिम क्रेता हैं, में स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है यदि लागत प्रति के डब्ल्यू एच 3 रुपए के नीचे रहता है तभी वे सोलर उर्जा खरीदेंगे। आसन्न रक्षोपाय शुल्कों के आलोक में, यह विकासकर्ता के लिए संभव नहीं होगा कि वे इस शुल्क को दें, जो प्रति के डब्ल्यू एच 3 रुपए से कम है और उससे यह वाणिज्यिक रूप से असंभव हो जाता है कि वे बोलियों और परियोजनाओं में भाग लें तथा इस प्रकार कम शुल्क दें।
- यद्यपि निश्चयात्मक रक्षोपाय शुल्क 12-15 सेंट प्रति वाट है जो विनियम दर पर निर्भर करते हुए 8-11 भारतीय रुपए तक शुल्क में वृद्धि होगी और उससे यह शुल्क बढ़कर लगभग 4 रुपए प्रति के डब्ल्यू एच तक पहुंच जायेगा। इस दर से सोलर उर्जा अप्रतिस्पर्धी हो जायेगा और विकासकर्ता चालू परियोजनाओं को भी छोड़ देंगे। संलग्न रिपोर्ट इस बात को सिद्ध करती है कि सोलर पावर शुल्क प्रति के डब्ल्यू एच 3 भारतीय रुपए से कम है और इसमें ग्रिड समता प्राप्त कर ली है।
- छ. सोलर पावर ग्रिड की समता को अस्त व्यस्त करने से विकासकर्ताओं और अंतिम ग्राहकों दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ता की यह गणना कि 20 सेंट का मामूली शुल्क लगाने से बिजली के शुल्क में 70 पैसे प्रति वाट की वृद्धि होगी, सही नहीं है। 12 – 15 सेंट तक शुल्क से पर्याप्त रूप से प्रशुल्क में वृद्धि होगी, जिसे ऊपर दर्शाया गया है।
- ज. अनेक विद्युत खरीद करार परियोजना के विकासकर्ताओं और वितरण कंपनियों के बीच किया गया है और 9000 मेगावाट तथा 18000 मेगावाट की क्षमता वाली वितरण कंपनियों को आवंटन के लिए निविदा भी दे दी गई है। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए अपेक्षित आयात अभी शुरू होने हैं और लगान के अधीन हैं तथा रक्षोपाय शुल्क लगाने से इन आयातों पर प्रभाव पड़ेगा और उस से विद्युत प्रशुल्कों में वृद्धि होगी।
- झ. रक्षोपाय लगाना उत्पादना के प्रतिकूल होगा और इसका एन एस एम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि प्रशुल्कों में वृद्धि को कभी भी राज्य वितरण कंपनियों द्वारा खपाया नहीं जा सकेगा।
- ञ. अप्रैल 2018 में, एम एन आर ई ने सोलर परियोजनाओं के लिए बोली लगाने संबंधी मानदंडों में “कानून में परिवर्तन” के संदर्भ में इस धारा के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जिसके द्वारा उक्त धारा में शुल्कों और उपकर को शामिल किया गया है। यद्यपि विचार किए जाने के लिए रक्षोपाय शुल्क को पास-श्रू के रूप में लिया जाना है, उसकी अभी जांच की जानी है और विनियामक प्रक्रिया के अंतर्गत उसे सिद्ध किया जाना है। यह नोट किया जाना है कि कोई भी ओफ-टेकर पास-श्रू तंत्र के अंतर्गत इस प्रभावको सहने नहीं जा रहा है और उसका संपूर्ण सोलर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पास-श्रू की प्रक्रिया भी बहुत अनिश्चित, लंबी और जटिल है और यदि शुल्क लगाया जाता है तब चालू परियोजनाओं का संरक्षण करने का कोई आश्वासन नहीं देता है। वर्तमान औसत प्रशुल्क 2.75 भारतीय रुपए प्रति के डब्ल्यू एच के साथ, इन प्रशुल्कों पर 35-40 प्रतिशत तक प्रभाव पड़ने की संभावना है। यदि शुल्क लगाया जाये और यह किसी वितरण कंपनी हो आगे आने के लिए आकर्षित नहीं करेगा और 3 भारतीय रुपए से अधिक पर विद्युत का विक्री संबंधी करार हो पायेगा। इस प्रकार से संपूर्ण मिशन असफल हो जायेगा और सोलर उद्योग, एक दूसरे पर निर्भर एम एस एम ई, नौकरियां और बैंक के कर्जों का भुगतान न करने पर सौर उद्योग समाप्त हो जायेगा।
- ट. रक्षोपाय शुल्क 1,00,000 करोड़ भारतीय रुपए से अधिक की सोलर बिजली परियोजनाओं को खतरे में डाल देगा क्योंकि हमारे सदस्यों ने पहले ही लगभग 27 जी डब्ल्यू चालू परियोजनाओं के लिए करार किया है।
- ठ. रक्षोपाय के संबंध में अनिश्चितता के कारण, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हाल में लगाई गई बोलियों में प्रशुल्कों में लगभग 20-25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारा विश्लेषण यह दर्शाता है कि भावी सौर उर्जा परियोजनाओं के लिए प्रशुल्कों में 40 प्रतिशत से अधिक तक वृद्धि हो सकती है और यह गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित बोलियों में हाल में पाये गये 2.98 भारतीय रुपए प्रति यूनिट और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित बोलियों में पाये गये 2.71 भारतीय रुपए प्रति यूनिट के बजाय लगभग 4 भारतीय रुपए प्रति यूनिट तक हो जायेगा। इस वृद्धि का अंतिम उपभोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ड. घरेलू उद्योग आकार, प्रौद्योगिकी के उन्नयन में निवेशों की कमी के मामले में कमजोर है जिसके फलस्वरूप भारत में उत्पादित सोलर सैल और मॉड्यूल की कार्यक्षमता में कमी आती है। घरेलू उद्योग मॉड्यूल में सोलर सैल की एसेंबली मात्र तक सीमित है जो समग्र मूल्य श्रृंखला में अंतिम चरण है। चीन से सिलीकॉन इनगोट्स, वेफर्स और सैल्स को

आयात करने पर निर्भरता भारत के निर्माण को सोलर निर्माण में अन्य एशियाई बड़ी कंपनियों से अप्रतिस्पर्धी रचना जारी रहेगी।

- ड. भारत सरकार घरेलू उद्योग को अन्य प्रोत्साहन राशि जैसे कम ब्याज पर ऋण देने पर विचार कर सकती है। रक्षोपाय लगाना परियोजना विकासकर्ताओं और अंतिम उपभोक्ताओं जिन्हें अपेक्षाकृत अधिक प्रशुल्कों का भुगतान करना होगा, पर इसके स्पिल ओवर प्रभाव पर विचार करते हुए सर्वोत्तम विकल्प नहीं हो सकता है।
- ण. निम्नलिखित उत्पादों उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए -
- (v) पी ई आर सी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सोलर सैल्स
 - (vi) थिन फिल्मस एंड बाई फेसियल एन प्रकार के सोलर सैल्स
 - (vii) 5 और 6 बस बार उत्पादन शब्दावली का उपयोग करते हुए अत्यधिक कार्यक्षम सोलर और
 - (viii) बोना सियस्टलाइंग प्रौद्योगिकी का सोलर मॉड्यूल
- त. याचिकाकर्ता ने याचिका में यह मान लिया है कि वे थिन फिल्म सोलर सैल्स और मॉड्यूल का निर्माण नहीं कर सकता है। इसके अलावा, उन्होंने समायोजन योजना में यह दावा किया है कि वे पी ई आर सी आधारित सैल्स का निर्माण करते रहेंगे। इस प्रकार से, स्वीकार्य रूप में, याचिकाकर्ता वर्तमान में इन सैलों का निर्माण नहीं कर सकता है। हमें मालूम है और यह सामान्य ज्ञान है कि याचिकाकर्ता 5 और 6 बस बार उत्पादन शब्दावली का उपयोग करते हुए और मोनो-क्रिस्टलाइन प्रौद्योगिकी पर सोलर सैल्स का निर्माण नहीं कर सकता है। किसी घरेलू उद्योग इन वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता है अतः उन्हें इस्पात के कार्यक्षेत्र से तत्काल बाहर किया जाना चाहिए।
- थ. याचिकाकर्ता कंपनियों के पास सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख (6) (ख) के साथ कथित रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.1 (ग) के संबंध में वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
- द. याचिकाकर्ता के आधार की जांच हिलियस पी वी लिमि. के लिए आंकड़ों पर विचार किए बिना सोलर सैलों और सोलर मॉड्यूल के लिए पृथक रूप से की जानी चाहिए क्योंकि उनके आंकड़े एम एन आर ई के पास उपलब्ध नहीं हैं। सोलर मॉड्यूल के लिए याचिकाकर्ताओं की कुल संस्थापित क्षमता भारतीय उत्पादन क्षमता में से कुल का मात्र 15 प्रतिशत है। इस प्रकार से याचिकाकर्ताओं के पास सोलर मॉड्यूल में घरेलू उद्योग के रूप में कोई आधार नहीं है। इसके अलावा, सैल और मॉड्यूल की मिश्रित क्षमता भारत के कुल संस्थापित क्षमता में 26.5 प्रतिशत है। अतः सैल और मॉड्यूल दोनों के लिए घरेलू उद्योग के रूप में आधार मौजूद नहीं है।
- ध. याचिका में कुल भारतीय उत्पादन के आंकड़े सही नहीं हैं क्योंकि यह अपनी पूर्णता में अन्य उत्पादकों के उत्पादन पर विचार नहीं करता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि सभी अन्य उत्पादक संबद्ध वस्तुओं के आयातक हैं। इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है और इस प्रकार से इसमें कोई विशेषता नहीं है। एम एन आर ई के आंकड़ों पर इस मामले में घरेलू उद्योग के आधार की जांच करने के लिए विचार किया जाना चाहिए।
- न. इस जांच में दो वस्तु नामतः सोलर सैल और सोलर मॉड्यूल शामिल हैं। घरेलू उद्योग के आधार का आकलन करते समय डी जी टी आर से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उन सोलर सैल्स और मॉड्यूल के निर्माताओं, जिन्होंने क्षति की अवधि के दौरान क्रमशः सोलर सैल्स और मॉड्यूल का आयात किया था, को बाहर कर दें।
- प. जब दो उत्पाद एक ही जांच के अध्वधीन हों, तब निर्दिष्ट प्राधिकारी पृथक रूप से घरेलू उद्योग के आधार की जांच करने की सतत् प्रथा का पालन करते हैं। ऐसा निम्नलिखित जांचों में किया गया है :
- (iii) चीन जन. गण. और मेक्सिको से पेनेसिलिन-जी पोटेसियम और 6-ए पी ए का आयात। अंतिम जांच परिणाम दिनांक 20 जनवरी, 2011 के अधिसूचना संख्या 14/19/2009 – डी जी ए डी के द्वारा जारी किया गया है।
 - (iv) चीन जन. गण. से फ्रंट एक्सेल वीम्स और स्ट्रेयरिंग नकल्स का आयात। अंतिम जांच परिणाम दिनांक 05 मार्च, 2010 के अधिसूचना संख्या 14/19/2008 – डी जी ए डी के द्वारा जारी किया गया है।
- फ. इसके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित याचिकाकर्ताओं को आधार से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि उनका प्राथमिक लक्ष्य निर्यात बाजार की मांग को पूरा करना है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के मामले में दिनांक 27 सितंबर, 2012 के महानिदेशालय के रक्षोपायों के अंतिम जांच परिणामों में, डब्ल्यू एस आई उद्योग (विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित) को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। जैसे ही विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों को बाहर कर दिया गया हो, तब शेष याचिकाकर्ताओं की संख्या भारत में वार्षिक मांग की तुलना में बहुत कम (कुछ सैकड़ा मेगावाट) रह जायेगा।

- ब. गैट के अनुच्छेद XIX(1) (क) के अंतर्गत दायित्व के अनुसरण में, भारत तब तक रक्षोपाय शुल्क नहीं लगा सकता है जब तक निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार यह दर्शाया नहीं जा सके कि बढ़ा हुआ आयात और परिणामी क्षति पूर्व में अनुमान न लगाये जाने वाले घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप तथा गैट के अंतर्गत भारत द्वारा लिये गये दायित्वों के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है।
- भ. डी एस 98 कोरिया – डेयरी में जिस व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय के अनुसार, याचिकाकर्त्ताओं को यह दर्शाना है कि किस प्रकार से सुलहकर्त्ताओं को कुछ घटनाक्रमों का पूर्व में अनुमान नहीं लगाया गया था, जब भारत ने गैट के अंतर्गत दायित्वों का निर्वाह किया। जिसके फलस्वरूप जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि हुई थी। यदि याचिकाकर्त्ताओं उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं तब निर्दिष्ट प्राधिकारी पर यह दायित्व बना रहता है कि वे उपर्युक्त विश्लेषण करें। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तब संबद्ध जांच को समाप्त कर दिया जायेगा।
- म. याचिकाकर्त्ताओं द्वारा पहचान किए गए घटनाक्रम ऐसा नहीं है जिसका गैट के अनुच्छेद XIX (1) (क) के तात्पर्य से पूर्व में अनुमान नहीं लगाया गया है। चीन में क्षमता, उत्पादन और निर्यात में तीव्र गति से विस्तार भारत में नवीकरणीय उर्जा के लिए मांग में वृद्धि का परिणाम है। याचिकाकर्त्ताओं ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि किस प्रकार से चीन में उत्पादकों की क्षमता, उत्पादन और निर्यात उन्मुखीकरण में विस्तार जांच की अवधि के दौरान आयातों में साल में, अचानक, तीव्र और पर्याप्त वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग एन एस एम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सृजित की गई है। यही एकमात्र कारण है जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है।
- य. याचिकाकर्त्ता यह दर्शाने में असफल रहे हैं कि किस प्रकार से चीन पर व्यापार निदान उपायों को लगाने के फलस्वरूप चीन का निर्यात परिवर्तित होकर भारतीय बाजार में हुआ है। निर्यातक किसी एक दिवस को निर्णय नहीं ले सकते हैं कि वे भारत में अपने निर्यात को परिवर्तित करेंगे क्योंकि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को अवरोद्ध कर दिया गया है। यदि राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय कोई निविदा नहीं निकालते हैं तब कोई भी पक्षकार संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति कर सकता है और इस प्रकार से कृषि स्रोत से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं होगा।
- र. यह तर्क कि पेरिस करार के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धता का पूर्व में अनुमान नहीं लगाया गया है हास्यास्पद है। भारत कृषि व्यापार संगठन में योगदान करने के बहुत पहले नवंबर 1993 में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेम वर्क सम्मेलन (यू एन एफ सी सी) की पुष्टि की है। इसके अंतर्गत भारत में दो प्रोटोकॉल नामतः 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल और 2016 में पेरिस करार पर हस्ताक्षर किया है। विश्व व्यापार संगठन में योगदान करते समय, भारत को यू एन एफ सी सी के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं की जानकारी थी।
- ल. आयातों में कोई हाल में, अचानक, तीव्र और पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है जो गैट के अनुच्छेद XIX (1) (क) के अंतर्गत आवश्यकता को पूरा करता हो। संबद्ध वस्तुओं का पिछली बार किए गए आयातों में अचानक उछाल देखा गया था और वह 2015-16 में हुआ था जिसके दौरान आयात में 228 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। इसके बाद 2016-17 में आयातों में केवल 52 प्रतिशत और 2017-18 वार्षिकी में केवल 49 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। एन एस एम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सृजित मांग आपूर्ति अंतर के कारण वृद्धि हुई है।
- व. याचिका किसी ऐसे दायित्व की पहचान नहीं करती है जिसे भारत द्वारा गैट के अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं के लिए प्रशुल्क रियायतों सहित किया गया हो जिसके फलस्वरूप आयातों में अचानक उछाल आया हो।
- श. याचिका और आरंभिक जांच परिणाम दो कथित दायित्वों की पहचान करता है जो भारत ने आई टी ए-1 के अंतर्गत प्रतिबद्धता की हो, जिसके फलस्वरूप सीमा शुल्क समाप्त हो गया हो और भारत ने डी एस 456 – भारत – सोलर सैल्स ने विश्व व्यापार संगठन के निर्णय का आदर किया है। उपर्युक्त दायित्वों में से कोई भी दायित्व प्रथमतः 2005 में आयात शुल्क के शून्य होने के कारण आयातों में हाल में, अचानक, शीघ्र और पर्याप्त वृद्धि हुई। परंतु याचिका और आरंभिक जांच परिणाम इस बात की पहचान नहीं कर पाता है कि किस प्रकार से गैट का यह दायित्व जो 12 वर्ष पहले लागू हुआ, के फलस्वरूप क्षति की अवधि के दौरान आयातों में हाल में, अचानक, तीव्र और पर्याप्त वृद्धि हुई। आयातों में 2005 के बाद कई वर्षों तक पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई। आयातों में भारत सरकार द्वारा एन एस एम शुरू किए जाने के बाद वृद्धि हुई। संबद्ध वस्तुओं के आयातों में इस वृद्धि के पीछे एकमात्र कारण यह है कि भारत ने और अधिक निविदाओं को निकालकर और बोलियों को आमंत्रित कर संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग सृजित की थी। दूसरा, याचिका और आरंभिक जांच परिणाम इस तथ्य को दर्शाने के लिए कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं करते हैं कि जैसे ही डी सी आर को निविदाओं से निकाल दिया गया था, संबद्ध वस्तुओं के आयातों में अचानक रूप से वृद्धि हुई। किसी आंकड़ों के बिना याचिकाकर्त्ता का तर्क विशुद्ध रूप से शैक्षणिक है। एम एन आर ई सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय उपक्रम योजना, जो इस

व्यापार संगठन के अनुकूल भी है, के अंतर्गत डी सी आर लागू कर भारतीय उद्योग को समर्थन जारी रखने की योजना बनाता है।

- प. याचिकाकर्ताओं को रक्षोपाय नियमावली के अनुबंध के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 8ख(6)(ग) और नियम 8 के संदर्भ में कोई गंभीर क्षति नहीं हुई थी क्योंकि आयातों में वृद्धि 2016-17 की तुलना में अधिकांश हाल की अवधि में केवल 49 प्रतिशत तक थी। भारत में बहुत अधिक मांग है और घरेलू उद्योग की क्षमता कुल मांग का मात्र 15 प्रतिशत है। घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान क्रमशः 253 प्रतिशत और 305 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 2014-15 में 60 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 78 प्रतिशत हो गया है।
- स. मुंद्रा ने 2017 में उत्पादन शुरू किया जिसके फलस्वरूप 2017-18 (वार्षिक) ने संस्थापित क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन बहुत अच्छा है और यह बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निवेश करने के लिए तैयार है। क्षमता के उपयोग में गिरावट केवल अस्थायी है और इसमें समय के क्रम में उत्पादन को स्थिर रखने के साथ सुधार आयेगा।
- ह. प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में क्षति की अवधि के दौरान कई गुणा वृद्धि हुई है। स्वतंत्र रूप में मजदूरी और प्रति किलोवाट मजदूरी में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप लाभ में गिरावट आई है और यह क्षति का कारण हो सकता है। अन्य कारणों में संस्थापित क्षमता, ब्याज लागत और मूल्यह्रास लागत में वृद्धि शामिल है।
- क्ष. बिक्री की लागत और बिक्री कीमत 2014-15 में 100 सूचीबद्ध बिंदुओं से गिरकर 2017-18 (वार्षिक) में प्रत्येक में 84 सूचीबद्ध बिंदु तक पहुंच गई। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री की लागत के अनुरूप है। कीमत पर कोई दबाव नहीं पड़ा है। अगर घरेलू उद्योग पर आयात का कोई दबाव पड़ता तब बिक्री कीमत बहुत कम हो गई होती। इस कारण से कीमत पर कोई मंदी नहीं हुई है। निर्यात बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 2014-15 में 100 सूचीबद्ध बिंदुओं से 2017-18 (वार्षिक) में 56 सूचीबद्ध बिंदुओं तक गिरावट आई। क्षति का यही कारण है।
- त्र. इंडोसोलर के कार्य निष्पादन में वित्तीय वर्ष 2016-17 में पर्याप्त रूप से सुधार आया है। इसका राजस्व वित्तीय वर्ष 2016-17 में शीघ्र रूप में 44,231.09 लाख रुपए तक पहुंच गया और उसी अवधि में इसका घाटा कम होकर 8,322.91 लाख रुपए हो गया। यह उस अवधि में बहुत बड़ा सुधार है, जिसके दौरान इंडोसोलर ने याचिका में आयातों के कारण क्षति का दावा किया है। स्पष्ट रूप से, इंडोसोलर के क्षति के दावे को इसके अपने आंकड़ों के द्वारा समर्थन नहीं मिला है। इसके अलावा, इंडोसोलर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बेहतर कार्य निष्पादन का अनुमान लगाया है क्योंकि यह आशा करता है कि सरकार कुछ अनुकूल नीतियां अपनायेगी।
- ज. वेबसोल की वित्तीय स्थिति में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है। वास्तव में, वित्तीय वर्ष 2015-17 में 647.48 लाख रुपए के घाटे से, वेबसोल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 8594.36 लाख रुपए का भारी मुनाफा कमाया है। इसने अपनी कार्यशील पूंजी और सावधिक ऋण का भी भुगतान कर दिया है। वेबसोल ने अपनी सैल क्षमता का विस्तार 100 से 200 मेगावाट तक किया है और इसका उद्देश्य अपनी सैल लाइन क्षमता का विस्तार 280-300 मेगावाट और मॉड्यूल लाइन क्षमता का विस्तार 100 मेगावाट से 300 मेगावाट तक करने की है। ऐसी मजबूत वित्तीय स्थिति को देखते हुए, हम यह नहीं समझ पाते हैं कि किस प्रकार से वेबसोल संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण क्षति का दावा करता है।
- कक. वित्तीय वर्ष 2016-17 में जूपिटर सोलर ने 3,999 लाख रुपए का लाख दर्ज किया। यह कंपनी द्वारा आपवादिक कार्य निष्पादन है।
- खख. मुंद्रा ने लगभग एक वर्ष पहले 2017 में अपना उत्पादन शुरू किया। जब नई निर्माण सुविधा स्थापित की जाती है तब ब्रेक इवन प्राप्त करने में काफी समय लगता है। इसके अलावा, आरंभिक अवधि में भी उच्च ब्याज और मूल्यह्रास लागत शामिल होता है जो क्षति का संभावित कारण है।
- गग. हिलिय पीवी लिमि. लंबे समय तक कोरपोरेट ऋण पुनर्संरचना कर रहा था और उसने तुलन पत्र में बहुत अधिक देयताएं जमा कर ली हैं। यह इस कंपनी के घाटे के लिए कारण हो सकता है।
- घघ. कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है क्योंकि 2015-16 और 2017-18 (वार्षिक) ने लाभप्रदता में गिरावट की प्रत्यक्ष रूप से इस अवधि के दौरान संस्थापित क्षमता, निवल स्थाई परिसंपत्तियां और ब्याज लागत में अचानक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को क्षति निर्यात बाजार में बिक्री कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। घरेलू उद्योग को क्षति इस तथ्य के कारण

भी हुई है कि यह अभी भी अप्रचलित प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। 19 दिसंबर, 2017 को हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित एक आर्टिकल में, एम एन आर ई ने यह उल्लेख किया कि 'देश में सैल/मॉड्यूल निर्माण क्षमता अप्रचलित है'। याचिकाकर्ता आई एस एम ए और इंडोसोलर ने स्वीकार किया है कि भारतीय निर्माता प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश नहीं कर सके क्योंकि बाजार की कोई निश्चितता नहीं थी।

- ड. घरेलू उद्योग का क्षति का वास्तविक कारण अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा आक्रामक मूल्य निर्धारण रिवाज और न की आयात है। इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि ये संलग्न न्यूज आर्टिकल का संदर्भ ले जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अदानी ग्रीन एनर्जी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, टाटा पावर सोलर और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे भारतीय उत्पादकों ने एक साथ 30 सेंट/ के डब्ल्यू एच क्षमता की रिकार्ड न्यूनतम कीमत (2.63 प्रति के डब्ल्यू एच) पर एनर्जी एफिसियेंसी सर्विस (ई ई एस एल) को 300 मेगावाट सोलर पैनल बेचा है जो अच्छी कोटि के चीन के सोलर पैनलों की दर की तुलना में सस्ता है। यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता और अन्य भारतीय उत्पादकों के बीच कीमत युद्ध घरेलू उद्योग को क्षति का वास्तविक कारण और न कि संबद्ध वस्तुओं का कथित आयात है।
- च. आवश्यकता के रूप में, घरेलू उद्योग को याचिका में यह दर्शाने के लिए एक समायोजन योजना उपलब्ध कराना है कि किस प्रकार से उनकी योजना रक्षोपाय की कार्य अवधि के दौरान समायोजित करने का है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी अलग अलग समायोजन योजनाओं पर गोपनीयता का दावा किया है जो किसी सार्थक टिप्पणियां करने के लिए इसे कठिन बनाता है। इसके अलावा, याचिका का एन सी वी समायोजन योजना के संबंध में अस्पष्ट सूचना ही देता है। याचिकाकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे संरचनात्मक समायोजनाओं के संबंध में अपनी योजनाओं को लिखित अनुरोधों में स्पष्ट करें कि प्रत्येक याचिकाकर्ता का प्रयास रक्षोपाय नियमावली के नियम 11(3) के परंतुक के साथ पथित एओएस के आर्टिकल 7.1 के संबंध में करने का है।
- छ. हालांकि, याचिका में उपलब्ध सूचना के आधार पर याचिकाकर्ता यह दावा करता है कि वे बैकवर्ड समेकन अर्थात् वेपरो और इनगोट्स का निर्माण करने के लिए संयंत्रों को स्थापित कर उत्पादन में किफायत को प्राप्त कर लेंगे। हालांकि, ऐसा तरीका अपनाने के फलस्वरूप अगले कुछ वर्षों में उसमें कटौती आयातों के प्रति समायोजन करने की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लागत हो जायेगी। इस कारण से इस प्रकार की समायोजन योजना संभव और व्यवहारिक नहीं है।
- ज. आयात जो हाल के बोलियों फलस्वरूप होता है, ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं अथवा लगभग 9000 मेगावाट की विद्युत खरीद करारों पर हस्ताक्षर रक्षोपाय शुल्क लगाने के पूर्व किया गया है, को शुल्क की परिधि छूट प्रदान की जाये।
- झ. एम एन आर ई ने 12000 मेगावाट की सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय उपक्रम योजना की एक अतिरिक्त योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। जिसमें एक आश्वस्त डी सी आर संघटक होता। यह घरेलू उद्योग को एक आश्वस्त बाजार उपलब्ध करायेगा। इस कारण से घरेलू उद्योग को भी गंभीर क्षति का भविष्य में कोई खतरा नहीं है।
- ञ. घरेलू उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता से 2017-18 (वार्षिक) के दौरान सोलर पावर के लिए भारतीय मांग का केवल 10 प्रतिशत पूरा कर सकता है। शेष को आयातों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।

(xvii) मैसर्स ए सी एम ई

- क. घरेलू सोलर पी वी मौजूद घरेलू निर्माण क्षमताएं बहुत कम अर्थात् कुल आवश्यकता का 10 प्रतिशत है। घरेलू उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता से 2017-2018 (वार्षिक) के दौरान सोलर पावर के लिए भारत की मांग का केवल 105 पूरा कर सकता है। शेष को आयातों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप सोलर पावर विकासकर्ता प्रमुख रूप से सोलर पी वी मॉड्यूल और सोलर सैल की आपूर्ति करने के उद्देश्य से आयातों पर प्रमुख रूप से निर्भर करते हैं।
- ख. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण क्षेत्र ("**ई एस डी एम**") में निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए एम-एस आई पी एस के लिए नीति अधिसूचित की। पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत (विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों के लिए 20 प्रतिशत) और पूंजीगत उपकरण पर इस्पात/ सी वी डी के प्रतिपूर्ति के मामले में वित्तीय प्रोत्साहन सोलर पी वी सैल्स और मॉड्यूल के डिजाइन और निर्माण में लगे एककों को उपलब्ध कराया गया था।
- ग. 19 नवंबर, 2012 को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक संबंधी राष्ट्रीय नीति इलेक्ट्रॉनिक बाजार में मौजूद भारी मांग आपूर्ति अंतर को देखती है और तदनुसार विभिन्न उद्देश्यों को निर्धारित किया है जिसका अन्य बातों के साथ साथ 2020 तक

सोलर पावर की 20 गीगावाट के उत्पादन को सहयोग देने के लिए सोलर पी वी की निर्माण क्षमता बनाने का लक्ष्य है। अवसररचना, ऋण और कर लाभ के मामले में विभिन्न प्रोत्साहन ई एस डी एम क्षेत्र को उपलब्ध कराया गया था।

- घ. सरकार द्वारा वर्ष 2012 से लगातार दिए गए प्रोत्साहन के बावजूद, घरेलू निर्माता अपने उत्पादन अथवा क्षमता को बढ़ाने में सफल नहीं हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक, सोलर सैल और पी वी मॉड्यूल का घरेलू निर्माता द्वारा निर्मित कुल संस्थापित क्षमता 7,157 मेगावाट की मांग की तुलना बहुत कम अर्थात् 573 मेगावाट थी। जब से जे एन एन एस एम की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई और राजकोषीय तथा अन्य प्रोत्साहन राशि दिए जाने के बावजूद, घरेलू निर्माता सोलर सैल और पी वी मॉड्यूल की भारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित क्षमताओं का निर्माण करने एवं संस्थापित करने में सफल नहीं हुए। घरेलू निर्माताओं को 2022 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जे एन एन एस एम के अंतर्गत इस दृष्टि की पूरी जानकारी थी। घरेलू उद्योग को पहले से ही अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए तथा अपने कार्य में सक्षम बनाने हेतु सरकार से अनेक प्रोत्साहन जैसे संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एस आई पी एस) और घरेलू वस्तु आवश्यकता (डी सी आर) का लाभ मिल रहा है।
- ङ. सरकार सोलर पोटोवोल्टेक्स, सिस्टम, डिवाइसेस और कम्पोनेंट गूड्स (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) दिनांक 30 अगस्त, 2017 के आदेश को भी अधिसूचित किया ताकि प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में आयात किए जाने वाले सोलर सैल और मॉड्यूल उल्लिखित मानक के अनुरूप हों और उस पर मानक चिह्न लगा हुआ हो। इस आदेश के कारण प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित हो गया कि भारत में कोई भी निम्न कोटि के उत्पाद का आयात नहीं किया जा रहा है। हालांकि, घरेलू उद्योग इसे उपलब्ध कराये गये अवसरों का अधिकतम लाभ लेने में सक्षम नहीं था और उनके द्वारा आने वाली मांग को पूरा किए जाने और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे। घरेलू प्रौद्योगिकी मौजूदा अप्रचलितता एक मानी हुई बात है। सरकार की नीत का पूरा बल घरेलू उद्योग को प्रौद्योगिकी अत्यंतित करना है और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना है।
- च. एम एन आर ई ने विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक कार्यक्रम बनाया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपकरण सरकारी खरीद के अंतर्गत घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित सोलर पी वी मॉड्यूल का 12 गीगावाट संस्थापित करने करेंगे।
- छ. पूर्व जांच में पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया था क्योंकि एम एन आर ई से कड़ा विरोध प्राप्त हुआ था क्योंकि जे एन एन एस एम पूरा नहीं किया जायेगा और इस कारण से आई एस एम ए ने अपनी याचिका वापस ले ली है।
- ज. आई एस एम ए ने 2017 में पाटनरोधी याचिका वापिस ले ली क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद के पाटन को उन औसतों तक दर्शाने में सफल नहीं हुआ जिसका दावा याचिका में किया गया और इस जांच से वह परिणाम प्राप्त नहीं होगा जिसका उद्देश्य है।
- झ. याचिका के साथ प्रस्तुत आंकड़े एम एन आर ई के आंकड़े से मेल नहीं खाते हैं जिसमें भारत में संस्थापित क्षमता 11562 मेगावाट होने का उल्लेख किया गया है और इस प्रकार से घरेलू उद्योग इसका केवल 7.5 प्रतिशत होता है।
- ञ. विभिन्न स्रोतों से आयात से लिए गए आंकड़े वित्तीय फलस्वरूप अंतर होता है और वह कम विश्वसनीय हो जाता है। इस कारण से विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए आंकड़ों पर निर्भर करते हुए आवेदन अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण हो जाता है।
- ट. 3 याचिकाकर्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित हैं और इस कारण से ऐसा दावा नहीं किया जा सकता है कि यह अनराउथ एल्मूनियम में पूर्व के महानिदेशालय रक्षोपाय के जांच परिणाम को देखते हुए घरेलू उद्योग है।
- ठ. मुंद्रा सोलर घरेलू उद्योग का भाग नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी स्थापना आई एस एम ए द्वारा दायर किए गए आवेदन के केवल 6 महीने पूर्व स्थापित किया गया था। मुंद्रा घरेलू बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा किए बिना विचाराधीन उत्पाद के बड़े हुए आयात के कारण क्षति का दावा नहीं कर सकता है। अधिक से अधिक मुंद्रा द्वारा यह दावा क्षति को रोकने के लिए है जिसे रक्षोपाय शुल्क के संबंध में जांच शुरू करने के लिए आधार नहीं हो सकता है।
- ड. मांग में क्रमिक वृद्धि आपूर्ति और मांग के अंतर को दूर करने के लिए मांग में वृद्धि के अनुपातित और आयात में वृद्धि के अनुरूप है। इस कारण से यह अचानक, पर्याप्त, अप्रत्याशित और तीव्र नहीं है।
- ढ. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि संस्थापित क्षमता में घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन तथा 1000 मेगावाट तक वृद्धि हुई। मांग में तेजी से विस्तार के बावजूद, घरेलू उद्योग की बिक्री और हिस्सा हाल के वर्षों में कमोवेश स्थिर रही है।

- ण. आवेदक अपनी क्षमता में प्रत्येक वर्ष भारी अप्रयुक्त क्षमताएं होने के बावजूद वृद्धि कर रहे हैं। घरेलू उद्योग की उत्पादन सुविधाओं का जांच की समग्र अवधि के दौरान कम उपयोग किया गया और क्षमता के उपयोग में बहुत अधिक गिरावट आई। वे आदर्श स्तर पर कार्य नहीं कर रहे थे जिसके कारण उनके पास अभी भी 49 प्रतिशत उपयोग न की गई क्षमता है। क्षमता से उपयोग में क्षमता को बढ़ाने की अनुपयुक्त निर्णय के कारण गिरावट आई।
- त. घरेलू बिक्री के बाजार हिस्से में अनुपातित वृद्धि हुई थी।
- थ. घरेलू उद्योग के उत्पादन में 473 मेगावाट से 838 मेगावाट तक वृद्धि हुई और आयात 6375 मेगावाट से बढ़कर 9334 मेगावाट हो गया। इस कारण से यह नहीं माना जा सकता है कि जांच की अवधि में केवल आयात में वृद्धि हुई है।
- द. कोई गंभीर क्षति नहीं है। एफ एस पी का रक्षोपाय संबंधी जांच परिणाम उस पर आधारित है जब यह पाया गया कि (1) क्योंकि आयातों में घरेलू उत्पादन और खपत के साथ साथ वृद्धि हुई और (2) घरेलू उद्योग को हानि उत्पादन की लागत का तथा विचाराधीन उत्पाद के अनुपातिक आधार पर बिक्री के उपयुक्त न होने के कारण हुआ है और न कि आयातों के कारण हुआ है।
- ध. कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग को हानि, यदि कोई हो निष्क्रिय उत्पादन क्षमता और निवेश जिसे अनियोजित तरीके से किया गया, संस्थापित क्षमता में वृद्धि तथा अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग न कर पाने के कारण हुआ है।
- न. आवेदकों द्वारा दावा किए गए हानि मिथ्या एवं भ्रामक हैं। दोनों आवेदकों जो जांच की अवधि के दौरान कार्य कर रहे थे अर्थात् डिजिटल सोलर और वेबसोल का तुलन पत्र। उक्त आवेदकों की स्थिति का सार एक तालिका में दिया गया है जहां यह देखा जा सकता है कि दोनों आवेदकों द्वारा 2017 में अर्जित राजस्व 2016 की तुलना में अधिक है। जूपिटर सोलर ने 2017 में 213 करोड़ रुपए की तुलना में 287 करोड़ रुपए अर्जित किए। वेबसोल ने 279 करोड़ रुपए की तुलना में 2017 में 296 करोड़ रुपए अर्जित किए। पिछले 2 वर्षों में उनके मार्जिन और स्थिति के हिस्से में स्पष्ट लाभ देखा गया है जो जांच परिणाम के बिलकुल प्रतिकूल है। वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित को दर्शाया गया है।
- प. वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार इंडोसोलर ने या तो हानि में गिरावट अथवा अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रदता दर्शायी है। एक अन्य आवेदक हिबिस काफी लंबे समय से कोरपोरेट ऋण पुनर्संरचना कर रहा था और इसकी बहुत अधिक देयताएं तुलन पत्र में हैं जो इसके द्वारा दर्शायी गई हानि का कारण है।
- फ. आई टी ए-1 उत्पादों को आई टी ए-1 पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत द्वारा दी गई छूट के कारण आयात में वृद्धि नहीं हुई। आयातों में वृद्धि घरेलू सोलर पावर विकासकर्ताओं द्वारा सोलर पावर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए बढी हुई मांग के कारण हुआ था जो भारत सरकार की सोलर पावर के उत्पादन का संवर्द्धन करने के लिए नीति के कारण हुआ है। इस प्रकार से 1996 में आई टी ए-1 के अंतर्गत भारत का दायित्व और 2015-16 में विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों के बीच कोई संबंध नहीं है और इस प्रकार से दो अलग अलग घटनाओं को जोड़ने के लिए आई एस एम ए द्वारा प्रयास किए गए संबंध और कारणात्मक संबंध का कोई आधार नहीं है। एन एस एम आरंभ करने के साथ, सोलर पावर क्षेत्र में नई कंपनियों का प्रादुर्भाव हुआ और सोलर उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में निवेश में वृद्धि हुई जिसे बाद में 2022 तक प्राप्त की जाने वाली 100 गीगावाट कर दिया गया। इस कारण से सोलर पैनल/ मॉड्यूल के निर्माण मांग में वृद्धि हुई और यह बहुत अधिक हो गया। प्रत्याशित भावी मांग के फलस्वरूप कुछ योजनाएं जैसे एम एस आई पी और डी सी आर बनाई गईं परंतु घरेलू उद्योग इस अवसर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था और उनके द्वारा आने वाली मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था जबकि चीन ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के उभरते हुए बाजार को देखा और इसने अपने उद्योगों को भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने के उद्देश्य से बढ़ाना शुरू कर दिया।
- ब. घरेलू उद्योग कभी भी 2022 तक 100 गीगावाट के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु सोलर मॉड्यूल और पैनल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था। इस तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मॉड्यूल और पैनलों का आयात करने के लिए सोलर पावर विकासकर्ता मजबूर हो गया।
- भ. जबकि चीन भारत में विचाराधीन उत्पाद का पहले से ही निर्यात कर रहा था, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में चीन से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद पर संरक्षणवादी उपाय 2015 में लगाये गये थे। इस कारण से यह कहना सही नहीं होगा कि ये कार्यवाही/ नीतियां करार पर हस्ताक्षर करने के वर्ष अर्थात् 1996 से लगभग दो दशकों के बाद हुई, 1996 में हस्ताक्षरकर्ता होने पर भारत के दायित्व के कारण हुआ था।
- म. आई एस एम ए ने यह तर्क दिया है कि गैट और (--आई टी ए-1") के अंतर्गत भारत के दायित्व के फलस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के सीमा शुल्क में दिनांक 1 मार्च, 2005 के सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 24/2005 – सीमा

शुल्क के द्वारा शून्य तक कटौती हुई। **आई एस एम ए** का यह तर्क गलत है और इसका कोई आधार नहीं है। आई टी ए-1 का उद्देश्य बिना किसी प्रशुल्क अवरोध के सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों का स्वतंत्र गतिशीलता प्राप्त करना था। इस कारण से आई टी ए-1 और विचाराधीन उत्पादन के बीच कोई संबंध नहीं है।

- य. घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए एक पृष्ठ के कथन को तब तक समायोजन योजना नहीं कहा जा सकता है जब तक उसे तकनीकी व्यौरों द्वारा इस संबंध में विधिवत समर्थन नहीं किया गया हो कि किस प्रकार से ये घरेलू उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनायेंगे। खोखले दावे को समायोजन योजना के रूप में नहीं माना जा सकता। "उचित व्यापार" के विरुद्ध "आपातकालीन" कार्यवाही होने के कारण रक्षोपाय उपयुक्त पुनर्गठन के माध्यम एक नई बाजार स्थिति को अपनाने के लिए घरेलू उद्योग को कुछ "उपयुक्त समय" की अनुमति देने के लिए अस्थाई आयात प्रतिबंध हैं। इस कारण से आवेदक को विस्तृत समायोजन योजना देनी चाहिए थी।
- र. भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग घरेलू उद्योग की क्षमता से अधिक है जिसके द्वारा मांग और आपूर्ति में अंतर होना है।
- ल. विभिन्न वितरण यूटिलिटी (डिस्कॉम) जो सोलर पावर एकमात्र खरीददार है, ने लगभग 2.50 रुपए प्रति यूनिट की न्यूनतम संभावित प्रशुल्क पर सोलर पावर की बढ़ी मात्रा खरीदने के लिए अपनी रुचि दर्शायी है। इस प्रशुल्क पर सोलर पावर कोयला एवं गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों की परिवर्तनशील लागत की तुलना में कम है। इस प्रकार से सोलर पावर बढ़ी मात्रा को समेकित करने से वास्तव में बढ़ते हुए घाटे को कम करने में सहायता मिलेगी और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विद्युतीकरण करने के लिए प्रतिबद्धताओं को सहायता दी जायेगी। हाल के उपयोग के अनुसंधान में भी यह दर्शाया गया है कि 3.0 रुपए प्रति यूनिट सोलर पावर के प्रशुल्क पर भारत सोलर संयंत्र का केवल 30 गीगावाट स्थापित करने में सक्षम होगा बल्कि 2.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से यह संभव नहीं होगा कि 100 गीगावाट के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसके आलवा, प्रशुल्क के 2 रुपए प्रति यूनिट तक कम किए जाने की स्थिति में, विभिन्न यूटिलिटी, रेलवे और अन्य भारी उपभोक्ताओं द्वारा लगभग 200 गीगावाट सोलर पावर की मांग होगी। रक्षोपाय शुल्क लगाने के कारण अंततः सोलर पावर के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और यह प्रशुल्क को उपभोक्ताओं के लिए महंगा पड़ेगा और इस कारण से अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी संयंत्र में डी सी से ए सी लोडिंग की मात्रा पर निर्भर करते हुए, यदि रक्षोपाय शुल्क 25 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है तब प्रशुल्क में 2.44 रुपए प्रति के डब्ल्यू एच से बढ़कर 3.13 रुपए प्रति के डब्ल्यू एच और यदि रक्षोपाय शुल्क 30 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है तब 3.25 रुपए प्रति के डब्ल्यू एच तक वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप शुल्क में बहुत अधिक वृद्धि होगी। इससे अंत में आम जनता को बिजली की लागत पर प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार से जनहित को परेशानी होगी।
- व. भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न योजनाएं, मिशन, नीतियां बनाई हैं जिसके कारण विचाराधीन उत्पाद की मांग में उछाल आया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर ए सी एम ई की रिट याचिका

- क. ए सी एम ई द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा जांच आरंभन की सूचना और जारी किए गए आरंभिक जांच परिणामों को रद्द करने के लिए आदेश दिए जाने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की गई। इस रिट याचिका में उठाये गए मुद्दों पर वर्तमान जांच में अनुरोधों के रूप में विचार किया जाना है।
- ख. ए सी एम ई ने यह तर्क दिया है कि सोलर पी वी मॉड्यूल की वर्तमान घरेलू निर्माण क्षमता कुल आवश्यकता का लगभग 10 प्रतिशत है। प्रतिवादियों और डिस्कॉम द्वारा हस्ताक्षर किए गए विद्युत खरीद करार (पी पी ए) के संबंध में, एस पी डी ने सोलर सैल और पी वी मॉड्यूल के आयात के लिए पहले ही आदेश दिए हैं।
- ग. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी जांच से अपना नाम वापिस लिया है क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद का उन स्तरों तक जिसका इसके द्वारा दावा किया गया, के पाटन को दर्शाने में सक्षम नहीं था।
- घ. महानिदेशक रक्षोपाय ने हितबद्ध पक्षकारों को आई एस एम ए द्वारा दायर किए गए आवेदन के संबंध में सूचना जारी करने से 30 दिनों की एक अवधि के भीतर अपने विचारों से अवगत कराने का निर्देश दिया। हालांकि, हितबद्ध पक्षकारों के विचारों की प्रतीक्षा किए बिना, महानिदेशक रक्षोपाय ने एकपक्षीय रूप में सार्वजनिक सूचना विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर 70 प्रतिशत की अंतिम रक्षोपाय उपाय शुल्क लगाने के लिए प्रारंभिक जांच परिणाम देते हुए पारित किया जिसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। अध्यावेदन करने के लिए अवसर प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए जाने के पूर्व किया जाना चाहिए था।

- ड. रक्षोपाय शुल्क चाहे वह अनंतिम हो अथवा अंतिम हो, को उस तिथि जब रक्षोपाय उपाय, चाहे वह अनंतिम हो/अंतिम हो अधिसूचित किया हो, के बाद पी पी ए पर हस्ताक्षर किए जाने के अनुसरण में किए गए आयातों के संबंध में बाद की तिथि से लगाया जाना चाहिए। पहले से किए गए विद्युत खरीद करार के संबंध में रक्षोपाय शुल्क लगाने का प्रतिकूल प्रभाव उन परियोजनाओं के नकदी के प्रवाह पर पड़ेगा और इससे वे अव्यवहार्य हो जायेंगे।
- च. महानिदेशक रक्षोपाय ने जांच आरंभ करने में शुल्क लगाने की सिफारिश करने में गलती की है क्योंकि यह रक्षोपाय नियमावली के साथ पठित धारा 8ख का उल्लंघन क्योंकि 5 में से 3 आवेदक वे एकक हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित हैं और इस कारण से वे घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं हो सकते हैं जैसा कि महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा पूर्व के मामलों में माना गया है। घरेलू उद्योग की परिभाषा से इन आवेदकों को निकाले जाने पर, यह आवेदन कायम रखने योग्य नहीं होगा।
- छ. मुंद्रा सोलर का घरेलू उद्योग के रूप में कोई स्थान नहीं है क्योंकि मई 2017 अर्थात् आवेदन दायर करने के 6 महीने पूर्व भी इसे सिद्ध किया गया था। इस कारण से भारत में विचाराधीन उत्पाद के बाजार में प्रतिस्पर्धा करना अभी बाकी है और यह घरेलू स्थान पर प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा किए बिना क्षति का दावा नहीं कर सकता है।
- ज. घरेलू उद्योग दायर की गई शिकायत की अनुपस्थिति में, महानिदेशक रक्षोपाय का क्षेत्राधिकार जांच शुरू करने की नहीं है और इन्होंने उस क्षेत्राधिकार को मान लिया है जो इसके पास कभी नहीं था।
- झ. महानिदेशक रक्षोपाय इन आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों/सूचना की सटीकता और पर्याप्तता की जांच किए बिना जांच आरंभ कर दी है। महानिदेशक रक्षोपाय ने विचाराधीन उत्पाद के मामले में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर ही विश्वास किया है जिसमें यह कहा गया है कि विचाराधीन उत्पाद का, उनका सामूहिक उत्पादन 544 मेगावाट की कुल उत्पादन की तुलना में 381 मेगावाट है और इस कारण से यह माना गया है आवेदक का उत्पादन कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है। आवेदकों द्वारा दिए गए आंकड़े सही नहीं हैं क्योंकि प्रतिवादियों ने अपनी सूचना का स्रोत और न ही उपर्युक्त विवरणों के लिए आंकड़ों के किसी स्वतंत्र स्रोत को नहीं दर्शाया है। आवेदकों ने 23 निर्माताओं की एक सूची पर विश्वास किया है जिनमें उनमें से 8 निर्माता विशेष आर्थिक क्षेत्र में हैं। उत्पादन के संबंध सूचना का कोई स्वतंत्र आधार और प्रमाणिक स्रोत नहीं है। सरकार का आधिकारिक यह प्रकट करता है कि घरेलू उद्योग की 31/5/2017 की स्थिति के अनुसार सकल प्रचालन गत क्षमता 7173 मेगावाट था और इस कारण से आवेदकों द्वारा दिए गए आंकड़े त्रुटिपूर्ण हैं।
- ञ. आवेदकों की उत्पादन क्षमता केवल 10.5 प्रतिशत है जो 2016-2017 में 72 प्रतिशत के उनके दावे की तुलना में कम है।
- ट. पेरिस करार अथवा राष्ट्रीय सोलर मिशन की प्रतिबद्धता के कारण कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिसका अनुमान पहले नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट सोलर 2016-2017 में यह माना कि इस मिशन का लक्ष्य 2022 तक 20,000 मेगावाट की ग्रिड से जुड़ी सोलर पावर को बहाल करना शामिल था। घरेलू उद्योग सोलर 2022 तक 100 गीगावाट के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के कारण सोलर मॉड्यूल और पैनल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कभी तैयार नहीं था, इसके कारण सोलर पावर के विकासकर्ताओं को बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मॉड्यूल और पैनल का आयात करने पर मजबूर होना पड़ा।
- ठ. आवेदकों को यह दर्शाना है कि किस प्रकार से अप्रत्याशित घटनाक्रमों का पूर्व में अनुमान नहीं लगाया जा सका था जब भारत गैट के अंतर्गत दायित्वों को प्राप्त किया।
- ड. रक्षोपाय एक प्रकार का उपाय है जिसे आपातकालीन कार्यवाही के भाग के रूप में लिया जाता है और कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिसके कारण इस उपाय को लागू किया जाना आवश्यक हो। सरकार द्वारा दी गई परियोजनाओं को कार्यान्वित कर भारी मांग को पूरा करने में सरकार के नीतिगत उपाय और घरेलू उद्योग की असफलता के कारण आयात में वृद्धि हुई है।
- ढ. आई टी ए-1 का उद्देश्य बिना किसी प्रशुल्क अवरोधों के आई टी उत्पादों के स्वतंत्र आवाजाही को प्राप्त करना है और आई टी ए-1 पर हस्ताक्षर करने पर भारत और विचाराधीन उत्पाद का भारत में बढ़े हुए आयात के बीच कोई संबंध नहीं है।
- ण. आयातों में वृद्धि चीन की अतिरिक्त क्षमता अथवा संयुक्त राज्य/यूरोपीय संघ द्वारा संरक्षणवादी उपायों के कारण नहीं हुआ है बल्कि यह सरकार की सोलर पावर के विकास को प्रोत्साहित करने की नीति के कारण हुआ है।
- त. प्रतिवादी को आपातकालीन प्रावधानों को लागू नहीं करना चाहिए था क्योंकि उन्होंने पूंजी और उत्पादन आर्थिक सहायता; सरकारी खरीद के अंतर्गत घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित 12 गीगावाट सोलर पी वी मॉड्यूल संस्थापना के

माध्यम से घरेलू निर्माताओं को 11,000 करोड़ भारतीय रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित योजना के द्वारा घरेलू सोलर उद्योग में जान फूंकने के लिए पहले ही एक योजना की अवधारणा बना ली है।

- थ. घरेलू उद्योग पिछले 2 वर्षों में अपने मार्जिन और इकटिरी के हिस्से में उल्लेखनीय लाभ अर्जित कर रहा है जो कंपनी रजिस्टार से प्राप्त तुलन पत्र के अनुसार पहुंच अधिक घाटा होने के उनके दावे के प्रतिकूल है। चूंकि मुंद्रा सोलर एक नई सुविधा है अतः इसे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता/ घाटे का निर्धारण करने में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एक नई सुविधा होने का अर्थ व्याज की अधिक लागत और मूल्यहास होगा जिसका प्रचालन के आरंभिक वर्षों के दौरान लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।
- द. इन याचिकाकर्ताओं की स्थिति में क्षति की अवधि के दौरान सुधार हुआ है और इसके विपरीत दो याचिकाकर्ताओं जिन्हें आंतरिक समस्याओं जैसे एक नई निर्माण सुविधा, पुनर्गठन और अप्रचलित प्रौद्योगिकी के कारण घाटे का सामना करना पड़ा। इस कारण से आयातों में वृद्धि के फलस्वरूप क्षति नहीं हुई है।
- ध. महानिदेशक रक्षोपाय ने एकतरफा दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि इसमें इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि विकासकर्ता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों जहां परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं, में रोजगार के भारी अवसर पैदा करते हैं।
- न. महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा अनंतिम शुल्क लगाने के लिए कोई नाजुक स्थितियां सिद्ध नहीं की गई हैं।
- प. याचिका में आवेदकों ने यह स्वीकार कर लिया है कि रक्षोपाय शुल्क को लगाने के फलस्वरूप बिजली प्रशुल्क में वृद्धि होगी परंतु अपने आरंभिक जांच परिणाम में प्रतिवादियों ने इस पर विचार नहीं किया गया है।
- फ. रक्षोपाय विचाराधीन उत्पाद को दी गई वी सी डी से छूट को अस्थायी रूप से वापस लिए जाने अथवा उसमें संशोधन करने तक भी सीमित रहता है। रक्षोपाय शुल्क के नकाब के अंतर्गत प्रतिवादी पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा सकते हैं।
- ब. उच्च अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के कारण मौजूदा परियोजनाएं गैर असक्षम हो जायेगी और इसका प्रतिकूल रूप से राष्ट्रीय सोलर मिशन पर प्रभाव पड़ेगा। सोलर सैल और मॉड्यूल के आयात की लागत में किसी वृद्धि का भारत में संपूर्ण सोलर पावर विकास उद्योग पर सीधा और ठोस प्रभाव पड़ेगा क्योंकि घरेलू सोलर उत्पादन आयातों पर निर्भर करता है क्योंकि घरेलू उद्योग सोलर उत्पादन उद्योग की तरह उसी गति से विकास नहीं कर रहा है।
- भ. प्रकट की गई पद्धति पर अनंतिम शुल्क के निर्धारण का आधार एकतरफा और अस्पष्ट है तथा यह गैट के आर्टिकल XIX की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।
- म. इसी संयंत्र में डी सी से ए सी लोडिंग की मात्रा पर निर्भर करते हुए, यदि रक्षोपाय शुल्क 70 प्रतिशत पर लगाया जाता है तब प्रशुल्क 244 रुपए प्रति के डब्ल्यू एच से बढ़कर 4.54 रुपए प्रति के डब्ल्यू एच हो जायेगा। इसके फलस्वरूप उस दर जिस पर रक्षोपाय शुल्क लगाया गया है के समरूप प्रशुल्क में बहुत अधिक वृद्धि होगी।
- य. पी पी ए में कानून की धारा में परिवर्तन रक्षोपाय शुल्क को लगाना शामिल कर सकता है। हालांकि, केंद्रीय आयोग के समक्ष याचिका दायर करना और संशोधित शुल्क का पता लगाना एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और प्रशुल्क को संशोधित करवाने में विलंब का व्यापार पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण परियोजनाएं आरंभ नहीं हो पायेगी और बैंक रक्षोपाय शुल्क लगाने पर अनिश्चितता के आलोक में निधियों डालने में इच्छुक नहीं होगी।

(xviii) मैसर्स कनेडियन सोलर लिमि.

- क. सोलर सैल और मॉड्यूल कोरिया – सरटेन पेपर (डब्ल्यू टी/डी एस 312) और ईसी – फास्टनर्स (डब्ल्यू टी/ डी एस 397/आर) के विश्व व्यापार संगठन में पाटनरोधी विवादों में 'समान वस्तु' की परिभाषा को देखते हुए समान उत्पाद नहीं हैं।
- ख. सोलर सैल मॉड्यूल के लिए इनपुट्स हैं इस कारण से सोलर सैल एक मॉड्यूल के स्थान पर व्यापारिक रूप से प्रतिस्थापन के योग्य नहीं है और वे अंतिम उपयोग/ अनुप्रयोग के मामले में अलग अलग हैं। एक सोलर सैल प्रकार के रूप में बिजली पैदा नहीं कर सकता है जिसका उपयोग किसी व्यापारिक अनुप्रयोग के लिए किया जा सके। अनेक सोलर सैल से बना हुआ मॉड्यूल का उपयोग विद्युत उत्पादन की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा के कारण व्यापारिक अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। इस कारण से सोलर सैल पब्लिक मॉड्यूल अंतिम प्रयोक्ता की दृष्टि से अलग अलग हैं।
- ग. सैल को मॉड्यूल में असेम्बल करने की प्रक्रिया तकनीकी और उत्कृष्ट प्रक्रिया है जिसमें सैल की लागत का 35 प्रतिशत तक मूल्यवर्धन अपेक्षित है। सोलर सैल का एल वी 13.71 भारतीय रुपए से 18.59 भारतीय रुपए तक का है जबकि मॉड्यूल का एल वी 24.19 से 36.58 है। एक दूसरे के प्रति अपस्ट्रीम उत्पाद है।

- घ. याचिकाकर्ता को मॉड्यूल पर क्षति नहीं हुई होगी (पाटनरोधी जांच में आंकड़े मॉड्यूल पर कीमत में किसी कटौती को नहीं दर्शाते हैं। यदि मॉड्यूल के आयात की तुलना मॉड्यूल के क्षति मानदण्डों से किया जाये तब यह आसानी से स्पष्ट हो जायेगा। आंकड़ों को मिलाकर य याचिकाकर्ताओं ने विश्लेषण पर पर्दा डाला है और मॉड्यूल को शुल्क के क्षेत्र में जोड़ा है।
- ङ. घरेलू उद्योग 28 अगस्त, 2017 की स्थिति के अनुसार सोलर सैल और मॉड्यूल निर्माताओं के संबंध में एम एन आर ई के आंकड़ों को ध्यान में रखकर भारत में उत्पादन का 'बड़ा हिस्सा' का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
- च. सैल और मॉड्यूल का अलग अलग विश्लेषण का घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। कोई भी आंकड़े घरेलू कंपनियों के सोलर सैल और मॉड्यूल के बीच अलग अलग उत्पादन के हिस्से का प्रतिशत नहीं देता है (सोलर सैल और मॉड्यूल के कुल उत्पादन की तुलना में)।
- छ. घरेलू उद्योग की 5 कंपनियां मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन का केवल 3.25 प्रतिशत उत्पादन करता है। पी एफ में, महानिदेशक ने मॉड्यूल के संबंध में घरेलू उद्योग की 5 कंपनियों की स्थिति का परीक्षण नहीं किया है और इसके बजाय उन्होंने सोलर सैल और मॉड्यूल को एक साथ मिलाकर उनकी स्थिति का आकलन किया।
- ज. विशेष आर्थिक क्षेत्र में 3 कंपनियां हैं और इंडोसोलर 100 प्रतिशत ई ओ यू है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा ई ओ यू एक का ध्यान निर्यात बाजार पर है और वे घरेलू बाजार में प्रारंभिक तौर पर प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं जबकि रक्षोपाय कानून का उद्देश्य घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में आयात प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करना है। इस कारण से ई ओ यू और विशेष आर्थिक क्षेत्र घरेलू उद्योग उसी सीमा तक बन सकता है जिस सीमा तक विद्यमान कानूनों के अंतर्गत उनकी हकदारी को अनुमति दी गई है।
- झ. महानिदेशक रक्षोपाय को अनराउथ एल्मूनिम में इसके पूर्व में निर्धारण का पालन करना चाहिए।
- ञ. समानांतर पाटनरोधी जांच में, संबंधित देशों के लिए जांच की अवधि के दौरान (1 अप्रैल, 2016 से 30 जून, 2017) के दौरान सोलर मॉड्यूल के लिए कीमत में कटौती नकारात्मक थी। वर्तमान मामले में वह बहुत अधिक है। इस कारण से इस मामले में गलत आरोप लगाया गया है।
- ट. क्षति के विश्लेषण की अवधि में केवल एक वर्ष अर्थात् 2015-16 है जहां बिक्री की लागत के अनुरूप कीमत में वृद्धि नहीं हुई है। अन्य सभी वर्षों में याचिकाकर्ता उसी रूप में अपने सामानों का कीमत निर्धारण करने में सक्षम हो पाये हैं जिस प्रकार से उनकी लागतों में वृद्धि हुई है और इस कारण से कीमत में कटौती का दबाव उनकी कीमतों पर नहीं पड़ा है।
- ठ. पी एफ ने कीमत में कटौती के कारण आयात और गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित किए हैं जिसे ऊपर गलत रूप में दर्शाया गया है और इस कारण से कारणात्मक संबंध खत्म हो जाता है।
- ड. याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया कि कार्य निष्पादन में डी सी आर को वापस लिए जाने के कारण गिरावट देखी गई है। यह कारणात्मक संबंध की आवश्यकता का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है।
- ढ. घरेलू उद्योग द्वारा सामना किए गए गंभीर क्षति, यदि कोई हो मुंद्रा सोलर पी वी लिमि. की आरंभिक लागत के कारण हुआ है। क्षमता के उपयोग में गिरावट मुंद्रा सोलर पी वी लिमि. द्वारा स्थापित 1.2 गीगावाट की क्षमता वृद्धि के कारण और न कि आयातों के कारण हुआ है।
- ण. पी वी मॉड्यूल से उत्पादित सोलर उर्जा की प्रशुल्क कीमतों में भारत में 2010 से तेजी से गिरावट देखी गई है। भारत का सोलर प्रशुल्क राजस्थान में भादला स्थित 250-मेगावाट (एम डब्ल्यू) क्षमता संयंत्र की नीलामी के दौरान एक नया निम्नतम 2.44 भारतीय रुपए प्रति यूनिट तक गिर गया। यह वैश्विक रूप से दी जाने वाली न्यूनतम कीमतों में से एक है। जब इसकी तुलना 2010 की दरों से की जाती है तब प्रशुल्क में लगभग 86 प्रतिशत की कमी को यह दर्शाता है।
- त. इस प्रशुल्क युद्ध के फलस्वरूप घरेलू सोलर सैल और मॉड्यूल निर्माताओं का मार्जिन कम हो गया। प्रशुल्क में तेजी से गिरावट का आंशिक परिणाम सोलर मॉड्यूल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में गिरावट के रूप में देखा गया। याचिकाकर्ताओं के लिए इस बाजार में प्रतिस्पर्धा करने हेतु, उनके लिए यह आवश्यकता था कि वे सोलर पावर विकासकर्ताओं द्वारा लगाई गई अपेक्षाकृत कम बोली और गिरती हुई अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप अपनी कीमतों को कम करें। डाउनस्ट्रीम उद्योग अर्थात् सोलर पावर विकासकर्ताओं में आक्रामक प्रतिस्पर्धा के कारण याचिकाकर्ताओं की निवल बिक्री प्राप्ति अथवा राजस्व में गिरावट विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण नहीं हो सकता है और न ही होना चाहिए।
- थ. मर्कॉम इण्डिया जो एक अग्रणी पक्ष उर्जा और परामर्शदाता प्रतिष्ठान है, द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, जबकि भारत में सोलर संस्थापनाओं में वृद्धि हुई है लेकिन निविदा और नीलामी क्रियाकलाप पिछले कुछ तिमाहियों के दौरान

मंद पड़ती रहती है। मर्कोम इण्डिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रेकर के अनुसार, लगभग 1.9 गीगावाट की सोलर परियोजनाओं की निविदा 2016 के अंतिम तिमाही 3.4 गीगावाट की तुलना में 2017 की पहली तिमाही में दी गई थी। नीलामी क्रियाकलाप में कमी उन कारकों जैसे वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति, अकुशल पारेषण, बिजली की कम मांग और व्यापारिक एवं औद्योगिक कंपनियों द्वारा केप्टिव उत्पादन में वृद्धि और अपनी नवीकरणीय उर्जा नीति में भारत की डी सी आर के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के फैसले के कारण हो सकता है।

- द. इसके अतिरिक्त, रैवा सोलर पार्क नीलामी में 3.30 भारतीय रुपए प्रति के डब्ल्यू एच की हालिया सबसे कम बोली के फलस्वरूप नीलामी संबंधी क्रियाकलापों में कमी आई है क्योंकि सरकार की एजेंसियां विद्युत खरीद करार के साथ मोल भाव करने के लिए इसे रोक रही है, जो रैवा में प्राप्त बोलियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक महंगी है।
- ध. भारतीय सोलर उर्जा निगम और एन टी पी सी ने 1800 मेगावाट और 2000 मेगावाट पर एक बोली के लिए अधिकतम क्षमता निर्धारित की है। इसका विरोध सोलर बाजार में अग्रणी विकासकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। जिसके कारण सोलर बाजार में अन्य घरेलू उत्पादकों को भी सोलर परियोजनाओं में सफलतापूर्वक भाग लेने में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- न. वार्षिक रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं को क्षति के लिए कारणों का उल्लेख करता है जिसमें आयात शामिल नहीं है।
- प. "31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय ब्यौरा" में इंडोसोलर ने 2017 के अंत के दौरान संस्थापना के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी को क्षति के कारण आपवादिक मदों से संबंधित खाते की सूचना दी।
- फ. हिलिअस ने जनवरी 2015 से मार्च 2016 के लिए अपने स्वतंत्र वित्तीय विवरण में यह सूचना दी है कि कंपनी का प्रचालन कामगारों के कारण 34 दिनों की अवधि के लिए कार्य के रूक जाने के कारण प्रभावित हुआ था। हिलिअस ने अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के लिए अपने स्वतंत्र वित्तीय विवरण में यह उल्लेख किया कि कंपनी द्वारा सामना किए जा रहे तरलता की कमियों का उनके निर्माण प्रचालन और क्षमता उपयोग के स्तरों को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। इसके अलावा, हिलिअस ने यह उल्लेख किया है कि डी सी आर आदेशों में उतार चढ़ाव और सब्सिडी के वितरण में विलंब का प्रभाव इसके निर्माण क्रियाकलापों पर पड़ा है। हिलिअस ने पृष्ठ 8 पर अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरण के माध्यम से निविदाओं की अनिरंतर रिलीज के कारण सतत मांग की कमी की वजह से लागत प्रभावी होने के लिए अक्षमता की अपनी चिंता की सूचना दी। वेबसोल में मार्च 2018 के वित्तीय विवरण (लेखाओं की टिप्पणी) में यह उल्लेख किया कि मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के लिए कोई पूर्ण उत्पादन नहीं हुआ।
- ब. वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 के पृष्ठ संख्या 16 पर इंडोसोलर लिमिटेड ने यह उल्लेख किया है कि क्षमताओं का उपयोग उद्योग के टाउनटर्न और उसके फलस्वरूप मांग में गिरावट के कारण हुई थी।
- भ. अप्रत्याशित घटनाक्रम गैट के अंतर्गत एक सदस्य द्वारा प्राप्त किए गए दायित्वों का प्रभाव होना चाहिए। इसका अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या प्रश्नगत घटनाक्रम पूर्व में अनुमान लगाये जाने योग्य नहीं था और किस प्रकार से उसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई।
- म. क्षमताओं में विस्तार एक अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं हो सकता है जैसा अनराउथ एल्मनियम में माना गया है। चीन का निर्यात उन्मुखीकरण तथा भारत की ओर दिशा में परिवर्तन भी एक अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं हो सकता है।
- य. 'अप्रत्याशित' के रूप में माने जाने वाली घटनाएं अवश्य रूप में अप्रत्याशित होनी होंगी। जब रियायतों के बारे में समझौता किया गया था। माराकेस करार के समझौते के समय, संविदा करने वाले पक्षकारों ने भी पाटनरोधी, पाटनरोधी सब्सिडी और रक्षोपाय के संबंध में करार किया। चूंकि, इन पक्षकारों को यह मालूम था कि प्रत्येक सदस्य राज्य के पास व्यापार निदान उपाय अपनाने का अधिकार होता है जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, अन्य सदस्यों द्वारा इन उपायों को अपनाना उस समय 'अप्रत्याशित' नहीं हो सकता है जब रियायतों के बारे में समझौता किया गया था।
- र. यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य द्वारा सभी जांच आयात में किसी कथित उछाल के बहुत पहले शुरू किया गया था इसलिए आयातों में उछाल इसके कारण नहीं हो सकता था।
- ल. पी एफ नोट करते हैं कि भारत के विरुद्ध डी एस 456 में विश्व व्यापार संगठन का निर्णय एक अप्रत्याशित घटनाक्रम था। विश्व व्यापार संगठन के कानून के संगत नहीं होना 'अप्रत्याशित' के रूप में नहीं माना जा सकता है। पी एफ में यह उल्लेख करते हुए कि "भारत का वास्तव में यह विश्वास है कि जे एन एन एस एम के अंतर्गत इसका डी सी आर गैट 1994 के आर्टिकल XX में निहित अपवाद के अनुरूप था" डी सी आर को विश्व व्यापार संगठन द्वारा हटाये जाने को

- ‘अप्रत्याशित’ नहीं माना जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन के फैसले की पुष्टि भारत द्वारा 1994 में की गई थी, और इस कारण से यह सत्यापित था कि विश्व व्यापार संगठन के उल्लंघन के फलस्वरूप डी सी आर को हटा दिया जायेगा।
- व. भारत द्वारा पेरिस करार के अंतर्गत सोलर क्षमता को बढ़ाने संबंधी प्रतिबद्धताओं को अप्रत्याशित के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह “एन यू एफ सी सी सी सी” के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं के विस्तार के अलावा कुछ नहीं है, जिसे भारत में 1 नवंबर, 1993 को पुष्टि की। इस कारण से भारत हमेशा अपनी कार्बन उत्तर्जनों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध था और इसको उस समय जब विश्व व्यापार संगठन की रियायतों के संबंध में समझौता किया गया, अपनी प्रतिबद्धताओं की पूरी जानकारी थी।
- श. याचिकाकर्ता की योजना क्षमता के उपयोग को बढ़ाने, वित्त पोषण लागत में कमी करने, कच्चे माल की कीमतों को कम करने आदि जैसे कदम उठाकर लागतों में कटौती करना है। इन समायोजन योजनाओं का कोई व्यापारिक आधार नहीं है क्योंकि यह न तो उनके नियंत्रण में अथवा न ही व्यापारिक रूप से संभव है।
- ष. उदाहरण के लिए कच्चे माल की कीमत उनके नियंत्रण में नहीं होना। इस साक्ष्य का कि इनपुट के आपूर्तिकर्ता अपनी कीमतों के संबंध में फिर से मोल भाव करेंगे कि कहीं कोई भनक नहीं लगी। याचिकाकर्ता की योजना रूप में लिए गए ऋण को अमरीकी डालर में ऋण के रूप में इस बात का उल्लेख किए बिना परिवर्तित कर वित्त पोषण लागत को कम करना है कि किस प्रकार से उनकी रूपए ऋण को अमरीकी डॉलर में ऋण के रूप में परिवर्तित करना है और जो आधार होगा तथा ऐसे परिवर्तन की व्यापारिक शर्तें होंगी। समायोजन योजना में कहीं भी पी एफ में कोई उल्लेख नहीं है। यह पी एफ जारी करते समय महानिदेशक द्वारा दिमाग का इस्तेमाल नहीं किए जाने का एक स्पष्ट संकेत है।
- स. सरकार हाल में सोलर परियोजनाओं के लिए न्यूनतम दरों को तय करने पर विचार करती रही है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने यह नोट किया है कि इस प्रकार से दर के निर्धारण का प्रभाव सोलर बाजार कंपनियों पर पड़ सकता है क्योंकि दर का निर्धारण उस समय हुआ है जब बाजार में कंपनियां सोलर पावर की कीमतों के बारे में निश्चित नहीं हैं।
- ह. विशेषज्ञों ने यह भी नोट किया है कि यदि रक्षोपाय महानिदेशालय की सिफारिश किए गए 70 प्रतिशत शुल्क को कार्यान्वित किया जाए तब इसके कारण सोलर पावर की कीमतों में लगभग 3 रूपए प्रति यूनिट तक वृद्धि हो सकती है जबकि अंतिम सिफारिश कभी भी नहीं लगाई गई थी, मुख्य सिद्धांत अंतिम जांच परिणाम की सिफारिश के लिए भी वही है। जनहित में, महानिदेशक रक्षोपाय को विचाराधीन उत्पाद पर कोई रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए और जांच को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि अंतिम प्रभाव शुल्कों को लगाये जाने के कारण सोलर बाजार में विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
- क्ष. वर्तमान जांच पुराने आंकड़ों के आधार पर इस समय चल रही है जो अपडेटिड किया प्रतीत नहीं होता है। पृष्ठभूमि के रूप में यह नोट किया जाए कि रक्षोपाय जांचों में आयातों और क्षति दोनों के लिए सबसे हाल में उपलब्ध आंकड़ों की जांच करने की स्थापित रिवाज है।
- त्र. चूंकि जांच के आरंभ होने के छ: महीने बीत चुके हैं अतः वर्ष 2017-18 के लिए आंकड़े अब आयात और क्षति दोनों के लिए उपलब्ध है। हालांकि, ऐसा प्रतीता होता है कि याचिकाकर्ताओं ने रिकार्ड पर हाल के किसी आंकड़ों को नहीं दर्शाया है।
- ज. पाटनरोधी जांच में घरेलू उद्योग ने वास्तव में जांच की अवधि के बाद की अवधि में इसको हुई गंभीर क्षति का प्रमाण दिया है। इस ओर से, यह नोट करना दिलचस्प है कि दोनों जांचों में जांच और क्षति की अवधि कुल मिलाकर एक ही रहती है और इसमें केवल तीन महीने हैं जो दोनों जांच की अवधियों में अंतर लाते हैं।
- कक. निर्यातकों को जब और जैसे ही अपडेटिड आंकड़े उपलब्ध हो जायें अतिरिक्त अनुरोध दायर करने के लिए एक अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। महानिदेशक रक्षोपाय को दिनांक 18 जून, 2018 के डी जी टी आर के पत्र के अनुसरण में निर्यातकों द्वारा दायर किए गए दिनांक 21 जून, 2018 के पत्र का संदर्भ लेना चाहिए जिसमें निर्यातकों ने आम सुनवाई के पूर्व लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट प्राधिकारी की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया है और नए और हाल के आंकड़े उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में आगे के अनुरोधों को प्रस्तुत करने के लिए उनके पास अधिकार सुरक्षित है।
- खख. याचिका दायर करने वाली कंपनियों में से तीन कंपनियों जो समानांतर पाटनरोधी जांच में भी थे, ने स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति जांच की अवधि अर्थात् अप्रैल 2016 से जून 2017 (जो लगभग वर्तमान जांच में जांच की अवधि को शामिल करता है) के लिए पाटित आयातों के कारण हुई थी। इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति को अब रक्षोपाय जांच को न्यायोचित ठहराने के लिए आयातों में अचानक वृद्धि को नहीं माना जा सकता है।

याचिकाकर्ता फोरम शॉपिंग में लगा हुआ है और इस कारण से महानिदेशक को जांच समाप्त कर देनी चाहिए क्योंकि यह क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है जो पाटनरोधी कानूनों न की रक्षोपाय की परिधि में आता है।

- गग. इसके अलावा, रक्षोपाय नियमावली के अनुबंध में इस बात का उल्लेख है कि यदि बड़े हुए आयातों के अलावा अन्य कारक हों जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों, तब इस प्रकार के कारकों को बड़े हुए आयातों का कारण नहीं माना 'जायेगा'।
- घघ. समानांतर पाटनरोधी जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी को भारतीय उत्पादकों द्वारा दिए गए आधारों में कोई विशेषता नहीं मिली।
- डड. चूंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी को पाटनरोधी जांच के 1 अप्रैल, 2016 से जून 2017 को शामिल करते हुए जांच की अवधि के लिए वापस लिए जाने हेतु घरेलू उद्योग के कारणों में कोई विशेषता नहीं मिली, यह संभव नहीं है कि महानिदेशक रक्षोपाय को "गंभीर" क्षति मिलेगी जब जांच की अवधि 2014-15 से 2017-2018 हो।

(xix) मैसर्स रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड

- क. विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित एककों को सीमा प्रशुलक अधिनियम की धारा 8(6)(ख)(ii) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए आंकड़े किसी भी प्रकार से संपूर्ण घरेलू निर्माण उद्योग का एक सही एवं यथार्थ तस्वीर नहीं पेश करते हैं और इस कारण से घरेलू उद्योग की क्षति को सिद्ध करने के लिए इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
- ख. विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता और सह विकासकर्ता एककों को निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से कर और राजकोषीय लाभ के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनेक छूट और रियायतें दी जाती हैं और इस कारण से अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं।
- ग. विशेष आर्थिक क्षेत्र के स्थित एकक निर्यात उन्मुख हैं और उनकी स्थापना घरेलू मांग को पूरा करने के लिए नहीं की गई है।
- घ. प्रतिस्पर्धी एवं आयातों के बेहतर प्रौद्योगिकी के कारण आवेदक घरेलू बाजार में अपने उत्पादों के लिए घरेलू मांग सृजित करने में सक्षम नहीं हैं।
- ड. आवेदक यह सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि अप्रत्याशित के रूप में दावा की गई स्थितियां वास्तव में वैसी थी और यह की ऐसी परिस्थितियों और आयातों में वृद्धि के बीच कारणात्मक संबंध था।
- च. चीन की बड़ी हुई क्षमता से बड़े हुए आयातों को संबद्ध करने के लिए आवेदक का तर्क आधार इसकी अपनी कमियों को ढकने के लिए द्वेषपूर्ण उद्देश्य है और यह पूर्ण रूप से अतार्किक, दोषपूर्ण है। क्योंकि आयातों में वृद्धि राष्ट्रीय सोलर मिशन के कारण हुई थी अतः उसे चीन की बड़ी हुई उत्पादन क्षमता से संबंधित नहीं किया जा सकता है।
- छ. चीन की घरेलू सोलर नीति प्रौद्योगिकी में लगातार निवेशों के लिए कारण था जिसके फलस्वरूप उत्पादन क्षमता, कार्य क्षमता और किफायत में वृद्धि हुई। क्षमता में वृद्धि के कारण तीन वर्षों की न्यूनतम गेस्टेशन अवधि की आवश्यकता होती है और उसे एक अप्रत्याशित घटना के रूप में नहीं माना जा सकता।
- ज. कोई भी देश भारत में निर्यात करने के उद्देश्य मात्र से अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा। स्वयं आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े यह दर्शाते हैं कि क्षमता में अधिकांश वृद्धि चीन के भीतर घरेलू खपत के लिए और न कि निर्यात के उद्देश्य से होती है।
- झ. डी सी आर को वापस लिया जाना एक अप्रत्याशित घटना नहीं है। इसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई क्योंकि वह जांच की अधिकांश अवधि में प्रचालन में थी। आवेदकों ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि अप्रत्याशित घटना के प्रभाव डी सी आर की मौजूदगी तक दृष्टिगत नहीं थी। डी सी आर को हटाये जाने से भी घरेलू उद्योग विभिन्न सरकारी योजनाओं के कारण असुविधाजनक स्थिति में नहीं रखा गया है।
- ञ. घरेलू उद्योग की संस्थापित उत्पादन क्षमता घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसके पूर्ण उपयोग से भी घरेलू मांग का केवल 9.12 प्रतिशत पूरा होगा जो इन आयातों के लिए मूल कारण है।
- ट. क्षति सिद्ध करने के लिए उत्पादन क्षमता से संबंधित जांच की अवधि के आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवेदक के उत्पादन के आंकड़ों का बड़ा हिस्सा मुंद्रा सोलर पी वी लिमिटेड द्वारा स्थापित 1200 मेगावाट संयंत्र के कारण है जिसने मई 2017 तक उत्पादन शुरू नहीं किया है और इस कारण से इसने पूर्ण उपयोगिता प्राप्त नहीं की है।

- ठ. घरेलू उद्योग का कम उपयोग सरकार द्वारा जारी मौसमी निविदाओं के कारण है। पूरे वर्ष के दौरान कोई लगातार मांग नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप परियोजना को शुरू करने के करीब मॉड्यूल की अचानक मांग के समय घरेलू उद्योग इस मांग को प्रति माह सीमित उत्पादन क्षमता की बाधाओं के कारण पूरा नहीं कर पाता है।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग की गई प्रौद्योगिकी वैश्विक निर्माताओं द्वारा उपयोग की जा रही प्रभावी प्रौद्योगिकी से निम्नतर है। केवल उस आवेदक जिसकी उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी है, की अधिकतम वार्षिक क्षमता, मुंद्रा सोलर पी वी लिमिटेड केवल 1200 मेगावाट है और घरेलू उद्योग भारत के बाहर से उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी से युक्त मॉड्यूल का आयात करने के लिए मजबूर होगा।
- ढ. सोलर पावर विकासकर्ता भारत में बहुत अधिक संख्या में रोजगार पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि प्रत्येक 1 मेगावाट सोलर पावर कम से कम 2 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। एस जी डी लगाने के फलस्वरूप नई परियोजनाओं की स्थापना के वित्तीय रूप से गैर अर्थसम हो जाने के कारण इस उद्योग द्वारा पैदा किए जाने वाले रोजगार में बहुत अधिक कमी आयेगी।
- ण. रक्षोपाय शुल्क लगाना इस उद्योग के विकास के लिए हानिकारक होगा क्योंकि इसके फलस्वरूप प्रशुल्क में 3.95 रुपए से बढ़कर 4.05 रुपए प्रति यूनिट हो जायेगा।
- त. घरेलू उद्योग यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हो पाया है कि क्या क्षति, यदि कोई हो कुछ देशों द्वारा पाटन के कारण अथवा बढ़े हुए आयातों के कारण हुआ है। आवेदकों का स्पष्ट रूप से यह विश्वास था कि संबद्ध देशों द्वारा पाटन के कारण क्षति हुई थी जैसा कि पाटनरोधी जांचों के लिए किए गए आवेदन से स्पष्ट है और इस कारण से वे अब बढ़े हुए आयातों के कारण क्षति का दावा नहीं कर सकते हैं।
- थ. रक्षोपाय शुल्क जनहित के विरुद्ध है क्योंकि इन शुल्कों को लगाने से ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी जहां सोलर पावर बहुत अधिक हो जायेगी और जनता द्वारा इसका वहन नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार के कोई व्यापार उपाय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का आदर करने के लिए तथा 2020 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता गंभीर रूप से बाधित होगी।

(xx) मैसर्स क्लीनमैक्स लिमि.

- क. विचाराधीन उत्पाद के विरुद्ध व्यापार निदान जांच का एक इतिहास है। पाटनरोधी महानिदेशालय ने 2014 में चीन, मलेशिया और ताइवान के इस उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। हालांकि, भारत सरकार ने सोलर पावर के साथ ग्रामीण और शहरी भारत में प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने के अपने लक्ष्य के आलोक में इस शुल्क को कार्यान्वित नहीं किया। क्लीनमैक्स इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम कर रहा है।
- ख. रक्षोपाय शुल्क भारत में समग्र सोलर बाजार को अस्त व्यस्त कर देगा। मौजूदा विद्युत खरीद करार खतरे में पड़ जायेगा क्योंकि वितरण कंपनियां विकासकर्ताओं द्वारा प्रशुल्क में वृद्धि को उपभोक्ताओं पर थोपने के प्रयासों का विरोध करेगा/ इसके संबंध में मुकदमा दायर करेगा। सोलर पावर सशुल्क में बहुत अधिक वृद्धि हो जायेगी जिससे विकासकर्ताओं को भावी निविदाओं में सही कीमत देने से पहले ही रोक दिया जायेगा। वितरण कंपनियां सोलर पावर विकासकर्ताओं से खरीदने में रुचि नहीं दिखायेगी और बिजली के परम्परागत स्रोत को यह अपना सकता है। 2022 तक एन एस एस एम लक्ष्य कभी सफल नहीं हो पायेगा।
- ग. जांच के अधीन अवधि में आयातों का हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन 86 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत तक हो गया – जिसे एक व्यापक विकास बमुश्किल कहा जा सकता है।
- घ. घरेलू उद्योग कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है और यदि वैसा है भी तो घरेलू उद्योग को हानि पहुंचाने वाला कोई संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग की जांच के अधीन अवधि के लिए 16 प्रतिशत पर एबिटडा मार्जिन 10 शीर्ष वैश्विक निर्माताओं के लिए एबिटडा मार्जिन की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत अधिक है। यह दर्शाता है कि उच्चतर पूंजी व्यय/ ब्याज लागतों के कारण उच्च ब्याज बोझ न कि आयात इसके लिए दोषी है।
- ड. महानिदेशालय को याचिकाकर्ता, एम एन आर ई आंकड़ों के अनुसार रक्षोपाय नियंत्रण अवधि के अधिकांश हिस्से तक घरेलू उद्योग का 51 प्रतिशत नहीं होता है। (महानिदेशालय रक्षोपाय के इस कथन की यह उद्योग घरेलू उद्योग का 96 प्रतिशत होता है, के बनाम) इसके अलावा, यदि घरेलू उद्योग में विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों को शामिल नहीं किया जाता है, जैसा कि तब याचिकाकर्ता आवश्यक 51 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है।
- च. महानिदेशालय रक्षोपाय का यह जांच परिणाम कि चीन ने यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य द्वारा उठाये गये व्यापार निदान संबंधी उपायों के कारण भारत में अपना निर्यात विकसित किया कि आयात में वृद्धि क्योंकि भारत अब घरेलू

उद्योग को डी सी आर संरक्षणवादी परिधि प्रदान नहीं कर सकता है जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई और यह कि आयातों में इस कारण से भी वृद्धि हुई क्योंकि भारत में आई टी ए-1 के अंतर्गत सोलर सैल और मॉड्यूल पर सीमा शुल्क हटाकर शून्य कर दिया, सही नहीं है। आयातों में वृद्धि भारत सरकार की सोलर उर्जा का संवर्द्धन करने की दृष्टि के कारण हुई। भारत सरकार को यह मालूम था कि भारतीय निर्माता मांग का 10 प्रतिशत से कम ही पूरा कर सकता है। हालांकि, सरकार इस बात का अनुमान नहीं लगा सकती कि आयात इस मांग-आपूर्ति के अंतर को दूर करने में सक्षम होगा। इस उत्पाद के आयातों के पीछे यहीं एकमात्र कारण है। चीन और अन्य देशों से आयात सिफ मांग – आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए ही हुआ। इस कारण से इस प्रकार के आयात किसी अप्रत्याशित घटनाक्रम का परिणाम नहीं है।

- छ. घरेलू उद्योग मैसर्स मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड को जोड़े जाने के कारण घाटे की तस्वीर पेश कर सकता है। मुंद्रा ने नई निर्माण सुविधा स्थापित की है और 2017 में व्यापारिक उत्पादन शुरू किया है। इस नई सुविधा के साथ उच्च व्याज और मूल्यहास लागत आती है, जिसका लाभप्रदता पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। इस कंपनी को क्षति आयातों के कारण नहीं बल्कि उच्च व्याज और मूल्यहास लागत के कारण होती है।
- ज. हीलियस पोटोवोल्टेक प्रा. लिमि. (पूर्व में मोजर बेयर) जो सीडी सहित विभिन्न उत्पादों के निर्माण में लगा हुआ है और वर्ष 2008 से घाटे उठा रहा है। कंपनी का लंबे समय से कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना हो रही थी और तुलन पत्र में इसकी देयताएं बहुत अधिक हैं।
- झ. भारतीय सैल निर्माता को प्रचालन स्तर पर बहुत अधिक लाभ मार्जिन मिलता है जो इस बात का एक सांकेतिक है कि क्या आयातों के कारण घरेलू उद्योगों को क्षति हो रही है अथवा नहीं। उनके घाटे प्रति मेगावाट बहुत अधिक पूंजी लागत, उच्च व्याज लागत और प्रबंधन की अक्षमताओं के कारण है।
- ञ. एम एन आर डी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर घरेलू उद्योग की सरचालन संबंधी क्षमता 933 मेगावाट है जो वर्ष 2017 में पूरी की गई, पर्याप्त किस्तों के साथ सैल की कुल क्षमता 56 प्रतिशत है। वर्ष 2016 के दौरान घरेलू उद्योग के पास 49.7 प्रतिशत की प्रचालन संबंधी क्षमता है।
- ट. सोलर निर्माण की परिभाषा में सैल और मॉड्यूल दोनों के निर्माण को शामिल किया जाना चाहिए। जबकि, वर्ष 2017 में घरेलू उद्योग का भारत की कुल सैल निर्माण क्षमता का 56 प्रतिशत है, घरेलू उद्योग 31 मई, 2017 को समाप्त अवधि के लिए भारत की कुल मॉड्यूल निर्माण क्षमता का केवल 2.6 प्रतिशत था।
- ठ. दिसंबर 2017 में एम एन आर डी ने एक वक्तव्य दिया है कि भारतीय निर्माता की संस्थापित क्षमता अप्रचलित है और यह सरकारी सहायता के रूप में 11,000 करोड़ भारतीय रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव करता है।
- ड. एम एन आर डी ने 12,000 मेगावाट की केंद्रीय क्षेत्र की एक अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रम योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है जिसका एक आश्वस्त डी सी आर संघटक होगा। इससे घरेलू उद्योग को एक आश्वस्त बाजार मिलेगा।
- ढ. महानिदेशालय रक्षोपाय ने पहले यह फैसला दिया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ण. घरेलू उद्योग को अप्रचलित प्रौद्योगिकी के कारण और न कि आयातों के कारण क्षति हुई है।

(xxi) मैसर्स ताईवान फोटोवोटेक इंडस्ट्री एसोसिएशन

- क. महानिदेशालय द्वारा 70 प्रतिशत यथामूल्य पर अनंतिम शुल्क लगाने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया है। रक्षोपाय शुल्क नियमावली 1997 के नियम 11(2) के संबंध में दिए जाने के लिए अपेक्षित औचित्य महानिदेशालय द्वारा यह दर्शाने के लिए नहीं दिया गया है किस प्रकार से ऐसी एक राशि गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका निदान करने और सकारात्मक समायोजन को आसान बनाने के लिए पर्याप्त है।
- ख. आरंभिक जांच परिणामों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है क्योंकि जांच आरंभ संबंधी अधिसूचना हितवद्ध पक्षकारों को जांच के संबंध में अपने विचारों से अवगत कराने के लिए 30 दिनों का समय देते हुए 19 दिसंबर, 2017 को जारी किया गया था जबकि आरंभिक जांच परिणाम हितवद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना इस प्रकार की अवधि के पूरा होने के पूर्व 5 जनवरी, 2018 को जारी किया गया था।
- ग. अनंतिम रक्षोपाय नाजुक परिस्थितियों का मूल्यांकन किए बिना नहीं लगाया जा सकता है। महानिदेशालय ने केवल उन परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिसने इसके अनुसार आरंभिक जांच परिणाम के समर्थन में किसी साक्ष्य का उल्लेख किए बिना क्षति पहुंचाई है। घरेलू उद्योग की ऐसी, 'नाजुक परिस्थिति' अथवा नाजुक हालत का कोई तार्किक

साक्ष्य नहीं दिए जाने की स्थिति में इस प्रकार के शुल्क को लगाना रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 6 और रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 9 का उल्लंघन है।

- घ. सी-एसआई और थिन फिल्म सैल्स समान उत्पाद नहीं हैं और इन दोनों का महानिदेशालय द्वारा समान उत्पाद के रूप में निश्चरण घरेलू उद्योग के अनुप्रयोगों का अंधानुकरण का परिणाम है। आरंभिक जांच परिणामों में इस प्रकार के जांच परिणामों की रिकार्डिंग महानिदेशक के तर्क का पूर्ण रूप से गलत प्रयोग को दर्शाता है और यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
- ङ. सी-एसआई और थिन फिल्म सैल्स उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल, निर्माण प्रक्रिया, परिवर्तित करने की क्षमता, उत्पादन और अन्य क्षमताओं जो सापेक्ष कीमतों को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने को सीमित करते हैं और इसके साथ ही वितरण के चैनलों में किसी ओवर लेप को सीमित करते हैं, में अंतर के कारण अलग अलग उत्पाद हैं।
- च. सी-एसआई सैल्स का अलग अलग निर्माण प्रक्रियाओं के कारण थिन फिल्म की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मॉड्यूल परिवर्तन क्षमता है। ये दोनों सैल व्यापारिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य भी नहीं हैं। घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के अधिकांश उत्पादक नहीं होते हैं और इस कारण से सीमा प्रशुल्क की धारा 8ख की आवश्यकता के संबंध में इस याचिका को जारी नहीं रखा जा सकता है।
- छ. रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार निर्माण के लिए संस्थापित और प्रचालन संबंधी क्षमता के आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन उद्योग के संपूर्ण हिस्से के रूप में केवल 26.41 प्रतिशत है।
- ज. यह दावा आवेदक घरेलू उद्योग की परिभाषा को पूरा करते हैं साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्ता का सत्यापन किए बिना स्वीकार कर लिया गया था और इस प्रकार से वर्तमान जांच के आरंभ करने को निरस्त कर दिया गया था।
- झ. घरेलू उद्योग की स्थिति विद्वेषपूर्ण है क्योंकि मुंद्रा, वेबसोल और हिलिअस फोटो बोलटेक को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि 5 में से 3 विशेष आर्थिक क्षेत्र में आधारित हैं और इस प्रकार से उन्हें घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ञ. इस प्रकार से बाहर किए जाने के फलस्वरूप, मुंद्रा और हिलिअस के संबंध में संस्थापित क्षमता और अन्य आर्थिक आंकड़ों को निकाल दिया जाना है (विशेष रूप में मुंद्रा की 2400 मेगावाट संस्थापित क्षमता) जो घरेलू उद्योग के अंशदान को विचाराधीन के उत्पादन में केवल 5.73 प्रतिशत तक कर देगा और यह प्रभावी रूप से घरेलू उद्योग के रूप में शेष आवेदकों के अयोग्य हो जायेगा।
- ट. मुंद्रा, वेबसोल और हिलिअस को शामिल किए जाने के साथ, यदि वे डी टी ए में अपने उत्पादों की बिक्री करते हैं तब ये उत्पाद रक्षोपाय शुल्क के अध्यक्षीन होगा और इस प्रकार से उनके उत्पादों को घरेलू बाजार में अप्रतिस्पर्धी बना देगा। उससे बचने के लिए, आवेदक सुविकसित योजना के भाग के रूप में सर्वप्रथम अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में शामिल करवायेंगे और उसके बाद रक्षोपाय शुल्क को लगाने से उन्हें बाहर किए जाने का अनुरोध करेंगे। यह घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए आवेदक के गलत उद्देश्य प्रकट करता है और सोलर सैल के आयातों के कारण होने वाली प्रतिस्पर्धा को बाहर कर देता है जो अपेक्षाकृत अधिक कार्यक्षम है और एक कारण है कि क्यों भारत में क्रेताओं द्वारा इसे वरियता दी जाती है।
- ठ. घरेलू रक्षोपाय कानूनों के अंतर्गत अप्रत्याशित घटनाओं का होना गैट के अनुच्छेद XIX के अंतर्गत विचार किए गए अनुसार रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए जांच आरंभ करने के लिए एक आवश्यक और प्राथमिक शर्त है।
- ड. सोलर सैल की पी आर सी की घरेलू खपत निर्यात से बहुत अधिक है। सोलर मॉड्यूल में, जबकि निर्यात 2014 में घरेलू खपत से अधिक थी, 2016 तक घरेलू खपत निर्यात से अधिक हुआ था। इस प्रकार से पी आर सी की अत्यधिक उत्पादन और क्षमता को एक अप्रत्याशित घटना के रूप में आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है।
- ढ. संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय के समक्ष डी सी आर की आवश्यकताओं को चुनौती दी। डी सी आर को अंतिम रूप में वापस लिये जाने का पूर्व में अनुमान नहीं लगाया गया था क्योंकि यह गैट के अंतर्गत राष्ट्रीय मान्यता दायित्वों के संबंध में गलत था और इस बात की हमेशा एक संभावना थी कि उसे विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दी जा सकती है। अंतिम रूप में डी सी आर ने घरेलू निर्माताओं के लिए अपनी उपयोगिता खो दी थी जो अनेक कारकों के कारण, आयातों के कारण समाप्त हो रहे थे। अंततः, इंडिया – सोलर सैल मामले के संबंध में पैनल की रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि डी सी आर उत्पादन की अपेक्षाकृत कम मात्रा को प्रभावित करता है। इस कारण से यह एक अप्रत्याशित घटना नहीं थी।

- ण. पेरिस करार एक अप्रत्याशित घटना नहीं थी बल्कि उन करारों और घटनाक्रमों की सर्वोत्तम सीमा थी जो 1992 (जब कानून बनाया गया था) और 1994 (जब इसे लागू किया गया था) से चल रहा था जिसने पर्यावरण संबंधी मुद्दों और विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के मामले का समाधान करने का प्रयास किया। तदनुसार, उसे अप्रत्याशित के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- त. आई टी ए-1 की प्रस्तावना के आलोक में, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके संबंध में अनुमान भारत सरकार द्वारा आई टी ए-1 के अंतर्गत रियायत देने के समय नहीं लगाया गया था कि कुछ घटनाक्रम विश्वव्यापी आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की सतत् प्रौद्योगिकीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा, आवेदक वास्तव में यह दर्शाने में सफल नहीं रहे हैं कि इस प्रकार से आई टी ए-1 के अंतर्गत किए गए विचाराधीन उत्पाद के आयातों के फलस्वरूप जांच की अवधि के दौरान आयातों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जब भारत 1997 में आई टी ए-1 का एक हस्ताक्षरकर्ता हो गया और शुल्कों को वर्ष 2000 तक समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार से आई टी ए-1 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले दायित्वों को एक अप्रत्याशित घटना नहीं माना जा सकता है।
- थ. आवेदकों का यह तर्क कि अनुप्रयोग के अनुबंध 9 के अंतर्गत उल्लिखित आंकड़ों पर विचार करते हुए विचाराधीन उत्पाद के आयात में 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान 732 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, प्रश्न उठाया गया है। आई एस एम ए द्वारा दायर पाटनरोधी जांच की याचिका के अनुबंध 1.3 द्वारा दिए गए आंकड़ों का अवलोकन करने के बाद, यह दावा किया गया है कि आयात के अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं जो इस तथ्य को सिद्ध करता है कि आवेदक द्वारा दिए गए साक्ष्य को बदला गया है।
- द. विचाराधीन उत्पाद का वास्तविक आयात मूल्य 2014-15 में 505,000 लाख भारतीय रुपए, 2015-16 में 1.55 मिलियन लाख भारतीय रुपए, 2016-17 में 2.14 मिलियन लाख भारतीय रुपए और 2017-18 में 2.47 मिलियन लाख भारतीय रुपए है। (पैरा 5.8.17) विचाराधीन उत्पाद के आयात संबंधी आंकड़े यह भी सिद्ध करते हैं कि वर्ष दर वर्ष आधार पर आयातों में वृद्धि के प्रतिशत में वास्तव में 27.98 प्रतिशत तक कमी आई है। इसके फलस्वरूप आयात में वृद्धि ऐसा नहीं है कि इसके कारण घरेलू उद्योग को ऐसी गंभीर क्षति होगी कि इस पर रक्षोपाय शुल्क लगाने की आवश्यकता पड़ेगी।
- ध. घरेलू उद्योग का अधिकतम उत्पादन, अधिकतम बिक्री, अधिकतम क्षमता उपयोग है और यह जांच की समग्र अवधि के दौरान क्षमता का विस्तार करता रहा है। इसे वर्तमान मामले में पर्याप्त समग्र क्षति की स्थिति में होना नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, इनमें से किसी भी कारक में घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति के माध्यम से कोई गंभीर क्षति दर्शायी नहीं गयी है।
- न. घरेलू उद्योग के बढ़ते हुए बाजार हिस्से के कारण, आयातकों की सुविधादाता की भूमिका के साथ यह सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग कोई गंभीर क्षति नहीं हो रही है।
- प. सोलर मॉड्यूल की लागत के निर्धारण में 50-60 प्रतिशत लागत सोलर सैल का है। इसका तात्पर्य यह है कि सोलर सैल की लागत में कमी प्रत्यक्ष रूप से सोलर मॉड्यूल की लागत के अनुपात में है। घरेलू उत्पादकों की बिक्री से प्राप्ति से संबंधित उपर्युक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सोलर सैल की कीमत में कमी आ रही है जबकि सोलर मॉड्यूल की कीमतों में वृद्धि हो रही है जो इस तर्क के प्रतिकूल है क्योंकि सोलर सैल की कीमत में कमी का प्रभाव मॉड्यूल की कीमत पर अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए।
- फ. घरेलू उद्योग के रोज़गार में 2014-15 से लेकर 2017-18 तक 450 प्रतिशत (लगभग 2600 कर्मचारियों) तक वृद्धि हुई। मुंद्रा सोलर के कर्मचारियों को बाहर निकाला जाना कानून की दृष्टि से सही नहीं है और यदि ऐसी स्थिति थी तब उन्हें पूर्ण रूप से घरेलू उद्योग के क्षेत्र से वापस ले लिया जाना चाहिए था। आंकड़ों का अवलोकन करने पर, यद्यपि मुंद्रा सोलर के कर्मचारियों को इस परिधि से बाहर कर दिया जाता है तब भी कर्मचारियों की संख्या में लगभग 27.1 प्रतिशत तक वृद्धि होगी। यह सिद्ध करने के लिए आवेदकों के वित्तीय विवरणों पर विश्वास किया गया है कि 5 में से 3 आवेदकों को लाभ प्राप्त हो रहा है। मुंद्रा की लाभप्रदता संगत नहीं थी क्योंकि यह मई 2017 में ही चालू हो गया था और इस कारण से प्रारंभ में ब्याज की अधिक लागत और मूल्यहास के कारण लाभप्रदता पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।
- ब. कारणात्मक संबंध के अदृश्य न होने की स्थिति में, जांच में अन्य संगत कारकों पर विचार किए और उसका मूल्यांकन किए बिना, गंभीर क्षति का निर्धारण रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 8 के क्षेत्र के भीतर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

- भ. उपर्युक्त अनुरोधों को देखते हुए जांच में अन्य संगत कारकों पर विचार किए और उसका मूल्यांकन किए बिना, गंभीर क्षति का निर्धारण रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 8 के क्षेत्र के भीतर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
- म. रक्षोपाय शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद का आयात महंगा हो जायेगा जिसके कारण सोलर क्षेत्र का विकास जो वर्तमान में पूर्ण गति से चल रहा है, बाधित होगा और इसके साथ ही जे एन एन एस एम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।
- य. आवेदकों द्वारा कथित रोजगार की हानि के संबंध में चिंताओं की पुष्टि नहीं की गई है और इसे वर्तमान सोलर पावर विकास युद्ध में अपेक्षाकृत अधिक रोजगार के अवसरों के सृजन के साथ व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता है।
- र. पूर्व में लगाया गया पाटनरोधी शुल्क को अंततः फिर से नवीकृत नहीं किया गया था क्योंकि विद्युत मंत्री ने यह उल्लेख किया था कि 700-800 मेगावाट के घरेलू सोलर उपक्रम निर्माण क्षमता नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के माध्यम से अपेक्षाकृत अधिक बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- ल. रक्षोपाय शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद की कीमत में वृद्धि होगी, जे एन एन एस एम की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी और भारत में विचाराधीन उत्पाद आपूर्ति और मांग में बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न हो जायेगा। इसके अलावा, इसके फलस्वरूप देश में नए और अपेक्षाकृत अधिक कार्यक्रम प्रौद्योगिकियों को आयात किए जाने से रोका भी जायेगा। इस कारण से रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में नहीं है।
- व. ताईवान से आयात को बाहर कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये आयात जांच की अवधि के दौरान 5 प्रतिशत से कम रहा है।
- श. सोलर मॉड्यूल सोलर सैल से बनाया जाता है जो इसके उत्पादन के लिए अपेक्षित इनपुट्स में से एक है। पैनेल में असेम्बल किये हुए सोलर सैल के एक मूल्यवर्धित उत्पाद होने के कारण इसके लिए अनेक उत्पादन क्रियाकलापों को किया जाना अपेक्षित है और उत्पादन सुविधा के लिए पर्याप्त निवेश को सोलर सैल की तुलना में पैनेलों में असेम्बल किए हुए सोलर सैल के विरुद्ध संरक्षण का अपेक्षाकृत अधिक स्तर प्रदान करते हुए अलग अलग रूप में माने जाने की आवश्यकता है।

(xxii) मैसर्स शूरजी पलोनजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी लिमिटेड

- क. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8(6)(ख)(ii) के तहत सेज में स्थित इकाइयों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए आंकड़े किसी भी प्रकार से संपूर्ण घरेलू निर्माण उद्योग का सही तथा वास्तविक चित्र प्रस्तुत नहीं करते और इसलिए घरेलू उद्योग को हुए नुकसान का निर्धारण करने के लिए इन्हें आधार नहीं बनाया जा सकता।
- ख. निर्यात बढ़ाने के दृष्टिकोण से विकासकों तथा सह-विकासक इकाइयों को सेज अधिनियम, 2005 के तहत कर तथा वित्तीय लाभों के रूप में विभिन्न छूट तथा रियायत दी जाती है और इसलिए ये एक अलग क्षेत्र में प्रचालित होती हैं।
- ग. सेज में स्थित इकाइयों निर्यात उन्मुखी होती हैं और इन्हें घरेलू मांग को पूरा करने के लिए स्थापित नहीं किया जाता।
- घ. आयात की प्रतिस्पर्धी तथा बेहतर प्रौद्योगिकी के कारण आवेदक घरेलू बाजार में अपने उत्पादों के लिए घरेलू मांग नहीं बना पाते।
- ड. आवेदक यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि उनके द्वारा जिन परिस्थितियों के अनपेक्षित होने का दावा किया जा रहा है वे वास्तव में ऐसी थीं, और यह कि ऐसी परिस्थितियों तथा आयात में वृद्धि के बीच कोई आकस्मिक संबंध था।
- च. आवेदकों का बड़े हुए आयात को चीन की बड़ी हुई क्षमता से जोड़ने का तर्क पूर्णतया अतार्किक है, वृष्टिपूर्ण है और इसमें उनकी स्वयं की कमियों को छुपाने का दुर्भावनापूर्ण इरादा नजर आता है। चूंकि आयात में वृद्धि राष्ट्रीय सौर मिशन के कारण हुई थी, इसे चीन की बड़ी हुई उत्पादन क्षमता से नहीं जोड़ा जा सकता।
- छ. चीन की घरेलू सौर नीति प्रौद्योगिकी में लगातार निवेश का कारण थी जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता, दक्षता तथा उत्पाद की मात्रा में वृद्धि हुई। क्षमता में वृद्धि के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की उत्पादनपूर्व अवधि की आवश्यकता होती है और इसे एक अनपेक्षित घटनाक्रम नहीं माना जा सकता।
- ज. कोई भी देश केवल भारत को निर्यात करने के उद्देश्य से अपनी क्षमता नहीं बढ़ाएगा। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े ही दर्शाते हैं कि क्षमता में अधिकतर वृद्धि चीन में घरेलू उपभोग के लिए हुई है और निर्यात के उद्देश्य से नहीं।

- झ. डीसीआर को वापस लिया जाना एक अनपेक्षित घटनाक्रम नहीं है जिससे आयात में वृद्धि हुई हो चूँकि यह पीओआई के अधिकतर समय प्रचालन में था। आवेदकों ने स्वयं स्वीकार किया है कि डीसीआर के लागू रहने के समय तक अनपेक्षित घटनाक्रम के प्रभाव दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी स्कीमों के कारण डीसीआर को वापस लिए जाने से घरेलू उद्योग अलाभकारी स्थिति में नहीं आया है।
- ट. घरेलू उद्योग की संस्थापित उत्पादन क्षमता घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है चूँकि इसका पूर्ण उपयोग किए जाने के बाद भी घरेलू मांग के केवल 9.12% भाग को ही पूरा किया जा सकेगा जो कि आयात का मूल कारण है।
- ठ. नुकसान के निर्धारण के लिए उत्पादन क्षमता से संबंधित पीओआई के आंकड़ों को आधार नहीं बनाया जा सकता चूँकि आवेदकों के उत्पादन आंकड़ों का बड़ा हिस्सा मुंडदा सोलर पीवी लिमिटेड द्वारा स्थापित 1200 मेगावाट के संयंत्र से संबंधित है जिसने मई, 2017 तक उत्पादन शुरू नहीं किया है और इसलिए इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है।
- ड. घरेलू उद्योग का क्षमता से कम उपयोग किया जाना सरकार द्वारा जारी की गई मौसमी निविदाओं के कारण है। पूरे वर्ष एक समान मांग नहीं होती जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं का कार्य सौंपे जाने के समय के आस-पास मॉड्यूल की आकस्मिक मांग के समय घरेलू उद्योग प्रति माह सीमित उत्पादन क्षमता के कारण मांग को पूरा नहीं कर पाते।
- ढ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी वैश्विक निर्माताओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली दक्ष प्रौद्योगिकी से हल्की होती है। बेहतर प्रौद्योगिकी वाले एकमात्र आवेदक मुंडदा सोलर पीवी लिमिटेड की अधिकतम वार्षिक क्षमता केवल 1200 मेगावाट है और घरेलू उद्योग भारत के बाहर से बेहतर प्रौद्योगिकी वाले मॉड्यूल आयात करने के लिए बाध्य होगा।
- ण. सौर ऊर्जा विकासक भारत के अंदर उल्लेखनीय रोजगार के सृजन के लिए जिम्मेदार हैं और प्रत्येक 1 मेगावाट सौर ऊर्जा से कम से कम 2 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलना चाहिए। एसजीडी लगाने से नई परियोजनाएं स्थापित करना वित्तीय रूप से अव्यवहार्य होने के कारण उद्योग द्वारा रोजगार सृजन में अत्यधिक कमी आएगी।
- त. रक्षोपाय शुल्क लगाना उद्योग के विकास के लिए हानिकारक होगा चूँकि इससे शुल्क में प्रति यूनिट 3.95-4.05 रुपये की वृद्धि होगी।
- थ. घरेलू उद्योग यह स्थापित नहीं कर पाया है कि क्या नुकसान, यदि हुआ है, कुछ देशों द्वारा उत्पादों की डंपिंग करने के कारण हुआ है अथवा बढ़े हुए आयात के कारण हुआ है। आवेदकों का स्पष्ट रूप से मानना था कि नुकसान निर्यात करने वाले देशों द्वारा डंपिंग के कारण हुआ है जैसा कि एंटीडंपिंग की जांच के लिए किए गए आवेदनों से स्पष्ट है, इसलिए वे अब बढ़े हुए आयात के कारण नुकसान की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकते।
- द. एसजीडी जन हित के विरुद्ध है चूँकि शुल्क लगाने से ऐसी स्थिति आएगी जहां सौर ऊर्जा जनता के लिए महंगी तथा पहुँच से बाहर हो जाएगी। ऐसा कोई भी व्यापार उपाय सरकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने और वर्ष 2020 तक 100 गीगा वाट का लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करेगा।

(xxiii) ताइवान आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र

- क. यह प्राधिकरण पूर्व में पीयूसी पर एंटी-डंपिंग जांच कर रहा था और इसे एंटी-डंपिंग जांच और चालू रक्षोपाय जांच के आंकड़ों के समूहों की तुलना करने में और यह निर्धारण करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि क्या रक्षोपाय याचिका उचित है।
- ख. ताइवान एक विकासशील देश है और यह रक्षोपाय समझौते (एओएस) के अनुच्छेद 9.1 में अपेक्षित न्यूनतम स्तर तक नहीं पहुंचा है और इस पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता।
- ग. भारत की राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई कई सौर निविदाओं के लिए शुल्क के संबंध में अनिश्चितता के कारण बोलीकर्ताओं से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
- घ. याचिकाकर्ताओं के पास एओएस के अनुच्छेद 4.1 की शर्तों के अनुसार घरेलू उद्योग माने जाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है इसलिए याचिकाकर्ताओं की स्थिति की सौर सेल तथा सौर मॉड्यूल के लिए अलग से जांच की जानी चाहिए। सौर मॉड्यूल के लिए याचिकाकर्ताओं की संस्थापित क्षमता भारत की संस्थापित क्षमता की 15% है, जिसका अर्थ है कि यदि याचिकाकर्ता उनकी पूर्ण क्षमता के अनुसार निर्माण करें तो सौर मॉड्यूल के लिए उनका हिस्सा 15% है। इसलिए समेकित उत्पाद सौर सेल तथा सौर मॉड्यूल के कुल घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा नहीं है।
- ड. प्रारंभिक निष्कर्षों में एनएसएम द्वारा सृजित मांग के कारण बढ़े हुए आयात को अनपेक्षित घटनाक्रम नहीं माना गया है।

- च. आईटीए-1 के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के परिणामस्वरूप वर्ष 2005 में पीयूसी पर आयात शुल्क शून्य हो गया, परंतु प्रारंभिक निष्कर्षों में यह चिह्नित नहीं हो पाया है कि कैसे 12 वर्ष पहले प्रभावी हुए इस जीएटीटी दायित्व से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2010 में एनएसएम की शुरुआत किए जाने के बाद आयात बढ़ा।
- छ. भारतीय निर्माता भारत की लगभग 10-15% वार्षिक मांग पूरी कर सकते हैं और शेष आयात द्वारा पूरा किया जाना होता है।
- ज. नुकसान की अवधि के दौरान तीन याचिकाकर्ताओं की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ परंतु केवल दो अन्य याचिकाकर्ताओं को आंतरिक समस्याओं जैसे कॉर्पोरेट ऋण की पुनर्संरचना आदि के कारण नुकसान हुआ।
- झ. नुकसान का एक प्रमुख कारण याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्यात में कमी है। याचिका में याचिकाकर्ताओं के निर्यात में भारी कमी दर्शाई गई है और यह वर्ष 2014-15 में 100 इंडेक्स अंकों से कम हो कर वर्ष 2017-18 (सालाना) में 13 इंडेक्स अंक पर आ गया। ऐसे कारणों से नुकसान की वजह पीयूसी के आयात को नहीं माना जा सकता।
- ञ. तेजी से बढ़ती क्षमताओं, जिन्हें स्थिर करना याचिकाकर्ताओं के लिए मुश्किल हो रहा है, के कारण लागत में ब्याज तथा मूल्य-ह्रास से संबंधित वृद्धि हुई है।
- ट. नुकसान की अवधि में याचिकाकर्ताओं के कर्मचारियों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है जिससे याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक की लागत में 4 गुना वृद्धि हुई है जो कि नुकसान का एक और कारण है।
- ठ. एमएनआई एक सुनिश्चित डीसीआर घटक लाने की योजना बना रहा है जिसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग के पास एक सुनिश्चित बाजार होगा।
- ड. पतली फिल्मों का आयात भारत में होने वाले कुल उत्पाद के 1% से भी कम है और इससे कोई गंभीर नुकसान नहीं हो सकता और इसे उत्पादों की सूची से बाहर किया जाना चाहिए।
- ढ. याचिकाकर्ताओं ने उनकी व्यक्तिगत समायोजन योजनाओं के संबंध में गोपनीयता की मांग की है जिससे ताइवान के लिए एओएस के अनुच्छेद 7.1 के तहत याचिकाकर्ताओं के प्रयासों के संबंध में कोई अर्थपूर्ण टिप्पणी देना मुश्किल हो जाता है।
- ण. समायोजन योजना के तहत लागत में कमी, उत्पादों की संख्या में वृद्धि, वेफर्स तथा सिल्लियों के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करने के रूप में पश्चवर्ती एकीकरण से केवल अगले कुछ वर्षों में लागत बढ़ेगी। ऐसी समायोजन योजना व्यवहार्य नहीं है और यह एओएस के अनुच्छेद 7.1 के संदर्भ में समायोजन को सुविधाजनक नहीं बनाएगी।
- त. ताइवान को एक विकाशशील देश माना जाना चाहिए क्योंकि डब्ल्यूटीओ के समझौतों में स्थापित स्व-मान्यता सिद्धांतों के अनुसार ताइवान स्वयं को विकाशशील देश मानता है।

(xxiv) घरेलू उद्योग

- क. जिस उत्पाद पर विचार किया जा रहा है वह है 'सौर सेल, मॉड्यूल्स अथवा पैनल्स में एकत्रित अथवा नहीं'। इस उत्पाद को सामंजस्यपूर्ण वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली, जिसे एचएसएन के रूप में जाना जाता है, के उप-शीर्ष 8541.40 और भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण के उप-शीर्ष 8541.40.11 के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- ख. ये उत्पाद *सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में व्यापार संबंधी मंत्रालयी घोषणा*, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) के रूप में जाना जाता है, के संलग्नक ए, धारा 1 के तहत शामिल किए गए हैं। आईटीए-1 में सूचीबद्ध उत्पादों पर सीमा शुल्क प्रभार तथा अन्य किसी प्रकार के प्रभार/शुल्क [जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद II: 1(बी) में दिए गए अर्थ के अनुसार] को हटाने का अधिदेश दिया गया था। चूंकि भारत ने आईटीए-1 पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए आयातित किए गए ये उत्पाद आधारभूत सीमा शुल्क से छूट प्राप्त हैं।
- ग. संगत प्रशुल्क शीर्ष सेल, मॉड्यूल तथा पतली फिल्म को एक उत्पाद के रूप में चिह्नित करता है और सभी तीन प्रकारों अर्थात् सी-एसआई सौर सेल, सी-एसआई सौर मॉड्यूल/पैनल और पतली फिल्म मॉड्यूल/पैनलों पर शुल्क में छूट लागू है।
- घ. दो प्रमुख प्रकार के सौर सेल होते हैं एक जिनमें क्रिस्टलीय सिलिकॉन (सी-एसआई) प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है और दूसरा जिनमें पतली फिल्म प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। आवेदक केवल सी-एसआई प्रकार के सौर सेल का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि आयात किए जाने वाले सेल में सी-एसआई प्रकार के और पतली फिल्म प्रकार के दोनों प्रकार के सेल का आयात किया जा रहा है।
- ड. चिह्नित करने की प्रक्रिया जांच के अधीन उत्पाद अथवा (पीयूसी) को चिह्नित करने से शुरू होती है। पीयूसी में सौर सेल शामिल होती हैं चाहे वे मॉड्यूल्स अथवा पैनलों में एकत्रित हों अथवा नहीं। पीयूसी में सभी सौर सेल शामिल होती हैं चाहे उनके

- निर्माण में किसी भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया हो। भारत में आयात में सी-एसआई और पतली फिल्म प्रौद्योगिकियों वाले सौर सेल शामिल होते हैं। आयात किए गए सी-एसआई प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए घरेलू रूप से उत्पादित सी-एसआई प्रौद्योगिकी वाली सेल समान वस्तु होंगी। भारत में आयात किए गए पतली फिल्म प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों के लिए घरेलू रूप से उत्पादित सी-एसआई प्रौद्योगिकी वाले उत्पाद 'प्रत्यक्ष प्रतियोगिता' वाली वस्तुएँ होंगी।
- च. दोनों प्रकार की सौर सेल के बीच कोई खास अंतर न होने के कारण इस मामले में सी-एसआई प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों और पतली फिल्म प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों के बीच अंतर करने का परिणाम होगा "समान अथवा प्रत्यक्ष प्रतियोगिता वाले उत्पाद" को परिभाषित नहीं करना बल्कि ऐसे समान अथवा प्रत्यक्ष प्रतियोगिता वाले उत्पादों के एक हिस्से को परिभाषित करना। ऐसा दृष्टिकोण डोमिनिकन गणराज्य – रक्षोपाय उपायों में डब्ल्यूटीओ के पैनलों के समझौते के तहत दिए गए अधिदेश के अनुसार समान अथवा प्रत्यक्ष प्रतियोगिता वाले उत्पादों के निर्धारण के असंगत है।
- छ. प्रचालन अथवा अंतिम उपयोग के संदर्भ में निर्मित दोनों सौर सेल के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, चूंकि सी-एसआई और पतली फिल्म प्रौद्योगिकियों पर आधारित सौर सेल का प्रयोग फोटोवोल्टिक प्रक्रिया का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तदनुसार आयातित उत्पादों के संबंध में एक "प्रत्यक्ष प्रतियोगी/प्रतिस्थापित किए जाने योग्य उत्पाद" के निर्धारण के लिए दोनों प्रकार के सौर सेल के बीच अंतर करने हेतु कोई आधार न होने के कारण पीयूसी का "मॉड्यूल अथवा पैनलों में संकलित अथवा संकलित नहीं सौर सेल" के रूप में सही निर्धारण किया गया है।
- ज. निर्दिष्ट प्राधिकरण एंटी-डंपिंग तथा संबद्ध शुल्क निदेशालय (डीजीएडी) ने पूर्व में चीन, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की थी। इस आवेदन में संबंधित वस्तुओं का दायरा उपर्युक्त एंटी-डंपिंग जांच के समान है।
- झ. विचाराधीन उत्पाद की श्रेणी में पतली फिल्मों को शामिल करना और/अथवा बाहर रखना प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर एक मामला-दर-मामला निर्धारण है। भारत में वर्तमान मामले से संबंधित तथ्य जांच के अधीन उत्पाद की श्रेणी में पतली फिल्मों को शामिल करना अनिवार्य बना देते हैं। अन्यथा यह पूरी प्रक्रिया रक्षोपाय शुल्क को दरकिनार करने की ओर चली जाएगी चूंकि आयातक किसी प्रकार के शुल्क से बचने के लिए सीधे पतली फिल्मों की ओर चले जाएंगे। यह नोट करना भी उचित होगा कि "पतली फिल्म के मॉड्यूल" भी उसी शीर्ष के अंतर्गत आयात किए जाते हैं और इन्हें भी सौर सेल/मॉड्यूल की तरह आधारभूत सीमा शुल्क से छूट प्राप्त होती है। वर्ष 2014 में सौर सेल के संबंध में एंटीडंपिंग जांच के अंतिम निष्कर्षों में एलडी. निर्दिष्ट प्राधिकरण ने निर्णय दिया कि सी-एसआई उत्पादों और पतली फिल्म उत्पादों को जांच के अधीन उत्पाद की श्रेणी के अंदर शामिल किया जाएगा।
- ञ. अंत में एलडी. निर्दिष्ट प्राधिकरण ने उचित निष्कर्ष देते हुए कहा कि पतली फिल्म को समान वस्तु की श्रेणी के अंदर माना जाना चाहिए क्योंकि भारत में पतली फिल्म और क्रिस्टलीय उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक तथा उल्लेखनीय है और पतली फिल्म मॉड्यूल की कम दक्षता से पतली फिल्म उत्पादों की मांग में वृद्धि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है। उपभोक्ता दोनों उत्पादों को एक उत्पाद की तरह देखते हैं और उन्हें उत्तम प्रतिस्थापन मानते हैं। भारत में विद्यमान ऐसी बाजार स्थितियों में एक उत्पाद को बाहर रखने से अन्य प्रकार के उत्पादों के लिए पीछे के दरवाजे से प्रवेश खुल जाएगा जिससे पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसलिए फिल्म को समान वस्तुओं की श्रेणी से बाहर नहीं रखा जा सकता अन्यथा प्रयोक्ता सीधे पतली फिल्म प्रौद्योगिकी की ओर चले जाएंगे जिससे पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य विफल हो जाएगा।
- ट. सेल तथा मॉड्यूल एक ही उत्पाद हैं। निर्दिष्ट प्राधिकरण ने वर्ष 2014 के अपने पूर्व के निर्णय में भी सौर सेल और मॉड्यूल को एक ही उत्पाद माना था।
- ठ. याचिकाकर्ता संबंधित वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और इसलिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8बी(6)(बी) के अर्थ के अनुसार घरेलू उद्योग माने जाने चाहिए चूंकि याचिकाकर्ताओं का कुल सामूहिक उत्पादन भारत में पीयूसी के कुल उत्पादन के 50% से अधिक है। इसलिए वे कुल भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए भारत में समान वस्तुओं का घरेलू उद्योग कहलाने योग्य हैं। एलडी. डीजी रक्षोपाय ने भी 05.01.2018 के प्रारंभिक निष्कर्षों में इस बात की पुष्टि की कि याचिकाकर्ता भारत में संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा रखते हैं और इसलिए वे घरेलू उद्योग कहलाने योग्य हैं।
- ड. एलडी. डीजी रक्षोपाय ने पाया कि मैसर्स मुंडडा सोलर पीवी लिमिटेड, मैसर्स वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड और मैसर्स हेलियोस फोटो वोल्टिक लिमिटेड विशेष आर्थिक जोन (सेज) में स्थित हैं और इसलिए रक्षोपाय शुल्क लगाते समय इन्हें पर्याप्त उपाय के माध्यम से लेवी से छूट दी जा सकती है। तथापि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने पर एक सेज से डीटीए को विचाराधीन वस्तुओं की स्वीकृति पर कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाएगा। यह सेज अधिनियम, 2005 की धारा 8बी(2ए) और धारा 30 को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। संदर्भ की सुलभता के लिए सेज अधिनियम, 2005 की धारा 30(ए)।

- द. सेज अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अंतर्गत एडीडी, सीवीडी और एसजीडी लगाए जाने के साथ 'जहां लागू हो' शब्द जोड़ा गया है। इसलिए व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी दिए गए मामले में कब एंटी-डंपिंग शुल्क, प्रतिकारी शुल्क अथवा रक्षोपाय शुल्क लागू होता है।
- ण. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबंधित धारा 9ए, प्रतिकारी शुल्क से संबंधित धारा 9 और रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से संबंधित धारा 8बी सभी की भाषा में पूर्णतया निश्चित शब्दों में उल्लेख किया गया है कि ये भारत में किसी वस्तु के आयात पर लागू होते हैं। इसलिए यदि कोई वस्तु भारत में आयात नहीं की जाती तो उपर्युक्त में से कोई शुल्क देय नहीं होगा। यद्यपि एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा एक कानूनी टकराव बनता है जहां सेज को भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर माना जाता है। भारत के किसी विद्यमान कानून के तहत कोई प्रावधान नहीं है जो एक सेज में निर्मित वस्तुओं को सेज से डीटीए को भेजे जाने को आयात मानता हो। यह तथ्य कि एक सेज में निर्मित वस्तुओं को सेज से डीटीए में भेजना भारत के क्षेत्र में आयात नहीं माना जाता अदालत के कई निर्णयों में भी दोहराया गया है जिनमें एस्सार स्टील बनाम भारत संघ [2010 जीएलएच (1) 52], इंडिया एक्स्पोर्ट्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [(2012) 47 वीएसटी 126], तिरुपति उद्योग लिमिटेड, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रबन्धक-प्रशासन श्री डी.वी. सराध्य द्वारा किया गया था, बनाम भारत संघ (यूओआई), जिसका प्रतिनिधित्व सचिव, वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था, एवं अन्य [2011 (272) ईएलटी 209(आ.प्र.)] शामिल हैं। इसलिए आयात के तथ्य के बिना एंटी-डंपिंग शुल्क, प्रतिकारी शुल्क अथवा रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जा सकता।
- त. पाटनरोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क देश विशिष्ट होते हैं और इसलिए यदि एक सेज में निर्मित और अंत में डीटीए को भेजी गई किसी समान वस्तु के अनुरूप उपर्युक्त शुल्क लगाए जाते हैं तो भी इन पर उपर्युक्त शुल्क नहीं लगाए जा सकते क्योंकि भारत के क्षेत्र में ही एक सेज के विरुद्ध डंपिंग अथवा सब्सिडी का आरोप लगाते हुए कोई एंटी-डंपिंग अथवा प्रतिकारी जांच कभी नहीं हो सकती और परिणामस्वरूप ऐसा कोई शुल्क लगाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसलिए सेज अधिनियम, 2005 की धारा 30 में दिए गए शब्दों के अर्थ को प्रभावी बनाने के लिए डीटीए स्वीकृति के दौरान उल्लिखित एंटी-डंपिंग शुल्क तथा प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने के उल्लेख का अर्थ अंतिम रूप से तैयार उत्पाद पर प्रयुक्त इनपुट के मूल्य पर देय शुल्क से होगा (यदि विनिर्दिष्ट देशों से आयातित इनपुट पर एंटी-डंपिंग शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क लागू हो) न कि तैयार उत्पाद पर, बाद की स्थिति असंभव है।
- थ. यही सिद्धान्त किसी समान वस्तु, जिसका निर्माण भी एक सेज में किया गया है और इसे डीटीए को भेजा गया है, पर लगाए गए रक्षोपाय शुल्क के लिए भी लागू है। यदि रक्षोपाय शुल्क आयात किए गए तथा अंत में डीटीए को भेजे गए अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट के विवरण पर लागू न किया गया हो, जिस मामले में रक्षोपाय शुल्क इनपुट के उसी मूल्य पर लगाया जाएगा (यह मानते हुए कि इनपुट पर रक्षोपाय शुल्क लागू है) जिसका प्रयोग अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के निर्माण में किया गया, अंतिम रूप से तैयार उत्पाद पर कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाएगा चाहे यह कोई समान वस्तु हो जिस पर भारत ने रक्षोपाय शुल्क लगाया है। यह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8बी(2ए) से भी स्पष्ट है। इसलिए सेज अधिनियम, 2005 की धारा 30 को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8बी(2ए) के साथ पढ़ने से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि रक्षोपाय शुल्क केवल अंतिम रूप से तैयार उत्पादों में प्रयुक्त इनपुट पर देय है और न कि अंतिम रूप से तैयार उत्पाद पर जिसका निर्माण सेज में किया गया है और जिसे डीटीए में भेज दिया गया है।
- द. एक सेज में निर्मित और डीटीए में भेज दिए गए अंतिम रूप से तैयार उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क एक अतिरिक्त कारण से भी देय नहीं होगा अर्थात् एक ऐसी स्थिति में जहां भारत द्वारा डीटीए में एक अंतिम रूप से तैयार उत्पाद में प्रयुक्त विवरण और अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के विवरण पर भी रक्षोपाय शुल्क लगाया गया है, तब डीटीए में भेजते समय प्रयुक्त इनपुट और अंतिम रूप से तैयार उत्पाद दोनों पर रक्षोपाय शुल्क लगेगा जिसके कारण दोहरा कर लगेगा। इस प्रकार शुल्क लगाया जाना अवैध होने के कारण सेज अधिनियम, 2005 की धारा 30 में एंटी-डंपिंग शुल्क, प्रतिकारी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क के उल्लेख का अर्थ हमेशा इनपुट का मूल्य होगा अन्यथा शुल्क लागू नहीं किया जा सकेगा।
- ध. भारत में जांच की अवधि के दौरान संबंधित वस्तुओं के आयात में तीव्र वृद्धि देखी गई है। भारत में चीन पीआर, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान सहित विभिन्न देशों से पीयूसी आयात किया जा रहा है। विचाराधीन वस्तुओं की अधिकतर मात्रा चीन पीआर से आयात की जा रही है। संबंधित उत्पादों का आयात वर्ष 2014-15 में 1,275 मेगावाट से बढ़ कर 2017-18 में 9,474 मेगावाट हो गया (सालाना), अर्थात् पिछले तीन वर्ष के दौरान 643% की वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्ष में आयात की मात्रा सतत रूप से बढ़ी है।
- न. वर्ष 2015-16 में आयात पिछले वर्ष की तुलना में 228% बढ़ा। इसी प्रकार आयात में वर्ष दर वर्ष वृद्धि वर्ष 2016-17 में 52% थी और 2017-18 में 49% थी जिससे इस बात में कोई संदेह नहीं रहता कि प्रत्येक वर्ष आयात की मात्रा उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। इसके अतिरिक्त एलडी. डीजी रक्षोपाय ने 05.01.2018 के प्रारंभिक निष्कर्षों में यह निष्कर्ष भी निकाला है कि वर्ष

2017-18 के पहले छः माह में आयात की मात्रा में अचानक तीव्र वृद्धि हुई है जो कि वर्ष 2016-17 के आयात के लगभग 74% के समान है। इसलिए आयात में निरपेक्ष वृद्धि हुई थी जो कि किसी भी मानदंड पर हाल ही की, अचानक, तीव्र तथा उल्लेखनीय थी।

- प. इसके अतिरिक्त भारत में विचाराधीन वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में भी आयात में वृद्धि हुई जिसे डीजी रक्षोपाय ने भी माना जिन्होंने पाया कि घरेलू उत्पादन की तुलना में पीयूसी का आयात वर्ष 2014-15 और 2017-18 के बीच लगातार बढ़ा है (सालाना)। बीच के वर्ष 2015-16 के दौरान घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में ऐसे आयात की वृद्धि दर उल्लेखनीय रूप से 1,371% थी। यहाँ तक कि घरेलू उत्पादन की तुलना में विचाराधीन वस्तुओं के आयात की समग्र वृद्धि दर वर्ष 2014-15 में 519% से बढ़ कर वर्ष 2017-18 में 814% हो गई। इस प्रकार पूरे पीओआई के दौरान घरेलू उत्पादन की तुलना में पीयूसी के आयात की मात्रा में न केवल लगातार वृद्धि देखी गई बल्कि ऐसी वृद्धि को उल्लेखनीय भी माना गया।
- फ. आयात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि आयात के मूल्य में वृद्धि के संदर्भ में भी प्रदर्शित होती है। आयात का मूल्य वर्ष 2014-15 के दौरान 3,991.21 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2017-18 के दौरान 21,701.38 करोड़ रुपये हो गया (सालाना)। तथापि मूल्य में वृद्धि आयात की मात्रा में वृद्धि के अनुपात में नहीं थी चूंकि इस अवधि के दौरान आयात मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई। वर्ष 2014-15 के दौरान सीआईएफ मूल्य 30.98 रुपये प्रति वाट था परंतु 2017-18 के दौरान यह घट कर 23.03 रुपये हो गया (सालाना)।
- ब. आयात में वृद्धि अत्यधिक कम मूल्य पर हुई है और पूरे पीओआई के दौरान आयात मूल्य में लगातार कमी आई है। परिणामस्वरूप सस्ते आयात में इस वृद्धि से घरेलू उद्योग को बहुत नुकसान हुआ है और यह इसके अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गया है।
- भ. अनुच्छेद XIX की मूल आवश्यकता को देखते हुए जिस घटनाक्रम के कारण सौर सेल का इतनी अधिक मात्रा में आयात हुआ और ऐसी स्थितियों में हुआ जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा ऐसा घटनाक्रम “अनपेक्षित” होना चाहिए था। ‘अनपेक्षित घटनाक्रम’ शब्द के क्षेत्र तथा अर्थ का निर्धारण करते हुए कोरिया-डेयरी और अर्जेन्टीना-फुटवियर (ईसी) में डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय ने निर्णय दिया कि यह “अप्रत्याशित” का समानार्थी है।
- म. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई घटना अनपेक्षित घटना थी किए जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या भुगतान का दायित्व लेते समय इसकी अपेक्षा की गई थी। अपीलीय निकाय के निर्णय के अनुसार परीक्षण यह नहीं है कि क्या घटनाक्रम अनपेक्षित था। बल्कि परीक्षण यह है कि भुगतान का दायित्व लेते समय क्या यह अनपेक्षित था अर्थात् डब्ल्यूटीओ के साथ समझौता, विभिन्न डब्ल्यूटीओ समझौतों के तहत प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करने का संकल्प, शुल्क में छूट देना और बाद में सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में व्यापार के संबंध में मंत्रालयी घोषणा (आईटीए 1) के माध्यम से शुल्क में उन छूट में संशोधन। इसलिए ये घटनाक्रम 13 दिसंबर, 1996 को अनपेक्षित अथवा अप्रत्याशित होना चाहिए था – जिस तारीख को मंत्रियों ने आईटीए 1 पर सहमति दी।
- य. जिस घटनाक्रम से भारत में विचाराधीन वस्तुओं का अत्यधिक मात्रा में आयात हुआ वह संयुक्त राज्य अमेरिका में (i) क्रिस्टलीय सिलिकॉन फोटोवोल्टोक (सीएसपीवी 1) जांच, जो 07.12.2012 को प्रभावी हुई और (ii) सीएसपीवी 2 जांच, जो 18.02.2015 को प्रभावी हुई, से संबंधित एंटी-डंपिंग तथा प्रतिकारी शुल्क आदेशों के परिणामस्वरूप चीनी आयात तथा भारत के बीच व्यापार पद्धति में बदलाव था। ईयू में भी इन्हीं वस्तुओं के संबंध में अंतिम उपाय 05.06.2013 को लागू हुआ और अंतिम उपाय 05.12.2013 को लागू कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईयू द्वारा लागू किए गए उपायों का समय एक दूसरे के आस-पास था और इनमें बहुत कम अथवा न के बराबर भिन्नता थी। इन उपायों का तत्काल प्रभाव जेएनएनएसएम के तहत घरेलू विषय-वस्तु आवश्यकताओं (डीसीआर) की उपस्थिति के कारण नजर नहीं आया।
- र. डीसीआर को वर्ष 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय के समक्ष चुनौती दी गई। सितंबर, 2016 में संयुक्त राज्य की जीत हुई जब डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय ने निर्णय दिया कि डीसीआर भारत द्वारा जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद III:4 और टीआरआईएमएस समझौते के अनुच्छेद 2.1 के तहत किए गए भुगतान के दायित्वों के असंगत है। डीसीआर को हटाए जाने के बाद व्यापार पद्धति में बदलाव स्पष्ट हो गया चूंकि इन उत्पादों की भारत में अत्यधिक मांग है। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा वर्ष 2022 तक 100 गीगा वाट की सौर ऊर्जा सृजन का महतवाकांक्षी तथा सराहनीय लक्ष्य रखे जाने के कारण और अधिक मांग हुई।
- ल. अनपेक्षित घटनाक्रम ने आयातित विचाराधीन वस्तुओं और घरेलू उद्योग के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों को संशोधित कर दिया है चूंकि संयुक्त राज्य और ईसी द्वारा प्रतिकारी तथा एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने से पहले भारत में चीन का निर्यात केवल 1.52% था जबकि ईसी तथा यूएसए को निर्यात 75.93% था। तथापि इन व्यापार सुधार उपायों के बाद चीन के निर्यात बाजार में आधारभूत बदलाव हुआ। वर्ष 2017 की स्थिति के अनुसार यूएसए और ईसी में मिला कर चीन का निर्यात केवल 10.7% है जबकि भारत में इसका निर्यात 29.8% है।

- व. यह बताने के लिए ऑन रिकॉर्ड कोई प्रमाण नहीं है कि भारत ने ईयू और यूएस द्वारा एक साथ चीन से निर्यात पर व्यापार सुधार उपाय लागू किए जाने का पूर्वानुमान कर लिया हो और इसलिए ये घटनाक्रम अप्रत्याशित था। इसके अतिरिक्त भारत का सही मायने में मानना था कि जेएनएनएसएम के तहत डीसीआर जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद XX में दिए गए अपवादों के संगत था। इसलिए भारत आईटीए:1 के तहत भुगतान का दायित्व लेते समय यह अनुमान नहीं कर सकता था कि इसकी डीसीआर, जिसे यह जीएटीटी के अनुच्छेद XX के संगत मानता था, उसे संधियों तथा समझौतों के तहत भुगतान के लिए गए दायित्वों के असंगत मान लिया जाएगा। परिणामस्वरूप पीयूसी के लिए भारत का बाजार सभी देशों से असंयमित आयात के लिए खुल गया।
- श. व्यापार की पद्धति में इस उल्लेखनीय बदलाव, जहां चीन ने ईयू और यूएसए आदि जैसे विकसित देशों/बाजारों की तुलना में भारतीय बाजार को पूरे ज़ोर से लक्षित करना शुरू कर दिया, का तार्किक रूप से अनुमान नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार घरेलू उद्योग के सामने बाजार में पूरी तरह से नया परिदृश्य प्रचालित हो रहा था। घरेलू उद्योग आगे चीनी निर्यातकों द्वारा क्षमता में अभूतपूर्व तथा अनपेक्षित विस्तार के कारण भी संकट में आ गया जिसे राज्य द्वारा प्रोत्साहन, सब्सिडी तथा टैरिफ के रूप में सहारा दिया गया।
- ष. एक अन्य अनपेक्षित घटनाक्रम यह है कि चीनी सौर उद्योग के विकास के शुरुआती चरणों में चीन सौर सेल तथा मॉड्यूल के निर्माण के लिए आवश्यक बहुत सा कच्चा माल, विशेष रूप से पॉलीसिलिकॉन का आयात करता था। तथापि घटनाक्रम में एक अनपेक्षित बदलाव से चीन के पॉलीसिलिकॉन उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई जिससे चीन को एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी लाभ मिला। शुरुआती वर्षों में चीन के पास पॉलीसिलिकॉन के निर्माण के लिए आवश्यक अत्यधिक पूंजी अथवा तकनीकी विशेषज्ञता नहीं थी। परंतु जब तीन चीनी कंपनियों अर्थात् सनटेक, यिंगली और कैनेडियन सोलर वर्ष 2005 और 2006 में न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सार्वजनिक रूप से गईं, तो एक विशाल सौर निर्माण विस्तार शुरू हो गया। पॉलीसिलिकॉन की मांग तेजी से बढ़ गई और हाजिर मूल्य 2004 में 50 \$ प्रति किलोग्राम से वर्ष 2008 में लगभग 475 \$ हो गया। एक बड़े अवसर को देखते हुए चीनी कंपनी जीसीएल ने पॉलीसिलिकॉन का निर्माण शुरू किया और अगले एक दशक में यह उल्लेखनीय रूप से बढ़ कर विश्व की सबसे बड़ी पॉलीसिलिकॉन निर्माता कंपनी बन गई। संयुक्त राज्य और चीन के बीच व्यापारिक युद्ध भी चीन के पक्ष में सिद्ध हुए। वर्ष 2012 में संयुक्त राज्य द्वारा यूएस में बेचे जाने वाले चीन में निर्मित सौर सेल पर शुल्क लगाए जाने के बाद चीन ने भी अपने यहाँ बेचे जाने वाले यूएस-निर्मित पॉलीसिलिकॉन पर शुल्क लगा दिए, और इस उपाय से चीन में पॉलीसिलिकॉन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए लाभदायक स्थिति बनी। यह लाभदायक स्थिति वैश्विक बाजार में निर्णायक सिद्ध हुई। चीन अब विश्व के 90% से अधिक पॉलीसिलिकॉन का निर्माण करता है। सौर वस्तुओं के निर्माण में महत्वपूर्ण कच्चे माल के उत्पादन की यह क्षमता चीनी कंपनियों को उनके किसी भी प्रतिस्पर्धी की तुलना में बहुत कम मूल्य पर अपने उत्पाद निर्यात करने की क्षमता देती है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, भारतीय घरेलू उद्योग चीनी सौर कंपनियों की आक्रामक मूल्यन नीतियों के परिणामस्वरूप बड़े झटकों का सामना कर रहा है।
- स. पॉलीसिलिकॉन के अतिरिक्त सौर सेल तथा मॉड्यूल के निर्माण के लिए आवश्यक अन्य सभी प्रकार की सामग्री चीन में ही बनाई जाती है। जो कंपनियाँ पूर्व में किसी अन्य व्यवसाय में थीं वे सौर सामग्री तथा टूलिंग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सौर आंदोलन में कूद पड़ीं। चीन की बढ़ती हुई निर्माण क्षमता वर्तमान क्षेत्रीय आपूर्तिकर्ताओं और नए आपूर्तिकर्ताओं को पर्याप्त बाजार अवसर उपलब्ध कराती है। कम लागत पर श्रम शक्ति तथा बड़ी संख्या में निर्माण के लाभों, जो चीन को पहले ही मिल रहे हैं, के अतिरिक्त घरेलू रूप से कच्चे माल तथा टूलिंग के उत्पादन की क्षमता उन सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से है जिनके कारण चीन में बनाई जाने वाली सौर वस्तुएँ अन्य किसी भी देश में बनाए जाने वाले सौर उत्पादों से सस्ती हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चीनी पॉलीसिलिकॉन तथा सौर टूलिंग उद्योग का विकास घटनाक्रम में एक अनपेक्षित तथा बिना किसी इरादे के आए घुमाव का परिणाम है जिसके कारण भारत जैसे देशों के लिए चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करना अथवा अपने स्वयं के सौर उद्योग को बनाए रखना लगभग असंभव हो गया।
- ह. एक अन्य अनपेक्षित घटनाक्रम है चीनी सरकार द्वारा अपने उत्पादकों को निर्माण में दिए जाने वाला समर्थन। इस संबंध में जो विशेष रूप से चीनी सौर निर्माण उद्योग के तीव्र विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है वह है वाणिज्यिक तथा सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों, नगरपालिका सरकारों तथा निवेश कॉर्पोरेशन (नगरपालिका सरकार के समर्थन से) से वित्तीय सहयोग। यह भूमि शुल्क तथा कर (कॉर्पोरेट आय कर, वैट तथा ऋण पर ब्याज) की वापसी अथवा छूट, बिजली उपभोग शुल्क की वापसी, वैट की वापसी तथा अनुसंधान एवं विकास उपकरणों के लिए आयात शुल्क, विभिन्न निवेश अनुदानों, ऋण गारंटी आदि सहित सौर निर्माण के लिए दिए जाने वाले कई उदार प्रोत्साहनों के अतिरिक्त है।
- क्ष. वर्ष 2010 में ही चीन विकास बैंक (सीडीबी) ने पाँच सर्वोच्च घरेलू निर्माताओं: एलडीके सोलर, सनटेक पावर, यिंगली, जेए सोलर और विना को कुल क्रेडिट सुविधाओं में अभूतपूर्व रूप से 30.41 बिलियन \$ की राशि प्राधिकृत की। और 2005 तथा

2013 के बीच सीडीबी ने चीन के प्रमुख सौर निर्माताओं को क्रेडिट सुविधाओं में लगभग 31.35 बिलियन \$ की राशि दी। यह इस अवधि के दौरान इन कंपनियों को उपलब्ध कराए गए कुल सार्वजनिक रूप से प्रकटित क्रेडिट का केवल लगभग 70% ही है। इसलिए ऐसे समय में जब विश्व के अधिकतर वित्तीय बाजार रुके हुए थे तब चीनी सौर निर्माताओं को एक बैंक कई बिलियन डॉलर का ऋण देने के लिए तैयार था। यह पूरे विश्व की परिस्थितियों के बिल्कुल प्रतिकूल है जहां सौर तथा अन्य नवीकरणीय-ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बैंक द्वारा उधार दिए जाने में उल्लेखनीय रूप से कमी आई थी। इस तरलता और पूंजी तक लगभग असीमित पहुँच ने चीनी सौर निर्माताओं को अत्यधिक विस्तार करने का अवसर दिया जिससे उन्हें अन्य देशों की कंपनियों, जो बाजार में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही थीं, पर नीतिगत बढ़त मिली।

- व. वर्ष 2016 में जब चीन की सबसे बड़ी सौर निर्माता कंपनी यिंगली गंभीर वित्तीय संकट में थी, तब चीनी बैंकिंग विनियामक आयोग ने सीडीबी से यह “सुनिश्चित” करने के लिए कहा कि यिंगली को नए ऋण के रूप में 1.16 \$ प्राप्त हों। इस ऋण से यिंगली को उसके विद्यमान ऋण चुकाने में सहायता मिली, जिससे एक संभावित चूक से कंपनी बच गई और नकद प्रवाह को पुनः चालू करने के लिए इसकी फैक्टरियों में उत्पादन को भी बढ़ाया गया। कुछ वर्ष पूर्व सनटेक को भी इस प्रकार सहारा दिया गया था। सनटेक, जिस कंपनी ने चीन का सौर उद्योग शुरू किया था, मार्च 2013 में सार्वजनिक रूप से ट्रेडेड ऋण में चूक करने वाली चीन की पहली कंपनी बन गई। इसने बाद में चीन और संयुक्त राज्य दोनों जगह दिवालिया सुरक्षा के लिए आवेदन किया। इस अवधि के दौरान जियांगसू प्रांत शहर, जहां सनटेक स्थित है, में वुक्सी नगरपालिका सरकार ने कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए 150 मिलियन \$ का ऋण उपलब्ध कराया और बाद में इसने इसे राजस्व कर में पाँच वर्ष की छूट भी दी। एलडीके को भी वर्ष 2016 में विभिन्न अनुदान तथा सब्सिडी दी गई जब इसकी कुछ सहायक कंपनियों ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया। इस प्रकार नकद दे कर तथा प्रोत्साहन दे कर बड़ी सौर कंपनियों को सहायता देना चीन की एक विशेषता है और इससे कई कंपनियों को वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने में सहायता मिली है और वर्तमान में यह निश्चित रूप से सौर उद्योग में एक अनपेक्षित तथा अप्रत्याशित घटना है।
- ज. चीन द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा विकास को उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता मानना भी एक अनपेक्षित घटनाक्रम था जिससे इसके निर्यात में तेजी आई और परिणामस्वरूप भारत में इसका आयात भी बढ़ा। वास्तव में नवीकरणीय ऊर्जा विकास उन सात नीतिगत उद्योगों में से एक है जिन्हें सरकार भविष्य के आर्थिक विकास के आधार के रूप में सहयोग देती है। इस संबंध में चीन सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम तथा प्रयास शुरू किए हैं। यहाँ विशेष रूप से नोट किए जाने वाला तथ्य यह है कि चीन ऐसी प्रौद्योगिकी पर बहुत जोर देता है जिसका शीघ्रता से तथा दक्षतापूर्वक व्यवसायीकरण किया जा सके।
- कक. राष्ट्रीय हाई टेक अनुसंधान एवं विकास (863) कार्यक्रम के तहत ऐसे शोध को वित्तपोषण किया जाता है जिसे एक अथवा दो वर्ष के अंदर बाजार में लाया जा सके। चीन ने सौर शोध के लिए 2 राज्य प्रमुख प्रयोगशालाएँ (एसकेएल) और 3 राज्य इंजीनियरिंग तथा अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं जो सरकार और उन बड़ी निजी सौर कंपनियों के साथ गहन समन्वय से इसी पद्धति पर काम करते हैं जिनके परिसर में ये प्रयोगशालाएँ स्थित हैं। यहाँ किए जाने वाले शोध को प्रकृति में अनुप्रयुक्त किया जाता है, जिनमें किसी नई उभरती हुई प्रौद्योगिकी के बजाय आसानी से बिक्री योग्य सिलिकॉन-आधारित प्रौद्योगिकियों में बार-बार सुधार करने पर जोर दिया जाता है। यह चीन में पिछले कुछ वर्षों में सिलिकॉन सेल की दक्षता में प्राप्त की गई विभिन्न उपलब्धियों को स्पष्ट करता है।
- खख. यह दृष्टिकोण चीनी कंपनियों द्वारा सौर पेटेंट प्राप्त करने में भी सहायक होता है। जिन पेटेंट के समाप्त होने की दर कम होती थी वे सामान्यतः ऐसे पेटेंट होते थे जिनके लिए व्यावसायिक बाजार है: अमोर्फस सिलिकॉन और गलियम-आर्सेनाइड (एक अन्य पतली-फिल्म प्रौद्योगिकी) के अतिरिक्त पॉलीसिलिकॉन, मोनोक्रिस्टलीन-सिलिकॉन, पीईआरसी, आईबीसी, एचआईटी और मल्टीजंक्शन (एक प्रौद्योगिकी जिसमें सेल में पी-टाइप और एन-टाइप सेमीकंडक्टर सामग्री के बीच कई इंटरफेस होते हैं)। यह बताता है कि चीनी अनुसंधान समुदाय कम-अवधि की प्रौद्योगिकियों के पेटेंट को उभरती हुई प्रौद्योगिकी से अधिक महत्व देता है। बिक्री योग्य सौर प्रौद्योगिकियों पर ऐसे गहन जोर से चीन को उल्लेखनीय रूप से इसके प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने में सहायता मिली है और चीन सरकार की कार्य प्रणाली में अस्पष्टता को देखते हुए भारत द्वारा इसका अनुमान लगाया जाना बहुत मुश्किल था।
- गग. इस घटनाक्रम के बाद एक मजबूत उत्पादन क्षमता से सुसज्जित चीनी निर्यातकों को इनके सौर सेल के निर्यात के लिए भारत में एक नया बाजार मिला। यह निर्यात बड़े पैमाने पर शुरू हो गया और जारी रहा और भारत में आयात 4 वर्ष की अवधि में 643% से अधिक बढ़ गया। चीन से पीयूसी के आयात में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है जो वर्ष 2015-16 के दौरान पिछले वर्ष से 3.3 गुना, 2016-17 में पिछले वर्ष से 1.52 गुना और वर्ष 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष से 1.48 गुना बढ़ी।
- घघ. इन अचानक, तीव्र तथा बड़े बदलावों को देखते हुए घरेलू उद्योग के सामने ऐसी स्थिति आ गई है जहां वे आयात के समक्ष अपने आप को बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं। न ही यूएसए और ईसी द्वारा चीन के विरुद्ध व्यापार उपाय अपनाने के कारण भारत को

चीन द्वारा आपूर्ति पर ज़ोर दिए जाने, न ही यूएसए द्वारा भारत के विरुद्ध उपाय अपनाने, जिनके कारण घरेलू उद्योग को दी जा रही डीसीआर की सुरक्षा हट गई, का पूर्वानुमान 13.12.1996 अर्थात् जिस तारीख को भारत ने डब्ल्यूटीओ के तहत दायित्व लिए थे, को किया जा सकता था।

- डड. यह दर्शाने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं कि चीन ने वर्ष 2012 से 2016 के बीच अपने सौर सेल तथा मॉड्यूल के उत्पादन को दुगने से भी अधिक कर लिया है। वर्ष 2012 में चीन 11.12 गीगा वाट सेल का उत्पादन करता था जो वर्ष 2016 में 27.78 गीगा वाट तक पहुँच गया। इसी प्रकार मॉड्यूल असेंबली वर्ष 2012 में 12.46 गीगा वाट से बढ़ कर 2016 में 35.47 गीगा वाट हो गई।
- चच. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि चीन की विचाराधीन वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता निर्यात उन्मुखी है। ये यह भी दर्शाते हैं कि चीन के पास उल्लेखनीय रूप से उच्च अतिरिक्त क्षमता है।
- छछ. आईटीसी व्यापार मानचित्र आंकड़े आयात में बढ़ोतरी को दर्शाने के लिए स्वतः स्पष्ट हैं कि वर्ष 2012 में चीन द्वारा भारत में केवल 1.52% निर्यात किया जाता था वहीं यूएसए और ईयू जैसे विकसित देशों तथा क्षेत्रों को 76% निर्यात के साथ इन पर ज़ोर दिया जाता था। तथापि इन देशों तथा क्षेत्रों द्वारा किए गए विभिन्न व्यापार उपायों के कारण निर्यात के रुझान में बड़े पैमाने पर बदलाव आया। जहां वर्ष 2014 में भारत में निर्यात चीनी निर्यातकों द्वारा विश्व को किए जाने वाले कुल निर्यात मूल्य का केवल 3.97% था, वहीं 3 वर्ष की लघु अवधि में भारत में चीन का निर्यात ईयू और यूएस को मिला कर किए जाने वाले निर्यात से अधिक हो कर लगभग 30% हो गया, जो चीन द्वारा निर्यात किए जाने वाले देशों में सर्वाधिक था। चीन द्वारा निर्यात में ऐसा उछाल, जिसने यूएस और ईयू जैसे विकसित देशों तथा क्षेत्रों को किए जाने वाले निर्यात को पीछे छोड़ दिया, भारत द्वारा भुगतान का दायित्व लेते समय पूर्वानुमानित नहीं किया गया था।
- जज. एक अन्य घटनाक्रम जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था, भारत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में नेतृत्व के लिए आगे आया। वर्ष 2015 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 2030 तक 2005 के स्तर से 33%-35% तक कम करने और गैर-जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता को 40% तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता की। इस घटनाक्रम, जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था, के लिए भारत द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के प्रति अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी। जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता, जो कि सरकार द्वारा अपने सौर संस्थापन को बढ़ाने का एक कारण था, ने भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की मांग को बढ़ाया है। भारत द्वारा 2015 के पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धता, जिस पर 197 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे (आज की तारीख तक 172 देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है), का पूर्वानुमान 13 दिसंबर, 1996 को आईटीए-1 के तहत सहमत सौर सेल के लिए आयात शुल्क छूट दिए जाने के समय नहीं किया जा सकता था।
- धध. अतः भारत के लिए दिनांक 13 दिसंबर, 1996 को (i) चीन की क्षमताओं, उत्पादन और निर्यात अभिमुखिता में तीव्र विस्तार; (ii) प्रमुख खपत बाजार जैसे यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा व्यापार उपचारी उपाय करना और (iii) पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धता, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए कार्बन डाई आक्साइड गैस के स्त्राव में (2005 के स्तर से) 33-35 प्रतिशत तक की कमी के लिए कहा गया है, अप्रत्याशित थे।
- नन. गैट के अनुच्छेद XIX में यह अपेक्षित है कि आयातों में वृद्धि गैट 1994 के तहत सदस्य द्वारा दायित्वों की पूर्ति के प्रभाव के रूप में होनी चाहिए। इस क्लॉज का प्रभाव यह है कि सुरक्षा उपायों का सहारा लेने के लिए संबंधित आयातक सदस्य देश में जांच प्राधिकारी यह भी दर्शाए कि कैसे गैट 1994 के तहत पूरे किए गए दायित्वों व टैरिफ छूटों के कारण सक्षम प्राधिकारी आयातों में वृद्धि को रोकने के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुसार उपाय नहीं कर पाए।
- पप. वर्तमान संदर्भ में, भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि दायित्वों के प्रभाव के रूप में इसे प्राप्त टैरिफ छूटों के कारण और विश्व व्यापार संगठन के अनुसार उपायों के माध्यम से आयातों में वृद्धि को न रोके जाने के कारण से ही इस संबंध में दो ऐसे कारक हैं, जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, प्रथमतः भारत ने विश्व व्यापार संगठन को छूट की समय अनुसूची प्रदान की और गैट के तहत प्रतिबद्धताओं का पालन किया। तदोपरान्त भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों (आई टी ए-1) में व्यापार संबंधी मंत्रालयी घोषणा के माध्यम से ऐसी टैरिफ छूटों में संशोधन किया। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क मद 85414011 के तहत आने वाली संबद्ध वस्तुएं भारत के आयात शुल्क से 'मुक्त' हैं। यह शुल्क 'मुक्त' टैरिफ दिनांक 13 दिसंबर, 1996 के सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर मंत्रालयी घोषणा (आई टी ए-1) के साथ पठित टैरिफ छूटों सहित गैट 1994 के तहत भारत पर बाध्यता के अनुसरण में लगाया गया था। संबद्ध वस्तुएं आई टी ए-1 की धारा, अनुबंध-क के तहत कवर होती हैं। आई टी ए-1 में, सूचीबद्ध उत्पादों पर गैट 1994 के अनुच्छेद II : 1(ख) के तात्पर्य से सीमा शुल्कों और अन्य शुल्कों/ किसी अन्य

प्रकार के प्रभारों को हटाने का प्रावधान है। अतः चूंकि भारत आई टी ए-1 का एक हस्ताक्षरकर्ता है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के आयातों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है। अतः आई टी ए-1 आयातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में भारत की "कार्रवाई की स्वतंत्रता" को प्रतिबंधित करता है और उसे अन्य विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल उपायों जैसे सीमा शुल्कों को बढ़ाने से रोकता है। दूसरे, घरेलू उद्योग को प्रारंभ में जे एन एन एस एम के तहत घरेलू मात्रा की अपेक्षाओं ("डी सी आर") के अनुरूप एक बड़े घरेलू बाजार का आश्वासन था। तथापि, 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान निकाय के समक्ष जे एन एन एस एम के तहत डी सी आर को चुनौती दी थी। भारत को विश्वास था कि जे एन एन एस एम के तहत घरेलू मात्रा की आवश्यकताएं (डी सी आर) इस आधार पर गैट के अनुसार थी कि गैट 1994 के अनुच्छेद XX में उल्लिखित अपवाद ऐसे उपायों पर लागू हैं। तथापि, विवाद का परिणाम यह था कि अक्टूबर, 2016 में विश्व व्यापार संगठन अपील निकाय ने डी सी आर को गैट 1994 के अनुच्छेद III:4 और टी आर आई एम के करार के अनुच्छेद 2.1 के अनुसार नहीं पाया। अतः भारत को डी सी आर को वापस लेना पड़ा था। इसीलिए भारत के दायित्व गैट 1994 के अनुच्छेद III:4 के तहत और टी आर आई एम के करार के अनुच्छेद 2.1 के तहत वर्तमान स्थिति से निपटने में भारत के लिए रुकावट है।

- फ.फ. समय के साथ-साथ आयातों में तीव्र वृद्धि और बिक्री मात्रा संबंधी डाटा घरेलू खपत गंभीर क्षति को साफ तौर पर दर्शाते हैं अथवा घरेलू उद्योग को अवश्यंभावी गंभीर क्षति को दर्शाते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि बढ़ती मांग के साथ ही आयातों का बाजार अंश भी 86 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हुआ है, जिससे घरेलू उत्पादों का बाजार अंश 14 प्रतिशत से गिरकर 10 प्रतिशत तक आ गया है।
- ब.ब. दोनों सैल और मॉड्यूल के लिए कीमत कटौती में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिससे बाद में सोलर सैल और मॉड्यूल की बिक्री कीमत में कटौती हुई है। क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान कीमत में 15.77 प्रतिशत तक की संचित गिरावट हुई है। यद्यपि लागत में वृद्धि कीमत वृद्धि के कारण हुई है, लेकिन घरेलू उत्पादक अपनी कीमतों नहीं बढ़ा पाए। अतः घरेलू उद्योग लाभ नहीं कमा पाया और क्षमता तथा गुणवत्ता के संदर्भ में आयातों के समान रखने के लिए व्यवहार्य अनसुंधान एवं विकास में निवेश नहीं कर पाया।
- भ.भ. कामगारों को भी इस स्थिति के कारण बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। कुल संस्थापित क्षमता की तुलना में करीब 2384 कर्मचारियों के लिए एक संभावित रोजगार की हानि हुई है।
- म.म. भारतीय सौर उद्योग को कई वर्षों तक कम कीमत के आयातों का खामियाजा भुगतना पड़ा। तथापि, हाल ही में, इन आयातों में तीव्र वृद्धि हुई है जबकि कीमतों में निरंतर कमी आई है, जो इसके बाद विस्तार से दर्शाई गई है। यह कानून का स्थापित कथन है कि आयातों में वृद्धि हाल ही में, अचानक से, तेजी से और महत्वपूर्ण रूप से, मात्रात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से, दोनों तरीके से, गंभीर क्षति के कारण अथवा गंभीर क्षति के परिणामस्वरूप हुई है, इनमें सभी वर्तमान मामले में लागू हो जाते हैं।
- य.य. घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादन की भारी मांग को देखते हुए संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए भारी निवेश किया है। तथापि, विभिन्न देशों से आयातों के अनुसार निवेश बहुत ही कीमतों पर हुए हैं। अतः घरेलू उद्योग ने पूर्व में भी पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए प्रयास किए थे। पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय ने पहले चीन, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातकों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। तथापि, वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2014 में शुल्क न लगाने का निर्णय लिया था। उद्योग बिल्कुल बंद होने के कगार पर था लेकिन डी सी आर की शुरुआत के चलते, जिससे घरेलू उत्पादों को एक नया जीवन मिला। सुधारों को मध्यवर्ती वर्षों में दर्शाया गया है। डी सी आर से परियोजनाओं में भारतीय निर्मित सोलर सैल का उपयोग सुनिश्चित हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को तर्कसंगत कीमत पर संबद्ध वस्तुओं की कुछ मात्रा प्राप्त करने में मदद मिली है।
- र.र. विश्व व्यापार संगठन के अपील निकाय ने डी सी आर को गैट 1994 के अनुच्छेद-III 4 और टी आर आई एम करार के अनुच्छेद 2.1 के अनुसार नहीं पाया। निर्यातकों को 2014 से 2017 तक नीति विलंबता का लाभ मिला था जिससे आयातों में अचानक और तीव्र वृद्धि हुई।
- ल.ल. डी सी आर को हटाने के प्रभाव इस प्रकार पड़े कि आयात में वृद्धि पहले से स्पष्ट है क्योंकि उपयोक्ता अब घरेलू रूप से उत्पादित सोलर सैल की खरीद करने के लिए बाध्य नहीं है। निष्पादन में गिरावट और क्षति कई मापदंडों में देखी गई और आगे क्षति की संभावना वास्तविक और अवश्यंभावी है। यदि इस समय कोई सुरक्षात्मक शुल्क नहीं लगाए गए तो आने वाली तिमाही में बिक्री और कीमत संबंधी मापदंडों के संदर्भ में अपूर्ण क्षति दिखाई देगी। घरेलू उद्योग को ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण और अपूर्ण विकास को रोकने के लिए यथाशीघ्र सुरक्षा उपायों की जरूरत होगी।
- व.व. चीन भारत की संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक है (आयातों का 94 प्रतिशत से अधिक हिस्सा) चीन, ताइवान, मलेशिया और अन्य देशों से निर्यातक विभिन्न व्यापार उपचारी उपायों (पाटनरोधी) सब्सिडीरोधी और रक्षोपाय के कारण और यूरोपीय

संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजिप्ट, तुर्की और रूस जैसे बड़ी खपत वाले बाजारों के निर्यात में काफी रुकावटों के कारण संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में काफी रुकावटों का सामना कर रहे हैं। परिणाम का तात्पर्य यह है कि सोलर सैल के निर्यातों के लिए संयुक्त राज्य के दरवाजे भी बंद हैं। अतः यदि भारत संबद्ध राज्यों के लिए असुरक्षित जोन रहेगा तो चीन जैसे देशों से उत्पादक निर्यातों में वृद्धि की ओर अग्रसर होंगे, जिससे भारत में सोलर उद्योग हमेशा के लिए अवश्य ही समाप्त हो जाएगा।

- शश. वर्तमान स्थिति में सुरक्षा शुल्क लगाये जाने की तत्काल आवश्यकता है। यद्यपि कुछ एक क्षति मापदंड जैसे हानियों में मध्यवर्ती अवधि में आधार वर्ष की तुलना में कमी आई थी, लेकिन ऐसे सुधार डी सी आर के कारण से ही थे, जो उस अवधि के दौरान लागू था। डी सी आर के लाभ रोजगार के साथ साथ उद्योग की क्षमता पर भी दिखाई दिये थे जिसमें उसके कर्मचारियों को तर्कसंगत भुगतान सुनिश्चित हो सका। जब डी सी आर लागू था, उस समय कीमत प्राप्ति अधिक थी, लेकिन डी सी आर बंद होने के बाद पुनः संशय बन गया है। इससे व्यापक पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी पहले ही हो गयी है और यह संकेत स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग द्वारा सृजित रोजगार गंभीर भारतीय खतरे में है और इसके परिणामस्वरूप यदि आयातों के आघात से सुरक्षा नहीं की गई तो रोजगार को और भी नुकसान होगा।
- पप. आयातों में निरपेक्ष संदर्भ में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। वर्ष दर वर्ष वृद्धि विगत वर्ष 2015-16 में 228 प्रतिशत थी। अतः 2015-16 से 2016-17 तक आयातों में वृद्धि भी 52 प्रतिशत थी। अंततः 2017-18 में आयातों में 2016-17 से करीब 49 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। आयातों में वृद्धि हाल में, अचानक, तीव्र और पर्याप्त थी। इसके अलावा, आयातों में वृद्धि न केवल निरपेक्ष संदर्भ में थी बल्कि सापेक्ष संदर्भ में भी थी अर्थात् भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के संदर्भ में थी। आयातों में वृद्धि मूल्य के संदर्भ भी दर्शाई गई है जो 2014-15 के दौरान 3,991-21 करोड़ रुपए से बढ़कर, 2017-18 के दौरान (वार्षिक रूप से) आयात, मूल्य में वृद्धि 21,701.38 करोड़ रुपए तक हुई। तथापि, मूल्य में वृद्धि आयातों की मात्रा में वृद्धि के अनुपात में नहीं हुई थी क्योंकि जैसा कि रक्षोपाय महानिदेशक द्वारा अपने प्रारंभिक निष्कर्ष में पाया गया है आयातों की मात्रा में वृद्धि के अनुपात में नहीं थी।
- सस. यद्यपि आयातों का पहुंच मूल्य वर्ष 2014-15 के दौरान सैल और मॉड्यूल के लिए क्रमशः करीब 18.78 और 36.96 रुपए था, जिसमें वर्ष 2017-18 के दौरान (वार्षिक रूप से) 23.03 रुपए तक की तीव्र गिरावट आई। मात्रा में यह तीव्र वृद्धि के साथ प्रति वाट मूल्य के समान रूप से भारी कमी होने से घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमतों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण कीमतों में काफी रुकावट व गिरावट आई जबकि घरेलू उद्योग को पारिश्रमिक कीमत पर उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से रुकावट आई। तथापि, यद्यपि घरेलू उद्योग लागत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहा है, आयातों की कीमतों में घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कमी होती रही, जिससे घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में समान वस्तु की मांग में भारी वृद्धि होने के बावजूद उसकी संस्थापित क्षमता से एक तर्कसंगत सीमा तक संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री करने में रुकावट आई।
- हह. आयातों में निचली कीमतों पर भारी तेजी आने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की बिक्री नहीं कर पाया, यद्यपि घरेलू उद्योग में मांग में भारी वृद्धि हुई थी, जो घरेलू उद्योग के बाजार अंश में देखी जा सकती है, जबकि मांग 2014-15 में 1476 मेगावाट से बढ़कर 2017-18 में 10,573 मेगावाट हो गई (वार्षिक रूप से) आयातों का बाजार अंश 86 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया और परिणामस्वरूप बाजार अंश की राशि, जो पहले घरेलू उत्पादकों के पास थी, जांच की अवधि के आरंभ में 2017-18 में कुल घरेलू खपत के 14 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो गई।
- क्षक्ष. घरेलू उद्योग को समूची जांच की अवधि के दौरान आयातित वस्तुओं में कीमत कटौती का सामना करना पड़ा। जिसका परिणाम यह हुआ कि घरेलू उद्योग को कीमतों में रुकावट का सामना करना पड़ा, जो इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि इसको निबल बिक्री वसूली में गिरावट आती रही और पूरी जांच की अवधि के दौरान बिक्री की लागत से कम रही। इस प्रकार की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट आना आयातों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के अलावा किसी अन्य कारण से नहीं हो सकती। कीमतों में गिरावट के साथ साथ कीमतों में रुकावट भी आई। घरेलू उत्पादक अपनी कीमतें तब भी नहीं बढ़ा सके जब लागतों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। वर्ष 2015-16 के दौरान तत्काल पूर्व के वर्ष से 9 प्रतिशत प्रतिवाट तक लागतों में वृद्धि हुई थी जबकि बिक्री कीमतों में 13 प्रतिशत प्रतिवाट तक गिरावट आई थी, जिससे कीमतों में प्रतिवाट 24 प्रतिशत तक की रुकावट हुई। ऐसी कीमत रुकावट और गिरावट के कारण से याचिकाकर्ता अपनी कीमतों को नहीं बढ़ा पाया और परिणाम यह हुआ कि उसे भारी हानि उठानी पड़ी।
- वव. उत्पादन और बिक्री के संबंध में आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा रखे गये छोटे बाजार अंश से देखे जा सकते हैं, जिसमें घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की मांग और आयातों की मांग से तुलना की जा सकती है।
- जज. घरेलू उद्योग का उत्पादन 2014-15 में 237 मेगावाट से बढ़कर 2017-18 में 838 मेगावाट (वार्षिक) हो गया। इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि घरेलू उद्योग के संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने की संस्थापित क्षमता भी बढ़कर 2017-18 में अतिरिक्त 1000 मेगावाट (वार्षिक) हो गई। जिसका कारण एक याचिकाकर्ता अर्थात् मुंद्रा सोलर पी वी लिमि. द्वारा प्रचालन

आरंभ करना है तथापि वर्ष 2017-18 में संस्थापित क्षमता में वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग के उत्पादन केवल 365 मेगावाट तक ही वृद्धि हो पाई। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रामें 643 प्रतिशत तक वृद्धि अर्थात् 2014-15 1275 मेगावाट से बढ़कर 2017-18 में 9474 मेगावाट (वार्षिक) हुई, जबकि घरेलू उद्योग उत्पादन में उसी अवधि के दौरान केवल 254 प्रतिशत वृद्धि हुई अर्थात् 237 मेगावाट से बढ़कर 838 मेगावाट हुई।

- ककक. घरेलू उद्योग की बिक्री के आंकड़ों से पता चलता है कि संबद्ध वस्तुओं की इतनी अधिक मांग के बावजूद इतनी खराब स्थिति रही, जिसके कारण आयातों में इतनी अधिक वृद्धि हो पाई, जबकि घरेलू उद्योग तो अपने द्वारा उत्पादन की गई सभी संबद्ध वस्तुओं की बिक्री तक नहीं कर पाया। जबकि बिक्रियों में वृद्धि 191 मेगावाट से 774 मेगावाट (वार्षिक) हुई, यह उल्लेखनीय है कि घरेलू उद्योग तो केवल अपनी संबद्ध वस्तुओं की बिक्री अपनी लागत से भी काफी कम कीमतों पर ही कर पाया, जिसके कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की बिक्री बिना पारिश्रमिक कीमतों पर करने के लिए मजबूर था, क्योंकि आयातों में वृद्धि जारी रही और घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट होती रही, वह तो जांच की अवधि के दौरान अपने द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं की पूरी बिक्री तक नहीं कर पाया। यह बढ़ती माल सूची में भी स्पष्ट तौर पर दर्शाया गया है।
- खखख. रक्षोपाय महानिदेशक ने यह सही टिप्पणी की है कि संबद्ध वस्तुओं के बढ़ते आयातों ने घरेलू बाजार में मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं का विकल्प प्रदान किया है।
- गगग. घरेलू उद्योग के समक्ष अपनी क्षमता में गहन कमी होने की समस्या का सबसे प्रकट कारण यह है कि उसकी क्षमता अपनी संस्थापित क्षमता की केवल 51 प्रतिशत ही है। ऐसी स्थिति में, जहां संबद्ध वस्तुओं की मांग में 9097 मेगावाट तक की वृद्धि हुई है, जो करीब 616 प्रतिशत है और घरेलू उद्योग की समूची संस्थापित क्षमता को पूरा करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है, जो 1653 मेगावाट है, तो संबद्ध वस्तुओं का बिलकुल ही निचली कीमतों पर आयात होने में तेजी आने के अलावा कोई अन्य कारण नहीं है, जिसके कारण घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग आधार वर्ष में 60 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2017-18 में 51 प्रतिशत (वार्षिक) हो गया। वास्तव में उत्पादन क्षमता में 2017-18 में 1000 मेगावाट (वार्षिक) की और वृद्धि हो जाने के बावजूद वास्तविक रूप में इस अतिरिक्त क्षमता का केवल 35 प्रतिशत ही उपयोग हो पाया। यहां तक कि समग्र जांच की अवधि के दौरान (वार्षिक) की उत्पादन सुविधाएं काफी कम उपयोग में लाई गईं। विचाराधीन उत्पाद के आयातों की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ यह कम क्षमता उपयोग होना स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का सामना करना पड़ा है।
- घघघ. इसके अलावा, समान वस्तु के अनेक अन्य घरेलू उत्पादों अर्थात् सुराना सोलर, उधायी एनजी, महर्षि सोलर, देव सोलर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमि., एक्सल एनजी, आई वाई एस ईआर टी एनजी और के आई एनजी में अपनी उत्पाद सुविधाओं को उपयोग नहीं किया। उनका उत्पादन या तो शून्य था या पर्याप्त नहीं था। यूरो मल्टीविजन और प्रीमियर सोलर का जुलाई – सितंबर, 2017 (2017-18 की दूसरी तिमाही) के दौरान कोई भी उत्पादन नहीं था। इस प्रकार जांच की अवधि के दौरान उत्पादन सुविधाओं का बहुत ही कम उपयोग हुआ। यहां तक कि जब संयंत्र प्रचलित किए जा रहे थे तो घरेलू उत्पादन अपने संयंत्र निरंतर चलाने की स्थिति में नहीं थे। यह कहना है कि ये संयंत्र बंद हो गए क्योंकि भारत में आयातों में वृद्धि हो रही थी, जिससे घरेलू उद्योग की अपनी तैयार संबद्ध वस्तुओं की बिक्री बंद हो गई।
- ङङङ. घरेलू उद्योग द्वारा सृजित रोजगार में भी पर्याप्त क्षमता में वृद्धि होने के बावजूद गिरावट आई। एक याचिकाकर्ता मैसर्स मुंद्रा सोलर पी वी लिमिटेड (एम एस पी वी एल) ने मई, 2017 में प्रचालन की शुरुआत होने से उद्योग में कर्मचारियों की कुल संख्या में सकल वृद्धि हुई लेकिन रक्षोपाय महानिदेशक ने दिनांक 5.1.2018 को अपनी प्राथमिक निष्कर्ष में यह सही उल्लेख किया है कि उद्योग की प्रवृत्ति में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। यदि घरेलू उद्योग का रोजगार एम एस पी वी एल के कर्मचारियों की संख्या को निकालकर देखा जाए तो घरेलू उद्योग में कर्मचारियों की कुल मिलाकर घटती संख्या दिखाई देगी। इसके अलावा, जैसा कि रक्षोपाय महानिदेशक ने अपने प्राथमिक निष्कर्ष में भी उचित उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग अपनी संस्थापित क्षमता से काफी कम प्रचालन कर रहा है और इसीलिए संभावित रोजगार अवसरों में काफी कमी हुई है। वास्तव में, इसमें बढ़ते नुकसान और घटते क्षमता उपयोग के कारण एक याचिकाकर्ता यथा इंडोसोलर ने हाल ही में अपने 250 कर्मचारियों को हटा लिया है।
- चचच. यद्यपि, घरेलू उद्योग 2016-17 तक अपने कर्मचारियों को कुल मिलाकर उसी स्तर पर वेतन का भुगतान करते रहा, जिसके कारण घरेलू उद्योग के समक्ष भारी वित्तीय समस्या आ गई और घरेलू उद्योग अपने बढ़ते घाटे के चलते आगे उसी स्तर पर वेतन का भुगतान करना जारी रख पाने में असमर्थ था और इसीलिए उसके कर्मचारियों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक में भी काफी गिरावट आई है।
- छछछ. एम एस पी वी एल का मई, 2017 में घरेलू उद्योग में प्रवेश होने से कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद, घरेलू उद्योग का उत्पादन प्रभावित होता रहा है। प्रति व्यक्ति उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान 0.316 मेगावाट था जो बाद में 2015-16 में

गिरकर 0.291 मेगावाट हो गया। यद्यपि ये आकड़े 2016-17 में थोड़ा बढ़कर 0.492 मेगावाट हो गए लेकिन 2017-18 में ये गिरकर 0.243 मेगावाट पर आ गई। इस प्रकार से प्रति कर्मचारी उत्पादन में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई, जिसमें 2016-17 में हल्की वृद्धि हुई थी, जो जारी नहीं रह सकी। वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि जब तक घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए पर्याप्त रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाए जाते निकट भविष्य में और भी गिरावट की प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है।

- जजज. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियों पर काफी घाटा उठाना पड़ा है। निबल बिक्री वसूली में महत्वपूर्ण गिरावट आने के कारण, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं पर सस्ते आयातों के कारण कीमत में रुकावट और गिरावट के प्रभाव के चलते वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान इसका घाटा काफी बढ़ गया है। वास्तव में यदि इससे पूर्व के वर्ष अर्थात् 2016-17 की तुलना की जाए तो वर्ष 2017-18 के दौरान (वार्षिक) घाटा दो गुणा से भी अधिक हुआ है। यदि आधार वर्ष अर्थात् 2014-15 से तुलना की जाए तो यह घाटा चार गुणा हो गया है। घाटे में इतनी वृद्धि होना क्षमता में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि और घरेलू बिक्रियों में वृद्धि होने जैसे मापदंडों के आलोक में देखा गया है। इसके परिणामस्वरूप, शामिल पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल मिला है। घरेलू उद्योग स्वयं और अधिक कायम नहीं रह सकता और उसे अपने प्रचालनों को स्थायी तौर पर बंद करना पड़ेगा, यदि इतने सस्ते आयातों का प्रवाह अबाध रूप से जारी रहता है।
- झझझ. घरेलू उद्योग की वस्तु सूची में जांचकी अवधि के दौरान चार गुणा से भी अधिक की वृद्धि हुई है यह तथ्य कि घरेलू बिक्रियां घरेलू उद्योग के उत्पादन की गति के अनुसार जारी नहीं रह सकी, इसकी संस्थापित क्षमता और घरेलू बाजार में मांग जो बिलकुल तुच्छ है, को देखते हुए वस्तु सूची के संबंध में आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है, जिसमें आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में काफी वृद्धि हुई है। एक घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की बढ़ती वस्तु सूची को देखते हुए संबद्ध वस्तु की अत्यधिक मांग के चलते यह बात स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग गंभीर क्षति का सामना कर रहा है।
- ञञञ. भारत में संबद्ध वस्तुओं की अत्यधिक मांग है और ऐसा कोई अन्य ज्ञात कारक नहीं है जो बाजार खराब करने के लिए जिम्मेदार हो, सिवाय इसके कि विभिन्न स्रोतों से काफी मात्रा में कम कीमत पर आयात हो रहा है।
- टटट. कारणात्मक संबंध साबित होता है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं के आयात वर्ष 2014-15 में 1275 मेगावाट से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 9474 मेगावाट हो गया है, अर्थात् 3 वर्षों के दौरान 643 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 2015-16 के दौरान आयातों में 3.3 गुणा तक की वृद्धि हुई है और वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः 1.52 और 1.48 गुणा तक की वृद्धि हुई है। अतः आयात में वृद्धि, हाल ही में, अचानक, तीव्रता से और अत्यधिक हुई है। आयातों का बाजार अंश 86 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग का बाजार अंश 13 प्रतिशत से गिरकर 7 प्रतिशत पर आ गया है। इतनी गंभीर क्षति बढ़ते आयातों के अलावा अन्य किसी कारक के कारण नहीं है।
- ठठठ. विगत प्रत्येक दो अर्ध वार्षिक अवधियों के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात वर्ष 2016-17 के प्रथम अर्ध वर्ष के दौरान के आयातों से काफी अधिक (2.7 गुणा अधिक) था। वर्ष 2017-18 के प्रथम अर्ध वर्ष के दौरान आयात की कीमतों में भी गिरावट 23.04 रुपए प्रतिवाट तक रही, जो कि 23 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है। चूंकि आयात कीमतों में गिरावट रही, घरेलू उद्योग पारिश्रमिक कीमतें प्राप्त करने की क्षमता में भी गिरावट आई। परिणामस्वरूप बिक्री और क्षमता उपयोग पर प्रभाव पड़ा।
- डडड. आयातों से मांग की 90 प्रतिशत से अधिक की पूर्ति हुई है और उसका घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह भी स्पष्ट है कि भारतीय बाजार में आयातों से बाजार खराब हो रहा है। उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उद्योग की खराब अवस्था 2017-17 में और भी खराब हो गई और इसीलिए भारत में सौर उद्योग की मौजूदगी के लिए रक्षोपाय शुल्क जरूरी है।
- ढढढ. याचिकाकर्ताओं ने भारत बाहर निर्यातकों के साथ लागत प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अपनी लागत कम करने के लिए यह योजना बनाई है कि (i) कच्चे माल के मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं के साथ मोल भाव किया जाए और कच्चे माल नए आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की जाए ताकि अपेक्षित दीर्घ आवधिक बड़े अनुबंध करके कच्चे माल की लागत में कमी लाई जा सके। (ii) बुनियादी कच्चे माल से बेफर और इंगोट के निर्माताओं के लिए संयंत्रों की स्थापना करके प्रतिगामी संयोजन करने के लिए परियोजनाएं आरंभ की जाए। प्रतिगामी संयोजन से बड़े पैमाने पर खर्च कम होगा। इससे प्रतिफल अधिक मिलेगा। इस प्रकार के प्रतिफल से अनेक उद्यमी लेकर निर्माण सुविधाओं में निवेश कर पाएंगे, जिसमें सोलर सैल और मॉड्यूल के उत्पादन की लागत का बड़ा हिस्सा शामिल है। कुछ याचिकाकर्ता इंगोट निर्माण सुविधाओं में भी निवेश करेंगे। (iii) जिनके पास केवल सैल निर्माण करने की सुविधाएं हैं उन्हें मॉड्यूल के निर्माण के लिए सुविधाएं स्थापित करके प्रतिगामी संयोजन करने के लिए परियोजनाएं लेना; (iv) जहां भी व्यवहार्य हो, पी ई आर सी प्रौद्योगिकी अथवा बायो-फेसिल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तकनीकी रूप से उत्तम उत्पादों के लिए परियोजनाएं शुरू करना; (v) प्रथमतः क्षमता का उपयोग बढ़ाकर परिवर्तन की लागत में कटौती करना, जो कुछ

हृद तक रक्षोपाय शुल्कों जैसे संरक्षण उपायों को लागू किए जाने के कारण बाजार में अनुकूल परिवर्तनों पर निर्भर होगा। (vi) रुपए में ऋण को यू एस डॉलर में ऋण में परिवर्तन करके वित्तीय लागत कम करना।

णणण. कुछेक व्यापक आर्थिक मामलों के आलोक में पुनः समायोजन की योजना पर विचार किया जाए जैसे कि एक तथ्य यह है कि भारत ने वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सोलर पावर के उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है और इसीलिए उत्पाद के लिए मांग निरंतर बढ़ रही है। पेरिस करार के तहत भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए लक्ष्य आवश्यक है जिसमें वर्ष 2022 तक (2005 के स्तर से) कार्बन उत्सर्जन में 33-35 प्रतिशत की कटौती के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता इन पहलों का समर्थन करता है और संस्थापित क्षमता में महत्वपूर्ण निवेश किया है। तथापि, निर्यातकों, खासकर चीन, मलेशिया और ताइवान ने भारत में घरेलू उद्योग को नष्ट करने का प्रयास किया है। रक्षोपाय शुल्कों से निरंतर निवेश, पूंजीगत कम विस्तार और किफायती उपायों के द्वारा लागत में कमी करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

ततत. रक्षोपाय शुल्क लगाना व्यापक लोकहित में भी है, जैसे (i) इससे बढ़ती बरोजगारी, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, क्षमता उपयोग में वृद्धि और आर एंड डी में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। (ii) विदेशी प्राप्त निवेश प्रवाह में वृद्धि होगी और निर्यातक भारत में निवेश और निर्माण करने को प्रोत्साहित होंगे। वास्तव में, अनंतिम रक्षोपाय शुल्कों की प्रारंभिक सिफारिश के कारण लोंगी, सी ई टी सी और जी सी सी द्वारा भारत में अतिरिक्त क्षमता की घोषणा की गई। (iii) कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और उपभोज्य वस्तुओं (जैसे वेफर, पेस्ट, ई वी ए, जंकशन बॉक्स, ग्लास इत्यादि) के आपूर्तिकर्ता नई इकाइयां लगाने को प्रोत्साहित होंगे। (iv) प्रत्येक 1 गीगावाट सैल + मॉड्यूल उत्पादन होने से करीब 3000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। याचिकाकर्ताओं का अनुमान है कि ऐसे उत्पादनसे करीब $3.5 \times$ (अर्थात् 10,500 लोगों) को सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के कारण प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा; (v) प्रत्येक 1 गीगावाट सैल + मॉड्यूल के उत्पादन में करीब 2,000 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होती है जिसमें से 30 प्रतिशत की पूर्ति इक्विटी से और 70 प्रतिशत की पूर्ति ऋण से होती है। ऋण औसतन 9-10 प्रतिशत लागत/ ब्याज दर पर दिया जाता है (यह दर ऋण साख के आधार पर प्रत्येक उत्पादक के लिए अलग अलग हो सकती है)। मामूली वापसी और प्रौद्योगिकी में निरंतर उत्पादन के साथ ही उत्पादकों को अपने निवेश को हासिल करने के लिए लंबी अवधि लगती है। (vi) यह उद्योग निरंतर प्रौद्योगिकी में उन्नयन करते रहने के अध्वधीन है, जो क्षमता के रूप में (उदाहरण के लिए सैल में बराबर वृद्धि करना) अथवा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उन्नयन रहना (उदाहरण के लिए सोलर सैल की सामग्री अथवा मूलभूत बनावट में परिवर्तन के कारण) हो सकेगा। दूसरे शब्दों में उन्नयन की लागत उत्पादकों पर भारी हो सकती है। अतः अनुसंधान एवं विकास में भारी राशि निरंतर निवेश की जाती है। (vii) प्रतिगामी संयोजन (जैसे कोई बेफर सुविधा) में समान मात्रा में निवेश की जरूरत होगी तथापि, किफायतता केवल प्रतिगामी संयोजन हासिल की जा सकती है। ऐसा संयोजनक आपूर्तिकर्ताओं की आर्थिक प्रणाली को विकसित करता है और बड़े पैमाने पर रोजगार और आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन करता है। (viii) आयात, जो वर्तमान में भारत में कुल घरेलू खपत का 90 प्रतिशत है, विदेशी विनियम भंडार पर बड़ा भार है और वर्तमान लेखा घाटे में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2020 तक आयातित उत्पादनों के कारण विदेशी विनियम का आउटफ्लो वित्त वर्ष 2017-18 के लिए मनरेगा के लिए भारत सरकार आवंटित किए गए बजट का करीब 60 प्रतिशत होने का अनुमान है। (ix) जैसा कि प्राथमिक निष्कर्ष में सिफारिश की गई है, 70 प्रतिशत। मूल्यानुसार शुल्क के साथ भी पावर टैरिफ में वृद्धि नगण्य हो रही है जो केवल दीर्घावधिक है, चूंकि याचिकाकर्ता अस्थायी संरक्षण से प्रतिस्पर्धी होंगे। स्वदेशीकरण से बढ़ते सरकारी राजस्व को पावर टैरिफ में किसी भी वृद्धि के लिए डिस्काँम की प्रतिपूर्ति करने के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। अतः कोई भी तर्क, जो बढ़ते टैरिफ के संबंध में विकासकों द्वारा लगाया जा सकेगा, वह न केवल आधारहीन होगा बल्कि बनावटी भी होगा; (x) आयातित सोलर सैल और मॉड्यूल के कारण भारी मात्रा में धनराशि विदेशों में जाती है। ऐसे लेन देन से भारत को बिना किसी आर्थिक लाभ के केवल बिचौलियों को बढ़ावा मिलता है। केवल मूर्त आर्थिक लाभ निर्यातक देशों, विशेषकर चीन, मलेशिया और ताइवान को ही होगा। (xi) एस जी डी लगाने से याचिकाकर्ताओं के पास उस राशि को रखने, प्रतिगामी संयोजन करने का प्रयास करने, मितव्ययता हासिल करने और उसे वास्तविक आर्थिक क्रियाकलापों में लगाने का अवसर तो मिलेगा। याचिकाकर्ताओं ने यह प्रदर्शित किया है कि वे सभी तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाले विश्वस्तरीय उत्पादकों का उत्पादन करने में सक्षम हैं; (xii) इसके अलावा, विकासकर्ताओं द्वारा रोजगार सृजित करने के बारे में कोई भी तर्क आधारहीन होगा। क्योंकि सुविधाओं में संस्थापन, प्रचालन और रखरखाव के लिए रोजगार मूलतः तटस्थ होता है। दूसरे शब्दों में वही रोजगार तब भी पैदा होगा, यदि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुएं सोलर पावर परियोजनाओं के संस्थापन, प्रचालन और रखरखाव में उपयोग में लाई जाएंगी। (xiii) प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर 50 गीगावाट की स्थानीय क्षमता के स्थानीय निर्माण लक्ष्य में वृद्धि के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए सी आई आई द्वारा एक कार्यबल की स्थापना की गई थी। (xiv) भारतीय निर्माताओं की बैंक जवाबदेही को सरल बनाया

जायेगा और बैंकों पर एन पी ए का भार कम किया जायेगा। एक मजबूत सोलर आपूर्ति चैन विविध अन्य उद्योगों (इको सिस्टम) के विकास और 1.20 मिलियन से अधिक रोजगार सृजित करने में सहायक होगा।

यथार्थ. रक्षोपाय शुल्क न लगाना भारत के लोकहित के खिलाफ होगा क्योंकि (i) स्थानीय निर्माण का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और 11,000 करोड़ रुपए का निवेश दिवालिया हो जाएगा और इसके कारण भारी बेरोजगार होगी। (ii) विदेशी निर्माताओं द्वारा घोषित क्षमता वृद्धि कभी भी प्राप्त नहीं होगी और रुकावट बनेगी; (iii) भेल ने हाल ही में 100 मेगावाट लाइन में निवेश किया है जो यदि रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाता है तो व्यर्थ हो जाएगा। (iv) मॉड्यूल और/ अथवा सैल की स्थापना और बेफरिंग में आगे विसतार के लिए सी ई सी, ई ओ आई भी कोई बोलियां आमंत्रित करने में विफल होगी। (v) भारत सरकार भी पहले से मौजूदा आयात निर्भरता में तेजी आती रहेगी क्योंकि भारत पहले से ही चीन का सर्वोच्च निर्यात स्थल है और हमारे आयातों में वर्ष दर वर्ष 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होकर वित्त वर्ष 2017-18 में हमारा आयात 4.1 बिलियन यू एस डालर हो गया है।

ददद. रक्षोपाय शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापार उदारीकरण की ओर वैश्विक परिवर्तन के लिए घरेलू उद्योगों का संरक्षण करना है, जैसे वैश्विक बाजार में वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा है। राज्यों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुक्त व्यापार प्रणाली से अधिकतम लाभ प्राप्त किए जा सकें। रक्षोपाय शुल्क, जो कि अंतरित उपाय है, घरेलू उद्योगों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुसार उद्योगों में अपनी स्थिति जांचने के लिए मदद करते हैं। तदनुसार, एक रक्षोपाय एक स्वच्छ व्यापार उपाय के लिए केवल संरक्षणवादी उपाय नहीं है बल्कि एक मांग है, जो घरेलू उद्योग एक ऐसी समायोजन योजना के साथ आए हैं, जिसमें पर्याप्त शुल्कों के रूप में सरकारी सहायता अपेक्षित है जो न केवल घरेलू उद्योगों को अपने वास्तविक उत्पादन लागत वसूलने में सहायक होगी बल्कि एक ऐसा संरक्षणवादी परिवेश भी प्रदान करती है कि उद्योग को अधिक फिकायती और प्रतिस्पर्धी बनने के प्रयोजन से अपनी समायोजन योजना को कार्यान्वित कर सके। इस संबंध में अपील निकाय में भी कोरिया-डेयरी में रक्षोपाय प्रतिक्रिया में समायोजन योजना के महत्व को स्वीकार किया है।

धधध. 95 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क चार वर्षों के लिए लगाया जाए ताकि विगत कुछ वर्षों में हुई क्षति के प्रभाव को कम किया जा सके और घरेलू उद्योगों को अपनी लागत की वसूली और अपनी समायोजन योजना का कार्यान्वयन करने दिया जाए ताकि उसे अन्य देशों उत्पादकों के समान लगाया जा सके। इसके अलावा, शुल्क को घरेलू उद्योग की समायोजन योजना को देखते हुए उदार बनाया जाए।

16. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य हितवद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोध पर दाखिल प्रतिवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है :

(i) घरेलू उद्योग

- क. महानिदेशक, रक्षोपाय ने यह स्पष्ट किया है कि विचाराधीन उत्पादन का दायरा 'सोलर सैल' है, जो चाहे मॉड्यूल अथवा पैनल में एकत्र किया गया हो, या नहीं।
- ख. उत्पादन के दायरे में दोनों सोलर सैल शामिल हैं, जो डिस्टलाइन सिलिकोन (सी – एसआई) तकनीक का उपयोग करते हैं और मॉड्यूल या पैनल, जो थिन फिल्म तकनीक का उपयोग करते हैं।
- ग. प्रतिवादियों ने थिन फिल्म तकनीक का उपयोग करने वाले सोलर से सैल को समान वस्तु मानने पर आपत्ति जताई है क्योंकि उनका मत है कि उत्पादन प्रौद्योगिकी, निर्माण प्रक्रिया, कच्ची सामग्री और सिस्टम में संतुलन का अंतर (बी ओ एस) उन्हें अलग करता है। तथापि, प्रतिनिधियों ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि थिन फिल्म सोलर सैल फोटोवोल्टाइक प्रक्रिया का उपयोग करके विद्युत के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तथापि, प्रतिनिधियों ने यह वादा किया है थिन फिल्म सोलर सैल का उपयोग कुछेक अनुप्रयोगों के कारण उपयोगकर्ताओं द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन इस बात से इन्कार भी नहीं किया है कि निम्न थिन फिल्म सोलर सैल क्रिस्टलाइन सिलिका टाइप सोलर सैल इस संदर्भ में प्रतिस्थापनीय है। सोलर पावर परियोजनाएं यह स्पष्ट नहीं करती कि क्या क्रिस्टलाइन सिलिका टाइप सोलर सैल अथवा थिन फिल्म सोलर सैल परियोजना के लिए बोली लगाने वाले विकासक द्वारा प्रदान किए जाने हैं और यह स्वीकार किया गया है कि यह विकासक के विवेक पर है कि वह कौन सी प्रौद्योगिकी का चयन करता है।
- घ. प्रतिवादियों ने यह कहकर एक नई संकल्पना शुरू की है कि थिन फिल्म सोलर सैल और क्रिस्टलाइन सिलिका सोलर सैल प्रतिस्थानीय नहीं है अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी है बल्कि इसकी बजाय 'वैकल्पिक', उत्पादन है। तथापि, 'वैकल्पिक' शब्द 'प्रतिस्थापन' और 'बदली' का समानार्थी है। अतः प्रतिवादियों का यह तर्क उनका अपना है।

प्रतिवादियों ने स्वयं ही यह कहा है कि विकास क्रिस्टलाइन सिलिका सोलर सैल अथवा थिन फिल्म सोलर सैल में से किसी का चयन परियोजना के कार्यान्वयन में कर सकता है।

- ड. 'समान वस्तु' के दायरे का निर्णय लेते समय कोई भी उत्पादन प्रक्रिया संगत नहीं है जैसा कि यू एस एस में विश्व व्यापार संगठन अपील निकाय द्वारा न्यूजीलैण्ड और आस्ट्रेलिया से फ्रेश, चिल्ड अथवा फ्रोजन लेम्ब मीट के आयातों पर रक्षोपाय के संबंध में पाया है, जिसमें यह पाया गया है कि उत्पादनों की पहचान और उनकी "समान अथवा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी" संबंधों पर ध्यान दिया जाना चाहिए न कि ऐसी प्रक्रिया पर जिसके द्वारा वह उत्पाद तैयार किया गया।
- च. उत्पादन प्रौद्योगिकी, निर्माण प्रक्रिया और प्रयुक्त की गई कच्ची सामग्री में अंतर का कोई प्रभाव नहीं है और केवल संगत कारक यह है कि कम वस्तुएं सीधे तौर पर एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करती हैं। यह प्रक्रिया विचाराधीन उत्पादन (पी वी सी) की पहचान से शुरू होती है। क्रिस्टलाइन सिलिका प्रौद्योगिकी के आयातित उत्पाद, घरेलू तौर पर उत्पादित क्रिस्टलाइन सिलिका प्रौद्योगिकी सैल समान वस्तु होंगे। भारत में आयातित थिन फिल्म प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए घरेलू तौर पर उत्पादित क्रिस्टलाइन सिलिका प्रौद्योगिकी के उत्पाद 'प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी' वस्तुएं होंगी।
- छ. जब यह विवाद नहीं है कि दोनों प्रकार के सैल सोलर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, तो क्रिस्टलाइन सिलिका प्रौद्योगिकी उत्पादों और थिन फिल्म प्रौद्योगिकी उत्पादों के बीच उनकी निर्माण प्रक्रिया अथवा उनमें इस्तेमाल की गई सामग्री के आकार पर अंतर करने का कोई भी प्रयास करने का अर्थ 'समान अथवा, प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद' न मानने के लिए परिभाषित करना होगा बल्कि ऐसी समान अथवा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु का एक हिस्सा मानना होगा। ऐसी सोच रक्षोपाय करार के अनुसार नहीं है, जैसा विश्व व्यापार संगठन पैनल की राय डोमिनिशियन रिपब्लिक रक्षोपाय विवाद में पाई गई है।
- ज. प्रतिवादियों ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद से थिन फिल्म को शामिल करना और/ अथवा निकालना मामला दर मामला आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी और कनाडा ने थिन फिल्मों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में माना है। वर्तमान मामले में शामिल तथ्यों से यह आवश्यक है कि थिन फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाए, अन्यथा समूची प्रक्रिया रक्षोपाय शुल्क लगाने की हो सकती है क्योंकि आज तक शुल्कों से बचने के लिए थिन फिल्म का प्रयोग करने लगेंगे। "थिन फिल्म मॉड्यूल" की उसी शीर्ष के तहत आयातित होती है और सोलर सैल/ माड्यूल जैसे बुनियादी सीमा शुल्क से उन्हें छूट प्राप्त है।
- झ. पूर्व निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि विभिन्न प्रौद्योगिकीय उत्पादों को अलग नहीं बनाती। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह पता था कि सोलर सैल, जो क्रिस्टलाइन और थिन फिल्म प्रौद्योगिकियों से बने हैं, (क) प्रौद्योगिकी (ख) बुनियादी कच्ची सामग्रियों के उपयोग (ग) उत्पादन प्रक्रिया (घ) संयंत्र एवं मशीनरी (ङ) प्रणाली में संतुलन और (च) क्षमता स्तर के संदर्भ में भिन्न है, थिन फिल्म सोलर सैल को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में माना है क्योंकि उनकी राय यह थी कि प्रौद्योगिकी में अंतर होने से सोलर पैनल के अनंतिम उपयोग को बदला नहीं जा सकता।
- ञ. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि क्रिस्टलाइन सिलिका सोलर सैल और थिन फिल्म सोलर सैल, दोनों ही सेमी कंडक्ट पी-एन जंक्शन डायोड हैं जो प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। दोनों ही प्रौद्योगिकियों से बने सोलर सैल अनंतिम उपयोगकर्ता के लिए मॉड्यूल/ पैनल के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे थे और यह कि लागत/ कीमत भी प्रति यूनिट वाट, सैल/ मॉड्यूल की क्षमता जैसे कारकों के आधार पर तय की गई है और क्रिस्टलाइन सिलिका और थिन फिल्म उत्पादों के बीच बाजार में प्रतिस्पर्धा सामान्यता दोनों प्रौद्योगिकियों के तहत ऐसे कारकों के आधार पर थी। इसके अलावा, दोनों प्रौद्योगिकियों के सोलर सैल साझा सीमा शुल्क वर्गीकरण और टैरिफ शीर्ष अर्थात 85414011 के तहत वर्गीकृत किए गए थे। अंततः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जो निम्न फिल्म सोलर सैल के लिए आवश्यक था वह इस तथ्य पर था कि दोनों प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले उत्पादनों के बीच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा थी क्योंकि वे दोनों ही सोलर लाइन से विद्युत बना सकते हैं और विकासक प्रारंभिक अवस्था में अपनी विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई भी प्रौद्योगिकी अपना सकते हैं और उसके बाद स्वतंत्र रूप से साथ साथ / एक प्रौद्योगिकी के उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाना, जो कि कार्यात्मक रूप से दूसरी प्रौद्योगिकी के उत्पाद से प्रतिस्थापनीय है, व्यर्थ होगा क्योंकि बिना शुल्क वाला उत्पाद बाजार में दूसरे को प्रतिस्थापित करेगा।
- ट. प्रतिवादियों ने इस बात को बल दिया कि क्रिस्टलाइन सिलिका सोलर सैल और थिन फिल्म सोलर सैल में प्रयुक्त बी ओ एस भिन्न और यह तर्क दिया कि चूंकि बी ओ एस दोनों मामलों में भिन्न है और उसकी लागत महत्वपूर्ण हो, थिन

फिल्म सोलर सैल और क्रिस्टलाइन सिलिका सोलर सैल समान वस्तु नहीं है तथापि, प्रतिवादियों ने इस बात से इन्कार नहीं किया है कि कोई परियोजना शुरू करते समय विकासक दोनों प्रौद्योगिकियों में से कोई भी प्रौद्योगिकी का सोलर सैल चुन सकते हैं। प्रतिद्वन्द्वियों ने यह केवल यह तर्क दिया कि कार्यान्वयन के चरण के बाद यह व्यवहारिक नहीं होगा कि किसी प्रौद्योगिकी को बदलकर प्रयोग करने वाले सोलर सैल प्रतिस्थापनीय हैं।

- ठ. समान वस्तु के अपने अलग डिजाइन के कारण हिस्सों की प्रतिस्पर्धा न होने से, जो खरीद के बाद उपभोक्ता के चयन को सीमित करती है, वस्तु को भिन्न नहीं माना जा सकता अर्थात् यदि विभिन्न ब्रांड से सेलुलर फोन भारत के क्षेत्र में पारित किए जाते हैं और प्रत्येक ब्रांड अपने प्रोपरायटरी चार्जर प्रयोग करते हैं, जो उपभोक्ता को खरीद के बाद ऐसी प्रोपरायटरी वाले चार्जर के चयन को सीमित करते हैं, तो इस अंतर से विभिन्न ब्रांड के सेल फोन को समान वस्तु नहीं माना जायेगा।
- ड. वास्वत में, सोलर सैल ने पाटन पर पूर्व अंतिम जांच परिणाम में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि क्रिस्टलाइन सिलिका सोलर सैल और थिन फिल्म सोलर सैल बी ओ एस की गणना में भी भिन्न है। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उसे समान वस्तु माना है।
- ढ. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि थिन फिल्म को यह मानकर समान वस्तु के दायरे में शामिल किया है कि भारत में प्रचलित बाजार स्थितियों के तहत, जिसमें उपभोक्ता दोनों ही उत्पादों को समान मानते हैं और उन्हें पूर्णतया एक दूसरे के प्रतिस्थापनीय पाया है, जिसमें एक उत्पाद को अलग करने से दूसरे प्रकार के उत्पाद के लिए पिछले दरवाजे से प्रवेश हो जाएगा और पूरी प्रक्रिया का प्रयोजन ही निष्फल हो जायेगा। अतः थिन फिल्म को अन्यथा बाहर नहीं किया जा सकता, उपभोक्ता समग्र प्रक्रिया को निष्फल करते हुए थिन फिल्म प्रौद्योगिकी की ओर जाएगा।
- ण. प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया है कि पूर्व में सोलर सैल पर पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणामों में अंतिम निर्णय नहीं हो पाया था। क्योंकि केंद्र सरकार ने शुल्क नहीं लगाया था। तथापि, यह मत गलत दिशा में जाता है कि क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटन के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक अंतिम जांच परिणाम में किया गया निर्धारण केवल सिफारिश के लिए था। इसके लिए नियम 17 स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि नियम 17(1)(ख) के तहत विनिर्दिष्ट शुल्क की मात्रा सिफारिश के रूप में है जबकि अन्य सभी निर्धारण, जो नियम 17 के तहत किये गये हैं, अंतिम है और केंद्र सरकार द्वारा आगे समीक्षा नहीं की जायेगी। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया गया उद्देश्यपरक निर्धारण मामलों का निष्कर्ष है। केंद्र सरकार का निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर शुल्क लगाने के लिए केवल व्यक्तिपरक विवेक होता है। यह तथ्य कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्षों की केंद्र सरकार द्वारा आगे समीक्षा नहीं की जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात द्वारा अलेम्बिक बनाम भारत संघ (2012 (291) ई एल टी 327) मामले में उल्लेख किया गया था। अतः सोलर सैल पर पूर्व के अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के तर्क पर विचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- त. पूर्व अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तर्क स्वीकार करना उचित है क्योंकि भारतीय परिपेक्ष्य में एक पूर्व जांच में विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण, संयुक्त राज्य और यूरोपीय संघ द्वारा अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किए गए निर्धारण की बजाय अधिक संगत होगा। इस बात पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से एकमत नहीं है कि क्या थिन फिल्म सोलर सैल को क्रिस्टलाइन सिलिका सोलर सैल के साथ समान वस्तु माना जाए। प्रत्येक जांच अधिकारी ने उनके अपने मामले के तथ्यों के आधार पर उसे शामिल करने/अलग करने का निर्णय लिया है जैसा कनाडा ने भी थिन फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया है।
- थ. प्रतिवादियों ने यह कहा है कि “पी ई आर सी” (पेसिवेटेड इमीटर शेयर सैल) आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले सोलर सैल, बाई-फेसियल एन-टाइप सोलर सैल, हाई एफिसिएंसी सोलर सैल, जो 5 और 6 बस बार उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाए गए हैं और मोनो क्रिस्टलाइन प्रौद्योगिकी को सोलर मॉड्यूल घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जाते। तथापि, यह मत बिना किसी आकार के हैं क्योंकि उपरोक्त सभी सैल के उत्पादन का प्रमाण सत्यापन के दौरान प्रदान किया जा चुका है।
- द. प्रतिवादियों के अनुसार एक सेज (एस ई जैड) यूनिट की स्थापना अतिरिक्त, आर्थिक क्रियाकलाप के उत्पादन, निर्यातों के संवर्धन, रोजगार अवसरों का सृजन करने और भारत में निवेश बढ़ाने, (एस ई जैड अधिनियम की धारा 5) के उद्देश्य से दी गई थी और सरकार निर्यात को प्रोत्साहित करने और सुकर बनाने के लिए अनेक रियायतें प्रदान करती है। घरेलू बाजार अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए में बिक्री) की सुविधा ऐसी इकाईयों इस कारण से दी गई केवल एक छूट है कि ऐसी इकाईयों के समक्ष कभी कभी अपने उत्पादों के सीधे निर्यात बाजार में बिक्री में समस्याएं आती हैं और उन्हें

अपने उत्पाद के उत्पादन को जारी रखने के लिए अनुमति दी जाती है। प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया कि जब घरेलू बाजार में बिक्री की अनुमति केवल छूट के लिए दी जाती है तो उसे ऐसी इकाईयों के लिए अधिकार का मामला नहीं माना जाना चाहिए ताकि वे घरेलू उद्योग के रूप में संरक्षण की मांग करें। तथापि, यह तर्क बिना मेरिट के है क्योंकि वादियों ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि सेज इकाईयां अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों के सृजन, रोजगार अवसरों के सृजन तथा भारत में निवेश बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः जब इसका प्रभाव अतिरिक्त क्रियाकलाप को लाभान्वित करने, निवेश सृजित करने और भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए है तो यह तथ्य कि वे एक कानूनी रूप से भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर मानी जाती हो, का कोई अर्थ नहीं है।

ध. सेज अधिनियम की धारा 51 के गैर-प्रतिबंधी खंड पर ताइवान फोटोवोल्टाइड इंडस्ट्री एसोसिएट (टी पी वी आई ए) पर निर्भरता यह कहकर कि यह अन्य सभी विधानों पर लागू होगा, का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि यह कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है कि यह केवल तभी प्रचालन में आएगा जब सेज अधिनियम और किसी अन्य विधान के प्रावधानों के बीच कोई विवाद हो। तथापि, टी पी वी आई ए सेज अधिनियम और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के बीच किसी संगतता को इंगित करने में विफल रहा हो।

न. यह निर्धारित करना कि क्या विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाली कोई यूनिट संबद्ध वस्तुओं की एक घरेलू उत्पाद मानी जा सकती है, को भी मामला दर मामला आधार पर तय किया जाना ही यद्यपि सामान्य स्थितियों में डी टी ए के लिए सेज की मंजूरी सीमा शुल्क को निर्धारित करता है क्योंकि भारत ने विचाराधीन उत्पाद के लिए अपना सीमा शुल्क घटाकर 'शून्य' कर दिया है क्योंकि भारत आई टी ए:1 एक हस्ताक्षरकर्ता है। याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन उत्पाद के लिए सेज में डी टी ए स्वीकृति किसी सीमा शुल्क को आकर्षित नहीं करती। इसके अलावा, सेज स्वीकृति के संबंध में, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई एक छूट है। सेज में आधारित इकाईयों के लिए यह दायित्व है कि सकारात्मक निवल विदेशी विनिमय (एन ई एफ) को बनाए रखे। तथापि, विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने वाली सेज आधारित इकाई के मामले में, सकारात्मक एन ई एफ बनाए रखने का यह दायित्व नियम 53 के उपनियम (क) से (ग) तक को देखते हुए डी टी ए स्वीकृति के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जिसके कुछेक मर्दें शामिल हैं, जिनकी डी टी ए में मंजूरी यह गणना में प्रयोजन के लिए निर्यात के एफ ओ बी मूल्य के लिए गिनी जाएगी कि क्या उस इकाई ने सकारात्मक एन एफ ई बनाकर रखा है। अतः एस डी ई जैड इकाईयां डी टी ए में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री निर्यात के दायित्व के बिना की जा सकती है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और वास्तव में ऐसा विशेष प्रावधान है, जो ऐसी सेज इकाईयों को डी टी ए में बिक्री की प्रक्रिया प्रदान करता है। सेज इकाईयों द्वारा ऐसी डी टी ए बिक्रियां डी टी ए में स्थित अन्य निर्माताओं के साथ घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा करती है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क किसी सेज इकाई द्वारा डी टी ए मंजूरी पर लागू नहीं है।

प. अनराउथ एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में निर्धारित अनुपात कानून की दृष्टि से सही नहीं है, जो एस्सार स्टील बनाम भारत संघ [2010 जी एल एच (1) 52], भारतीय निर्यात बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2012)46 वी एस टी 126, त्रिपूति उद्योग लिमिटेड जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध – प्रशासन श्री डी वी; साराधि बनाम सचिव वित्त मंत्रालय के माध्यम भारतीय संघ (यू ओ आई) और अन्य [2011 (272) ई एल टी 209 (ए. पी.)] माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना है जिसने यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र से डी टी ए की स्वीकृति आयात नहीं है। इस कारण से यदि डी टी ए ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों द्वारा बिक्री आयात नहीं है और विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तु डी टी ए में उसकी स्वीकृति पर बिना किसी प्रतिबंध के घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं तब ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों डी टी ए एककों को संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के रूप में नहीं माना जा सकता है।

फ. भारत में "सेचूरेटिड फैटी एल्कोहल" के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच में अंतिम जांच परिणामों में जिसमें यह माना गया था कि 100 प्रतिशत ई ओ यू भी एक घरेलू उत्पादक है, में विद्वान महानिदेशक रक्षोपाय का तर्क वर्तमान जांच के तथ्यों और परिस्थितियों पर भी पूर्ण रूप से लागू होता है। जिस प्रकार से एक ई ओ यू द्वारा डी टी ए में वस्तुओं की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उसी प्रकार से एक विशेष आर्थिक क्षेत्र से डी टी ए में भी वस्तुओं की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विद्वान महानिदेशक रक्षोपाय ने यह माना था कि यद्यपि एक ई ओ यू द्वारा डी टी ए की बिक्री एक अपवाद है, फिर भी सतत् रूप से इस प्रकार के अपवाद का लाभ उठाने घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने के लिए जिम्मेदार थे। वर्तमान मामले में भी,

इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों में आधारित याचिकाकर्ता सतत् रूप से डी टी ए की बिक्री करते आ रहे हैं। इसके अलावा, विशेष आर्थिक क्षेत्र में आधारित घरेलू उत्पादकों द्वारा डी टी ए में बेची गई विचाराधीन उत्पाद की मात्रा भारतीय उत्पादकों की कुल उत्पादन और बिक्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और इस कारण से इस प्रकार के उत्पादकों के पास संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है।

- (ब) अनरॉट एल्युमिनियम के मामले में विद्वान महानिदेशक, रक्षोपाय ने इस तथ्य पर विश्वास किया था कि डीटीए से एसईजेड को की गई बिक्रियों को एसईजेड अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्यात माना जाता है। तथापि, डीटीए को एसईजेड के क्लीयरेंस को एसईजेड से "निर्यात" अथवा भारत को "आयात" नहीं माना जाता है। इसलिए महानिदेशक, रक्षोपाय द्वारा विश्वास किए गए विधि का प्रावधान, घरेलू उद्योग के दायरे के भीतर एसईजेड माना जाना प्रासंगिक नहीं है। यह तथ्य भी प्रासंगिक नहीं है कि एसईजेड भारत के सीमा-शुल्क के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि महानिदेशक, रक्षोपाय माननीय उच्च न्यायालय के ईसार स्टील बनाम भारत संघ (सुप्रा), इंडिया एक्सपोर्ट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (सुप्रा) और तिरुपति उद्योग लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखने में विफल रहे हैं, जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि एसईजेड यूनिट पूर्णतया भारत के अधिकार-क्षेत्र के भीतर आते हैं और उन्हें केवल कानूनी कल्पना द्वारा भारत में सीमा-शुल्क के अधिकार-क्षेत्र से बाहर माना जाता है। तिरुपति उद्योग लिमिटेड (सुप्रा) के बारे में उच्च न्यायालय ने यह माना है कि एसईजेड यूनिटों को भारत में स्थापित यूनिटों के बतौर माना जाना होगा अन्यथा वे भारतीय कानूनों और विनियमों के अधीन नहीं होंगे तथा एसईजेड अधिनियम स्वतः उन पर लागू नहीं होगा जो कि उसे असंगत बना देगा।
- (भ) अनरॉट एल्युमिनियम के मामले में विद्वान महानिदेशक, रक्षोपाय ने यह पाया है कि यह प्रासंगिक नहीं है कि एसईजेड यूनिटों को पाटन-रोधी जांच में घरेलू उत्पादक माना गया है और यह दो कानूनी विधियों के अंतर्गत ऐसे भेद-भाव के लिए किसी कारण पर कोई परिचर्चा किए बिना रक्षोपाय जांच में लागू नहीं होता है। ईओयू और एसईजेड यूनिटों को घरेलू उत्पादकों के रूप में माने जाने के संबंध में पाटन-रोधी अथवा रक्षोपाय प्रावधानों में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। इसलिए इस तथ्य के बावजूद कि पाटन-रोधी जांच में एसईजेड यूनिटों को घरेलू उत्पादक माना जाता है, एसईजेड यूनिटों को घरेलू उत्पादक नहीं माने जाने पर विचार करते समय उसके लिए कारणों का उल्लेख किए जाना आवश्यक था। पूर्व जांच-रोधी जांच में एसईजेड यूनिट को घरेलू उत्पादक माने जाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए महत्वपूर्ण कारण वर्तमान सुरक्षा जांच के तथ्यों और परिस्थितियों पर भी समान रूप से लागू होते हैं।
- (म) यह देखते हुए कि अनरॉट एल्युमिनियम के मामले में एसईजेड यूनिटों को समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के रूपा में नहीं माना जा सकता है, विद्वान महानिदेशक, रक्षोपाय (1) माननीय उच्च न्यायालय के के उपरोक्त निर्णय को नोट करने में विफल रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से यह माना गया है कि एक एसईजेड यूनिट द्वारा डीटीए की बिक्रियां भारत में आयात अथवा एसईजेड द्वारा निर्यात नहीं हैं और एसईजेड यूनिट पूर्णतया भारत के क्षेत्राधिकार के भीतर हैं; (2) यह सुस्पष्ट करने में विफल रहे हैं कि पाटन-रोधी कानूनों के अधिकार-क्षेत्र के भीतर एसईजेड यूनिट कैसे घरेलू उत्पादक हैं और (3) साथ ही यह भी सुस्पष्ट करने के विफल रहे हैं कि घरेलू उत्पादक के रूप में 100% निर्यातोन्मुख एकक मानने के लिए कैसे परीक्षण लागू होते हैं, जो कि यह निर्धारित करने के लिए लागू नहीं होते हैं कि क्या एसईजेड यूनिट को घरेलू उत्पादक भी माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्वान महानिदेशक, रक्षोपाय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि पर भी विचार करने में विफल रहे हैं और उन्होंने पाटन-रोधी विधियों और सुरक्षा विधियों के लिए घरेलू उत्पादकों के बतौर माने जा रहे एसईजेड यूनिटों और रक्षोपाय विधियों के अनुसार नहीं माने जा रहे यूनिटों के बीच के अंतर का भी उल्लेख नहीं किया है और साथ ही 100% निर्यातोन्मुख एकक माने जाने के लिए परीक्षणों को लागू नहीं किए जाने के बारे में उल्लेख किया है। इसलिए अनरॉट एल्युमिनियम के मामले में विद्वान महानिदेशक, रक्षोपाय का निर्णय पर *इन्क्युरियम* और *सब साईलेंटो* दोनों हैं और ये महानिदेशक, रक्षोपाय पर बाध्यकारी नहीं हैं। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम सिंथेटिक्स और केमिकल्स लिमिटेड और अन्य {(1991) 4 एससीसी 139} ने निर्णय दिया है, ऐसे मुद्दे पर निर्णय जो कि पर *इन्क्युरियम* और *सब साईलेंटो* है, बाध्यकारी पूर्वदृष्टांत नहीं है और परवर्ती मामले पर निर्णय लेने के लिए विचार करते समय इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।
- (य) प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया है कि याचिकादाता एमएनआरई के आंकड़ों पर आधारित संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के प्रमुख भाग का उत्पादन नहीं करते हैं क्योंकि भारत में सेल्स और मॉड्यूल्स की कुल स्थापित क्षमता 11562 मेगावाट है, जबकि याचिकादाताओं की कुल स्थापित क्षमता 3164 मेगावाट है। तथापि, यह तर्क रक्षोपाय विधि के अनुचित आधार और अवधारणा पर आधारित है क्योंकि घरेलू उद्योग के आधार का निर्धारण करने के लिए संबद्ध कारक भारत में घरेलू उत्पादकों की स्थापित क्षमता नहीं बल्कि संबद्ध वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन है।

- (कक) प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया है कि चूंकि सोलर मॉड्यूल्स को समान वस्तु माना गया है, इसलिए कुल उत्पादन का परिकलन करने को प्रयोजनार्थ आयातित सोलर सेल्स से विनिर्मित सोलर मॉड्यूल्स पर भी विचार किया जाना चाहिए और विकल्प के रूप में सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स के पृथक् रूप से घरेलू उत्पादन को ध्यान में रख कर घरेलू उद्योग के आधार की जांच की जाए। तथापि, ये निवेदन निराधार हैं क्योंकि विचाराधीन उत्पाद सोलर सेल्स हैं और इसलिए आयातित सोलर सेल्स को कभी भी समान वस्तु का घरेलू उत्पादन नहीं माना जा सकता है क्योंकि तथ्य यह है कि इन्हें मॉड्यूल्स विनिर्माताओं द्वारा मॉड्यूल्स में संकलन किया जाता है और वे इन्हें आयातित सेल्स से घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु में परिवर्तित नहीं करते हैं। घरेलू रूप से उत्पादित सोलर से उत्पादित कुछ मॉड्यूल्स को संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके फलस्वरूप समान वस्तु के कुल उत्पादन की दोहरी गणना होगी क्योंकि घरेलू रूप से उत्पादित सोलर सेल्स की गणना पहले सोलर सेल्स विनिर्माताओं द्वारा उत्पादन करने के समय की जाएगी और उसके बाद उसकी दुबारा गणना घरेलू मॉड्यूल्स विनिर्माताओं द्वारा उनको मॉड्यूल्स में व्यवस्थित करने के लिए की जाएगी। इसके फलस्वरूप उसी सोलर सेल की गणना भारत में विचाराधीन उत्पाद की कुल आउटपुट का परिकलन करने के लिए की जाएगी और इसलिए यह अस्वीकार्य है।
- (खख) यदि आयातित सोलर सेल्स को जिन्हें बाद में मॉड्यूल्स में व्यवस्थित किया जाता है, भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ शामिल किया जाता है, तब भी याचिकादाताओं का उत्पादन समान वस्तु के कुल उत्पादन का प्रमुख भाग बनेगा। तथापि, भारत में आयातित सेल्स से सोलर मॉड्यूल्स के उत्पादन की मात्रा के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (गग) प्रतिवादियों के इस अनुरोध के संबंध में कि मुन्द्रा सोलर पीवी लिमिटेड को घरेलू उद्योग से बाहर रखा जाए क्योंकि यह अभी भी प्रारंभिक चरण में है, निवेदन है कि रक्षोपाय विधि उन्हें अयोग्य नहीं बनाती है अथवा घरेलू उत्पादकों के बीच उनके प्रचालन की अवधि के आधार पर अंतर को निर्धारित नहीं करती है। इसके अतिरिक्त मुन्द्रा सोलर पीवी लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया है और उसे घरेलू बाजार में बेचा है, इसलिए यह आरोप पूर्णतया निराधार है कि वह विचाराधीन उत्पाद के घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही है। हालांकि मुन्द्रा सोलर पीवी लिमिटेड ने हाल ही में उत्पादन करना शुरू किया है, वह सस्ते आयातों के कारण घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं को बेचने में असमर्थ है और इसलिए वह अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ गंभीर क्षति का सामना कर रही है।
- (घघ) कुछ प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया है कि आयातों में तेज वृद्धि नहीं हुई है अथवा वृद्धि अचानक नहीं हुई ताकि गॉट के अनुच्छेद XIX के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और यह कि आयातों ने मांग के साथ गति बनाई रखी है और इसलिए वृद्धि उत्तरोत्तर थी। इस संबंध में विद्वान महानिदेशक, रक्षोपाय ने दिनांक 05.01.2018 के प्रारंभिक अंतिम जांच परिणाम में यह निर्णय दिया है कि जांच शुरू करने से पहले तात्कालिक अवधि अर्थात् वर्ष 2017-18 के प्रथम छः महीनों में आयातों की मात्रा में अचानक और व्यापक उछाल आया था, जो कि वर्ष 2016-17 में आयातों का लगभग 74% था। इसलिए आयातों में संपूर्ण वृद्धि हुई है, जो कि किसी भी मानक के अनुसार हाल ही में, अचानक, तेज और अत्यधिक थी।
- (ङङ) अनुच्छेद XIX के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित आयातों में वृद्धि, आयातों की मात्रा में संपूर्ण वृद्धि के साथ-साथ घरेलू उत्पादन और खपत दोनों के संबंध में हो सकती है। संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन के संबंध में आयातों में व्यापक वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त याचिकादाताओं द्वारा क्षमताओं का संवर्धन और अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं की बिक्रियां शुरू किए जाने के बावजूद भारत में खपत के संबंध में आयातों में भी वृद्धि हुई है।
- (चच) जेएनएनएसएम के अंतर्गत संशोधित लक्ष्य ने भारत में विचाराधीन उत्पादन की अचानक अत्यधिक मांग सृजित कर दी है और डीसीआर को समाप्त करने के साथ भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में व्यापक उछाल आया है। आयातों में उछाल वर्ष 2015 में विचाराधीन उत्पाद की अचानक सृजित अत्यधिक मांग के कारण नहीं आया था, बल्कि यह इस तथ्य के कारण था कि ऐसे आयात अत्यधिक सस्ती कीमतों पर किए जा रहे थे। इसलिए ऐसे सस्ते आयातों के व्यापक उछाल ने घरेलू उद्योग की गंभीर क्षति पहुंचाई है, जो कि उनके अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं।
- (छछ) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अप्रत्याशित घटनाओं को "दूरस्थ" विगत की घटनाओं के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसा तर्क उनको प्रमाणित करने के लिए आवश्यक तथ्यों और ब्यौरों को प्रमाणित किए बिना दिया गया है क्योंकि हितबद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि किन अप्रत्याशित घटनाओं को "दूरस्थ" विगत कहा जा सकता है।
- (जज) क्रिस्टेलीन सिलीकोन फोटोवोल्टेड (सीएसपीवी 1) के मामले में संयुक्त राज्य अमरीका में प्रथम पाटन-रोधी और प्रतिकारी शुल्क आदेश 07.12.2012 से प्रभावित हुए थे और क्रिस्टेलीन सिलीकोन फोटोवोल्टेड (सीएसपीवी 1) की दूसरी जांच के अनुसरण में शुल्क 18.02.2015 को प्रभावित हुए थे। यूरोपीय यूनियन में उन्हीं संबद्ध वस्तुओं के संबंध में अंतिम उपाय 05.06.2013 से प्रभावित हुए थे और अंतिम उपाय 05.12.2013 को लागू किए गए थे। संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय

यूनियन द्वारा लागू उपायों की समय-सीमा कुल मिला कर एक दूसरे के समकालीन और न्यूनतम थी अथवा उनमें कोई अंतर नहीं था। इन उपायों को लागू करने के फलस्वरूप जेएनएनएसएम के अंतर्गत घरेलू मात्रा की आवश्यकताओं (डीसीआर) के कारण आयातों में तत्काल उछाल नहीं आया था। तथापि, कुछ समय के बाद विश्व व्यापार संगठन द्वारा जेएनएनएसएम को, गॉट 1994 के अनुच्छेद III:4 और वर्ष 2016 में टीआरआईएम करार के अनुच्छेद 2.1 के अंतर्गत भारत द्वारा निभाए गए दायित्वों के असंगत घोषित कर दिया गया था। इन अप्रत्याशित घटनाओं के फलस्वरूप आयातों में प्रत्यक्ष उछाल आया था और यह उछाल के समकालीन था तथा इसलिए इसे बसुशिकल विगत नहीं कहा जा सकता है।

(झ) कुछ हितबद्ध पक्षकारों की यह अवधारणा गलत है कि कुछ अप्रत्याशित घटनाएं आयातों के उछाल के लिए जिम्मेदार थीं, जो कि गॉट के अंतर्गत एक दायित्व के प्रभाव अथवा बहुपक्षीय करारों के परिणाम स्वरूप आया था, क्योंकि गॉट के अनुच्छेद XIX की भाषा में ऐसा उल्लेख नहीं है अथवा वह इसे किसी भी तरीके से उल्लिखित नहीं करती है। बल्कि उसमें ऐसी परिकल्पना है कि आयातों में उछाल, अप्रत्याशित घटना के साथ-साथ गॉट के अंतर्गत निभाए गए दायित्वों दोनों के परिणाम स्वरूप होना चाहिए। गॉट के अनुच्छेद XIX में वाक्यांश "के परिणाम स्वरूप", "अप्रत्याशित घटनाओं" और "दायित्वों के प्रभाव" दोनो शर्तों से पूर्व आता है और ये दोनों को जोड़ता नहीं है। इस संबंध में यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि "अप्रत्याशित घटनाओं" और "दायित्वों के प्रभाव" वाक्यांश दोनों के बीच "और" शब्द के साथ जोड़ते हैं। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संविधि में शब्दों का सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए जब तक कि इसके परिणाम स्वरूप कोई संविधि के के परिप्रेक्ष्य में कोई संदिग्धता अथवा भिन्न आशय नहीं निकलता है। यह नोट करना आवश्यक है कि "और" शब्द "के साथ", "के साथ-साथ", "इसके अतिरिक्त", "सहित" आदि शब्दों के समानार्थक हैं और इनका प्रयोग अनुच्छेदों के शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने "और" शब्दों को "के कारण" शब्दों से प्रतिस्थापित कर दिया है और इस प्रकार अनुच्छेद XIX की शर्त को "दायित्वों के प्रभाव के कारण अप्रत्याशित घटनाओं के परिणाम स्वरूप" पढ़ा है। अनुच्छेद XIX की ऐसी संरचना तर्क संगत नहीं है क्योंकि संविधि में शब्दों को ऐसे जोड़ना अथवा पढ़ना अस्वीकार्य है, जो कि उसके प्रारूप निर्माताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा आवश्यक विविक्षा के कारण प्रदान नहीं किए गए हैं। अप्रत्याशित घटनाओं की शर्त गॉट के अंतर्गत दायित्वों के प्रभाव के अतिरिक्त है। इसलिए जब तक आयातों में उछाल रहता है और ऐसा दर्शाया जा सकता है कि यह इन दशाओं अर्थात् दायित्वों के प्रभाव और अप्रत्याशित घटनाओं दोनों के परिणाम स्वरूप हैं, अनुच्छेद XIX की आवश्यकताएं पूरी होती हैं।

(ञ) प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया है कि जिन घटनाओं के फलस्वरूप आयात हुए हैं, वे अप्रत्याशित नहीं हैं और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वे क्यों अप्रत्याशित नहीं हैं। तथापि, प्रतिवादियों की यह अवधारणा ऐसे गलत अनुमान पर टिकी हुई है कि अप्रत्याशित घटनाएं अप्रत्याशित होनी चाहिए क्योंकि यह निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कोई घटना अप्रत्याशित घटना थी अथवा ऐसी घटना अप्रत्याशित है, दायित्वों का निर्वहन करने के समय वह प्रत्याशित थी, उनकी जांच की जानी चाहिए। अपील निकाय ने अर्जेंटीना फुटवीयर के मामले में यह निर्णय दिया था कि की जाने वाली जांच यह नहीं है कि घटनाएं अप्रत्याशित थीं। बल्कि जांच यह है कि क्या विश्व व्यापार संगठन के अभिगमन के दायित्वों के निर्वहन के समय घटनाएं अप्रत्याशित थी, जो कि विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न करारों के अंतर्गत वचनबद्धताओं का अनुपालन करने के लिए थीं, जिनमें टैरिफ रियायतों और उन टैरिफ रियायतों में *(वर्तमान मामले के परिप्रेक्ष्य में मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन ट्रेड इन इनफोरमेशन टेक्नोलोजी प्रोडक्ट्स (आईटीए 1))* परवर्ती संशोधन किए जाने की व्यवस्था है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिन घटनाओं के कारण अत्यधिक बड़ी हुई मात्राओं में आयात हो रहे हैं और ऐसी दशाओं में जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, उनको दिनांक 13 दिसंबर, 1996 को - जिस तारीख को मंत्री आईटीए-1 के प्रति सहमत हुए थे, उनको अप्रत्याशित अथवा असंभावित माना गया है।

(ट) यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा व्यापार के उपाय लागू करने से पहले इन क्षेत्रों में चीन के निर्यात, उसके कुल निर्यातों का 75.93% थे, जब कि भारत को ऐसे निर्यात मात्र 1.52% थे। तथापि, इन उपायों को लागू करने के बाद संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय यूनियन में चीन से निर्यात समग्र रूप से 10.71% थे, जबकि भारत में इस समय ये निर्यात 29.8% हैं, जो कि चीन के निर्यात पैटर्न में अंतरण होने की विवर्तनिका का संकेत देते हैं। इसलिए अप्रत्याशित घटनाओं ने वस्तुतः आयात किए जा रहे और भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की दशाओं में परिवर्तन कर दिया है। व्यापार के पैटर्न में ऐसा विशिष्ट परिवर्तन होने से चीन ने यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका आदि जैसे विकसित देशों/बाजारों की तुलना में उग्र रूप से भारतीय बाजार को अपना लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया है, जो कि उचित रूप से प्रत्याशित नहीं था। इसके अतिरिक्त भारत को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के समय चीन के निर्यातकों द्वारा शुरू किए गए अभूतपूर्व और अप्रत्याशित क्षमता विस्तार की भी प्रत्याशा नहीं थी, जिसे प्रोत्साहनों के रूप में राज्य की सहायता, सब्सिडी और टैरिफ का समर्थन प्राप्त है।

- (ठठ) रिकार्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह पता चले कि आईटीए:1 के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन करने के समय भारत ने यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा द्वारा चीन से आयातों पर व्यापार के उपचारी उपाय के प्रभार की प्रत्याशा की थी। इसके अतिरिक्त भारत ने वास्तव में यह विश्वास किया था कि जेएनएनएसएम के अंतर्गत डीसीआर, गॉट 1994 के अनुच्छेद XX में निहित अपवादों के सुसंगत था। इसलिए आईटीए:1 के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन करने के समय भारत ऐसी प्रत्याशा नहीं कर सका था कि उसका डीसीआर, जिस पर उसने यह विश्वास किया था कि वह गॉट के अनुच्छेद XX के सुसंगत है, को गॉट के अंतर्गत उसके दायित्वों के असंगत घोषित कर दिया जाएगा।
- (डड) न तो चीन के खिलाफ संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय यूनियन द्वारा अपनाए गए व्यापार के उपाय, जिनसे उसने अपना ध्यान भारत में संकेन्द्रित कर दिया है और न ही भारत के खिलाफ लगाए गए संयुक्त राज्य अमरीका के उपाय, जिसने घरेलू उद्योग को पेश किए गए गॉट डीसीआर के संरक्षण को समाप्त कर दिया था, को 13.12.1996 से पहले लंबे वर्षों तक नहीं देखा गया था, जिस तारीख को भारत ने गॉट के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन किया था। इससे पता चलता है कि उपरोक्त घटनाएं प्रत्याशित नहीं थीं और भारत ऐसी घटनाओं को उचित रूप से नहीं देखा सका था, जो कि राष्ट्रों के बीच कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में घटनाओं के चरम बिन्दु पर पहुंचने का परिणाम थी।
- (ढढ) इस तथ्य की भी प्रत्याशा नहीं की गई थी कि भारत पर्यावरण में परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2030 तक 33% - 35% के स्तर तक कमतर बहिष्काव की वचनबद्धता को पूरा करने और नॉन-फोसिल आधारित विद्युत जेनरेशन क्षमता में अपने अंशदान को 40% तक बढ़ाने में नेतृत्व कर लेगा। 197 देशों (जिसे इस समय 172 देशों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है) द्वारा हस्ताक्षरित वर्ष 2015 पेरिस करार के अंतर्गत भारत द्वारा की गई वचनबद्धता को 13 दिसंबर, 1996 को आईटीए-1 के अंतर्गत स्वीकृत सोलर सेल्स के लिए आयात टैरिफ रियायत के समय अप्रत्याशित था। एसीएमई नामक एक प्रतिवादी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि भारत द्वारा अपनी क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने के अपना लक्ष्य निर्धारित करने के फलस्वरूप सोलर पेनलों/मॉड्यूल्स की मांग बढ़ गई है और यह अत्यधिक हो गई है। यह तथ्य कि भारत ऐसा एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य स्थापित करेगा और यह तथ्य कि डीसीआर में अनिवार्य रूप से घरेलू अंश की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा, भारत के लिए आईटीए:1 के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करते समय निश्चित रूप से अप्रत्याशित था।
- (णण) इससे मनाही नहीं की जा सकती है कि समस्त अप्रत्याशित घटनाएं जो कि एक साथ घटित हुई हैं और जो कि समकालीन हुई हैं, जैसे कि बहुविध देशों द्वारा व्यापारिक सुधार उपायों को लागू करना, इन उपायों के फलस्वरूप चीन के व्यापार निर्यात पेटर्न में परिवर्तन होना और उसके तुरंत पश्चात डीसीआर को हटा दिया जाना जिसका तात्पर्य यह है कि घरेलू रूप से उत्पादित उत्पाद अब अनिवार्य आवश्यकता नहीं हैं, आईटीए:1 पर हस्ताक्षर करने के समय भारत द्वारा प्रत्याशित नहीं थीं।
- (तत) कुछ पक्षकारों ने यह उल्लेख करते हुए आपत्ति की है कि आईटीए:1 के अंतर्गत भारत के दायित्वों का प्रभाव का वर्ष 2015 में आयातों में उछाल आने से कोई संबंध नहीं है क्योंकि दोनों घटनाएं उस समय असंबंधित थीं। तथापि, प्रतिवादी अनुच्छेद XX में प्रयुक्त शब्दों को समझने में विफल रहे हैं, जो कि रिकार्ड पर यह प्रदर्शित करते हैं कि दायित्वों के प्रभावों में टैरिफ रियायतें शामिल होंगी। भारत ने विश्व व्यापार संगठन को रियायतों की अनुसूची प्रदान की है और गॉट के अंतर्गत इन वचनबद्धताओं को पूरा करने का संकल्प लिया है। भारत और विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों ने *मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन ट्रेड इन इनफोरमेशन टेक्नोलोजी प्रोडक्ट्स (आईटीए 1)* के माध्यम से रियायतों की इस अनुसूची में संशोधन किए हैं। सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की सीमा-शुल्क टैरिफ मद 85414011 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तुओं पर भारत का आयात टैरिफ "शून्य" है। इस "शून्य" टैरिफ को गॉट 1994 के अंतर्गत भारत पर दायित्व के अनुसरण में शुरू किया गया था, जिसमें उसके अंतर्गत ऐसी रियायतें शामिल थीं, जिनमें संशोधन दिनांक 13 दिसंबर, 1996 ("आईटीए-1") *मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन ट्रेड इन इनफोरमेशन टेक्नोलोजी प्रोडक्ट्स (आईटीए 1)* के अनुसरण में किया गया था। संबद्ध वस्तुओं को आईटीए-1 के संलग्नक-क, भाग-1 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आईटीए-1 में गॉट 1994 के अनुच्छेद-2:1(ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर सूचीबद्ध उत्पादों पर सीमा-शुल्क और किसी भी प्रकार के अन्य शुल्कों/प्रभारों को समाप्त करने का अधिदेश है। इसलिए आईटीए-1 के अंतर्गत भारत के दायित्वों के प्रभाव के कारण भारत को विचाराधीन उत्पाद पर सीमा-शुल्कों को समाप्त करना था, जिसने आयातों के उछाल को सुकर बना दिया था और यदि यह आयात सीमा-शुल्कों के अध्येधीन होते, तो यह वर्तमान स्तर तक नहीं होते। इसके अतिरिक्त आईटीए-1 आयातित विचाराधीन उत्पाद पर भारत की *स्वतंत्र कार्रवाई (पेनल रिपोर्ट, यूक्रेन - पेसेंजर कार्स, पैरा 7.96 को देखें)* को भी सीमित करता है और उसे आयातों में उछाल को नियंत्रित रखने के लिए सीमा-शुल्क को बढ़ाने से भी रोकता है।

- (थथ) अप्रत्याशित घटनाओं के विपरीत जो कि आयातों में वृद्धि होने के समय घटित हुई थीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि गॉट के अंतर्गत निभाए गए दायित्व, आयातों में वृद्धि होने के समकालीन हों।
- (दद) दायित्वों के प्रभाव की अन्य घटना भी वही थी, जिसके फलस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के आयातों में उछाल आया है, गॉट 1994 के अनुच्छेद-III :4 और टीआरआईएम करार के अनुच्छेद 2.1 के अंतर्गत भारत के निर्वहन से हुई थी। घरेलू उद्योग को प्रारंभ में जेएनएनएसएम के अंतर्गत घरेलू अंश की मात्रा ("डीसीआर") द्वारा निर्दिष्ट मात्रा तक केप्टिव घरेलू बाजार का आश्वासन प्राप्त था। तथापि, डीसीआर को संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा चुनौती दिए जाने के अनुसरण में विश्व व्यापार संगठन के अपील निकाय ने उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत भारत के दायित्व को असंगत घोषित कर दिया था। इसलिए गॉट के अंतर्गत भारत के दायित्वों ने उसे ऐसे उपाय बनाए रखने से रोका था, जो कि घरेलू अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक थे और जिन्होंने आयातों के अंतप्रवाह को रोका था। विश्व व्यापार संगठन के अपील निकाय के निर्णय के अनुसरण में डीसीआर को हटाने का अभिप्राय यह था कि भारत को डीसीआर को हटाना था और इसलिए गॉट के अंतर्गत भारत के दायित्वों जिन्होंने उसे डीसीआर को बनाए रखने से रोका था, जिसके फलस्वरूप उस समय आयातों में उछाल आया था।
- (धध) कुछ प्रतिवादियों ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग ने किसी गंभीर क्षति का सामना नहीं किया है क्योंकि घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग को पूरा करने की अपर्याप्त क्षमता के कारण आयात जरूरी थे और इसलिए घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है। ऐसे तर्क का कोई महत्व नहीं है क्योंकि क्षमता का उपयोग करने में याचिकादाताओं की असमर्थता का कारण सस्ते आयातों की मौजूदगी है, जो कि घरेलू उद्योग को उसकी वर्तमान क्षमता तक संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने और बेचने से रोक रहे हैं। जब घरेलू उद्योग अपनी वर्तमान क्षमता तक संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने अथवा बेचने में समर्थ नहीं है और जब अत्यधिक मांग होने के कारण भी वर्ष-दर-वर्ष उसकी क्षमता का उपयोग घट रहा है, तब याचिकादाताओं के लिए क्षमता में और संवर्धन करना अव्यावहारिक हो जाता है क्योंकि उससे नियत लागत में और अधिक वृद्धि होगी। चूंकि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेची जाने वाली संबद्ध वस्तुओं की कीमतें बहुत कम होती हैं, तथ्य यह है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के लिए उसे लाभप्रद कीमतें नहीं मिल सकती हैं, जो कि उसकी क्षमता में और संवर्धन करने के लिए उसे रोकती हैं।
- (नन) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को अलाभप्रद कीमतों पर बेचने के कारण उसे अत्यधिक घाटे हुए हैं, जिसके कारण उसे और निवेश करने के लिए पूंजी जुटाने में भी कठिनाई हुई है। वस्तुतः यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि इंडोसोलर सेल्स का विनिर्माण (इंडोसोलर की क्षमता का दुगुना बढ़ाने के लिए) करने के लिए अन्य उत्पादन श्रृंखला को जोड़ने की प्रक्रिया में थी और मुन्द्रा सोलर पीवी लिमिटेड भी अपनी क्षमता को 1.2 गीगावाट से बढ़ा कर 3.0 गीगावाट करने (150% तक बढ़ाने) की प्रक्रिया में थी। तथापि, चूंकि बहुत सस्ते आयातों के अंतप्रवाह के कारण घरेलू उद्योग अपने द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को घरेलू बाजार में बेचने में असमर्थ था, उसने क्षमता विस्तार करने की अपनी समस्त योजनाओं को आस्थगित कर दिया था और वस्तुतः अधिकतर याचिकादाताओं ने इस समय मुन्द्रा सोलर पीवी लिमिटेड के साथ प्रचालनों को बंद कर दिया है, जो कि अन्तर-विराम से अपनी उत्पादन श्रृंखला का प्रचालन कर रही है। यही स्थिति हेलिओज फोटोवोल्टाईक लिमिटेड की भी है, जिसने मई, 2017 में अपनी लाईन को बंद कर दिया है और ज्युपीटर सोलर ने नवंबर, 2017 में उत्पादन करना बंद कर दिया है।
- (पप) प्रतिवादियों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति नहीं हो रही है क्योंकि कुछ आर्थिक प्राचल अत्यधिक गिरावट नहीं दर्शाते हैं। इस प्रयोजनार्थ उन्होंने भारतीय उत्पादकों के बाजार के हिस्से से संबंधित आंकड़ों पर विश्वास किया है, जिन्होंने समग्र 4% की गिरावट दर्शाई है। तथापि, इसे भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। घरेलू उद्योग की अपनी उत्पादन क्षमताओं की समग्र सीमा तक संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए पर्याप्त मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए अपनी संस्थापित क्षमता के उचित स्तर तक का भी उपयोग नहीं कर सका है और इसके अतिरिक्त वह अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की समग्र मात्रा को बेचने में भी समर्थ नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप ऐसा पता चलता है कि भारतीय उत्पादकों की संस्थापित क्षमता की समग्र सीमा का उपयोग करने वाले मजबूत बाजार में भारतीय उत्पादकों के बाजार का हिस्सा 4% तक कम हो गया है। बल्कि घरेलू उद्योग की मालसूचियों में वृद्धि हुई है।
- (फफ) प्रतिवादियों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है क्योंकि उसके उत्पादन और बिक्रियों के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। तथापि, इसे घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने की क्षमता में संवर्धन होने के आलोक में समझना होगा। यदि घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता का संवर्धन किए बिना उसके उत्पादन और बिक्रियों में सुधार हुआ है, तो संभवतः यह तर्क दिया जा सकता है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है। तथापि, हालांकि घरेलू उद्योग ने संस्थापित क्षमता में

संवर्धन किया है, फिर भी उसके उत्पादन और बिक्रियों में समनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। तथ्य यह है कि अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, इसलिए इस तथ्य की जांच वर्ष 2014-15 और 2015-16 में उनके नगण्य उत्पादन के आलोक में की जाने की आवश्यकता है। बल्कि इस पर विचार करने की भी आवश्यकता है कि अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ-साथ घरेलू उद्योग की बिक्रियां, उसके अपने स्वतंत्र आधार पर बढ़ रही हैं, जब कि भारतीय उत्पादकों के बाजार के हिस्से में वस्तुतः 4% तक की गिरावट आई है।

- (बब) प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया है कि उत्पादन के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है क्योंकि एसईजेड में स्थापित 3 यूनिट निर्यात करने में असमर्थ रहे हैं। तथापि, यह तर्क ऐसा है, जैसे कि निर्यात करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के एसईजेड यूनिटों के लिए ऐसी कोई बाधयता नहीं है, क्योंकि वे डीटीए क्लीयरेंस द्वारा सकारात्मक एनएफई प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, प्रारंभ में निर्यात बाजारों में बिक्रियां नगण्य थीं और यह घरेलू बाजार में बिक्री के लिए उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तुओं का बहुत कम हिस्सा बनती थीं और इसलिए उसके कार्य निष्पादन में कोई भी गिरावट, घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में मात्र नगण्य सीमा तक प्रतिबिंबित होगी। तीसरे, उत्पादन के संबंध में आयातों की तुलना, घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की सीमा तक प्रतिबंधित नहीं है और बल्कि उसमें सभी घरेलू उत्पादकों द्वारा भारत में समग्र घरेलू उत्पादन शामिल है। चौथे, निर्यातों के प्रभाव के अपवर्जन के बाद क्षति के प्राचल प्रस्तुत किए गए हैं।
- (भभ) प्रतिवादियों ने यह दावा किया है कि मुन्द्रा सोलर पीवी लिमिटेड के संवर्धन को ध्यान में रखते हुए जिसने वर्ष 2017-18 में उत्पादन करना शुरू किया था, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग, प्रति कर्मचारी उत्पादकता और लाभप्रदता में कमी आई है। तथापि, इस संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि यदि मुन्द्रा सोलर पीवी लिमिटेड के आंकड़ों के अपवर्जन के बाद घरेलू उद्योग के इन प्राचलों की जांच की जाती है, तो यह फिर भी यह प्रदर्शित करेगी कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति हुई है।
- (मम) प्रतिवादियों ने यह दावा किया है कि कीमत में कटौती होने के आंकड़े, किसी कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण होने का संकेत नहीं देते हैं। जबकि एक मात्र सोलर सेल्स के आयातों के लिए अनेक कीमत कटौतियां कम हुई हैं, लेकिन यह इस तथ्य के कारण नहीं है कि उनके पहुंच मूल्य में वृद्धि हुई है। बल्कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की कीमतों को आयातों की कीमतों के साथ यथा संभव प्रतिस्पर्धी बनाने के प्रयास कर रहा है, ताकि वह अपनी मालसूची को बेच सके। तथापि, अनेक कीमत कटौतियां अभी भी उस सीमा तक अत्यधिक हैं, जहां आयातों का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की बिक्रियों की आधी लागत से भी कम है। इसलिए घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं की कीमत को बिक्रियों की अपनी लागत से भी कम करने पर विवश होना पड़ा है और उसे क्षति हो रही है।
- (यय) सोलर मॉड्यूल के पहुंच मूल्य में विकट कमी हुई है, जो कि इस सीमा तक है कि सोलर मॉड्यूल का ऐसी कीमत पर आयात किया जा रहा है, जो कि मॉड्यूल में व्यवस्थित नहीं किए गए सोलर सेल्स का उत्पादन करने के लिए घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत से भी कम है। इसके परिणाम स्वरूप मॉड्यूल में व्यवस्थित नहीं किए गए सोलर सेल्स की कीमत कटौती की श्रृंखला में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग समस्त जांच अवधि के दौरान बेची गई अपनी संबद्ध वस्तुओं के लिए लाभप्रद कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहा है, जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि घरेलू उद्योग की कीमत न्यूनीकरण से क्षति हो रही है।
- (रर) प्रतिवादियों ने यह दावा किया है कि निकृष्ट निर्यात निष्पादन होने के कारण मेसर्ज सुराणा वेन्चर्स, मेसर्ज उधय एनर्जी फोटोवोल्टाइक्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्ज एक्सएल एनर्जी लिमिटेड बंद हो गई हैं क्योंकि वे एसईजेड यूनिट थीं। यह तर्क पूर्णतया निराधार है क्योंकि एसईजेड यूनिट पर निर्यात करने की कोई बाधयता नहीं है। बल्कि ये एसईजेड यूनिट, भारत में संबद्ध वस्तुओं की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए लाभ अर्जित करने में समर्थ रहे हैं।
- (लल) इसके अतिरिक्त प्रतिवादियों ने यह दावा किया है कि 260 वाट की चरम सीमा से 330 वाट की चरम सीमा तक के मॉड्यूल की कार्य-क्षमता में वृद्धि होने, सृजन होने और पोलिसिलिकोन के लिए आपूर्ति श्रृंखला में बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ प्राप्त होने, बेफर्स और इनगोट्स का उत्पादन होने, प्रमुख मॉड्यूल आपूर्तिकर्ताओं के साथ एकीकृत विनिर्माण क्षमताओं और सीधे एकीकरण द्वारा किए गए उपयोग और समग्र विनिर्माण लागत को कम करने तथा पीईआरसी जैसी नई प्रक्रियाओं को शुरू करने से कार्यक्षमता को और बढ़ाया जा सकता है, जिसके कारण प्रति वाट कम कीमत प्राप्त की जा सकती है, आदि के कारण आयातों की कीमतों में कमी हुई है। यह नोट किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग पहले से इन उपायों को क्रियान्वित कर रहा है और इसी कारणवश रक्षोपाय शुल्कों की मांग की गई है ताकि उनके क्रियान्वयन के समय घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जा सके।
- (वव) प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया है कि वर्ष 2017-18 में घरेलू उद्योग के लाभ/क्षति में सुधार हुआ है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर प्रतिवादियों ने घरेलू उद्योग की क्षतियों में वृद्धि को अन्यथा लाभप्रदता में वृद्धि होने जैसा गलत समझा है क्योंकि रिकार्ड से यह स्पष्ट पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की क्षतियां चौगुणा हो गई हैं।

- (शश) प्रतिवादियों ने याचिकादाताओं द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्टों में उल्लिखित कुछ प्रकथनों पर विश्वास किया है, जिनमें ऐसा उल्लेख किया गया है कि वैश्विक बाजार में मंदी है। तथापि, उक्त प्रेक्षणों को परिप्रेक्ष्य से बाहर लिया गया है क्योंकि उल्लिखित किसी भी प्रकथन में ऐसा निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि याचिकादाताओं को हुई क्षतियां, संबद्ध वस्तुओं के निर्यात करने में उनके समर्थ नहीं होने के कारण हुई हैं। वास्तव में याचिकादाताओं की वार्षिक रिपोर्टों से उद्धृत विवरणों की बारीकी से संवीक्षा करने से पता चलता है कि वे भारत में घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए तैयार हो रहे थे। तथापि, सस्ते आयातों के अंतरप्रवाह के कारण घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं को बेचने में असमर्थ रहा है अथवा उन्हें मात्र अलाभप्रद कीमतों पर बेचने में समर्थ रहा है।
- (सस) कुछ प्रतिवादियों ने यह दावा किया है कि सस्ते कच्चे माल, निर्यातक देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा पश्चगामी एकीकरण, इन उत्पादकों द्वारा अपनाई जा रही पीईआरसी जैसी उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों, परिवर्तन की निम्नतर लागत आदि के कारण अधिक प्रतस्पर्धी कीमतों पर आयात होते हैं। इस संबंध में यह नोट करना प्रासंगिक है कि घरेलू उद्योग की समायोजन योजना भी उपरोक्त उपायों के क्रियान्वयन पर आधारित है। इसलिए प्रतिवादी अब ऐसा तर्क नहीं दे सकते हैं कि घरेलू उद्योग की समायोजन योजना, उसे आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता देने में पर्याप्त नहीं है।
- (हह) जनहित का मूल्यांकन करने में मुख्यतया विभिन्न पक्षकारों के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन बनाए रखना निहित होता है, जो कि वर्तमान मामले में निम्नानुसार है:-
- (क) ऐसे सोलर सेल्स के घरेलू विनिर्माता (वर्तमान मामले में याचिकादाता), जिन्हें मॉड्यूल्स अथवा पेनलों में जोड़ा गया है अथवा नहीं।
- (ख) सोलर मॉड्यूल्स के ऐसे घरेलू विनिर्माता जो कि आयातित सोलर सेल्स पर विश्वास करते हैं।
- (ग) पॉवर डेवलेपर्स जिन्हें निम्नोक्त श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-
- (i) श्रेणी-1 : ऐसे पॉवर डेवलेपर्स जिन्होंने डिसकोम्स के साथ पीपीए किया है और जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद का पहले से आयात किया है।
 - (ii) श्रेणी-2 : ऐसे पॉवर डेवलेपर्स जिन्होंने डिसकोम्स के साथ पीपीए किया है लेकिन विचाराधीन उत्पाद का अभी तक आयात नहीं किया है।
 - (iii) श्रेणी-3 : ऐसे पॉवर डेवलेपर्स जो कि भावी परियोजनाओं के लिए बोली दे सकते हैं और जो विचाराधीन उत्पाद का आयात करने की आशा कर रहे हैं।
- (घ) विद्युत के उपभोक्ता।
- (क्षक्ष) भारत में जन हित के संबंध में विदेशी सरकारों और निर्यातकों की अदा करने की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि विदेशी सरकारें केवल विदेशी उत्पादकों के हितों को देखेंगी और वे विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करने में इच्छुक होंगी, ताकि उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो और प्रतिस्पर्धा के समस्त स्रोत समाप्त हो जाएं।
- (त्रत्र) सोलर सेल्स पर विश्वास रखने वाले सोलर मॉड्यूल विनिर्माताओं, श्रेणी 2 के पॉवर डेवलेपर्स और विद्युत उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत घरेलू उद्योग के हितों को महत्व दिया जाना चाहिए। यह निवेदन किया जाता है कि चूंकि आयात पहले से पूरे हो चुके हैं, इसलिए रक्षोपाय शुल्क लागू करने से श्रेणी 3 के पॉवर डेवलेपर्स अप्रभावित होंगे। इसी प्रकार श्रेणी 3 के पॉवर डेवलेपर्स बड़ी हुई आयात कीमत (रक्षोपाय शुल्क लागू करने के परिणाम स्वरूप) को अपने टैरिफ उद्धरणों में शामिल कर लेंगे अथवा संभवतः अर्थक्षमता अंतर निधियन प्राप्त करने लगेंगे। प्रभावित होने वाले पक्षकार अत्यधिक संकुचित श्रेणी 2 के ऐसे पॉवर डेवलेपर्स होंगे, जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद की प्रचलित आयात कीमतों के आधार पर टैरिफ उद्धृत किया है, लेकिन जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद का अभी आयात करना है। यहां तक कि श्रेणी 2 के ऐसे पॉवर डेवलेपर्स के लिए जिन्हें नव और नवीकरण योग्य मंत्रालय (एमएनआरई) ने पहले से पास-श्रु सुविधा अर्थात् शुल्क को लागू करने की व्यवस्था अधिसूचित कर दी है, उन्हें चेंज-इन-लॉ के अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और डेवलेपर्स द्वारा शुल्क के प्रभाव को डिसकोम को अंतरित कर दिया जाएगा। इसलिए यह विनम्र निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार ने अत्यधिक संकुचित श्रेणी के ऐसे पॉवर डेवलेपर्स के हितों के संतुलन के लिए पहले से कदम उठाए हैं, जो कि रक्षोपाय शुल्क को लागू करने से वास्तविक रूप से प्रभावित होंगे।

- (जज) केवल ऐसे आर्थिक कार्यकर्ता, जिनके हित विपम हैं, याचिकादाता, आयातित सोलर सेल्स पर विश्वास करने वाले मॉड्यूल्स के उत्पादक और विद्युत उपभोक्ता हैं।
- (श्रथ) जहां तक विद्युत उपभोक्ताओं का संबंध है, उनका हित संभावित सस्ती दर पर विद्युत प्राप्त करना होता है। जबकि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि विद्युत की कीमत में वृद्धि को केवल सोलर इलेक्ट्रीसिटी के लिए परिकलित किया जाना चाहिए, लेकिन उनका यह तर्क गलत है क्योंकि अंततः विद्युत उपभोक्ता विद्युत प्राप्त नहीं करते हैं, जिसे मूल स्रोत के आधार पर अभिज्ञात किया जा सकता है। राज्य विद्युत वितरण कंपनियां विभिन्न स्रोतों से विद्युत प्राप्त करती हैं और ऐसी विद्युत की आपूर्ति विभिन्न उपभोक्ताओं को की जाती है। इसलिए रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव का मूल्यांकन समग्र विद्युत सांचे के लिए किया जाना चाहिए जिसमें समस्त विभिन्न स्रोतों से उत्पादित विद्युत शामिल है।
- (ककक) जबकि अधिकतर हितबद्ध पक्षकारों ने सोलर टैरिफ के संबंध में केवल दृढकथन किए हैं, एसीएमई द्वारा प्रस्तुत अनुमानों की अनदेखी की जानी चाहिए क्योंकि एसीएमई ने मॉड्यूल की कीमत अमरीकी डालर 0.31/डब्ल्यूपी मानी है, जबकि चीन से उद्धृत कीमतें, पहले से अमरीकी डालर 0.27/डब्ल्यूपी हैं। जबकि एसीएमई ने आयातों पर रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव पर विचार किया है, एसीएमई ने अर्थक्षमता अंतर निधियन (बीजीएफ) के लिए प्रावधान नहीं किया है, जिसे नव और नवीकरण योग्य ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त एसीएमई ने समग्र भारतीय मांग पर रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव पर विचार किया है, जबकि भारतीय सेल्स (लगभग 25%) से विनिर्मित भारतीय मॉड्यूल्स पर यह प्रभाव सीमित रहेगा। अधिशेष मांग के लिए ऐसे प्रभाव को संग्रहीत रक्षोपाय शुल्क से डेवलपर्स को प्रदत्त पीजीएफ द्वारा दूर कर दिया जाएगा।
- (खखख) भारत में सफेद/पीले रंग के फॉसफोरस के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच के अंतिम जांच परिणाम पर विश्वास करते हुए कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि मांग और पूर्ति के बीच अंतर होने के कारण रक्षोपाय शुल्क लागू करना जन हित के खिलाफ होगा। तथापि, मांग और पूर्ति के बीच अंतर अनेक कारकों में से एक ऐसा कारक है जिसे माननीय महानिदेशक, रक्षोपाय ने उक्त जांच पर विचार किया था। बल्कि माननीय महानिदेशक, रक्षोपाय ने ऐसे अन्य मामलों में रक्षोपाय शुल्क लागू करने की सिफारिश की थी, जिनमें घरेलू उद्योग की क्षमता मांग से कमतर थी, जैसे कि इंडस्ट्रियल सिलाई मशीनों की सुईयों के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच, ओक्सो अल्कोहल्स के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच और सोडियम नाइट्रेट के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच आदि।
- (गगग) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आयातों के लिए विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमान भ्रामक हैं। पक्षकारों ने परिकलन का विरोध नहीं किया है, बल्कि यह तर्क मात्र दिया है कि कच्चे माल के आयातों के कारण विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन होगा। जैसा की सत्यापन के दौरान प्रदर्शित किया गया है, याचिकादाता पश्चगामी जांच के लिए प्रयास कर रहे हैं। सोलर ग्लास, आईवीए शीट, बैक शीट आदि वस्तुओं के कुछ प्रमुख विनिर्माताओं ने भारत में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पहले से अत्यधिक निवेश किया है। इसलिए पश्चगामी एकीकरण के साथ-साथ परिकल्पित प्रतिलाभ से भारत में घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और भारत से विदेशी मुद्रा का अत्यधिक बहिर्गमन रुकेगा।
- (घघघ) प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया है कि डीसीआर के प्रभावी होने पर भी पश्चगामी एकीकरण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। ऐसे निवेदन सत्य से परे हैं क्योंकि विद्वान महानिदेशक, रक्षोपाय ने सत्यापन के दौरान पहले से प्रमाणित किया है कि भारत में ईवीए और बैक शीट के लिए कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के दो संयंत्र देश में सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स के बड़े उत्पादक के निकटस्थ पहले से प्रचालन कर रहे हैं।
- (ङङङ) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि रक्षोपाय शुल्क लागू किए जाने के फलस्वरूप सोलर पावर की लागत में 3 रुपए/यूनिट तक बढ़ जाएगी। तथापि, एक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में गुमनाम विशेषज्ञों के बयानों पर किसी वास्तविक आधार के बिना अथवा ऐसे निराधार आरोपों का खंडन करने के लिए घरेलू उद्योग को अवसर प्रदान किए बिना विश्वास नहीं किया जा सकता है।
- (चचच) हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि रक्षोपाय शुल्क लागू किए जाने से सोलर पावर के 100 गीगा वाट के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा आएगी। यह देखा जा सकता है कि ऐसे लक्ष्य की घोषणा वर्ष 2015 के प्रारंभ में की गई थी, जब आयातित सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स की कीमतें, वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान प्रचलित कीमतों की तुलना में बहुत अधिक थीं। इसलिए यदि वे कीमतें 100 गीगा वाट के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा नहीं थीं, तो रक्षोपाय शुल्क लागू करने के बाद वर्तमान कीमतों को सोलर पावर के 100 गीगा वाट की स्थापना के लिए एक बाधा नहीं माना जा सकता है।
- (छछछ) महानिदेशक, रक्षोपाय के लिए केवल यही आवश्यकता है कि गंभीर क्षति की रोकथाम, गंभीर क्षति के उपाय और समंजन को सुकर बनाने के तीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यथावश्यक उपाय लागू किए जाएं। गंभीर क्षति की रोकथाम अथवा उपाय करने के

लिए यथावश्यक मापदंड लागू किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में उन्हें समंजन को सुकर बनाना होगा। केवल यही नहीं, गंभीर क्षति की रोकथाम अथवा उपाय करने के लिए जरूरी रक्षोपाय शुल्क की मात्रा के संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं है। इसके अतिरिक्त, समंजन को सुकर बनाने के लिए भी जरूरी उपाय करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई दिशानिर्देश नहीं है।

(जजज) यह नोट किया जाना चाहिए कि अन्य व्यापारिक उपचारी तंत्रों में समंजन को सुकर बनाने की आवश्यकता उपलब्ध नहीं है, जैसे कि पाटन-रोधी और प्रतिकारी शुल्क। विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी करार में दो प्रावधान हैं - पहला प्रावधान क्षति का निदान करना और दूसरा प्रावधान शुल्क की सीमा अथवा उच्चतम सीमा का निर्धारण करना। जबकि उद्देश्य यह है कि जिस पाटन के कारण क्षति हो रही है, उसकी रोकथाम करने के लिए यथावश्यक शुल्कों को किया जाए और उच्चतम सीमा का निर्धारण किया जाए ताकि शुल्क, पाटन मार्जिन से अधिक नहीं हो। इसी प्रकार की स्थिति प्रतिकारी शुल्कों की भी है। तथापि, रक्षोपाय करार में ऐसी कोई भी उच्चतम सीमा का प्रावधान निहित नहीं है। पाटन-रोधी शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क उपायों की तुलना में रक्षोपाय उपायों से संबंधित कानूनी प्रावधानों में व्याप्त अंतर को ध्यान में रखते हुए ऐसे शुल्क की राशि का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ जो कि रक्षोपाय के मामले में लागू किया जा सकता है, पाटन-रोधी अथवा प्रतिकारी शुल्क की विधियों में अनुसरण किए जा रहे सिद्धांतों को लागू करना उचित नहीं है।

(झझझ) भारत ने पाटन-रोधी विधि में क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने से संबंधित नियम निर्धारित किया है। विधि में प्राधिकारी से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वे प्रचालन की सामान्य दशाओं में कच्चे माल और प्रयोज्यताओं आदि की कुछ लागतों को सामान्य बना कर और साथ ही फेक्टरी गेट के बाद किए गए व्ययों, जैसे कि कमीशन, गोदामों के व्यय, निकुष्ट ऋण आदि को मान्यता नहीं देते हुए लागतों का निर्धारण करेंगे और साथ ही उन्हें वास्तविक व्याज के बजाय नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के उचित दर को जोड़ना आवश्यक होगा। यह नोट किया जाना चाहिए कि रक्षोपाय विधि ऐसा आपात स्थिति का निदान करती है जिसमें आपात उपाय करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में लागू किए जाने वाले ऐसे शुल्क की मात्रा का निर्धारण करने में सामान्यकरण सिद्धांतों को लागू करना अभिशाप होगा।

(जजज) क्षति रहित कीमत मॉडल तीसरी आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, जो कि समंजन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक संघटक है। जब तक यह विचार करने के लिए कि समंजन को सुकर बनाने के लिए क्या आवश्यक है, कोई प्रावधान नहीं बनाया जाता है, तब तक रक्षोपाय शुल्क की मात्रा का निर्धारण करने के लिए क्षति रहित विधि का अनुसरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुल्क की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी वैकल्पिक विधि का पता लगाया जाए। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य अनुच्छेद 5.1 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से उचित किसी भी कार्य-प्रणाली को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय विधि में भी कोई दिशा-निर्देश नहीं है। इस संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और यूरोपीय यूनियन में अपनाई जा रही कार्य-प्रणाली पर विचार किया जा सकता है।

(टटट) यह तर्क कि पाटन मार्जिन और/अथवा क्षति मार्जिन के कारण घरेलू उद्योग जांच से पीछे हट गया है, न केवल किसी तथ्य से परे और निराधार है, बल्कि यह पूर्णतया अनुमान और परिकल्पना मात्र है। घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय शुल्क लागू करने के लिए आवश्यक सभी संघटकों नामतः (1) अप्रत्याशित घटना, (2) गॉट के अंतर्गत निर्वहन दायित्वों के प्रभाव, (3) आयातों में अचानक उछाल, (4) गंभीर क्षति, (5) बड़े हुए आयातों और गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, (6) आधार और (7) जन हित को प्रमाणित किया है।

(2) ताईवान फोटोबोलटाईक इंडस्ट्री एसोसिएशन

(क) घरेलू उद्योग धारा 8 ख (6) (ख) की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है क्योंकि उसका उत्पादन प्रमुख भाग नहीं बनता है। एमएनआरई के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 20 सोलर सेल विनिर्माता और 17 सोलर मॉड्यूल विनिर्माता हैं। तदनुसार, 31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, भारत में स्थापित कुल क्षमता का 26.41 प्रतिशत है।

(ख) घरेलू उद्योग के निवेदनों में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में उसके आधार का निर्धारण करने के लिए भारत में सोलर मॉड्यूल की विनिर्माण क्षमता निहित नहीं है, हालांकि सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल दोनों को विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया गया है। इसलिए जानबूझ कर गलत परिकलन किए जाने के कारण जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(ग) एसईजेड यूनिटों को घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है। एसईजेड अधिनियम की धारा 51 का अन्य घरेलू विधान पर अभिभावी प्रभाव पड़ा है। एसईजेड अनिश्चित घरेलू बाजार से प्रतिरक्षित है।

(घ) एसईजेड निर्यात करने वाली कंपनियों को छूट देने की पेशकश करता है और प्रयोज्यताओं के पास एसईजेड में यूनिट स्थापित करने का विकल्प है। इस प्रकार एसईजेड में यूनिट स्थापित करने से इसकी संपुष्टि होती है कि एसईजेड यूनिटों ने निर्यात बाजार

- की आवश्यकताओं को पूरा करने का मुख्य संकल्प किया है और न कि डीटीए का। इसलिए एसईजेड यूनिटों को घरेलू उद्योग का दर्जा स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।
- (ड) घरेलू उद्योग का तर्क विरोधाभासी है क्योंकि एक तरफ वह घरेलू उद्योग के आधार का निर्धारण करने के लिए एसईजेड यूनिटों में शामिल होना चाहता है, तो दूसरी ओर वह एसईजेड यूनिटों पर रक्षोपाय शुल्क लागू करने से छूट चाहता है। मामले की विधि केवल यह स्थापित करती है कि डीटीए को एसईजेड में विनिर्मित वस्तुओं की क्लियरेंस का तात्पर्य आयात से नहीं है। धारा 8 ख (2 क) (2) में स्पष्ट प्रावधान है कि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाए। जैसा कि स्नेह इंटरप्राइज {2006 (202) ईएलटी 7 (एससी)} के मामले में निर्णय दिया गया है शुल्क लागू करने के प्रयोजनार्थ कड़े निर्वचन को लागू किया जाना चाहिए।
- (च) जैसा कि 21 जुलाई, 2017 को शुरू की गई पाटन-रोधी जांच से पता चलता है, जिसमें मुन्द्रा सोलर और हेलियोज फोटो वोल्टाईक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा गया है क्योंकि ये कंपनियां सोलर सेल का आयात करती हैं अथवा घरेलू उत्पादकों से खरीदती हैं, को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन उत्पाद की उत्पादक, मुन्द्रा सोलर और हेलियोज फोटो वोल्टाईक केवल आयातित सोलर सेल्स को मॉड्यूल्स में जोड़ने के कार्य में लगी हुई हैं।
- (छ) मुन्द्रा सोलर ने 2400 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ मई, 2017 में प्रचालन करना शुरू किया है। उसकी इस संस्थापित क्षमता को शामिल किए बिना घरेलू उद्योग का आधार मात्र 5.3 प्रतिशत होगा और शेष आवेदक घरेलू उद्योग के आधार के योग्य नहीं होंगे। इसलिए केवल इस आधार पर वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- (ज) घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के आयातों के मूल्य में वृद्धि होने के रूप में गलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में आयातों में वृद्धि 15 प्रतिशत हुई है, जिसे विगत वर्षों में हुई वृद्धि की तुलना में तेज, अचानक और अत्यधिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता है।
- (झ) घरेलू उद्योग ने अप्रत्याशित घटनाओं के रूप में विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख किया है। टीपीवीआईए ने इसका घोर खंडन करते हुए उल्लेख किया है कि गॉट के दायित्वों का निर्वहन करने के समय ये परिस्थितियां अप्रत्याशित नहीं थीं और घरेलू उद्योग ने ऐसे निवेदनों के लिए कोई विश्वसनीय तथ्य परक साक्ष्य अथवा कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं किया है कि ये घटनाएं अप्रत्याशित थीं।
- (ञ) घरेलू उद्योग ने जिन आंकड़ों पर विश्वास किया है, उनसे यह पता चलता है कि चीन जनवादी गणराज्य की क्षमता निर्यातोन्मुख नहीं है क्योंकि सोलर सेल्स की उसकी घरेलू खपत निर्यातों से अधिक है।
- (ट) हालांकि वर्ष 2014 में घरेलू खपत की तुलना में सोलर मॉड्यूल के निर्यात अधिक थे, वर्ष 2016 में इस स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ जब घरेलू खपत अधिक थी। घरेलू उद्योग ने चीन के सोलर बाजार को बिल्कुल गलत समझा है और यह आरोप निराधार है कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की उसकी क्षमता निर्यातोन्मुख है।
- (ठ) घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया यह तर्क कि चीन के उत्पादकों को चीन की सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, आर्थिक सहायता जांच के लिए प्रासंगिक है, न कि रक्षोपाय जांच के लिए। घरेलू उद्योग के कारण और औचित्य, आर्थिक सहायता विद्यमान होने को प्रमाणित करने के आधार हैं और न कि अप्रत्याशित घटनाओं के।
- (ड) अप्रत्याशिक घटनाओं की आवश्यकता को इन दशाओं से पूरा किया जा रहा है कि यह विश्व व्यापार संगठन के करार के अंतर्गत निभाए गए दायित्वों का प्रभाव है, ताकि बड़े हुए निर्यातों को प्रमाणित किया जा सके। ऐसी कोई भी कल्पना करने से सोलर क्षेत्र में चीन जनवादी गणराज्य की अर्थव्यवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत निर्वहन किए गए दायित्वों का प्रभाव है।
- (ढ) मांग बढ़ने से और घरेलू उद्योग की अक्षमता से केवल चीन जनवादी गणराज्य से नहीं बल्कि अन्य देशों से भी आयातों में वृद्धि हुई है। तथापि, अन्य देशों से आयातों में वृद्धि होने के बारे में घरेलू उद्योग के निवेदनों में लेश मात्र भी उल्लेख नहीं है। जब किसी एक विशिष्ट देश के कारण क्षति होती है, तब वैश्विक रक्षोपाय नहीं किए जा सकते हैं। रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य आयातों से आपातकालीन सुरक्षा प्रदान करना है और सिद्धांततः इससे किसी विशिष्ट देश से आयातों को लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता है।
- (ण) इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि डीसीआर की आवश्यकता सदैव विश्व व्यापार संगठन के दायित्व का निर्वहन नहीं करने के जोखिम पर है और भारत सरकार घरेलू विनिर्माताओं को संरक्षण करने का प्रयास कर रही है।
- (त) घरेलू उद्योग का यह तर्क गलत है कि व्यापार पेटर्न में परिवर्तन डीसीआर को हटाने के अनुसरण में था क्योंकि डीसीआर ने भारत में उत्पादन की कम मात्रा को प्रभावित किया था, जैसा कि *सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स से संबंधित कुछ उपाय - डब्ल्यूटी/डीएस 456/आर को देखें - भारत में पेनल द्वारा नोट किया गया है।* डीसीआर के होते हुए भी आयात अधिक थे।

- (थ) अप्रत्याशित घटना का निर्धारण करने का मानक यह नहीं है कि "वार्ताकारों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, लेकिन यह है कि वे मस्तिष्क में क्या विचार कर सकते हैं, जैसा कि कुछ स्टील उत्पादकों के आयातों पर सुनिश्चित रक्षोपाय - डब्ल्यूटी/डीएस 248, 249, 251, 252, 253, 254, 258, 259/एबी/आर को देखें - संयुक्त राज्य अमरीका में पैनल" ने पाया है। पेरिस करार यूएनएफसीसीसी के भीतर एक ऐसा करार है, जो कि वर्ष 1994 में लागू हुआ था और इस प्रकार इसे अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने और विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच वैश्विक तपन का निदान करना के लिए दो दशकों के प्रयासों की पराकाष्ठा है।
- (द) आईटीए:1 की प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा आईटीए -1 के अंतर्गत छूट देने के समय इसे नहीं देखा गया था कि वैश्विक आधार पर आसूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सतत प्रौद्योगिकीय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं। एक दायित्व को पूरा करने के समय सरकार द्वारा और न कि घरेलू उद्योग द्वारा परिस्थितियों अप्रत्याशित होती हैं, जैसा कि डोमिनिकन गणराज्य -पोलीप्रापलीन बैग्स (डब्ल्यूटी/डीएस 177, 178/एबी/आर) में पैनल ने निर्णय लिया है।
- (ध) घरेलू उद्योग वस्तुतः यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि आईटीए-1 के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के आयात कैसे निशुल्क हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप केवल जांच अवधि के दौरान अप्रत्याशित घटनाएं बड़ी हैं, जब भारत ने वर्ष 1997 में आईटीए-1 पर हस्ताक्षर किए थे और वर्ष 2000 तक टैरिफ समाप्त कर दिए गए थे।
- (न) यदि पाटन-रोधी जांच में क्षति का विश्लेषण, क्षति को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, तब यह रक्षोपाय जांच में गंभीर क्षति को दर्शाने की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि "गंभीर" शब्दांश, "वास्तविक" शब्दांश की तुलना में क्षति के अत्यधिक उच्चतर मानक का संकेत देता है, जैसा कि अपील निकाय द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका-लैम्ब (डब्ल्यूटी/डीएस 177, 178/एबी/आर) के मामले में पाया गया है।
- (फ) मरकोम 2017-क्यू 4 और एनवल इंडिय सोलर मार्किट अपडेट के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य से आयातित मॉड्यूल्स की औसत बिक्री कीमत में 2017-क्यू-3 से 2017 क्यू-4 में 23.45/डब्ल्यू तक की वृद्धि हुई है। मॉड्यूल्स की कीमत में 4 प्रतिशत तक की वृद्धि से घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत क्षति की छवि दूषित प्रतीत होती है।
- (ब) घरेलू उद्योग आयातों और गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों को दर्शाने में विफल रहा है। वह क्षति के लिए अन्य स्रोतों से जिम्मेदार कारणों को समझने में विफल रहा है, जैसे कि अकुशलता, घरेलू उत्पादकों की अक्षमता, घरेलू रूप से विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद की निकृष्ट गुणवत्ता, मुन्द्रा सोलर द्वारा केवल मई, 2017 में उत्पादन शुरू करना, सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के कारण मांग बढ़ना, विश्वभर में भारत को सबसे बड़ा हरित ऊर्जा उत्पादक बनाना, भारत में विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण क्षमता निर्मित करने के लिए विभिन्न योजनाओं द्वारा सरकारी सहायता प्रदान करना, जैसे केन्द्रीय लोक क्षेत्र के उपक्रमोंकी योजना, पूंजीगत माल के आयातों पर सीमा-शुल्क से छूट के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देना, सोलर क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) का सृजन आदि, सोलर फोटोवोल्टिक्स प्रणालियों के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद का अनिवार्य पंजीकरण, विकास और संघटक वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2017 और सोलर उद्योग की पूंजी और प्रौद्योगिकी की गहन प्रकृति।
- (भ) घरेलू उद्योग ने विनम्रता से यह निवेदन किया है कि 70 प्रतिशत सम मूल्य का प्रभार होने पर भी पाँवर टैरिफ में वृद्धि नगण्य होगी। श्री सुबोध राय, वरिष्ठ निदेशक, क्रिसिल रेटिंग के अनुसार रक्षोपाय शुल्क लागू करने से परियोजना की लागत में 25% तक की वृद्धि होगी और अर्थक्षम टैरिफ में वृद्धि, लगभग <3 प्रति यूनिट से <3.75 प्रति यूनिट होगी, जो कि सोलर पाँवर को डिस्कोम्स के लिए कम आकर्षक बनाएगी।
- (म) रक्षोपाय शुल्क लागू करने से अंततः अंत-उपभोक्ता पर भार पड़ेगा।
- (य) घरेलू उद्योग का ऐसा दृढकथन निराधार है कि यदि रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो विदेशी विनिर्माताओं द्वारा घोषित क्षमता संवर्धन कभी भी नहीं होगा क्योंकि कंपनियों ने पहले से निवेश योजनाएं शुरू कर दी हैं, जो कि घरेलू उत्पादकों को आर्थिक बचत प्राप्त करने में सहायक होंगी। घरेलू उद्योग का उद्देश्य अपने प्रचालनों के लिए सभी स्रोतों से निवेश और ऋण प्राप्त करके और अक्षमताओं को छिपाने के लिए सरकार से संरक्षण के आवरण में अन्य सहायता प्राप्त करके दोहरा संरक्षण प्राप्त करना है।

(र) रक्षोपाय शुल्क को प्रस्ताव केवल बढे हुए आयातों के कारण होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए किया जाना चाहिए और न कि अन्य कारणों के लिए जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका - कोरिया से सुनिश्चित सर्कुलर बेलिडड कार्बन क्वालिटी लाईन पाईप के आयातों (डब्ल्यूटी/डीएस 2028/एबी/आर) के मामले में अपील निकाय ने रिपोर्ट में निर्णय दिया है।

(3) मेसर्स फस्ट सोलर इंक, संयुक्त राज्य अमरीका, मेसर्स फस्ट सोलर एफई होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड और मेसर्स फस्ट सोलर मलेशिया एसडीएन, बीएचडी

(क) घरेलू उद्योग से संबंधित अधिकतर क्षति प्राचल सुधार दर्शा रहे हैं। विगत रक्षोपाय जांच के विश्लेषण ने दर्शाया है कि गंभीर क्षति की मौजूदगी तभी प्रमाणित होती है, जब अधिकतर प्राचल गिरावट दर्शाते हैं। नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी को इसकी जांच करनी अपेक्षित होती है कि क्या घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हो रहा है, महानिदेशक, रक्षोपाय को यह निर्णय देना चाहिए कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति नहीं हुई है।

(ख) उत्पादन, बिक्रियां, क्षमता उपयोग, घाटे, बाजार का हिस्सा, निवेश पर प्रतिलाभ आदि जैसे प्राचलों में सुधार हुआ है। क्षमता उपयोग, लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ जैसे प्राचलों में किसी भी प्रकार की गिरावट आना, मुन्द्रा सोलर द्वारा क्षमता का 653 मेगावाट से 1000 मेगावाट तक अत्यधिक संवर्धन करने का परिणाम है। मुन्द्रा सोलर के कारण घरेलू उद्योग की क्षतियां बड़ी हैं। यदि इसको शामिल नहीं किया जाता है, तो घरेलू उद्योग को हुई क्षतियों में अत्यधिक कमी होगी।

(ग) याचिकादाताओं ने विभिन्न स्थानों पर प्रारंभिक जांच परिणामों पर विश्वास किया है। तथापि, ऐसा विश्वास करना अत्यधिक गलत है क्योंकि जांच परिणाम हितबद्ध पक्षकारों के मतों पर विचार किए बिना दिए गए थे और ये मुख्यतया याचिकादाताओं के दावों पर आधारित थे। इसलिए अपने निवेदनों के समर्थन में किसी भी प्रारंभिक जांच परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

(घ) याचिकादाता विभिन्न प्रोद्योगिकी को प्रयुक्त करके ई-सी और थिन-फिल्म को इकट्ठा कर उन्हें संसाधित करके उन्हें समान उत्पाद प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। तथापि, यहां उत्पाद न केवल कच्चे माल की किस्म और प्रयुक्त प्रोद्योगिकी, बल्कि उत्पाद की वास्तविक और तकनीकी गुणक्षमताओं में भिन्न है।

(ङ) दो उत्पादों के बीच अंतरभूत भिन्नता होने के साथ-साथ दोनों के लिए अपेक्षित विभिन्न वीओएस के संबंध में प्रतिवादियों के निवेदनों के आलोक में ई-सी फोटोवोल्टाईक और थिन फिल्म उत्पाद परस्पर रूप से परिवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन ये वैकल्पिक उत्पाद हैं।

(च) अंत उत्पाद प्रतिस्थापनीय क्षमता यह निर्णय देने के लिए कभी भी मानदंड नहीं हो सकती है कि उत्पाद स्वतः प्रतिस्थापनीय हैं। याचिकादाता दो भिन्न वस्तुओं को इस आधार पर विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं कर सकते हैं, कि इन दो भिन्न वस्तुओं से उत्पादित उत्पाद परस्पर रूप से परिवर्तनीय हैं और एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी हैं।

(छ) याचिकादाताओं ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके द्वारा उत्पादित ई-सी उत्पाद कैसे सीधे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। याचिकादाताओं द्वारा दिए गए ये तर्क पूर्णतया निराधार हैं याचिकादाताओं द्वारा उत्पादित उत्पाद, थिन फिल्म उत्पादों के समान नहीं है अथवा उनसे सीधे प्रतिस्पर्धी नहीं हैं और तदनुसार परवर्ती उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

(ज) याचिकादाताओं द्वारा प्राधिकारी के विगत जांच परिणाम पर विश्वास करना अनुचित है। चूंकि शुल्क स्वतः लागू नहीं हुआ था, प्रतिवादी निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय और विगत आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के अवसर का कभी भी लाभ नहीं उठा सकते थे। विगत जांच परिणाम भी अंतिम नहीं हैं और इसलिए उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।

(झ) इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि सी-एसई फोटोवोल्टाईक और थिन फिल्म उत्पाद समान वस्तुएं हैं, प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त तथ्यों पर विश्वास किया है:-

- (1) थिन फिल्म के आयात, संबद्ध देशों से कुल आयातों का 25% थे।
- (2) उत्पादों की प्रति वॉट कीमत के बीच बहुत कम अंतर था, जो कि दो उत्पादों के बीच 5% से कम है।
- (3) लागत/कीमत निर्धारण और प्रतिस्पर्धा (बाजार की भाषा शैली में) का निर्णय भी वाट प्रति यूनिट, दोनों प्रोद्योगिकियों के अंतर्गत सेल्स/मॉड्यूल्स की कार्यक्षमता जैसे कारकों के आधार पर लिया जाता है।

(ज) तथापि, उपरोक्त कारकों के संबंध में थिन फिल्म उत्पादों की तुलना में ई-सी उत्पादों की स्थिति में नाटकीय परिवर्तन हुआ है, जो इस प्रकार है:-

- (1) याचिकादाताओं द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार थिन फिल्म के आयात, भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों का केवल 0.15% है।
- (2) इसके अतिरिक्त दोनों उत्पादों के बीच कीमत अंतर नगण्य नहीं है, जैसा कि पहले मामले में नोट किया गया था, बल्कि थिन फिल्म और सी-एसई उत्पादों की कीमत में यह अंतर 15% है।
- (3) जबकि काफी समय से थिन फिल्म उत्पाद की प्रति वॉट कीमत बढ़ रही है, फिर भी सी-एसई उत्पादों की कीमत में गिरावट आ रही है।

इसलिए यह स्पष्ट है कि यहां तक कीमतों का संबंध हैं, बाजार में ये दोनों उत्पाद एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं।

- (ट) याचिकादाताओं ने दावा किया है कि सोलर सेल्स के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय यूनियन के जांच परिणामों के बजाए कनाडा के प्राधिकारियों के रक्षोपाय जांच परिणाम पर विश्वास किया जाना चाहिए, जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर नहीं आने वाले दोनों उत्पादों पर विचार किया है, जिसके लिए उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है। फिर भी यदि ऐसे जांच परिणाम का हवाला दिया जाता है, तो रक्षोपाय जांच परिणामों में यूएसटीआईसी के जांच परिणाम, वर्तमान मामले में अधिक प्रासंगिक हैं।
- (ठ) यदि संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय यूनियन के प्राधिकारियों ने सी-एसई और थिन फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया है, तो उससे यह पता चलता है कि इसका अत्यधिक औचित्य है कि वर्तमान मामले में भी इन दोनों उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के समान दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- (ड) याचिकादाताओं द्वारा कुछ जांच परिणामों पर खंडशः विश्वास स्वीकृत नहीं किया जा सकता है और स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। याचिकादाता ऐसे एक तथ्य का उल्लेख करने में विफल रहे हैं, जो थिन फिल्म उत्पादों के मुद्दे पर यूएसआईटीसी के जांच परिणाम को विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट और उनके बहिष्करण को यथोचित ठहराया जा सके।
- (ढ) जब याचिकादाताओं ने स्वयं स्वीकार कर लिया है और सेल्स और मॉड्यूल को शामिल करने के मुद्दे पर यूएसआईटीसी के जांच परिणाम पर विश्वास किया है, तब वे ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं कि थिन फिल्म उत्पादों को शामिल करने के मुद्दे पर जांच परिणाम का अनुसरण नहीं किया जाए।
- (ण) याचिकादाताओं द्वारा आवेदन-पत्र में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की तुलना में प्रारंभिक जांच परिणाम के आंकड़ों और लिखित निवेदनों में परिवर्तन हुआ है। प्रारंभिक जांच परिणाम अथवा लिखित निवेदनों में ऐसे परिवर्तन के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
- (त) प्राधिकारी के विगत जांच परिणामों के आलोक में एसईजेड यूनियों के घरेलू उद्योग का भाग नहीं होने के मुद्दे को अंतिम रूप दिया गया है और याचिकादाताओं द्वारा इसका खंडन नहीं किया जा सकता है।
- (थ) रक्षोपाय शुल्क तभी लागू होता है, जब तैयार उत्पादों को निर्मित करने के लिए प्रयुक्त इनपुट पर रक्षोपाय शुल्क लगा हो और यह स्पष्ट करता है कि डीटीए पर शुल्क लगा था, इसलिए यह मुद्दा यह निर्धारित करने के लिए अप्रासंगिक है कि क्या एसईजेड यूनियों को घरेलू उद्योग का भाग माना जाए अथवा नहीं।
- (द) वर्ष 2016 में अप्रत्याशित घटनाएं घटित हुई हैं और आयातों में वृद्धि का मूल्यांकन उसके बाद की अवधि के लिए किया जाना चाहिए और न कि उससे पहले की अवधि के लिए। वर्ष 2014-15 की बजाए वर्ष 2015-16 में तुलना करने पर आयातों में केवल 123% की वृद्धि हुई है, जबकि इस अवधि के दौरान मांग में 133% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार मांग में वृद्धि होने के फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है।
- (ध) जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि उत्पादन के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है, ऐसा इस तथ्य के कारण हुआ है कि आयातों में गिरावट आने के कारण उत्पादन निरूद्ध हुआ है।
- (न) आयातों की मात्रा और मूल्य में वृद्धि होने के याचिकादाताओं के तर्क भ्रामक हैं क्योंकि ये उक्त गिरावट के लिए अन्य कारणों को पृथक् करने में कीमतों में गिरावट की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो कि प्रतिवादियों के विस्तृत निवेदनों का भाग हैं।

- (फ) डीसीआर को समाप्त कर दिए जाने के बाद आयातों में वृद्धि हुई है। ऐसी घटना जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है, विश्व व्यापार संगठन के अपील निकाय के निर्णय के अनुसरण में डीसीआर को हटाया जाना था, न कि यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा शुल्क लागू किया जाना था।
- (ब) गॉट के अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन से डीसीआर की असंगतता एक अप्रत्याशित घटना नहीं है क्योंकि डीसीआर तब अस्तित्व में नहीं था, जब दायित्वों को निभाया गया था और उन्हें हाल ही में शुरू किया गया था।
- (भ) याचिकादाता ऐसी किसी भी घटना का उल्लेख करने में विफल रहे हैं, जिससे आयातों में वृद्धि हुई हो, बल्कि दायित्वों को निभाया गया था और जिन्हें हाल ही में शुरू किया गया था और उस समय डीसीआर अस्तित्व में नहीं था।
- (म) अप्रत्याशित घटना के याचिकादाताओं के दावे के संबंध में विधि में अप्रत्याशित घटनाओं और अज्ञात तथ्यों का होना अपेक्षित है। चीन में उत्पादकों द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ मात्र के कारण विश्वभर के सभी देशों पर शुल्क लागू नहीं किया जा सकता है।
- (य) ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकादाता यह विश्वास करते हैं कि जांच केवल चीन के खिलाफ होनी चाहिए क्योंकि उनके द्वारा उल्लिखित प्रत्येक अप्रत्याशित घटना पूर्णतया और विशेषतः चीन से संबंधित है। यह पूरी तरह से देखा गया था कि उद्योगों को विकसित करने के लिए उपाय किए जायेंगे, जिस कारण से सब्सिडी-रोधी करार किया गया था। यह उपयुक्त नहीं होगा कि संबद्ध वस्तुओं के सभी निर्यातकों पर शुल्क लगाया जाए और क्योंकि चीन में विकास हो रहा है, इसलिए आयातों की लागत को बढ़ाया जाए।
- (र) आयातों के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि उनमें मात्र 4% की वृद्धि हुई है। किसी भी परिस्थिति में इसे अचानक, तीव्र और अत्यधिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता है।
- (ल) निरंतर सकारात्मक कीमत कटौती होने के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि उनका याचिकादाताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि उनके उत्पादन, बिक्रियों, क्षमता उपयोग में न तो कोई गिरावट आई है और न ही कोई कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण हुआ है, लाभ में गिरावट आई है और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (मुन्द्रा सोलर के लिए आंकड़ों को छोड़ कर) में कमी हुई है।
- (व) थिन फिल्म उत्पादों के लिए कोई कीमत कटौती का प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे दुबारा यह सिद्ध होता है कि न तो सेल्स और न ही मॉड्यूल्स, ऐसे उत्पादों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
- (श) याचिकादाताओं की बिक्री कीमत में गिरावट, लागत में गिरावट में समनुरूप हुई है। यदि कच्चे माल की लागतों में गिरावट आई है और उत्पादन की कुल लागत में वृद्धि हुई है, तो यह इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि मुन्द्रा सोलर के क्षमता संवर्धन के कारण लागत में वृद्धि हुई है।
- (स) मुन्द्रा सोलर को बाहर रखने के बाद कंपनियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन परिस्थितियों में आयातों में कथित उछाल आने के कारण रोजगार में गिरावट आने का कोई प्रश्न नहीं उठ सकता है।
- (ह) रक्षोपाय नियमवाली के अंतर्गत निर्धारित प्राचलों के अनुसार याचिकादाताओं ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि उन्हें गंभीर क्षति हुई है। विश्व व्यापार संगठन-एबी रिपोर्ट द्वारा डीसीआर को हटाने के कारण हुई क्षति के तर्क, मेरिट के आधार पर कोई मामला नहीं होने पर सहानुभूति प्राप्त करने का एक प्रयास मात्र है।
- (क्ष) किसी भी नए संयंत्र के पूर्णतया प्रचालनात्मक बनने में कुछ समय लगता है और प्रारंभिक अवधि में क्षमता उपयोग सदैव कम होता है। इसलिए एमएसपीवीएल द्वारा प्रवेश किए जाने पर संस्थापित क्षमता को बढ़ा कर 1000 मेगावाट कर दिए जाने के बाद भी 365 मेगावाट पर प्राप्त किया गया उत्पादन वास्तव में कम है। उत्पादन के निम्न स्तर भी याचिकादाताओं के बिक्री निष्पादन के लिए जिम्मेदार है।
- (त्र) याचिकादाताओं की असमर्थता का ऐसा दावा, यदि कोई है, कि जितना वे उत्पादन करते हैं, उतनी बिक्री केवल उनके निकृष्ट निर्यात निष्पादन के कारण होनी चाहिए चूंकि अवधि के दौरान बिक्रियों में चौगुणा वृद्धि हुई है।
- (ज) उत्पादों की लागत की तुलना में उनकी कीमतें कम होने के कारण बिक्रियों के बढ़ने के कारण घाटों में वृद्धि के संबंध में याचिकादाताओं के निवेदनों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि याचिकादाताओं के प्रति यूनिट घाटे में वास्तव में गिरावट आई। यदि घाटे बढे हैं तो उनका कारण मुन्द्रा सोलर की ऊपरी लागतें हैं।
- (श्र) यह स्वीकार्य तथ्य है कि याचिकादाताओं की बिक्रियां बढ़ी हैं और उनमें कोई गिरावट नहीं आई है। नियमावली में प्राधिकारी से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वे गंभीर क्षति और विभिन्न आर्थिक प्राचलों में संभावित अत्यधिक गिरावट की जांच करेंगे।

प्राधिकारी यह नहीं मान सकते हैं कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है क्योंकि कुछ प्राचलों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है, जितनी बड़े हुए आयातों की अनुपस्थिति में हो सकती थी।

- (कक) एमएसपीवीएल के संवर्धन के बावजूद आयातों में वृद्धि को प्रति कर्मचारी उत्पादता में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है क्योंकि यदि नया विनिर्माता अत्यधिक कार्यबल के साथ स्थापित होता है, तो अल्प प्रचालन में उसकी प्रति कर्मचारी उत्पादकता गिरावट दर्शायेगी। तथापि, याचिकादाताओं की उत्पादकता में कोई गिरावट नहीं आई है और वास्तव में उनकी प्रति दिवस उत्पादकता बड़ी है।
- (खख) याचिकादाताओं को आयातों में वृद्धि होने से पहले घाटे हो रहे हैं। वास्तव में वर्ष 2014-15 में उनके घाटों में गिरावट आई है। इसलिए वर्ष 2014-15 एक असमान्य वर्ष हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से याचिकादाताओं को घाटे हो रहे हैं और उनका आयातों में वृद्धि होने से कोई सह-संबंध नहीं है।

(गग) कारणात्मक संबंध के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादियों के निम्नलिखित निवेदनों पर विश्वास किया गया है:-

1. आयातों की मात्रा में वृद्धि देश में मांग और पूर्ति में व्याप्त अंतर के कारण हुई है।
2. कच्चे माल की लागत में गिरावट आने के कारण आयात कीमतों में गिरावट आई है।
3. सोलर से प्राप्त पहले अनुरोध में प्राधिकारी को कच्चे माल में और उत्पाद की कीमतों में परिवर्तन पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।
4. कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के दावे का सुदृढता से खंडन किया गया है। उत्पादन की लागत में वृद्धि, मुन्द्रा सोलर के आंकड़ों को शामिल करके सूचित की गई है। यदि मुन्द्रा सोलर के आंकड़ों को अलग कर दिया जाता है, तो यह देखा जाएगा कि लागत में गिरावट बिक्री कीमत में गिरावट से अधिक है। इस प्रकार कीमत में कटौती होने के बावजूद कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यदि आंकड़े लागत में वृद्धि दर्शाते हैं, तो यह केवल इस तथ्य के कारण है कि मुन्द्रा सोलर ने हाल ही में अपना वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू किया है और उसने अधिक ऊपरी लागत का सामना करना पड़ा है, जो कि कम उत्पादन के कारण गैर-अवशोषित बना हुआ है।
5. घरेलू उद्योग को काफी समय से उनके निर्यात बाजार के ढह जाने और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन क्षमता का कम उपयोग किए जाने के कारण वित्तीय घाटे हो रहे हैं। यहां तक कि निर्यात में उछाल आने से पहले से घरेलू उद्योग अपनी वास्तविक लागतों से अधिक कीमतें प्राप्त करने में असमर्थ था।
6. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उनकी बिक्रियों और क्षमता उपयोग को नुकसान हुआ है। घरेलू उद्योग ने यह दावा नहीं किया है कि इनकी मात्राओं में गिरावट आई है। वास्तव में बिक्रियों की मात्राओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यदि बिक्रियों की मात्राओं में वृद्धि हुई है, तो इसके लिए गंभीर क्षति होने का कोई आधार नहीं है।
7. घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में कोई गिरावट नहीं आई है। वास्तव में आयातों में उछाल आने से पहले घरेलू उद्योग का बाजार का हिस्सा काफी कम था।
8. निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट, मुन्द्रा सोलर के आंकड़ों को शामिल करने के कारण आई है, जिसने हाल ही में अपना वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू किया है। मुन्द्रा सोलर के आंकड़ों को शामिल नहीं किया जाता है, तो यह देखा जायेगा कि घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ बढ़ा है।
9. मालसूचियों में वृद्धि होने के संबंध में उल्लेखनीय है कि यह वृद्धि मुन्द्रा सोलर द्वारा हाल ही में अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के कारण हुई है। यह नितान्त स्पष्ट है कि याचिकादाताओं की कंपनियों की क्षमता ___ से बढ़ कर ___ हो गई है। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूचियां भी बढ़ जायेंगी। तथापि, उत्पादन के संबंध में मालसूची पर विचार करने की आवश्यकता है। उत्पादन के संबंध में मालसूची में स्तर तक वृद्धि नहीं हुई है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि याचिकादाता, याचिका देने वाले घरेलू उद्योग पर बड़े हुए आयातों के किसी प्रतिकूल प्रभाव को सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं।

(घघ) याचिकादाताओं की समंजन योजना अत्यधिक अस्पष्ट और ओछी है।

- (डड) चीन, मलेशिया और ताईवान काफी लंबे समय से भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के निर्यात कर रहे हैं। यदि आयात उचित कीमतों (जिसके कारण रक्षोपाय शुल्क होता है) पर किए जाते हैं, तो ऐसे तर्क को कोई आधार नहीं है कि संबद्ध देशों से

निर्यातक घरेलू उद्योग को विध्वंस करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी अवधारणा से स्वतः जब आयात उचित कीमत पर किए जाते हैं, भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धी नहीं हैं।

- (चच) घरेलू उद्योग मांग की पूर्ति नहीं कर सकता है और महानिदेशक, रक्षोपाय ने विगत में तब शुल्क लगाने की सिफारिश करने से मना कर दिया है, जब मांग और पूर्ति के बीच व्यापक अंतर व्याप्त था।
- (छछ) याचिकादाताओं ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि टैरिफ में वृद्धि नगण्य होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि देशीकरण होने के कारण सरकार के राजस्व में कैसे वृद्धि होगी।
- (जज) याचिकादाताओं ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि शुल्क को लागू नहीं करना कैसे भारत में जनहित के खिलाफ होगा। ऐसी पूर्णतया परिकल्पना है कि स्थानीय विनिर्माता समाप्त हो जायेंगे।
- (झझ) घरेलू उद्योग का उत्पादन बढ़ रहा है और यदि मुन्द्रा सोलर के उत्पादन को शामिल नहीं किया जाता है तो क्षमता उपयोग भी वृद्धि दर्शायेगा। इसलिए यह तर्क निराधार है कि आयातों से भारत में उत्पादन श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- (ञञ) याचिकादाताओं ने सुगमता से इस तथ्य की अनदेखी की है कि उसने इस कारणवश पाटन-रोधी शुल्क लगाने के अपने आवेदन-पत्र को वापिस ले लिया है कि क्षति मार्जिन नगण्य अथवा नकारात्मक था। इन परिस्थितियों में यह पूर्ण रूप से समझे जाने की बात है कि याचिकादाता रक्षोपाय के उपायों के मामले में 95% तक का अधिकतम शुल्क लगाए जाने का कैसे दावा कर सकते हैं।
- (टट) यदि शुल्क लगाया जाता है, तो वह पाटन-रोधी जांच पर लागू होने वाले समान सिद्धांतों को लागू करने के बाद परिकलित क्षति रहित कीमत के आधार पर क्षति मार्जिन के आधार पर लगाया जाना चाहिए।

(4) मेसर्स नार्थ इंडिया मॉड्यूल मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन

- (क) याचिकादाताओं द्वारा उत्पादित सोलर सेल्स, उनके निजी मॉड्यूलस का विनिर्माण करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- (ख) याचिकादाताओं ने झूठमूठ यह तर्क दिया है कि रक्षोपाय शुल्क लागू करने के बाद उसके पास अतिरिक्त क्षमता हो जाएगी।
- (ग) सोलर मॉड्यूलस पर शुल्क लगाए जाने चाहिए और न कि सोलर सेल्स पर क्योंकि उनकी मांग अत्यधिक है और अंतिम उत्पाद होने के नाते सोलर मॉड्यूलस के लिए मांग और पूर्ति के बीच व्यापक अंतर व्याप्त है तथा घरेलू उद्योग की सोलर सेल्स की क्षमता। अनुकूलतम क्षमता उपयोग किए जाने पर भी कुल मांग के केवल 15% मांग को पूरा करने के लिए क्षमता उपलब्ध है। अडानी पावर कंपनी अपनी समग्र क्षमता का उपयोग केप्टिवली कर रही है और वह सोलर सेल्स की एक निबल आयातक कंपनी है।
- (घ) याचिका में ऐसी किसी असाधारण अथवा आपात स्थिति का प्रकटन नहीं किया गया है, जिसके लिए रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता हो। स्वतः इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- (ङ) कोई अप्रत्याशित घटना घटित नहीं हुई है। याचिकादाता की मुख्य समस्या वेफर्स की अनुपलब्धता है, जो कि सुज्ञात कारक है। आयात में प्रत्येक वृद्धि अथवा भारत से बाहर कम कीमतों पर माल की उपलब्धता को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।
- (च) आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि भारत में वेफर्स की अनुपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग की समस्या यथावत् बनी हुई है। घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई वस्तुपरक आधार प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह पता चल सके कि उसके द्वारा दावा की गई क्षति का कारण आयातों में वृद्धि होना है।
- (छ) घरेलू उद्योग एक विश्वसनीय और अर्थक्षम समंजन योजना प्रस्तुत करने में विफल रहा है। जब तक भारत में सिलिकोन इनगोट और सिलिकोन वेफर्स का विनिर्माण नहीं किया जाता है, तब तक भारतीय सेल विनिर्माता, आयातों के साथ बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं।
- (ज) रक्षोपाय लागू करना जन हित के खिलाफ है।

(5) मेसर्स अवाडा पावर प्राइवेट लिमिटेड

- (क) रक्षोपाय नियमावली के नियम 2 (ङ) के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा उन्हें विनिर्मित नहीं किया जाता है:-
 - (1) प्रोद्योगिकी आधारित "पीईआरसी" (पेसिवेटिड इमीटर रियर सेल) प्रयुक्त करने वाले सोलर सेल्स।
 - (2) थिन फिल्में और बाई-फेसियल एन-टाईप सोलर सेल्स।

- (3) अधिक कार्यक्षमता के सोलर सेल्स जिनमें 5 और 6 बस बार उत्पादन प्रौद्योगिकी प्रयुक्त होती है।
- (4) मोनो क्रिस्टलिंग प्रौद्योगिकी के सोलर मॉड्यूल्स।
- (ख) घरेलू उद्योग रक्षोपाय शुल्क को लागू करने की कानूनी अपेक्षाओं के अंतर्गत रक्षोपाय शुल्क लागू करने के लिए अपनी पात्रता को पूरा करने और/अथवा प्रमाणित करने में बुरी तरह से विफल रहा है।
- (ग) सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स के लिए आधार की जांच पृथक् रूप से की जानी चाहिए। इस जांच में सोलर मॉड्यूल्स के लिए घरेलू उद्योग के रूप में याचिकादाताओं का कोई आधार नहीं है।
- (घ) एसजेडई यूनिटों में अवस्थित याचिकादाताओं को आधार के विश्लेषण से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उनका प्रमुख उद्देश्य निर्यात बाजार की संपूर्ति करना है।
- (ङ) भारत में सोलर पाँवर को बढ़ावा देने के भारत सरकार की परिकल्पना के फलस्वरूप संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि होने के पीछे एक मात्र यही कारण है। मांग और पूर्ति में व्यापक अंतर व्याप्त होने के कारण आयात हुए हैं।
- (च) याचिकादाता ऐसे किसी भी विकास को अभिज्ञात करने में विफल रहे हैं, जो कि गॉट के अनुच्छेद XIX (1) (क) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर अप्रत्याशित माना जाता है।
- (छ) याचिकादाता गॉट के किसी भी विशिष्ट दायित्व को अभिज्ञात करने में विफल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप गॉट के अनुच्छेद XIX (1) (क) के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के आयातों में अचानक, तीव्र, अत्यधिक और हाल ही में वृद्धि हुई है।
- (ज) याचिकादाताओं के गंभीर क्षति होने के दावों का कोई महत्व नहीं है। ऐसा याचिकादाताओं की वार्षिक रिपोर्टों से प्रतिबिंबित होता है।
- (झ) वित्तीय वर्ष 2016-17 में इंडो सोलर और बेवसोल के कार्य-निष्पादन में अत्यधिक सुधार हुआ है, जबकि ज्युपीटर सोलर पाँवर लिमिटेड ने इसी अवधि के दौरान 3,999 लाख रूपए का लाभ दर्ज किया है। मुन्द्रा सोलर पीवी लिमिटेड ने लगभग एक वर्ष पहले वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू किया है और उससे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह अपनी अनुकूलतम क्षमता का उपयोग करेगी। इस कंपनी को क्षति होने का कारण अत्यधिक ब्याज और लागत का अवमूल्यन होना है। मेसर्स हेलिओज फोटो वोल्टाईक लिमिटेड लंबे समय से पुनर्निर्माण करने के लिए कापॉरेट ऋण के बोझ से दबी हुई थी और उसके तुलन पत्र में बहुत अधिक देयताएं जमा हो गई हैं तथा याचिकादाताओं की क्षति का यही कारण है।
- (ञ) याचिकादाताओं की समंजन योजना अर्थक्षम और व्यावहारिक नहीं है और यह रक्षोपाय नियमावली के नियम 11 (3) के साथ पठित रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 7.1 के अनुसार समंजन को सुकर नहीं बनाएगी।
- (ट) सोलर पाँवर के अंततः क्रेता जो कि विभिन्न डिसकोम्स हैं, ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि सोलर पाँवर की खरीदारी, भारतीय रूपए 3/किलो वाट घंटे से अधिक नहीं की जाएगी। तथापि, लागू किए जाने वाले शुल्क इस दर को गैर-अर्थक्षम बनायेंगे। सोलर पाँवर की शुल्क-पश्चात दरें न केवल अप्रतिस्पर्धी होंगी, बल्कि डेवलपर्स को भी सतत परियोजनाओं के विकास को छोड़ना पड़ जाएगा।
- (ठ) ऐसा कोई भी शुल्क जो कि सोलर पाँवर ग्रिड को आंशिक रूप से प्रभावित करता है, वह न केवल परियोजना के डेवलपर्स को बल्कि अंतः उपभोक्ताओं को भी कुप्रभावित करेगा।
- (ड) पेरामिड के नीचे पड़े विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय वर्तमान कीमतों पर सोलर पाँवर की ओर प्रवृत्त हुए हैं। रक्षोपाय शुल्क लागू करने से ग्रामीण विद्युतीकरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- (ढ) चूंकि याचिकादाता रक्षोपाय शुल्क लागू करने के लिए कानूनी रूप से हकदार नहीं हैं, इसलिए वे 95% रक्षोपाय शुल्क लागू करने का अनुरोध नहीं करेंगे।

(VI) मै. चायना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स

- क. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में आवेदक का दावा भ्रामक है क्योंकि दोनों प्रौद्योगिकियों से विनिर्मित उत्पादों के बीच अंतर कच्ची सामग्री, उत्पादन प्रक्रिया, दक्षता, लचीलेपन और कीमतों आदि जैसे कई पहलुओं में महत्वपूर्ण हैं।
- ख. अन्य देशों द्वारा शुरू की गई पाटनरोधी जांचों में क्रिस्टलीन उत्पादों और थिन फिल्मों को भिन्न-भिन्न उत्पादों के रूप में माना गया है, जैसाकि यू एस आई टी सी और ई यू के जांच परिणामों से सिद्ध है।

- ग. उसी उत्पाद का भाग बनने वाले सोलर सैलों और सोलर मॉड्यूलों के संबंध में याचिका के दावे वृद्धिपूर्ण हैं। भारत में मॉड्यूल के विनिर्माता चीन जैसे दूसरे देशों से सोलर सैलों के आयातों पर विश्वास करते हैं। सोलर सैल मॉड्यूलों की कच्ची सामग्री हैं, सोलर सैलों से मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए कई अन्य सामग्री तथा अतिरिक्त उत्पादन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। वे भिन्न उत्पाद हैं जिनकी विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को आवश्यकता होती है।
- घ. अप्रत्याशित परिस्थितियों के संबंध में याचिकाकर्ताओं के दावे तर्कहीन हैं क्योंकि आयातों में वृद्धि और उनके द्वारा इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के संबंध में किए गए दावे के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। आयात मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप बढ़े हैं न कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण।
- ङ. यद्यपि, कुछ अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत ठोस प्रतिबद्धताएं अप्रत्याशित हो सकती हैं, परंतु यह देखे जाने की आवश्यकता है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय करार हस्ताक्षरित किए गए हों और संबंधित बाजार में प्रभाव एवं परिवर्तन ला सकते हों।
- च. घरेलू उद्योग का यह कहते हुए दावा कि जो गंभीर क्षति हुई है वो इस तथ्य के कारण है कि डी सी आर का संरक्षित घेरा डब्ल्यू टी ओ अपील निकाय के आलोक में ज्यादा देर तक नहीं दिया जा सकता। उनके निर्णय की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि डब्ल्यू टी ओ – ए बी ने डी सी आर को संगत डब्ल्यू टी ओ नियमों में असंगत माना है। डी सी आर के माध्यम से घरेलू उद्योग की सुरक्षा करना डब्ल्यू टी ओ नियमों के अनुसार अनुचित और असंगत है।
- छ. तथाकथित क्षति घरेलू उद्योग की बढ़ती हुई क्षमता में अत्यधिक निवेश करने के गलत प्रचालन निर्णय और उत्पादन मांग में वृद्धि के अनुपात में न होने के कारण हो सकता है।
- ज. रक्षोपाय शुल्क लगाना भारत के सार्वजनिक हित के विरुद्ध है क्योंकि इस समय भारत की फोटोवोल्टाइप उत्पादों की 80 प्रतिशत उत्पादन क्षमता आयातित सोलर सैलों पर आधारित है जिसमें आधा चीन का है। सोलर उत्पादों के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से भारत के निचले स्तर के प्रयोक्ताओं यथा विद्युत केन्द्र प्रचालकों, निदेशकों और आयातकों के हितों को नुकसान पहुंचेगा।
- झ. एस ई जैड में स्थित स्वदेशी विनिर्माता किसी भी शुल्क घेरे की परिधि में आ जाएंगे जोकि सोलर सैलों और मॉड्यूलों पर लगाया जाएगा जिससे वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे।
- ञ. जांचकर्ता प्राधिकारी ने न तो आयातकों अथवा अंतिम प्रयोक्ताओं के हितों का उल्लेख किया और न ही समग्र सार्वजनिक हितों का उल्लेख किया बल्कि केवल इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित अनंतिम रक्षोपाय शुल्क घरेलू उद्योग के हितों की सुरक्षा के लिए है।
- ट. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित 95 प्रतिशत शुल्क की मात्रा प्रारंभिक जांच परिणाम में प्रस्तावित शुल्क दर से अधिक है।

(VII) **मै. सोलर पावर डेवलपर्स एसोसिएशन**

- क. रक्षोपाय नियमावली के नियम 2(ड.) के अनुसार निम्नलिखित वस्तुएं उत्पाद क्षेत्र से अलग की जानी चाहिए क्योंकि उनका विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है।
- “पीईआरसी” (पेसीवेटेड एनीटर रियर सैल) आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले सोलर सैल
 - थिन फिल्म और बाई फिसिकल एन टाइप सोलर सैल
 - 5 और 6 बस बार उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले उच्च दक्षता वाले सोलर सैल ; और
 - मोनो क्रिस्टलीन प्रौद्योगिकी के सोलर मॉड्यूल
- ख. घरेलू उद्योग रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए कानूनी आवश्यकताओं के तहत रक्षोपाय शुल्क लगाने की अपनी पात्रता सिद्ध करने और/अथवा पूरी करने में बुरी तरह विफल रहा है।
- ग. सोलर सैलों और सोलर मॉड्यूलों के लिए आधार की जांच पृथक् रूप से की जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं का इस जांच में सोलर मॉड्यूलों के घरेलू उद्योग के रूप में आधार नहीं है।
- घ. एस ई जैड युनिटों में स्थित याचिकाकर्ताओं को आधार विश्लेषण से अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि उनका प्राथमिक लक्ष्य निर्यात बाजार की पूर्ति करना है।
- ङ. संबद्ध सामानों का आयात भारत में सौर विद्युत का संवर्धन करने के लिए भारत सरकार के लक्ष्य के परिणामस्वरूप बढ़ा। संबद्ध सामानों के आयात में वृद्धि के पीछे यही एकमात्र कारण है। आयात केवल मांग एवं आपूर्ति के भारी अंतराल को पूरा करने के लिए हुए।
- च. याचिकाकर्ता किसी ऐसी घटना की पहचान करने में विफल रहे हैं जो जीएटीटी के अनुच्छेद-XIX (1)(क) के अभिप्राय के अंतर्गत अप्रत्याशित बनता है।
- छ. याचिकाकर्ता किसी विशिष्ट जी ए टी टी दायित्व की पहचान करने में विफल रहे हैं जिससे जी ए टी टी के अनुच्छेद-XIX (1)(क) के अनुसार संबद्ध सामानों के आयातों में अचानक, तेजी से महत्वपूर्ण और हाल की वृद्धि हुई है।
- ज. याचिकाकर्ताओं के भारी क्षति के दावे का कोई औचित्य नहीं है। यह याचिकाकर्ताओं की वार्षिक रिपोर्टों में दर्शाया गया है।

- झ. इंडो सोलर और वैबसोल का निष्पादन वित्तीय वर्ष 2016-17 में काफी सुधरा है जबकि जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड ने उसी अवधि के दौरान 3,999 लाख रूपए का लाभ दर्ज किया। मुन्द्रा सोलर पी वी लिमिटेड ने लगभग एक वर्ष पूर्व ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है और उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह इष्टतम क्षमता पर प्रचालन करेगा। इस कंपनी को क्षति अत्यधिक ब्याज एवं मूल्यह्रास लागतों के कारण है। मै. होलियोज फोटो वोल्टाइक लिमिटेड पर लंबी अवधि से निगम ऋण पुनर्निर्माण चल रहा है और तुलन पत्र में अत्यधिक देयताएं संचित हो गई हैं तथा वही याचिकाकर्ताओं की इन हानियों का कारण है।
- ञ. याचिकाकर्ताओं की समायोजन योजना व्यवहार्य नहीं है और रक्षोपाय नियमावली के नियम 11 (3) के साथ पठित रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 7.1 के अनुसार समायोजन की सुविधा नहीं होगी।
- ट. सोलर पावर के अंतिम क्रेता, जो विभिन्न डिस्कॉम हैं, ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सौर विद्युत 3 भारतीय रूपए /कि.वॉ. से अनधिक पर खरीदी जाएगी। तथापि, शुल्क लगाने से यह दर अव्यवहार्य हो जाएगी। सौर विद्युत की शुल्क लगाने की बाद की दरें केवल गैर-प्रतिस्पर्धी ही नहीं हो जाएंगी बल्कि विकासकर्ताओं को सतत परियोजनाओं के विकास का कार्य भी छोड़ना होगा।
- ठ. कोई भी शुल्क जो सौर विद्युत ग्रिड की समानता में व्यवधान उत्पन्न करता है, वह केवल परियोजना के विकासकर्ताओं को ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा बल्कि अंतिम उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करेगा।
- ड. पिरामिड के तल पर स्थित भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भारतीय वर्तमान कीमतों पर सौर विद्युत में जाने में सक्षम हुए हैं। रक्षोपाय शुल्क लगाने से ग्रामीण विद्युतीकरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि याचिकाकर्ता रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए कानूनी रूप से हकदार नहीं हैं, अतः 95 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए उनके अनुरोध का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(VIII) मै.आर ई सी सोलर

क. रक्षोपाय शुल्क, यदि कोई है, विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर नहीं लगाया जाना चाहिए :

- सिंगापुर के मूल के और
- सिंगापुर में विनिर्मित उच्च दक्षता वाले सीएसपीपी सैलों का उपयोग करना।

ख. एस ई जैड यूनिटों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं होना चाहिए क्योंकि ये युनिटें भारत की सीमाशुल्क क्षेत्र से बाहर पड़ती हैं।

एसईजैड यूनिटों के लिए शुल्कमुक्त आयातों के रूप में विशेष प्रोत्साहन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 26 में प्रावधान है जो डीटीए में स्थित यूनिट के लिए नहीं है।

ग. उन्होंने चीन जन.गण. से भारत में इलैक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच में अंतिम जांच परिणाम पर विश्वास किया जिसकी बाद में 'अनरोट एल्युमिनियम' (अलॉय विहीन एल्युमिनियम और एल्युमिनियम एलॉय) के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच में पुष्टि की गई थी।

घ. उसी विचाराधीन उत्पाद और उसी जांच की अवधि के लिए तथा उसी क्षति विश्लेषण अवधि के लिए घरेलू उद्योग पाटनरोधी जांच में वास्तविक क्षति और रक्षोपाय जांच में भारी क्षति का दावा कर रहा है जो यह दर्शाता है कि क्षति को अलग-अलग नहीं दिया गया है।

ड. यदि आयातों में वृद्धि के सिवाय कोई ऐसा कारक है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो वे कारक बढ़े हुए आयातों के कारक नहीं होने चाहिए और ऐसे मामलों में शिकायत को पाटनरोधी अथवा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच के लिए भेजा जाए।

च. घरेलू उद्योग को बढ़े हुए आयातों के कारण हुई क्षति से पाटित आयातों के निमित्त हुई क्षति को अलग-अलग देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। *फ्रंट एक्सल वीम, स्टेयरिंग नकल और मीडियम क्रैंक शैफ्ट तथा भारी वाणिज्यिक वाहन।*

छ. जहां आवेदक खुद ही विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण "बाजार व्यवधान" को स्वीकार और दावा कर रहे हैं, जोकि केवल चीन जन. गण. से आयातों पर लागू है, वहां विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए वर्तमान आवेदन पत्र में कोई औचित्य नहीं है और इसे रद्द किया जाए।

- ज. बड़े हुए आयात दर्शाने में अपर्याप्तता है और फिर भी यदि आयातों की मात्रा में कोई वृद्धि हुई है तो आयातों में वृद्धि की दर गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाती है।
- झ. विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय घरेलू उद्योग ने पूरी जांच की अवधि में अपने निष्पादन में काफी सुधार किया है।
- ट. भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात को भारत में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।
- ठ. भारतीय सौर विनिर्माण उद्योग में अंतर-निहित कमी है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 15 दिसंबर, 2017 को एक संकल्पना नोट जारी किया गया था जिसमें यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति विचाराधीन उत्पाद के बड़े हुए आयातों के कारण नहीं है बल्कि उनकी अंतर्निहित कमियों के कारण है।
- ड. विचाराधीन उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग को तथाकथित भारी क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क निम्नलिखित कारणों से टूट गया है :
- (i) विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि की दर में गिरावट
 - (ii) मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की असमर्थता
 - (iii) भारतीय सौर विनिर्माण उद्योग में अंतर्निहित कमी।
- ढ. बड़े हुए आयातों के सिवाय अन्य कारकों के कारण यदि घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है, तो वह विचाराधीन उत्पाद के बड़े हुए आयातों के कारण नहीं होनी चाहिए।
- ण. घरेलू उद्योग यह औचित्य सिद्ध करने में विफल रहा है कि भारत आई टी ए में हस्ताक्षर करता है और डीसीआर को हटाना एक अप्रत्याशित परिस्थिति है जिससे आयात में वृद्धि हुई है।
- त. डीसीआर नीति को हटाने के संबंध में मई, 2017 में घरेलू उद्योग के अनुप्रयोग को अंतिम रूप दिए जाते समय तक दिसंबर, 2016 में डी सी आर को हटाने के समय से आयात प्रवृत्ति के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अप्रत्याशित परिस्थितियां होने के रूप में डीसीआर को हटाने का कारा भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उपर्युक्त तर्कों के मद्देनजर उत्तरदाता सादर अनुरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग जी ए टी टी अनुच्छेद XIX की अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ नहीं रहा है।
- थ. आवेदकों द्वारा दी गई समायोजन योजना अत्यधिक अंदाजे वाली है और ठोसपरकता से अलग है। घरेलू उद्योग ने उसके कार्यान्वयन के संबंध में समय-सीमा अथवा ब्यौरे के बारे में समायोजन योजना की कोई खास बातें नहीं बताई हैं और इसीलिए उसे एक अर्थक्षम समायोजन योजना नहीं माना जा सकता।
- द. यदि कोई रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो समग्र सौर प्रयोक्ता उद्योग पर उसका नकारात्मक प्रभाव होगा और व्यापक जन हित में वह हानिकारक सिद्ध होगा।

(ix) **मै. विक्रम सोलर लिमिटेड**

- क. हम एस ई जैड में स्थापित यूनिटों को घरेलू उद्योग के रूप में शामिल करने को मानते हैं, जैसा कि महानिदेशक (रक्षोपाय) ने अपने दिनांक 5 जनवरी, 2018 के प्रारंभिक जांच परिणाम में माना है। जांच प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के रूप में एसईजैड में स्थापित यूनिटों को इस तरह से शामिल करने इस निर्णय के समर्थन में निवेदन किया जाता है कि घरेलू उद्योग के रूप में एसईजैड में स्थापित यूनिटों पर विचार करने के विरुद्ध भारतीय रक्षोपाय विधि के अंतर्गत और रक्षोपाय संबंधी करार के अंतर्गत कोई प्रतिबंध नहीं है।
- ख. एसईजैड में स्थापित सोलर यूनिट रोजगार प्रदान करके देश में सामाजिक, आर्थिक संवृद्धि और विकास में योगदान दे रहे हैं तथा राष्ट्रीय जीडीपी में संवर्धन कर रहे हैं तथा ये वर्ष 2022 तक सोलर पावर के 100 गीगावाट के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।
- ग. घरेलू उद्योग निम्नलिखित सूचीबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण नहीं कर रहा है, इन वस्तुओं को रक्षोपाय जांच के विचाराधीन उत्पाद से अलग किया जाना चाहिए।
- (1) पेसीवेटेड एमीटर रियर सैल (पीईआरसी) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले सोलर सैल
 - (2) थिन फिल्म और बाई फिसिकल एन टाइप सोलर सैल
 - (3) 5 और 6 बस बार उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले उच्च दक्षता वाले सोलर सैल
 - (4) हीटरोजंक्शन प्रौद्योगिकी पर आधारित उच्च दक्षता वाले सोलर सैल

- घ. एस ई जैड यूनितों तथा डीटीए क्षेत्र में स्थापित यूनितों, दोनों को हुई क्षति को रेट कोटा (टीआरक्यू) के रूप में रक्षोपाय शुल्क लागू करके तथा एसईजैड में स्थापित यूनितों को टीआरक्यू का पर्याप्त अंश आवंटित करके दूर किया जा सकता है।
- ड. सोलर सैलों की घरेलू उत्पादन क्षमता सोलर मॉड्यूलों अथवा पैनलों के उत्पादन की घरेलू आवश्यकता से कहीं कम है।

(X) मै. ट्रीना सोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (वियतनाम)

- क. वियतनाम से संबद्ध सामानों का आयात अलग-अलग तीन प्रतिशत से अधिक और सामूहिक रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है जब अन्य विकासशील देशों (चीन और मलेशिया को छोड़कर) से उसे आयातों के साथ लिया जाए। इस प्रकार वियतनाम पर कोई अनंतिम रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश नहीं की गई थी।

(Xi) ट्रीना सोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (थाइलैंड)

- क. थाइलैंड से संबद्ध सामानों का आयात अलग-अलग तीन प्रतिशत से अधिक और सामूहिक रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है जब अन्य विकासशील देशों (चीन और मलेशिया को छोड़कर) से उसे आयातों के साथ लिया जाए। इस प्रकार थाइलैंड पर कोई अनंतिम रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश नहीं की गई थी।

(Xii) मै. कनाडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग (लुयांग) इंक और कनाडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग (चांगशु) इंक

- क. चूंकि जांच की शुरुआत से 6 माह गुजर गए हैं अतः वर्ष 2017-18 के लिए आंकड़े अब आयात और क्षति दोनों के लिए उपलब्ध हैं। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता हाल के आंकड़े रिकॉर्ड में नहीं लाए हैं (चाहे आयात के लिए हों या क्षति के लिए हो) और उन्होंने सामान्य रूप से अपने विश्लेषण में वार्षिक जांच की अवधि पर विश्वास किया है।
- ख. जांच की अवधि और क्षति की अवधि दोनों जांचों में अधिकतर सामान्य हैं जिसमें केवल दो जांच अवधियों में तीन माह का अंतर है।
- ग. सोलर सैल और मॉड्यूल अंतिम प्रयोग तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता, कीमत और उत्पाद विशेषताओं के कारण प्रत्येक से निम्नलिखित रूप में भिन्न हैं।
1. उत्पाद विशेषताएं : सोलर सैल मॉड्यूलों के लिए इनपुट हैं। एक मॉड्यूल कई सोलर सैलों से बनाया जाता है।
 2. अंतिम प्रयोग : यद्यपि, सोलर सैल और मॉड्यूल दोनों में समान आधारभूत गुणधर्म हैं, अर्थात् सूर्य की रोशनी से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, सोलर सैल मॉड्यूल में वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है तथा वे अंतिम प्रयोग/अनुप्रयोगों के संदर्भ में भिन्न हैं। एक अकेला सोलर सैल बिजली का विशेष रूप से उत्पादन नहीं कर सकता जिसका प्रयोग किसी वाणिज्यिक अनुप्रयोग के लिए किया जा सके। दूसरी ओर एक मॉड्यूल जोकि कई सोलर सैलों से बनाया जाता है, उसका प्रयोग विद्युत उत्पादन की अत्यधिक मात्रा के कारण वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। अतः सोलर सैल और मॉड्यूल अंतिम प्रयोक्ता के परिप्रेक्ष्य से भिन्न-भिन्न हैं।
 3. तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से अप्रतिस्थापनीय : सोलर सैलों को मॉड्यूलों में असेंबल करने की प्रक्रिया एक तकनीकी एवं अत्याधुनिक प्रक्रिया है जिसमें सोलर सैलों की लागत का 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक मूल्यवर्धन की आवश्यकता होती है। संबद्ध देशों से सोलर सैलों का पहुंच मूल्य स्वयं याचिका के अनुसार 13.71 भारतीय रूपए/वॉट से 18.59 भारतीय रूपए/वॉट तक है और मॉड्यूलों का पहुंच मूल्य जांच की अवधि में 24.19 भारतीय रूपए/वॉट से 36.58 भारतीय रूपए/वॉट है।
- घ. सोलर सैल और मॉड्यूल एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते – एक-दूसरे का ऊपरी स्तर का उत्पाद है। मॉड्यूलों का आयात सैल के विनिर्माताओं द्वारा बेचे गए उत्पादों अथवा उसके विपरीत प्रतिस्पर्धा नहीं करते।
- ड. उल्लिखित सोलर सैल और मॉड्यूल अलग-अलग उत्पाद हैं (जैसे कि ऊपर पहले ही जोर दिया गया है), पांच याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा सोलर सैलों और मॉड्यूलों के बीच उत्पादन विभाजन के प्रतिशत हिस्से के संबंध में कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं। (सोलर सैलों और मॉड्यूलों के कुल उत्पादन के विरुद्ध)।
- च. सार्वजनिक पटल की सूचना के आधार पर पांच याचिकाकर्ता कंपनियां मॉड्यूलों के कुल घरेलू उत्पादों का केवल 3.25 प्रतिशत ही होंगे।
- छ. 3 याचिकाकर्ता कंपनियां एसईजैड हैं। उन्हें ‘अनरॉट एल्युमिनियम(अलॉय विहीन) एल्युमिनियम और एल्युमिनियम एलॉय’ के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच में अंतिम जांच परिणाम के अनुसरण में घरेलू उद्योग से अलग किया जाना चाहिए।
- ज. निर्यातक इस स्थिति से सहमत हैं कि रक्षोपाय शुल्क, यदि कोई हों, एसईजैड में विनिर्मित परिष्कृत सामानों पर लागू नहीं होंगे और वे डी टी ए में जाएंगे - परंतु, इनपुट 5 पर लागू होंगे जो उपर्युक्त परिष्कृत सामानों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। (यह मानते हुए कि इनपुट पर शुल्क लगाया जाता है और परिष्कृत सामान इनपुट की समान वस्तु है)।

- झ. चूँकि सोलर सैल और मॉड्यूल न तो समान वस्तु हैं और न ही सीधे ही प्रतिस्पर्धी हैं (जैसाकि यहां ऊपर खंड-ख में दिया गया है), माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे याचिकाकर्ताओं को निर्देश दें कि वे बड़े हुए आयातों के संबंध में सोलर सैलों और मॉड्यूलों के लिए अलग-अलग आंकड़े दें ताकि गंभीर क्षति का प्रभावी मूल्यांकन किया जा सके।
- ट. याचिकाकर्ताओं ने अपने लिखित अनुरोधों के पैरा सं. 50 से 68 में केवल चाइना में अप्रत्याशित घटनाओं के संबंध में अपने कथनों को सीमित किया है और अन्य देशों के संबंध में किन्हीं अप्रत्याशित घटनाओं का विवरण देने में विफल रहे हैं जहां से भारत में तथाकथित आयात हुए हैं।
- ठ. "अप्रत्याशित" मानी जाने वाली घटना उस समय होनी चाहिए थी जब छूट पर वार्ता की गई थी। मरक्केश पैकेज की वार्ता के समय संविदाकार पक्षकारों ने भी व्यापार उपचार उपायों अर्थात् अर्थात् पाटनरोधी, सब्सिडीरोधी और रक्षोपाय से संबंधित करारों पर वार्ता की थी। व्यापार उपचार उपायों को कुछ उत्पादों के संबंध में अपनाना उस समय "अप्रत्याशित" नहीं था जब छूटों पर वार्ता की गई थी।
- ड. डब्ल्यू टी ओ कानून में विसंगति को "अप्रत्याशित" नहीं माना जा सकता।
- ढ. इस संबंध में दिए गए आंकड़े असिद्ध प्रतीत होते हैं और उनको आगे प्राधिकृत किए जाने की आवश्यकता है। ये घटनाएं कंपनियों द्वारा वैश्विक रूप से अपने व्यापार को दक्ष बनाने के लिए लिए गए व्यापारिक निर्णय हैं। ये घटनाएं रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने पर ध्यान न देकर भी किसी उद्योग में मौजूद रहेंगी। व्यापार में मात्रा में वृद्धि अथवा चीनी निर्यातकों की निर्यातानुमुखता को अप्रत्याशित घटना नहीं माना जा सकता।
- ण. चीनी घरेलू उत्पादकों को दिए गए प्रोत्साहन वर्तमान रक्षोपाय जांच के प्रयोजन के लिए असंगत रहते हैं। जो बात संगत रहती है वह मांग है जो भारत सहित विश्व भर में बड़ी। चीन द्वारा अपनाए गए सब्सिडी उपायों को जी ए टी टी 1994 के अनुच्छेद-XIX : 1 (क) के अभिप्राय से भारत द्वारा "अप्रत्याशित घटनाएं" के रूप में नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए अनुरोध कर चीन के सब्सिडी उपायों का विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं।
- त. पैरिस करार कुछ नहीं है बल्कि जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्य ढांचा सम्मेलन ("यू एन एफ सी सी") के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं का विस्तार है, जिस पर भारत ने 1 नवंबर, 1993 को प्रतिक्रिया दी थी और इसीलिए भारत हमेशा अपने कार्बन उत्सृजन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध रहा तथा उसे उस समय भी यू एन एफ सी सी सी के तहत अपनी सतत प्रतिबद्धताओं के संबंध में पूरी जानकारी थी जब सीओपी 21 को एक नई घटना के रूप में देखा जाना था, उसे कभी भी "अप्रत्याशित" घटना नहीं माना जा सकता।
- थ. याचिकाकर्ताओं ने खुद ही स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण है (जैसा कि उपर्युक्त पैरा सं. 37 में दर्शाया गया है) और चूँकि पाटित आयातों से निपटने के लिए संगत जांच पाटनरोधी जांच है अतः माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे याचिकाकर्ताओं को निर्देश दें कि वे रक्षोपाय नियमावली और डब्ल्यूटीओ के तहत अपने दायित्व के अनुसरण में संगत जांच कराएं।
- द. वर्तमान जांच समय के बाद के आधार पर वर्तमान में चल रही है और आंकड़े वृटिपूर्ण रूप से वार्षिकीकृत हैं जिन्हें अद्यतन न किया गया प्रतीत होता है। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि तब तक जांच की कार्यवाही न करें जब तक हितबद्ध पक्षकारों को नए और सर्वाधिक हाल की क्षति के आंकड़े उपलब्ध न कराए जाएं।
- ध. याचिकाकर्ताओं ने सुविधाजनक रूप से इस तथ्य की उपेक्षा की है कि उनकी क्षमताएं (मुन्द्रा सोलर पी वी लिमिटेड को शामिल करने तक) जांच की अवधि में भारत की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं और विकासकर्ताओं के पास भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त कीमतों पर सैलों और मॉड्यूलों का आयात करने के अलावा, कोई विकल्प नहीं था।
- न. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग पूरी जांच की अवधि में काफी बड़ी तथापि, भारतीय क्षमता में भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग को पूरा करने हेतु उसी दर पर वृद्धि नहीं हुई।
- प. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विगत में संबद्ध सामानों के संबंध में रक्षोपाय शुल्क न लगाने का निर्णय लिया है जिसमें भारत में बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने के निमित्त तथा भारत में मांग एवं आपूर्ति के अंतराल को पूरा करने के लिए आयातों में वृद्धि हुई थी।
- फ. याचिकाकर्ताओं ने नकली क्षति का अनुकूलन करने का प्रयास किया है जैसाकि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर दर्शाया जाएगा। चीन जन.गण., ताइवान और मलेशिया (संबद्ध देश) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों के विरुद्ध

समानांतर पाटनरोधी जांच में संबद्ध देशों के लिए जांच की अवधि (1 अप्रैल, 2016 से 30 जून, 2017) के दौरान सोलर मॉड्यूलर के लिए कीमत कटौती नकारात्मक थी।

- ब. याचिकाकर्ताओं ने सुगमता से कीमत कटौती के संबंध में सैलों और मॉडलों के लिए सुविधाजनक रूप से अलग-अलग आंकड़े दिए हैं जबकि न्यूनीकरण एवं ह्रास जैसे अन्य क्षति मानदंडों के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने घरेलू उद्योग पर सोलर सैलों और मॉड्यूलों के आयातों का संयुक्त प्रभाव देने का विकल्प चुना है। (जब सोलर सैल और मॉड्यूल यदि अलग-अलग निर्धारित किए जा सकते हैं तो वे तथाकथित क्षति नहीं दर्शा सकते)।
- भ. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे सोलर सैलों और मॉड्यूलों के आयातों के निमित्त अलग-अलग तथाकथित क्षति का पृथक् विश्लेषण करें क्योंकि सैल और मॉड्यूल समान और प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं हैं।
- म. वर्तमान तथ्यों में कोई कीमत न्यूनीकरण/ह्रास नहीं है क्योंकि बिक्री कीमत उसी दर पर बनाए रखी गई है जो बिक्री लागत की कीमत है। पूरी क्षति अवधि में केवल एक वर्ष है जहां याचिकाकर्ताओं की लागत अर्थात् 2015-16 में उसके साथ नहीं गई है। अत्यधिक मूल्यह्रास, उच्च ब्याज लागत उच्चतर निर्धारित लागत और क्षमता उपयोग की धीमी गति के कारण नए उत्पादक के लिए बड़ी हुई लागत बनाना बाध्यकारी था (जैसाकि किसी भी नए संयंत्र के मामले में होता है)।
- य. पूरी जांच की अवधि में याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई बिक्री में सुधार हुआ है और यदि याचिकाकर्ताओं को कोई भारी क्षति हुई है तो वह निम्नलिखित संगत भाग में चर्चित विभिन्न न मानने वाले कारकों के कारण है।
 - र. क्षमता बढ़ी है और घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम हुआ प्रतीत होता है। याचिकाकर्ता यहां विचाराधीन उत्पाद के अन्य उत्पादकों के क्षमता आंकड़े देने की मांग आसानी से कर रहे हैं जब उन्होंने सजग रूप से उपर्युक्त उत्पादकों को "घरेलू उद्योग" के घरे से बाहर किया है।
 - ल. सुराना सोलर लिमिटेड जिस पर याचिकाकर्ता पैरा-113 में अपनी क्षति विश्लेषण में विश्वास करने की मांग कर रहे हैं, यह सिद्ध है कि कंपनी वर्ष 2013 से निरंतर लाभ कमा रही है।
 - व. एक्स एल एनर्जी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के पृष्ठ 43 पर यह उल्लेख किया है कि क्षमताएं उद्योग के घटने के कारण अनुपयुक्त थीं और मांग में फलस्वरूप गिरावट थी।
 - श. निर्यातक अनुरोध करते हैं कि यूरो मल्टीविजन के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए प्रकटन को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि यूरो मल्टीविजन को तथाकथित क्षति स्वप्रभावित थी और आयातों के कारण नहीं थी।
 - प. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में तथाकथित गिरावट की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं की अपनी अदक्षताओं के कारण है।
 - स. यह बात दोहराई जाती है कि चूंकि मुद्रा एक नई स्थापित कंपनी है अतः उसने निश्चित रूप से कुछ स्थापना संबंधी लागतें, उत्पादन लागतें और अन्य खर्च लगाए होंगे (जोकि किसी अन्य स्थापित कंपनी से अधिक होने चाहिए)- परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग का समग्र निष्पादन प्रभावित हुआ।
 - ह. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या उपर्युक्त याचिकाकर्ताओं का निर्यात कम हुआ है और उससे मालसूची में तथाकथित वृद्धि हुई है।
 - क्ष. घरेलू उद्योग को यदि कोई भारी क्षति हुई है तो वह स्वप्रभावित है। प्रशुलक में भारी गिरावट आंशिक रूप से सोलर मॉड्यूलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में गिरावट के परिणामस्वरूप थी। इस बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए याचिकाकर्ताओं के लिए उन्हें सौर विद्युत विकासकर्ताओं द्वारा दी गई कम बोली के अनुरूप तथा घटती हुई अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप अपनी कीमतें घटाने की आवश्यकता थी।
- ज. नीलामी क्रियाकलाप में गिरावट इन कारणों से मानी जा सकती है जैसे डिस्कॉम की कमजोर वित्तीय स्थिति, अदक्ष पारेषण, कम विद्युत मांग, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक कंपनियों द्वारा कैपिटल उत्पादन में वृद्धि तथा उसकी नवीकरण ऊर्जा नीति में भारत के डीसीआर के विरुद्ध डब्ल्यू टी ओ नियम।
- कक. भारतीय सौर ऊर्जा निगम और एन टी पी सी ने एक बोलीदाता के लिए 1800 मेगावाट तथा 2000 मेगावाट की अधिकतम क्षमता निर्धारित की है तथा सौर बाजार में प्रमुख विकासकर्ताओं द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है।
- खख. एक याचिकाकर्ता कंपनी, इंडो सोलर लिमिटेड ने अपने "31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण" द्वारा 2017 के अंत के दौरान संस्थापन के तहत संयंत्र और मशीनरी के नुकसान के निमित्त अत्यधिक मदों की हानियां सूचित की हैं।
- गग. कंपनी को इस अवधि में 300 से अधिक करोड़ की हानि हुई है जोकि पूरी तरह गलत आयातों से असंबद्ध कारण से है।

- घघ. हेलियोज फोटो वोलाटाइक लिमिटेड (संक्षेप में "हेलियोस") कंपनी के प्रचालन 34 दिनों की अवधि के लिए कार्य बंद होने के कारण प्रभावित हुई है।
- डड. हेलियोस ने निम्नलिखित के द्वारा:
- (1) कंपनी के सामने आई परिसमापन संबंधी कठिनाइयों से उनके विनिर्माण प्रचालन तथा क्षमता उपयोग स्तर बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता अत्यधिक प्रभावित हुई है।
 - (2) निविदाओं को मध्यवर्ती रूप से जारी करने के कारण सतत मांग के अभाव की वजह से असमर्थता की चिंता लागत प्रभावी हुई।
- चच. वैबसोल एनर्जी सिस्टम- मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए पूरा उत्पादन नहीं था।
- छछ. इंडो सोलर लिमिटेड ने वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 के पृष्ठ-16 पर उल्लेख किया है कि क्षमताएं उद्योग के घटने तथा मांग में परिणामस्वरूप गिरावट आने के कारण अनपयुक्त थीं।
- जज. याचिकाकर्ता दीर्घावधि संविदाओं में आकर पुनः वार्ता के अनुसरण में कच्ची सामग्री कीमतों को कम करके अपनी लागतें घटाते हैं - यह सादर अनुरोध है कि यह परिपाटी लगाए जा रहे रक्षोपाय शुल्कों पर ध्यान न देते हुए अपनाई जानी चाहिए थी।
- झझ. यदि याचिकाकर्ता अपनी लागतें कम करने के लिए अग्रवर्ती और पिछली एकीकरण परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं तो यह अनुरोध है कि मुन्द्रा सोलर पी वी लिमिटेड (अदानी ग्रुप) जैसी लाभ कमाने वाली याचिकाकर्ता कंपनियों को इन दीर्घावधि परियोजनाओं में जाने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं हो सकती और उसके बाद समायोजन योजना के भाग के रूप में अपनी लागतें कम करने में वे प्रभावी रूप से सफल हो सकते हैं। याचिकाकर्ता रूप में उधार हो अमरीकी डॉलर उधार में परिवर्तित कर वित्त पोषण लागत कम करने की योजना बनाते हैं - निर्यातकों का अनुरोध है कि याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करने में विफल रहे हैं कि उन्होंने रूप में ऋण को अमरीकी डॉलर के ऋण में परिवर्तित करने की योजना कैसे बनाई और यदि यह संभव हो भी जाए तो इस परिवर्तन का आधार एवं वाणिज्यिक शर्तें क्या होंगी।
- ञञ. विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाना भारत के सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा क्योंकि निम्नलिखित कारणों से भारत में सौर बाजार पर इसका भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- टट. निर्दिष्ट प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद पर कोई रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश नहीं करनी चाहिए और जांच को रद्द करना चाहिए क्योंकि अंतिम रूप से शुल्क लगाए जाने के कारण सौर बाजार में विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा।
- ठठ. यदि विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है जिससे उन्नत प्रौद्योगिकी के आयातों का प्रवेश प्रभावित होगा - तो घरेलू बाजार भारतीय सौर बाजार में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा।
- डड. यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो इससे रोजगार की हानि की स्थिति बनेगी।
- ढढ. ऐसी कोई अप्रत्याशित घटनाएं नहीं हैं जिससे भारत में आयातों में वृद्धि हो सकती हो, आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई भारी क्षति नहीं है तथा घरेलू उद्योग को स्वप्रभावित क्षति के कारण बढ़े हुए आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क में कटाव की मौजूदगी नहीं है- याचिकाकर्ताओं का यह प्रकथन कि 90 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क लगाया जाए, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जनहित में रद्द किया जाना चाहिए।

(xiii) मै. ए सी एम ई सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड ("एसीएमई सोलर") और मै. एसीएमई क्लीनटेक सोल्युशन प्रा.लि. ("एसीएमई क्लीनटेक")

- क. रक्षोपाय शुल्क नियमावली की धारा 2 (ड.) "समान वस्तु" को "जांचाधीन वस्तु के हर तरह से समान वस्तु" के रूप में परिभाषित करती है।
- ख. सी-एसआई और थिन फिल्म में अंतर
- (i) थिन फिल्म प्रौद्योगिकी से निर्मित सोलर सैल और सी-एसआई प्रौद्योगिकी से निर्मित सोलर सैल एक-दूसरे से प्रतिस्थापित नहीं हो सकते अथवा एक-दूसरे में मिलाए नहीं जा सकते।
 - (ii) सी-एसआई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विनिर्मित सोलर सैल क्रिस्टलिंग सिलिकन से क्रिस्टलों की वृद्धि को शामिल करने वाली प्रक्रिया के माध्यम से बनाए जाते हैं, वैफर्स का उत्पादन किया जाता है और उसके बाद वैफर्स को सैलों में परिवर्तित किया जाता है जबकि थिन फिल्म प्रौद्योगिकी में थिन पीवी मेटेरियल ग्लास अथवा स्टेनलैस स्टील जैसी डाई सेन्सीटाइज सबस्ट्रेट्स में रखे जाते हैं।
 - (iii) सी-एसआई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विनिर्मित सोलर सैल में अधिक वॉट उत्पादन होता है और थिन फिल्म प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विनिर्मित सोलर सैलों की तुलना में अधिक परिवर्तन दक्षताएं होती हैं।

- (iv) सी-एसआई प्रौद्योगिकी से निर्मित सोलर सैल स्थल दक्ष होते हैं परंतु महंगे होते हैं और इनका प्रयोग प्रायः आवासीय तथा छोटे क्षेत्रों के लिए किया जाता है जबकि थिन फिल्म प्रौद्योगिकी से बने सोलर सैल पूर्व के सैलों के स्थल और कीमत के संदर्भ में विपरीत हैं और उनका प्रयोग अधिक तापमान और बड़े स्थान वाले क्षेत्रों के लिए किया जाता है।
- ग. घरेलू उद्योग ने अपने लिखित निवेदनों में यह स्वीकार किया है कि वे थिन फिल्म प्रौद्योगिकी प्रयुक्त करके सोलर सैल का विनिर्माण नहीं करता है।
- घ. घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि उनका कुल उत्पादन 381 मेगावाट है जोकि देश में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का 7.5 प्रतिशत मात्र है। प्रत्युत्तर संबंधी निवेदन के साथ एमएनआरई अनुबंध-क के रूप में संलग्न है।
- ङ. जांच अवधि के दौरान प्रचालनरत घरेलू उद्योग में शामिल जुपिटर सोलर और वैबसोल नामक दो कंपनियों के तुलन पत्र स्पष्टतया राजस्व में पर्याप्त वृद्धि दर्शाते हैं।
- च. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि रक्षोपाय शुल्क लागू करने के परिणामस्वरूप टैरिफ में भारतीय रूपए/किलोवाट घंटा 0.70 तक की वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप टैरिफ में मामूली वृद्धि होगी जोकि भारतीय रूपए/किलोवाट घंटा 3.14 होगी। घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क की दर (अर्थात् 95 प्रतिशत) परिकल्पित है और यह उसमें शामिल आंकड़ों और अन्य कारकों के किसी भी आनुभविक अध्ययन पर आधारित नहीं है।
- छ. यदि रक्षोपाय शुल्क 25 प्रतिशत की दर से 3.67 प्रति के डब्ल्यू एच भारतीय रूपए तक लगाया जाता है, यदि रक्षोपाय शुल्क 30 प्रतिशत की दर से 4.54 प्रति के डब्ल्यू एच भारतीय रूपए तक लगाया जाता है, यदि रक्षोपाय शुल्क 70 प्रतिशत की दर से तब प्रशुल्क 2.87 भारतीय रूपए प्रति के डब्ल्यू एच से बढ़कर 3.56 भारतीय रूपए प्रति के डब्ल्यू एच हो जायेगा और इसके फलस्वरूप उस दर जिस पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है, के समान प्रशुल्क में बहुत अधिक वृद्धि होगी।
- ज. एक उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित के प्रतिकूल होगा क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर घरेलू उद्योग कमजोर क्षमता उपयोग के कारण कई गुणा बढ़ जायेगा और इससे एन एस एम के अंतर्गत निर्धारित योजनाओं में विलंब होगा।

ग. महानिदेशालय (रक्षोपाय) की जांच एवं जांच परिणाम

17. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच आरंभन की प्रतिक्रिया में किए गए अनुरोधों आरंभिक जांच परिणाम और आम सुनवाई, उपलब्ध विभिन्न प्राथमिक और गौण अभिलेखों, किया गया घरेलू सत्यापन के आधार पर, मैंने विभिन्न पहलुओं के संबंध में चिंताओं की जांच की है और मेरा अंतिम जांच परिणाम निम्नानुसार है :
18. आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के मामले का निपटान सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) के अंतर्गत किया जाता है। इसकी उपधारा (1) में किसी वस्तु पर केंद्र सरकार द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाने का प्रावधान है यदि उस वस्तु का आयात भारत में इस प्रकार से बढ़ी हुई मात्राओं में तथा इस प्रकार की स्थितियों के अधीन किया जा रहा हो, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होती हो अथवा होने का खतरा हो।
19. सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 में उन तरीकों और सिद्धांतों का प्रावधान है जिससे जांच शासित होती है।
20. इस जांच को उक्त नियमावली के अनुसार किया गया है और अंतिम जांच परिणाम को इस अधिसूचना के माध्यम से रिकार्ड किया गया है।

क) विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी)

21. आरंभिक जांच परिणाम में, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित को सही ठहराया गया था :
- (i) "विचाराधीन उत्पाद सोलर सैल है चाहे उसका एसेम्बल मॉड्यूल अथवा पैनल में किया गया हो, अथवा नहीं" जिसे सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क शीर्षक 8541 और प्रशुल्क मद 85414011 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। सोलर सैल को बाजार की भाषा में फोटोवोल्टेइक सैल के रूप में भी जाना जाता है। फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिक आणविक स्तर पर सूरज की रोशनी को बिजली में सीधे परिवर्तित करने में सक्षम है और सोलर सैल ठोस अवस्था में विद्युतीय डिवाइस हैं जो फोटोवोल्टेइक प्रभाव द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर सूरज की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करता है। व्यावहारिक उपयोग के लिए, सोलर सैल की पैकेजिंग की जाती है और इसे एक एसेम्बली में जोड़ा जाता है और इस प्रकार की सोलर सैल की एसेम्बली को एक सोलर पैनल अथवा सोलर मॉड्यूल के रूप में संदर्भित किया जाता है। विद्युतीय संयोजन सोलर सैल में क्रम में किया जाता है ताकि अपेक्षित उत्पादन वाटेज प्राप्त की जा सके और/ अथवा इसके समानांतर अपेक्षित बिजली सक्षमता उपलब्ध कराई जा सके।

- (ii) विचाराधीन उत्पाद का निर्माण दो प्रमुख प्रौद्योगिकियों में से : (1) क्रिस्टलाइन सिलिकॉन (सी-एसआई) आधारित सोलर सैल प्रौद्योगिकी जिसे सिलिकॉन बेफर आधारित प्रौद्योगिकी के रूप में भी जाना जाता है और (2) थिन फिल्म प्रौद्योगिकी में से इसी का उपयोग करते हुए किया जा रहा है। सी-एसआई प्रौद्योगिकी एन-प्रकार के और पी-प्रकार के सिलिकॉन और मोनो-क्रिस्टलाइन और बहु क्रिस्टलाइन सामग्रियों का भी उपयोग कर सकता है। थिन फिल्म प्रौद्योगिकी एमोरफस सिलिकॉन, केडमियम टेलरियम (सी डी टी ई) अथवा कॉपर इण्डियम गैलियम सीरेनियम का उपयोग सेमी कंडक्टर सामग्री के रूप में कर सकता है। सी-एसआई प्रौद्योगिकी और थिन फिल्म प्रौद्योगिकी दोनों पर आधारित सोलर सैल का आयात भारत में किया जाता है।
- (iii) आवेदक केवल सी-एसआई प्रौद्योगिकी और न कि थिन फिल्म प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सोलर सैल/ मॉड्यूल/ पैनल का निर्माण करते हैं। आवेदकों ने यह दावा किया है सी-एसआई और थिन फिल्म प्रौद्योगिकियों पर आधारित सोलर का उपयोग सोलर पावर संयंत्रों में किया जाता है। आवेदकों के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन (जे एन एन एस एम) जैसी केंद्र सरकार की परियोजनाओं अथवा विभिन्न राज्य सरकार की परियोजनाओं में न तो प्रौद्योगिकियों में अंतर करता है और न ही विभिन्न प्रौद्योगिकियों के आधार पर परियोजनाओं के लिए अलग अलग नीलामी कीमत तय करता है। इसके अलावा, इन प्रौद्योगिकियों में से किसी पर आधारित सोलर सैल के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है और इन सभी का उद्देश्य एक ही अंत प्रयोग के लिए है। इस कारण आवेदक इस बात का विरोध करते हैं, सी-आई एस प्रौद्योगिकी पर आधारित घरेलू रूप से उत्पादित विचाराधीन उत्पाद एक समान है और प्रत्यक्ष रूप से सी-एसआई प्रौद्योगिकी अथवा थिन फिल्म प्रौद्योगिकी में से किसी एक पर आधारित आयात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद का प्रतिस्पर्धी उत्पाद है।
22. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के पास थिन फिल्म प्रौद्योगिकी और "पी ई आर सी" (पेसिवेटिड एमिटर रियर सैल) आधारित प्रौद्योगिकी और बाई-फेसियल एन-टाइट सोलर सैल : उच्च कार्यक्षमता वाले सोलर सैल जिनमें 5 और 6 बस बार उत्पादन शब्दावली का उपयोग होता हो; और मोनो क्रिस्टलाइन प्रौद्योगिकी का सोलर मॉड्यूल नहीं है और इस कारण विचाराधीन उत्पाद को घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन क्षमता/ उत्पादन के कार्यक्षेत्र तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। मैंने इस पहलू की बड़े ध्यान से जांच की है और यह नोट किया कि विभिन्न प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकारों सोलर सैल कार्य क्षमता, कीमत, भौतिक विशेषताओं जैसे आकार और वजन आदि के मामले में अलग अलग होते हैं। यद्यपि, इन परिवर्तनों के फलस्वरूप कीमत और कार्य क्षमता के मामले में व्यापार में गतिरोध उत्पन्न होता है, फिर भी विचाराधीन उत्पाद का अंतिम उपयोग केवल बिजली का उत्पादन करना है।
23. रक्षोपाय शुल्क नियमावली (सीमा प्रशुल्क) (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 – दिनांक 29.07.1997 की अधिसूचना संख्या 35/97 – एन टी –सीमा शुल्क (इसके पश्चात रक्षोपाय नियमावली के रूप में कहा जायेगा) किसी घरेलू उत्पाद को "भारत में समान वस्तु का एक उत्पादक अथवा प्रत्यक्ष रूप प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादक या व्यापार अथवा व्यापार संघ, जिसके अधिकतर सदस्य भारत में समान वस्तु अथवा प्रत्यक्ष रूप प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन करते हों, अथवा उसका व्यापार करते हों और "समान वस्तु का आशय उस वस्तु से है जो "जांच के अधीन वस्तु के सभी प्रकार से सदृश्य अथवा समान वस्तु हो", के रूप में परिभाषित "समान वस्तु" के रूप में मानते हैं। विचाराधीन उत्पाद का सामान एवं आच्छादन संबंधी अनुप्रयोग यह सिद्ध करते हैं कि आयात किए गए और घरेलू तौर पर उत्पादित संबद्ध वस्तु प्रत्यक्ष रूप में प्रतिस्पर्धी हैं। इस कारण से इसे विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर किया जाना आवश्यक नहीं है, जैसा कि जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना में उल्लेख किया गया है। इस कारण से मैं दिनांक 05.01.2018 के आरंभिक जांच परिणाम के पैरा 5.1 में यथा विचार किए गए और उल्लेख किए गए विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र को सही मानता हूं और उसकी पुष्टि करता हूं।
- ख) घरेलू उद्योग (डी आई) का कार्यक्षेत्र और स्थान**
24. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उपधारा (6) के खंड (ख) में घरेलू उद्योग की परिभाषा (इसके पश्चात "डी आई" के रूप में संदर्भित) नीचे दिए गए अनुसार है:
- (ख) "घरेलू उद्योग" का अभिप्राय उन उत्पादकों से है -
- भारत में समान वस्तु को संपूर्ण रूप में अथवा प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिस्पर्धी वस्तु के रूप में,
 - जिनकी भारत में समान वस्तु अथवा प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिस्पर्धी वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है।
25. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र एवं स्थान के संबंध में, दिनांक 19.12.2017 के जांच आरंभन और दिनांक 05.01.2018 के प्रारंभिक जांच परिणाम में, आवेदक ने शामिल किए गए विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों पर भी घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र में विचार किया है। इस कार्यक्षेत्र के निर्धारण के लिए प्रारंभिक जांच परिणाम में औचित्य नीचे दिए गए अनुसार दिया गया है।

“विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की निर्यात संवर्धन योजना है, निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उसके अंतर्गत कार्यरत एककों को राजकोषीय और गैर-राजकोषीय लाभ देता है और एक कानूनी काल्पनिक कहानी बनाकर विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों को ऐसा माना जाता है मानो एक भारत से बाहर हों। हालांकि, विशेष आर्थिक क्षेत्र एकक भौतिक रूप में भारत में है और उसी तरह से अन्य घरेलू निर्माण एकक है, ये एकक इस देश के कानूनों को मानते (यद्यपि कभी कभी शिथिलताओं के साथ), रोजगार पैदा करते हैं। घरेलू बिक्री करते हैं आदि। इस प्रकार से किसी भी मद के आयातों में वृद्धि का भी प्रभाव उसी रूप में विषय क्षेत्र के एककों पर पड़ता है क्योंकि यह विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर कार्यरत कोई अन्य घरेलू उत्पादक हो। इस कारण से आवेदक विशेष आर्थिक क्षेत्र के एकक घरेलू उद्योग के भाग के रूप में होने की अर्हता रखते हैं स्वयं घरेलू उद्योग के रूप आवेदकों के उत्पादन की मात्रा के बल पर। विशेष आर्थिक क्षेत्र के सभी अन्य एककों जो उसी प्रकार से समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों के उत्पादन लगे हुए हैं, को भी घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माना जायेगा”

26. हालांकि जांच आरंभ और आरंभिक जांच परिणाम के बाद तथा आगे सुनवाई की प्रतिक्रिया में (अनुरोध और प्रत्युत्तर दोनों) अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित आधारों विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर किए जाने के लिए तर्क दिया है :

घरेलू उद्योग को छोड़कर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- क. पांच में से तीन आवेदक घरेलू उत्पादक विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित हैं और इन्हें घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र को भारत के बाहर प्रक्षेत्र के रूप में माना जाता है और वस्तु के आयात एवं निर्यात के लिए निर्यात को शासित करने वाले सभी विधायन उन पर लागू होंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र के एकक द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संबंध यह नहीं जा सकता है कि उनका निर्माण घरेलू रूप में हुआ है। इस कारण से विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 (विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम) की धारा 53 जिसमें यह प्रावधान है विशेष आर्थिक क्षेत्र को भारत सीमा प्रक्षेत्र से बाहर एक प्रक्षेत्र के रूप माना जाता है, को देखते हुए कानून की दृष्टि सही नहीं है।
- ख. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम की धारा 30 और विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.08 के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थिति एककों और इ ओ यू को भारत के बाहर इसकी होने के रूप में माना जाता है और इस कारण से घरेलू उद्योग के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है।
- ग. विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों की स्थापना करने का मूलभूत उद्देश्य निर्यात का संवर्धन करना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के क्षेत्रों को घरेलू प्रशुलक क्षेत्र की परिभाषा से बाहर किया जाता है और उससे हटाना सीमा शुल्क के अधधीन है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के एकक निर्मित वस्तुओं की डी टी ए बिक्री आयात लाइसेंस को प्रस्तुत करने पर ही किया जा सकता है। घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र के एकक को मानने के लिए तर्क स्वीकार किये जाने लायक नहीं हैं।
- घ. रक्षोपाय कानून में प्रयोग की गई शब्दावली “भारत में उत्पादक” है और विशेष आर्थिक क्षेत्र के एकक को उस प्रक्षेत्र के रूप में माना गया है जो भारत की सीमा शुल्क प्रक्षेत्र से बाहर हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा ई ओ यू एकक का ध्यान निर्यात बाजार पर है और यह घरेलू बाजार में प्राथमिक रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है जबकि रक्षोपाय कानून का उद्देश्य घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में आयात प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करना है। इस कारण से ई ओ यू और विशेष आर्थिक क्षेत्र घरेलू उद्योग का उस सीमा तक ही हो सकते हैं जिस सीमा तक विद्यमान कानूनों के अंतर्गत उनकी हकदारी की अनुमति दी गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकासकर्ता और सह-विकासकर्ता एककों को निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करोड़ों और राजकोषीय लाभों के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न छूट एवं रियायतें दी गई हैं और इस कारण से वे अलग अलग क्षेत्र में हैं।
- ङ. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं होने के संबंध में कानून के सिद्धांत पर निष्कर्ष निकाला है और उसका पालन किया जाना चाहिए क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी एक अर्ध-न्यायिक निकाय है और इसे निर्णय करने की प्रक्रिया में एकरूपता अवश्य बनाये रखनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मामले में दिनांक 27 सितंबर, 2012 के महानिदेशालय रक्षोपाय के अंतिम जांच परिणाम में डब्ल्यू एस आई उद्योग (विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित) को भी घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर किया गया था।
- च. आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप विशेष आर्थिक क्षेत्र में एककों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे अनेक मामले हैं जहां प्राधिकारी ने विशेष आर्थिक क्षेत्र को घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में नहीं माना है। इसके फलस्वरूप, इन तीनों शिकायतकर्ताओं को घरेलू उद्योग (डी आई) के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है और शेष शिकायतकर्ता “सामूहिक उत्पादन जो भारत में कुल वस्तु का एक बड़ा हिस्सा होता हो” की सीमा पार नहीं करता है जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की स्थिति संबंधी आवश्यकता पूरी नहीं की जा रही है। महानिदेशक रक्षोपाय ने एस ई जैड यूनिटों को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में नहीं माना है।

- छ. "भारत में 'अनराउट एल्यूमीनियम (एल्यूमीनियम जो अलॉयड नहीं हो और एल्यूमीनियम अलॉयड)' के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच' में।
- ज. घरेलू उद्योग की 5 कंपनियां मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन का केवल 3.25 प्रतिशत उत्पादन करता है। पी एफ में, महानिदेशालय ने मॉड्यूल के संबंध में घरेलू उद्योग की 5 कंपनियों की स्थिति की जांच नहीं की है और इसके बजाय सोलर सैल और मॉड्यूल को एक साथ लेकर उनके स्थान का आकलन किया है।
- झ. इस प्रकार के बर्हिगमन के परिणामस्वरूप, मुंद्रा और हीलिअस के संबंध में संस्थापित क्षमता और अन्य आर्थिक आंकड़े निकाले जाने हैं (विशेष रूप से मुंद्रा की 2400 मेगावाट संस्थापित संस्था) जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में घरेलू उद्योग का योगदान सिर्फ 5.73 प्रतिशत तक कर देगा और इससे घरेलू उद्योग के रूप में शेष आवेदक प्रभावी रूप से अयोग्य हो जायेंगे।
27. मैंने दोनों पक्षों के तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। 'अनराउट एल्यूमीनियम (एल्यूमीनियम जो अलॉयड नहीं हो और एल्यूमीनियम अलॉयड)' और 'इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर' के रक्षोपाय जांच परिणाम महानिदेशालय रक्षोपाय के विगत में दिए गए निर्णयों का स्मरण किया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं को इस संबंध में रेखांकित किया गया है :
- क. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 निर्यात के संवर्धन और उससे जुड़े मामलों तथा उसके गौण मामलों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, विकास और प्रबंधन का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- ख. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(i) में घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र का आशय पूरे भारत (प्रक्षेत्रीय जल और उपमहाद्वीपीय शैल्फ सहित) से है परंतु इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र के क्षेत्रफल शामिल नहीं हैं।
- ग. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ड)(ii) के अनुसार 'निर्यात' का आशय किसी एकक अथवा विकासकर्ता को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से 'वस्तुओं की आपूर्ति करने अथवा सेवाएं प्रदान करने' से है।
- घ. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 30 में यह प्रावधान है कि -
- "इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अध्यक्षीन :-
- (क) विशेष आर्थिक क्षेत्र से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में निकाली गई किसी वस्तु पर सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत पाटनरोधी, प्रतिकर और रक्षोपाय शुल्क सहित सीमा शुल्क जहां भी लागू हो, वसूला जायेगा जैसा कि आयात किये जाते समय ऐसी वस्तुओं पर इन शुल्कों को लगाया जाता है; और
- (ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र से निकाली गई वस्तुओं पर लागू शुल्क की दर और प्रशुल्क मूल्यांकन, यदि कोई हो, इस प्रकार से निकाले जाने की तिथि और जहां इस प्रकार की तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता है, शुल्क के भुगतान की तिथि को को लागू दर और प्रशुल्क मूल्यांकन होगा।
- ड. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 53 में आगे यह प्रावधान है कि :
- (1) एक विशेष आर्थिक क्षेत्र को निर्धारित दिन को अथवा उससे प्राधिकृत प्रचालनों को शुरू करने के उद्देश्य से भारत का सीमा शुल्क का प्रक्षेत्र से बाहर का होना माना जायेगा
- (2) एक विशेष आर्थिक क्षेत्र उस स्थिति से जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे, को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत एक पोर्ट, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, लैंड स्टेशन और लैंड सीमा शुल्क स्टेशन जो भी स्थिति हो, माने जाने के लिए अधिसूचित कर सकता है;
- बशर्ते कि इस धारा के उद्देश्य से केंद्र सरकार अलग अलग विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग तिथियों को अधिसूचित करे।"
- च. विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 के नियम 47 में नीचे दिए गए अनुसार उल्लेख किया गया है।
- "घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री - (1) कोई एक निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन धारा 30 के अंतर्गत सीमा शुल्क के भुगतान पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में रिजेक्श अथवा अपशिष्ट अथवा स्क्रैप अथवा बचे हुए सामानों अथवा टूट हुए हीरे

अथवा उप उत्पादों जो निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता हो अथवा उससे जुड़ी सामानों एवं सेवाओं की बिक्री कर सकता है।

किसी एकक द्वारा निर्मित वस्तुओं की उपनियम (1) के अंतर्गत घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री विदेशी व्यापार नीति के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में समान वस्तुओं के आयात पर यथालागू आयात लाइसेंस को प्रस्तुत करने पर होगा।

छ. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 की धारा 2 (ण) के अनुसार, "आयात" का आशय निम्नलिखित है :

(i) भूमि, समुद्र अथवा हवाई मार्ग या किसी अन्य माध्यम से भारत के बाहर किसी स्थान से एकक अथवा विकासकर्ता द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र में सामानों को लाना अथवा सेवाएं प्राप्त करना, चाहे वह भौतिक रूप में हो अन्यथा अन्य प्रकार हो; अथवा

(ii) उसी विशेष आर्थिक क्षेत्र के अथवा एक अलग विशेष आर्थिक क्षेत्र के एक अन्य एकक अथवा विकासकर्ता से एकक अथवा विकासकर्ता द्वारा समान अथवा सेवाएं प्राप्त करना।

ज. उपनियम (1) और (2) की धारा 53 में एन एफ ई की गणना के लिए कुछ डी टी ए स्वीकृति पर विचार करने का प्रावधान है। विशेष आर्थिक क्षेत्र को भारत के सीमा शुल्क प्रक्षेत्र के बाहर एक प्रक्षेत्र होना माना गया है और इसे पोर्ट, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, लैंड स्टेशन और लैंड सीमा शुल्क स्टेशन जो भी स्थिति हो, माने जाने के लिए सीमा शुल्क, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत माना जा सकता है।

झ. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम और उसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र एककों के उपर्युक्त प्रावधान और विशेषताएं यह सिद्ध करती हैं कि यद्यपि विशेष आर्थिक क्षेत्र एकक प्रक्षेत्रीय दृष्टि के संबंध में भारत का हिस्सा नहीं है बल्कि "डी टी ए बिक्री के संबंध में निर्यातों के उल्लिखित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डी टी ए से आर्थिक रूप से निरूपित किया गया है यद्यपि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम/ उसके नियमों के अंतर्गत अनुमत्य केवल वे अपवाद हैं और आमतौर पर डी टी ए में एक घरेलू उत्पादक जैसा सामान्य मॉडल के रूप में व्यापार नहीं है जिसका प्राथमिक तौर पर ध्यान उस केंद्रित है क्योंकि उनके पास बाजार बिक्री है। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिसमें डी टी ए स्वीकृतियों की स्थिति विशेष आर्थिक क्षेत्र के एकक के लिए बिलकुल अनुकूल और उदार हो सकता है परंतु यह किसी भी प्रकार से विशेष आर्थिक क्षेत्र के एकक के निर्यात उन्मुख रहने के प्राथमिक उद्देश्य में परिवर्तन नहीं करता हो, अथवा उसमें संशोधन नहीं करता हो।

ञ. यद्यपि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम की धारा 2(i) में डी टी ए में एक आयात के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र के एक एकक द्वारा डी टी ए स्वीकृति के बारे में विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं है परंतु इस प्रकार की स्वीकृति सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क और धारा 8ख के अनुसार यथालागू पाटनरोधी शुल्क, प्रतिकर शुल्क और रक्षोपाय शुल्क जैसे शुल्कों के अध्यधीन है। लागू पाटनरोधी, प्रतिकर और रक्षोपाय शुल्कों को वसूले जाने की शर्त के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 30 में प्रविष्टि के बिल को दायर करना अपेक्षित है जो इस तथ्य को वैध ठहराता है कि वास्तव में इस प्रकार की डी टी ए स्वीकृतियों को आयात के रूप में माना जाना है। इस कारण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जाता है।

(i) विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों को स्थापित करने का मूलभूत उद्देश्य निर्यातों का संवर्धन है जिसे एक विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 द्वारा शासित किया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रक्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(1) के अंतर्गत डी टी ए की परिभाषा अलग किया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में डी टी ए से वस्तुओं की आपूर्ति निर्यात माना जायेगा।

(ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र के एकक द्वारा निर्मित वस्तुओं की डी टी ए बिक्री भारत में समान वस्तुओं के आयात पर यथा लागू आयात लाइसेंस को प्रस्तुत करने पर ही किया जा सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र से डी टी ए में वस्तुओं की बिक्री अथवा स्वीकृति सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार क्रमशः धारा 9 और 8ख के अनुसार लगाये और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 की धारा इसके अनुसार आरोपित विभिन्न शुल्कों अर्थात् पाटनरोधी शुल्क प्रतिदर शुल्क और रक्षोपाय शुल्क के अध्यधीन है।

(iii) ई ओ यू विशेष विदेशी व्यापार नीति संबंधित प्रावधानों से शासित होता है और विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों में एक बिक्री पर विचार निर्यात के रूप में किया जाता है। विशेष व्यापार नीति में प्रावधान डी टी ए के एककों और उन पर भी लागू होता है जो आयात एवं निर्यात करना चाहते हैं। इसके अलावा, ई ओ यू द्वारा जी टी ए स्वीकृति लागू उत्पाद शुल्कों करों के लिए भी उत्तरदायित्व है। वे विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रक्षेत्रों के बाहर कार्य करते हैं जो उसी पारिस्थितियों में समान डी जी एक एककों के बिलकुल सदृश है।

- (iv) इस कारण से उपर्युक्त के आधार पर मैं यह मानता हूँ कि किसी विशेष क्षेत्र के एकक द्वारा विभिन्न मामलों में अलग अलग विशेषताओं के साथ एक अपवाद के रूप में जी टी ए को बिक्री का प्रावधान विशेष आर्थिक क्षेत्र एककों को विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 का व्यापक ढाँचे के संदर्भ को ध्यान में रखकर व्यापार निदान संबंधी उपायों के संदर्भ में एक घरेलू उत्पादक के रूप में विचार किए जाने के लिए न्यायोचित नहीं ठहरता है इस कारण से इस जांच में घरेलू उद्योगों का कार्यक्षेत्र केवल उन उत्पादों अर्थात् मैसर्स इंडो सोलर लिमिटेड (ई ओर यू) और जूपिटर पावर सोलर लिमिटेड, जिसमें ई ओ यू एक भी सामने नहीं पाया, तक ही सीमित है क्योंकि भौतिक रूप से डी टी ए में स्थित है। उन्मुखीकरण के माध्यम से विशेष व्यापार नीतियों द्वारा शासित किया जाता है।
- (v) विशेष आर्थिक क्षेत्र के तीन एककों को बाहर किए जाने के साथ, घरेलू उद्योग अब मैसर्स इंडो सोलर लिमिटेड और मैसर्स जूपिटर सोलर पावर लिमि. तक सीमित है जो सामूहिक रूप से डी टी ए में कुल घरेलू उत्पादन का 38 प्रतिशत उत्पादन करता है। आई एस एन ए की सहायता इसके प्रबंधन समिति के संकल्प के माध्यम से की गई है और बिना किसी विरोध के कारण दो आवेदक एकक भारतीय उद्योग का अधिकांश हिस्से की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण योग्य है।

विवरण	एकक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितंबर 2017 तक)	2017-18 (वार्षिक)
कुल भारतीय उत्पादन	मेगा वाट	170	206	587	421	842
घरेलू उद्योग का उत्पादन (आवेदक)	मेगा वाट	141	191	314	159	318
कुल भारतीय उत्पादन में घरेलू उद्योग के उत्पादन का हिस्सा	%	83	93	53	38	38

- (vi) मैं यह देखता हूँ कि कुछ मॉड्यूल निर्माताओं जिन्होंने सैल का आयात किया है, घरेलू उद्योग के भाग के रूप में विचार किये जाने के लिए अनुरोध किया है। चूंकि "विचाराधीन उत्पाद" जिसका अपने आप में समग्र रूप में मॉड्यूलस में परिवर्तित किए जाने के लिए आयात किया जा रहा है, इस प्रकार के प्रतिष्ठान केवल आयातक के रूप में और न कि घरेलू उद्योग के भाग के रूप में योग्य हैं। सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उपधारा (6) के खंड (ख) के संबंध में उपर्युक्त पैरा (v) में यथाउल्लिखित दो उत्पादक घरेलू उद्योग होते हैं।

ग) जांच की अवधि

28. सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 और रक्षोपाय संबंधी उक्त नियमावली एवं विश्व व्यापार संगठन एक करार और गैट का अनुच्छेद XIX जांच की अवधि के संबंध में न तो परिभाषित करते हैं और न ही मार्गदर्शन देते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि घरेलू बाजार स्थितियां, घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन आदि जैसे विभिन्न संगत कारकों के आधार पर निकाले जाने के लिए उचित निष्कर्षों की अनुमति देने के लिए समुचित रूप से लंबा और पर्याप्त रूप से समय के मामले में हालिया होना चाहिए कि क्या बड़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तव में गंभीर क्षति हो रही है अथवा होने का खतरा है और इस कारण से यह रक्षोपाय शुल्क लगाये जाने की आवश्यकता को सही ठहराता है। इस आधार पर, वर्तमान मामले में 2014-2015 से 2017-2018 (वार्षिक) के रूप में जांच की अवधि (पी ओ आई) का निर्धारण करने के लिए तर्कसंगत और उचित माना गया है।

घ) सूचना का स्रोत

29. जांच आरंभन के समय घरेलू उद्योग ने विचारणीय उत्पाद के लिए लेन देन वार आयात आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिसका स्रोत (i) वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), वाणिज्यिक विभाग, भारत सरकार द्वारा 2014-2015 से 2017-2018 की पहली तिमाही के अंत तक की अवधि के लिए और (ii) 2017-2018 की दूसरी तिमाही (जुलाई 2017 से सितंबर 2017 तक) की अवधि के लिए मैसर्स इंडोड्राइव इण्डिया, नई दिल्ली है। स्वयं घरेलू उद्योग के संबंध में 2014-2015 से 2017-2018 (सितंबर 2017 तक) की अवधि के लिए समान आंकड़े आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और उसका सत्यापन जांच आरंभन के समय उत्पादन, बिक्री, माल सूची आदि के संबंध में उनकी (i) लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट (ii) वित्तीय अभिलेख (iii) विभिन्न अन्य अभिलेख के आधार पर किया गया था। इसके अलावा, जुलाई 2017 से सितंबर 2017 तक की अवधि के लिए आयात आंकड़े प्रारंभिक जांच परिणाम के चरण में डी जी सी आई एंड एस, वाणिज्यिक मंत्रालय, कोलकता से पृथिक रूप से प्राप्त की गई थी। इन आंकड़ों पर विचार प्रारंभिक जांच परिणाम के लिए विश्लेषण हेतु किया गया था। बाद में क्षति की समय अवधि अर्थात् 2014-2015 से 2017-2018 के लिए लेन देन वार आंकड़े अंतिम जांच परिणाम के लिए डी जी सी आई एंड एस से मांगे गए थे और उसे क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के पहुंच मूल्य का परिकलन करने के लिए अपनाया गया है।

ऊ) गोपनीय एवं प्रस्तुत सूचना

30. घरेलू उद्योग ने गोपनीय आधार पर अपने आवेदन में कुछ सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं और यह अनुरोध किया है इसे गोपनीय के रूप में माना जाए। घरेलू उद्योग ने महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा फाईल संख्या डी-2201/75/2009 के अंतर्गत जारी दिनांक 21.12.2009 के व्यापार नोटिस के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत यथाअपेक्षित अपने आवेदन का अगोपनीय पाठ एन सी वी भी उपलब्ध कराया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने इस सूचना की गोपनीयता के अपने दावे को न्यायोचित ठहराते हुए कारणों को भी प्रस्तुत किया है।
31. उक्त नियमावली के नियम 7 के संबंध में, आवेदक सूचना को प्रकट नहीं करने का विकल्प ले सकते हैं जो प्रकृति से गोपनीय है और उसका एक अगोपनीय सार उपलब्ध करा सकते हैं। घरेलू उद्योग ने सूचना की गोपनीयता का दावा करने के लिए कारणों को प्रस्तुत किया है और गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का एक अगोपनीय सार प्रस्तुत किया। घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कारणों की ध्यानपूर्वक जांच किए जाने पर, मैं यह पाता हूं कि ये कारण उक्त नियमावली के नियम 7 की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। तदनुसार, आवेदकों द्वारा दावा की गई गोपनीयता को एकक द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

च) आयात की प्रकृति और मात्रा

क) स्वतंत्र रूप में

विचाराधीन उत्पाद का आयात चीन जन. गण., मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान सहित विभिन्न देशों से किया जा रहा है। विचाराधीन उत्पाद का बड़ी मात्रा में आयात चीन जन. गण. से किया जा रहा है। जैसा कि देखा जा सकता है विचाराधीन उत्पाद की आयात की मात्राओं में 2014-2015 में 1275 मेगावाट से 2017-2018 में 9833 मेगावाट (वार्षिक) तक वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 के लिए डी जी सी आई एस के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात 9790 मेगावाट है। यह आधार वर्ष 2014-2015 से 2017-2018 में 671 प्रतिशत (वार्षिक) (वास्तविक के अनुसार 688 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस प्रकार से इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयात की मात्राओं में प्रत्येक वर्ष बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 2017-2018 के प्रथम 6 महीने के दौरान आयात की मात्रा में अचानक उछाल आया है जो 2016-2017 में आयातों का 77 प्रतिशत है। 2014-2015 से 2017-2018 की अवधि (वार्षिक) के दौरान स्वतंत्र रूप में और प्रतिशत रूप में विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती हुई आयात मात्रा नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गई है :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (2017 सितंबर तक)	2017-18 (वार्षिक)	2017-18 (वास्तविक)
कुल आयात	मेगा वाट	1,275	4,186	6,375	4,917	9,833	9790
पिछले वर्ष की तुलना में आयातों में वृद्धि का	%	-	228	52	-	54	

प्रतिशत							54
---------	--	--	--	--	--	--	----

ख) सापेक्ष

घरेलू उत्पादन की तुलना में विचाराधीन उत्पाद का आयात 2014-2015 और 2017-2018 (वार्षिक) के बीच सतत रूप से वृद्धि हुई पाई गई है। घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार के आयातों की वृद्धि दर बीच की अवधि अर्थात् वर्ष 2015-16 के दौरान उल्लेखनीय 2036 प्रतिशत रही थी। घरेलू उत्पादन की तुलना में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की समग्र वृद्धि दर बहुत अधिक है अर्थात् 2014-15 में 750 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 1169 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार से जांच की समग्र अवधि के दौरान, अपने घरेलू उत्पादन की तुलना में विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्राओं में सतत रूप से बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (2017 सितंबर तक)	2017-18 (वार्षिक)
कुल आयात	मेगा वाट	1,275	4,186	6,375	4,917	9,833
भारतीय उत्पादन	मेगा वाट	170	206	587	421	842
भारतीय उत्पादन का प्रतिशत के रूप में आयात	%	750	2036	1086	1169	1169

- वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान वास्तविक आयातों के आधार पर भारतीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात ---- बनते हैं ।

छ. अप्रत्याशित घटनाक्रम

32. मैं इस संबंध में प्रारंभिक निश्चरण में इस जांच परिणाम का स्मरण करता हूं और इसे पुनः प्रस्तुत करता हूं।

"5.8.1 न तो सीमा प्रथुलक अधिनियम 1975 की धारा 8ख और न ही उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली महानिदेशक (रक्षोपाय) पर अप्रत्याशित घटनाक्रम जिसके फलस्वरूप बड़े हुए आयात हुए हैं, पर कोई बाध्यता डालता है। कानूनी प्रावधानों न तो कोई ऐसा मानदंड है जिसका सत्यापन अप्रत्याशित घटनाक्रम की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए और न ही वे किसी पद्धति का उल्लेख करते हैं जिसका पालन इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाओं के विश्लेषण में किया जाना चाहिए। हालांकि, गैट का अनुच्छेद XIX के साथ पठित रक्षोपायों संबंधी विश्व व्यापार संगठन का करार राष्ट्रीय प्राधिकारियों पर "अप्रत्याशित घटनाक्रमों" की जांच करने का दायित्व डालता है जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग को परिणामी गंभीर क्षति हुई। इस अपेक्षा को देखते हुए, यह निदेशालय अपनी जांचों में 'अप्रत्याशित घटनाक्रम' के मुद्दे की सतत रूप से जांच करता रहा है। इस कारण से वर्तमान मामले में भी, इसे उपयुक्त माना गया है कि उन अप्रत्याशित घटनाक्रमों अथवा परिस्थितियों की जांच की जाये जिसके फलस्वरूप जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि, ऐसा करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि "अप्रत्याशित घटनाक्रम अथवा परिस्थितियों" शब्दावली के आयात को सर्वप्रथम समझा जाये और इसके लिए विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय के विभिन्न फैसलों का संदर्भ लिए जाने की आवश्यकता है।

"5.8.2 अर्जेंटीना - फुटवियर (ई सी) वाद में विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय निकाय ने यह माना कि ऐसी बड़ी हुई मात्राओं और इस प्रकार की परिस्थितियों में आयात जिससे घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हो अथवा क्षति होने का खतरा हो, की प्रत्याशा लगाई गई होगी। उस मामले में यह भी माना गया था कि बड़े हुए आयातों का विकास "अप्रत्याशित घटनाक्रमों" के कारण हुई होगी। इसी प्रकार से कोरिया-डेयरी वाद में विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय निकाय ने यह माना कि अप्रत्याशित घटनाक्रम वे घटनाक्रम हैं जिनका पूर्व में अनुमान अथवा जिसकी प्रत्याशा पूर्व में नहीं की जा सकती है, जब सदस्य ने उस दायित्व को प्राप्त किया। उस स्थिति में इस को भी माना गया था कि अप्रत्याशित घटनाक्रम वे परिस्थितियां हैं जिन्हें वास्तव में अवश्य दर्शाया जाना चाहिए। एक अन्य मामले में यू एस - स्टील रक्षोपाय संबंधी पैनल ने यह निष्कर्ष निकाला कि अनेक घटनाओं का एक साथ प्रभाव अप्रत्याशित घटनाक्रम का आधार बनाने के लिए एक हो सकता है। यह भी नोट किया गया था कि बड़े हुए

आयात अप्रत्याशित घटनाक्रम का परिणाम होना चाहिए अर्थात् यह अप्रत्याशित घटनाक्रम है जिसके फलस्वरूप आयात में वृद्धि हुई।

"5.8.3 वर्तमान मामले में उपरोक्त जांच परिणामों को लागू करते हुए यह स्पष्ट है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में विधि की क्षणिक प्रवृत्ति जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा जो इस प्रकार की गंभीर क्षति के खतरे को उत्पन्न करता है, का अनुमान नहीं लगाया गया होगा अथवा यह अप्रत्याशित और वास्तविक रहा होगा। जबकि स्वयं बड़े हुए आयातों की घटना आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर दर्शाने योग्य होना चाहिए, इसके अप्रत्याशित होने की प्रकृति के संबंध में जांच परिणाम संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान मामले में इसके लिए एक संगत प्रसंग वह घटना अथवा घटनाएं होंगी जिसके फलस्वरूप भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात पर प्रशुल्क रियायतें दी गईं। अन्य शब्दों में, जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के बड़े हुए आयातों की सत्यता दावेतु ग्रहण करते समय, अर्थात् विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न करारों के अंतर्गत प्रतिवद्धताओं का पालन करने का संकल्प लेते समय, प्रशुल्क रियायतें देते समय और बाद में 13 दिसंबर, 1996 को सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों (आई टी ए-1) के व्यापार संबंधी मंत्रालय की घोषणा के माध्यम से उन प्रशुल्क रियायतों में संशोधन करते समय अर्थात् विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनते समय अप्रत्याशित रही होगी।

"5.8.4 निर्धारण किए जाने के संदर्भ में यदि जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में बहुत अधिक और तीव्र वृद्धि का वर्तमान घटनाक्रम वास्तव में अप्रत्याशित घटनाक्रम था तब आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्यों की जांच की गई है और उनके संबंध में जांच परिणाम नीचे दिए गए हैं।

- (i) चीन ने 2012 में 11.12 गीगावाट की सोलर सैल की अपनी उत्पादन क्षमता को दुगुना करते हुए 2016 में 27.78 गीगावाट तक पहुंचा दिया है। उसी प्रकार से सोलर मॉड्यूल की उत्पादन क्षमता में 2012 में 12.46 गीगावाट से बढ़कर 2016 में 35.47 गीगावाट हो गया। इसके अलावा, 35 उत्पादकों जिनका चीन में सोलर मॉड्यूल के उत्पादन का 67 प्रतिशत और सोलर सैल के उत्पादन का 57 प्रतिशत के आंकड़े अत्यधिक क्षमता को दर्शाते हैं जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। भारी उत्पादन आधार होने के साथ साथ अतिरिक्त क्षमता के पहलू का आवेदक के मामले पर प्रभाव पड़ता है कि चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में अचानक वृद्धि हुई है।

सोलर सैल					
गीगावाट में	2012	2013	2014	2015	2016
क्षमता (सैल)	16.70	19.30	22.19	26.46	33.13
उत्पादन (सैल)	11.12	14.03	18.54	22.72	27.78
घरेलू खपत	10.68	13.06	17.31	22.26	26.76
निर्यात	0.40	0.81	0.87	0.52	0.50
निष्क्रिय क्षमता	33.41%	27.31%	16.49%	14.13%	16.15%
सोलर मॉड्यूल					
क्षमता (सोलर मॉड्यूल)	20.13	22.77	27.99	34.71	46.40
उत्पादन (सोलर मॉड्यूल)	12.46	16.32	22.07	28.79	35.47
घरेलू खपत	2.46	5.94	7.73	12.86	20.69
निर्यात	9.61	10.39	13.64	15.62	13.93
निष्क्रिय क्षमता	38.10%	28.32%	21.15%	17.05%	23.99%
उत्पादन में निर्यात का हिस्सा	77.12%	63.66%	61.80%	54.25%	39.27%

- (ii) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में चीन का निर्यात उन्मुखीकरण पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है परंतु यह एक वास्तविक सत्य है जो पिछले दो वर्षों के दौरान हुआ है, इसकी दिशा और निर्यात व्यापार की मात्रा दोनों में भारत के प्रति बहुत महत्वपूर्ण तरीके से परिवर्तन हुआ है जो नीचे दी गई तालिका से सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए जब भारत में चीन का आयात 2012 के दौरान इसके कुल वैश्विक निर्यात का मामूली 1.52 प्रतिशत था तब 2016 के दौरान इसमें 21.58 प्रतिशत वृद्धि हुई।

निम्नलिखित में चीन का निर्यात (अमरीकी डालर हजार में)	2012	2013	2014	2015	2016
विश्व	12,775,263	10,150,759	12,319,183	12,938,427	11,347,462
जापान	892,923	2,794,236	4,394,922	3,341,833	2,558,724
भारत	193,756	510,278	488,619	1,356,754	2,448,216
यू एस ए	1,416,963	1,208,074	1,818,175	1,634,799	1,368,664
यूरोपीय संघ	8,283,128	2,914,197	2,352,842	2,054,177	1,288,605
भारत का हिस्सा	1.52%	5.03%	3.97%	10.49%	21.58%
यूरोपीय संघ + यू एस ए का हिस्सा	75.93%	40.61%	33.86%	28.51%	23.42%

- (iii) भारत में विचाराधीन उत्पाद चीन के निर्यात की दिशा में उपर्युक्त परिवर्तन की पुनः पुष्टि अपेक्षाकृत अधिक वर्तमान समय के आंकड़ों से हो जाती है। जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, 2016 की पहली छमाही (एच1 2016) के दौरान, भारत में चीन का निर्यात इसके कुल निर्यात का 18.51 प्रतिशत था जिसकी तुलना में यूरोपीय संघ और यू एस ए में इसका मिश्रित निर्यात 30.65 प्रतिशत (इसके कुल निर्यात का) था। इस स्थिति में बाद के दो अर्ध वार्षिक अवधियों के दौरान नाटकीय ढंग से बदलाव आया। 2016 की दूसरी छमाही में (एच2 2016), भारत में चीन का निर्यात 25.09 प्रतिशत था जबकि यूरोपीय संघ और यू एस ए में इसका निर्यात गिरकर 15.12 प्रतिशत हो गया। पुनः 2017 की पहली छमाही में (एच1 2017), भारत में चीन के निर्यात में इसके कुल निर्यात का 38.7 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि यूरोपीय संघ और यू एस ए में इसका निर्यात सिकुड़कर केवल 5 प्रतिशत (इसके कुल निर्यात का) हो गया। व्यापार के पैटर्न में इस प्रकार का महत्वपूर्ण बदलाव जिसमें चीन ने यूरोपीय संघ और यू एस ए आदि जैसे विकसित देशों/ बाजारों की तुलना में अधिक कठोरता से भारतीय बाजार को लक्ष्य बनाना शुरू किया, का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था।

निम्नलिखित में चीन का निर्यात (अमरीकी डालर हजार में)	H1 2016	H2 2016	H1 2017
विश्व	6,062,679	5,284,783	5,350,966
भारत	1,122,083	1,326,133	2,074,573
जापान	1,219,493	1,339,231	1,095,773
यूरोपीय संघ	838,606	450,002	233,481
यू एस ए	1,019,870	348,793	34,268
भारत का हिस्सा	18.51%	25.09%	38.77%

यूरोपीय संघ + यू एस ए का हिस्सा	30.65%	15.12%	5.00%
---------------------------------	--------	--------	-------

"5.8.5 एक अन्य अप्रत्याशित घटनाक्रम जिसके कारण भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में उछाल आया और अन्य विदेशी बाजारों से परिवर्तित होना चीन से आयातों पर यूरोपीय संघ और यू एस ए द्वारा व्यापार निदान उपायों को लगाना था। (i) क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टेइक (सी एस पी वी 1) जांच 7.12.2012 को लागू हुआ और (ii) सी एस पी वी 2 जांच 18.2.2015 को प्रभावी हुआ, के साथ साथ यू एस ए में पाटनरोधी और प्रतिकर शुल्क आदेश लागू हुए। इसके अलावा, यूरोपीय संघ में अंतिम उपाय 5.6.2013 को लागू हुआ (आयोग विनियमन (ई यू) संख्या 513/2013 दिनांक 4.6.2013)। इन उपायों का तत्काल प्रभाव जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जे एन एम एस एम) के अंतर्गत घरेलू विषय वस्तु आवश्यकता (डी सी आर) की आवश्यकता के कारण नहीं देखी गई थी। इस प्रकार से घरेलू उद्योग को डी सी आर द्वारा आदेशित सीमा तक एक केप्टिव घरेलू बाजार का आश्वासन मिला था। हालांकि, 2013 में यू एस ए ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय के समक्ष जे एन एन एस एम के अंतर्गत जी सी आर को चुनौती दी और परिणाम यह निकला कि अक्टूबर 2016 में, विश्व व्यापार संगठन के अपील निकाय ने डी सी आर को गैट 1995 के अनुच्छेद 11.4 और टी आर आई एम करार के अनुच्छेद 2.1 के अनुरूप नहीं माना। इस कारण से भारत में डी सी आर को वापस ले लिया। डी सी आर को वापस लिए जाने के अनुसरण में, व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन विचाराधीन उत्पाद के आयात के बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने के साथ अधिक स्पष्ट हो गया जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, इन घटनाक्रमों का अनुमान नहीं लगाया जा सका।

"5.8.6 2015 में भारत ने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दूर करने के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस करार में 2005 के स्तरों से 33-35 प्रतिशत तक सी ओ 2 के उत्सर्जन में कमी करने की प्रतिबद्धता की थी। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, भारत वर्ष 2022 तक सौर पावर उत्पादन का 100 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। इस प्रतिबद्धता के कारण भारत में सौर पावर उत्पादन परियोजनाओं के लिए मांग में वृद्धि हुई। यह स्पष्ट है कि पेरिस करार के अंतर्गत भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता जिस पर 197 देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था (आज की स्थिति के अनुसार 172 देशों द्वारा उसकी पुष्टि की गई) उस समय अप्रत्याशित था जब विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात प्रशुल्क रियायतों पर 13 दिसंबर, 1996 को आई टी ए-1 के अंतर्गत सहमति दी गई थी। उसी प्रकार से एक लघु अवधि में भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में भारी वृद्धि जिसने आंशिक रूप में आयातों में उछाल में योगदान किया, भी अप्रत्याशित थी।

"5.8.7 एक अन्य संगत कारक जो उभरकर सामने आया है यह है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात बहुत कम कीमतों पर हो रहे हैं; आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के पहुंच मूल्य में अचानक और उल्लेखनीय गिरावट हुई है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है। इसका तत्काल प्रभाव यह हुआ है कि घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादों की बिक्री के कारण होने वाली प्रामि में गिरावट का सामना किया। इस प्रकार से आयातों और घरेलू उत्पादन के बीच घरेलू उत्पादन के लिए असुविधा पैदा करते हुए प्रतिस्पर्धी संबंध में सतत रूप से गिरते हुए पहुंच मूल्य पर आयातों में उछाल के कारण बदलाव हुआ। इससे घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धा करने और विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने और उसकी बिक्री करने की क्षमता बाधित हुई है। यह स्पष्ट ही है कि प्रतिस्पर्धी संबंध में यह परिवर्तन पूर्ण रूप से अप्रत्याशित था।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (2017 सितंबर तक)	2017-18 (वार्षिक)
आयात की गई लैंडेड मूल्य						
सोलर सैल	रु./ वाट	18.78	18.81	15.42	14.04	14.04
सोलर मॉड्यूल	रु./ वाट	36.95	36.18	29.20	24.77	24.77
घरेलू उद्योग में कुल बिक्री						
सोलर सैल (इंडेक्स)	रु./ वाट	100	94	88	62	62
सोलर मॉड्यूल	रु./ वाट	100	103	82	92	92

(इंडेक्स)						
-----------	--	--	--	--	--	--

“5.8.8 सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की सीमा प्रशुल्क मद 854 14011 के अंतर्गत आने वाले विचाराधीन उत्पाद पर भारत का आयात प्रशुल्क “निशुल्क” है। इस “निशुल्क” प्रशुल्क को दिनांक 13 दिसंबर, 1996 के सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद का व्यापार (इसके पश्चात ‘आई टी ए-1’ के रूप में भी संदर्भित) संबंधी मंत्रालय की घोषणा के साथ पठित गैट 1994 जिसमें उसके अंतर्गत प्रशुल्क रियायत शामिल हैं, के अंतर्गत भारत पर दायित्वों के अनुसरण में आरंभ किया गया था। विचाराधीन उत्पाद को आई टी ए-1 के संलग्नक क, धारा 1 के अंतर्गत शामिल किया गया है। आई टी ए-1 ने उसमें सूचीबद्ध उत्पादों पर गैट 1994 के अनुच्छेद 11:1 के आशय के भीतर किसी प्रकार का सीमा शुल्क और अन्य शुल्क/प्रभार को समाप्त करने का अधिदेश दिया। चूंकि भारत आई टी ए-1 का एक हस्ताक्षरकर्ता है अतः विचाराधीन उत्पाद के आयात सीमा शुल्क से मुक्त हैं। इस प्रकार आई टी ए-1 आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारत की “कार्रवाई की स्वतंत्रता” को सीमित कर देता है और इसे विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप अन्य उपायों जैसे सीमा शुल्क में वृद्धि से इसे रोक देता है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भारत का वास्तव में यह विश्वास था कि जे एन एन एस एम के अंतर्गत इसका डी सी आर गैट 1994 के अनुच्छेद XX में निहित अपवादों के अनुरूप था परंतु 2016 में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय द्वारा इस कदम को अस्वीकार किए जाने के बाद विचाराधीन उत्पाद के लिए भारत का बाजार सभी देशों से अप्रतिबंधित आयातों के लिए खुल गया। इस प्रकार घरेलू उत्पादन को वरियता दिए बिना विचाराधीन उत्पाद का अप्रतिबंधित प्रशुल्क मुक्त आयातों को अनुमति देने के लिए गैट 1994 और आई टी ए-1 के अंतर्गत भारत के दायित्व के कारण भारत में विचाराधीन उत्पाद आयात मात्राओं में बहुत अधिक और अप्रत्याशित वृद्धि हुई।

“5.8.9 निष्कर्ष यह है कि जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में अचानक और तीव्र वृद्धि विभिन्न वैश्विक और घरेलू घटनाक्रमों के एक साथ होने का परिणाम है, उनमें से सभी अप्रत्याशित और अनुमान न लगाये जाने वाले थे। स्पष्टता के उद्देश्य से, इन अनुमान न लगाये जाने वाले और अप्रत्याशित घटनाक्रमों को संक्षेप में नीचे दिए गए अनुसार दोहराया जाता है

- (i) जब यूरोपीय संघ और यू एस ए को निर्यात में बाधाओं का सामना करना पड़ा तब चीन की विचाराधीन उत्पाद का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन और अतिरिक्त क्षमताएं जो अन्य प्रकार से भी निर्यात उन्मुख हैं, को एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश करनी पड़ी जो उन्होंने भारत में पाया।
- (ii) चीन से यूरोपीय संघ और यू एस ए में आयात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद पर संरक्षणवादी उपाय लगाने से चीन का निर्यात केंद्र भारत की ओर हो गया।
- (iii) जे एन एन एस एम के अंतर्गत भारत के डी सी आर को यू एस ए द्वारा चुनौती, जिसके फलस्वरूप विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय ने डी सी आर को गैट 1994 का अनुच्छेद 11:4 और टी आर आई एम के करार का अनुच्छेद 2.1 के अनुरूप नहीं मानने के कारण इसने अपना नाम वापस ले लिया और इसके कारण घरेलू उद्योग को बाजार की कमी को पूरा करने के लिए आयातों में परिणामी उछाल आया।
- (iv) 1915 में पेरिस करार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ने घरेलू प्रतिबद्धता के लिए विचाराधीन उत्पाद के उपयोग में वृद्धि करने का मार्ग प्रशस्त किया जो अन्य घटनाक्रमों के साथ आयातों में उछाल लाया।
- (v) प्रतिस्पर्धी समीकरण में परिवर्तन लाने के लिए तथा घरेलू उद्योग को असुविधाजनक स्थिति पैदा करने जिसे उनमें दर्शाया गया था अर्थात् घरेलू उद्योग आयातों के कारण विचाराधीन उत्पाद का अपना घरेलू बाजार का हिस्सा खो दिया, के अन्य कारकों के साथ साथ विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते हुए आयातों की गिरती हुई पहुंच कीमत।
- (vi) गैट 1994 और आई टी ए-1 के अंतर्गत भारत के दायित्व के कारण विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर इसका सीमा प्रशुल्क “निशुल्क” किया जा रहा है।

“5.8.10 उपर्युक्त विभिन्न वैश्विक और घरेलू अनुमान न लगाये जाने वाले और अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप, भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में निःसंदेह सत्यापित उछाल आया है। आयातों में इस उछाल ने घरेलू उद्योग के लिए असुविधा स्थिति पैदा करते हुए आयात किये गये और घरेलू तौर पर उत्पादित विचाराधीन उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धी संबंध में बहुत अधिक संशोधन किया है।

33. **प्रारंभिक जांच परिणाम और सार्वजनिक सुनवाई के बाद :** अनेक हितवद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि अप्रत्याशित तरह का सूचित घटनाक्रम वास्तव में प्रत्याशित प्रकृति का है। स्पष्टता के वास्ते, इन मुद्दों की जांच की गई यद्यपि कुछ स्थानों पर विश्लेषण की पुनरावृत्ति हो सकती है जो इन तर्कों पर बल देने तथा उन्हें स्पष्ट करने के लिए किया गया है।
34. मैंने सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और भारतीय रक्षोपाय नियमावली के प्रावधानों की जांच की है। इन दोनों में से कोई भी प्रावधान मुझ पर इस तथ्य का विश्लेषण करने का दायित्व नहीं सौंपते हैं कि (i) अप्रत्याशित घटनाक्रम; और (ii) इस करार के अंतर्गत संविदा करने वाले पक्षकार द्वारा किए गए दायित्वों का प्रभाव जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है। कानूनी प्रावधानों में न तो कोई ऐसा मानदंड है जिसका सत्यापन अप्रत्याशित घटनाक्रमों की पहचान करने के लिए अवश्य किया जाना चाहिए और न ही वे किसी पद्धति का उल्लेख करते हैं जिसका पालन इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाक्रमों के विश्लेषण में अवश्य किया जाना चाहिए। हालांकि, मैं यह मानता हूँ कि गैट के अनुच्छेद XIX के साथ पठित रक्षोपाय संबंधी विश्व व्यापार संगठन का करार राष्ट्रीय प्राधिकारियों को दोनों कारकों जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग पर परिणामी गंभीर क्षति हुई, की जांच करने के लिए दायित्व सौंपता है। इस आवश्यकता को देखते हुए, महानिदेशालय रक्षोपाय ने सतत रूप से अपनी जांचों में 'अप्रत्याशित घटनाक्रमों' और 'गैट के अंतर्गत प्राप्त किए गए दायित्वों' के मुद्दे की जांच करता रहा है। इस कारण से वर्तमान मामले में भी मैं इन दोनों कारकों जिसके कारण विचाराधीन उत्पाद के आयातों में तेजी से वृद्धि हुई, की जांच इस जांच की अवधि के दौरान करना उपयुक्त मानते हूँ।
35. आरंभिक जांच परिणाम विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न अपीलीय निकायों की रिपोर्टों और पैनल की रिपोर्टों में निर्धारित कानूनी मानदंड को रिकार्ड करते हैं। मैंने विस्तृत रूप में उसकी और हितवद्ध पक्षकार द्वारा दिए गए विभिन्न तर्कों की जांच की है। मैं यह मानता हूँ कि कानूनी परीक्षण सही ढंग से संक्षिप्त रूप में दिया गया है। संदर्भ की सुविधा के लिए, उसका पुनः उल्लेख किया जाता है। प्रारंभिक जांच परिणाम में अर्जेन्टीना – फुटवियर (ई सी)8 में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय पर विश्वास किया है जिसमें यह माना गया था कि इस प्रकार से बड़ी हुई मात्राओं में और इस प्रकार की स्थितियों में आयात जिससे घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है अथवा होने का खतरा है, निश्चित रूप से अप्रत्याशित रहा होगा। उस स्थिति में भी यह भी माना गया था कि बड़े हुए आयातों का घटनाक्रम 'अप्रत्याशित घटनाक्रम' के कारण हुआ होगा। उसी प्रकार से कोरिया – डेयरी9 वाद में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय ने यह माना कि अप्रत्याशित घटनाक्रम वे घटनाक्रम हैं जिनका पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता है अथवा जो प्रत्याशित नहीं है जब सदस्य ने उस दायित्व को प्राप्त किया। अपीलीय निकाय द्वारा यह भी माना गया था कि अप्रत्याशित घटनाक्रम वे परिस्थितियाँ हैं जिन्हें वास्तव में अवश्य दर्शाया जाना चाहिए।
36. हितवद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अप्रत्याशित घटनाक्रम वह नहीं है जो विशिष्ट मध्यस्थों के मस्तिष्क में था बल्कि यह वह है जो उनके मस्तिष्क में (तार्किक रूप से) आ सकता था। इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रकार का दृष्टिकोण विश्लेषण का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। यू एस – स्टील रक्षोपाय10 में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट और पैनल की रिपोर्ट11 जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अनेक घटनाक्रमों का एक साथ प्रभाव पड़ने से अप्रत्याशित घटनाक्रम का आधार बन सकता है, की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। यह भी नोट किया गया था कि बड़े हुए आयात अप्रत्याशित घटनाक्रम के परिणाम होने चाहिए अर्थात् यह अप्रत्याशित घटनाक्रम है जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है। संदर्भ की सुविधा के लिए इन टिप्पणियों को फिर से प्रस्तुत किया जाता है :

10.99 अनुच्छेद XIX में "अप्रत्याशित घटनाक्रम" के रूप में अनेक घटनाक्रमों का एक साथ प्रभाव पड़ने के संबंध में विचार करने का प्रावधान नहीं है। तदनुसार, पैनल का यह मानना है कि घटनाक्रमों का एक साथ प्रभाव गैट 1994 के अनुच्छेद XIX के उद्देश्य से "अप्रत्याशित घटनाक्रम" का आधार बन सकता है। इस कारण से पैनल का यह दृष्टिकोण है कि प्रत्येक सदस्य को यह दर्शाना होगा कि परिस्थितियों जिसे यह उस समय जब इसने अपना प्रशुल्क समझौता किया था, अप्रत्याशित मानता है, का सह-प्रभाव के फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई और इसके कारण गंभीर क्षति हुई।

37. उपर्युक्त को देखते हुए मेरा यह मत है कि आरंभिक जांच परिणाम में विस्तृत रूप से उल्लेख किए गए अनेक घटनाक्रमों का एक साथ प्रभाव पड़ा है जो अप्रत्याशित घटनाक्रम होता है। इस समय मेरा यह मानना है कि अलग अलग पक्षकारों में प्रत्येक कारक का अलग अलग रूप से समाधान किया है, जिसका संक्षिप्त विवरण आरंभिक जांच परिणामों में किया था। हालांकि, इसके बारे में कोई अनुरोध नहीं किया गया है कि किस प्रकार से घटनाओं के सह-प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। उदाहरण के लिए हितवद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि व्यापार निदान संबंधी उपायों को आरोपित करने और कार्बन उत्सर्जनों में कटौती उस समय प्रत्याशित थी जब भारत में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय करारों पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, भारत इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता था कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य एक ही साथ चीन और कुछ अन्य देशों के विरुद्ध व्यापार निदान संबंधी उपाय अधिरोपित करेगा जो सी ओ पी 21 (पेरिस करार) के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं के कारण मांग में वृद्धि भी होगी।

38. वर्तमान मामले में उपरोक्त जांच परिणामों को लागू करते हुए यह स्पष्ट है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में विधि की क्षणिक प्रवृत्ति जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा जो इस प्रकार की गंभीर क्षति के खतरे को उत्पन्न करता है, का अनुमान नहीं लगाया गया होगा अथवा यह अप्रत्याशित और वास्तविक रहा होगा। जबकि स्वयं बढ़े हुए आयातों की घटना आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर दर्शाने योग्य होना चाहिए, इसके अप्रत्याशित होने की प्रकृति के संबंध में जांच परिणाम संदर्भ के अनुसार हो सकता है। मैं दोहराता हूँ कि इसका एक संगत प्रसंग वह घटना अथवा घटनाएं होंगी जिसके फलस्वरूप भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात पर प्रशुल्क रियायतें दी गईं। अन्य शब्दों में, जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों की सत्यता दायित्व ग्रहण करते समय, अर्थात् विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न करारों के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं का पालन करने का संकल्प लेते समय, प्रशुल्क रियायतें देते समय और बाद में 13 दिसंबर, 1996 को सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों (आई टी ए-1) के व्यापार संबंधी मंत्रालय की घोषणा के माध्यम से उन प्रशुल्क रियायतों में संशोधन करते समय अर्थात् विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनते समय अप्रत्याशित रही होगी। जबकि आई टी ए-1 का संदर्भ एक अप्रत्याशित घटना नहीं है, फिर भी गैट के अंतर्गत प्राप्त किया गया दायित्व एक अप्रत्याशित घटना है।
39. प्राथमिक जांच परिणाम में यह पाया गया था कि चीन ने सोलर सेलों की अपनी उत्पादन क्षमता 2012 में 11.2 गीगावाट से बढ़ाकर 2016 में 27.78 गीगावाट करके दोगुने से भी अधिक कर ली है। इसी प्रकार, सोलर मॉड्यूलों की उत्पादन क्षमता 2012 में 12.46 गीगावाट से बढ़कर 2016 में 35.47 गीगावाट हो गई।
40. हितबद्ध पक्षकारों ने आंकड़ों पर प्रश्न नहीं उठाया है। उन्होंने केवल यह तर्क दिया है कि चीन में घरेलू खपत वर्ष 2017 में उसके निर्यात से अधिक है। तथापि, ये अनुरोध चीन में बेकार क्षमता का हल करने और व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन लाने में विफल रहे।
41. प्राथमिक जांच परिणाम में यह पाया गया था कि पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात व्यापार की दिशा और मात्रा दोनों भारत की ओर काफी तरीके से परिवर्तित हुए हैं।
42. यह स्पष्ट है, यद्यपि चीन का भारत को निर्यात 2012 के दौरान उसके कुल वैश्विक निर्यात का आंशिक रूप से 1.52 प्रतिशत था, यह बढ़कर 2017 के दौरान 29.8 प्रतिशत हो गया (अद्यतन)।
43. प्राथमिक जांच परिणाम में मैंने पाया कि दूसरी अप्रत्याशित घटना, जिसने भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में उछाल में योगदान किया तथा अन्य विदेशी बाजारों से दूर गई, 2012 और 2013 में चीन से आयातों पर यूरोपीय संघ और यूएसए द्वारा व्यापार उपचार उपाय लगाना थी।
44. एक हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि अप्रत्याशित घटनाएं सुदूर विगत से संबंधित नहीं हो सकतीं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिन घटनाओं से आयात हुए हैं, वे अप्रत्याशित होनी चाहिए और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रश्नगत घटनाएं अप्रत्याशित क्यों थीं। इस संबंध में उत्तरदाताओं ने दावा किया है कि एक संविदाकार सदस्य यथा वर्तमान मामले के संदर्भ में यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा व्यापार उपचार उपायों का सहारा लेना उस समय अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता जब भारत जीएटीटी के तहत दायित्व और डब्ल्यूटीओ के तहत बहुपक्षीय करार कर रहा हो। अर्जेटीना – फुटबियर्स (ईसी) ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूटीओ अपीलिय निकाय की टिप्पणी यह स्पष्ट करते हुए कि आयात में उछाल जिस घटना से हुआ, वह अप्रत्याशित होनी चाहिए, इस संबंध में संगत है।
45. मैं प्राथमिक जांच परिणाम में निष्कर्षों/विचारों को दोहराता हूँ कि इन उपायों का तत्काल प्रभाव जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के तहत घरेलू मात्रा की आवश्यकताओं (डीसीआर) की अपेक्षा के कारण भारत में नहीं दिखाई दिए। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को डीसीआर द्वारा बताई गई सीमा तक कैप्टिव घरेलू बाजार का आश्वासन था। तथापि, 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय के समक्ष जेएनएनएसएम के तहत डीसीआर को चुनौती दी और परिणाम यह था कि अक्तूबर, 2016 में डब्ल्यूटीओ अपीलिय निकाय ने डीसीआर को ट्रिंस करार के अनुच्छेद 2.1 तथा जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद III:4 के असंगत माना। अतः भारत में डीसीआर को वापस ले लिया। डीसीआर की वापसी के अनुसरण में व्यापार पैटर्न में परिवर्तन काफी बढ़ रहे विचाराधीन उत्पाद के आयातों में अधिक उल्लेखनीय हो गए, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, ये घटनाएं अप्रत्याशित नहीं हो सकतीं।
46. 2015 में भारत वैश्विक वार्मिंग को हल करने के लिए कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन 2005 के स्तरों से 33-35 प्रतिशत तक कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस करार के प्रति प्रतिबद्ध था। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप भारत में वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर विद्युत उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य स्थापित किया। इस प्रतिबद्धता से भारत में सौर विद्युत परियोजनाओं की मांग बढ़ गई। यह स्पष्ट है कि पेरिस करार जिस पर 197 देशों ने हस्ताक्षर किए थे (आज की तारीख के अनुसार 172 देश) के तहत भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता 13 दिसंबर, 1996 को आईटीए-1 के तहत सहमत विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात प्रशुल्क छूट के समय अप्रत्याशित थी। इसी प्रकार, एक छोटे से समय में भारत ने विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में भारी वृद्धि जिसने आयात में उछाल को आंशिक रूप से बढ़ाया, भी अप्रत्याशित थी।

47. मैं नोट करता हूँ कि विचाराधीन उत्पाद के आयात काफी कम कीमतों पर हो रहे हैं; आयातित विचाराधीन उत्पाद के पहुँच मूल्य में अचानक एवं सराहनीय गिरावट आई है जो कि निम्नलिखित तालिका से सिद्ध है। इस तथ्य का किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विरोध नहीं किया है। इसका तत्काल प्रभाव यह रहा है कि घरेलू उद्योग की उनके उत्पादों की बिक्री वसूली में गिरावट आई। इस प्रकार, निरंतर गिर रही पहुँच कीमत पर आयातों में उछाल से आयातों और घरेलू उत्पादन के बीच प्रतिस्पर्द्धी संबंध में परिवर्तन आया जिससे घरेलू उद्योग को हानि हुई। इससे घरेलू उद्योग की क्षमता विचाराधीन उत्पाद का निर्माण एवं बिक्री तथा प्रतिस्पर्द्धी करने के लिए बाधित हुई। यह सिद्ध है कि प्रतिस्पर्द्धी संबंध में यह परिवर्तन पूर्णतः अप्रत्याशित था। आंकड़ों की यह प्रवृत्ति का विशेष उल्लेख प्रारंभिक जांच परिणाम में भी किया गया था।

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितं., 2017 तक)	2017-18 (वार्षिकीकृत)
आयातों का पहुँच मूल्य						
सोलर सेल	रु./वाट	18.96	18.99	15.58	13.61	13.61
सोलर मॉड्यूल	रु./वाट	36.18	36.53	29.49	22.63	22.63
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली						
सोलर मॉड्यूल (सूचीबद्ध)	रु./वाट	100	87	82	60	60

48. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की सीमा प्रशुल्क मद 85414011 के तहत आने वाले विचाराधीन उत्पादों पर भारत का आयात प्रशुल्क "निःशुल्क" है। यह "निःशुल्क" प्रशुल्क जीएटीटी 1994 के तहत भारत संबंधी दायित्वों के अनुसरण में शुरू किया गया था जिसमें 13 दिसंबर, 1996 के सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में व्यापार संबंधी सचिवालयी घोषणा (जिसे यहां आगे "आईटीए-1" भी कहा गया है) के साथ पठित उनके अधीन प्रशुल्क छूट शामिल है। विचाराधीन उत्पाद आईटीए-1 के संलग्नक-क, 1 के तहत शामिल है। आईटीए-1 उसमें सूचीबद्ध उत्पादों पर जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद 11:1(ख) के अभिप्राय से किसी भी किस्म के शुल्क/प्रभार तथा सीमा शुल्क को समाप्त करना अधिदेशित करता है। चूंकि, भारत आईटीए-1 पर हस्ताक्षरकर्ता है, अतः विचाराधीन उत्पाद के आयात सीमा शुल्क से मुक्त हैं। इस प्रकार, आईटीए-1 आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारत की "कार्टवाई की स्वतंत्रता"¹² को बाध्यकारी बनाता है और उसे सीमा शुल्क बढ़ाने जैसे अन्य डब्ल्यूटीओ संगत उपाय करने से रोकता है। भारत ने विश्वास किया कि जेएनएनएसएम के तहत उसका डीसीआर जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद XX में निहित अपवादों के संगत था, परंतु इस उपाय को 2016 में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय द्वारा रद्द किए जाने के बाद विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय बाजार सभी देशों से अप्रतिबंधित आयातों के लिए खुल गया। इस प्रकार, घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता दिए बिना विचाराधीन उत्पाद के अप्रतिबंधित प्रशुल्क मुक्त आयातों की अनुमति देने के लिए जीएटीटी 1994 और आईटीए-1 के तहत भारत के दायित्व से भारत में विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा में महत्वपूर्ण एवं अप्रत्याशित वृद्धि हुई।

इसलिए मैं यह दोहराता हूँ कि प्रारंभिक जांच परिणाम में सूचित अप्रत्याशित घटनाएं विश्लेषण की संवीक्षा में भी अप्रत्याशित ही है तथा अनेक घटनाओं और गैट के अनुच्छेद-XIX के प्रावधान और विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान के सम्मेलन के रूप में इन्हें अप्रत्याशित ही समझा जाता है।

¹² पैनल रिपोर्ट, उक्रेन – पैसेंजर कार्स, पैरा 7.96

([http://www.worldtradelaw.net/reports/wtopanels/ukraine-passengercars\(panel\).pdf.download](http://www.worldtradelaw.net/reports/wtopanels/ukraine-passengercars(panel).pdf.download))

ज) गंभीर क्षति तथा/अथवा गंभीर क्षति का खतरा

49. निर्धारण के लिए दूसरा मामला यह है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के काफी बढ़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और/अथवा समान अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्द्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने का खतरा है। अपनी प्रकृति में यह एक जटिल कार्य है क्योंकि घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद की क्षति विभिन्न मानदंडों का प्रकार्य है, यथा आयात, बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग की तुलना में घरेलू बाजार में उसका हिस्सा बताने के लिए कुछ है। इसके अतिरिक्त, यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी नकारात्मक मानदंड एक घटना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सतत प्रवृत्ति दर्शानी चाहिए। तदनुसार, नीचे दिए गए अनुसार विभिन्न संगत मानदंडों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की जा रही है कि क्या जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों से क्षति हुई है और/अथवा वे समान अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्द्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने का खतरा पैदा कर रहे हैं।

- (i) **घरेलू बाजार का हिस्सा:** घरेलू मांग में तीव्र विस्तार के बावजूद घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ है; घरेलू उद्योग का 2014-15 में 8 प्रतिशत हिस्सा था, जो घटकर 2017-18 (क) में 3 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि में आयातों का बाजार हिस्सा 90 प्रतिशत से बढ़कर 93 प्रतिशत हो गया।

बाजार हिस्सा	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितं., 2017 तक)	2017-18 (वार्षिकीकृत)
आयात	मे.वाँ.	1,275 (90%)	4,186 (96%)	6,375 (92%)	4,917 (93%)	9,833 (93%)
आवेदकों/घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बिक्री	मे.वाँ.	115 (8%)	178 (4%)	299 (4%)	157 (3%)	314 (3%)
अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा घरेलू बिक्री	मे.वाँ.	28 (2%)	15 (0.3%)	244 (4%)	235 (4%)	471 (4%)
कुल घरेलू बिक्री	मे.वाँ.	143 (10%)	193 (4%)	543 (8%)	392 (7%)	785 (7%)
घरेलू मांग	मे.वाँ.	1419 (100%)	4381 (100%)	6918 (100%)	5309 (100%)	10618 (100%)

- (ii) **बिक्री:** उपर्युक्त तालिका भी यह बताती है कि घरेलू उत्पादकों की बिक्री 115 मेगावाट से बढ़कर 314 मेगावाट अर्थात् 199 मेगावाट तक बढ़ी। तथापि, यह यह नोट करने का विषय है कि जब घरेलू बिक्री 199 मेगावाट तक बढ़ी तो आयात 8558 मेगावाट तक बढ़े। इस प्रकार आयातों में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि से अधिक थी। साथ ही, चूंकि घरेलू मांग 2014-15 में 1419 मेगावाट से बढ़कर 2017-18 (वार्षिकीकृत) में 10618 मेगावाट हो गई। अतः यह स्पष्ट है कि विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयात विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू मांग को पूरा करने में घरेलू उत्पादन के लिए प्रतिस्थापित हो गए।
- (iii) **उत्पादन:** घरेलू उद्योग का उत्पादन 2014-15 में 141 मेगावाट से बढ़कर 2017-18 (वार्षिकीकृत) में 318 मेगावाट हो गया। साथ ही यद्यपि विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा 2014-15 में 1275 मेगावाट से बढ़कर 2017-18 (वार्षिकीकृत) में 9833 मेगावाट हो गई अर्थात् उसी अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में बढ़ी हुई 176 प्रतिशत की तुलना में 671 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह निष्कर्ष निम्नलिखित तालिका में आंकड़ों के आधार पर है:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितं., 2017 तक)	2017-18 (वार्षिकीकृत)
कुल आयात	मेगावाट	1,275	4,186	6,375	4,917	9,833
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मेगावाट	141	191	314	159	318

- (iv) **क्षमता उपयोग:** घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 2014-15 में 48 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 (वार्षिकीकृत) में 85 प्रतिशत हो गया।

मांग में संवृद्धि के साथ तुलना करने पर जोकि वर्ष 2017-18 में बढ़कर 10618 मेगावाट हो गई, घरेलू उद्योग की कुल क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए था। बढ़ी हुई मांग के रहते भी 100 प्रतिशत से कम क्षमता यह सूचित करती है कि आयातित विचाराधीन उत्पाद को प्राथमिकता दी जाती है।

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितं., 2017 तक)	2017-18 (वार्षिकीकृत)
संस्थापित क्षमता	मेगावाट	292	373	373	185	373
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मेगावाट	141	191	314	159	318
क्षमता उपयोग	%	48	51	84	86	85

- (v) **रोजगार:** घरेलू उद्योग द्वारा सृजित रोजगार में वर्ष 2017-18 में मामूली सी गिरावट आई है लेकिन कुल मिलाकर यह स्थिर बनी रही है।

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितं., 2017 तक)
कर्मचारियों की संख्या (सूचीबद्ध)	100	108	106	99

- (vi) प्रति व्यक्ति उत्पादकता से वृद्धि की उसी प्रवृत्ति का पता चला है जोकि उत्पादन की वृद्धि रही है जिसमें अभी भी वृद्धि हो रही है। यह ऐसी परिस्थिति में प्रत्याशित होता है जब मांग और पूर्ति के बीच अत्यधिक अंतर व्याप्त होता है।

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितं., 2017 तक)	2017-18 (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग का उत्पादन (मेगावाट)	141	191	314	159	318
प्रति कर्मचारी उत्पादकता (मेगावाट)	0.290	0.365	0.607	0.329	0.660

- (vii) लाभ/हानि: विगत वर्ष और यहां तक कि क्षति अवधि के आधार वर्ष की तुलना में अप्रैल, 2017 से सितंबर, 2017 की अवधि के दौरान प्रति वाट उत्पादकता विकट रूप से प्रभावित हुई थी।

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितं., 2017 तक)
रु. वाट में हानि (सूचीबद्ध)	-100	-143	-22	-107

- (viii) **मालसूची:** घरेलू उद्योग द्वारा ली गई मालसूची जांच की अवधि के दौरान दोगुना से भी अधिक बढ़ी, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितं., 2017 तक)
अंतिम मालसूची (सूचीबद्ध)	100	114	243	251

- (viii) **कीमत कटौती:** निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार पूरी जांच की अवधि में आयातित सामानों से काफी कीमत कटौती हुई। यह स्पष्ट होता है कि कीमत कटौती के उच्च स्तर से घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को बढ़ाने से रोका गया है, जिसके फलस्वरूप उसको घाटे हुए हैं।

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितं., 2017 तक)	2017-18 (वार्षिकीकृत)
आयातों का पहुंच मूल्य						
सोलर सेल	रु./वाट	18.96	18.99	15.58	13.61	13.96
सोलर मॉड्यूल	रु./वाट	36.18	36.53	29.49	22.63	22.96
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली						
सोलर सेल (सूचीबद्ध)	रु./वाट	100	87	82	60	48
कीमत कटौती						
सोलर सेल (सूचीबद्ध)	रु./वाट	100	61	83	36	-4

झ क्षति मार्जिन और क्षति का खतरा

संरक्षण के स्तर की मात्रा का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत का परिकलन, 1.4.2017 से 30.9.2017 तक की अवधि के दौरान उसके द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद (सेल्स) के लिए किया गया है। उचित बिक्री कीमत (एफएसपी) निर्धारित करने के लिए उत्पादन की लागत में ब्याज रहित उत्पादन की लागत का उचित प्रतिलाभ जोड़ा गया है। क्षति मार्जिन का परिकलन आयातित सेल्स के पहुंच मूल्य और एफएसपी के बीच अंतर के रूप में किया गया है। उपरोक्त कार्यप्रणाली के अनुसार निर्धारित की गई क्षति मार्जिन की सीमा नीचे तालिका में दर्शायी गई है। जांच पश्चात अवधि के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि पहुंच मूल्य के साथ तुलना करने पर जांच पश्चात अवधि में उत्पादन की लागत और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) निरंतर कीमत ह्रास दर्शाती हैं। निरंतर कीमत कटौती के फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें घरेलू उद्योग पहुंच मूल्य से ऊपर कीमतें जुटाने में असमर्थ है। यह गंभीर खतरा है।

ट. कारणात्मक संबंध :

50. कोरिया डेयरी संबंधी डब्ल्यूटीओ पैनल¹³ ने "कारणात्मकता" निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित रूप में अपना मूल दृष्टिकोण निर्धारित किया:

"कारणात्मक संपर्क मूल्यांकन करने में हमारा यह मत है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी को यह विश्लेषण और निर्धारण करने की आवश्यकता है कि क्या गंभीर क्षति दर्शाने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा माने गए उद्योग में घटनाएं बड़े हुए आयातों से हुई हैं। अपने कारणात्मकता मूल्यांकन में राष्ट्रीय प्राधिकारी पर उस उद्योग की स्थिति पर बाधक बनने वाले वस्तुपरक एवं मात्रात्मक प्रकृति के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करने का दायित्व है। इसके अतिरिक्त, यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी ने बड़े हुए आयातों को छोड़कर अन्य कारकों की पहचान की है, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है तो वह सुनिश्चित करेगा कि इन कारकों से हुई कोई क्षति बड़े हुए आयातों के कारण हुई क्षति नहीं मानी गई है। कारणात्मक संपर्क स्थापित करने के लिए कोरिया को यह दर्शाना है कि उसके घरेलू उद्योग को क्षति बड़े हुए आयातों के परिणामस्वरूप है। दूसरे शब्दों में, कोरिया को यह दर्शाना है कि एसएमईपी के आयातों से मिल्क पाउडर और कच्चा मिल्क का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को क्षति होती है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने पर कोरिया प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे अन्य कारकों से हुई किसी क्षति को बड़े हुए आयातों के कारण न मानें।

51. 2014-15 से 2017-18 (सितंबर, 2017 तक) तक की अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात काफी उच्च स्तर पर रहे हैं और विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतें भी काफी नीचे आई हैं। इससे घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों कम करके संशोधित करनी पड़ी हैं जिससे बूट स्ट्रेपिंग होने की घटना का स्पष्ट पता चलता है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली में आधार वर्ष की तुलना में तेजी से गिरावट आई है। आयातों से काफी कीमत कटौती के परिणामस्वरूप घरेलू बिक्री कीमतों में काफी कीमत न्यूनीकरण होने का पता चलता है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

विवरण (सूचीबद्ध)		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (H1)
बिक्री प्राप्ति	रु./वाट	100	87	82	60
कीमत न्यूनीकरण (वर्ष-दर-वर्ष)	रु./वाट		100	37	173
कीमत न्यूनीकरण (संचयी))	रु./वाट		100	137	309
बिक्री की लागत	रु./वाट	100	95	74	86

लागत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)	रु./वाट		100	437	(248)
कीमत न्यूनीकरण (वर्ष-दर-वर्ष)	रु./वाट		100	(283)	509
कीमत वृद्धि रोकने की मात्रा	रु./वाट	100	142	22	238

52. इस संबंध में घरेलू उद्योग को बड़े हुए आयातों का कारण एवं प्रभाव संबंध और जांच की अवधि में भारी क्षति तथा भविष्य में भारी क्षति का खतरा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कारक भी संगत हैं:

- (i) आयातों की मात्रा पूर्ण दृष्टि से आधार वर्ष में 1275 मेगावाट से बढ़कर जांच अवधि में 9833 मेगावाट तक हो गई।
- (ii) आयातों का बाजार हिस्सा 90 प्रतिशत से बढ़कर 93 प्रतिशत हो गया और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 8 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गया।
- (iii) चूंकि, आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमतों पर उपलब्ध हैं और उस समय भी कम हो रहे हैं, अतः उपभोक्ता इस कारण आयातित विचाराधीन उत्पाद की ओर जा रहे हैं कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बनाए रखने में ही असमर्थ नहीं हैं, बल्कि उनके सामने बढ़ती हुई मालसूची (विचाराधीन उत्पाद की) की समस्या भी है।
- (iv) कम कीमतों पर बड़े हुए आयातों का दूसरा प्रभाव यह है कि घरेलू उद्योग भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग/खपत में वृद्धि की दर की तुलना में अपना उत्पादन और बिक्री बढ़ाने में असमर्थ हैं।
- (v) यद्यपि, घरेलू उद्योग सहित भारतीय उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्षमताएं स्थापित कीं, तथापि, निरंतर घटती हुई पहुँच कीमतों पर काफी बड़े हुए आयातों से बेकार उत्पादन क्षमताएं गिरती हुई बिक्री वसूली आदि हुई; और
- (vi) घरेलू उद्योग को अत्यधिक घाटे हो रहे हैं।

53. संक्षेप में ऊपर दर्शाए गए मानदंडों का व्यापक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को भारी क्षति हो रही है और विचाराधीन उत्पाद की बढ़ी हुई और सतत रूप से बढ़ते हुए आयातों के कारण भविष्य में इसके जारी रहने की संभावना है। यह नोट करना भी संगत है कि इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की कारणात्मकता निर्धारित करने में बाधक वाली वस्तुपरक एवं मात्रात्मक प्रकृति के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन किया गया है।

(ज) समायोजन योजना

54. रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार की एक प्रमुख विशेषता घरेलू उद्योग द्वारा समायोजन पर जोर देना है। इस संबंध में, रक्षोपाय संबंधी करार की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा को सीमित करने के बजाए संरचनात्मक समायोजन की महत्ता को पहचानना और उसे बढ़ाने की आवश्यकता।

55. इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 5.1 में यह प्रावधान है कि (क) सदस्य रक्षोपाय उपायों के लिए केवल गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए और समायोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए यथा आवश्यक सीमा तक ही आवेदन करेंगे। रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 7.1 में डब्ल्यूटीओ सदस्य देश के लिए केवल उसी समयावधि के लिए रक्षोपायों हेतु आवेदन करना अधिदेशित है जो गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने तथा समायोजन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 7.4 में अधिदेशित है कि उस स्थिति में समायोजन को सुकर बनाने के लिए जहाँ अनुच्छेद 12 के पैरा 1 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित रक्षोपाय उपाय की प्रत्याशित अवधि एक वर्ष से अधिक है, वहाँ उपाय के लिए आवेदन करने वाले सदस्य प्रमुख रूप से आवेदन की अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर उसे उदार बनाएगा। यह प्रावधान रक्षोपाय नियमावली 4(4)(ii), 11(2), 11(3) के परंतुक, 12(1), 16(1) और 16(2) के परंतुक के मानदंडात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय नियमावली के नियम 5(2) में निम्नलिखित प्रावधान है:

(2) उप नियम (1) के तहत कोई आवेदन इस संबंध में महानिदेशक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगा और उस आवेदन में निम्नलिखित साथ होंगे:

(ख) आयात प्रतिस्पर्द्धा में सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों अथवा किए जाने के लिए योजना बनाए गए प्रयासों, अथवा दोनों के संबंध में एक विवरण।

56. रक्षोपाय शुल्क लगाने का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दी गई समायोजन योजना अत्यधिक अंदाजे वाली है और उसमें समायोजन के लिए ठोस कदम अथवा वास्तविक महत्वपूर्ण उपाय नहीं हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि आपूर्तिकर्ताओं के साथ वार्ता अथवा दीर्घावधि संविदा को समायोजन योजना के रूप में नहीं अपनाया जा सकता। रक्षोपाय शुल्क लगाने का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने कार्यान्वयन के संबंध में विशिष्ट समयावधि तथा अन्य ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं और इसलिए समायोजना नियमावली की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।

57. मैं देखता हूँ कि रक्षोपाय नियमावली के नियम 5(2) नियोजित समायोजन के रूप में दिए गए समायोजन के विवरण के लिए प्रपत्र का प्रावधान नहीं है। रक्षोपाय संबंधी करार में कोई मांग दर्शन भी नहीं दिया गया है। मैंने घरेलू उद्योग बनाने वाले प्रत्येक उत्पादक द्वारा उनकी अलग-अलग प्रश्रावली के उत्तरों के साथ संलग्न घरेलू उद्योग द्वारा की जाने वाली योजना के प्रयासों के विवरण की जांच की है। इस विवरण की कुछ विशेषताएं संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

क) घरेलू उद्योग ने ठोस कदमों के रूप में अगले तीन वर्षों के लिए भारी निष्पादन का पूर्वानुमान दिया है, यथा – (i) कच्ची सामग्री की दीर्घावधि खरीद, दर तथा मात्रात्मक छूट, यदि बेहतर नकद प्रवाह प्राप्त किया जाए; (ii) उच्चतर क्षमता उपयोग जिससे बेहतर परिवर्तन लागत बने; (iii) अर्ध-नियत तथा नियत लागत का बेहतर भाग; (iv) बेहतर ऋण रेटिंग उधार लागत को कम करेगी और ऋण की बेहतर सेवाई होगी; (v) पिछड़े एकीकरण के प्रति प्रयास तथा पूरी पारि-प्रणाली विकसित करना; (vi) प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुसंधान एवं विकास।

ख) घरेलू उद्योग ने प्रत्येक कदम के प्रभाव की मात्रा तथा समय ढांचा बताया है जिसके भीतर ये प्रभाव दिखाई देंगे।

ग) अतः समायोजन योजना में प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन के संदर्भ में लागत में कमी लाने संबंधी प्रयास, दक्षता सुधार, मूल्य शृंखला का अग्रवर्ती एवं पश्चवर्ती एकीकरण शामिल हैं।

58. मैंने पाया है कि परिष्कृत सोलर मॉड्यूल की लागत का महत्वपूर्ण भाग (लगभग 45 प्रतिशत) कच्ची सामग्री है जिसमें मोटे तौर पर वेफर घटक इस लागत का आधार है। अतः प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घावधि कीमत वार्ता एक विश्वसनीय और यथार्थवादी प्रयास है। घरेलू उद्योग के ऐसे अनुमान विश्वसनीय हैं कि बेहतर मांग दृष्टिकोण वेफर आपूर्तिकर्ताओं के साथ लक्षित वार्ताओं में सहायता करेगा। मूल्यहास लागतें लागत संरचना का महत्वपूर्ण संघटक हैं तथा इससे क्षमता के बेहतर उपयोग से मूल्यहास की वसूली में सहायता मिलेगी।

59. मैं नोट करता हूँ कि कोरिया डेयरी मामले (डब्ल्यूटी/डी-598) में पैनल की रिपोर्ट में समायोजन योजना के संबंध में निम्नलिखित माना गया है: "हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम प्राधिकारी द्वारा समायोजन योजना पर विचार करने की आवश्यकता के रूप में अनुच्छेद 5.1 का निर्वचन नहीं करते, जैसा कि यूरोपीय समुदाय कहते हैं। यह पैनल कोई विशेष आवश्यकता नहीं देखता कि इस प्रकार की समायोजन योजना का अनुरोध किया जाना चाहिए और रक्षोपाय संबंधी करार के पाठ में उस पर विचार किया जाना चाहिए। यद्यपि, इसके दो प्रावधानों में उद्योग समायोजन के संदर्भ हैं तथापि, रक्षोपाय संबंधी करार के पाठ में कुछ भी यह सुझाव नहीं है कि किसी विशिष्ट समायोजन योजना पर विचार उपाय को अपनाने से पहले किए जाने की आवश्यकता है। इसके बजाए हमारा विश्वास है कि समायोजन का प्रश्न गंभीर क्षति को रोकने तथा उपचार करने के प्रश्न के साथ प्राधिकारी के उस उपाय के तर्कसंगत स्पष्टीकरण का भाग होना चाहिए जो उसने लागू करने के लिए चुना है। फिर भी, हम नोट करते हैं कि रक्षोपाय के अनुप्रयोग के संदर्भ में समायोजन योजना की जांच एक सशक्त साध्य होगा जिस पर प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या वे उपाय गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने तथा समायोजन को सुकर बनाने के उद्देश्य के अनुरूप था।"

60. अतः उपर्युक्त तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समायोजन योजना के मद्देनजर मैं मानता हूँ कि दी गई पारि-प्रणाली में उद्योग द्वारा निर्धारित समायोजन योजना पूर्णतः व्यावहारिक है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि रक्षोपाय के तहत राहत एक आपातकालीन उपाय के रूप में सीमित समयावधि के लिए ही है। अतः आयातों में उछाल को रोकने के उद्योग के समायोजन प्रयासों को इस समयावधि में प्राथमिक रूप से देखे जाने की आवश्यकता है।

ट) सार्वजनिक हित

61. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 3.1 में निम्नलिखित उल्लेख है:

"कोई सदस्य रक्षोपाय के लिए जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद X के अनुरूप सार्वजनिक किए गए तथा पूर्वतः स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में उस सदस्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच के बाद ही आयोजन कर सकता है। इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों का उपयुक्त सार्वजनिक सूचना तथा सार्वजनिक सुनवाई अथवा अन्य उपयुक्त उपाय शामिल होंगे जिनमें आयातक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार साध्य प्रस्तुत कर सकें तथा अपने विचार दे सकें जिनमें अन्य पक्षकारों की प्रस्तुतियों का उत्तर देने का अवसर तथा उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर शामिल है, चाहे रक्षोपाय का आवेदन जनहित में हो या न हो। सक्षम प्राधिकारी अपने जांच परिणाम और तथ्यतः कानून के सभी व्यावहारिक मुद्दों पर पहुँचकर तर्कसंगत निष्कर्षों को निर्धारित करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।"

62. यद्यपि, सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख तथा सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क का मूल्यांकन तथा पहचान) नियमावली, 1997 में जनहित की जांच किए जाने की आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक हित का मूल्यांकन रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने से पहले निरंतर मूल्यांकित किया गया है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक हित के संबंध में अनुरोध किए हैं, जैसा कि अनुरोधों के तहत पैराओं में दिया गया है।

63. उपर्युक्त के मद्देनजर, यद्यपि, अनुच्छेद 3.1 में सार्वजनिक हित के मूल्यांकन के संबंध में कोई मार्गदर्शन नहीं किया गया है, तथापि, सार्वजनिक हित के मूल्यांकन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न दावेदारों के संबंध में व्यापक रूप से रक्षोपाय के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिस्पर्द्धी हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में कई हितबद्ध पक्षकार हैं – (i) सोलर सेलों के घरेलू उत्पादक, (ii) सोलर मॉड्यूलों के घरेलू विनिर्माता जो खुद सेलों का विनिर्माण नहीं करते हैं और घरेलू एवं आयातित सेलों पर विश्वास करते हैं, तथा (iii) विद्युत विकासकर्ता और (iv) बिजली के उपभोक्ता बढ़े हुए विद्युत प्रशुल्क के रूप में रक्षोपायों के बोझ को वहन करते हैं।
64. निःसन्देह रक्षोपाय शुल्क लगाने से केवल घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कम ही नहीं होगी, बल्कि सोलर सेलों/मॉड्यूलों के विनिर्माण की मूल्य श्रृंखला में जुड़े ऊपरी एवं निचले उद्योग की अर्थक्षमता में भी सुधार होगा। सेलों/मॉड्यूलों की कीमतों, जो निःसन्देह बढ़ेंगी, का प्रयोक्ता उद्योग अर्थात् आयातित सेलों अथवा घरेलू सेलों का प्रयोग करने वाले मॉड्यूल विनिर्माताओं, मॉड्यूल आयातकों, विद्युत विकासकर्ताओं और उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा।
65. घरेलू उद्योग का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि जब घरेलू उद्योग के पास भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है, तो रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा। इस संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों ने मेरा ध्यान भारत में सफेद/पीले फॉस्फोरस के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच में अंतिम जांच परिणाम की ओर आकर्षित किया है। अंतिम जांच परिणाम का अवलोकन करने पर हमने पाया कि अपर्याप्त क्षमता के अलावा, रक्षोपाय शुल्क लगाना लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता, घरेलू उद्योग की कैप्टिव आवश्यकताओं, निर्यात संवर्धन योजना के तहत आयातों तथा निचले बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा प्राप्त करने के लिए घरेलू उद्योग की असमर्थता के कारण जनहित में नहीं माना गया था। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय जांचों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिनमें घरेलू बाजार में पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता न रखने वाले घरेलू उद्योग के बावजूद शुल्क लगाया गया है – (i) औद्योगिक सिलाई मशीनों की सुईयों के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच, (ii) ऑक्सो एल्कोहॉल के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच, (iii) सोडियम नाइट्राइड के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का अवलोकन करने पर मेरा यह मत है कि क्षमता मांग अंतराल यद्यपि एक महत्वपूर्ण पहलू है, तथापि, इसे अलग से नहीं माना जा सकता। सार्वजनिक हित को संगत तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक मामले में निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
66. वर्तमान मामले के तथ्यों में जब घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार को पूरा करने के लिए तथा पश्चवर्ती एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए हैं तो आयातों में अचानक एवं तेजी से उछाल के विरुद्ध उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय शुल्क एक मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है, अतः आयातों के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद की खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहां तक कि ऐसी स्थिति में जब घरेलू उद्योग में विचाराधीन उत्पाद की मांग को पूरा करने की क्षमता हो तो रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव यह है कि घरेलू उत्पादक अपनी लागत वसूलने, उपयुक्त आय कमाने और अपनी समायोजन योजना का कार्यान्वयन करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाएं।
67. जहां तक विद्युत विकासकर्ताओं के हित का संबंध है, घरेलू उद्योग ने कुछ तर्क उठाए हैं। विद्युत विकासकर्ताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया सकता है: (क) वे विकासकर्ता जो डिस्कॉमों के साथ पीपीए में आए हैं और जिन्होंने पहले ही विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है; (ख) वे विकासकर्ता जो डिस्कॉमों के साथ पीपीए में आए हैं, परंतु विचाराधीन उत्पाद का आयात अभी तक नहीं किया है और (ग) वे विकासकर्ता जो भावी परियोजनाओं में बोली लगा सकते हैं तथा विचाराधीन उत्पाद के आयात की आशा कर रहे हैं, अपने प्रशुल्क कोटेशनों में बढ़ी हुई आयात कीमत शामिल करेंगे और गैर-प्रतिस्पर्द्धी हो सकते हैं। जो विद्युत विकासकर्ता वर्तमान में प्रभावित होंगे, वे डिस्कॉमों के साथ पीपीए में आने वाले विकासकर्ता हैं और जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद की विद्यमान आयात कीमतों के आधार पर प्रशुल्क की दरें दी हैं, परंतु अभी तक विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। तथापि, चूंकि केंद्र सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में ऐसे प्रभावित विद्युत विकासकर्ताओं के हितों को संतुलित करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं, जिसमें करारों की "कानून में परिवर्तन" की धारा पर स्पष्टीकरण के माध्यम से सुविधा अधिसूचित की गई है तथा इसीलिए मैं यह अनुभव करता हूं कि यदि रक्षोपाय शुल्क लगाना "कानून में परिवर्तन" की धारा के तहत शामिल किया जाता है तथा शुल्क का प्रभाव डिस्कॉमों पर डाला जाता है।
68. यह स्पष्ट है कि जहां एक ओर भारत में सोलर विनिर्माण उद्योग को शक्तिशाली बनाए जाने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर सौर विद्युत से 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य समान रूप से सोलर सेल/मॉड्यूल आयात किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि देश में घरेलू आपूर्ति आधार वर्तमान स्थिति में अत्यधिक कम है।
69. मैंने घरेलू उद्योग द्वारा तथा एक विद्युत विकासकर्ता अर्थात् मैसर्स एसीएमई द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत रक्षोपाय शुल्क संरक्षण के विभिन्न स्तरों पर अनुकूलन की जांच की है। दोनों अनुकूलन कुछ अवधारणाओं पर आधारित हैं। मैं देखता हूं कि एसीएमई के अनुकूलनों से व्यापक निष्कर्ष है कि विचाराधीन उत्पाद पर 25 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क से प्रशुल्क में 23 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि घरेलू उद्योग का अनुमान यह है कि 30 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क लगाने की स्थिति में प्रशुल्क केवल 5 प्रतिशत बढ़ेगा जो देश की समग्र ऊर्जा में से सौर विद्युत के कम भार तक हो जाएगा। घरेलू उद्योग ने अनुमानों के आधार पर ऐसे आशावादी अनुरोध किए हैं कि विकासकर्ता जो भावी परियोजनाओं पर बोली लगा सकते हैं और विचाराधीन उत्पाद के आयात की आशा कर रहे हैं,

अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, वे ऐसा कोई साध्य प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं कि ऐसी कोई योजना मौजूद है। अतः मैंने विश्लेषण में ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया है। चूंकि, परियोजना लागत में मॉड्यूल की लागत लगभग 60 प्रतिशत आंकी जाती है, अतः मैसर्स एसीएमई द्वारा अनुकूलन में प्रस्तावित प्रभाव का आयाम अत्यधिक मात्रा होने के नाते अयथार्थवादी लगता है। दूसरी ओर, शुल्क वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग का अनुमान काफी कम है। चूंकि, अनुकूलन अवधारणा आधारित है और दो अत्यधिक वृद्धियां प्रस्तुत की गई हैं, अतः यह उपयुक्त रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विद्युत प्रशुल्क में वृद्धि दो अत्यधिक वृद्धियों के बीच कहीं होगी।

70. उपर्युक्त बातें यह सिद्ध करती हैं कि रक्षोपाय उस मात्रा और अवधि में लगाए जाने की सिफारिश करना जनहित में है जो दो प्रतिस्पर्द्धी संबंधितों में संतुलन बनाएगी। इसके अतिरिक्त उपाय का उचित स्तर सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उपाय की वही मात्रा (स्वमूल्यन %) स्टैंड एलॉन के रूप में सोलर सैल अथवा मॉड्यूल/पैनल्स में जोड़े गए सोलर पर भी लगाई जाए ताकि ऐसी स्थिति से बचा जाए जोकि उपाय की भावना के प्रतिकूल हो और जो जनहित का संतुलन बनाए रखने के लिए परिकल्पित की गई हो।

झ) विकासशील देश

71. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(1) के परंतुक में यह प्रावधान है कि रक्षोपाय शुल्क तब तक विकासशील देश के मूल की वस्तु पर नहीं लगाया जाएगा जब तक उसके आयातों का हिस्सा उस वस्तु के कुल आयातों का 30 प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाता अथवा जहां वस्तु एक से अधिक विकासशील देश के मूल की है। फिर जब तक सभी विकासशील देशों से कुल आयात, प्रत्येक 3 प्रतिशत आयात शेयर से कम लेकर, उस वस्तु के कुल आयातों के 9 प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाता। इसके अतिरिक्त, 05 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमा शुल्क (एनटी) में इस प्रावधान के लिए विकासशील देशों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान मामले में उपलब्ध आंकड़ों के लिए उपर्युक्त अधिसूचना के साथ पठित इस कानूनी प्रावधान को लागू करने पर निष्कर्ष यह है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात चीन जन. गण. और मलेशिया सहित उल्लिखित एक से अधिक विकासशील देश के मूल का है। तथापि, भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात की प्रतिशतता चीन जन. गण. और मलेशिया से आयात अलग-अलग 3 प्रतिशत से अधिक हैं, जबकि प्रत्येक अन्य विकासशील देश का हिस्सा अलग-अलग 3 प्रतिशत से कम है। साथ ही, उन विकासशील देशों का सामूहिक हिस्सा, जिनका अलग से हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है, भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात का 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होता। अतः, चीन जन. गण. और मलेशिया को छोड़कर विकासशील देशों के मूल के विचाराधीन उत्पाद के आयात को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(1) के परंतुक के अनुसार रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के अध्वधीन रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

ड) अन्य मुद्दे तथा रक्षोपाय शामिल करना

72. मैं प्राथमिक जांच परिणाम के पैरा छ को याद करता हूँ जिसमें यह कहा गया था कि "एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 3 का प्रयोग सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख के तहत रक्षोपायों को लगाने का निषेध करेगा और प्रति उत्पादक होगा। इसका उपचार रक्षोपाय की सीमा तक शुल्क छूट होगा जब विचाराधीन उत्पाद एसईजेड यूनिट द्वारा घरेलू बाजार में मंजूर किया जाए। इससे घरेलू उद्योग के हित में रक्षोपाय की संगति बनाए रखी जाएगी। यह सभी घरेलू उत्पादकों अथवा घरेलू उद्योग के सभी घटकों को आयातित विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय लागू करने के संबंध में समान रखकर समानता के सिद्धांत को भी पूरा करेगा। तथापि, यह मामला वर्तमान कार्यवाहियों की परिधि से बाहर आता है जो उसकी नियमावली के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के प्रावधानों से कठोरता से शासित होता है तथा इसीलिए इसे सरकार के विचार के लिए छोड़ा गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से संबंधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(2क)(ii) के प्रावधान आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अध्वधीन वस्तु को घरेलू बाजार में एसईजेड से अलग किए जाने पर अथवा किसी ऐसे समान के निर्माण में प्रयुक्त होती है जो एसईजेड द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में होगी, लागू होंगे।"
73. इस पहलू के संबंध में घरेलू उद्योग ने भी विस्तृत अनुरोध किए हैं:

क. याचिकाकर्ताओं का संबद्ध सामानों के कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और इसीलिए वे सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की 8ख(6)(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं का सामूहिक उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है। अतः वे कुल भारतीय उत्पादन के प्रमुख अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए भारत में समान वस्तु के घरेलू उद्योग हैं। एलडीडीजी ने रक्षोपाय में भी अपनी दिनांक 05.01.2018 के प्राथमिक जांच परिणाम में पुष्टि की कि याचिकाकर्ताओं का भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है और इसीलिए वे घरेलू उद्योग हैं।

ख. एलडी डीजी रक्षोपाय ने पाया कि मैसर्स मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड, मैसर्स वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स लि. और मैसर्स हेलियोस फोटो वोल्टेक लि. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित हैं और इसीलिए रक्षोपाय शुल्क लगाते समय उन्हें एक पर्याप्त उपाय के माध्यम से शुल्क से छूट दी जाए। तथापि, एसईजेड से डीटीए में संबद्ध सामानों की मंजूरी पर वह लगाए जाने की स्थिति में कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं लगेगा। यह एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 8ख(2क) और धारा 30 को साथ-साथ पढ़कर स्पष्ट है। संदर्भ की सरलता के लिए एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 30क।

- ग. एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत पाटनरोधी शुल्क, सीडी और रक्षोपाय शुल्क लगाना "जहां लागू हों" शब्दों द्वारा अर्हता प्राप्त हैं। अतः किसी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कब पाटनरोधी शुल्क, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क किसी दिए गए मामले में लागू है।
- घ. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबंधित धारा 9क प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के संबंध में धारा 9 और रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से संबंधित धारा 8ख की भाषा निश्चित संदर्भों में यह कहती है कि वह भारत में वस्तु के आयातों पर लागू है। अतः यदि कोई वस्तु भारत में आयातित नहीं की जाती है तो उपर्युक्त कोई भी शुल्क लागू नहीं है। यद्यपि, एक मानने की स्थिति से एक कानूनी धारणा बनाई जाती है जिससे एसईजेड को भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर माना जाता है। भारत में किसी भी विद्यमान कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एसईजेड में विनिर्मित सामानों की मंजूरी आयात के रूप में डीटीए में माने। यह तथ्य कि एसईजेड से डीटीए में विनिर्मित सामानों की मंजूरी भारत के क्षेत्र में आयात नहीं बनती, भी एस्सार स्टील बनाम भारत संघ [1210 जीएलएच (1) 52], इंडिया एक्सपोर्ट्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [(2012) 47 वीएसटी 126], तिरुपति उद्योग लि., जिसका प्रतिनिधित्व उसके प्रबंधक, प्रशासक श्री डी. वी. सारथी ने किया, बनाम भारत संघ (यूओआई) – सचिव, वित्त मंत्रालय के माध्यम से और अन्य [2011 (272) ईएलटी 209 (ए.पी.)] सहित निर्णयों में दोहराई गई है। अतः आयात के तथ्य के बिना कोई पाटनरोधी शुल्क, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क अथवा रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जा सकता।
- ङ. पाटनरोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क देश विशिष्ट हैं और इसीलिए यदि उपर्युक्त समान वस्तु के विवरण पर लगाए भी जाते हैं जो कि एसईजेड में विनिर्मित किए जाते हैं और फिर डीटीए में मंजूर किए जाते हैं तो उन पर उपर्युक्त शुल्क नहीं लगाए जा सकते क्योंकि भारत के क्षेत्र में ही एसईजेड के विरुद्ध पाटन अथवा सब्सिडी का आरोप लगाते हुए पाटनरोधी अथवा प्रतिसंतुलनकारी जांच कभी नहीं हो सकती और परिणामस्वरूप इस प्रकार का कोई शुल्क लगाए जाने का प्रश्न नहीं उठेगा। अतः एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 30 में शब्दों के अभिप्राय को प्रभाव देने के लिए डीटीए मंजूरी के दौरान उसमें उल्लिखित पाटनरोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने का उल्लेख का अर्थ परिष्कृत उत्पाद के लिए प्रयुक्त और खुद परिष्कृत उत्पाद पर अप्रयुक्त, जो कि असंभव है, इनपुट (जिस स्थिति में विनिर्मित देशों से आयातित इनपुट पर पाटनरोधी शुल्क अथवा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगता है) के मूल्य पर देय शुल्क है।
- च. यही सिद्धांत किसी समान वस्तु के विरुद्ध लगाए गए रक्षोपाय शुल्क पर भी लागू है जो कि एसईजेड में विनिर्मित किया जाता है और डीटीए में मंजूर किया जाता है। जब तक आयातित इनपुट तथा परिष्कृत उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट, जो डीटीए में मंजूर किया गया है, जिस स्थिति में रक्षोपाय शुल्क परिष्कृत उत्पाद के विनिर्माण में लगाए गए इनपुट (यह मानते हुए कि इनपुट पर रक्षोपाय शुल्क लगता है) के मूल्य की सीमा तक ही लगाया जाएगा, परिष्कृत उत्पाद पर कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाएगा, भले ही यद्यपि वह समान वस्तु हो, जिसके विरुद्ध भारत में रक्षोपाय शुल्क लगाए हैं। यह सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(2क) से भी सिद्ध है। अतः सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(2क) के साथ पठित एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 30 यह स्पष्ट करती है कि रक्षोपाय शुल्क केवल परिष्कृत उत्पादों में प्रयुक्त इनपुट पर ही देय है, न कि परिष्कृत उत्पादों पर जो कि एसईजेड में विनिर्मित किए जाते हैं और डीटीए में मंजूर किए जाते हैं।
- छ. एसईजेड में विनिर्मित और डीटीए में मंजूर परिष्कृत उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क एक अतिरिक्त कारण से अर्थात् ऐसी स्थिति में जहां भारत द्वारा डीटीए में परिष्कृत उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट के विवरण पर तथा परिष्कृत उत्पाद के विवरण पर डीटीए में मंजूरी के समय रक्षोपाय शुल्क लगाया गया है, रक्षोपाय शुल्क देय नहीं होंगे। उपर्युक्त दोनों इनपुट तथा परिष्कृत उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगेंगे जिनका दोगुना कराधान होगा। ऐसा शुल्क गैर-कानूनी होने के नाते एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 30 पाटनरोधी शुल्क, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क के संदर्भ का अभिप्राय हमेशा इनपुट के मूल्य पर होगा क्योंकि अन्यथा शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकेगा।
74. मैंने प्राथमिक जांच परिणाम में की गई टिप्पणियों और घरेलू उद्योग के अनुरोधों को पढ़ा है। चूंकि, घरेलू उद्योग का क्षेत्र तीन एसईजेड यूनिटों को हटाकर संशोधित किया गया है, अतः सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और एसईजेड अधिनियम की धारा 30 के निर्वचन के माध्यम से डीटीए बिक्रियों/एसईजेड द्वारा मंजूरीयों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के मुद्दे को संगत संबंधित प्राधिकारियों द्वारा लिए जाने की आवश्यकता है और इस जांच के क्षेत्र से बाहर है।

ढ) निष्कर्ष

75. उपर्युक्त जांच और विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि:

- (i) पूरी जांच की अवधि में पूर्ण दृष्टि से तथा कुल भारतीय उत्पादन के संबंध में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में काफी वृद्धि हुई है।
- (ii) बाजार हिस्सा और लाभप्रदता, जो 2014-15 से 2017-18 (वार्षिकीकृत) की क्षति अवधि में तेजी से घटी है, जबकि आयातों का बाजार हिस्सा उसी अवधि में बढ़ा है, जैसे सूचीबद्ध आर्थिक मानदंडों के आधार पर समग्र निष्पादन को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। इससे घरेलू उद्योग को काफी समग्र हानि हुई है। आयातों में वृद्धि और क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति कारणात्मकता सिद्ध करती है।

- (iii) घरेलू उद्योग यह दर्शाने में सक्षम रहा है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में उछाल पर बाजार में घटनाएं जीएटीटी के अनुच्छेद XIX के संदर्भ में अप्रत्याशित थीं।
- (iv) विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क के परिणामस्वरूप सौर विद्युत विकासकर्ताओं और अंततः उपभोक्ता पर कुछ प्रभाव पड़ेगा।
- (v) तथापि, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस मामले में रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में होगा क्योंकि इससे देश में सौर उद्योग के विनिर्माण आधार का पूर्णतः अपरदन रुकेगा जो कि होने वाला है और भविष्य में देश में सशक्त विनिर्माण आधार के लिए आश्वासन देते हैं। इसके साथ ही सौर विद्युत लागत में अनुचित वृद्धि और अंतिम उपभोक्ता के प्रशुल्क में अनुचित वृद्धि को रोकना भी जनहित में है तथा यह कि वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर विद्युत नियोजन का लक्ष्य प्राप्त करना पटरी से न उतरे। दो प्रतिस्पर्द्धी हितों पर विचार करने के लिए एक संतुलित मत की आवश्यकता है।
- (vi) जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग की स्थिति विचाराधीन उत्पाद की सतत कम कीमत के कारण और भी बिगड़ी है जिससे घरेलू उद्योग को निरंतर कीमत की क्षति हुई जिससे क्षति का खतरा भी सिद्ध होता है।

ण) सिफारिशें

76. भारत में "विचाराधीन उत्पाद" के बड़े हुए आयातों से क्षति हुई है और "विचाराधीन उत्पाद" के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होने का खतरा हुआ है तथा दो वर्षों की अवधि के लिए सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क का मूल्यांकन एवं पहचान) नियमावली, 1997 के नियम 12 के अनुसार भारत में "विचाराधीन उत्पाद" के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में होगा। उत्पादन लागत पर उपयुक्त आय में से ब्याज घटाकर, नीचे दिए गए रक्षोपाय शुल्क लगाने की अनुमति के बाद घरेलू उत्पादकों के "विचाराधीन उत्पाद" के उत्पादन की औसत लागत मानते हुए, सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 85414011 के तहत आने वाले आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद पर घरेलू उद्योग के हित की रक्षा करने के लिए पर्याप्त माना जाता है, रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है। यहां उल्लिखित प्रशुल्क मद केवल संकेतात्मक है और आयातित सामानों का विवरण सिफारिश किए गए रक्षोपाय शुल्क के लागू होने को निर्धारित करेगा।

वर्ष	सिफारिश किया गया रक्षोपाय शुल्क
प्रथम वर्ष	रक्षोपाय शुल्क @ 25% यथा मूल्य पर
द्वितीय वर्ष (पहले 6 माह के लिए)	रक्षोपाय शुल्क @ 20% यथा मूल्य पर
द्वितीय वर्ष (अगले 6 माह के लिए)	रक्षोपाय शुल्क @ 15% यथा मूल्य पर

77. चूंकि, दिनांक 05 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमा शुल्क (एनटी) में सूचीबद्ध किए गए अनुसार चीन जन. गण. और मलेशिया को छोड़कर विकासशील राष्ट्रों से आयात अलग-अलग 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं और सामूहिक रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, अतः चीन जन. गण. और मलेशिया को छोड़कर विकासशील राष्ट्रों के मूल के विचाराधीन उत्पाद के आयात पर सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(1) के परंतुक के अनुसार रक्षोपाय शुल्क नहीं लगेगा।

सुनील कुमार अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**New Delhi, the 16th July, 2018

Subject: Safeguard investigation concerning imports of “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” into India – Final Findings - Proceedings under the Customs Tariff Act, 1975 and the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 - Reg.

F. No. 22/1/2018 - DGTR .—(A) Introduction

1. An application dated 28.11.2017 has been filed before me on 05.12.2017 under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter also referred to as the “said Rules”) by the Indian Solar Manufacturers Association (ISMA) on behalf of five Indian producers, namely (i) M/s Mundra Solar PV Limited, Adani House, Meetha Khali 6 Road, Navrangpura, Ahmedabad-380009, Gujarat; (ii) M/s Indosolar Limited, 3C/1, EcoTech-II, Udyog Vihar, Dist: Gautam Budh Nagar, Greater Noida-201306, Uttar Pradesh; (iii) M/s Jupiter Solar Power Limited, Village Katha, Post Office Baddi, Teh. Nalagarh, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173205; (iv) M/s Websol Energy Systems Limited, Falta SEZ Sector-II, Falta, Dist: 24 South Praganas, West Bengal-743504; and (v) M/s Helios Photo Voltaic Limited, 43B, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020, through M/s Athena Law Associates, 808, L&T Building, Sector 18B, Dwarka, New Delhi-110075, seeking imposition of Safeguard Duty on imports of “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC”) into India to protect the Domestic Industry of like or, directly competitive products from serious injury / threat of serious injury caused by their increased imports. The applicants have claimed that on account of the surge in imports of the PUC many domestic producers have kept their production facilities almost idle and the heavy losses have crippled the Domestic Industry. For this reason, the applicants had requested for imposition of provisional Safeguard Duty as a measure to mitigate their injury.

2. An examination of the application and the evidence / details / documents submitted under said Rules was undertaken. Thereafter, a Safeguard investigation against imports of the PUC into India was initiated vide Notice of Initiation (NOI) dated 19.12.2017. The NOI was published in the Gazette of India, Extraordinary dated 19.12.2017 vide GSR No.1522 (E).

3. In accordance with sub-rules (2) and (3) of Rule 6 of the said Rules, a copy of the NOI dated 19.12.2017 and a copy of a Non-confidential Version (NCV) of the application dated 28.11.2017 filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government in the Ministry of Commerce & Industry, Ministry of Finance and Ministry of New and Renewable Energy, the Governments of major exporting countries through their Embassies in India, and the interested parties mentioned in the said application. Further, the questionnaire to be answered by the exporters / importers / domestic producers, as prescribed under Rule 6(4) of the said Rules, was forwarded to the known interested parties with a request to make their views known in writing within 30 days from the date of issue of the NOI.

4. On 20.12.2017, the two associations of the domestic Solar Cells producers, namely (i) M/s Indian Solar Manufacturers Association (ISMA) and (ii) M/s Solar Power Developers Association (SPDA) were sent a copy of the NOI dated 19.12.2017, a copy of the NCV of the application dated 28.11.2017 and the questionnaire to be answered by the exporters / importers / domestic producers.

5. The request made by the domestic industry for imposition of provisional safeguard duty was examined and it was prima facie found that there existed critical circumstances which warranted imposition of provisional safeguard duty in order to provide interim relief to the domestic industry from suffering irreparable damage, which could have been difficult to repair.

6. Accordingly, the Preliminary Findings for Provisional safeguard duty was issued under Rule 9 (2) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 5th January, 2018 and was published in the Gazette of India on the same day. However, the Provisional safeguard duty was not implemented due to stay granted by the Hon’ble Chennai High Court which was vacated after a period of almost 3 months.

7. Either request to consider as an interested parties or submissions were received from the following parties:

1.	Indian Solar Manufacturing Association (ISMA)
2.	M/s Mundra Solar PV Limited
3.	M/s Indosolar Limited
4.	M/s Jupiter Solar Power Limited Limited,
5.	M/s Websol Energy Systems Limited
6.	M/s Helios Photo Voltaic Limited,
7.	Indian Solar Association
8.	Indian Solar Power Producers Alliance
9.	US-India strategic Partnership Forum
10.	Indian Electrical & Electronics Manufacturers' Association
11.	Gintech, 9F no 295 tiding blvd. Sec 2 Taipei, Taiwan 11493 R.O.C
12.	Sterling and Wilson Pvt. Ltd.
13.	Cells OT Thalheim, Sonnenalle 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany
14.	JA Solar No 36, Jiang Chang San Road, Zhabei, Shanghai 200436, China
15.	Delsolar, 6 Kebei 2nd Road, Zhunan Science Park, Zhunan Township, Miaoli County 35053 Taiwan, ROC
16.	Sunengine Corporation Ltd., No. 10 Wenhua Rd., Hukou Township, Hsinchu County 30352, Taiwan
17.	TSI (Topcell Solar International Co Ltd, No 1560, Sec 1, Zhongshan Rd., Guanyin Township, Taoyuan County 328, Taian ROC
18.	E Ton Solar, No 498 sec 2, Bentian St. , Tainan, 709, Taiwan ROC
19.	Big Sun Energy Technology Inc No 458-9 Sinsing Rd. Hukou Township, Hsinchu County 30353, Taiwan
20.	Goldpoly, Economic Development Zone, Jin Jiang 363300, Fujian, China
21.	KPE, 1985-12 Yeonsan - dong, Yeonje-gu, Busan-611832 Korea, 23-2 Palyong-dong , Changwon, Gyeongsangnam-do 6410847, Korea
22.	Sharp Corporation, 3, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UK (europe)
23.	Q-Cells, Bitterfeld-Wolfen, Germany
24.	Tsec, 9F, No. 10, Sec 3, Minsheng E. Rd., Jhongshan Dist., Taipei City 10480 Taiwan ROC
25.	Solar Tech Energy, No. 51, Dinghu 1st Street 4th Industrial Park, Guelshan, Taoyuan 333, Taiwan RO China
26.	Shin Sung, 404-1 Baekhyeon-dong, Bundang-gu Seongnam-SI, Gyeonggi-do, Korea: 463420
27.	NSP (Neo Solar Corporation), 7, Li-hsin 3rd Rd. , Hsinchu Science Park, Hsinchu, 30078, Taiwan
28.	TGE(Top Green Energy Technology), 9F No 246 Lien Chen Road, Chung Ho City, Tapei Hsien Taiwan ROC
29.	Taienergy (Thai Solar Energy Corporation Ltd.), 3199 Maleenont Tower, 16th floor, RAMA IV Rd. Klongtan, Klongtoey, Bangkok 10110
30.	Unitech Solar Corp, Mno. 16, sec 2, Lkigong 1st Road, Wujiw Township Yilan County 26841, Taiwan
31.	Motech, Southern Taiwan Science Park, No. 2, Dashun 9th Rd., Xinshi Dist., Tainan City 74145, Taiwan
32.	Schott, Hattenbergstr 1055122 Mainz

33.	Hanwha Solar One, 1199 Minsheng Road Building 1, Room 1801 Shanghai, China 200135
34.	Renewable Energy Corporation (REC), Sandvika, Norway
35.	AE Solar GmbH, Messerschmittring 54, 86343 Konigsbrunn, Germany
36.	Ningbo Reneled New Energy Co. Ltd.
37.	Panasonic Energy Malaysia SDN. BHD
38.	Zhejiang Beyondsun Pv Co. Ltd.
39.	Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd.
40.	Wuxi Saijing Solar Co., Ltd.
41.	Anhui Yinxin New Energy Technology Co., Ltd.
42.	Win Win Precision Technology Co., Ltd
43.	Zhejiang Trunsun Solar Co., Ltd.
44.	Tongwei Solar (Hefei) Co., Ltd Tongwei Solar (Chengdu) Co. Ltd.
45.	Gintech Energy Corporation
46.	Tainergy Tech. Co., Ltd Vietnergy Co., Ltd
47.	Suzhou Talesun Solar Technologies co., Ltd
48.	AU Optronics Corporation
49.	China Sunenergy (Nanjing) Co., Ltd
50.	JianxiRisun Green Energy co., Ltd
51.	Renesola Jiangsu Ltd
52.	Ming Hwei Energy Co. Ltd.
53.	Ningbo Osda Solar Co., Ltd
54.	LOF Solar Corp.
55.	Hareon Solar Technology Co., Ltd Hareon (Wuxi) New Energy Technology Co., Ltd Hareon Solar Equipment Sales Co., Ltd Hareon Solar Co., Ltd Hareon International Co., Ltd. Hefei Hareon Solar Technology co., Ltd JiangyinHareon Power Co., Ltd. TaicangHareonColar Co., Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co., Ltd JiangyinXinhui Solar Energy Co., Ltd
56.	Solartech Energy Corp
57.	Trina solar Co., Ltd

	Trina Solar (Vietnam) Schience& Technology Co. Ltd Trina Solar Science & Technology (Thailand) Ltd
58.	Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co., Ltd
59.	Jetion Solar (China) co., Ltd
60.	SUMEC Hong Kong Co., Ltd
61.	Ningbo Reneled New Energy co., Ltd
62.	Lightway Green New Energy Co., Ltd
63.	Anji Dasol Solar Energy S&T Co., Ltd
64.	Jiangsu Aiduo Photovoltaic Technology Co., Ltd
65.	Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd CSI Solar Power Group Co., Ltd
66.	Yingli Solar
67.	Alternative Energy (AE) Solar Co., Ltd
68.	Jiangsu Green Power PV Co., Ltd
69.	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd
70.	China Machinery Engineering Wuxi Co., Ltd
71.	E-TON Solar Tech co., Ltd
72.	TSEC Corporation
73.	Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd
74.	LONGi Solar Technology Co., Ltd
75.	Sino-American Silicon Products Inc.
76.	Phono Solar Technology Co., Ltd
77.	Zhejiang Aiko Solar Energy Technology co., Ltd
78.	CCCME
79.	Anhui Yingfa Ruineng Technology Co., Ltd.
80.	Levosolar Technology Co., Ltd
81.	Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited
82.	Jinneng Clean Energy Technology Ltd.
83.	GCL System Integration Technology Co., Ltd
84.	Risen Energy Co., Ltd
85.	ZNSHINE PV-TECH Co., Ltd
86.	Changzhou GS Energy & Tech. Co., Ltd
87.	Panasonic Corporation / SANYO Electric
88.	First Solar FE Holdings Pte. Ltd. (Singapore) and First Solar Inc (USA)
89.	M/s Zhejiang Sunflower Light Energy Science and Technology LLV
90.	Panasonic Energy Malaysia Sdn Bhd

91.	Nice Sun PV Co., Ltd
92.	Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd
93.	ACME Solar Holdings Ltd.
94.	Neo Solar Power Corporation
95.	Motech Industries Inc
96.	JA Solar PV Technology Co., Ltd.
97.	Acess Solar Ltd. Plot #s5, Phasr-II, TIE, Balanagar, Hyderabad, 500037-Telangana
98.	Jain Irrigation Systems Ltd. jain Plastic Paek, Jalgoan 425001
99.	Kotak Urja Pvt. Ltd. , 378, 10th Cross , 4th Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore, 560058, Karnataka
100.	PLG Power Limited 139, A-1 Shah & Nahar Ind. Est. Lower Parel(W) Mumbai
101.	Ever Green Solar System India Pvt. Ltd. Sulochana mills Mettupalayam Road Coimbatore. Tamil nadu
102.	Ammini Group Plot. No.33-37, KINFRA Small Industries Park St. Xaviers Collage PO, Trivandrum 695582
103.	KL Solar Company Pvt. Ltd. 1/482-B Transport Nagar, Neelambur, Coimbatore. Tamil nadu
104.	PHOTONIX Solar Private Limited, 38/A, sahakar Vrind Society, Paud Road, Opposite Vanaz Factory, Kothrud, Pune 411038 Maharastra
105.	JJ PV Solar PVT LTD. Suryvey no. 237,238 Plot no. 2,3 N/H 8B village veraval Shapar dist. Rajkot 360024 Gujarat.
106.	L&T Construction, Power Transmission and Distributionj, IFCI Tower, 14 th Floor, 61, Nehru Place, New Delhi-110019.
107.	Amplus Energy Solutions Private Ltd.
108.	Clean Max Enviro Energy Solutions Pvt. Ltd.
109.	Green Energy Association
110.	North India Module Manufacturer Association
111.	ACME Cleantech Solutions Pvt. Ltd
112.	Vikram Solar Limited
113.	Madhav Infra Projects Limited
114.	Aditya Birla Renewables Limited
115.	Solar Power Developers Association
116.	Krishiraj Renewables Energy Private Limited
117.	Viraj Solar Maharashtra
118.	Avaada Power Private Limited
119.	The Embassy of Republic of Korea
120.	The Embassy/High Commission of the United Kingdom
121.	The Embassy/High Commission of Singapore
122.	The Embassy/High Commission of Malaysia
123.	The Embassy of Italy

124.	The Embassy of Germany
125.	The Embassy of Taiwan
126.	The Embassy of Japan
127.	The Embassy of People's Republic of China
128.	The Embassy of Norway
129.	The Embassy of Royal Thai
130.	Taiwan Economic & Cultural Centre
131.	The Embassy of Mexico
132.	United States International Trade Commission
133.	China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products
134.	Taiwan Photovoltaic Industry Association
135.	European Commission
136.	DGFT, Govt. of Indonesia
137.	Sterling and Wilson Pvt. Ltd.
138.	Guangdong Aiko Solar Energy Technology Company Ltd.
139.	Schutten Solar Energy Co. Ltd.
140.	Econess Energy Co. Ltd.
141.	JA Solar including JA Shanghai, JA Hefei, JA Xingtai, JA Yangzhou, JingAo Solar and JA Solar Malaysia Sdn. Bhd.
142.	Yingli Energy (China) Co. Ltd.
143.	Yixing JS Solar Co. Ltd.
144.	Yuhuan Sinosola Science and Technology Co. Ltd.
145.	Anhui Daheng Energy Technology Co. Ltd.
146.	Jiangsu Eco Green Energy Co. Ltd.
147.	Big Sun Energy Technology Inc., Taiwan
148.	Zhejiang Isola New Energy Co. Ltd.
149.	Simax (Suzhou) green New Energy Co. Ltd.
150.	Anhui Technology Imp. And Exp. Co. Ltd.
151.	Ningbo Fuxing Electric Co. Ltd.
152.	Wuxi Suntech Power Co. Ltd.
153.	Zhejiang G&P New Energy Technology Co, Ltd.
154.	Changzhou Eging Photovoltaic Technology Co. Ltd.
155.	Shenzen Topray Solar Co. Ltd.
156.	Yarrow Infrastructure Pvt. Ltd.
157.	Rattan India Solar 2 Pvt. Ltd.
158.	Leapton Solar (changshu) Co. Ltd.

159.	CECEP Solar Energy (Zhenjiang) Co. Ltd.
160.	Sepset Constructions Ltd.
161.	Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd.
162.	Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd.
163.	High Hope Int'l Group Jiangsu Foodstuffs Imp & Exp Corp. Ltd.
164.	EEPV Corp., Taiwan
165.	Sichuan Yingfa Solar Energy Technology Co. Ltd.
166.	Warburg Pincus India Pvt. Ltd.
167.	Harsha Abakus Solar Private Limited
168.	Solar Energy Equipment Manufacturers Association of Telangana (SEEMAT)
169.	Anchor Electricals Private Limited
170.	Chloride Power System & Solutions Limited
171.	Advaita Legal representing M/s. Renew Solar Power Private Limited, M/s. Solar Edge Power and Energy Private Limited and M/s Shapoorji Pallonji Infrastructure Capital Company Private Limited
172.	Hild Energy Pvt. Ltd. Eagle Press Pvt. Ltd.
173.	ASYS Group Asia Pte. Ltd.
174.	Hanwha Q Cells Corp India
175.	Neosol Technologies Pvt. Ltd.
176.	Waree Energies Limited
177.	Solsys Koncepts LLP
178.	Mytrah Energy (India) Private Limited
179.	BSES Rajdhani Power Limited
180.	REC Solar Pte Ltd, Singapore
181.	Mehar Solar Technology Pvt Ltd.
182.	Germany Trade and Invest
183.	Maxop Research & Testing Institute Pvt Ltd.
184.	Tata Cleantech Capital Limited
185.	Enkay Solar Power & Infrastructure Pvt Ltd.
186.	Azure Power
187.	Heraeus Photovolatics
188.	Mahindra Susten Pvt. Ltd.
189.	Renewsys India Pvt. Ltd.
190.	Council On Energy, Environment and Water (CEEW)
191.	Bharat Light & Power Private Limited
192.	Jinko Solar Trading Private Limited

193.	E. I DuPont India Pvt. Ltd.
194.	Applied Materials India Pvt. Ltd.
195.	Canadian Solar Manufacturing Inc.
196.	Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.
197.	LNV Technology Pvt. Ltd.
198.	Nextech Electronics Pvt. Ltd.
199.	UL India Pvt. Ltd.
200.	Uratom Solar (India) Pvt. Ltd.
201.	Tata Power Company
202.	Sembcorp Green Infra Limited
203.	BHEL
204.	Rhine Solar Limited
205.	Hero Future Energies.

8. The submissions made by all interested parties either in public hearing or otherwise have been appropriately examined and addressed under relevant paras. As many issues are repetitive, they have been collectively addressed. Data submitted by the DI has been verified onsite/desk study to the extent possible and considered appropriately.

9. In addition to the above, some of the interested parties including M/s Shree Cements Ltd and Pricewaterhouse Coopers (PWC) requested to attend the public hearing on 26th June, 2018. The Authority has granted the permission for the same.

10. A public hearing was held on 26th June, 2018. The interested parties, along with the Domestic Industry made oral submissions at the time of public hearing. In terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, all the interested parties who participated in the public hearing were requested to file written submission of the views presented orally.

11. Copy of written submissions filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties.

12. All the views expressed by the interested parties in their written submissions in pursuant to the public hearing held on 26th June, 2018 were examined and have been taken into account in making appropriate determination. The non-confidential version of the information received or acquired has been kept in the public file.

13. The list of interested parties and those who filed rejoinders were hosted on the DGTR's website for information of all concerned.

C. POST INITIATION SUBMISSIONS:

14. The submissions received in response to the initiation notice but prior to the Public Hearing are summarized as under:

(i) M/s Green Energy Association

- a. The main reasons for the petitioner's losses have not been increased imports of PUC but erroneous business decisions, global turmoil, European financial crash, etc. Till 2012-13 the Petitioners, specifically, Indo Solar, Websol, Jupiter and Moser Baer were engaged mostly in exports and least considerations were on the domestic market.

- b. Indo Solar was focused on export to the European market and also applied for being converted into a 100% EOU Company. The economic crisis in Europe due to Lehman Brother's crash on 15th September, 2008 led to the solar industry crashing and the prices falling.
- c. In 2011, the demand in Italy & Germany collapsed and the true wafer prices started showing steep downward trend. Indo Solar had signed a long term agreement at committed prices and incurred significant financial losses.
- d. Similarly, Moser Baer has also suffered losses due to the Italian government dialling down the solar policy which has resulted in demand falling much below the supply. Consequently, the prices for solar panels have gone down by 50%.
- e. Moser Baer went into losses before the start of the national solar mission, before the imports started in the country and primarily due to venturing into amorphous silicon technology and loss in advances paid to wafer/cell suppliers which did not allow the company to recover.
- f. Websol, XL Energy, etc. have faced losses due to heavy inventories being piled up in markets which have crashed such as Europe. Financial losses which have restricted them to compete in the Indian market is therefore on account of poor export performance rather than increased imports of the PUC.
- g. Petitioners have shown total production induced, comparing them to imports whereas they have not shown how much they have produced and sold from their total manufacturing capacity. Petitioners have also shown increase in the manufacturing capacity of China in terms of %age growth while not showing the manufacturing capacity in the country.
- h. The operational capacity of Mundra Solar when added, increases the petitioners capacity by a further 1200 MW. The National Solar Mission has also resulted in increase in capacity. Other solar PV module manufacturers will start suffering if safeguard duty is imposed.

(ii) M/s Eastman and Auto Power Limited

- a. Levy of SGD would result in project escalation, burden the domestic developers of solar projects, increase the tariffs and impact state DISCOMs and ultimately the end consumers.
- b. Any new imposition of duty should happen in the sunset period and must not be applicable in this fiscal year. Duty, if any, imposed must be prospective in nature and should not impact ongoing solar projects.
- c. Imposition of SGD will have far reaching consequences on India's mission to reduce carbon emission by 35% till year 2030 as per the Paris Summit.
- d. The domestic industry has been performing poorly since the country does not have a manufacturing base for polysilicon, ingots and wafers, i.e., the upstream stages of the Solar PV manufacturing chain; there is lack of setup, economies of scale and modern technology and the assured market available to the domestic manufacturers is not fully explored for the foregoing reasons.
- e. Implementation of safeguard duties is a protectionist measure and may not help the domestic industry in the medium to long run; create a huge demand supply gap.
- f. Imposition of SGD would be detrimental to the success of Indian Solar Mission.

(iii) M/s Windsor Export

- a. Indigenous manufacturers who operate out of the SEZ will be adversely affected by any blanket safeguard duties. As a result, the imposition of SGD will be counterproductive.
- b. Higher costs of power due to the duties will discourage the overall industry and lead to a decrease in demand resulting in serious setback to the National Solar Mission.
- c. Imposition of SGD must happen after the sunset review and must not be applicable this fiscal year.

(iv) M/s Vikram Solar

- a. Large proportion of the solar power production facilities located in the SEZ's; more than 60% of the solar cells and 40% of the module manufacturing facilities are located in the SEZs and therefore the imposition of safeguard duty would be counterproductive to the domestic industry.
- b. Preliminary report also suggested exempting goods coming from the SEZ units from the levy of safeguard duties.
- c. Achieving government target of 100 GW by 2022 would require the SEZ units to run at full capacity without making them uncompetitive and loading them with any extra burden. Solar units in the DTA can cater to only 1164 MW of the annualized demand of 10573 MW, which is only 11% of the demand.

- d. Imposition of SGD on imports which are required to cater to the domestic demand would only lead to an increase in the deployment cost of solar projects. Imposition of duties would therefore also be against the public interest.

(v) Economic Division, Taipei Economic and Cultural Center in India

- a. Petitioners do not have adequate standing as the domestic industry under Article 4.1(c) of the Agreement on Safeguards since, while as per MNRE there are 20 manufacturers of solar cells and 117 manufacturers of solar modules in India, the petitioners claim that these other Indian producers are importers without providing any proof to substantiate their claim.
- b. Petitioner Helios does not find mention in the MNRE table dated 28th August 2017. There must be clarity as to whether this Petitioner is a producer of solar cells, modules or both.
- c. The standing of the petitioners must be evaluated for solar cells as well as solar modules. Excluding the data submitted for Helios, the petitioners have a mere 15% share of installed capacity for solar modules out of the total capacity in India.
- d. Even the combined share of capacity of solar module is only 26.5%. Petitioners therefore do not have the standing of the domestic industry and the investigation must be terminated accordingly.
- e. Imports did not increase because of the allegedly unforeseen circumstances as is the requirement under Article XIX:1(a) of the GATT but because of the Government of India's vision to promote solar power in India, installing 100 GW of solar power grid by 2022 while being fully aware that manufacturers can cater only to 10% of the annual demand. This is the sole reason for such increase in imports.
- f. Petitioners have also failed to show how commitments entered into pursuant to ITA 1 in 2005, much before the period under consideration, could be the reason for sudden, sharp significant and recent increase in imports. Petitioners have failed to show unforeseen developments and GATT obligations as a cause for the increase in imports.
- g. Position of 3 petitioners has been improving during the POI only two petitioners have faced losses due to internal problems. While Mundra Solar PV has started commercial manufacturing in 2017 and requires more time to stabilize capacities, etc, annual reports of Indo Solar, Websol Energy Systems Limited as well as Jupiter Solar have shown either significant decline in losses or increase in profitability. Helios has been undergoing corporate debt restructuring, which is the reason for high losses to the company.
- h. Petitioners are further injured due to obsolete technology and not imports as stated by the MNRE.
- i. Major cause of injury to the petitioners has been a decline in exports from 100 indexed points in 2014-15 to 13 indexed points in 2017-18. Injury due to such factors cannot be attributed to imports of the PUC.
- j. Petitioners are also finding it difficult to stabilise rapidly increasing capacities which are leading to increasing losses due to interest and depreciation.
- k. The number of employees of petitioners has increased by 5 times during the injury period which has led to an increase in the wage costs incurred by them by 4 times.
- l. There are no critical circumstances that warrant the levy of provisional duties since the MNRE has proposed to have a Central Public Sector Undertaking (CPSU) scheme of 12,000 MW having an assured DCR component. This would provide the domestic industry with an assured market.
- m. Adjustment plan given by the petitioners indicate plans of backward integration. However, a backward integration would only lead to higher costs in the next few years and the petitioners would not be able to adjust to imports.

(vi) M/s China Chamber of Commerce for Imports and Exports of Machinery and Electronic Products

- a. DG did not wait for parties to submit their views within 30 days of initiation notice and in a hasty manner issued its Preliminary Findings within 18 days of the initiation of the investigation.
- b. SGD's can only be imposed after investigation. Without giving the interested parties an opportunity to present their view, investigation could not have been completed
- c. The entire proceedings in the instant investigation are vitiated as the same were carried out in violation of the Principles of Natural Justice. Wrongs done at various stages of the investigation cannot be rectified now by any act of DG.

- d. There is a huge domestic demand which needs to be met in light of inability of the DI to do so. Imposition of SGD will increase the cost of production. For the same reason positive findings on ADD were made but duty was not levied in public interest. Same reasons must operate here.
- e. India needs high quality imported PV products, especially from China, to meet revised targets under JNNSM.
- f. India needs a constant supply of PV Cells. SGD's would have adverse effect on downstream industries; healthy development of solar cell industry and rural electrification projects initiated by the Govt.
- g. It is normal that exports from China to EU and USA decline due to trade remedies. However, increase in exports from China to India has nothing to do with this issue. It is a free market where sales volume is market oriented. Signing ITA-1; GATT or Paris Agreement are of no consequence since it is the natural law of the market that increasing demand fuelled imports.
- h. It is a trend that the price is declining; therefore the same can't be termed as unforeseen.
- i. Increase in imports is in tandem with increase in demand of Indian Industry.
- j. The domestic industry thinks that the data cannot prove material injury suffered by the domestic industry, otherwise it would not have decided to request to terminate the anti-dumping investigation in the final stage.
- k. Data submitted by the domestic industry cannot even prove existence of material injury, then it can be easily inferred that serious injury will not be determined. There was no need of increasing the capacity every year by the applicant. Such inappropriate decisions of increasing the capacity every year might have caused injury to the applicants not the imports from subject countries.
- l. There is no correlation between the landed price and net sales realization for the Domestic Industry.
- m. First the domestic producers must establish that there is increased imports and the Domestic producer needs time and plan to adjust themselves to meet the situation of competition offered by such increased imports.
- n. The applicant's claim is inaccurate and misleading, as the differences between products manufactured from both technologies are significant in several aspects, such as raw materials, production processes, efficiency, flexibility and prices, etc.
- o. CCCME as well as other interested parties have emphasized the negative influence of trade remedy measures on the public interests for several times in the written submissions and on the hearing for the anti-dumping investigation.
- p. The following should be removed from the PUC: (i) Solar cells using the "PERC" (Passivated Emitter Rear Cell) based technology; (ii) Thin films & Bi-facial N-type solar cells; (iii) High efficiency solar cells using 5 and 6 bus bar production terminology; and (iv) Solar modules of mono crystalline technology since Adjustment Plan states that DI will produce PERC type cells.
- q. Petitioner Helios Photo Voltaic Limited does not find mention in the list of MNRE dated 28 August 2017. The DGTR must clarify whether Helios is a producer of cells, modules or both.
- r. Standing of the Petitioners should be examined separately for solar cells and solar modules. It is requested that the Designated Authority should follow its established practice and examine standing of Petitioners for solar cells and solar modules separately.
- s. India stands to act directly contrary to its obligations under the AoS by imposing a safeguard duty without demonstrating that unforeseen developments exist in the present case.
- t. Increase in imports is only due to the demand-supply gap in India. Demand has been created by the Government of India under National Solar Mission and the domestic producers and exporters are enabling the nation to fulfil the commitments under the National Solar Mission.
- u. Neither the Petition nor the Preliminary Findings objectively identify the specific GATT obligation incurred by India that led to sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods.
- v. None of the above identified GATT obligations led to recent, sudden, sharp and significant increase in imports of the subject goods in terms of Article XIX(1)(a) of GATT.

- w. There is no nexus between India's ITA-1 commitment for the subject goods and the alleged recent and sudden increase in imports. Production and sales of the domestic industry have increased by 253% and 305%, respectively during the injury period. This increase is significant.
- x. The Indian industry can only satisfy 10-15% of the Indian demand. The remaining demand has to be met by imports to meet the target under the National Solar Mission.
- y. Domestic industry's selling price sharply declined in the export market from 100 indexed points in 2014-15 to 56 indexed points in 2017-18. Imports have nothing to do with injury suffered. Real cause of injury to the domestic industry is aggressive pricing practices of other Indian producers and not imports. Backward integration in this manner will only lead to higher cost in the next few years. The Petitioners will not be able to adjust to imports if the adjustment plan requires incurring more cost rather than reduction of the same.

(vii) Solar Power Developers Association

- a. The domestic industry does not produce Solar cells using the "PERC" (Passivated Emitter Rear Cell) based technology; Thin films & Bi-facial N-type solar cells; High efficiency solar cells using 5 and 6 bus bar production terminology; and Solar modules of mono crystalline technology.
- b. Standing of the domestic industry should be examined separately for solar cells and solar modules.
- c. Relied on MNRE data for May 2017 and stated that for solar cells, the share is 56% and for modules, it is mere 15%. Arguendo, the total installed capacity is 26.5%. These data are not sufficient to constitute domestic industry.
- d. Three entities are SEZ units and these should be excluded as they cater primarily to the export market. Reliance placed on Electric Insulators.
- e. The data shows only the surge was in 2015-16. (228%) Other increases are mere (52% and 49% in subsequent years). No recent, sharp, sudden and enough imports in 2016-17 & 2017-18.
- f. Huge demand and the domestic industry can only meet 15% of the demand. Production and sales have increased by 253% and 305% respectively. Decline in utilization is temporary and will improve when production is stabilized. Mundra began its production demonstrates that the DI is doing well. Increase in wages led to decline in profits of the industry. The selling price is in line with the cost of sales in 2017-18, therefore, there's no price suppression and price depression. Indosolar's revenues have sharply increased which led to the decrease in losses by 8,322.91 lakhs. Websol improved its performance and incurred huge profit in 2016-17 of Rs. 8,594.36 lakhs. Websol also expanded its operations. Jupiter also registered a profit of Rs. 3,999 lakhs.
- g. Increase in installed capacity, net fixed assets and interest cost led to the decline in profitability. Imports of subject goods have nothing to do with the deteriorating export performance. Usage of Obsolete technology. Aggressive pricing by Adani, BHEL, Tata Power and Central Electronics have sold panels at a record low of 30 cents/kwh capacity.
- h. China's capacity is not unforeseen as it is the result of market reality. The demand for the goods have been created under the JNNSM which aims to deploy 100GW of solar power by 2022. It is reasonably expected that dumped or unfairly subsidized products face trade remedy action. The products have come from China because the state governments or public bodies have floated tenders. India ratified the United Nation Framework Convention on Climate Change in November 1993 before joining the WTO. The Paris Agreement is an agreement within UNFCCC. The commitment in Paris is result of commitments under UNFCCC.
- i. The duties became zero in 2005 only as result of India's commitments under ITA-1. Imports increased after 2010 (JNNSM). No data has been demonstrated to show that the Solar Cells case affected the imports. MNRE proposes to have a CPSU scheme of 12,000 MW with assured DCR.
- j. India expects to reach 100 GW of solar power grid connectivity. India's current solar capacity is 20GW. This is insufficient to meet the target of the solar mission. Imposition of Safeguard duty will adversely affect the National Solar Mission as the tariffs for future solar projects could rise substantially. Safeguard duty will put more than Rs. 1,00,000 crore worth of solar power projects in jeopardy.
- k. DISCOMs have indicated that they would purchase solar power only if the cost is around INR 3 per kWh. The safeguard duty in range of around 12-15 cents a year would increase the duty upto Rs 4 per kWh. There are a number of power purchase agreements between DISCOMS and project developers with capacity of around 9000 MW. Imports of such goods would be detrimentally impacted by imposition of safeguard duty.

- l. The safeguard investigation for solar cells has been hastily initiated. The examination of dumping and injury margin by DGAD was still undergoing when the safeguard had been initiated.
- m. 70% safeguard duty had been imposed without seeking any comments from interested parties. If the safeguard duty is imposed, it will distort the entire market. DISCOMS will not purchase from solar power developers as the tariffs will shoot up.
- n. The unforeseen developments mentioned by the Ld. DG did not lead to increase in imports. The increase in imports had increased because of the Government's vision to promote the renewable source of energy. The Government of India floated tenders keeping in mind that the Indian manufacturers could only cater to less than 10% of the demand.
- o. Moreover, 70% of the domestic manufacturing capacity are located in the SEZ area, mainly targeting the exports market. Therefore, such imports are not the result of unforeseen developments, rather demand created due to National Solar Mission.
- p. The DI's data for the same period reflects profits in the anti-dumping investigation. The inclusion of the recent facility, Mundra Solar PV Limited, has resulted in showing the losses to the DI.
- q. The available Annual Reports of Websol Energy Systems and Jupiter Solar Power show that there has been significant decline in losses or high profitability. The reason for losses to Helios is because of undergoing corporate debt structuring.
- r. MNRE has also proposed that the technological facility is obsolete. Moreover, the injury will not happen to the DI as MNRE is planning to include DCR in 12,000 MW of the power generation.
- s. The tariffs will increase substantially and will reach Rs. 4 per unit which will defeat the purpose of cheap supply of power. All the projects would be challenged in the courts seeking relief under 'change in law' clause.

(viii) M/s. Renew Solar Power Private Limited and M/s Solar Edge power and Energy Private Limited.

- a. The DI has emphasized on the fact that solar cells and modules manufactured using c-Si technology and thin film technology are like articles and should be treated as Product under consideration (PUC). PUC has been incorrectly defined as solar cells manufactured from c-Si and thin film technologies are two separate products and cannot be considered as like articles and cannot form part of a single investigation. The two products are differentiated on the basis physical characteristics, raw material, production process, wattage output uses and interchangeability.
 - i. Solar cells manufactured from c-Si technology and thin film technology cannot be used interchangeably as solar cells manufactured using thin film technology have lower conversion efficiencies and lower wattage output in comparison to solar cells manufactured using c-Si technology.
 - ii. At the stage of conceiving the project, the developer has the option of choosing either of the two technologies depending upon geographical indications, efficiency sought to be achieved and financial consideration. Once chosen a particular technology, it is not feasible to switch to solar cells of different technology.
 - iii. In the tenders issued by the MNRE, the government carves out distinction for solar cells of the two technologies treating them as two separate products.
 - iv. At the stage of replacement, the subject goods of thin film technology cannot be substituted with the subject goods of crystalline technology.
 - v. Post installation, the end user cannot replace a thin film technology with the module of a c-Si technology. The only way to switch from C-Si technology to thin film technology or vice-versa is if the whole of the installation under one technology is changed making it highly cost-inefficient and impractical.
- b. The DI does not manufacture solar cells using thin film industry and both products i.e. products using thin film and c-Si technology are not like article and subject goods manufactured using thin film technology cannot be treated as a part of the present investigation.

- c. Solar cells and solar modules cannot form a part of a single investigation in as much as they do not qualify as 'like article'. Module is a value added product which involves a solar cell as a raw material/input. A solar cell has limited capacity to generate electricity as opposed to a module which can generate desirable and useable electricity on a standalone basis. A solar cell cannot be inter-changeable substituted with a solar module for the purpose of generation of power.
- d. A DI comprises of the domestic producers who are engaged in the manufacture of the like article in India or those producers whose collective output constitute major proportion of the total domestic production. Certain applicant domestic producers are importers of solar cells and engaged in assembling solar cells into modules, and cannot constitute DI as they are engaged in import of subject goods and are not producers of the like article.
- e. As per MNRE's notice, there are 117 solar module 20 solar cell manufacturers in India. The application is filed by ISMA which comprises 23 members. Applicant producers have failed to provide any evidence in support that the remaining producers which do not form a part of ISMA do not manufacture the subject goods.
- f. Applicant producers located in EOU and SEZ units do not constitute DI for the purposes of the initiation notification and the preliminary finding notice because an SEZ is deemed to be a territory outside the customs territory of India for the purposes of authorised operations. Further, any goods removed from the EOU unit to the DTA will be chargeable to duties of customs including safeguard duties where applicable on such goods when imported. Therefore, units located in SEZ and EOUs are units outside the domestic territory of India and cannot be considered DI as they are at a separate commercial position on account of various incentives and benefits accruing to them, and production and sales of SEZ/EOU units are not impacted by conditions of competition in the domestic market.
- g. The power of the DGS is limited to investigations of existence of serious injury or threat of serious injury, identification of the article, submissions of provisional and final findings, recommending the amount and duration of duty and reviewing the need for continuance of safeguard duty. The recommendation of the DG for exemption of safeguard duty on goods cleared into the domestic market from the SEZ units because of certain applicant operating in the SEZs is without any authority.
- h. Factors such as Chinese excess capacities, scrapping of the domestic content requirement, India's commitment to Paris 2015, declining landed prices of imports due to decrease in global prices of inputs such as wafers, cells, silicone etc., India's obligations under the GATT and the ITA leading to its Customs Tariff elimination on imports of PUC cannot be unforeseen and unexpected.
- i. While the volume of imports increased from the base year, there has been a reduction in the percentage volume of imports on a year on year basis. The performance of the DI improved during the POI. With the increase in volume of imports, the volume of domestic sales has also risen. This evidences that there has been a substantial increase in the volume and value of domestic sales and no injury has been caused to the domestic industry. Further, there has been a significant decrease in the volume of imports of thin films and such decreased imports cannot cause serious injury or threat thereof.
- j. Decrease in market share of the applicant domestic producers is on account of the significant gap between capacities of domestic industry engaged in the manufacture of the subject goods and the actual demand for the subject goods in the country. This is evident from the fact that demand for the subject goods in the POI has consistently increased but the installed capacity of the applicant domestic producers has not increased in a proportionate manner to meet such increased demand. Therefore, there has been an increase in the market share of the import of the subject goods so as to meet the increased domestic demand.
- k. The applicant domestic producers seek to take refuge under the garb of safeguard duty for furthering their own objectives of increasing their market share without fairly competing with international players.
- l. Economic parameters such as total production, capacity utilisation, domestic sales and employment of labour force are critical in determining the level of injury. These parameters establish that the domestic industry is in-fact growing establishing that the DI has not suffered any injury on account of the imports of the subject goods.
- m. With the scrapping of DCR, developers have the option of using goods manufactured by the domestic industry or imported goods. Price of subject goods along with factors like efficiency, wattage output, after sales service etc determine the type of module that a developer will use for its projects. If subject goods manufactured by the DI fare well on these factors *vis a vis* the subject goods imported into India, there

cannot be any reasonable probability of injury to the domestic industry on account of scrapping of the DCR. Therefore, scrapping of DCR leading to an injury to the DI is misplaced.

n. There is no causal link between the alleged injury and the alleged increased imports as injury is on account of other reasons such as decrease in global demand of subject goods, reduced demand for subject goods manufactured by applicant producers, facilities such 25 year warranties not being provided by the DI, inability to employ new technological changes in the quality of solar cells and modules offered by the DI. Thus, injury caused to the DI on account of developments in technology and competition with foreign producers cannot be linked to the imports of the subject goods.

o. The preliminary finding notice issued by the DGS disregards principles of natural justice as it does not afford any opportunity of hearing to the interested parties and makes a preliminary determination of 70% ad valorem duty before the expiry of the time period provided to the interested parties.

p. Critical circumstances for undertaking a preliminary determination contemplate principles of natural justice in as much as critical circumstances require clear evidence and clarity of evidence cannot be arrived at unless representations of the other side are taken cognizance of. Evidence adduced by applicant DI cannot be clear evidence as it is open for rebuttal by other interested parties. Therefore, until this evidence is subject to some verification and cross-questioning which make it precise and explicit; it cannot be treated as clear evidence.

q. Irreparable damage is a sine qua non for recording preliminary findings by the DGS. The recommendation for the impositions fails to justify/explain the irreparable damage which would be caused to the DI justifying the preliminary determination. 'Further damage' to the DI cannot be equated with 'irreparable damage'.

(ix) M/s. ACME Solar Holdings Ltd.

- a. They are the largest solar power developers with a portfolio of more than 2GW with 874MW operational capacity working in 12 different states. Solar modules constitute more than 50% of the components required for setting up a solar power plant and are therefore, critical to the business of the company.
- b. 60% of the petitioner companies are placed in Special Economic Zones and enjoy many fiscal and non-fiscal benefits extended by the government and cannot be treated as DI for the purposes of safeguard duty. Data related to these petitioners should be excluded for representing and calculating the injuries to the Indian DI.
- c. There is a complete mismatch in the data of DI production in investigation report which is 544MW in contrast to data from government sources which is 7173MW. There is a huge difference between these two numbers and relying on the number in the investigation report has led to a flawed recommendation of imposition of safeguard duty.
- d. There has been a misrepresentation of the DI capacity as the DI constitutes much less than 72% share in the domestic solar manufacturing industry in 2017 as 10.5% of the industry in 2016.
- e. There is no unforeseen circumstance arising out of the commitment to the Paris Agreement or the National Solar Mission as the Ministry of New & Renewable Energy in their Annual Report Solar 2016-17 acknowledged that the mission targeted included deployment of 20,000 MW of grid connected solar power by 2022. The DI was never prepared to cater to the increasing demand of solar modules and panels due to the government's commitment for 100GW by 2022. This forced solar power developers to import modules and panels to fulfil rising demand.
- f. The DGS linking India's commitment under the Information Technology Agreement providing for exemption of BCD for ITA-1 goods was undertaken way back in 1996 and any recent increase in imports of PUC are remote and cannot be unforeseen.
- g. These circumstances of increase in imports aren't unforeseen and are not an effect of obligations under the GATT including tariff concessions. Therefore, the requirement under Article XIX of the GATT is not satisfied.
- h. The cost of a solar cell is 50 to 60% of the total cost of module. The prices of Indian models have gone down by margin of 27 to 30% in contrast to the decrease shown in the report in the period of 2014-15 to

2017-18. The cost of cell has gone down by 38% in 2017 with respect to 2014-15 whereas the cost of module has gone down by only 8%. This is contrary to logic as cells are approximately 60% of the cost of module. Therefore, the effect of decline in cell price should be more significant on the module price. Therefore, there has been a blemished assumption of Net sales realisation of DI.

- i. The growth of solar power sector has created more number of semi skilled jobs providing opportunity to youth in rural areas. The growth in employment opportunities is depending on the cheaper power to be made available to the DISCOMS.
- j. The DI is making noticeable profits in their margin and equity portion in the past 2 years which is contradictory to their claims of incurring significant losses as per the balance sheet obtained from the Registrar of Companies.
- k. The growth of total production of DI has grown from 473 to 838 which is near to 100% of growth in the production. Therefore, it is not appropriate to look at the import data in isolation when the complete ecosystem of solar business grew by 100% in year of 2016-2017.
- l. Imposition of the safeguard duty has violated principles of natural justice as the DGS did not afford an opportunity to exporters or other interested parties to raise their objections against the initiation.
- m. The DGS solely relied on the data provided by the DI regarding injury to the DI without verifying the authenticity of the information so provided. Only in respect of the import data, the same has been obtained from the DGCI & S, Department of Commerce for POI till June 2017 and thereafter from Infodrive Media for the balance period of the POI. No independent data has been produced by the DI to show serious injury to DI as a result of increased imports. Most of the data provided by DI pertaining to profit/loss, employment, and production is wrong and misleading as demonstrated with independent data from an authentic source.
- n. Any levy should be supported by data and reason for arriving at the levy and there should be a direct nexus between the levy and the object being achieved by introducing such a levy. Such reason is absent in the preliminary finding of the DGS.
- o. The government notified the revised Tariff policy on January 28, 2016 wherein the policy recognised the need to attract adequate investments in the power sector for ensuring availability of electricity to different categories of consumers at reasonable rates and for achieving rapid economic growth and improvement in living standard of citizens. All the PPAs except those mandating domestic procurement factored in the costs of import of solar cells and modules. Increase in the cost of import of solar cells and modules will have a direct and material impact on the solar power development industry.
- p. The indigenous module manufacturing industry only contributes about 10-13% jobs in the entire value chain. The ancillary sector named BOS has 60 industries wherein the total employment generation is 70-90%. With developers under strain, this entire quantum will come under jeopardy.
- q. Due to competitive bidding process, solar power developers take into account customs duty in respect of solar modules used for setting up the power plant. The rate quoted by solar power developers is required to be maintained for 25 years subject to change in law clause in the PPA. At the time of bidding, the company did not take into account safeguard duty for the purpose of quoting the unit price and any levy of safeguard duty would increase the cost of power rendering the entire project unviable. Further, in respect of contracts already awarded, the company placed order for import of solar cells and modules, levy of duty would lead to a huge cash flow issue when the imports are cleared from the customs on payment of such duty. The exercise of filing a petition before the Commission to amend the change in law clause in the PPA to cover levy of safeguard duty will be a long drawn process and delay in getting the tariff revised would impact the business.
- r. Due to delay, most projects will fail to take off and banks will be reluctant to infuse funds in light of uncertainty over the levy of safeguard duty.
- s. Imports in India increased because of the Government's vision to promote renewable sources of energy in contrast to the DG's view that China diverted its exports to India because of trade remedy measures by the US and that India can no longer provide the protective ambit of Domestic Content Requirement to the

domestic industry. Imports from China and other countries fill the demand supply gap in India wherein the Indian manufacturers could cater to only less than 10% of the demand.

- t. The DI paints a picture of losses due to the addition of a company with a new manufacturing facility in 2017. New facilities involve high cost of interest and depreciation which have a detrimental impact on profitability. Injury to such companies is not because of imports but because of high interest cost and depreciation cost.
- u. Position of three petitioners have improved in the injury period in contrast to two petitioners who faced losses due to intrinsic problems such as a new manufacturing facility, restructuring and obsolete technology. Therefore, an increase in imports has not led to injuries.
- v. The MNRE has proposed to have an additional CPSU scheme of 12,000MW which will have an assured DCR component allowing the domestic industry an assured market. This, the DG's conclusion that serious injury will occur if provisional safeguard duty is not imposed is incorrect.

(x) M/s. Amplus Energy Solutions Private Limited

- a. The proposed safeguard duty imposition of 70% duty on imports of "Solar Cells whether or not assembled in modules or panels" will lead to an NPA of INR 700 Crores in projects due to inability of the company to pay immediate imposition of the duty leading to 100% equity write-off of the company and non-commissioning of under construction solar projects.
- b. Imposition of duty will cause reputation loss to India's "Ease of Doing Business" and "Investor Friendly Policy" due to FDI Investment of INR 1000 Crore.
- c. Imposition of duty will lead to the company's inability to supply at the tariff contracted in Power Purchase Agreements with leading global companies and shake their confidence in Indian policy regime and hinder further expansion.
- d. The company's financial distress will result in loss of jobs for 2700 people, which is higher than the employment in Domestic Cell Industry.
- e. Impact on employment will be worse with large solar developers and the EPC Industry due to employment of 10,000 employees, therefore, imposition of the duty with a grace period will provide adequate period to domestic solar EPC industries.

(xi) M/s. Clean Max Enviro Energy Solutions Pvt. Ltd.

- a. They are the largest "Rooftop Solar Developer" in India with an average 22% market share in the last 3 years.
- b. The company will have to pay safeguard duty of INR 350 Crores which is a loss as it is greater than the total equity investment of INR 260 Crores in the project to develop 166MW AC Capacity of solar in Karnataka. This will cause the company to declare bankruptcy.
- c. The cascading effect of the duty will be an increase in banking NPA upto INR 660 Crores due to inability of the company to pay immediate imposition of the duty leading to 100% equity write-off of the company and non-commissioning of under construction solar projects.
- d. The company's financial distress will result in loss of jobs for 2165 people, which is higher than the employment in Domestic Cell Industry.
- e. Impact on employment will be worse with large solar developers and the EPC Industry due to employment of 10,000 employees, therefore, imposition of the duty with a grace period will provide adequate period to domestic solar EPC industries.
- f. Imposition of duty will cause reputation loss to India's "Ease of Doing Business" ranking of World Bank and "Investor Friendly Policy" due to FDI Investment of INR 250 Crores.
- g. Impact on financial health of sub-contractors who are small scale businesses due to the financial distress of the company.

(xii) Government/Embassy of Mexico

- a. Imports of Mexican product carried out by India during the period of January 1, 2014 to September 30, 2017 are less than 3% of the total imports by India in the same period. Mexico is a developing country and the exports of Mexico should be excluded from the application of the safeguard duty by virtue of Article 9.1 of the Agreement on Safeguards.

(xiii) European Commission

- a. The major quantity of the PUC is imported from China. The entire reasoning used to justify the need for imposition of the safeguard duty is built around imports from China. Increase in imports from one country only, even if sharp and significant is not enough to justify the use of safeguards which applies equally to all imports. Chinese imports are currently subject to an anti-dumping and it seems appropriate to wait for the conclusion of this ongoing AD investigation before imposition of a safeguard duty.
- b. Based on the data provided, it not possible to draw a conclusion of a surge in import volumes during the first six months of 2017-18 by 74% as compared to imports in 2016-17. To make a consistent comparison, the first six months of 2017-18 should be compared to the same period in the previous year. The alleged surge of 76% remains unclear, wherein on the contrary there was a decrease of 26%. The investigating authorities should clarify these figures and provide the relevant data.
- c. Imposition of trade remedy measures by the EU and US on imports of the same product from China and scrapping of the DCR in India are seen as unforeseen developments. Following the imposition of AD and CVD measures by the EU and US, India did not immediately suffer from increased imports due to the DCR. Following a challenge in 2013, the WTO declared the DCR as inconsistent and India had to abandon it. This took place in 2013 and cannot constitute an unforeseen development for increase of imports in 2017.
- d. Commitments to reduce CO2 emissions have caused an increased in Indian demand for solar energy. If an increase in demand results in an increase of imports, it may indicate that the DI did not have enough capacity to satisfy the increased domestic demand.
- e. Serious injury in safeguard investigations is more demanding than the material injury required in AD/CVD investigations. Total sales of the DI increased more than 5 times and production increased more than 3 times over the period considered. The DI installed an additional capacity of 1000MW in 2017-18 when it still has 22% unutilised capacity. The drop in capacity utilisation is a consequence of investment in additional capacity.
- f. A new company entered the domestic markets leading to an overall increase in the total number of employees. DI argued that jobs generated by new company should be taken out of figure to observe decline in employment. Such exclusion is artificial and intends to hide relevant facts in the assessment of employment.
- g. The DI incurred losses throughout the whole period considered before the alleged increase in imports. This means there are causes other than imports that must be investigated as a cause of losses.
- h. export markets combined with a negative performance in the domestic Factors such as decisions to invest in additional capacity, heavy losses in industry during a period of increase in demand, imports constituting a major and stable share of the domestic market which put the causal link in question have not been taken into account.
- i. Any safeguard measure would equally affect imports from all sources which enter the Indian market in low quantities and which are not responsible for any injury caused to the DI.
- j. Huge increase in domestic demand of more than 600% over the period considered means that even if the DI were to produce at 100% of its capacity, it would cover only 16% of the total Indian demand. Therefore, any safeguard measure will apply to almost 85% of the market which would lead to unduly increase in prices for Indian importers and downstream users, limit product choice and lead to serious shortages in the domestic market which would additionally not help India in achieving its commitments under the Paris Agreement.

(xiv) Taiwan Photovoltaic Industry Association

- a. Three out of five applicant domestic producers are located in the SEZ and cannot be treated as domestic industry as SEZ area is deemed to be territory outside India and all governing legislations for import or export goods will apply to them. Goods produced by an SEZ unit cannot be said to be domestically manufactured.
- b. Application filed by the DI is not maintainable due to excessive confidentiality claimed by the DI affecting rights of defence of interested parties, falling prices, excess capacity not being justifiable grounds to substantiate injury to the DI, imposition of duties significantly impacting the National Solar Mission, increase in imports not being unexpected and sharp and significant enough for imposition of the duty.
- c. Growing demand for subject goods is met by both DI and imports due to lack of capacity of the DI to meet the demand. Domestic demand is much higher than the installed capacity of the DI.
- d. DGAD has initiated Anti-Dumping Duty Investigations on imports of solar cells whether or not assembled from China PR, Taiwan and Malaysia. Interest of the DI is being protected by the AD investigations from potential material injury caused due to increased dumped imports if a finding is made by the DGAD. Levy of both AD Duty and Safeguard duty amounts to double jeopardy.
- e. Domestic producers namely Indosolar, Websol and Jupiter Solar filed petition for imposition of AD Duty and vide final finding, the DGAD imposed such a duty. However, the Central government didn't notify imposition of such duty. The DI since then, is on a course to eliminate competition from import of subject goods. The DI has filed another application for imposition of safeguard duty as method of forum shopping and creating a cartel to gain advantage under the garb of safeguard duty and eliminate fair competition.

(xv) First Solar FE Holdings Pte. Ltd. (USA, Singapore)

- a. Thin film products and c-SI PV are not like article or directly competitive articles on the basis of parameters such as physical and technical properties, production technology, etc. Neither of the two products can generate useable electricity without Balance of System. It is only after integration with Balance of System that the two products can generate useable electricity. This makes them two alternatives and not like articles. Thin film products are required to be excluded from the purview of the PUC. Present investigation tantamount to investigating two alternate products in one investigation.
- b. The fundamental objective of establishing of SEZ units is promotion of exports. Areas of the SEZ are excluded from the definition of Domestic Tariff Area and removals therefrom are subject to duties of customs. DTA sale of goods manufactured by a SEZ unit can be made only on submission of import license. The contentions for treating the SEZ unit as part of the DI are not acceptable.
- c. Term used in the safeguard law is 'producers in India' and the SEZ unit established in SEZs are very much producers in India being the same is not tenable as SEZ unit is deemed to be a territory outside the customs territory of India. SEZ producer cannot be a DI and should be excluded from the scope of DI.
- d. Petitioners do not have standing to maintain the present petition as their production does not constitute a major proportion in Indian Production and largely constitutes production for exports.
- e. Import of cells is import of raw materials and cannot be included in imports. There is no surge in Imports as module production in India by other producers must be added to Indian production. Thin films should not be included in the purview of causing injury as surge in imports are predominantly due to C-SI PV.
- f. The notice of initiation does not identify any unforeseen development and is inconsistent. Surge in imports of cell is due to industry itself importing the cell rather than producing in India. Imports by other producers not part of the petition cannot be described as unforeseen.
- g. Performance of the DI has materially improved. Products and sales of the DI have shown a significant increase over the injury period. DI has not suffered injury due to imports into India. Petitioners have suffered injury to exports which cannot be remedied by safeguard duty.
- h. Threat of serious injury parameters cannot be same as injury parameters as no further data or analysis in the notice of initiation shows that there is threat of serious injury.
- i. As a result of collapse of export market for the DI, the cost of production of the DI has substantially increased. The domestic market as a result of several govt initiatives to enhance solar power capacity

in India has shown an upturn. Companies which have not been able to utilise capacity for significant part of last four years has recommenced commercial production.

- j. The DGAD has earlier recommended ADD which were not imposed by the Central Govt. in absence of serious injury to the DI from imports, a safeguard duty increased prices of imported goods for the domestic consumers and provides cushion for DI to increase prices, where the ultimate sufferer is the domestic consumer. This establishes that imposition of safeguard duty is not in public interest.

(xvi) First Solar Inc.

- a. Preliminary objection on the ground that an SEZ unit had been deemed to be part of the Domestic Industry. SEZ unit cannot be considered as part of the domestic industry, as was also evident from inconsistency with the past decisions of the Director General. This issue should be decided before proceeding further in the case.

(xvii) Solar Energy Equipment Manufacturers Association of Telangana

- a. There is a solar cell manufacturing capacity of 1.6GW and module manufacturing capacity of 5.5GW in the country. Solar cell manufacturers have a solar module manufacturing facility which consumes solar cells produced by them. Imposition on safeguards duty in solar cells will lead to a problem in procuring solar cells by solar module manufacturers.
- b. Solar cells and modules are considered as single entity for imports, the solar modules and solar cells are allowed at zero duty. Solar cells consist 60% of the cost of solar module and 40% of the material required for manufacture of the solar module is procured by the solar modules manufacturers by paying import duties but imported modules is allowed free of duty. Imposition of SME solar module manufacturers will be in a severe disadvantage compared to the solar cells manufacturers.
- c. Solar cells are not available in India as most solar cell manufacturers have module manufacturing capacity to use up all their production. Manufacturing cost for the solar module manufacturers which are mostly SME will go up by 42% compared to the manufacturers who have cell manufacturing as they are forced to import cells by paying 70% duty.
- d. There should be a different safeguard duty for solar cells and modules. There is no enough capacity in solar cells and creating capacity is expensive and time consuming, so there shouldn't be an imposition of safeguard duty on solar cells.

(xviii) Warburg Pincus India Pvt. Ltd.

- a. The company has invested in CleanMax Solar, which is executing about 300MW solar projects across India serving leading domestic and multi-national corporate as well as government owned entities. Safeguard duty on the company's ongoing projects will result in job losses and impairment of investor capital damaging its long-term prospects.
- b. Debt financing of ongoing projects provided by Indian banks will be at the risk of turning into non-performing assets.

(xix) M/s Vikram Solar Limited

- a. Solar Cells are the most basic unit of a solar PV system. A PV module consists of multiple PV cells connected in a series to provide higher voltage output. Modules are value added products that convert solar cells into a commercially useful commodity used for generation of electric power. In light of the limited domestic capacity for manufacture of solar cells, module manufacturers have to depend on imported cells.
- b. Safeguard duties imposed on solar cells will have the effect of the SEZ unit paying the duties for all its solar cells modules being removed from the DTA. Such a measure will lead to adverse impacts on SEZ units.
- c. The government's plan to install 100GW of Solar energy by the year 2022 requires SEZ units to be allowed to run to their full capacities without loading them with any extra burden and without making them uncompetitive. The domestic solar energy demand to a great extent depends upon the production in SEZ

units and on imported solar cells. Imposition of duty will lead to increase in deployment cost of solar projects.

- d. There is a huge gap in the demand and supply of solar modules manufactured by domestic producers. Large fractions of domestic production is located in SEZ's and imposition of Safeguard duties would not only adversely affect such manufacturers but also make it impossible to attain the target of 100GW of solar power by 2022 as large parts of the 100GW target has to be catered through imports. This will lead to generation of power through conventional fuels such as coal and related environmental issues. Imposition of safeguard duties is therefore clearly against public interest, which is the guiding principle for imposing SGD.
- e. If SGD is imposed, DG must prescribe a Tariff Rate Quota (TRQ) of 5GW at nil rate of duty. TRQ would address most of the concerns of the stakeholders. It would cater to the demand-supply gap without any additional burden on the cost of production of solar power generation while giving relief to the domestic production facilities set up in the SEZ's and protecting the DTA producers by providing SGD on imports beyond the prescribed quotas under the TRQ regime.
- f. Government of India should grant specific exemption under section 25(1) of the Customs Act, 1962 from payment of SGD on solar modules removed from SEZ to DTA.
- g. Relied on the USITC Safeguard recommendations wherein it recommended a higher Safeguard duty on the Solar Cells assembled in Modules/Panels as compared to Solar Cells to request an imposition of a higher safeguard duty on solar cells assembled in Modules/Panels.

(xx) Department of Foreign Trade, Royal Thai Government

- a. Safeguard measures shall not be applied against a product originating in a developing country member as long as its share of imports of the product concerned in the importing Member does not exceed 3%. Imports from Thailand are below 3% in the past three years. Therefore, Thailand should be excluded from the imposition of these measures.

(xxi) Green Energy Association

- a. There are two products under consideration in the instant case, (i) Solar cells unassembled in modules or panels and (ii) Solar cells assembled in modules or panels. The petitioners do not fulfil the requirements of the DI in both the PUCs.
- b. In both the PUCs, the petitioners do not fulfil the criteria of Domestic Industry as the operational facility of the petitioners is less than 50%.
- c. The production of the cell manufacturers which operational facilities have increased y-o-y and the overall productivity has also been more than 90%.
- d. The Government has committed to generate electricity from Solar Energy. For the same, Ujwal DISCOM Assurance Yojna (UDAY) was launched providing for financial turnaround and revival of Power Distribution Companies in aiming to ensure a sustainable permanent solution to the problem.
- e. The business and profitability of the Indian module and cell manufacturers have gone up.

(xxii) Mahindra Susten Pvt. Ltd.

- a. India is set to become the third biggest solar market globally in 2017. Many solar power developers of India have accordingly built up projects exceeding 1 GW mark. This has led to steep fall in the prices of the cells and modules which subsequently pushed India to achieve 100 GW of solar power by 2022.
- b. This has been possible because of efficient and low cost solar modules. Module prices account for 75% of the total cost of the solar project. Since the module transactions are entirely dependent on market and environmental factors, the companies have bid on these criteria only. The protection under Safeguards has not been accounted at the time of bidding. Therefore, the prices of the products will subsequently rise leading to increased rate of tariff.
- c. It will also lead to the drying up the future projects as the investors will be more circumspect and wary of investigating in the future. This will break the entire chain and a lot of people will remain unemployed.
- d. One of the biggest fallouts will be the banks/financial institutions, who have provided loans to the solar companies. These banks will have additional non-performing assets due to solar projects being non-viable and the new NPAs are expected to be anywhere between Rs. 12,000-20,000 crores.

(xxiii) Clean Max Enviro Energy Solutions Pvt. Ltd.

- a. Clean Max has received government approval to develop 166 MW AC capacity in Karnataka, 40 MW of rooftop projects and 24 MW of solar capacity under the Solar Energy Corporation of India rooftop allocation programmes.
- b. It has also attracted the Foreign Direct Investment of Rs. 245 crores. For fulfilling the above demand, it has taken term loans to develop from Yes Bank, State Bank of India, RBL Ltd., IDFC and Tata Capital.
- c. The proposed imposition will result bankruptcy and subsequent litigation under the contracted price increase.
- d. There would be total loss of Rs. 350 Crores which is more loss as compared to the estimates. This will create potential NA of Rs. 660 crores. 2000+ people will lose their jobs, 165 direct and the rest in the chain supply. The ease of doing business rank of India will also go down.

(xxiv) M/s ACME

- a. The safeguard investigation for solar cells has been hastily initiated. The examination of dumping and injury margin by DGAD was still undergoing when the safeguard had been initiated.
- b. 70% safeguard duty had been imposed without seeking any comments from interested parties. If the safeguard duty is imposed, it will distort the entire market. DISCOMS will not purchase from solar power developers as the tariffs will shoot up.
- c. The unforeseen developments mentioned by the Ld. DG did not lead to increase in imports. The increase in imports had increased because of the Government's vision to promote the renewable source of energy. The Government of India floated tenders keeping in mind that the Indian manufacturers could only cater to less than 10% of the demand.
- d. Moreover, 70% of the domestic manufacturing capacity are located in the SEZ area, mainly targeting the exports market. Therefore, such imports are not the result of unforeseen developments, rather demand created due to National Solar Mission.
- e. The DI's data for the same period reflects profits in the anti-dumping investigation. The inclusion of the recent facility, Mundra Solar PV Limited, has resulted in showing the loss to the DI.
- f. The available Annual Reports of Websol Energy Systems and Jupiter Solar Power show that there has been significant decline in losses or high profitability. The reason for losses to Helios is because of undergoing corporate debt restructuring.
- g. MNRE has also proposed that the technological facility is obsolete. Moreover, the injury will not happen to the DI as MNRE is planning to include DCR in 12,000 MW of the power generation.
- h. The tariffs will increase substantially and will reach Rs. 4 per unit which will defeat the purpose of cheap supply of power. All the projects would be challenged in the courts seeking relief under 'change in law' clause.

(xxv) Solar Power Developers Association

- a. The safeguard investigation for solar cells has been hastily initiated. The examination of dumping and injury margin by DGAD was still undergoing when the safeguard had been initiated.
- b. 70% safeguard duty had been imposed without seeking any comments from interested parties. If the safeguard duty is imposed, it will distort the entire market. DISCOMS will not purchase from solar power developers as the tariffs will shoot up.
- c. The unforeseen developments mentioned by the Ld. DG did not lead to increase in imports. The increase in imports had increased because of the Government's vision to promote the renewable source of energy. The Government of India floated tenders keeping in mind that the Indian manufacturers could only cater to less than 10% of the demand.
- d. Moreover, 70% of the domestic manufacturing capacity are located in the SEZ area, mainly targeting the exports market. Therefore, such imports are not the result of unforeseen developments, rather demand created due to National Solar Mission.
- e. The DI's data for the same period reflects profits in the anti-dumping investigation. The inclusion of the recent facility, Mundra Solar PV Limited, has resulted in showing the loss to the DI.

- f. The available Annual Reports of Websol Energy Systems and Jupiter Solar Power show that there has been significant decline in losses or high profitability. The reason for losses to Helios is because of undergoing corporate debt structuring.
- g. MNRE has also proposed that the technological facility is obsolete. Moreover, the injury will not happen to the DI as MNRE is planning to include DCR in 12,000 MW of the power generation.
- h. The tariffs will increase substantially and will reach Rs. 4 per unit which will defeat the purpose of cheap supply of power. All the projects would be challenged in the courts seeking relief under 'change in law' clause.

- **Solar Power Developers Association – Letter to CBEC**

- a. The domestic PV manufacturing sector is not aligned to support the 100 GW Solar Mission due to obsolete technology, high cost of land/electricity, low capacity utilization, high cost of financing, and lack of skilled workforce.
- b. MNRE came up with a concept note for creating the value chain of PV manufacturing capacity within India and adequate support to be competitive with other countries like China, USA, etc.
- c. Investors trusted Government's policies and increased solar power capacity from 1.4GW to 16GW in 2018. 80% of the country's module requirements is met through imports with solar cells & modules manufactured on latest technologies, high efficiencies and at competitive price.
- d. Since the anti-dumping investigation has not been concluded, there is no point of having a parallel safeguard investigation. DG Safeguard has imposed provisional duty within 17 days only without even waiting for the submissions.
- e. Imposition of duty will prompt countries to increase the cost of silicon and wafers which will subsequently lead to increase in the module prices.
- f. The costs of modules have increased significantly, and developers are putting hold on the further dispatches of module. Coal Mafia is also involved to halt the growth of renewable sector. At the current domestic production, it is not possible to meet the requirements of the nation. All the development done in the field of renewable energy will come to halt and the government will move towards the thermal energy. It may result in the increase in imports of coal.
- g. The total employment generation in the ancillary sector amounts to 70 to 90% whereas the manufacturing sector only contributes 10 to 13%. Imposition of safeguard will hamper the employment generation and also will stop the investments in the Indian solar sector. Moreover, it would also lead to the germination of a lot of legal disputes.

- **Solar Power Developers Association – Letter to DGS**

- a. The country is aiming for 100 GW of power generation. India has currently achieved a little more than 12 GW. India's demand of power cannot be met by the domestic producers.
- b. Investments of around 40,000 crores have happened recently and more than 50,000 jobs have been created lately. Any duty would adversely affect the financial viability of these projects and render the bank loans into NPAs.
- c. Since the anti-dumping investigation has not been concluded, there is no point of having a parallel safeguard investigation. DG Safeguard has imposed provisional duty within 17 days.

(xxvi) **Aditya Birla Renewables Limited**

- a. Government is offering protection to the domestic cell manufacturers by way of tenders under DCR category.
- b. There are no poly-silicon and wafer manufacturing capacity in India and prices of both the items are quite volatile in the global market. All these work on the cost-plus model which makes estimates of tariffs to be bid in the auctions extremely challenging. In India, the monopolistic situation will not be able to take bids.
- c. The current pricing is competitive as they have control over entire value chain. Overseas manufacturers have the advantage of economy of scale, low rate of interest, low electricity cost, higher productivity, common Effluent Treatment Plants, the complete eco-system involving the machinery and raw materials for solar manufacturing and logistics infrastructure. All these lead to the reduction in costs.

- d. Imposing the safeguard duty will increase the electricity tariff and consumers have to pay the electricity tariff.

(xxvii) First Solar Inc

- a. Thin Films products and c-SI PV products are not like articles or directly competitive products because there is a significant difference in physical & technical properties, production technology, manufacturing process, plant & equipment, raw materials, difference in Balance of System (BOS), costs and prices. Without BOS, the two products are two alternatives and cannot make like products.
- b. BOS are different for Thin Film and c-SI PV. The findings in USA have provided that Thin film and crystalline modules are different articles.
- c. Based on Unwrought Aluminium, First Solar submits that the SEZ units cannot be considered as Domestic Industry. The SEZ unit is deemed to be a territory outside customs territory of India and all produce therein treated as a produced outside India.
- d. Reliance is placed on the findings in Electrical Insulators and it was stated that these SEZ units are not competing with other domestic units, therefore, it cannot be treated as Domestic Industry.
- e. The petitioners do not constitute major proportion in the Indian production as the production constitute below 25% of the product. The imported cells used for making modules should not be included in the Domestic Industry. The petitioners have not quantified the Indian production in an objective manner.
- f. Assuming that the petitioners produce more than 50% of the products, the DG Safeguards have to determine the Domestic Industry which did not happen in the present case and the DG Safeguards accepted the claims of the petitioners without any evidence.
- g. Imports of cells should not be included as these are imports of raw materials. Cells imports in India for production of modules should be excluded from imports. The surge is because of c-SI PV and not because of thin films.
- h. There have not been any unforeseen developments demonstrated in the initiation. Government of India has planned for development of solar power in the country. Trade measures are also not recent and therefore, cannot be seen as unforeseen developments.
- i. The performance of the domestic industry has significantly improved. The sales and production have shown a substantial increase over the period. Productivity and Capacity Utilization have shown marked improvement.
- j. Initiation notice lacks objectivity as certain parameters after segregating the domestic industry into two parts while certain parameters have not been.
- k. Market share presented by the Domestic Industry is incorrectly presented as it does not include the production of modules by other parties whereas market share of domestic industry by their own claim increased in the recent period.
- l. Capacity Utilization has declined due to addition of new producer. Employment has shown massive increase.
- m. There has been substantial decline in exports of the products. As a result, the cost of production has substantially increased. The per unit costs determined by the petitioners are based on the actual sales made by the domestic industry in domestic and export market. The export performance has materially deteriorated, thus, leading to showing the deterioration in both domestic and export market.

(xxviii) Harsha Abakus Solar

- a. Duties should not be levied on under construction projects as the modules are ordered or are yet to be ordered or in the pipeline in logistics.

15. A brief summary of the written submissions filed by the interested parties are as under:

(i) European Commission

- a. Use of the SGD instrument is not appropriate for the present case as it is restricted for extraordinary cases as they apply to imports from all sources. Imports have increased mainly from China, which also accounts for

94% of import volumes and 95% of import values, while minor quantities are imported from other countries.

- b. Increase in imports only from one country are not enough to justify imposition of global Safeguard measures. Use of such trade restrictive measure must be deferred till determination of the anti-dumping investigations against imports from China.
- c. Use of safeguard measures would affect imports from all sources, including those that account for less than 5% of total import value which cannot be responsible for injury to the domestic industry.
- d. Article XIX of GATT permits the use of SGD measures to instances where imports increase as a result of unforeseen developments.
- e. Imposition of trade remedy measures by US and EU in 2012 and 2013 have taken place much before the considered period.
- f. The dismissal of the Domestic Content Requirement as WTO-incompatible following a 2013 WTO ruling cannot form part of unforeseen developments as contemplated under Article XIX of GATT as the same happened 4 years ago.
- g. Imports increased to satisfy increased domestic demand since the Domestic Industry was unable to meet the surge in demand following India's commitments under the Paris Agreement.
- h. No Causal Link has been established since the Domestic Industry was already facing losses at the beginning of the period of investigation, i.e., since before the imports increased; while key indicators such as total sales and production has been increasing.
- i. Other factors as prescribed under Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguards need to be evaluated.
- j. The loss making domestic industry has made investments to increase its capacity rather than exploiting the 22% capacity that already lies unutilized. Consequent drop in capacity utilization has proven that the same wasn't a prudent business decision and its impact on the Domestic Industry needs to be taken into account.
- k. There has been a significant decline in export performance of the Domestic Industry which has led to decrease in overall profitability. Inefficiencies and other reasons for negative export performance must be identified before attributing the same to increased imports.
- l. Imports have always maintained an important share of the domestic solar market suggesting that the domestic industry has not been able to meet the domestic demand.
- m. Imposition of SGD measures are against public interest since the unduly increased price restricts product choice and in light of increased demand and Domestic Industry's inability to meet the same, lead to serious shortages and adversely affect India's commitments under the Paris Agreement.

(ii) Embassy of the People's Republic of China in India

- a. Anti-dumping investigation against Chinese imports was terminated on 23rd March, possibly, for the lack of any injury or dumping and the final finding would not favour the Domestic Industry. Safeguard measures require stricter conditions and if no injury was determined in the anti-dumping investigation, then serious injury or threat thereof could not have existed. The investigations must therefore be terminated without any measures.
- b. Half of the 80% of the imports that the total solar installation capacity of 100 GW sought to be achieved relies on comes from China. Imposition of Safeguard measures could therefore increase India's power generation cost and consequently India's infrastructure construction and development of the economy.
- c. Investigations must be conducted in a fair and objective manner in accordance with the WTO rules. Safeguard measure is a strong tool to provide overprotection to the Domestic Industry and the same is to the disadvantage of the development of India's solar photovoltaic industry.
- d. Imports from China to India are made under fair and normal conditions and haven't caused or threatened to cause serious injury to the Domestic Industry. Chinese producers have maintained good trading partnerships with Indian companies and developed effective cooperation with India's relevant institutions in the aspects of investment, technology transfer, etc. There is huge scope for cooperative business opportunities in the field of renewable energy between China and India.

(iii) M/s WAAREE Energies Ltd.

- a. Close to 90% of estimated 10.7 GW of modules installed in India in previous financial year was captured by overseas module manufacturers with almost all major utility scale installations using Chinese modules. This

has been possible in spite of multiple BNEF Tier 1 Domestic Manufacturers and more than adequate domestic capacity.

- b. Major markets for Chinese modules have imposed anti-dumping barriers and consequent increased imports are stifling the growth of domestic manufacturing segment.
- c. There are signs of predatory pricing to hold and expand existing market share, as reflected in one instance, where the Chinese module prices came down by more than 21% in a span of 3 weeks without any accompanying technological breakthrough or changes. No commercial economies of scale can be expected to bring such drops other than predatory pricing.

(iv) M/s First Solar Inc., First Solar FE Holding Pte. Ltd. & First Solar Malaysia SDN. BHD.

- a. Petitioner has been forum shopping as is evident from the withdrawal of ADD Application on 27th February, 2018 after Provisional SGD of 70% was imposed on 5th January, 2018. Petitioner withdrew ADD application, as the dumping margins and injury margins would not have been high enough to warrant such a high duty.
- b. Articles are not like/directly competitive on basis of physical and technical properties, production technology, manufacturing process, plant and equipment, raw materials, difference in balance of systems (BOS), costs and prices. The only rationale behind the inclusion of thin film products within the scope of product under consideration seems to be that they are used for the same purpose.
- c. Substantial investments in BOS required for converting electricity into AC form that is usable. Cost of systems for Thin Film and c-Si Cells constitute 45-50% of total project costs and the same vary significantly.
- d. Without integration with BOS, neither cell can create usable electricity and this makes them 2 alternatives instead of like/directly competitive products. The BOS are different, with entirely different cost structures, in respect of thin film products and c-Si PV products.
- e. Petitioner has misled the Authority into believing that the consumers have interchangeably used thin film products and c-Si cells and modules. While consumers of the products have set up plants using both the technologies, there is no evidence to show that these consumers have interchangeably used thin film products and its BOS in the same c-Si photovoltaic plant.
- f. Once a developer has chosen one of the two technologies and has started implementation of the project, the developer is not in a position to switch over to other type of technology.
- g. Merely because thin film products and c-Si can be used for the same purpose does not justify inclusion thereof within the scope of PUC. There are other products which convert solar energy into electrical energy and if a criterion applied at present to treat them is to be adopted, there are other products as well which shall become like article to the products under consideration
- h. Investigating authorities in US and EU determined that c-Si and thin film products have limited interchangeably and the two products are not similar with reference to findings in ADD, SGD and CVD investigations.
- i. In investigations conducted in US and EU, Domestic Industry producers were producing both the product but still the investigating authorities took note of the fact that thin film products and c-Si products are extremely different in their nature and characteristics and cannot be clubbed under one investigation
- j. Present investigation is a different investigation having no linkage with the previous ADD investigation where duty wasn't even levied by the Government of India. Scope of PUC's across findings has been changed in some ADD investigations such as the PUC as Ammonium Nitrate differed between different investigations. Therefore, when the scope of PUC in a previous ADD investigation was not considered binding in the subsequent investigation, it cannot be argued that the scope of product under consideration in the previous ADD investigation of the subject goods is binding on the present safeguard investigation.
- k. Similarly, PUC has also changed between ADD investigations and SGD investigations for the same product such as in the case of scope of Caustic Soda under ADD investigation and SGD investigations
- l. Since none of the petitioning producers or any other domestic producer of the subject goods is producing and selling thin film products, and their claim for safeguard duty is not maintainable on this account.
- m. 3 of the producers are SEZ units, with objectives of export promotion, etc. Facility for sale in DTA is a concession given to surpass the volatility of export markets, however such sales to the DTA attract customs

duties. When the sale in the domestic market by such units is allowed merely as a liberty, it cannot be treated as a matter of right by such units so as to entitle them to seek protection as domestic industry. Further, given the fact that their supplies are attracting customs duties in the DTA, it follows that they are not at par with domestic manufacturers.

- n. Past investigations of the DG have held that SEZ units are not part of DI. Ref. made to “safeguard investigations concerning imports of Electrical Insulators into India” where the Director General, Safeguards gave a categorical finding on a principle of law that a unit operating under SEZ cannot be considered as a part of the domestic industry. These findings have attained finality and have not been upset by any judicial decision to the contrary.
- o. Reference made to “Safeguard investigation concerning Imports of ‘Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)’ into India”. Previous findings of the DA (quoted findings from Para 25&26) show that DA has made findings on a principle of law w.r.t. SEZ’s not being part of the DI and the same should be followed since DA is a quasi-judicial body and must maintain uniformity in decision making process.
- p. Both requirements of constituting DI in terms of S-8B(6)(b) of Customs Tariff Act, 1975 have not been met.
- q. The petitioner is estopped from claiming a different list of producers as constituting the DI when 25 other producers (including Vikram Solar, Evergreen Solar Systems, etc.) that found mention in the ADD application filed by the petitioner themselves as being producers of the PUC have been omitted from the present application.
- r. The petitioner has not come with clean hands as a number of these producers, who are in fact, members of the Association have not been disclosed in the application. Presumably, the members of the Association must be manufacturers of the subject goods, and that these members were well within the knowledge of the petitioner. There has thus been gross suppression of facts which should not be condoned.
- s. In the absence of a corresponding eligibility under S-8B to omit the producers, who undertake imports, from the definition of DI as required under the Rule 2(b) of the AD Rules, the share of the DI must be calculated accordingly.
- t. Production of manufacturers producing modules out of imported solar cells must be included as part of the DI and the production share of the DI must be calculated thereafter. Such a determination would show that petitioners do not account for major proportion of domestic production and accordingly do not constitute DI as u/s-8B of the Act.
- u. Increase in imports must not be seen in isolation from other factors. Imports increased to meet deficit in supply. There was a spike in the demand for PUC by 9000 MW, but corresponding increase in capacity of the DI was only 1200 MW. MSPVL started production only in May, 2017 and could not achieve desirable level of production instantaneously. Indian industry was in no position to cater to increased demand.
- v. Relative increase in market share of imports is not significant @4%, given the circumstances. Imports relative to production have increased since the capacities of the producers, as being SEZ/EOU units, have been set up majorly to serve the export markets. Production of petitioners has been suppressed due to collapse of exports. Increase in production not proportionate to the rise in demand
- w. Market share of imports have shown insignificant change only due to increase in domestic demand not being met by the DI. Petitioners had capacity of only 109% of the domestic demand before the setting up of MSVPL. Share of DI has also increased by 3%.
- x. Petitioners are not facing injury as volume parameters are showing exceptional performance. Capacity, production and sales of the petitioners have shown a significant increase over the injury period. Sales have quadrupled. Despite being a nascent industry, participating producers have managed to increase their domestic sales in line with the increase in capacity with both increasing to four times of that in the beginning of the period.
- y. All petitioners with the exception of Jupiter Solar are SEZ/EOU units. Their primary focus is on export markets. Decline in capacity utilization has been caused by a decrease in export sales of the producers and not on account of their performance in the domestic market.
- z. MSPVL started operations recently and accounts for a major chunk of the capacity of the petitioning producers while not having reached expected capacity utilization, giving impression of overall low capacity utilization, which might not be the case.
- aa. Data w.r.t. productivity per employee has been unduly distorted due to entry of MSVPL which is still in the initial phases of production.

- bb. Petitioners have been suffering losses even before the increase in imports, so injury not attributable to sudden increase in imports. Petitioners have suffered losses even during base year of 2014-15 when volume of imports was low. Petitioner claimed losses on account of increased imports with respect to 2017-18, however during that year losses are 16% lesser in comparison to base year and 65% less in comparison to 2015-16
- cc. Decline in employment as a result of poor export performance and cannot be considered as a factor for indicating injury.
- dd. Selective analysis of data for injury analysis with respect to inclusion of MSVPL on certain counts where it helps the case of the Petitioners.
- ee. Petitioner has listed entities which had to shut down operations as a result of imports when in fact these were SEZ units that suffered due to poor export performance
- ff. Petitioner has not provided weighted average price undercutting. Even if price cutting is positive no visible impact has occurred to the plaintiff. No price undercutting has been calculated for Thin Film products.
- gg. Both, selling price as well as cost have reduced proportionately, each declining by 16 index points during the POI. Petitioner cannot claim there is price suppression.
- hh. Decline in imports of PUC are only on account of increased efficiency of modules from 260 Watt peak to 330 Watt peak; creation and benefit of economies of scale enjoyed in the supply chain for polysilicon, wafers and ingots production; creation of integrated manufacturing capacities with the major module suppliers and further improvements in capacity utilization and overall manufacturing cost brought about by the vertical integration; and introduction of new processes like PERC, which allows further efficiency improvements, due to which lower cost per watt can be achieved
- ii. Injury on account of increase in inventory defies logic in light of increased domestic sales.
- jj. Entire revenue of Jupiter Solar, the only producer not an SEZ unit/EOU has come from sale of solar cells and earned profits. Other producers, being SEZ units/EOU's incurred loss on account of poor export performance
- kk. While export performance has materially deteriorated, domestic sales of producers have increased. Adverse performance with respect to capacity utilization on account of global downturn. Therefore, while domestic sales have increased by 304%, the export sales have reduced by 87%.
- ll. Excerpts from the annual reports of Indosolar clearly show it has suffered on account of poor export performance.
- mm. Number of factors such as lack of access to low cost financing; inadequate infrastructure, lack of raw materials, etc. with no relation to imports are affecting poor performance.
- nn. Liquidity constraints are a major reason for poor performance with respect to Helios and Moserbaer as reflected in annual statement.
- oo. Petitioners are engaged in low value addition without any backward integration. As a result, even if SGD imposed, the industry would remain uncompetitive.
- pp. Capacity addition during 2016-17 saw huge jump pursuant to revised targets by MNRE which is why sales as well as imports increased.
- qq. Injury margin under SG laws mean the same thing as under AD law and requires determination of NIP. DA had already applied the same principles for determination of NIP even before it was codified in 2011.
- rr. Determination of NIP specifically done for SGD imposition since the remedies are protectionist in nature and the duty is not levied to offset any unfair pricing behavior of the exporters
- ss. Signing GATT and ITA does not amount to unforeseen developments.
- tt. No concrete adjustment plan has been provided as to how the producers are going to become more competitive. There is absolutely no quantification regarding what measures would be taken and what cost benefits would be achieved thereby
- uu. No backward integration was attempted by the domestic producers even when protection in the form of Domestic Content Requirements was in force. Even if such steps are taken, it would take years for the same to materialize and ambitious targets for clean energy set by the Govt. would not be realized.

Additional Submissions by Parties:

- vv. In light of the petitioner's submissions that cells and modules are different products, there is no basis for the petitioner's case that module manufacturers not be considered as part of the Domestic Industry. The Authority must examine the cells and modules separately.
- ww. Much of the petitioner's emphasis has been on how the Domestic producers produce like or directly competitive products. Petitioner now seeks to include these items as different products, however the same wasn't represented in the petition and now the petitioners cannot claim that they are one article.
- xx. Petitioners reliance on Canadian authorities judgment for supporting the inclusion of thin film is misplaced since the USA and EU decided not to include thin film despite domestic production and the investigation authorities clearly held that thin film products were different from c-Si products.
- yy. Petitioner's reliance on previous findings of the DG is misplaced because the duty pursuant to that finding was not imposed by the Ministry and consequently such a determination cannot be said to have achieved finality.
- zz. Module manufacturers must not be excluded from the scope of investigations. The Authority must direct petitioners to give details of list of manufacturers that are only producing modules. The SEZ units cannot be considered as part of the Domestic Industry since the mere fact that the company may be producers of the PUC, is not reason enough to hold that such a company forms part of the domestic industry since the SEZ has created a deeming fiction that such companies shall be treated as foreign entities.
- aaa. Unforeseen developments must be seen in the context of surge in imports and the Domestic Industry is required to identify the period when imports surged and identify the unforeseen circumstances accordingly. The POI having been determined as April '16 to September '17, the unforeseen developments must pertain to this period and not before such period as identified by the petitioners.
- bbb. Petitioner has not updated the data since September 2017 for the simple reason that such updated data will not show that industry continues to suffer serious injury.
- ccc. Even in Anti-dumping investigations the Designated Authority found that injury margins were negligible. In such a situation, the decline in prices cannot be indicative of a situation requiring safeguard remedies.
- ddd. Shifting of China's exports from third countries into India is not a cause but an effect, and unforeseen developments required to be causes for the surge in imports.
- eee. It is an admitted position that if petitioner is not able to meet domestic demand, the Authority shall not levy SGD.
- fff. Impact of SGD must be seen only in the specific case of solar power and not other sources of power. Even an increase of 1 paisa of the solar power generation is a significant increase. A significant proportion of cost of module is only on the basis of the basic raw material, being the solar cells. Proposed SGD will therefore not save foreign exchange.
- ggg. The petitioner was on the one hand convinced that the injury margin was negative or low, while on the other contending that even 70% SGD is inadequate to them. It is therefore, evident that the petitioner has made blatantly misleading and inaccurate claims.

(v) M/s Panasonic Energy Malaysia SDN BHD (PECMY)

- a. Product exported by PECMY are different than the subject goods and should be removed from the scope of the PUC;
- b. Solar cells and modules cannot be treated 'like' to each other as both solar cells and modules have different costs and prices, therefore they are two separate products.
- c. Silicon Heterojunction (SHJ) is a very unique technology and was under a patent to Panasonic Corporation, Japan until 2016. The solar modules manufactured using SHJ Technology is different than the Subject Goods.
- d. 3 applicants namely M/s Mundra Solar PV Limited, M/s Websol Energy Systems Limited and M/s Helios Photo Voltaic Limited are based in Special Economic Zones (SEZ) and they cannot be included in the calculation of domestic installed capacity;
- e. SEZ plant is only for export;
- f. The applicants cannot claim to be DI in view of earlier DG Safeguards finding in Unwrought Aluminum (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys);

- g. Initiation is bad in law in view of Section 53 of Special Economic Zone Act, 2005 (SEZ Act) which provides that SEZ is deemed to be a territory outside the custom territory of India;
- h. As per Section 30 of SEZ Act and para 6.08 of Foreign Trade Policy, units located in SEZs and EOUs are deemed to be situated outside India, and therefore cannot be considered as DI.
- i. PECMY has imported only to M/s Anchor Electricals Pvt. Ltd. (AEPL) during POI. Both are 100% subsidiary companies of Panasonic Japan;
- j. No injury caused to the petitioners by PECMY as the landed value in India of exports of its SHJ technology based solar cells and modules is substantially higher (nearly double) than the landed value in India of imports by other Indian importers.
- k. Imports only increased because of Government of India's vision to promote renewable source of energy;
- l. Indian manufacturers could cater to only less than 10% of the demand in India;
- m. Imports from other countries including Malaysia happened only to fill demand-supply gap created by Indian manufacturers;
- n. Domestic demand of the Subject Goods was much higher than installed capacity of the DI. Thus, demand of the DI during the POI was largely fed by imports as the DI was incapable to meet the demand of indigenous customers;
- o. Therefore, such imports are not a result of any unforeseen developments but because of huge demand-supply gap.
- p. Currently 80% of India's production capacity of photovoltaic products is based on the imported solar cells, and duty on imports of solar products will harm the interests of India's downstream users like power station operators, investors and importers;
- q. This may subsequently increase the power generation cost which will adversely affect the India's infrastructure construction and the development of economy;
- r. In the preliminary findings, interest of importers, end users and overall public interest was not mentioned;
- s. Therefore, imposition of safeguard measures will affect the development of Indian economy.

(vi) M/s North India Module Manufacturer Association (NIMMA)

- a. Solar Modules are different from Solar cells and the SGD must be levied only on the modules and not on cells since there is a huge demand supply gap for solar cells.
- b. Solar Cell manufacturers can cater to only 15% of the domestic demand at 100% capacity utilisation.
- c. Solar module manufacturers are facing tough and unhealthy competition from imported modules and running from pillar to post to protect the manufacturing base.
- d. Safe Guard Duty at this juncture on solar cells that too when there is a huge demand supply gap for solar cells, would lead to further increase in import of solar modules and the limited availability of solar cells in India will further weaken the position of Indian manufacturers of solar modules. The users of solar modules will prefer to import modules to avoid the burden of Safe Guard Duty on solar cells and this will lead to complete collapse of solar panel manufacturing in India.
- e. Any injury occurred to the domestic industry on account of the inability of the domestic industry to meet the demand cannot be used as a tool to seek Safe Guard Duty on a misleading claim of surge in imports.
- f. Petitioners could not establish causal link between the increase in imports and injury to the Domestic industry.

(vii) M/s REC Solar Pte Ltd

- a. REC Solar Pte Ltd has been the only Singaporean CSPV manufacturer of the PUC during the POI, and thereby grants exemption from any Safeguard measures any solar cells, whether or not assembled into modules or panels, manufactured in Singapore.
- b. The imports from REC Solar Pte Ltd (in such a case to be representative of Singapore) individually do not account for more than 3%.
- c. Throughout the period of investigation, REC Solar Pte Ltd's shipments to India have been less than 1.4% of total demand for PUC in India while the Domestic Industry supplied on average 10% of the total demand for PUC in India over the POI.

(viii) M/s China Chamber of Commerce for Imports and Exports of Machinery and Electronic Products

- a. DG did not wait for parties to submit their views within 30 days of initiation notice and in a hasty manner issued its Preliminary Findings within 18 days of the initiation of the investigation.
- b. SGD's can only be imposed after investigation. Without giving the interested parties an opportunity to present their view, investigation could not have been completed
- c. The entire proceedings in the instant investigation are vitiated as the same were carried out in violation of the Principles of Natural Justice. Wrong done at various stages of the investigation cannot be rectified now by any act of DG.
- d. There is a huge domestic demand which needs to be met in light of inability of the DI to do so. Imposition of SGD will increase the cost of production of PUC for the same reason positive findings on ADD were made but duty was not levied in public interest. Same reasons must operate here.
- e. India needs high quality imported PV products, especially from China, to meet revised targets under JNNISM.
- f. India needs a constant supply of PV Cells. SGD's would have adverse effect on downstream industries; healthy development of solar cell industry and rural electrification projects initiated by the Govt.
- g. It is normal that exports from China to EU and USA decline due to trade remedies. However, increase in exports from China to India has nothing to do with this issue. It is a free market where sales volume is market oriented. Signing ITA-1; GATT or Paris Agreement are of no consequence since it is the natural law of the market that increasing demand fuelled imports
- h. It is a trend that the price is declining; therefore the same can't be termed as unforeseen.
- i. Increase in imports is in tandem with increase in demand of Indian Industry
- j. the domestic industry thinks that the data cannot prove material injury suffered by the domestic industry, otherwise it would not have decided to request to terminate the anti-dumping investigation in the final stage.
- k. Data submitted by the domestic cannot even prove existence of material injury, then it can be easily inferred that serious injury will not be determined.
- l. there was no need of increasing the capacity every year by the applicant. Such inappropriate decisions of increasing the capacity every year might have caused injury to the applicants not the imports from subject countries
- m. There is no correlation between the landed price and net sales realization for the Domestic Industry.
- n. First the domestic producers must establish that there is increased imports and the Domestic producer needs time and plan to adjust themselves to meet the situation of competition offered by such increased imports.
- o. the applicant's claim is inaccurate and misleading, as the differences between products manufactured from both technologies are significant in several aspects, such as raw materials, production processes, efficiency, flexibility and prices, etc
- p. CCCME as well as other interested parties have emphasized the negative influence of trade remedy measures on the public interests for several times in the written submissions and on the hearing for the anti-dumping investigation.
- q. The following should be removed from the PUC: (i) Solar cells using the "PERC" (Passivated Emitter Rear Cell) based technology; (ii) Thin films & Bi-facial N-type solar cells; (iii) High efficiency solar cells using 5 and 6 bus bar production terminology; and (iv) Solar modules of mono crystalline technology since Adjustment Plan states that DI will produce PERC type cells.
- r. Petitioner Helios Photo Voltaic Limited does not find mention in the list of MNRE dated 28 August 2017. The DGTR must clarify whether Helios is a producer of cells, modules or both.

- s. standing of the Petitioners should be examined separately for solar cells and solar modules.
- t. it is requested that the Designated Authority should follow its established practice and examine standing of Petitioners for solar cells and solar modules separately.
- u. India stands to act directly contrary to its obligations under the AoS by imposing a safeguard duty without demonstrating that unforeseen developments exist in the present case.
- v. Increase in imports is only due to the demand-supply gap in India. Demand has been created by the Government of India under National Solar Mission and the domestic producers and exporters are enabling the nation to fulfil the commitments under the National Solar Mission.
- w. Neither the Petition nor the Preliminary Findings objectively identify the specific GATT obligation incurred by India that led to sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods.
- x. None of the above identified GATT obligations led to recent, sudden, sharp and significant increase in imports of the subject goods in terms of Article XIX(1)(a) of GATT.
- y. There is no nexus between India's ITA-1 commitment for the subject goods and the alleged recent and sudden increase in imports
- z. Production and sales of the domestic industry have increased by 253% and 305%, respectively during the injury period. This increase is significant.
- aa. The Indian industry can only satisfy 10-15% of the Indian demand. The remaining demand has to be met by imports to meet the target under the National Solar Mission.
- bb. Domestic industry's selling price sharply declined in the export market from 100 indexed points in 2014-15 to 56 indexed points in 2017-18. Imports have nothing to with injury suffered
- cc. Injury to the domestic industry is entirely due to such reasons and not due to alleged dumped imports.
- dd. Real cause of injury to the domestic industry is aggressive pricing practices of other Indian producers and not imports.
- ee. Backward integration in this manner will only lead to higher cost in the next few years.
- ff. The Petitioners will not be able to adjust to imports if the adjustment plan requires incurring more cost rather than reduction of the same.

(ix)M/s Vikram Solar Limited

- a. Solar Cells are the most basic unit of a solar PV system. A PV module consists of multiple PV cells connected in a series to provide higher voltage output. Modules are value added products that convert solar cells into a commercially useful commodity used for generation of electric power. In light of the limited domestic capacity for manufacture of solar cells, module manufacturers have to depend on imported cells.
- b. Safeguard duties imposed on solar cells will have the effect of the SEZ unit paying the duties for all its solar cell modules being removed from the DTA. Such a measure will lead to adverse impacts on SEZ units.
- c. There is a huge gap in the demand and supply of solar modules manufactured by domestic producers. Large fractions of domestic production is located in SEZ's and imposition of Safeguard duties would not only adversely affect such manufacturers but also make it impossible to attain the target of 100GW of solar power by 2022 as large parts of the 100GW target has to be catered through imports. This will lead to generation of power through conventional fuels such as coal and related environmental issues. Imposition of safeguard duties is therefore clearly against public interest, which is the guiding principle for imposing SGD.
- d. If SGD is imposed, DG must prescribe a Tariff Rate Quota (TRQ) of 5GW at nil rate of duty. TRQ would address most of the concerns of the stakeholders. It would cater to the demand-supply gap without any additional burden on the cost of production of solar power generation while giving relief to the domestic production facilities set up in the SEZ's and protecting the DTA producers by providing SGD on imports beyond the prescribed quotas under the TRQ regime.

- e. Government of India should grant specific exemption under section 25(1) of the Customs Act, 1962 from payment of SGD on solar modules removed from SEZ to DTA.

(x) M/s LNV Technology Limited

- a. Three of the complainants (Mundra, Websol and Helios Photo Voltaic) operate from SEZ's, supplies to and from which are exempt from imposition of any duties and taxes.
- b. All imports into SEZ are excluded from application of ADD and Safeguard duties. Since SEZ's are treated differently for import-exports, the same should not be clubbed with DI.
- c. Increase in imports do not result in impact on units in SEZ. There is a no. of cases where the Authority has regarded SEZ to not be a part of DI. Resultantly, these three complainants cannot be considered to be a part of the domestic industry (DI) and the remaining complainants do not cross the threshold of 'collective output constituting a major share of total article in India', which results in such a standing requirement not being satisfied.
- d. the remedy of duty exemption to the extent of safeguard measure when the PUC is cleared by an SEZ into a domestic unit would be harmful at large to the DI itself.
- e. The determination on increase in imports does not evaluate all relevant factors on objective and quantifiable basis as specified by Rule 8 of Customs (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. This is especially the case when it comes to evaluating domestic demand and capacity
- f. With reference to the data provided, it has been argued that the domestic demand has increased 7 times between 2014-15 to 2017-18, whereas the capacity of DI has increased only 4 times. Assuming that DI worked at 70% capacity, the aggregate of domestic production and imports exceeded demand in 2014-15, 2015-16 and 2017-18 by 5%, 3% and 1% respectively, which can be explained due to exports by DI.
- g. Many developers including LNV are contracted with PSUs to develop Solar Parks and such clauses have prices as all-inclusive with no flexibility for change even in imposition of such a duty.
- h. Since Solar Panels constitute 60% of the cost, developers would not be in a position to clear imports and would lead to these projects reaching standstill. As a solution, the safeguard duty should be imposed only for imports involving future projects which have not been awarded.

(xi) Trina Solar (Vietnam) Science & Technology Co. Ltd.

- a. No provisional safeguard duty has been recommended against Vietnam as import of subject goods do not exceed 3% individually and 9% collectively when taken along with imports from other developing countries (other than China & Malaysia).
- b. In case the Designated Authority issues positive final findings, it is a request no definitive safeguard duty should be imposed on Vietnam in line with the recommendation in preliminary findings.

(xii) Trina Solar (Thailand) Science & Technology Co. Ltd.

- a. No provisional safeguard duty has been recommended against Thailand as import of subject goods do not exceed 3% individually and 9% collectively when taken along with imports from other developing countries (other than China & Malaysia).
- b. In case the Designated Authority issues positive final findings, it is a request no definitive safeguard duty should be imposed on Thailand in line with the recommendation in preliminary findings.

(xiii) Icon Solar-En Power Technologies Pvt. Ltd.

- a. A 95% SG duty as proposed by other parties however, would be detrimental to the growth of the Indian Solar Industry and would result in an oligopolistic cartel.
- b. Renewable energy targets of India can only be achieved by stabilization of costs.
- c. A significant portion of the manufactured modules are being utilized in the successful execution of schemes such as "Solar Pumps in Agriculture" and the "Saubhagya Home Lighting System" which directly relate to boosting the agricultural income and rural equitable growth.
- d. The revision of tariffs in PRC has resulted in plummeting prices, thereby affecting the DI seriously.

(xiv) Vibgyor Energy/Sunbeam Corporation

- a. Recent emergence of solar rooftop solutions as an alternative, which is also not in sync with the yearly additions required to meet target of 40 GW by 2022.
- b. Existence of regulatory ambiguities such as rate of GST on Solar Systems, constant scare of duties being imposed, poor net metering implementation have created an unsettling atmosphere for the players.
- c. Due to relatively recent emergence, most consumers have only now started shifting towards solar rooftop solutions. Most contracts for these have either been awarded or are in a late stage of negotiation. Companies do not have the capacity to factor in such a duty at this point of time.
- d. Imposition of the duty will endanger the fulfilment of these contracts, cause significant losses and would also deviate from the targets that the government wishes to achieve.
- e. The safeguard duty has no benefit since DI does not have the capacity to cater to their demands.
- f. Even if duty were to be imposed, a reasonable time period (of 6 months) should be considered before giving effect to the same. A reasonable and correctly timed duty levy will not hamper the economic adoption of solar in India.
- g. India must plan to create a “planned support mechanism” to increase capability of domestic manufacturers while avoiding collateral damage to ancillary service providers.

(xv) Solar Power Developers Association

- a. Interested parties were given 30 days to make their views known as per Initiation Notice but Preliminary findings were issued before we could make our views known.
- b. DA expressed displeasure as anti-dumping investigation was withdrawn at conclusive stage and on unconvincing grounds. As per Para 18 and 21 of ADD Termination Order, the DI is bound to undergo change in injury suffered during course of investigation and if petitions start getting withdrawn on this basis then it will lead to a chaotic situation.
- c. DA possesses the data from the ADD investigation and ongoing safeguard petition and the investigation period overlaps, the DA can compare the two data sets to examine whether the safeguard petition has any merit.
- d. The recommendation of 70% provisional safeguard duty on 5 January 2018 indeed led to a chaotic situation. Many solar tenders by India's state government have failed to attract good responses from bidders because of the uncertainty on the duties.
- e. To fulfil solar Mission target of 80GW by 2022 in Phase III, there must be average annual installation of 20GW per year. The preset domestic manufacturing capacity of solar cells (3164 MW/year) and solar modules (8398 MW/year) is clearly insufficient to meet the target.
- f. DISCOMS who are ultimate purchasers of solar power have clearly indicated that they would purchase solar power only if the cost is under INR 3 per kWh. In the light of impending safeguard duties, it will not be feasible for the developers to offer tariff which is under INR 3 per kWh thereby making it commercially unviable to participate in bids and projects and offer such low tariffs.

Even if definitive safeguard duty is in range of 12-15 cents per watt which is equivalent to INR 8-11 per watt depending on exchange rate, it will lead to increase in tariff by 80 paise to INR 1.30 per kWh, thereby increasing the tariff up to a range of about Rs. 4 per kWh. At this rate solar power would become uncompetitive and developers would also abandon ongoing projects. Enclosed reports establishing that solar power tariff are below INR 3 per kWh and have achieved grid parity.

- g. Disturbing solar power grid parity would adversely affect both developers and end customers. Petitioner's calculation that modest duty of 20 cents would increase power tariff by 70 paise per watt is incorrect. A duty in range of 12 – 15 cents would significantly increase tariff as demonstrated above.
- h. Number of power purchase agreements has been entered into between project developers and DISCOMS with capacity of 9000 MW and 18000 MW is also tendered out for allocation. Imports required for such

projects are yet to commence or under shipment and imposition of safeguard duty will impact these imports thereby increasing the power tariffs.

- i. Imposition of safeguard will be counterproductive and will have adverse effect on NSM since increase in tariffs will never be absorbed by state DISCOMs.
- j. In April 2018, the MNRE issued clarification on the clause w.r.t “Change in Law” in the bidding norms for solar projects whereby duties and cess have been included in the said clause. Even if the safeguard duty to be considered as the pass-through, the same is yet to be tested and established under the regulatory process. It is to be noted, No off-taker is going to bear the impact under the pass through mechanism and same would have an adverse effect on entire solar industry. The process of pass through is also very uncertain, long and complex and does not provide any assurance of protecting the ongoing projects, if the duty is imposed. With current average tariffs INR 2.75/Kwh, these tariffs are likely to be hit by 35-40% if the duty is imposed and would not attract any DISCOM to come forward and sign power sale agreements above INR 3. Entire mission will fail by killing the solar industry, interdependent MSMEs, jobs, and banks with loan defaults.
- k. Safeguard duty will put more than INR 1,00,000 crore worth of solar power projects under jeopardy, since our members have already committed to ongoing projects of about 27 GW.
- l. Due to uncertainty over safeguard, there has already been a hike of around 20-25% in tariffs in recent bids in Karnataka and Maharashtra. Our analysis indicates tariff for future solar power projects could rise substantially by more than 40% to nearly INR 4 per unit instead of INR 2.98 per unit recently discovered in bids conducted by Gujrat Urja Vikas Nigam Ltd and INR 2.71 per unit discovered in bids conducted by Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited. These hikes will adversely affect end consumer.
- m. DI is weak in terms of scale, technology and lack of investments in technology up-gradation resulting in to low efficiency of solar cells and modules produced in India. DI is restricted to mere assembly of solar cells into modules which is last stage in entire value chain. Dependency on importing silicon Ingots, wafers, and cells from China would continue to keep India’s manufacturing uncompetitive from other Asian giants in solar manufacturing.
- n. GOI may consider providing DI other incentives such as low interest loans. Imposition of safeguard may not be best option considering its spill over impact on project developers and end consumers who will have to pay higher tariffs.
- o. Following products should be excluded from the product scope-
 - (i) Solar cells using PERC technology.
 - (ii) Thin films & Bi facial N type solar cells
 - (iii) High efficiency solar cells using 5 and 6 bus bar production terminology; and
 - (iv) Solar modules of mono crystalline technology
- p. Petitioner has admitted in petition that they can’t manufacture thin film solar cells and modules. Further they have claimed in adjustment plan that they will be manufacturing PERC based cells. Thus, admittedly, petitioner cannot presently manufacture these cells. We are aware and it is common knowledge that petitioner cannot manufacture solar cells using 5 and 6 bus bar production terminology and on mono-crystalline technology. As DI cannot manufacture these articles, they should be excluded from product scope immediately.
- q. The petitioner companies do not have adequate standing to be considered as DI in present case in terms of article 4.1(c) of the Agreement on Safeguards read with section 8B(6)(b) of Customs Tariff Act, 1975.
- r. Standing of petitioners should be examined separately for solar cells and solar modules without considering the data for Helios PV Ltd as their data is not available with MNRE. The total installed capacity of petitioners for solar modules is mere 15% of total Indian production capacity. Thus, petitioners do not have standing as DI in solar modules. Further, the combined capacity of cells and modules is

- 26.5% in total installed capacity of India. Therefore, standing as DI for both cells and modules is not present.
- s. Data of total Indian production in Petition is incorrect because it fails to consider production of other producers in its entirety as the Petitioners claim that all the other producers are importers of subject goods. This claim is unsubstantiated and thus, lacks merit. Data of MNRE should be considered for examining standing of DI in this case.
 - t. This investigation covers two articles, namely, Solar cells and solar modules. While assessing the standing of DI, DGTR is requested to exclude those solar cells and modules manufacturers that had imported solar cells and modules respectively during the injury period.
 - u. When two products are subject to same investigation, DA follows consistent practice of examining the standing of DI separately. This has been done in following investigations:
 - (i) Penicillin-G Potassium and 6-APA imports from China PR and Mexico. Final findings issued vide Notification No. 14/19/2009-DGAD dated 20 January 2011.
 - (ii) Front Axle Beams and Steering Knuckles imports from China PR Final findings issued vide Notification No. 14/19/2008-DGAD dated 5 March 2010.
 - v. Further petitioners located in SEZ should be excluded from standing as their primary goal is to cater to the export market. In final findings of DG Safeguards dated 27 September 2012 in Electrical Insulators case, WSI Industries (located in SEZ) was excluded from the scope of the domestic industry. Once the SEZ units are excluded the remaining petitioners would be miniscule (a few hundred MW) in comparison to annual demand in India.
 - w. Pursuant to obligation under article XIX(1)(a) of GATT, India may not impose safeguard duty unless it can be demonstrated to the satisfaction of DA that increased imports and consequential injury arise a result of unforeseen developments and of the effect of obligations incurred by India under the GATT.
 - x. As per WTO Appellate Body in DS 98 Korea – Dairy, petitioners have to show how certain developments were unforeseen to the negotiators when India incurred obligations under the GATT, which led to the increase of imports of the subject goods during the investigation period. If petitioners fail to explain the same, the burden still lies on the DA to carry out the above analysis. Failure to do so would render the subject investigation liable to be terminated.
 - y. Developments identified by the Petitioners are not unforeseen within the meaning of Article XIX (1) (a) of GATT. The rapid expansion in capacity, production and exports in China is a result of rise in demand for renewable energy in India. The petitioners have failed to explain how expansion in capacity, production and export orientation of producers in China led to recent, sudden, sharp and significant increase in imports during investigation period. Demand for subject goods has been created by Government of India under NSM. This is the sole reason that led to increase in imports.
 - z. Petitioners have failed to demonstrate how imposition of trade remedy measures on China led to diversion of China's export to Indian market. Exporters cannot just decide on a given day that they will divert their exports to India because the EU and the USA have been blocked. If the state government or public bodies do not float any tender, no party can supply the subject goods, and thus, imports of the subject goods from any source would not happen.
 - aa. The contention that India's commitment under Paris Agreement is unforeseen is comical. India ratified the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in November 1993, much before joining the WTO. Under this India signed two protocols, namely, Kyoto Protocol in 2002, and Paris Agreement in 2016. At the time of joining WTO, India was aware of its commitments under UNFCCC.
 - bb. There is no recent, sudden, sharp and significant increase in imports that meets the requirement under Article XIX: (1) (a) of GATT. The last time imports of subject goods witnessed a sudden surge was in 2015-16 that saw imports increase by 228%. After that imports increased by a mere 52% in 2016-17 and only 49% in 2017-18 annualised. Increase is due to demand supply gap created by GOI under NSM.
 - cc. The Petition does not identify any obligation incurred by India including tariff concessions for the subject goods under GATT that resulted in sudden surge in imports.
 - dd. The petition and Preliminary findings identify two alleged obligations that India incurred, namely, commitment under ITA-1 that led to elimination of custom duty and India honouring the WTO ruling in DS456- India – Solar Cells. None of the above obligations led to recent, sudden, sharp and significant increase in imports due to firstly, import duty became zero in 2005. But the petition and preliminary

finding fails to identify that how this GATT obligation that came into effect more than 12 years ago, led to recent, sudden, sharp and significant increase in imports, during the injury period. Imports did not significantly increase for many years after 2005. Imports increased after GOI launched NSM. The only reason behind increase in imports of the subject goods is that India had created demand for the subject goods by floating more tenders and inviting bids. Second, the petition and preliminary findings present no data to demonstrate that as soon as DCR were removed from the tenders, imports of the subject goods suddenly increased. Without any data, the Petitioners contention is purely academic. MNRE plans to continue to support the Indian industry by applying DCR under CPSU scheme, which is also WTO compliant.

- ee. The Petitioners had not suffered any serious injury with reference to Section 8B(6)(c) of the Act and Rule 8 read with Annexure of Safeguard Rules as Imports increased by only 49% in most recent period when compared to 2016-17. There is huge demand in India and DI is capacity is mere 15% of the total demand. Production and sales of DI have increased by 253% and 305% respectively during injury period. Capacity utilisation of DI has increased from 60% in 2014-15 to 78% in 2016-17.
- ff. Mundra began production in 2017 that led to increase in installed capacity and production in 2017-18(A). This demonstrates that DI is performing well and is ready to invest to cope up with growing demand. The decline in capacity utilisation is only temporary and will improve with the stabilisation of production over time.
- gg. Productivity per day and per employee increased manifold during injury period. Wages in absolute terms and per KW increased during injury period, which led to decline in profits and could be the reason for injury. Other reasons include increase in installed capacity, interest cost and depreciation cost.
- hh. The cost of sales and selling price declined from 100 indexed points in 2014-15 to 84 indexed points each in 2017-18(A). The DI selling price is in line with cost of sales. There is no price suppression. Had imports exerted any pressure on DI, the selling price would have been much lower. Hence, there is no price depression. DI selling price in export market declined from 100 indexed points in 2014-15 to 56 indexed points in 2017-18(A). This is the reason for injury.
- ii. Indosolar's performance has improved significantly in FY 2016-17. Its revenues sharply jumped to Rs. 44,231.09 Lakhs in FY 2016-17, its losses decreased by Rs. 8,322.91 lakhs in the same period. This is significant improvement in a period during which Indosolar has claimed injury due to imports in the petition. Clearly, Indosolar's injury claim is not supported by its own data. Further, Indosolar has projected better performance during the FY 2017-18 in its Annual Report 2016-17 as it expects the Government to adopt certain favourable policies.
- jj. Websol's financial situation significantly improved during FY 2016-17. In fact, from a loss of Rs. 647.48 lakhs in FY 2015 – 16, Websol incurred huge profit of Rs. 8,594.36 lakhs during FY 2016-17. It has also settled its Working capital and term loans. Websol expanded its cell capacity from 100 to 200MW and intends to expand its cell line capacity to 280-300 MW and Module line Capacity to 300 MW from 100 MW. In view of such strong financials, we fail to understand how Websol claims injury due to imports of the subject goods.
- kk. In FY 2016 -17, Jupiter Solar registered profits of Rs 3,999 lakhs. This is exceptional performance by the company.
- ll. Mundra started its production about a year ago in 2017. When new manufacturing facility is set up, it takes a long time to achieve break even. Further, the initial period also involves high interest and depreciation cost which is the possible reason of injury.
- mm. Helios PV Ltd. was undergoing corporate debt restructuring for a long period and has accumulated very high liabilities in the balance sheet. This is the reason for losses to this company.
- nn. Causal Link is absent because decline in profitability in 2015-16 and 2017-18(A) directly coincides with sudden increase in installed capacity, net fixed assets and interest cost during the period. Injury to DI is caused due to decline in selling prices in export market. Injury to DI is also due to the fact that it still uses obsolete technology. In an article published in the Hindu Business Line on 19 December 2017, the MNRE stated that 'the cell/module manufacturing capacity in the country is obsolete'. The petitioner ISMA and Indosolar have admitted that Indian Manufacturers could not invest in technology up gradation as there was no visibility of market.
- oo. The real cause of injury to the DI is aggressive pricing practices by other Indian producers and not imports. In this regard, the DA is requested to refer to the news articles enclosed, which stated that Indian

producers such as Adani Green Energy, Bharat Heavy Electricals, Tata power Solar and Central Electronics have together sold 300 MW solar panels to Energy Efficiency Services (EESL) at a record low price of 30 cents/Kwh capacity (Rs 2.63/Kwh), which is cheaper than the rate of good quality Chinese solar panels. This demonstrates that price war between the Petitioners and other Indian producers are the real cause of injury to DI and not the alleged imports of the subject goods.

- pp. As a requirement, the DI has to provide an adjustment plan in the petition to demonstrate how they plan to adjust during the tenure of the safeguard measure. The petitioners have claimed confidentiality on their individual adjustment plans which makes it difficult to make any meaningful comments. Further, the NCV of petition provides only the vague information on the adjustment plan. The Petitioners are requested to clarify in written submissions their plans on the structural adjustments that each petitioner endeavours to undertake in terms of Article 7.1 of the AoS read with proviso to Rule 11(3) of the Safeguard Rules.
- qq. However, based on available information in the Petition, the Petitioner claims that they will achieve economies of scale by backward integration, viz., establishing plants for manufacturing wafers and ingots. However, this manner will lead to higher cost in next few years than reduction of the same to adjust to imports. Such an adjustment plan is, therefore, not feasible and practical.
- rr. Imports which occur as a result of recent bids, signed LOIs or power purchase agreements of roughly 9000MW that have been signed prior to levy of safeguard duty be exempt from scope of duty.
- ss. MNRE has proposed to have an additional CPSU scheme of 12000 MW, which would have an assured DCR component. This will allow the DI an assured market. Therefore there is no future threat of serious injury also to the domestic industry.
- tt. The DI at full capacity could meet only 10% of the Indian demand for solar power during 2017-18(A). The remaining could only be met by imports.
- uu. The share of imports in period under examination grew from 86% to 90% of the total domestic consumption – which can hardly be called a massive growth.
- vv. There is no serious injury and causal link as DI's EBITDA margins at 16% for the period under investigation are roughly 60% higher than EBITDA margins for top global manufacturers. This indicates that high interest burdens due to higher capex/ interest costs are to blame and not imports.
- ww. The Petitioners do not comprise 51% of Domestic Industry for a majority of the control period as per MNRE data. Further, if domestic industry excludes SEZ units as has been held in DG Safeguards investigations in 2016 and 2012, then the petitioners are much lesser than the needed 51%.
- xx. Imports only increased due to Government of India's vision to promote this renewable source of energy and not due to unforeseen developments of imposition of trade measures by EU and US or loss of protective ambit of DCR or India's obligation under ITA-1. The Government was well aware that Indian manufacturers could only cater to only less than 10% of the demand in India. Had the Government not created the demand, the imports would not have happened. Rather, the NSM envisages participation of domestic and global players so that the best and most advanced solar cells and modules fulfil the Mission of 175 GW solar power grid connectivity by 2022. The Ld. DG has found that the DI is suffering losses. In contrast, the DI's data for the same period reflects profits in the ongoing anti dumping investigation. There is a serious mismatch. Further, there are discrepancies in the information provided to DG (Safeguards) (Utilisation fell from 78% to 51%) in their statements in their own annual reports.
- yy. The DI could paint a picture of losses because of addition of M/s Mundra solar PV Limited in the safeguard petition. This petitioner has setup a new manufacturing facility and with new facility comes high interest and depreciation cost. Injury to this company is not because of imports but high interest and depreciation cost.
- zz. The 3 DIs have reported revenue at a CAGR of 18.2% since FY 2015 and average EBITDA margin has improved from 9.4% in 2016 to 22.3% in 2017.
- aaa. The data for Helios PV Pvt Ltd (formerly Moser Baer) should be excluded as the company is engaged in manufacturing of various products including CDs, investment in power and has been making losses since 2008. The company was undergoing corporate debt restructuring for a long time and has very high liabilities in the balance sheet, therefore their data cannot be considered.
- bbb. It is evident that cell manufacturer enjoy much higher profit margin at operating level which is an indicator of whether or not imports are causing injury to DI. There losses are due to high capital cost per MW, high interest cost and management inefficiencies.

- ccc. Domestic Industry constitutes operational capacity of 56% of total cell capacity with significant instalments completed in the year 2017. During the year 2016 the DIs constitutes operational cell capacity of 49.7%.
- ddd. Further, solar manufacturing should include both cell and module manufacturing. In 2017, DI constituted 56% for total cell manufacturing capacity of India whereas it constituted only 2.6% of total module manufacturing capacity of India for period ending 31st May 2017.
- eee. Further, in December 2017, the MNRE has made a statement that installed capacity of Indian Manufacturers is obsolete and it proposes an investment of INR 11,000 Crores by way of Govt. assistance.
- fff. The Ld. DG's conclusion that serious injury would occur if provisional safeguard duty is not imposed is incorrect. The MNRE plans to continue DCR support through CPSU scheme of 12,000 MW. Therefore, there are no critical circumstances.
- ggg. DG (Safeguards) have previously ruled (2016 & 2012) that SEZ units cannot be considered as DI.
- hhh. SEZ units should be treated as outside India as held in case of imposition of safeguard duty in April 2016 on imports of "Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)".

(xvi) M/s. Avaada Ltd.

- a. Interested parties were given 30 days to make their views known as per Initiation Notice but Preliminary findings were issued before we could make our views known.
- b. DA expressed displeasure as anti-dumping investigation was withdrawn at conclusive stage and on unconvincing grounds. As per Para 18 and 21 of ADD Termination Order, the DI is bound to undergo change in injury suffered during course of investigation and if petitions start getting withdrawn on this basis then it will lead to a chaotic situation.
- c. DA possesses the data from the ADD investigation and ongoing safeguard petition and the investigation period overlaps, the DA can compare the two data sets to examine whether the safeguard petition has any merit.
- d. The recommendation of 70% provisional safeguard duty on 5 January 2018 indeed led to a chaotic situation. Many solar tenders by India's state government have failed to attract good responses from bidders because of the uncertainty on the duties.
- e. To fulfil solar Mission target of 80GW by 2022 in Phase III, there must be average annual installation of 20GW per year. The present domestic manufacturing capacity of solar cells (3164 MW/year) and solar modules (8398 MW/year) is clearly insufficient to meet the target.
- f. DISCOMS who are ultimate purchasers of solar power have clearly indicated that they would purchase solar power only if the cost is under INR 3 per kWh. In the light of impending safeguard duties, it will not be feasible for the developers to offer tariff which is under INR 3 per kWh thereby making it commercially unviable to participate in bids and projects and offer such low tariffs. Even if definitive safeguard duty is in range of 12-15 cents per watt which is equivalent to INR 8-11 per watt depending on exchange rate, it will lead to increase in tariff by 80 paise to INR 1.30 per kWh, thereby increasing the tariff up to a range of about Rs. 4 per kWh. At this rate solar power would become uncompetitive and developers would also abandon ongoing projects. Enclosed reports establishing that solar power tariff are below INR 3 per kWh and have achieved grid parity.
- g. Disturbing solar power grid parity would adversely affect both developers and end customers. Petitioner's calculation that modest duty of 20 cents would increase power tariff by 70 paise per watt is incorrect. A duty in range of 12 – 15 cents would significantly increase tariff as demonstrated above.
- h. Number of power purchase agreements has been entered into between project developers and DISCOMS with capacity of 9000 MW and 18000 MW is also tendered out for allocation. Imports required for such projects are yet to commence or under shipment and imposition of safeguard duty will impact these imports thereby increasing the power tariffs.
- i. Imposition of safeguard will be counterproductive and will have adverse effect on NSM since increase in tariffs will never be absorbed by state DISCOMs.
- j. In April 2018, the MNRE issued clarification on the clause w.r.t "Change in Law" in the bidding norms for solar projects whereby duties and cess have been included in the said clause. Even if the safeguard duty to

be considered as the pass-through, the same is yet to be tested and established under the regulatory process. It is to be noted, No off-taker is going to bear the impact under the pass through mechanism and same would have an adverse effect on entire solar industry. The process of pass through is also very uncertain, long and complex and does not provide any assurance of protecting the ongoing projects, if the duty is imposed. With current average tariffs INR 2.75/Kwh, these tariffs are likely to be hit by 35-40% if the duty imposed and would not attract any DISCOM to come forward and sign power sale agreements above INR 3. Entire mission will fail by killing the solar industry, interdependent MSMEs, jobs, and banks with loan defaults.

- k. Safeguard duty will put more than INR 1,00,000 crore worth of solar power projects under jeopardy, since our members have already committed to ongoing projects of about 27 GW.
- l. Due to uncertainty over safeguard, there has already been a hike of around 20-25% in tariffs in recent bids in Karnataka and Maharashtra. Our analysis indicates tariff for future solar power projects could rise substantially by more than 40% to nearly INR 4 per unit instead of INR 2.98 per unit recently discovered in bids conducted by Gujrat Urja Vikas Nigam Ltd and INR 2.71 per unit discovered in bids conducted by Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited. These hikes will adversely affect end consumer.
- m. DI is weak in terms of scale, technology and lack of investments in technology up-gradation resulting in to low efficiency of solar cells and modules produced in India. DI is restricted to mere assembly of solar cells into modules which is last stage in entire value chain. Dependency on importing silicon Ingots, wafers, and cells from china would continue to keep India's manufacturing uncompetitive from other Asian giants in solar manufacturing.
- n. GOI may consider providing DI other incentives such as low interest loans. Imposition of safeguard may not be best option considering its spill over impact on project developers and end consumers who will have to pay higher tariffs.
- o. Following products should be excluded from the product scope-
 - (v) Solar cells using PERC technology.
 - (vi) Thin films & Bi facial N type solar cells
 - (vii) High efficiency solar cells using 5 and 6 bus bar production terminology; and
 - (viii) Solar modules of mono crystalline technology
- p. Petitioner has admitted in petition that they can't manufacture thin film solar cells and modules. Further they have claimed in adjustment plan that they will be manufacturing PERC based cells. Thus, admittedly, petitioner cannot presently manufacture these cells. We are aware and it is common knowledge that petitioner cannot manufacture solar cells using 5 and 6 bus bar production terminology and on mono-crystalline technology. As DI cannot manufacture these articles, they should be excluded from product scope immediately.
- q. The petitioner companies do not have adequate standing to be considered as DI in present case in terms of article 4.1(c) of the Agreement on Safeguards read with section 8B(6)(b) of Customs Tariff Act, 1975.
- r. Standing of petitioners should be examined separately for solar cells and solar modules without considering the data for Helios PV Ltd as their data is not available with MNRE. The total installed capacity of petitioners for solar modules is mere 15% of total Indian production capacity. Thus, petitioners do not have standing as DI in solar modules. Further, the combined capacity of cells and modules is 26.5% in total installed capacity of India. Therefore, standing as DI for both cells and modules is not present.
- s. Data of total Indian production in Petition is incorrect because it fails to consider production of other producers in its entirety as the Petitioners claim that all the other producers are importers of subject goods. This claim is unsubstantiated and thus, lacks merit. Data of MNRE should be considered for examining standing of DI in this case.
- t. This investigation covers two articles, namely, Solar cells and solar modules. While assessing the standing of DI, DGTR is requested to exclude those solar cells and modules manufacturers that had imported solar cells and modules respectively during the injury period.

- u. When two products are subject to same investigation, DA follows consistent practice of examining the standing of DI separately. This has been done in following investigations:
 - (iii) Penicillin-G Potassium and 6-APA imports from China PR and Mexico. Final findings issued vide Notification No. 14/19/2009-DGAD dated 20 January 2011.
 - (iv) Front Axle Beams and Steering Knuckles imports from China PR Final findings issued vide Notification No. 14/19/2008-DGAD dated 5 March 2010.
- v. Further petitioners located in SEZ should be excluded from standing as their primary goal is to cater to the export market. In final findings of DG Safeguards dated 27 September 2012 in Electrical Insulators case, WSI Industries (located in SEZ) was excluded from the scope of the domestic industry. Once the SEZ units are excluded the remaining petitioners would be miniscule (a few hundred MW) in comparison to annual demand in India.
- w. Pursuant to obligation under article XIX(1)(a) of GATT, India may not impose safeguard duty unless it can be demonstrated to the satisfaction of DA that increased imports and consequential injury arise a result of unforeseen developments and of the effect of obligations incurred by India under the GATT.
- x. As per WTO Appellate Body in DS 98 Korea – Dairy, petitioners have to show how certain developments were unforeseen to the negotiators when India incurred obligations under the GATT, which led to the increase of imports of the subject goods during the investigation period. If petitioners fail to explain the same, the burden still lies on the DA to carry out the above analysis. Failure to do so would render the subject investigation liable to be terminated.
- y. Developments identified by the Petitioners are not unforeseen within the meaning of Article XIX (1) (a) of GATT. The rapid expansion in capacity, production and exports in China is a result of rise in demand for renewable energy in India. The petitioners have failed to explain how expansion in capacity, production and export orientation of producers in China led to recent, sudden, sharp and significant increase in imports during investigation period. Demand for subject goods has been created by Government of India under NSM. This is the sole reason that led to increase in imports.
- z. Petitioners have failed to demonstrate how imposition of trade remedy measures on China led to diversion of China's export to Indian market. Exporters cannot just decide on a given day that they will divert their exports to India because the EU and the USA have been blocked. If the state government or public bodies do not float any tender, no party can supply the subject goods, and thus, imports of the subject goods from any source would not happen.
- aa. The contention that India's commitment under Paris Agreement is unforeseen is comical. India ratified the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in November 1993, much before joining the WTO. Under this India signed two protocols, namely, Kyoto Protocol in 2002, and Paris Agreement in 2016. At the time of joining WTO, India was aware of its commitments under UNFCCC.
- bb. There is no recent, sudden, sharp and significant increase in imports that meets the requirement under Article XIX: (1) (a) of GATT. The last time imports of subject goods witnessed a sudden surge was in 2015-16 that saw imports increase by 228%. After that imports increased by a mere 52% in 2016-17 and only 49% in 2017-18 annualised. Increase is due to demand supply gap created by GOI under NSM.
- cc. The Petition does not identify any obligation incurred by India including tariff concessions for the subject goods under GATT that resulted in sudden surge in imports.
- dd. The petition and Preliminary findings identify two alleged obligations that India incurred, namely, commitment under ITA-1 that led to elimination of custom duty and India honouring the WTO ruling in DS456- India – Solar Cells. None of the above obligations led to recent, sudden, sharp and significant increase in imports due to firstly, import duty became zero in 2005. But the petition and preliminary finding fails to identify that how this GATT obligation that came into effect more than 12 years ago, led to recent, sudden, sharp and significant increase in imports, during the injury period. Imports did not significantly increase for many years after 2005. Imports increased after GOI launched NSM. The only reason behind increase in imports of the subject goods is that India had created demand for the subject goods by floating more tenders and inviting bids. Second, the petition and preliminary findings present no data to demonstrate that as soon as DCR were removed from the tenders, imports of the subject goods suddenly increased. Without any data, the Petitioners contention is purely academic. MNRE plans to continue support the Indian industry by applying DCR under CPSU scheme, which is also WTO compliant.
- ee. The Petitioners had not suffered any serious injury with reference to Section 8B(6)(c) of the Act and Rule 8 read with Annexure of Safeguard Rules as Imports increased by only 49% in most recent period when

- compared to 2016-17. There is huge demand in India and DI capacity is mere 15% of the total demand. Production and sales of DI have increased by 253% and 305% respectively during injury period. Capacity utilisation of DI has increased from 60% in 2014-15 to 78% in 2016-17.
- ff. Mundra began production in 2017 that led to increase in installed capacity and production in 2017-18(A). This demonstrates that DI is performing well and is ready to invest to cope up with growing demand. The decline in capacity utilisation is only temporary and will improve with the stabilisation of production over time.
- gg. Productivity per day and per employee increased manifold during injury period. Wages in absolute terms and per KW increased during injury period, which led to decline in profits and could be the reason for injury. Other reasons include increase in installed capacity, interest cost and depreciation cost.
- hh. The cost of sales and selling price declined from 100 indexed points in 2014-15 to 84 indexed points each in 2017-18(A). The DI selling price is in line with cost of sales. There is no price suppression. Had imports exerted any pressure on DI, the selling price would have been much lower. Hence, there is no price depression. DI selling price in export market declined from 100 indexed points in 2014-15 to 56 indexed points in 2017-18(A). This is the reason for injury.
- ii. Indosolar's performance has improved significantly in FY 2016-17. Its revenues sharply jumped to Rs. 44,231.09 Lakhs in FY 2016-17, its losses decreased by Rs. 8,322.91 lakhs in the same period. This is significant improvement in a period during which Indosolar has claimed injury due to imports in the petition. Clearly, Indosolar's injury claim is not supported by its own data. Further, Indosolar has projected better performance during the FY 2017-18 in its Annual Report 2016-17 as it expects the Government to adopt certain favourable policies.
- jj. Websol's financial situation significantly improved during FY 2016-17. In fact, from a loss of Rs. 647.48 lakhs in FY 2015 – 16, Websol incurred huge profit of Rs. 8,594.36 lakhs during FY 2016-17. It has also settled its Working capital and term loans. Websol expanded its cell capacity from 100 to 200MW and intends to expand its cell line capacity to 280-300 MW and Module line Capacity to 300 MW from 100 MW. In view of such strong financials, we fail to understand how Websol claims injury due to imports of the subject goods.
- kk. In FY 2016 -17, Jupiter Solar registered profits of Rs 3,999 lakhs. This is exceptional performance by the company.
- ll. Mundra started its production about a year ago in 2017. When new manufacturing facility is set up, it takes a long time to achieve break even. Further, the initial period also involves high interest and depreciation cost which is the possible reason of injury.
- mm. Helios PV Ltd. was undergoing corporate debt restructuring for a long period and has accumulated very high liabilities in the balance sheet. This is the reason for losses to this company.
- nn. Causal Link is absent because decline in profitability in 2015-16 and 2017-18(A) directly coincides with sudden increase in installed capacity, net fixed assets and interest cost during the period. Injury to DI is caused due to decline in selling prices in export market. Injury to DI is also due to the fact that it still uses obsolete technology. In an article published in the Hindu Business Line on 19 December 2017, the MNRE stated that 'the cell/module manufacturing capacity in the country is obsolete'. The petitioner ISMA and Indosolar have admitted that Indian Manufacturers could not invest in technology up gradation as there was no visibility of market.
- oo. The real cause of injury to the DI is aggressive pricing practices by other Indian producers and not imports. In this regard, the DA is requested to refer to the news articles enclosed, which stated that Indian producers such as Adani Green Energy, Bharat Heavy Electricals, Tata power Solar and Central Electronics have together sold 300 MW solar panels to Energy Efficiency Services (EESL) at a record low price of 30 cents/Kwh capacity (Rs 2.63/Kwh), which is cheaper than the rate of good quality Chinese solar panels. This demonstrates that price war between the Petitioners and other Indian producers are the real cause of injury to DI and not the alleged imports of the subject goods.
- pp. As a requirement, the DI has to provide an adjustment plan in the petition to demonstrate how they plan to adjust during the tenure of the safeguard measure. The petitioners have claimed confidentiality on their individual adjustment plans which makes it difficult to make any meaningful comments. Further, the NCV of petition provides only the vague information on the adjustment plan. The Petitioners are requested to clarify in written submissions their plans on the structural adjustments that each petitioner endeavours to undertake in terms of Article 7.1 of the AoS read with proviso to Rule 11(3) of the Safeguard Rules.

- qq. However, based on available information in the Petition, the Petitioner claims that they will achieve economies of scale by backward integration, viz., establishing plants for manufacturing wafers and ingots. However, this manner will lead to higher cost in next few years than reduction of the same to adjust to imports. Such an adjustment plan is, therefore, not feasible and practical.
- rr. Imports which occur as a result of recent bids, signed LOIs or power purchase agreements of roughly 9000MW that have been signed prior to levy of safeguard duty be exempt from scope of duty.
- ss. MNRE has proposed to have an additional CPSU scheme of 12000 MW, which would have an assured DCR component. This will allow the DI an assured market. Therefore there is no future threat of serious injury also to the domestic industry.
- tt. The DI at full capacity could meet only 10% of the Indian demand for solar power during 2017-18(A). The remaining could only be met by imports.

(xvii) M/s. ACME

- a. Domestic manufacturing capabilities of solar PV modules are very low only around 10% of the total requirement. The DI at full capacity could meet only 105 of the Indian demand for solar power during 2017-18(A). The remaining could only be met by imports. As a result, the Solar Power Developers predominantly rely on imports for the purpose of sourcing the solar PV modules and solar cells.
- b. Ministry of Communications and Information Technology notified policy for M-SIPS to encourage investments in Electronics System Design and Manufacturing ("**ESDM**") sector. Financial incentives in terms of 25% of capex (20% for SEZ units) and reimbursement of excise/CVD on capital equipment were made available to units engaged in the design and manufacturing of solar PV cells and modules.
- c. The National Policy on Electronics notified on 19th November, 2012 observes the steep demand supply gap prevailing in the electronic market and, accordingly, has set out various objectives that are *inter alia* aimed at building manufacturing capacity of solar PVs to support the generation of 20GW of solar power by 2020. Various incentives in terms of infrastructure, loans and tax benefits were made available to the ESDM sector.
- d. Despite continuous incentives given by the Government since 2012, the domestic manufacturers have failed to increase its production or capacity. Till the end of FY 2016-17, total installed capacity built up by domestic manufacturers of solar cells and PV modules was a meagre 573 MW against a demand of 7,157 MW. since the JNNSM was announced by the Government of India and despite granting both fiscal and other incentives, domestic manufacturers failed to install and manufacture capacities required for catering to the huge requirement of solar cells and PV modules. domestic manufacturers were fully aware of the vision under the JNNSM to achieve 100 GW by 2022. DI already enjoying several incentives from the Government to enable them to improve their performance such as Modified Special Incentive Package Scheme (**M-SIPS**) and the Domestic Content Requirement (**DCR**).
- e. The Government also notified the Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) order, 2017 dated August 30, 2017 effectively ensuring that solar cells and modules being imported into India conform to Specified Standard and bear the Standard Mark. this Order effectively ensured that no poor-quality products are imported into India. However, the domestic industry was not capable enough to maximise the opportunities made available to it and no steps were taken by them to meet the upcoming demands and to become competitive. The existing obsolescence of domestic technology is an admitted fact. Entire thrust of Government's policy is to update the domestic industry with technology and make it competitive in the international market.
- f. MNRE has devised a program in pursuance of WTO guidelines, wherein central public-sector undertakings shall install 12 GW of solar PV modules manufactured by DI under government procurements.
- g. AD in earlier investigation was not imposed since strong opposition was received from MNRE as JNNSM would not be met and therefore, ISMA withdrew their petition.
- h. ISMA withdrew 2017 AD petition because it was unable to demonstrate the dumping of PUC to the extent of the levels claimed in their petition and the investigation would not lead to the intended outcome.
- i. Data submitted with petition does not match MNRE data wherein installed capacity in India is states to be 11562 MW and as such, Domestic Industry constitutes only 7.5% of it.

- j. Data of imports taken from multiple sources which lead to differences and less reliable. Therefore, the Application relying upon data sourced from various places becomes vague and erroneous.
- k. 3 of the petitioners are based in SEZs and therefore, cannot claim to be DI in view of earlier DG Safeguards finding in Unwrought Aluminium.
- l. Mundra Solar cannot be part of DI because it was established only 6 months before the application filed by ISMA. Mundra cannot claim injury on account of increased import of PUC without effectively competing in the domestic space. At best, the claim by Mundra is a pre-emption of injury which cannot be a basis for initiating investigation concerning safeguard duty.
- m. Gradual increase in demand matched with increase in imports and proportional to the increase in demand meeting the supply demand gap. Therefore, not sudden, significant, unexpected [and] rapid.
- n. No injury to the Domestic Industry as installed capacity increased by 1000 MW and production of PUC by DI also increased. Despite rapid expansion in demand, sales and share of the DI has more or less remained constant in recent years.
- o. Applicants are increasing their capacity every year despite having huge unutilized capacities. production facilities of the DI were under- utilised during the entire POI and the capacity utilisation declined significantly. They were not operating at optimum level because of which they still have 49% unutilized capacity utilization. capacity utilization decreased due to its inappropriate decision of increasing the capacity.
- p. There was a proportionate increase in market share of the domestic sales.
- q. Production of DI increased from 473 MW to 838 MW and the imports increased from 6375 MW to 9334 MW. Therefore, it cannot be held that only imports have increased in the POI.
- r. No serious injury. Safeguard findings of FSP relied upon where it was found that 1.) as imports increased along with the domestic production and consumption and 2.) loss to DI due to non-appropriating of the cost of production and sales of PUC on proportional basis to other products and not on account of imports.
- s. No causal link because the loss to domestic industry, if any, is due to idle production capacity and investment made in unplanned increase in installed capacity and not being able to utilise their capacity fully.
- t. Losses claimed by the Applicants are false and misleading. The balance sheet of two of the Applicants who were operational during the POI viz. Jupiter solar and Websol. The status of the said Applicants have been summarized in a table where it can be seen that revenue earned by both Applicants in 2017 are higher than 2016. Jupiter Solar earned Rs.287 crore in 2017 in contrast to Rs. 213 Cr. Websol earned Rs. 296 Cr in 2017 in contrast of Rs.279 Cr. Noticeable profits in their margin and equity portion in the past 2 years, which is clearly contrary to findings. Annual reports tendered as exhibits.
- u. As per annual reports, Indosolar show either decline in losses or high profitability. Another Applicant, Helios was undergoing corporate debt restructuring for a long time and has very high liabilities in the balance sheet which is the reason for losses shown by it.
- v. Exemption granted by India to ITA-1 products pursuant to signing the ITA-1 did not cause increased imports. The increase in imports was owing to increased demand by domestic solar power developers for setting up solar power projects which is on account of Indian Government's policy to promote solar power generation. Thus, no nexus between India's obligations under ITA-1 in 1996 and increased imports of PUC in 2015 -16 and as such, nexus and causal link attempted by ISMA to link two separate events is without any basis. With launch of NSM, the solar power sector saw emergence of new players and increased investment in the sector with the view to meet the target solar production, which was subsequently increased to 100 GW to be achieved by 2022. Hence, the demand for solar panels/modules increased and became huge. The expected future demand devised certain schemes viz. MSIP and DCR, but domestic industry was not capable enough to capture the opportunity and no steps were taken by them to meet the upcoming demand while China, noticed the emerging market of PUC in India and it started increasing its industries with a view to export the PUC in India.
- w. Domestic Industry was never prepared to cater to increasing demand of solar modules & panels to fulfill Government's commitment for 100GW by 2022. This forced Solar Power Developers to import the modules & panels to fulfill this steeply rising demand.
- x. While China was already exporting the PUC to India, the protective measure on the PUC imported from China into the EU and USA were imposed in 2015. Therefore, it will be incorrect to state that the

- actions/policies occurred after almost two decades from the year of signing the agreement i.e. from 1996 were due to the obligation of India on becoming the signatory in 1996.
- y. ISMA has contended that India's obligation under GATT & ("ITA-1") led to the reduction of customs duty of PUC to nil vide Customs Notification No. 24/2005- Cus. dated 01st March, 2005. This contention of **ISMA** is wrong and without any basis. Object of ITA-I was to achieve free movement of Information Technology Products without any tariff barrier. Therefore, there is no nexus between the ITA-1 and PUC.
 - z. One-page statement filed by DI cannot be termed as Adjustment Plan unless same is duly supported by technical details on how these will make DI more competitive. Bald claims cannot be termed as adjustment plan. Being "emergency" actions against "fair trade", safeguard measures are typically temporary import restraints to allow some "breathing time" to DI for adapting to a new market situation through appropriate restructuring. Therefore, Applicant should have provided detailed Adjustment Plan.
 - aa. Demand of the PUC in India is higher than the capacity of the DI whereby there is bound to be a demand-supply gap.
 - bb. Various distribution utilities (DISCOMS) who are sole purchasers of solar power have indicated their willingness to buy sizeable quantity of solar power at lowest possible tariff around Rs.2.50 per unit. Solar power at this tariff is lower than variable cost of coal and gas based thermal power plants. Thus integrating large quantity of solar power would actually help reduce mounting losses and also support commitments to rapidly electrify rural areas. A recent industry research also highlights that at a tariff of Rs.3.0 per unit solar power, India would be able to set up only 30 GW of solar plant but at Rs.2.50 per unit it would be possible to achieve the target of 100 GW easily. Further, in the event of tariff getting reduced to Rs. 2/unit, there would be a demand for nearly 200 GW of solar power by various utilities, Railways and other bulk consumers. Levy of SGD would ultimately impact solar power generation and render tariffs expensive to the consumers and therefore, impact the economy. Depending on amount of DC to AC loading at a plant, tariff would increase from Rs.2.44/kWh to Rs.3.13/kWh if safeguard duty is levied @25% and to Rs.3.25/kWh if safeguard duty is levied @30% thereby resulting in a considerable increase in tariff. It will ultimately impact the cost of power to the public at large and thus will jeopardise the public interest.
 - cc. India has formulated various plans, mission, policies due at National as well as International level, due to which the surge in demand of PUC arose.

ACME Writ Petition filed in Delhi High Court

- dd. A Writ petition was filed by ACME before the Delhi High Court seeking an order to quash the notice of initiation and preliminary findings issued by the DG Safeguards. The issues raised in this Writ petition is to be considered as submissions in the present investigation.
- ee. ACME has contended that the current domestic manufacturing capability of solar PV modules is around 10% of the total requirement. In respect of the Power Purchase Agreements (PPA) signed by the Respondents and DISCOMS, SPD's have already placed orders for import of solar cells and PV modules.
- ff. Domestic Industry withdrew from the AD investigation because it was unable to demonstrate dumping of PUC to the extent of levels claimed by it.
- gg. DG Safeguards directed interested parties to make views known respect of application filed by the ISMA within a period of 30 days from the date of notice. However, without awaiting the views of the interested parties, the DG Safeguards unilaterally passed the public notice giving preliminary findings to impose a provisional safeguard duty of 70% on imports of PUC which has violated the principles of natural justice. Opportunity to make representation ought to have been provided before issuing preliminary findings.
- hh. Safeguard duty, whether provisional/final, should be levied prospectively i.e. in respect of imports made pursuant to PPAs signed after the date when the safeguard duty whether provisional/final is notified. Levying of safeguard duty in respect of PPAs already executed will adversely impact the cash flow to these projects rendering them unviable.
- ii. The DG Safeguards has erred in initiating the investigation and recommending the levy of duty as it is in contravention of Section 8B read with the Safeguard rules as three out of the 5 applicants are units located in SEZs and therefore, cannot form a part of the DI as held by the DG Safeguards in previous cases. On exclusion of the 3 applicants from the definition of DI, the application will not be maintainable.

- jj. Mundra Solar has no standing as Domestic Industry as it was established only in May 2017 i.e. 6 months before filing of the application. Therefore, it is yet to compete in the PUC market in India and cannot claim injury without effectively competing in the domestic space.
- kk. In the absence of a complaint filed by the Domestic Industry, the DG Safeguards does not have jurisdiction to initiate investigation and has assumed jurisdiction which never vested in it.
- ll. The DG Safeguards has initiated the investigation without examining the accuracy and adequacy of documents/information provided by the applicants. The DG Safeguards has solely relied upon data submitted by the applicants in respect of the PUC wherein it says their collective output of PUC is 381 MW in comparison to the total production of 544MW and as such, held that the applicants constitute more than 50% of the total production. Data provided by applicants is incorrect because respondents have not indicated the source of their information, neither any independent source of data for the above particulars. The applicants have relied upon a list of 23 manufacturers wherein 8 of them are in the SEZ. Information regarding production has no independent basis and authentic source. The official data of the Govt. reveals that aggregate operational capacity of the DI on 31.05.2017 was 7173 MW and therefore, data provided by the applicants is erroneous.
- mm. The applicants constitute a mere 10.5% of production capacity which is lesser than their claim of 72% in 2016-2017.
- nn. There is no unforeseen circumstance arising out of the commitment to the Paris Agreement or the National Solar Mission as the Ministry of New & Renewable Energy in their Annual Report Solar 2016-17 acknowledged that the mission targeted included deployment of 20,000 MW of grid connected solar power by 2022. The DI was never prepared to cater to the increasing demand of solar modules and panels due to the government's commitment for 100GW by 2022. This forced solar power developers to import modules and panels to fulfil rising demand.
- oo. Applicants have to show how the unforeseen developments were unforeseeable when India incurred the obligations under GATT.
- pp. Safeguard measures are a type of measure taken as a part of emergency actions and no emergent situation has arisen which warrants invocation of the measure. The Government's policy measures and the Domestic Industry's failure to cater to the huge demand by executing projects awarded by the Government has led to increased imports.
- qq. The object of ITA-1 is to achieve free movement of IT products without any tariff barrier and there is no nexus between India signing the ITA-1 and increased imports of PUC in India.
- rr. Increase in imports is not due to excess capacity of China or protective measures by the US/EU, it is due to the Govt.'s policy to encourage solar power development.
- ss. The Respondent should not have invoked emergency provisions because they have already conceptualised a plan to revamp the domestic solar industry through a dedicated scheme for providing financial support of INR 11,000 Crore to the domestic manufacturers through capital and production subsidies; installation of 12GW of solar PV modules manufactured by the DI under govt. procurement.
- tt. The DI is making noticeable profits in their margin and equity portion in the past 2 years which is contradictory to their claims of incurring significant losses as per the balance sheet obtained from the Registrar of Companies. Mundra Solar being a new facility should not be included in determining the profitability/loss of the DI as being a new facility would mean high cost of interest and depreciation which would have an adverse impact on the profitability during the initial years of operation.
- uu. Position of three petitioners have improved in the injury period in contrast to two petitioners who faced losses due to intrinsic problems such as a new manufacturing facility, restructuring and obsolete technology. Therefore, an increase in imports has not led to injuries.
- vv. The DG Safeguards has taken a one sided view as it has overlooked the fact that developers generate huge employment opportunities, especially in rural areas where the projects are being set up.
- ww. No critical circumstances have been established by the DG Safeguards to levy provisional duty.
- xx. The applicants in the petition have admitted that imposition of safeguard duty would lead to an increase in power tariffs but the respondents in their preliminary findings have not considered this.
- yy. Safeguard measure has to be restricted to temporary withdrawal or modification of the exemption from BCD provided to PUC. Respondent under the garb of safeguard duty cannot levy AD duty.

- zz. High provisional safeguard duty will render the existing projects unviable and would affect the National Solar Mission adversely. Any increase in the cost of import of solar cells and modules will have a direct and material impact on the entire solar power development industry in India as domestic solar generation is dependent on imports because the DI is not growing at the same pace as the solar generation industry.
- aaa. Basis of determination of provisional duty on the method disclosed is arbitrary and vague and not in line with the requirements of Article XIX of GATT.
- bbb. Depending on amount of DC to AC loading at a plant, tariff would increase from Rs. 2.44/kWh to Rs. 4.54/kWh if safeguard duty is levied at 70% resulting in considerable increase in tariff corresponding to the rate at which safeguard duty is levied.
- ccc. The change in law clause in the PPA may cover levy of safeguard duty, however filing a petition before the Central Commission and to ascertain the revised tariff is a long drawn process and delay in getting tariff revised will adversely impact the business. Because of this projects would fail to take off and banks will be reluctant to infuse funds in light of the uncertainty over the levy of safeguard duty.

(xviii) M/s Canadian Solar Ltd.

- a. Solar cells and modules are not like product in view of definition of 'Like Article' in WTO Anti-Dumping disputes of Korea-Certain Paper (WT/DS312) and EC-Fasteners WT/DS397/R).
- b. Solar cells are inputs for modules. Therefore, a solar cell is not commercially substitutable with a module and they are different in terms of end-use/ applications. A single solar cell cannot typically generate electricity which can be used for any commercial application. A module made up of several solar cells can be used for commercial applications due to higher amount of electricity generation. Therefore, solar cells/modules are different from perspective of end-user.
- c. Process of assembling cells into modules is technical & sophisticated process requiring value addition of up to 35% of cost of cells. LV of solar cells ranges from INR 13.71 to 18.59 whereas LV of modules is 24.19 to 36.58. one is an upstream product to the other.
- d. Petitioners may not have suffered injury on modules (data in AD investigation shows no price undercutting on modules). If imports of modules are compared to injury parameters of modules, this would become readily evident. By combining data, Petitioners have obscured the analysis and added modules into scope of duty.
- e. Domestic Industry is not representative of 'major share' of production in India in view of MNRE data on solar cell and module manufacturers as on 28th August, 2017.
- f. Separate analysis of cells and modules will have an impact on standing of DI. No data provided about percentage share of production split between solar cells and modules of DI Companies (as against the total production of solar cells and modules).
- g. 5 DI Companies would constitute only 3.25% of the domestic production of modules. In PF, DG has not examined standing of 5 DI Companies with respect to modules and instead, assessed their standing by taking solar cells and modules together.
- h. 3 are in SEZs and Indosolar is 100% EOU. SEZ or EOU units focus is on export market and do not compete primarily in domestic market whereas purpose of safeguard law is to protect the Domestic Industry from import competition in domestic market. Therefore, EOU and SEZ may form DI only to the extent of their entitlement permitted under the extant laws.
- i. DG Safeguards must follow its earlier determination in unwrought aluminium.
- j. In parallel AD investigation, price undercutting for solar modules during POI (1 April 2016 to 30 June 2017) for subject countries was negative. In present case, the same is very high. Therefore, false simulation in this case.
- k. There is only one year in injury analysis period where price has not moved in tandem with cost of sales i.e. 2015-16. In all other years, Petitioners have been able to price their goods in line with how their costs have moved and therefore, undercutting has not suppressed their prices.
- l. PF established causal link between imports and serious injury on account of price undercutting which has been shown to be wrong above and hence, breaks the causal link.
- m. Petitioners admitted that performance has seen decline due to withdrawal of DCR. This reflects a clear breach of the causal link requirement.

- n. Serious injury, if any, suffered by DI is n account of start-up cost of Mundra Solar PV Ltd. Capacity utilization declined on account of capacity addition of 1.2GW set up by Mudra Solar PV Ltd and not on account of imports.
- o. The tariff prices of solar energy generated out of PV modules have seen a steep decline in India since 2010. India's solar power tariffs fell to a new low of INR 2.44 per unit during the auction of a 250-megawatt (MW) capacity plant at Bhadla in Rajasthan. This is one of the lowest prices offered globally. When compared to the rates of 2010, this indicates a decrease in tariffs of nearly 86%.
- p. This tariff war led to squeezing the margins of domestic solar cells and modules manufacturers. The steep decline in tariff was, in part, result of decline in international price of solar modules. For Petitioners to compete in this market, they needed to drop its prices in line with the lower bid made by the solar power developers and declining international prices. The fall in net sales realization or the revenue of the Petitioners due to the aggressive competition in the downstream industry i.e. solar power developers cannot be and must not be attributed to imports of the PUC.
- q. According to one report by Mercom India, a leading clean energy and consulting firm, while solar installations in India have increased, tender and auction activity have been slowing down over the last couple of quarters. According to the Mercom India Solar Project Tracker, approximately 1.9 GW of solar projects was tendered in the first quarter of 2017 compared to 3.4 GW in last quarter of 2016. The decrease in auction activity can be attributed to factors such as weak financial condition of DISCOM, inefficient transmission, less power demand and increase in captive generation by commercial and industrial companies, and the WTO ruling against India's DCR in its renewable energy policy.
- r. Additionally, the recent record low bid of INR 3.30/kWh at REWA Solar Park Auction has resulted in decrease in auction activity since government agencies are stalling to renegotiate PPAs that are more expensive than bids received at REWA.
- s. Solar Energy Corporation of India and NTPC have set a maximum capacity for a single bidder at 1800 MW and 2000MW. This is being protested by leading developers in the solar market. This is causing hurdles to other domestic producers in the solar market from successfully participating in solar projects.
- t. Annual Reports state reasons for injury to petitioners which are not inclusive of imports.
- u. Indosolar in "Statement of Audited Financial for the Quarter and Year ended on 31 March 2018" reported exceptional items losses on account of impairment of plant and machinery under installation during end of 2017.
- v. Helios reported in its Standalone Financial Statement for January 2015 to March 2016 that the operations of the company were affected due to stoppage of work for a period of 34 days due to workers. Helios, in their Standalone Financial Statement for April 2016 to March 2017 stated that liquidity constraints faced by the company have critically impacted their ability to enhance their manufacturing operations and capacity utilization levels. Further, Helios has stated that the volatility in DCR orders and delay in disbursement of subsidies has impacted its manufacturing operations. Helios vide Standalone Financial Statement for April 2016 to March 2017 at page 8 reported its concern of inability to be cost effective due to lack of consistent demand because of intermittent release of tenders. Websol in Financial Statement (Notes to Accounts) March 2018 stated that there was no full production for quarter ending March 2018.
- w. Indosolar Limited at page 16 of the Annual Report 2014-15 has stated that capacities were unutilized due to the industry downturn and resultant fall in demand.
- x. Unforeseen developments should be the effect of the obligations incurred by a Member under the GATT. it must be explained as to why the developments in question were unforeseeable and how they led to an increase in imports.
- y. Expansion in capacities cannot be an unforeseen development as held in unwrought aluminium. China's export orientation and change in direction towards India also cannot be an unforeseen development.
- z. Events qualifying as 'unforeseen' must have been unexpected when the concession was negotiated. At the time of negotiation of Marrakesh agreement, contracting parties also negotiated agreements pertaining to anti-dumping, anti-subsidy and safeguard. Since parties knew that every Members State has right to adopt trade remedy measures when the circumstances arise, adoption of these measures by other members cannot be 'unexpected' at the time when concessions were negotiated.
- aa. All investigations by EU & US were initiated *well before any alleged surge in imports* so could not have caused the surge in imports.

- bb. PF notes that WTO ruling in DS 456 against India was an unforeseen development. inconsistency with WTO law cannot be considered as “unforeseen”. By stating in PF that “India truly believed that its DCR under JNNSM was consistent with the exception contained in Article XX of GATT 1994”, WTO’s removal of DCR cannot be termed “unforeseeable”. WTO rules were ratified by India in 1994. therefore, it was foreseeable that violation of WTO would result in DCR being removed.
- cc. Commitments by India on enhancing solar capacity under Paris Agreement cannot be considered as unforeseen as it is nothing but an extension of India’s commitments under the “UNFCCC” which India ratified on 1 November 1993. Therefore, India was always committed to reduce its carbon emissions and was fully aware of its commitments at the time when WTO concessions were negotiated.
- dd. Petitioners plan to cut costs by taking measures like ramping up capacity utilization, reduction of financing cost, reduction of raw material cost etc. These adjustment plans have no commercial basis as this is either not in their control or not commercially feasible.
- ee. For example, cost of raw material is not in their control. No whisper of evidence that input suppliers would renegotiate their prices. Petitioners plan to reduce financing cost by converting Rupee borrowings into USD borrowings without explaining how they plan to convert Rupee loans to USD loans and what would be the basis and commercial terms of such conversion. Adjustment plan does not even find a mention in the PF. This is a clear indication of non-application of mind by DG while issuing PF.
- ff. Government has recently been contemplating to benchmark the rates for solar projects. However, few experts have noted that such benchmarking could affect the players in the solar market as benchmarking has come at a time when the players in the market are unsure about the costs on solar power.
- gg. Experts have also noted that if the Director General of Safeguard’s recommended duty of 70% were to be implemented, it could increase the costs of solar power to almost 3 Rupees/unit. While the provisional recommendation was never levied, the core principle remains the same even for a final finding recommendation. In public interest, the DG Safeguards should not recommend any safeguard duties on the PUC and terminate the investigation as the ultimate impact would be on the users of the PUC in the solar market due to imposition of duties.
- hh. Present investigation is currently proceeding on the basis of outdated data, which does not appear to have been updated. As background, it may be noted that it is established practice in safeguard investigations to examine the most recently available data for both imports and injury.
- ii. Since six months have passed from the initiation of investigation, the data for the year 2017-18 is now available for both imports as well as injury. However, the Petitioners do not seem to have brought any recent data on record.
- jj. The Domestic Industry in the Anti-dumping investigation had actually alluded to the grave injury suffered by it in the period following the period of investigation. In this behalf, it is interesting to note that the period of investigation and injury period in both investigations remains largely common, with the only three months differentiating the two investigation periods.
- kk. The Exporters submit must have an opportunity to file further submissions as and when the updated data becomes available. The DG Safeguards should refer to letter dated 21st June 2018 filed by the Exporters pursuant to DGTR letter dated 18th June, 2018 wherein the Exporters have questioned the Designated Authority’s requirement of filing the Written Submissions prior to the public hearing and have reserved their right to file further submissions in the event new and recent data is made available
- ll. 3 Petitioning Companies, who were also in parallel AD investigation, admitted that injury to DI was on account of *dumped imports* for POI April 2016 to June 2017 (which also nearly covers POI in present investigation). Consequently, injury suffered by DI cannot be now attributed to surge in imports to justify a safeguard investigation. Petitioners are engaging in forum shopping and therefore, DG should terminate investigation as injury is due to dumped imports which fall under ambit of AD laws and not Safeguard.
- mm. Further, the Annexure to the Safeguard Rules states that – if there are factors other than increased imports that are causing injury to the Domestic Industry, such factors “shall” not be attributed to the increased imports.
- nn. DA in parallel AD investigation found no merit in the grounds raised by Indian producers.
- oo. Since DA found no merit in DI’s reasons for withdrawal for POI covering 1 April 16 to June 17 of AD investigation, it is unlikely that the DG Safeguards will find “serious” injury when POI is 14-15 to 17-18.

(xix) M/s Renew Solar Power Private Limited

- a. Units located in the SEZ cannot be considered as part of the Domestic Industry under section 8(6)(b)(ii) of the Customs Tariff Act. The data given by petitioners does not in any manner provide a correct and realistic picture of the entire domestic manufacturing industry and hence, cannot be relied upon to establish injury of the Domestic Industry.
- b. Developers and Co-developer units in the SEZ's are given various exemptions and concessions under the SEZ Act, 2005 in the form of tax and fiscal benefits with a view to increase exports and therefore operate in a different sphere.
- c. Units located in the SEZ are export oriented and not set up for meeting the domestic demand.
- d. It is due to competitive and better technology of imports that the applicants are not able to create a domestic demand for their products in the domestic market.
- e. Applicants have failed to establish that circumstances claimed as unforeseen were actually so, and that there was a causal link between such circumstances and an increase in the imports.
- f. Applicants' rationale for linking the increased imports to the increased capacity of China is completely illogical, flawed and reeks of malafide intention to cover its own shortcomings. As increase in the imports was on account of the National Solar Mission, the same cannot be related to increased production capacity of China.
- g. China's domestic solar policy was the reason for consistent investments in technology which resulted in increased production capacity, efficiencies and economies of scale. Increase in capacity requires a minimum gestation period of 3 years and the same cannot be termed as an unforeseen development.
- h. No country would increase its capacity for the sole purpose of exporting to India. Data submitted by the applicants themselves show that most of the increase in capacity is for domestic consumption within China and not for the purpose of Exports.
- i. Withdrawal of DCR is not an unforeseen development that led to increase in imports as the same was in operation for most of the POI. Applicants have themselves admitted that the effects of the unforeseen development were not visible till the DCR's presence. Even the removal of the DCR has not put the domestic industry in a disadvantageous position on account of various government schemes.
- j. Installed production capacity of the domestic industry is not enough to cater to domestic demand as even its full utilization would only lead to satisfying 9.12% of the domestic demand which is the root cause for the imports.
- k. Data of the POI relating to production capacity to establish injury cannot be relied upon as large proportion of the Applicant's production data is on account of the 1200 MW plant set up by Mundra Solar PV Limited which has not started production line till May, 2017 and hence, hasn't achieved full utilization.
- l. Underutilization of the DI is on account of seasonal tenders issued by the Government. There is no constant demand throughout the year as a result of which at time of sudden demand of modules close to the commissioning of the Projects, the domestic industry is unable to meet the demand due to the constraints of limited production capacity every month.
- m. Technology used by the DI is inferior to efficient technology used by global manufacturers. Maximum annual capacity of the only applicant having superior technology, Mundra Solar PV Limited, is only 1200 MW and the domestic industry would be constrained to import modules equipped with superior technology from outside India.
- n. Solar Power Developers are responsible for generation of considerable employment within India with every 1MW of solar power giving direct employment to at least 2 persons. Imposition of SGD would lead to drastic reduction in employment generated by the industry due to setting up of new projects becoming financially unviable.
- o. Imposition of safeguard duties would be detrimental to the growth of the industry as it would lead to increase tariffs by Rs. 3.95-4.05 per unit.
- p. DI has not been able to establish whether the injury, if any, is on account of dumping by certain countries or due to increased imports. The Applicants clearly believed that injury was suffered on account of dumping by the subject countries as is evident from the application made for antidumping investigations, therefore they cannot now claim injury due to increased imports.
- q. SGD is against public interest as imposition of the duties would lead to a situation where solar power would become high and unaffordable by the public. Any such trade measure would severely hamper the ability of the government to honour international commitments as well as achieving the target of 100 GW by 2020.

(xx) M/s Cleanmax Ltd.

- a. There is a history of trade remedy investigations against the PUC. DGAD had recommended ADD on imports of this product from China, Malaysia and Taiwan in 2014. However, GOI did not implement the duty in light of its mission to power every home in rural and urban India with solar power. Cleanmax is working hard to fulfil this mission.
- b. SGD will distort the entire solar market in India. Existing PPAs will be in jeopardy – as Discoms will contest / litigate attempts by Developers to pass on tariff hikes. Solar power tariffs will shoot up, foreclosing developers from quoting fair prices in prospective tenders. DISCOMS will lose interest in purchasing from solar power developers and may shift to conventional source of power. The NSSM target by 2022 will never see fruition.
- c. The share of imports in period under examination grew from 86% to 90% of the total domestic consumption – which can hardly be called a massive growth.
- d. There is no serious injury to domestic industry and even if so, there is no link of trade to woes of domestic manufacturers. The DI's EBITDA margins at 16% for the period under investigation are roughly 60% higher than EBITDA margins for top 10 global manufacturers. This indicates that high interest burdens due to higher capex/ interest costs are to blame – and not imports.
- e. The petitioners to DG, Safeguards do not comprise 51% of domestic industry for a majority of the control period as per MNRE data (vs. DG Safeguards assertion that DI is 96% of industry). Further, if domestic industry excludes SEZ units, then the petitioners are much lesser than the needed 51% share.
- f. The DG Safeguards finding that China diverted its exports to India because of trade remedy measures by the EU and US, that imports increased as India could no longer provide the protective ambit of DCR to the domestic industry which led to the increase in imports and that imports also increased because India reduced the customs duty to zero on solar cells and modules under the ITA-1 is wrong. Imports increased because of GOI's vision to promote solar energy. GOI was aware that Indian manufacturers could only cater to less than 10% of the demand. However, the Government could foresee that imports would be able to fill this demand-supply gap. This is the sole reason behind imports of this product. Imports from China and other countries happened only to fill this demand-supply gap. Therefore, such imports are not a result of any unforeseen developments.
- g. The domestic industry could paint a picture of losses because of the addition of M/s Mundra Solar PV Limited. Mundra set up a new manufacturing facility and began commercial production in 2017. With new facilities came high interest cost and depreciation which had a detrimental impact on profitability. Injury to this company is not because of imports but because of high interest cost and depreciation cost.
- h. Helios Photo voltaic Pvt. Ltd. (formerly Moser Baer), a Company engaged in manufacturing of various products including CDs, has been making losses from the year 2008. The Company was undergoing corporate debt restructuring for a long time and has very high liabilities in the balance sheet.
- i. Indian cell manufacturer enjoy much higher profit margin at operating level which is an indicator of whether or not imports are causing injury to DI. Their losses are factors of high capital cost per MW, high interest cost and management inefficiencies.
- j. Based on data from MNRE, Domestic Industry has operational capacity of 933 MWs which is 56% of the total cell capacity with significant instalments completed in the year 2017. During the year 2016 the DIs constitute operational capacity of 49.7%.
- k. Definition of Solar Manufacturing should include both Cell and Module manufacturing. While in the year 2017, DIs constitute 56% in cell manufacturing of the total Cell Capacity in India, DI constitute only 2.6% in the module manufacturing for the period ending 31st May 2017.
- l. In December 2017, MNRE made a statement that installed capacity of Indian manufacturers is obsolete and it proposes an investment of INR 11,000 Crores by way of Govt. assistance.
- m. MNRE has proposed to have an additional CPSU scheme of 12,000 MW which would have an assured DCR component. This will allow the domestic industry an assured market.
- n. DG Safeguards has previously ruled that SEZ units cannot be considered as DI.
- o. The domestic industry is injured because of obsolete technology and not imports

(xxi) M/s Taiwan Photovoltaic Industry Association

- a. No justification has been offered by the DG for imposing provisional duties at 70% ad valorem. Justifications required to be provided in terms of Rule 11(2) of the SGD Rules, 1997 have not been given by the DG to show how such an amount is adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate positive adjustment.
- b. Preliminary findings have been issued in violation of principles of Natural justice as initiation notification had been issued on December 19, 2017 giving 30 days' time to the Interested Parties to make their views known on the investigation while the Preliminary Findings were issued on January 5, 2018 before the completion of such period, without giving an opportunity hearing to the Interested Parties.
- c. Provisional safeguard measures cannot be imposed without an evaluation of critical circumstances. The DG has only narrated the circumstances which according to it has caused injury without citing any evidence in support of the Preliminary Findings. Imposition of such duty, in absence of any cogent evidence of such 'critical situation' or critical state of DI is violative of Article 6 of the Safeguards Agreement and Rule 9 of Safeguard Duty Rules.
- d. C-si and Thin Film cells are not like articles and the DG's determination of the two as the same product is a result of blindly following the Domestic Industry's application. Recording of such findings in the Preliminary Findings show complete misapplication of the DG's mind and is a violation of principles of natural justice.
- e. C-si and Thin Film cells are different products on account of difference in raw materials used, manufacturing process, conversion efficiency, output and other capabilities, which affect relative prices, limit interchangeability and also limit any overlap in channels of distribution.
- f. C-si cells have a higher module conversion efficiency than thin film on account of different manufacturing processes. The two cells are also not commercially interchangeable. DI does not constitute majority of the producers of the PUC and therefore, in terms of requirement of Section 8B of the Customs Tariff, the petition is not maintainable.
- g. On the basis of the installed and operational capacity for manufacture as specified in the report, it has been contended that production by DI is a mere 26.41% as a whole for the industry.
- h. the claim that the Applicants satisfy the definition of DI was accepted without verifying accuracy and adequacy of evidence, and thus the initiation of the present investigation should be set aside.
- i. The standing of DI is vitiated as Mundra, Websol and Helios Photo Voltaic cannot be treated as a domestic industry since 3 out of 5 are based in SEZ and thus cannot be treated as DI.
- j. As a result of such exclusion, the installed capacity and other economic data with respect to Mundra and Helios are to be excluded (specifically Mundra's 2400 MW installed capacity), which would render the contribution of DI in production of PUC to a mere 5.73% and would effectively disqualify remaining applicants as DI.
- k. With inclusion of Mundra, Websol and Helios, in case they sell their products in DTA, the products would be subject to Safeguards Duty thus making their products uncompetitive in the domestic market. To avoid the same, the applicants as a part of well-conceived plan first got their SEZ units included as a part of DI and thereafter requested for their exclusion from imposition of safeguard duty. This uncovers the mala fide intent of the Applicant to offer protection to DI and exclude competition arising out of Solar Cell imports, which are more efficient and is a reason why it is preferred by buyers in India.
- l. Existence of unforeseen developments under domestic safeguard laws is an essential and primary condition for initiating investigations for levy of Safeguards Duty as contemplated under Article XIX of GATT.
- m. PRC's domestic consumption of Solar Cells is far more than exports. In solar modules, while exports exceeded domestic consumption in 2014, by 2016 domestic consumption had surpassed exports. Thus allegation on excessive production and capacity of PRC being an unforeseen development is unfounded.
- n. USA challenged DCR requirements before the WTO Appellate Body. Eventual withdrawal of DCR was not unforeseen since it fell foul of National Treatment obligations under GATT and there was always a possibility that the same could be challenged at WTO. Eventually, DCR had also lost its utility to domestic manufacturers who were losing out to imports due to a number of factors. Eventually, the Panel Report relating to India-Solar Cells matter referred to the fact that DCR affects a relatively small amount of production. Hence it was not an unforeseeable development.

- o. The Paris Agreement was not an unforeseeable event but rather a culmination of agreements and developments that had been underway from 1992 (when enacted) and 1994 (when it came into force) which attempted to deal with environmental issues and specifically climate change. Accordingly, the same cannot be considered to be unforeseen.
- p. In light of the Preamble of ITA-1, it can be inferred that it was not unforeseen by the GoI at the time of granting concession under ITA-1 that certain developments may arise to encourage continued technological development of IT industry on a world-wide basis. Moreover, the Applicants have failed to demonstrate as a matter of fact how imports of the PUC being made free under ITA-1 has led to unexpected increase in imports only during the POI, when India became a signatory to ITA-1 in 1997 and tariffs were eliminated by 2000. Thus obligations arising under ITA-1 could not be termed as an unforeseen development.
- q. The contention of the Applicants that the import of the PUC increased by 732% in the course of 2014-15 to 2017-18 relying upon the data mentioned under Annexure 9 of the application has been questioned. On perusal of data given by Annexure 1.3 of the Anti-Dumping Investigation Petition filed by ISMA, it is claimed that different figures of import are given, which proves the fact that evidence provided by the applicant is doctored.
- r. The actual import value of PUC is INR 505,000 lakhs in 2014-15, 1.55 mn lakhs in 2015-16, 2.14 mn lakhs in 2016-17 and 2.47 mn lakhs in 2017-18. (Para 5.8.17) Import data of PUC also establishes that percentage of increase in imports on a year to year basis has actually declined by 27.98%. As a result, increase in import is not such that it would cause serious injury to DI such that it would require imposition of Safeguard Duty.
- s. The DI has maximum production, maximum sales, maximum capacity utilization and has been undertaking capacity expansion during the entire POI. As cannot be said to be in the position of significant overall impairment in the present case. Further, no serious injury is demonstrated through financials of DI in any of these factors
- t. Due to increasing market share of the DI, along with the facilitator role of the imports establish that no serious injury is being caused to the DI.
- u. In determination of cost of solar module 50-60% cost is of solar cells which means that decrease in cost of solar cells is directly proportional to cost of solar module. From an analysis above data of sales realisation of domestic producers, it can be inferred that price of solar cells is decreasing whereas price of solar modules is increasing, which is contrary to logic because effect of decline in solar cell price should be more significant on module price.
- v. Employment in DI increased by 450% (by around 2600 employees) from 2014-15 to 2017-18. Exclusion of Mundra Solar employees was bad in law, and if such were the case then they should have been withdrawn from the scope of DI altogether. On perusal of the data, even if Mundra Solar's employees are excluded from the purview, there would still be a rise in no. of employees by about 27.1%. reliance is placed on financial statements of the Applicants to establish that 3 out of 5 Applicants were running in profit. The profitability of Mundra was irrelevant since it became operational only in May, 2017 and therefore, have detrimental impact on profitability due to high cost of interest and depreciation initially.
- w. In the absence of missing causal link, without considering and evaluating other relevant factors in the investigation, serious injury cannot be determined within scope of Rule 8 of the Safeguard Duty Rules.
- x. In view of above submissions, without considering and evaluating other relevant factors in the investigation, serious injury cannot be determined within scope of Rule 8 of the Safeguard Duty Rules.
- y. Levy of safeguard duty would make imports of PUC expensive which would hinder the development of solar sector, currently in full swing, and also may lead to targets set under JNNSM unachievable.
- z. Concerns on loss of employment alleged by the Applicants is unsubstantiated and needs to be looked in a broader perspective with creation of more employment opportunities in the present solar power development crusade.
- aa. ADD imposed earlier was eventually not renewed since the Power Minister had stated that domestic solar equipment manufacturing capacity of 700-800 MW is not sufficient to meet the government's ambitious plans of adding more power generation capacity through renewable energy sources.
- bb. imposition of Safeguard Duty would increase price of the PUC, hurdle progress of JNNSM and create huge gap in supply and demand of the PUC in India. Moreover, it will also lead to denial of new and more

efficient technologies from being imported in the country. Therefore, imposition of Safeguard Duty is not in public interest.

- cc. Imports from Taiwan should be excluded as the imports have been less than 5% during the POI.
- dd. Solar Modules are made from Solar Cells, which is one of the inputs required for its production. Solar Cells assembled in panel being a value-added product requires various production activities to be carried out and substantial investment for the production facility needs to be treated differently by providing a higher level of protection against Solar Cells assembled in panels than Solar Cells.

(xxii) M/s Shapoorji Pallonji Infrastructure Capital Co. Ltd.

- a. Units located in the SEZ cannot be considered as part of the Domestic Industry under section 8(6)(b)(ii) of the Customs Tariff Act. The data given by petitioners does not in any manner provide a correct and realistic picture of the entire domestic manufacturing industry and hence, cannot be relied upon to establish injury of the Domestic Industry.
- b. Developers and Co-developer units in the SEZ's are given various exemptions and concessions under the SEZ Act, 2005 in the form of tax and fiscal benefits with a view to increase exports and therefore operate in a different sphere.
- c. Units located in the SEZ are export oriented and not set up for meeting the domestic demand.
- d. It is due to competitive and better technology of imports that the applicants are not able to create a domestic demand for their products in the domestic market.
- e. Applicants have failed to establish that circumstances claimed as unforeseen were actually so, and that there was a causal link between such circumstances and an increase in the imports.
- f. Applicants' rationale for linking the increased imports to the increased capacity of China is completely illogical, flawed and reeks of malafide intention to cover its own shortcomings. As increase in the imports was on account of the National Solar Mission, the same cannot be related to increased production capacity of China.
- g. China's domestic solar policy was the reason for consistent investments in technology which resulted in increased production capacity, efficiencies and economies of scale. Increase in capacity requires a minimum gestation period of 3 years and the same cannot be termed as an unforeseen development.
- h. No country would increase its capacity for the sole purpose of exporting to India. Data submitted by the applicants themselves show that most of the increase in capacity is for domestic consumption within China and not for the purpose of Exports.
- i. Withdrawal of DCR is not an unforeseen development that led to increase in imports as the same was in operation for most of the POI. Applicants have themselves admitted that the effects of the unforeseen development were not visible till the DCR's presence. Even the removal of the DCR has not put the domestic industry in a disadvantageous position on account of various government schemes.
- j. Installed production capacity of the domestic industry is not enough to cater to domestic demand as even its full utilization would only lead to satisfying 9.12% of the domestic demand which is the root cause for the imports.
- k. Data of the POI relating to production capacity to establish injury cannot be relied upon as large proportion of the Applicant's production data is on account of the 1200 MW plant set up by Mundra Solar PV Limited which has not started production line till May, 2017 and hence, hasn't achieved full utilization.
- l. Underutilization of the DI is on account of seasonal tenders issued by the Government. There is no constant demand throughout the year as a result of which at time of sudden demand of modules close to the commissioning of the Projects, the domestic industry is unable to meet the demand due to the constraints of limited production capacity every month.
- m. Technology used by the DI is inferior to efficient technology used by global manufacturers. Maximum annual capacity of the only applicant having superior technology, Mundra Solar PV Limited, is only 1200 MW and the domestic industry would be constrained to import modules equipped with superior technology from outside India.
- n. Solar Power Developers are responsible for generation of considerable employment within India with every 1MW of solar power giving direct employment to at least 2 persons. Imposition of SGD would lead to

- drastic reduction in employment generated by the industry due to setting up of new projects becoming financially unviable.
- o. Imposition of safeguard duties would be detrimental to the growth of the industry as it would lead to increase tariffs by Rs. 3.95-4.05 per unit.
 - p. DI has not been able to establish whether the injury, if any, is on account of dumping by certain countries or due to increased imports. The Applicants clearly believed that injury was suffered on account of dumping by the subject countries as is evident from the application made for antidumping investigations, therefore they cannot now claim injury due to increased imports.
 - q. SGD is against public interest as imposition of the duties would lead to a situation where solar power would become high and unaffordable by the public. Any such trade measure would severely hamper the ability of the government to honour international commitments as well as achieving the target of 100 GW by 2020.

(xxiii) Taiwan Economic and Cultural Centre

- a. The authority was earlier handling the anti-dumping investigation on the PUC and should have no difficulty in comparing the data sets from the anti-dumping investigation and the ongoing safeguard investigation and determine whether the safeguard petition has any merit.
- b. Taiwan is a developing country and has not reached the de-minimis level required in Article 9.1 of the Agreement on Safeguards (AOS) and cannot be subject to duty.
- c. Many solar tenders by India's state governments have failed to attract good responded from bidders because of the uncertainty on the duties.
- d. Petitioners do not have adequate standing to be considered as DI in terms of Article 4.1 of the AOS as standing of the petitioners should be examined separately for solar cells and solar modules. The installed capacity of Petitioners for solar modules is 15% of the installed capacity in India, meaning that the share of petitioners for solar modules is 15% if they manufactured at their full capacity. Therefore, their collective output does not constitute major proportion of total domestic production of solar cells and solar modules.
- e. The Preliminary findings fail to examine unforeseen developments as imports increased due to demand created by NSM.
- f. Import duties on PUC became zero in 2005 as a result of India's commitments under ITA-1, but preliminary findings fail to identify how this GATT obligation that came into effect 12 years ago led to a significant increase in imports. Imports increased after the Indian govt. inaugurated NSM in January, 2010.
- g. Indian manufacturers can cater to about 10-15% of the annual demand on India leaving the remaining to be fulfilled by imports.
- h. The financial position of three of the petitioners improved during the injury period but only two other petitioners faced losses due to intrinsic problems such as corporate debt restructuring, etc.
- i. A major cause of injury is decline in exports by the petitioners. The petition shows a sharp decline in exports of the petitioners from 100 indexed points in 2014-15 to 13 indexed points in 2017-18 (Annualised). Injury due to such factors cannot be attributed to imports of the PUC.
- j. Rapidly increasing capacities which the petitioners are finding hard to stabilise has led to high cost related to interest and depreciation.
- k. Number of employees of petitioners have increased 5 times in the injury period, leading to a 4 times increased in the wage cost incurred by the petitioners which is another reason of injury.
- l. MNRE plans to have an assured DCR component means that the DI has an assured market.
- m. Imports of thin films are less than 1% of total products into India and cannot cause serious injury and should be excluded from the product scope.
- n. Petitioners have claimed confidentiality on their individual adjustment plans which makes it difficult for Taiwan to provide any meaningful comment to the Petitioner's endeavours under Article 7.1 of the AOS.
- o. Backward integration in the form of reduction in cost, achieving economies of scale, establishing plants for manufacturing wafers and ingots as a part of the adjustment plan will only lead to higher cost in the next few years. Such an adjustment plan is not feasible and will not facilitate adjustment in terms of Article 7.1 of the AOS/
- p. Taiwan should be considered as a developing country because Taiwan recognises itself as one according to the self-recognition principle enshrined in WTO Agreements.

(xxiv) Domestic Industry

- a. The product under consideration is ‘Solar Cells, whether or not assembled in Modules or Panels’. The product is classified under sub-heading 8541.40 of the Harmonized Commodity Description and Coding System, popularly called HSN, and sub-heading 8541.40.11 of the Indian Customs Tariff Classification.
- b. The products are covered under Attachment A, Section 1 of the *Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products*, popularly known as Information Technology Agreement (ITA-1). The ITA-1 mandated elimination of customs duties and other duties / charges of any kind [within the meaning of Article II:1(b) of the GATT 1994] on the products listed therein. Since India is a signatory to ITA-1, the imported products are exempt from basic customs.
- c. The relevant tariff heading identifies cells, modules and thin film modules as one product and the duty exemption is applicable to all the three types i.e. c-Si solar cells, c-Si solar modules/panels and Thin film modules/panels.
- d. There are two major types of solar cells, one that use Crystalline Silicon (c-Si) Technology and the other using Thin Film technology. The Applicants are producing only c-Si type solar cells, while the cells imported are both c-Si type as well as Thin Film type.
- e. The identification process starts with the identification of the product under investigation or (PUC). The PUC comprises of Solar Cells whether or not assembled in modules or panels. The PUC covers solar cells irrespective of the technology used to manufacture them. The imports into India comprise of Solar cells of c-Si as well as thin film technologies. For the c-Si technology products imported, domestically produced c-Si technology cells would be the like articles. For the thin film technology products imported into India, domestically produced c-Si technology products would be the ‘directly competitive’ articles.
- f. In the absence of any material differences between the two types of Solar Cells, any attempt at drawing a distinction between c-Si technology products and thin film technology products in this case would result in defining not the “like or directly competitive product” but a *portion* of such like or directly competitive products. Such an approach is inconsistent with the determination of like or directly competitive product as mandated under the Agreement as held by the WTO Panel’s in Dominican Republic – Safeguard Measures.
- g. There are no material differences between the two Solar Cells manufactured in terms of function or end use, since Solar Cells based on both c-Si and Thin Film technologies are used to generate electricity using the photovoltaic process. Accordingly, there being no basis for differentiating between the two types of Solar Cells for the determination of a “directly competitive/substitutable product” in relation to the imported products, the PUC has correctly been determined as “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels”.
- h. The Designated Authority, Directorate of Anti-Dumping & Allied Duties (DGAD) had earlier recommended imposition of anti-dumping duties against imports from China, Malaysia, Taiwan and USA. The scope of subject goods in this application is similar to the said anti-dumping investigation.
- i. The inclusion and/or exclusion of thin films from the scope of product under consideration is a case-by-case determination based on facts of each case. The facts surrounding the present case in India make it essential to include thin films also in the scope of product under investigation. Otherwise, the entire exercise may lead to circumvention of safeguard duties since the importers may simply switch to thin films to avoid any duties. It is also pertinent to note that “Thin Film Modules” are also imported under the same heading and are exempt from basic customs duty like solar cells/modules. In the 2014 final findings of the antidumping investigation on solar cells, the Ld. Designated Authority held that c-Si products and Thin film products shall be covered within the scope of the product under investigation.
- j. Finally, the Ld. Designated Authority correctly appreciated that thin film should be considered within the scope of like article as in India, the competition between thin films and crystalline products are very high and significant and the low efficiency of thin film modules hasn’t vitiated the growth of demand for thin film products. Consumers perceive both the products as similar and find them as perfect substitutes. Under such market conditions prevailing in India, exclusion of one product will open up backdoor entries to the other type nullifying the purpose of entire exercise. Therefore, thin film cannot be excluded from the scope of like article as otherwise, users will simply switch over to thin film technology nullifying the purpose of the entire exercise.
- k. Cells and modules form a single product. The Designated Authority, in its earlier 2014 decision, had also considered Solar Cells and Modules to be a single product.

- l. The petitioners constitute a major proportion of the total Indian production of the subject goods and therefore, constitute Domestic Industry within the meaning of 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act, 1975 as the collective production of the petitioners accounts for more than 50% of the total production of the PUC in India. Therefore, they represent a major proportion of the total Indian production and therefore, constitute Domestic Industry of the like article in India. The Ld. DG Safeguards also confirmed in the Preliminary Findings dated 05.01.2018 that the petitioners accounted for a major share of production of the subject goods in India and therefore, constituted Domestic Industry.
- m. The Ld. DG Safeguards observed that M/s Mundra Solar PV Limited, M/s Websol Energy Systems Limited and M/s Helios Photo Voltaic Limited are based in Special Economic Zones (SEZ) and therefore, while imposing the safeguard duty, the same may be exempted from its levy by means of an adequate measure. However, clearance of subject goods from an SEZ to the DTA will not attract any safeguard duty in the event that the same is levied. This is clear from a combined reading of Section 8B(2A) and Section 30 of the SEZ Act, 2005. For ease of reference, Section 30(a) of the SEZ Act, 2005.
- n. The levy of the ADD, CVD and SGD under Section 30 of the SEZ Act, 2005 are qualified by the words 'where applicable'. Therefore, one needs to ascertain as to when anti-dumping duty, countervailing duty or safeguard duty is applicable in any given case.
- o. The language of Section 9A pertaining to the levy of anti-dumping duty, Section 9 with respect to countervailing duty and Section 8B pertaining to the levy of safeguard duty all state, in no uncertain terms, that the same are applicable on imports of an article into India. Therefore, if an article is not imported into India, none of the aforesaid duties are payable. Though by a deeming provision, a legal fiction is created whereby SEZ's are considered to be outside the customs territory of India, there is no provision under any extant law in India which deems the clearance of goods manufactured in an SEZ to the DTA as an import. The fact that clearance of goods manufactured in an SEZ to the DTA does not amount to import into the territory of India has also been reiterated in a catena of judgments including *Essar Steel v. Union of India* [2010 GLH (1) 52], *India Exports v. State of U.P. & Ors* [(2012) 47 VST 126], *Tirupathi Udyog Limited rep. by its Manager-Administration Shri D.V. Saradhy v. Union of India (UOI) through the Secretary, Ministry of Finance and Ors.* [2011 (272) ELT 209(A.P.)]. Therefore, without the factum of import, there can be no levy of anti-dumping duty, countervailing duty or safeguard duty.
- p. Anti-dumping duties and countervailing duties are country specific and therefore, even if the aforesaid duties are levied on the description of a like article which is manufactured in an SEZ and eventually cleared into the DTA, the same can never attract the aforesaid duties as there can never be an anti-dumping or countervailing investigation alleging dumping or subsidies against an SEZ in the territory of India itself and consequently, the question of levying any such duty would not arise. Therefore, to give effect to the meaning of the words in section 30 of the SEZ Act, 2005, the mention of levy of anti-dumping duty and countervailing duty mentioned therein during DTA clearance has to mean duty payable on the value of the inputs (*in the event that the inputs imported from specified countries attract anti-dumping duty or countervailing duty*) used on the finished product and not on the finished product itself, the latter being an impossibility.
- q. The same principle is also applicable to safeguard duties levied against any like article that is also manufactured in an SEZ and cleared into the DTA. Unless safeguard duty has been imposed on the description of the inputs which have been imported and used in the manufacture of the finished product that is eventually cleared into the DTA, in which case the safeguard duty will be levied only to the extent of the value of the input (*assuming the input attracts safeguard duty*) employed in the manufacture of the finished article, no safeguard duty will be attracted on the finished product itself even though the same may be a like article against which India has imposed safeguard duties. This is also evident from Section 8B(2A) of the Customs Tariff Act, 1975. Therefore, Section 30 of the SEZ Act, 2005 read with Section 8B(2A) of the Customs Tariff Act, 1975 make it abundantly clear that safeguard duty is only payable on the inputs used in the finished products and not the finished product itself that is manufactured in the SEZ and cleared into the DTA.
- r. Safeguard Duty would not be payable on the finished product manufactured in an SEZ and cleared into the DTA for one additional reason i.e. in a situation where safeguard duty has been levied by India on the description of inputs used in the manufacture of a finished product in the DTA as well as on the description of the finished product as well, then while clearance into the DTA, both the inputs used as well as the finished product will attract safeguard duty which will amount to double taxation. Such a levy being illegal,

- the reference to anti-dumping duties, countervailing duties and safeguard duties in section 30 of the SEZ Act, 2005 will always have to mean on the value of inputs as otherwise, the duty will be unworkable.
- s. India has faced a massive surge in imports of the subject goods during the period of investigation. The PUC is being imported into India from various countries including China PR, Malaysia, Singapore and Taiwan. Major quantity of the subject goods are being imported from China PR. Imports of the product concerned increased from 1,275 MW in 2014-15 to 9,474 MW in 2017-18 (Annualised), an increase of over 643% during the last three years. Import volumes have increased steadily over the past three years.
 - t. The imports increased by 228% in 2015-16 over the previous year. Similarly, year on year increase in imports was 52% in 2016-17 and 49% in 2017-18 which leaves no manner of doubt that import volumes increased significantly each year. Moreover, the Ld. DG Safeguards has also arrived at a finding in the Preliminary Findings dated 05.01.2018 there has been a sudden surge in import volumes during the first six months of 2017-18 which is equivalent to approximately 74% of the imports in 2016-17. Therefore, there was an absolute increase in imports which was recent, sudden, sharp and significant by any standard.
 - u. Furthermore, imports also increased in relation to production of the subject goods in India which was also appreciated by the DG Safeguards who found that relative to domestic production, imports of the PUC consistently increased between 2014-15 and 2017-18 (Annualized). The growth rate of such imports as a percentage of the domestic production was a remarkable 1,371% during the intervening year 2015-16. Even the overall growth rate of imports of the subject goods in relation to domestic production rose from 519% in 2014-15 to 814% in 2017-18. Thus, during the entire POI, the import volumes of the PUC relative to its domestic production were found to have not only increased consistently but such increase was also found to be significant.
 - v. This significant increase in the volume of imports has also been reflected in terms of increase in value of imports. From Rs. 3,991.21 crores during 2014-15, import value increased to Rs. 21,701.38 crores during 2017-18 (Annualised). The increase in value was, however, not in proportion to the increase in volume of imports as import prices declined significantly during the same period. CIF Price was Rs.30.98 Per Watt during 2014-15 but it declined to Rs. 23.03 during 2017-18 (annualised).
 - w. The surge in imports has been at extremely cheap prices and prices of imports have consistently been reducing throughout the POI. Consequently, this surge in cheap imports has caused serious injury to the Domestic Industry and is threatening its very existence.
 - x. In view of the substantive requirement of Article XIX, the developments which led to *Solar Cells* being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause serious injury to domestic producers should have been “unforeseen”. While determining the scope and meaning of the term ‘unforeseen developments’, the Appellate Body of the WTO in *Korea – Dairy* and *Argentina – Footwear (EC)*, held that the same is synonymous with “unexpected”.
 - y. The test to be applied for the purpose of determining whether any event was an unforeseen development is whether the same was expected at the time of incurring the obligations. As held by the Appellate Body, the test is not whether the developments were unforeseeable. Rather, the test is whether the same were unexpected at the time of incurring the obligations, i.e. accession to WTO, resolving to abide by the commitments under various WTO Agreements, providing tariff concessions and subsequently amending those tariff concessions through *Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products* (ITA 1). Therefore, the developments should have been unforeseen or unexpected on December 13, 1996 – the date on which the Ministers agreed on ITA 1.
 - z. The developments which led to the massive surge of subject goods into India was the shift in trade pattern between Chinese imports and India as a result of the Anti-dumping and Countervailing duty orders in the USA associated with (i) the Crystalline Silicon Photovoltaic (CSPV 1) investigations, which became effective on 07.12.2012 and (ii) the CSPV 2 investigations, that became effective on 18.02.2015. Also, in the EU, the provisional measure with respect to the same subject goods came into effect on 05.06.2013 and the final measure was imposed on 05.12.2013. The timelines of the measures imposed by the US and the EU more or less coincided with each other with minimal or no variance. The immediate impact of these measures was not visible because of the presence of Domestic Content Requirements (DCR) under the JNNSM.
 - aa. The DCR was challenged in the year 2013 before the Dispute Settlement Body of the World Trade Organisation by the United States. In September 2016, the United States won when the WTO Appellate Body held the DCR to be inconsistent with the obligations incurred by India under Article III:4 of the

- GATT 1994 and Article 2.1 of the TRIMs Agreement. Pursuant to the removal of DCR, the change in pattern of trade became pronounced as the products have a robust demand in India. More so, because of India establishing an ambitious and laudable target of achieving 100 GW of solar power generation by the year 2022.
- bb. Unforeseen developments have modified the conditions of competition between imported subject goods and the goods produced by the domestic industry as before the imposition of countervailing and Anti-Dumping duties by US and EC, China's exports to India accounted for a meagre 1.52% while those to EC and USA accounted for 75.93%. However, after these trade remedy measures, there was a tectonic shift in China's export markets. As of 2017, the USA and EC collectively account for only 10.7% of China's exports whereas India now accounts for 29.8%.
 - cc. There is no evidence on record to suggest that India had foreseen the contemporaneous levy of trade remedy measures on imports from China by the EU and US and therefore, these developments were unexpected. Further, India truly believed that the DCR under JNNSM was consistent with the exceptions contained in Article XX of GATT 1994. Therefore, India could not have expected at the time of incurring the obligations under ITA:1 that its DCR, which it believed to be consistent with Article XX of the GATT, would be considered as inconsistent with its obligations incurred under the treaties and agreements. Consequently, the Indian market for the PUC became open for unrestricted imports from all countries.
 - dd. Such a significant shift in pattern of trade in which China started targeting the Indian market more vigorously as compared to developed countries / markets like EU and USA etc. could not have been reasonably expected. The Domestic Industry was thus faced with completely new dynamics operating in the market. The Domestic Industry was further distressed on account of unprecedented and unforeseen capacity expansion undertaken by Chinese exporters, which was backed by state support in the form of incentives, subsidies and tariffs.
 - ee. Another unexpected development is that at the initial stages of the development of the Chinese solar industry, China used to import a lot of the raw material required to manufacture solar cells and modules, in particular, polysilicon. However, an unexpected turn of events fueled the growth of the Chinese polysilicon industry giving China a sharp competitive edge. In the early years, China did not have the extensive capital or technical expertise required to manufacture polysilicon. But when three Chinese companies viz. Suntech, Yingli and Canadian Solar went public on the New York Stock Exchange in 2005 and 2006, it spurred a massive solar manufacturing expansion. The demand for polysilicon soared and the spot price surged from less than \$50 per kilogram in 2004 to approximately \$475 per kilogram in 2008. Sensing a huge opportunity, the Chinese company GCL began to manufacture polysilicon and over the next decade grew phenomenally to become the world's largest polysilicon manufacturer. Trade wars between the US and China also worked out in the latter's favour. After the US imposed tariffs in 2012 on Chinese-made solar cells sold in the US, China imposed tariffs of its own on U.S.-made polysilicon sold in China, a move that created an advantage for companies that produce polysilicon in China. That advantage has proved decisive in the global market. China now produces over 90% of all the polysilicon in the world. This capacity to produce a critical raw material in the manufacture of solar goods, allows Chinese companies to export their products at a much lower price than any of their competitors. As indicated earlier, the Indian domestic industry is suffering major setbacks as a result of the aggressive pricing strategies of the Chinese solar companies.
 - ff. Apart from polysilicon, all manner of other materials required for the manufacture of solar cells and modules are made in China itself. Companies that were earlier engaged in other businesses, jumped on the solar bandwagon to meet the strong demand for solar materials and tooling. China's escalating manufacturing capacity offers ample market opportunities for existing regional suppliers, as well as newcomers. In addition to the benefits of low cost labour and economies of scale that China already enjoyed, the ability to produce raw materials and tooling domestically is among the most important reasons why solar goods made in China are so much cheaper than everywhere else. Thus, it is evident that the development of the Chinese polysilicon and solar tooling industry is a result of an unexpected and unintended turn of events which rendered it nearly impossible for countries like India to compete against China or even keep their own solar industry afloat.
 - gg. Another unexpected development is that the support to manufacturing extended by the Chinese government to its producers. In this regard, especially critical to the rapid growth of the Chinese solar manufacturing industry has been financial support from commercial and state-owned banks, municipal governments and

- investment corporations (*with municipal government backing*). This is in addition to a host of generous incentives offered to solar manufacturers including refund or exemption of land fee and tax (*corporate income tax, VAT and interest on loans*), refund of electricity consumption fees, refund of VAT and import fees for R&D equipment, various investment grants, loan guarantee etc.
- hh. In 2010 alone, the Chinese Development Bank (CDB) authorized an unprecedented \$30.41 billion in total credit facilities to five top domestic manufacturers: LDK Solar, Suntech Power, Yingli, JA Solar, and Trina. In fact between 2005 and 2013, the CDB extended nearly \$31.35 billion in credit facilities to China's major solar manufacturers. This is only about 70% of the total *publicly* disclosed credit made available to these companies during this period. So, Chinese solar manufacturers had a bank willing to lend them billions of dollars, at a time when the financial markets in much of the world had seized up. This is in complete contrast to the rest of the world where bank lending to finance solar and other renewable-energy projects had slowed considerably. This liquidity and almost unrestricted access to capital allowed the Chinese solar manufacturers to expand immensely giving them a strategic advantage over companies in other countries which were struggling to survive.
- ii. In 2016, when Yingli, China's largest solar manufacturer was in serious financial trouble, the China Banking Regulatory Commission, asked the CDB to "ensure" that Yingli receives \$1.16 billion in new loans. This debt helped Yingli pay off its existed debt, avoiding a potential default and also ramp up production in its factories to resuscitate the cash flow. A couple of years earlier, Suntech was also supported in a similar fashion. Suntech, the company that essentially launched China's solar boom, became, in March 2013, the first Chinese company to default on publicly traded debt. It subsequently filed for bankruptcy protection in both China and the United States. During this time, the Wuxi municipal government in Jiangsu province city where Suntech is located provided \$150 million to resurrect the company and subsequently also gave a five year exemption from revenue taxes. Even LDK received a variety of grants and subsidies in 2016 when some of its subsidiaries filed for bankruptcy. Bailing out large solar companies by way of cash injections and incentives in this manner is a uniquely Chinese phenomenon and has helped several companies maintain their position in the global market and is certainly an unexpected and unforeseen occurrence in the solar industry.
- jj. China's treatment of renewable energy development as a high national priority was also an unexpected development which spurred its exports and consequently, imports into India. In fact, renewable energy development is one of seven strategic industries the government supports as foundations of future economic growth. To this end, the Chinese government has introduced a number of programs and initiatives to help foster technological development in the field of solar energy. Of particular note here, is the fact that China lays a lot of emphasis on technology which can be quickly and efficiently commercialized.
- kk. The National High Tech R&D (863) program funds research that can be brought to the market within a year or two. China has established 2 State Key Labs (SKLs) and 3 State Engineering and Research Centres for solar research which too function in a similar manner, in close co-ordination with the government and large private solar companies on whose premises these labs are located. The research undertaken is applied in nature, focussing on iterating improvements in the easily marketable silicon-based technologies rather than any new emerging technology. This explains the string of improvements achieved in silicon cell efficiencies in the last few years in China.
- ll. This approach also extends to the securing of solar patents by Chinese companies. Patents that had a lower lapse rate were, generally, those for which there is a commercial market: polysilicon, monocrystalline-silicon, PERC, IBC, HIT, and multijunction (a technology in which the cell has multiple interfaces between p-type and n-type semiconductor material), in addition to amorphous-silicon and gallium-arsenide (*another thin-film technology*). That suggests that the Chinese research community values patents on near-term technologies more than on emerging ones. Such intense focus on marketable solar technologies has helped China remain ahead of its competitors in a very significant manner and could hardly have been foreseen by India, given the opacity in the functioning of the Chinese government.
- mm. Subsequent to these developments, Chinese exporters, armed with a fortified production capacity, found a new market in India for it to export its Solar Cells. The same started and continued on a massive scale, with imports increasing by over 643% over a period of 4 years. There has been a year-on-year growth in the imports of PUC from China increasing by 3.3 times during 2015-16 over the previous year, 1.52 times in 2016-17 and 1.48 times during 2017-18 over the respective preceding years.

- nn. In light of these sudden, sharp and drastic developments, the Domestic Industry has been faced with a situation where they are not able to sustain themselves against the imports. Neither the trade remedies that were adopted by USA and EC against China prompting it to focus its supply into India, nor those by USA against India, which lifted the protection of DCR offered to the domestic Industry were foreseen on 13.12.1996 i.e. the date on which India acceded to obligations under the WTO.
- oo. There is sufficient data to indicate that China has more than doubled its solar cell and module production capacity between the years 2012 to 2016. In the year 2012, China had 11.12 GW of Cells production which reached 27.78 GW in the year 2016. Similarly, the module assembly expanded from 12.46 GW in the year 2012 to 35.47 GW in the year 2016.
- pp. The data furnished by the petitioners demonstrates that China's capacity for producing subject goods is export oriented. It also demonstrates that China has significantly high excess capacities.
- qq. The ITC Trade Map data is self-explanatory in demonstrating the surge of imports inasmuch as while India accounted for only 1.52% of the exports from China in 2012, developed countries and territories such as USA and EU were the focus of around 76%, of exports. However, due to various trade measures resorted to by these countries and territories, there was a paradigm shift in the trend of exports. Whereas the exports to India in 2014 were only 3.97% of the total value of Chinese exports to the world, in a short span of 3 years, Chinese exports to India had overtaken that of its combined exports to that of EU and the US and amounted to nearly 30%, the highest amongst all countries that it exports to. Such a surge in exports from China, which far outstripped that to developed nations and territories such as the US and EU, was not foreseen by India at the time of incurring the obligations.
- rr. In another development that could not be foreseen, India assumed leadership in the fight against climate change. In 2015, India committed to lower the emissions intensity of its economy by 33%–35% of 2005 levels by 2030 and increase the share of non-fossil based power generation capacity to 40%. These developments which could not have been foreseen, require a greater commitment by India towards renewable energy, especially solar. The commitment towards climate change, which was also one of the reasons for the government increasing its solar installation targets, has pushed up the demand for solar power generation projects in India. The commitment given by India under the 2015 Paris Agreement that was signed by 197 countries (as on date ratified by 172 countries) was unforeseen at the time the import tariff concession for solar cells was agreed to under ITA-1 on 13th December, 1996.
- ss. Therefore, (i) rapid expansion in capacities, production and export orientation of China; (ii) imposition of trade remedy measures by major consumption market such as the EU and the USA; and (iii) commitments under the Paris Agreement which call for reduction by 33-35% of CO2 emissions (from 2005 levels) to address the global warming, were unforeseen by India on December 13, 1996.
- tt. Article XIX of the GATT requires that increase in imports should be as a result of the effect of obligations incurred by the Member under GATT 1994. The effect of the clause is that the investigating authority in the concerned importing member, seeking to resort to safeguard measures, must also demonstrate as to how the obligations incurred under the GATT 1994, including tariff concessions, prevented the competent authorities from taking WTO-consistent measures to address the surge in imports.
- uu. In the present context, increased importation of the subject goods in India is directly attributable to tariff concessions incurred by it as an effect of obligations and of not being able to address the surge in imports through WTO consistent measures. In this regard, two factors which are required to be taken note of are *firstly*, India provided a schedule of concession to the WTO and resolved to abide by the commitments under GATT. India subsequently amended those tariff concessions through the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products (ITA 1). India's import tariff on the subject goods falling under Customs Tariff Item 85414011 of the Customs Tariff Act, 1975 is 'Free'. This 'Free' tariff was introduced pursuant to the obligations on India under GATT 1994, including the tariff concessions thereunder read with the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products dated 13th December, 1996 ("ITA-1"). The subject goods are covered under Attachment A, Section 1 of the ITA-1. The ITA-1 mandated elimination of Customs duties and other duties / charges of any kind within the meaning of Article II:1(b) of GATT 1994 on the products listed therein. Therefore, since India is a signatory to ITA-1, the imports of PUC are free of Customs duties. Thus, ITA-1 binds India's "*freedom of action*"¹ with respect

¹ Panel Report, *Ukraine – Passenger Cars*, para. 7.96.

- to the imported subject goods and prevents it from taking other WTO-consistent measures, such as increasing the Customs duties. *Second*, the Domestic Industry initially had the assurance of a captive domestic market to the extent dictated by the Domestic Content Requirements (“DCR”) under JNNSM. However, in 2013, USA challenged the DCR under JNNSM before the WTO Dispute Settlement Body. India believed that the Domestic Content Requirements (“DCR”) under JNNSM were consistent with GATT on the ground that the exceptions contained in Article XX of GATT 1994 applied to such measures. However, the outcome of the dispute was that in October 2016, the WTO Appellate Body held the DCR to be inconsistent with Article III:4 of the GATT 1994 and Article 2.1 of the TRIMs Agreement. Hence, India had to withdraw the DCR. Therefore, India’s obligations under Article III:4 of the GATT 1994 and Article 2.1 of the TRIMs Agreement prevents India from addressing the current situation.
- vv. The exponential increase in imports over the years and data pertaining to sales volumes and domestic consumption clearly paint the picture of serious injury or at the very least an imminent threat of serious injury to the Domestic Industry. The data reflects that with increased demand the market share of imports also increased from 86% to 90%, further pushing down the market share of the domestic producers from 14% to a paltry 10%.
- ww. Price undercutting for both cells and modules increased substantially which subsequently led to the reduction of the selling price of the solar cells and modules. During the injury analysis period, prices declined cumulatively by 15.77%. Despite the cost going up because of inflation, the domestic producers could not raise their prices. Therefore, the Domestic Industry has not been able to make profits and invest in feasible research and development to put them at par with the imports both in terms of efficiency as well as quality.
- xx. The workers also faced unemployment because of this situation. Compared to the total installed capacity, there is a potential employment loss for about 2384 employees.
- yy. The Indian solar industry bore the brunt of low priced imports for many years. However, in recent times, these imports have sharply increased whereas the prices have decreased consistently which is demonstrated in detail hereinafter. It is an established proposition of law that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause ‘serious injury’, all of which are satisfied in the present case.
- zz. The Domestic Industry has made large investments to produce the subject goods looking at the robust demand of the product in India. However, the investments have been vulnerable to imports from various countries at very low prices. Therefore, the domestic industry pursued imposition of anti-dumping duties in the past. The Directorate of Anti-Dumping & Allied Duties (DGAD) had earlier recommended imposition of anti-dumping duties against exporters from China, Malaysia, Taiwan and USA. However, the Ministry of Finance, in the year 2014, decided not to levy the duty. The industry was looking at complete closure but for the introduction of DCR which provided a fresh lease of life to the domestic producers. The improvements are reflected in the intermediary years. The DCR ensured usage of Indian made solar cells in the projects which helped the domestic industry to realize some volume of the subject goods at a reasonable price.
- aaa. The WTO Appellate Body held the DCR to be inconsistent with Article III:4 of the GATT 1994 and Article 2.1 of the TRIMs Agreement. The exporters took advantage of the policy latency between 2014 to 2017 leading to the sudden and sharp surge in imports.
- bbb. The impact of removal of DCR is such that a surge in import is already apparent since the users are no longer bound to buy domestically produced solar cells. The deterioration in performance and the injury is reflected in many of the parameters and the threat of further injury is real and imminent. If no safeguard duty is imposed at this juncture, the upcoming quarters will reflect irreparable losses in terms of sales and price parameters. The Domestic Industry requires the protection of safeguards measures at the earliest to arrest such unfortunate and irreparable developments.
- ccc. China is the largest exporter of the subject good to India (share of more than 94% of imports). Exporters from China, Taiwan, Malaysia and other countries are facing significant hurdles in exporting the subject goods on account of various trade remedy measures (anti-dumping, anti-subsidy and safeguards measures) and local content requirements in markets with large consumption such as the EU, the USA, Egypt, Turkey and Russia. The outcome of safeguards investigation conducted by the United States has meant that the doors to the US for exports of Solar Cells are also closed. Therefore, should India remain an unprotected

- zone for the subject goods any longer, producers from countries like China will push for a further spike in exports which will inevitably lead to the end of the solar industry in India forever.
- ddd. The current situation requires immediate imposition of safeguard duties. While certain injury parameters such as losses have declined in the intermediate period when compared to the base year, such improvements were directly attributable to the DCR which was in force during that period. The benefits of DCR were visible on employment as well as on the ability of the industry to ensure reasonable payments to its employee. The price realization, which was higher while DCR was in force, is in jeopardy once again with the removal of DCR. This has already led to large scale retrenchment of employees and the indication is clear that employment generated by the domestic industry is under serious threat and will result in further loss of employment unless it is safeguarded against the onslaught of imports.
- eee. There was a significant increase of imports in absolute terms. The year on year increase was a substantial 228% in 2015-16 over the previous year. Thereafter, the increase in imports from 2015-16 to 2016-17 was also a substantial 52%. Finally, imports in 2017-18 increased by approximately 49% over 2016-17. Increase in imports was recent, sudden, sharp and significant. Furthermore, imports increased not only in absolute terms but also in relative terms i.e. in relation to production of the subject goods in India. The increase in imports was also reflected in terms of value which increased from Rs. 3,991.21 crores during 2014-15, import value increased to Rs. 21,701.38 crores during 2017-18 (Annualised). The increase in value was, however, not in proportion to the increase in volume of imports as import prices declined significantly during the same period as found by the DG Safeguards in its preliminary findings.
- fff. While the landed value of imports was around Rs.18.78 and 36.95 for cells and modules respectively during 2014-15, the same sharply declined to Rs. 23.03 during 2017-18 (annualized). This sharp increase in volumes coupled with an equally drastic reduction in value per watt had an extremely adverse effect on the prices of the like article in the Domestic Market and consequently, resulted in severe price suppression and depression whereby the Domestic Industry was prevented from selling the subject goods produced by it at a remunerative price. However, despite the Domestic industry selling the subject goods at below cost, the prices of imports continued to massively undercut the prices of the Domestic Industry which, in turn, prevented the Domestic Industry from producing and selling the subject goods to a reasonable extent of its installed capacity despite a colossal increase in the demand of the like article in the domestic market.
- ggg. As a result of the massive surge in imports at rock bottom prices, the Domestic Industry has not been able to sell the subject goods despite a massive increase in demand in the domestic market which is reflected in the market share of the Domestic Industry. while demand increased from 1476 MW in 2014-15 to 10,573 MW in 2017-18 (Annualised), market share of imports increased from 86% to 90% and consequently, the minuscule amount of market share that was initially held by the domestic producers as a whole at the beginning of the POI to the tune of 14% shrunk to 10% of the total domestic consumption in 2017-18.
- hhh. The Domestic Industry faced significant price undercutting from the imported goods throughout the POI. As a result thereof, price suppression and depression was also faced by the Domestic Industry which is palpable from the fact that its net sales realization kept on reducing and was also below the cost of sales throughout the period of investigation. Such significant price depression could not be attributed to any cause other than unprecedented increase in imports. The price depression was coupled with a significant price suppression as well. The domestic producers could not raise their prices even when the costs increased significantly. During 2015-16, costs increased by 9% per watt from that of the year immediately preceding it whereas the selling prices declined by 13% per watt, thereby leading to an increase in price suppression by 24% per watt. As a result of such price suppression and depression, the petitioners were prevented from increasing their prices to the break-even level and consequently suffered massive losses.
- iii. The data with respect to production and sales is reflective of the abysmal market share held by the domestic industry which when compared to the demand of the subject goods in the domestic market and the volume of imports.
- jjj. Production of the Domestic Industry increased from 237 MW in 2014-15 to 838 MW in 2017-18 (Annualized). In this regard, it is relevant to note that installed capacity of the Domestic Industry to produce the subject goods also increased by an additional 1,000 MW in 2017-18 (Annualized) as a result of one of the petitioners viz. Mundra Solar PV Limited commencing operations. However, despite the increase in installed capacity in 2017-18, the production of the Domestic Industry managed to increase by only 365 MW. Furthermore, while import volumes of the PUC increased by 643% i.e. from 1,275 MW in 2014-15

to 9,474 MW in 2017-18 (Annualized), the production of DI increased by only 254% during the same period i.e. from 237 MW to 838 MW.

- kkk. The data with respect to sales of the Domestic Industry reveals an even worse state of affairs inasmuch as despite the burgeoning demand of the subject goods which has facilitated such a tremendous increase in imports, the Domestic Industry was not even able to sell all of the subject goods produced by it. While sales increased from 191 MW to 774 MW (Annualized), it is to be noted that the Domestic Industry was only able to sell the subject goods by pricing them much lower than its cost of sales which consequently resulted in huge losses. Notwithstanding the fact that the Domestic industry was forced to sell the subject goods at unremunerative prices, as the imports continued to significantly undercut the prices of the Domestic Industry, it could not even sell all of the subject goods produced by it during the POI. This is also clearly reflected in the mounting inventories.
- III. The Ld. DG Safeguards correctly observed that increased imports of the subject goods have substituted the subject goods produced by the Domestic Industry while meeting the demand in the domestic market.
- mmm. The most revealing factor which demonstrates serious injury being suffered by the Domestic Industry is its capacity utilisation which stands at only 51% of its installed capacity. In a situation where the demand of the subject goods increased by 9097 MW, which is approximately 616% and more than sufficient to cater to the entire installed capacity of the Domestic Industry which stands at 1653 MW, there is absolutely no reason other than the surge in imports of the subject goods at rock bottom prices which has led to the drop in the capacity utilization of the Domestic Industry from 60% in the base year to 51% in 2017-18 (Annualized). In fact, despite the production capacity being further enhanced by 1,000 MW in 2017-18 (Annualized), only 35% of this additional capacity was actually utilized. Even otherwise, the production facilities of the Domestic Industry were grossly underutilized during the entire POI. Coupled with the increasing trend of imports of the PUC, this low level of capacity utilization clearly shows that there has been a significant overall impairment of the Domestic Industry and thus, it has suffered serious injury.
- nnn. Additionally, a number of other domestic producers of the like article were keeping their production facilities idle such as Surana Solar, Udhaya Energy, Maharishi Solar, Dev Solar, Bharat Electronic Ltd, Excel Energy, IYSERT Energy and K I Solar. Their production was either nil or insignificant. Euro Multivision and Premier Solar had no production at all during July-September 2017 (Q2 of 2017-18). Thus, there was significant underutilization of production facilities during the period under examination. Even when the plants were being operated, domestic producers were not able to run their plants continuously. It is submitted that these plant shut downs were only due to increased imports coming into India which stopped the Domestic Industry from selling the subject goods produced by it.
- ooo. The employment generated by the Domestic Industry also declined despite significant capacity addition. The commencement of operations of one of the petitioners viz. M/s. Mundra Solar PV Ltd. (MSPVL) in May 2017 contributed to the overall increase in the total number of employees in the industry as a whole but the DG Safeguards has correctly appreciated in the Preliminary Findings dated 05.01.2018 that the same is not reflective of the industry trend. If the employment of the Domestic Industry is viewed de hors the number of employees of MSPVL, the declining employment in the industry as a whole is evident. Further, as also correctly appreciated by the DG Safeguards in its Preliminary Findings, the Domestic Industry has been operating far below their installed capacity and as such, there has been a significant loss in potential employment opportunities. In fact, owing to its mounting losses and reducing capacity utilization, one of the petitioners viz. Indosolar, has had to lay off 250 employees in recent times.
- ppp. Though the Domestic Industry was able to maintain the wages paid to its employees at more or less the same level till 2016-17, as a result of the tremendous financial strain faced by the Domestic Industry due to mounting losses, the Domestic Industry was unable to maintain the wages at the same level any longer and therefore, the remuneration paid to its employees has also declined sharply.
- qqq. Even with the addition of a significant number of employees by the entrance of MSPVL into the Domestic Industry in May 2017, the productivity of the Domestic Industry continued to suffer. Per employee production was 0.316 MW during 2014-15 which further fell down to 0.291 MW in 2015-16. Though this figure rose slightly to 0.492 MW in 2016-17, it declined significantly in 2017-18 to a low 0.243 MW. Thus, productivity per employee has decreased throughout the POI, save for a slight increase in 2016-17 which did not last. The current situation indicates a downward trend that is likely to be aggravated even further in the near future unless an adequate safeguard duty is imposed to protect the Domestic Industry.

- rrr. The Domestic Industry has incurred significant losses on domestic sales over the course of the POI. Due to a significant decline in the net sales realization as a result of the price suppressing and depressing effects of cheap imports on the subject goods being produced by the Domestic Industry, its losses have compounded during 2017-18 as compared to 2014-15. In fact, the losses more than doubled during 2017-18 (Annualized) when compared to the year immediately preceding it i.e. 2016-17. When compared to the base year, i.e. 2014-15, the losses have quadrupled. Such increase in losses has to be seen in the light of contrasting parameters such as the increase in capacity, increase in production and increase in domestic sales. This in turn has also resulted in a negative return on capital employed. The Domestic Industry cannot sustain itself much longer and will have to shut down operations permanently if the influx of such cheap imports continues unabated.
- sss. The inventories held by the Domestic Industry increased by more than 4 times during the POI. The fact that domestic sales could not keep pace with the production of the Domestic Industry, which was paltry in itself considering its installed capacity and demand in the domestic market, is clearly demonstrated in the figures with respect to inventory which have shown a very sharp increase in 2017-18 from that of the base year. The factum of ever mounting inventories of the Domestic Industry in a domestic market having such a huge demand for the subject goods unerringly points towards the fact that the Domestic Industry is suffering serious injury.
- ttt. There is a overwhelming demand for the subject goods in India and there are no other known factors that may be contributing to the market disruption other than low priced imports in significant volumes from various sources.
- uuu. Causal Link is established as imports of subject goods increased from 1,275 MW in 2014-15 to 9,474 MW in 2017-18, an increase of over 643% over 3 years. Further, the imports increased by up to 3.3 times during 2015-16 and by 1.52 and 1.48 times during 2016-17 and 2017-18. The increase in import is therefore recent, sudden, sharp and significant. The market share of imports has increased from 86% to 90% and, consequently, market share of the DI has declined from 13% to 7%. The serious injury is not attributable to any factor other than the increased imports.
- vvv. Imports of the subject goods during each of the last two half yearly periods were significantly higher (2.7 times higher) than the imports during the first half of 2016-17. The import prices also came down to Rs. 23.04 per watt during first half of 2017-18, a decline of over 23%. As import prices declined, ability of the DI to get remunerative prices also declined. As a consequence, sales and capacity utilization also suffered.
- www. Imports cater to more than 90% of the demand and have adversely impact the investments made by the domestic industry. It is also evident that imports are causing market disruption in the Indian market. The abovesaid data makes it evident that the precarious state of the Domestic Industry has only worsened in 2017-18 and therefore, safeguard duties are essential for the existence of the solar industry in India.
- xxx. The petitioners have planned to reduce their cost to become cost-competitive with exporters from outside India by (i) Renegotiation with existing suppliers of raw materials as well as identifying new suppliers of raw materials with a view to reduce the cost of raw material by entering into long term bulk contracts as may be required; (ii) Taking up projects for backward integration by establishing plants for manufacture of wafers and ingots from the basic raw material. Backward integration would help realise larger economics of scale. This will, in turn, lead to a robust return. Such a return will enable multiple entrepreneurs to invest in wafer manufacturing facilities which accounts for a significant proportion of the cost of production of solar cells and modules. Some of the petitioners would also invest in ingot manufacturing facilities; (iii) Taking up projects for forward integration by establishing facilities for manufacturing modules by those who only have facilities for making cells; (iv) Taking up projects, wherever feasible, for technically superior products using PERC technology or Bi-facial technology; (v) Reduction of cost of conversion primarily by ramping up utilisation of capacity, which to an extent would be dependent upon favourable changes in the market due to imposition of protective measures such as safeguard duties (vi) Reduction of financing cost by converting Rupee borrowings into USD borrowings.
- yyy. The readjustment plan is to be considered in light of the certain macro-economic issues such as the fact that India has established a target of achieving 100 GW of solar power generation by the year 2022 and as such, the demand for the product is continuously increasing. The target is essential for achieving India's commitments under the Paris Agreement which calls for reduction by 33-35% of CO₂ emissions by the year 2022 (from 2005 levels). The petitioners support the initiatives and have made significant investments in installed capacity. However, the exporters, especially from China, Malaysia and Taiwan, intend to

annihilate the domestic industry in India. The safeguard duties will provide an incentive for continuous investment, capex expansion and reduction in cost by achieving the economies of scale.

- zzz. Imposition of safeguard duty is also in the larger public interest as (i) It will lead to an increase in employment, increase in capex expansion, increase in capacity utilization and will also promote investment in R&D; (ii) Increase in FDI flow and the exporters will be encouraged to invest and make in India. In fact, the initial recommendation of provisional safeguard duties resulted in additional capacity announcement by Longi, CETC and GCL in India; (iii) Suppliers of raw materials and consumable (such as wafer, paste, EVA, junction box, glass, etc.) will be encouraged to establish new units; (iv) Every 1 GW of cell + module production provides direct employment to approx. 3000 people. The petitioners estimate that such production also generates indirect employment to the tune of 3.5x (i.e. 10,500 people) on account of supply chain and logistics; (v) Every 1 GW of cell + module production requires an investment of approx. INR 2,000 Crores of which 30% is met with equity infusion and 70% is met with debt. The debt is serviced at the average 9-10% cost of borrowing / interest rate (the rates would vary from producer to producer based on credit worthiness). With a marginal return and frequent upgradation in technology, it could take a longer duration for the producers to recoup the investment; (vi) The industry is subject to frequent technology upgradation which could be in form of efficiency (for instance - increasing the busbars in a cell) or upgradation from one generation to another (for instance – on account of change in material or fundamental architecture of solar cells). In other words, the cost of upgradation could be a huge drain on producers. Therefore, large amounts are continuously invested in Research and Development; (vii) The backward integration (such as a wafer production facility) could require equal amount of investment. However, the scale of economies can only be achieved from backward integration. Such integration develops the ecosystems of suppliers and create large scale employment and economic activity; (viii) The imports which currently account for above 90% of the total domestic consumption in India are a huge drain on the foreign exchange reserves and responsible for increase in current account deficit. The forex outflow by 2020 on account of imported products is expected to be approximately 60% of the budget allocated by the GOI for MNREGA for the FY 2017-18; (ix) even with 70% ad valorem duty as recommended in the preliminary findings, the increase in power tariffs is going to be negligible which is only short term since the petitioners will be competitive with the temporary protection. The increased government revenue from indigenization could also be used to compensate DISCOMs for any increase in power tariff. Therefore, any arguments which may be raised by developers regarding increased power tariffs will not only be baseless but also disingenuous; (x) a substantial portion of the amount is remitted abroad on account of imported solar cells and modules. Such transactions only promote middleman without any real economic benefit to India. The only tangible economic benefits are those occurring in exporting countries especially China, Malaysia and Taiwan; (xi) With imposition of SGD, petitioners will have even chance of retaining that amount, attempting backward integration, achieving economies of scale and putting it to use for real economic activity. Petitioners have demonstrated that they are capable of producing world-class products meeting all technical requirements; (xii) Further, any argument regarding employment generation by developers will also be baseless because the employment for installation, operation and maintenance of the facility is origin neutral. In other words, same employment will be generated even if goods produced by the petitioners is used in the installation, operation and maintenance of solar power projects (xiii) A task force has also been formed by CII under the directive of PMO for a road map for enhanced local manufacturing targeting 50GW local capacity; (xiv) Bank liabilities of the Indian manufacturers will be streamlined and relieve pressure of NPA on Banks. A vibrant solar supply chain will fuel growth in multiple other industries (Ecosystem) and creating over 1.20 million jobs.
- aaaa. Non-levy of safeguard duty would be against the public interest of India because (i) Local manufacturing will cease to exist and Rs. 11,000 Crores investment will become insolvent and result in mass unemployment (ii) Addition of Capacity announced by Overseas manufacturers will never be realized and will be halted; (iii) BHEL had recently invested in a 100 MW line which will be idled if safeguard duty is not levied; (iv) CEL EOI for setting up Module and/or Cell and further expanding to Wafering will also fail to attract any bids (v) The already existing skewed import dependence of Government of India will continue to inflate exponentially as India is already China's top export destination and our imports have increased by 20% Year-on-year to US\$ 4.1 billion in FY 2017-18.
- bbbb. The underlying objective of imposing Safeguard duties is to protect the domestic industries in the face of a global shift towards trade liberalization where goods compete in the global market. Comparative

advantages are exploited by states in order to ensure maximum benefit can be reaped of the open trading system. Safeguard duties, which are interim measures, provide for the domestic industries to calibrate their position in their industry on being faced with international competition. Accordingly, a safeguard duty is not merely a protectionist measure in the garb of a fair-trade remedy but rather, demands that a domestic industry come up with an adjustment plan that necessitates governmental support in the form of the adequate duties that not only allows the Domestic Industry to recover its actual cost of production as it stands during the current period but also, such a protective environment that the industry may be allowed to implement its adjustment plan for the purpose of becoming more cost effective and competitive. In this regard, the Appellate Body has also underscored the importance of the adjustment plan in the Safeguard process in Korea-Dairy.

- cccc. 95% Safeguard duty should be imposed for four years, to curtail the impact of the damage that happened in the past few years and allow the Domestic Industry to recover its cost as well as implement its adjustment plan to bring it at par with the producers in other countries. Furthermore, the duty should be liberalized keeping in view the adjustment plan of the Domestic Industry.

16. The brief summary of the rejoinders filed by the interested parties to the written submissions of other interested parties are as under:

(i) Domestic Industry

- a. The Ld. DG Safeguards has clarified that the scope of the PUC is 'Solar Cells, whether or not assembled in Modules or Panels'.
- b. The product scope includes both solar cells that use Crystalline Silicon (c-Si) Technology as well as modules or panel that use Thin Film technology.
- c. Respondents have objected to considering solar cells using thin film technology as like article as they contend that production technology, manufacturing process, raw material and difference in balance of systems (BOS) renders them different. However, respondents have not disputed the fact that thin film solar cells are used for generation of electricity using photovoltaic process as well. Though respondents have claimed that thin film solar cells may not be preferred by users for certain applications, it has not been denied that thin film solar cells and c-Si type solar cells are interchangeable on this aspect. Solar power projects do not specify whether c-Si type solar cells or thin film solar cells are to be provided by the developer bidding for the project and it is admitted that the discretion vests with the developer in choosing to employ either technology.
- d. The respondents have sought to introduce a new concept by stating that thin film solar cells and c-Si solar cells are not interchangeable or directly competitive but rather, 'alternative' products. However, the word 'alternative' is synonymous with the words 'substitute' and 'replacement'. Therefore, this argument of the respondents is self-defeating. Respondents themselves have conceded that developers can choose between either c-Si solar cells or thin film solar cells while implementing a project.
- e. Any distinction on production process is not relevant while deciding the scope of 'like article' as held by the WTO Appellate Body in US – Safeguard Measures on Imports of Fresh, Chilled or Frozen Lamb Meat from New Zealand and Australia wherein it was held *the focus must be on the identification of the products and their "like or directly competitive" relationship and not on the processes by which those products are produced.*
- f. Difference in production technology, manufacturing process and raw materials used are of no consequence and the only relevant factor is whether the articles are directly competing with each other. The process starts with the identification of the product under investigation or (PUC). For c-Si technology products imported, domestically produced c-Si technology cells would be like article. For thin film technology products imported into India, domestically produced c-Si technology products would be the 'directly competitive' articles.
- g. When it is not disputed that both types of cells are used for the generation of electricity from solar energy, any attempt at drawing a distinction between c-Si technology products and thin film technology products based on their manufacturing process or the material used therein would result in defining not the "like or directly competitive product" but rather, a *portion* of such like or directly competitive products. Such an

approach is inconsistent with the Safeguard Agreement as held by the WTO Panel's observation in the dispute of Dominican Republic – Safeguard Measures.

- h. Respondents claimed that inclusion and/or exclusion of thin films from product under consideration should be made on a case-by-case determination. The Designated Authority and Canada had considered thin films within the scope of product under consideration. Facts surrounding the present case make it essential to include thin films in the scope of product under investigation as otherwise, the entire exercise may lead to circumvention of safeguard duties since the importers may simply switch to thin films to avoid duties. "Thin Film Modules" are also imported under the same heading and are exempt from basic customs duty like solar cells/modules.
- i. In the earlier finding, the Designated Authority concluded that different technologies do not make end products different. Notwithstanding the fact that the Designated Authority was aware that solar cells made of crystalline and thin film technology differed in terms of (a) technology (b) usage of basic raw materials (c) production process (d) plant and machinery (e) Balance of System and (f) efficiency levels, it considered thin film solar cells to be within the scope of the product under consideration because it was of the opinion that difference in technology does not alter or impede the end uses of solar panels.
- j. The Designated Authority noted that both C-si solar cells as well as thin film solar cells were semiconductor p-n junction diodes which convert light into electricity. Solar Cells made from both these technologies were being offered in module/panel form to the ultimate end user and that the cost/pricing was also being decided based on factors such as Watt per unit, efficiency of the cell/modules and competition in market parlance between C- si and thin film products were generally based on such factors under both technologies. Furthermore, Solar Cells of both technologies were also classified under the common customs classification and tariff heading i.e. 8541 40 11. Finally, the Ld. Designated Authority observed that the most important fact which warranted the inclusion of thin film solar cells was the fact that there was direct competition between the products using both technologies as they could both produce power out of solar light and developers could choose either of the technologies for their power projects in the inception stage and thereafter, simultaneously in independent lines. Imposition of antidumping duty on the product of one technology, which is functionally substitutable with the product of another technology would be futile, as the product having no duty can replace the other in the market.
- k. Respondents emphasized that BOS utilized in c-Si solar cells and thin film solar cells are different and contended that since the BOS is different in both cases and as its cost is significant, thin film solar cells and c-Si solar cells are not like article. However, respondents have not denied that while initiating a project, a developer may use solar cells of both technologies interchangeably. The respondents have only contended that it would not be feasible for solar cells using either technology to be used interchangeably post the implementation phase.
- l. Non-compatibility of parts of the like article due to its own unique design which limits the choice of the user post purchase does not render an article different e.g. if cellular phones of different brands are dumped into the territory of India and each brand uses their own proprietary charger which limits the choice of the user to such proprietary charger post purchase, this difference would not render cellular phones of different brands as not like article.
- m. In fact, even in the earlier Final Findings on dumping of solar cells, the Ld. Designated Authority had noted that c-Si Solar Cells and Thin Film solar cells differed on the count of BOS. However, the Ld. Designated Authority considered the same to be like article.
- n. The Ld. Designated Authority had concluded that thin film should be included within the scope of like article by observing that under the market conditions prevailing in India wherein consumers perceived both products as similar and found them to be perfectly substitutable, exclusion of one product would open up backdoor entries to the other type nullifying the purpose of the entire exercise. Therefore, thin film cannot be excluded as otherwise, users will simply switch over to thin film technology nullifying the purpose of the entire exercise.
- o. Respondents have contended that the earlier final findings in the AD Investigation on solar cells had not attained finality as the duty was not imposed by the Central Government. However, this contention proceeds on an erroneous premise that determination with respect to injury, causal link and dumping made by the Designated Authority in a Final Findings are merely recommendatory. Rather, Rule 17 clearly indicates that only the quantum of duty specified under Rule 17(1)(b) is recommendatory whereas every other determination made under Rule 17 is final and not open to further review by the Central Government.

The objective determinations made by the Ld. Designated Authority are conclusive of the issues therein. The Central Government is only vested with the subjective discretion to levy the duty based on the quantum recommended by the Designated Authority. The fact that findings of the Designated Authority are not open for further review by the Central Government was also observed by the Hon'ble High Court of Gujarat in the case of *Alembic v. Union of India* [2012 (291) ELT 327]. Therefore, there is no embargo in considering the reasoning of the Ld. Designated Authority in the earlier final findings on solar cells.

- p. It is preferable to adopt the reasoning of the Ld. Designated Authority in the earlier Final Findings as determination of the PUC in an earlier investigation in the Indian context would be more relevant than a determination made by the US and the EU in their own peculiar facts and circumstances. There is no consensus internationally on whether thin film solar cells are to be considered as like article with c-Si based solar cells. Each investigating authority has taken a stand on its inclusion/exclusion based on the facts of their own case e.g. Canada also included thin films into the scope of the product under consideration.
- q. Respondents have submitted that Solar cells using the "PERC" (Passivated Emitter Rear Cell) based technology, Bi-facial N-type solar cells, High efficiency solar cells using 5 and 6 bus bar production technology and Solar modules of mono crystalline technology are not being manufactured by the Domestic Industry. However, the said contention is without any basis as proof of production of all the aforesaid cells have been provided during verification.
- r. According to the respondents, an SEZ unit is set up with the objective of generation of additional economic activity, promotion of exports, creation of employment opportunities and increasing investment in India (Section 5 of SEZ Act) and the Government grants several concessions to encourage and enable them to export. The facility for sale in the domestic market or Domestic Tariff Area (DTA) is only a liberty given to such units for the reason that such units may at times, face difficulties in finding steady export markets for their products, and to allow them to achieve continuity in their production. The respondents have further contended that when sale in the domestic market is allowed merely as a liberty, it cannot be treated as a matter of right by such units so as to entitle them to seek protection as domestic industry. However, this contention is without merit as respondents have themselves admitted that SEZ units are set up with the objective of generation of additional economic activity, creation of employment opportunities and increasing investment in India. Therefore, when the effect of it is to benefit economic activity, create investment and employment in India, the fact that they are deemed to be outside the customs territory of India pursuant to a legal fiction is of no consequence.
- s. Reliance by Taiwan Photovoltaic Industry Association (TPVIA) on the non-obstante clause at Section 51 of SEZ Act stating that it would prevail over all other legislation is of no consequence as it is a fundamental principal of law that it would come into operation only when there is a conflict between provisions of the SEZ Act and any other legislation. However, TPVIA has failed to point any inconsistency between the SEZ Act and Section 8B of the Customs Tariff Act 1975.
- t. The determination of whether any unit producing the PUC can be considered as a domestic producer of the subject goods is also to be performed on a case by case basis. Although in the ordinary course, SEZ clearances to the DTA attract customs duties, since India has reduced its customs duties to 'nil' for the PUC pursuant to being a signatory to ITA:1, DTA clearances for the PUC by the petitioners based in the SEZ do not attract any customs duties. Furthermore, with respect to SEZ clearances being a 'liberty' granted by the Government of India, there is an obligation for units based in an SEZ to maintain positive Net Foreign Exchange (NFE). However, in the case of units based in the SEZ manufacturing the PUC, this obligation to achieve positive NFE can be discharged by way of DTA clearances in view of Sub-rules (a) to (o) in Rule 53 which list certain items whose clearance into the DTA shall be count towards the Free on Board (FOB) value of exports for the purpose of calculating whether the unit has achieved positive NFE. Therefore, SEZ Units can sell the PUC in the DTA without any compulsion to export. There is no embargo and in fact there is a specific provision which facilitates the sales in DTA by such SEZ units. Such DTA sales by the SEZ units compete in the domestic market with other manufacturers based in the DTA. It has also been clarified that safeguard duties are not leviable on DTA clearances by an SEZ unit. Therefore, SEZ units are also domestic producers.
- u. The ratio laid down in *Unwrought Aluminium and Electrical Insulators* is bad law, being in derogation of the judgment of the judgments of the Hon'ble High Courts in *Essar Steel v. Union of India* [2010 GLH (1) 52], *India Exports v. State of U.P. & Ors* [(2012) 47 VST 126], *Tirupathi Udyog Limited rep. by its Manager-Administration Shri D.V. Saradhy v. Union of India (UOI) through the Secretary, Ministry of*

Finance and Ors. [2011 (272) ELT 209(A.P.)] wherein it has categorically been held that DTA clearances from SEZs are not imports. Therefore, if sale by SEZ units into DTA are not imports and subject goods manufactured by SEZs compete in the domestic market without any restriction on the clearance thereof into the DTA, there is no reason why the DTA units cannot be treated as domestic producers of the subject goods.

- v. The reasoning of Ld. DG Safeguards in Final Findings in Safeguard Investigation concerning imports of “Saturated Fatty Alcohols” into India wherein it was held that even a 100% EOU is a domestic producer is squarely applicable to the facts and circumstances of the present investigation. Just as there is no restriction on sales of goods in the DTA by an EOU, similarly there is no restriction on sale of goods from an SEZ to a DTA either. The Ld. DG Safeguards had held that although DTA sales by an EOU are an exception, a domestic producer availing such an exception consistently was liable to be considered as Domestic Industry. In the present case also, the petitioners based in the SEZ units have been making DTA sales consistently. Furthermore, quantity of PUC sold in the DTA by the domestic producers based in the SEZ constitutes an overwhelming portion of the total production and sales of Indian producers and therefore, such producers have the right to seek protection.
- w. In the case of Unwrought Aluminium, the Ld. DG Safeguards had relied upon the fact that sales from the DTA to an SEZ are considered as exports under the SEZ Act, 2005. However, SEZ clearances to the DTA are not counted as either ‘exports’ from the SEZ or ‘imports’ into India. Therefore, the provision of law relied upon by the Ld. DG Safeguards has no relevance as far as treatment of SEZ units within the scope of Domestic Industry is concerned. The fact that an SEZ is outside the customs territory of India is also of no relevance as the Ld. DG Safeguards failed to notice the judgment by the Hon’ble High Courts in *Essar Steel v. Union of India* (Supra), *India Exports v. State of U.P. & Ors* (Supra) and *Tirupathi Udyog Limited* (Supra) wherein it was held that SEZ units are very much within the territory of India and they are only deemed to be outside the customs territory of India by a legal fiction. In *Tirupathi Udyog* (Supra), the High Court held that SEZ units have to be considered as units in India as otherwise, they would not be subject to Indian laws and regulations and the SEZ Act, 2005 in itself would be inapplicable to it which would render the same an absurdity.
- x. In unwrought aluminium, the Ld. DG Safeguards observed that SEZ units considered to be domestic producers in anti-dumping investigations are not relevant and the same are not applicable on safeguard investigations without any discussion on the reasons for such differential treatment under the two laws. There is no prescription either in anti-dumping or safeguard provisions with respect to treatment of EOUs and SEZ units as domestic producers. Therefore, while choosing not to consider SEZ units as domestic producers notwithstanding the fact that SEZ units are considered to be domestic producers in anti-dumping investigations, it was incumbent to furnish reasons for the same. The reasons that weighed with the Designated Authority while considering an SEZ unit as a domestic producer in the earlier anti-dumping investigation are squarely applicable to the facts and circumstances of the present safeguard investigation also.
- y. While observing that SEZ Units cannot be considered as domestic producers of a like article in Unwrought Aluminium, the Ld. DG Safeguards (i) failed to note the aforesaid judgments of the Hon’ble High Courts wherein it was specifically held that DTA sales by an SEZ unit are not imports into India or exports by the SEZ and that SEZ units are very much inside the territory of India; (ii) failed to distinguish how SEZ units are domestic producers within the ambit of anti-dumping laws but not safeguard laws; and (iii) also failed to distinguish how the tests applied for considering a 100% EOU as a domestic producer cannot be applied for determining whether an SEZ unit can also be considered to be a domestic producer. the Ld. DG Safeguards also failed to consider the law laid down by the High Courts and did not provide reasons for the difference between SEZ units being considered as domestic producers for anti-dumping laws and not safeguard laws as well as non-applicability of the tests for considering a 100% EOU as a domestic producer on SEZ units. therefore, the aforesaid finding of the Ld. DG Safeguards in the case of Unwrought Aluminium is both per incuriam and sub silentio and as such, not binding on the Ld. DG Safeguards. As held by the Hon’ble Supreme Court in the case of *State of U.P. & Anr. v. Synthetics and Chemicals Ltd. & Anr.* [(1991) 4 SCC 139], a decision on an issue which is per incuriam and sub-silentio is not a binding precedent and can be discarded from consideration when deciding a subsequent case
- z. The respondents have raised a contention that the petitioners do not account for a major share of the production of the subject goods based on MNRE data as total installed capacity of cells and modules in

India is 11562 MW whereas the total installed capacity of the petitioners is only 3164 MW. However, this contention is based on an incorrect premise and understanding of safeguard law as the relevant factor for determination of standing of the Domestic Industry is not installed capacity of the domestic producers in India but rather, actual production of the subject goods.

- aa. Respondents have contended that since solar modules have been considered as like article, therefore, solar modules produced from imported solar cells should also be taken into consideration for the purpose of calculating total production and in the alternative, the standing of Domestic Industry be examined by considering domestic production of solar cells and solar modules separately. However, these submissions are baseless as product under consideration is solar cells and therefore, imported solar cells can never account for domestic production of like article as the fact that they are assembled into modules by module manufacturers does not change them from an imported solar cell into a domestically produced one. Solar modules produced from domestically produced solar cells cannot be taken into consideration for the purpose of calculating total domestic production of the subject goods either as this would result in double counting of the total production of the like article because domestically produced solar cells will first be accounted for at the time of production by the Solar Cell manufacturers and thereafter, again be counted at the time of arrangement into modules by the domestic module manufacturers. This would lead to counting the same solar cell twice for calculating total output of the PUC in India and is therefore, impermissible.
- bb. Even if imported solar cells which are subsequently arranged into modules are considered for the purpose of computing the total production of the PUC in India, petitioners would still constitute a major proportion of the total production of the like article. However, no data has been provided by any of the interested parties regarding the quantum of production of solar modules from imported cells in India.
- cc. With respect to request by respondents to exclude Mundra Solar PV limited from Domestic Industry as it is still in its initial stages, safeguard law does not disqualify or distinguish between domestic producers based on the duration of their operations. Furthermore, as Mundra has produced the PUC and sold it in the Domestic Market, the allegation that it is not competing in the domestic market of the PUC is entirely baseless. Though Mundra has commenced operations recently, it is unable to sell the subject goods in the domestic market due to presence of cheap imports and therefore, facing serious injury along with other domestic producers.
- dd. Dome respondents have contended that increase in imports was not sharp or sudden so as to satisfy the requirements under Article XIX of GATT and that imports have kept pace with the demand and therefore, increase was gradual. In this regard, the Ld. DG Safeguards arrived at a finding in the Preliminary Findings dated 05.01.2018 that in the time period immediately preceding the initiation of the investigation i.e. during the first six months of 2017-18, there had been a sudden and massive surge in import volumes which was equivalent to approximately 74% of the imports in 2016-17. Therefore, there was an absolute increase in imports which was recent, sudden, sharp and significant by any standard.
- ee. Increase in imports required for meeting the requirements of Article XIX can be both with respect to absolute increase in the quantum of imports as well as in relation to domestic production and consumption. There has been a massive increase in imports in relation to Indian production of the subject goods. Furthermore, imports in relation to consumption in India has also increased notwithstanding the addition of capacity by the petitioners and commencement of sales of the subject goods by other Indian producers.
- ff. Revised target under the JNNSM created a sudden huge demand of the PUC in India and coupled with the removal of the DCR, this was followed by an equally sudden and massive surge in the volume of imports of the PUC into India. The surge in imports was not only because of the huge demand of the PUC that was suddenly created in 2015 but was also due to the fact that these imports were being made at extremely cheap prices. Therefore, such a massive surge of cheap imports has seriously injured the Domestic Industry threatening its very existence.
- gg. Certain interested parties have contended that unforeseen developments cannot relate to the remote past. The said assertion has been made without averring to the necessary facts and details required to substantiate it as the interested parties have failed to demonstrate which unforeseen developments were in the 'distant' past and how, in light of the timeline to which such unforeseen developments pertain to, such unforeseen developments can be said to be in the 'distant' past.
- hh. The first Anti-dumping and Countervailing duty orders in the USA with respect to Crystalline Silicon Photovoltaic (CSPV 1) became effective on 07.12.2012 and the duty pursuant to the second investigation on Crystalline Silicon Photovoltaic (CSPV 2) became effective on 18.02.2015. In the EU, the provisional

measure with respect to the same subject goods came into effect on 05.06.2013 and the final measure was imposed on 05.12.2013. The timelines of the measures imposed by the US and the EU more or less coincided with each other with minimal or no variance. The imposition of these measures did not result in an immediate surge in imports because of the Domestic Content Requirements (DCR) under the JNNSM. However, shortly thereafter the JNNSM was held by the WTO to be inconsistent with the obligations incurred by India under Article III:4 of the GATT 1994 and Article 2.1 of the TRIMs Agreement in 2016. These unforeseen developments directly led to the surge in imports and coincided with the surge and therefore, can hardly be said to be in the past.

- ii. The understanding of certain interested parties that unforeseen developments which are referred to as responsible for the surge in imports should be a result of the effect of an obligation under the GATT or the multilateral agreements is wrong as the language of Article XIX of the GATT does not state or indicate this in any manner. Rather, what it envisages is that the surge in imports should have been a result of both unforeseen development as well as an effect of obligations incurred under the GATT. The words 'as a result of' in Article XIX of GATT precedes the condition of both 'unforeseen developments' and 'effect of obligations' and does not connect the two. Rather, it is important to note that the words 'unforeseen developments' and 'effect of obligations' are connected in the sentence with the word 'and' between them. It is a settled principle of law that words in a statute have to be given their ordinary meaning unless it results in an absurdity or a different intention appears from the context of the statute. It is pertinent to note that 'and' is synonymous with the words 'along with', 'as well as', 'in addition to', 'including', 'also' etc. and is used as a conjunction to connect words of clauses or sentences. However, the interested parties have sought to replace the words 'and' with 'due to' and thereby, read the conditions in Article XIX as "*as a result of unforeseen developments due to the effect of obligations*". Such a construction of Article XIX is not tenable as it is impermissible to add or read words into the statute which have not been provided by the drafters thereof, either expressly or through necessary implication. The condition of unforeseen developments is in addition to the effect of obligations under GATT. Therefore, as long as there is a surge in imports and it can be shown that the cause thereof is a result of the existence of both these conditions i.e. effect of obligations and unforeseen developments, the requirements of Article XIX are fulfilled.
- jj. Respondents have also contended that developments that led to imports must have been unforeseeable and it must be explained why they were unforeseeable. However, the understanding of the respondents is hinged on the erroneous premise that 'unforeseen developments' should have been 'unforeseeable' as the test to be applied for the purpose of determining whether any event was an unforeseen development is whether the same was 'expected' at the time of incurring the obligations. The Appellate Body, in *Argentina Footwear*, held that the test to be applied is not whether the developments were unforeseeable. Rather, the test is whether the same were unexpected at the time of incurring the obligations, i.e. accession to WTO, resolving to abide by the commitments under various WTO Agreements, providing tariff concessions and subsequently amending those tariff concessions (*through the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products (ITA 1) in the context of the present case*). In other words, the developments which led to *Solar Cells* being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause serious injury to domestic producers should have been unforeseen or unexpected on December 13, 1996 – the date on which the Ministers agreed on ITA 1.
- kk. Before the imposition of trade measures by the EC and the US, China's exports to these territories accounted for 75.93% of its total exports whereas India accounted for a meagre 1.52%. However, after imposition of these measures, the USA and EU collectively accounted for only 10.7% of China's exports whereas India now accounts for 29.8%, signaling a tectonic shift in China's export pattern. Therefore, unforeseen developments indeed modified the conditions of competition between the PUC being imported and that produced by the Domestic Industry in India. Such a significant shift in pattern of trade in which China started targeting the Indian market more vigorously as compared to developed countries / markets like EU and USA etc. could not have been reasonably expected. Furthermore, the unprecedented and unforeseen capacity expansion undertaken by Chinese exporters (not only within China but also in South East Asia), which was backed by state support in the form of incentives, subsidies and tariffs was also not expected by India at the time of incurring its obligations.
- ll. There is no evidence on record to suggest that India had expected the contemporaneous levy of trade remedy measures on imports from China by the EU, US and Canada at the time of incurring the obligation under ITA:1. Furthermore, India truly believed that the DCR under JNNSM was consistent with the

exceptions contained in Article XX of GATT 1994. Therefore, India could not have expected at the time of incurring the obligations under ITA:1 that its DCR, which it believed to be consistent with Article XX of the GATT, would be declared as inconsistent with its obligations under the GATT.

- mm. Neither the trade remedies that were adopted by USA and EC against China prompting it to focus its supply into India, nor those by USA against India, which lifted the protection of DCR offered to the domestic Industry were foreseen 18 long years before 13.12.1996 i.e. the date on which India incurred obligations under the GATT. It is evident that the foregoing events were not expected and India could not have reasonably foreseen the same to be a result of the culmination of events in the usual course of transaction between nations.
- nn. The fact that India would assume leadership in the fight against climate change by committing to lower emissions by 33%–35% of 2005 levels by 2030 and increase the share of non-fossil based power generation capacity to 40% were also not foreseen. The commitment given by India under the 2015 Paris Agreement that was signed by 197 countries (as on date ratified by 172 countries) was unforeseen at the time the import tariff concession for solar cells was agreed to under ITA-1 on 13th December, 1996. One of the respondents viz. ACME has itself admitted that demand for solar panels/modules increased and became huge pursuant to India increasing its target to 100GW. The fact that India would set up such an ambitious target and the fact that the DCR, which mandatorily required domestic content, would be removed was definitely unexpected by India at the time of incurring the obligations under ITA:1.
- oo. It cannot be denied that all of the unforeseen developments which occurred simultaneously and coincided in the same time period i.e. the contemporaneous imposition of trade remedy measures by multiple countries, the shift in China's trade export pattern as a result of these measures and the removal of the DCR at a point of time immediately thereafter which meant that domestically produced subject goods were no longer mandatorily required, were not expected by India at the time of signing ITA:1.
- pp. Certain parties have raised an objection stating that the effect of obligations of India under ITA:1 has no nexus with the surge in imports in 2015 as both events are disconnected in time. However, the respondents have failed to appreciate the words used in Article XIX which provide on the face of the record that effect of obligations would include tariff concessions. India provided a schedule of concession to the WTO and resolved to abide by these commitments under GATT. India and certain other member countries of the WTO subsequently modified this schedule of concessions through the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products (ITA 1). India's import tariff on the subject goods falling under Customs Tariff Item 85414011 of the Customs Tariff Act, 1975 is 'Free'. This 'Free' tariff was introduced pursuant to the obligations on India under GATT 1994, including the tariff concessions thereunder which were modified pursuant to the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products dated 13th December, 1996 ("ITA-1"). The subject goods are covered under Attachment A, Section 1 of the ITA-1. The ITA-1 mandated elimination of Customs duties and other duties / charges of any kind within the meaning of Article II:1(b) of GATT 1994 on the products listed therein. Therefore, due to the effect of India's obligations under ITA:1, India had to eliminate custom duties on the PUC which facilitated the surge in imports which would not have happened to the present extent had the same been subject to customs duties. Furthermore, ITA-1 also bounds India's "*freedom of action*"² with respect to the imported PUC and prevented it from increasing Customs duties to contain the surge in imports.
- qq. Unlike unforeseen developments which must coincide with the increase in imports, there is no requirement that obligations incurred under GATT must also coincide with the increase in imports.
- rr. Another instance of the effect of obligations which resulted in the surge in imports of the PUC was those incurred by India under Article III:4 of the GATT 1994 and Article 2.1 of the TRIMs Agreement. The Domestic Industry initially had the assurance of a captive domestic market to the extent dictated by the Domestic Content Requirements ("DCR") under JNNSM. However, the same was held by the WTO Appellate Body to be inconsistent with India's obligations under the aforesaid provisions pursuant to USA's challenge to the DCR. Therefore, India's obligations under the GATT prevented it from maintaining measures which necessitated domestic procurement and checked the influx of imports. The removal of the DCR pursuant to the WTO Appellate Body ruling meant that India had to withdraw the DCR and therefore,

² Panel Report, *Ukraine – Passenger Cars*, para. 7.96.

- India's obligations under the GATT which prevented it from maintaining the DCR which then led to the surge in imports.
- ss. Certain respondents claimed that the Domestic industry producing the subject goods have not faced any serious injury as the installed capacity of the Domestic Industry is not sufficient to meet the demand of the subject goods in India and that due to insufficient capacity to service the demand of the subject goods in India, imports were necessitated and therefore, no serious injury could have been caused to the Domestic Industry. The said contention is without merit as the very reason for the petitioners inability to ramp up capacity is due to presence of cheap imports which are stopping the Domestic Industry from producing and selling the subject goods to the extent of its current capacity. When the Domestic Industry is not able to produce or sell the subject goods to the extent of its current capacity and when the capacity utilisation is reducing year on year despite the huge demand, it is impracticable for the petitioners to add more capacity as that would increase fixed costs even more. Since the subject goods produced and sold by it are at extremely low prices, the fact that it cannot get remunerative prices for the subject goods produced by it acts also acts as a deterrent to add more capacity.
- tt. Due to selling the subject goods produced by it at unremunerative prices, the Domestic industry has suffered huge losses which has also made it difficult for it to raise capital for further investments. In fact, it is relevant to point out that Indosolar was in the process of adding another production line for manufacturing cells (doubling the capacity of Indosolar) and Mundra Solar PV Limited was also in the process of increasing the capacity from 1.2 GW to 3.0 GW (increase of 150%). However, being unable to sell the subject goods produced by it in the domestic market any longer due to influx of much cheaper imports, all expansion plans have been put on hold and in fact, most of the petitioners have halted operations currently with Mundra Solar PV Limited operating its production line only intermittently. Similar is the situation with Helios Photovoltaic Limited which shut down its line in May 2017 and Jupiter Solar which shut down production in November 2017.
- uu. Respondents have claimed that the Domestic Industry is not suffering serious injury as certain economic parameters do not show a significant deterioration. For this purpose, they have relied upon data with respect to market share of Indian producers which has shown a decline of 4% overall. However, the same has to be appreciated in the context of the increase in demand of the subject goods in India. Despite the demand being sufficient for the Domestic Industry to manufacture the subject goods to the entire extent of its production capabilities, the Domestic Industry could not utilize even a reasonable level of its installed capacity to produce the subject goods and furthermore, was not even able to sell the entire quantity produced by it. Consequently, this was reflected in the market share of the Indian producers which fell by 4% in a robust market capable of consuming the entire extent of the installed capacity of Indian producers. Rather, the inventories of the Domestic Industry increased.
- vv. Respondents have claimed that Domestic Industry has not suffered any serious injury as production and sales figures have improved. However, the same has to be considered in light of the addition of capacity to manufacture the subject goods by the Domestic Industry. Had production and sales of the Domestic Industry improved without the installation of additional capacity, it could have perhaps been contended that the situation of the Domestic Industry has improved. However, though the Domestic Industry has installed additional capacity, their production and sales have not increased commensurately. The fact that production of other Indian producers has increased also has to be examined in light of the fact that their sales were negligible in 2014-15 and 2015-16. Rather, it needs to be considered that despite sales of the other domestic producers as well as the Domestic Industry increasing on a standalone basis, the market share of Indian producers actually reduced by 4%.
- ww. Respondents have contended that imports increased in relation to production as 3 units based in SEZs have been unable to export. However, this contention is as there is no compulsion SEZ units of the PUC to export as they can achieve positive NFE by DTA clearances also. *Second*, the sales to the export markets were negligible to begin with and only constituted a very small fraction of the subject goods being produced for sale in the domestic market and therefore, any drop in the performance thereof will be reflected only to an insignificant extent in the production and capacity utilization of the Domestic Industry. *Third*, comparison of imports in relation to production has not been restricted to extent of production of the subject goods by the Domestic Industry and rather, includes entire domestic production in India by all domestic producers. *Fourth*, the injury parameters have been submitted after excluding the effects of exports.

- xx. Respondents have claimed that capacity utilization, productivity per employee and profitability of the Domestic Industry has decreased in view of addition of Mundra Solar PV Limited who has commenced production in 2017-18. However, in this respect, it may be noted that even if these parameters of the Domestic Industry are examined after excluding the data of Mundra Solar PV limited, it will still demonstrate that Domestic Industry has suffered considerably.
- yy. Respondents have claimed that price undercutting data does not indicate any price suppression or depression. While the range of undercutting for imports of solely solar cells has gone down, it is not due to the fact that the landed value thereof has increased. Rather, the Domestic Industry has been attempting to price the subject goods as competitively as possible with that of imports in order to sell its inventory. However, the range of undercutting is still significant to the extent that the landed value of imports is less than half of the cost of sales of the Domestic Industry. Therefore, the Domestic Industry has been compelled to price the subject goods much below its cost of sales and incurring losses.
- zz. Landed value of solar modules has reduced drastically to the extent that even solar modules are being imported at a price that is lower than the cost of sales of the Domestic Industry for producing the solar cells not arranged into modules. Consequently, the range of undercutting for solar cells arranged in modules has increased manifold. The Domestic Industry has been unable to fetch remunerative prices for the subject goods sold by it throughout the duration of the POI clearly establishes that the Domestic Industry is suffering from price suppression.
- aaa. Respondents have claimed that shutdown of M/s Surana Ventures, M/s Udhaya Energy Photovoltaics Private Limited and M/s XL Energy Limited was on account of poor export performance as they were SEZ units. This contention is entirely baseless as there is no compulsion on SEZ units to export. Rather, these SEZ units should have been able to thrive in view of the huge demand of subject goods in India.
- bbb. Furthermore, the respondents have claimed that prices of imports have decreased due to increased efficiency of modules from 260 Watt peak to 330 Watt peak, creation and benefit of economies of scale enjoyed in the supply chain for polysilicon, wafers and ingots production, creation of integrated manufacturing capacities with the major module suppliers and further improvements in capacity utilization and overall manufacturing cost brought about by the vertical integration and introduction of new processes like PERC, which allows further efficiency improvements, due to which lower cost per watt can be achieved. It is to be noted that Domestic Industry is already implementing these measures and the very reason why safeguard duties have been sought is to afford protection to the Domestic Industry while implementing them.
- ccc. Respondents have contended that the profit/loss of the Domestic Industry has improved in 2017-18. However, it seems that most respondents have misconstrued the increase in losses of the Domestic Industry as increase in profitability as otherwise, it is clear on the face of the record that the losses of the Domestic Industry has quadrupled from that of the base year.
- ddd. Respondents have relied upon certain averments by the petitioners in their annual reports whereby it has been stated that a slowdown in the global market. However, the said observations have been taken out of context as none of the averments referred to have indicated that the losses suffered by the petitioners is due to not being able to export the subject goods. In fact, a closer scrutiny of the statements extracted from the annual reports of the petitioners indicate that they were gearing up to service the demand of the subject goods in the domestic market of India. However, due to the influx of cheap imports, the Domestic Industry has either not been able to sell the subject goods or able to sell them only at unremunerative prices.
- eee. Certain respondents claimed that imports are more competitively priced due to cheaper raw material, backward integration by producers of the subject goods in the exporting countries, superior technologies such as PERC being employed by these producers, lower cost of conversion etc. In this regard, it is relevant to note the adjustment plan of the Domestic Industry is also based upon implementing the aforeasaid measures. Therefore, the respondents cannot now contend that the adjustment plan of the Domestic Industry is not sufficient to help it compete with imports.
- fff. Evaluation of public interest essentially evolves balancing the competing interests of different interested parties which are as follows in the present case:
- a) The domestic manufacturers (petitioners in the present case) of solar cells whether or not assembled in modules or panels;

- b) The domestic manufacturers of solar modules who rely on imported solar cells;
- c) The power developers which can be divided into the following categories
 - (i) Category 1 - The developers who have entered into PPAs with DISCOMS and have already imported the product under consideration;
 - (ii) Category 2 - The developers who have entered into PPAs with DISCOMS but have not yet imported the product under consideration;
 - (iii) Category 3 - The developers which may bid on future projects and are hoping to import the product under considerations.
- d) The consumer of electricity.

ggg. Foreign governments and exporters have no role to play as regards public interest in India is concerned as foreign governments would only look after the interests of foreign producers and be interested in supplying the product under consideration which maximizes their return and eliminates all sources of competition.

hhh. The interest of the Domestic Industry must be weighed against the interest of solar module manufacturers who rely on imported solar cells, Category 2 developers and the consumer of electricity. It is submitted that Category 1 power developers would be unaffected by the imposition of safeguard duty since imports have already been completed. Similarly, Category 3 power developers would incorporate the enhanced import price (as a result of imposition of safeguard duty) into their tariff quotations or possibly receive viability gap funding. The only affected party is the extremely narrow Category 2 power developers who have quoted the tariff based on prevailing import prices of product under consideration but are yet to import the product under consideration. Even for such Category 2 power developers, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has already notified pass-through facility¹ i.e. the imposition of duty will be covered under the Change in Law clause and the impact of duty will be passed on by the developers to the DISCOM. Therefore, it is humbly submitted that Central Government has already taken steps to balance the interests of the extremely narrow category of power developers who will be actually affected by the imposition of the safeguard duty.

iii. The only economic players whose interests are at odds are the petitioners, the module producers who rely on imported solar cells and the consumers of electricity. However, one of the largest module producers, Waree Energies Ltd., has supported the imposition of safeguard duties

jjj. As regards the consumers of electricity are concerned, their interest is in obtaining electricity at the cheapest rate possible. While some interested parties have argued that the increase in price of electricity must be computed for solar electricity alone, the argument is fallacious because the ultimate consumer of electricity does not receive electricity which could be identified based upon origin. The state electricity distribution companies obtain electricity from different sources and such electricity is supplied to various consumers. Therefore, impact of safeguard duty must be assessed for the entire power matrix comprising of electricity produced from all different sources.

kkk. While most interested parties have made bare assertions regarding the increase in solar tariff, projections filed by ACME must be disregarded as ACME has considered module prices at USD 0.31/Wp whereas the prices quoted from China are already at USD 0.27/Wp. While ACME has considered the impact of safeguard duty on imports, ACME has not accounted for viability gap funding (VGF) proposed to be provided by the Ministry of New and Renewable Energy. Furthermore, ACME has considered the impact of safeguard duty on the entire Indian demand whereas the impact would be limited to Indian Modules made from Indian cells (approximately 25 %). For the remaining demand, the impact would be offset by the VGF provided to the developers from the safeguard duty collected.

lll. Certain interested parties alleged that imposition of safeguard duty will be against public interest due to the gap between demand and supply relying upon Final Findings in *Safeguard investigation concerning imports of White/Yellow Phosphorus into India*. However, gap between demand and supply was one of the several factors which were considered by the Hon'ble DG Safeguards in that investigation. Rather, the Hon'ble DG Safeguards has recommended imposition of safeguard duties in other cases wherein capacity of Domestic industry was lesser than demand such as Safeguard investigation concerning imports of

Industrial Sewing Machine Needles, Safeguard investigation concerning imports of Oxo Alcohols, Safeguard investigation concerning imports of Sodium Nitrite, etc.

- mmm. Certain interested parties have argued that projections submitted by the Domestic Industry for foreign exchange outflow for importation is misleading. Parties have not contested the computation but merely argued that there will be foreign exchange outflows on account of importation of raw materials. As demonstrated during verifications, the petitioners are attempting for backward integration. Certain key supplies such as solar glass, EVA Sheet, back sheet, etc. have already made significant investments for improving production capacity in India. Therefore, the backward integration along with assured returns will augment domestic production in India and stem the huge outflow of foreign exchange from India.
- nnn. Respondents have contended that no backward integration was attempted by the Domestic Industry even when DCR was in effect. Such submissions are far removed from the truth as the Ld. DG Safeguards has already witnessed during verification that two plants of raw material suppliers – for EVA and back sheet are already operating in India near the largest producer of solar cells and modules in the country.
- ooo. Certain interested parties have contended that imposition of SGD would lead to increase in cost of solar power to the tune of 3 Rs./Unit. However, the statements from unnamed experts in a newspaper article cannot be relied on without any factual basis or providing an opportunity to the Domestic Industry to confront such baseless accusations.
- ppp. The interested parties have argued that imposition of safeguard duty will be significant impediment to achieving the target of 100 GW of solar power. It may be observed that the target was announced in early 2015 when the prices of imported solar cells and modules were much higher than prevailing during the period 2017-18. Therefore, if those prices were not an impediment in achieving the target of 100 GW, the present prices after the imposition of safeguard duty cannot be termed as an impediment to installation of 100 GW of solar power.
- qqq. The only requirement for SGD is that the measure shall be applied to the extent necessary to meet the three objectives - prevent serious injury; remedy serious injury and facilitate adjustment. The measure may be applied to the extent necessary to prevent 'or' remedy serious injury but in either case, it has to facilitate adjustment. Not only, there is no guidance on the extent of duty necessary to prevent or remedy serious injury, but also there is no guidance whatsoever on the extent necessary to facilitate adjustment.
- rrr. It must be noted that the requirement to facilitate adjustment is not present in other trade remedy instruments such as antidumping and countervailing duties. WTO Antidumping Agreement has two provisions one - addressing the injury and the other addressing the limitation or ceiling of duty. While the objective is to impose duties to the extent necessary to counteract dumping which is causing injury, the ceiling is that the duty shall not exceed the margin of dumping. Similar situation exists in the case of countervailing duties also. However, no such ceiling has been provided for under the Safeguards Agreement. In view of the differences in the legal provisions concerning safeguard measures as compared to antidumping or countervailing duty measures, it is not appropriate to apply the principles followed in antidumping or countervailing duty laws for the purpose of determining the duty amount that may be applied in the case of safeguards.
- sss. India has introduced rules relating to determination of NIP in antidumping laws. The law requires the authority to determine costs under normal conditions of operations by normalizing certain costs such as raw materials, utilities, etc. and also in not recognizing expenses incurred after the factory gate such as commission, warehousing expenses, bad debts, etc. and also requires addition of an appropriate rate of return on capital employed instead of actual interest and a profit. It must be noted that Safeguards law addresses an emergency situation calling for emergency measures. In such a situation, it would be anathema to apply normalization principles in arriving at the 'extent' of duty that may be imposed.
- ttt. The NIP model does not meet the third requirement i.e. a component that is necessary to facilitate adjustment. So long as there is no provision to consider what is necessary to facilitate adjustment, NIP law cannot be followed for determining the extent of safeguard duty. Therefore, it is necessary to find alternate methods of arriving at the 'extent' of safeguard duty. WTO Members are free to choose any methodology reasonable enough to meet the objectives of Article 5.1. There is no guidance in the Indian law also. In this regard, one may look at the methodologies followed by USA, Canada and EU.
- uuu. The allegation that the Domestic Industry withdrew from the investigation because the dumping margin and/or injury margin does not have any foundation in facts and is entirely in the realm of surmises and conjecture. The domestic industry has established all the ingredients necessary for imposition of

safeguards duty namely – (i) unforeseen development; (ii) effect of obligations incurred under GATT; (iii) sudden surge in imports; (iv) serious injury; (v) causal link between increased imports and serious injury; (vi) standing; and (vii) public interest.

(ii) Taiwan Photovoltaic Industry Association.

- a. DI does not satisfy requirement of Section 8B(6)(b) as their production does not constitute major share. As per MNRE data, there are about 20 Solar Cell manufacturers and 117 Solar Module manufacturers in India. Accordingly, capacity of Domestic Industry for Solar cells and Solar modules as on May 31, 2017 is merely 26.41% of total installed capacity in India.
- b. Data provided in DI's submissions completely excludes solar module manufacturing capacity in India to determine standing though solar cells and modules are both covered in scope of the PUC. Therefore, investigation should be terminated on the ground of deliberate miscalculation..
- c. SEZs cannot be treated as domestic industry. Section 51 of the the SEZ Act has overriding effect on other domestic legislation. SEZ are immune from vagaries domestic market.
- d. SEZ offer concessions to companies for exports and entities have a choice to set up units in SEZ or in DTA. Thus, setting up a unit in SEZ confirms that the SEZ Units have opted primarily for catering to export market and not DTA. Hence, SEZ Units cannot be extended the status of Domestic Industry.
- e. DI's stand is contradictory as on one hand, they want inclusion of SEZ Units in determining standing of DI and on the other, seek exemption from levy of SGD on the SEZ Units. Case laws cited only hold that clearance of goods manufactured in SEZ to DTA does not amount to import. Section 8B(2A)(ii) expressly provides that Safeguard Duty shall be levied. Strict interpretation should be applied for the purpose of levy of Duty as held in Sneh Enterprises [2006 (202) ELT 7 (SC)].
- f. Mundra Solar and Helios Photo Voltaic are producers of the PUC as they are involved only in assembly of imported solar cells into modules in view of the AntiDumping investigation initiated on July 21, 2017 wherein Mundra Solar and Helios Photo Voltaic were excluded from the scope of the Domestic Industry as these companies import Solar Cell or buy from domestic producers.
- g. Mundra Solar with installed capacity of 2400 MW became operational only in May, 2017. Without including this installed capacity, standing of DI would be merely 5.73% and remaining applicants would not qualify to be Domestic Industry. Present investigation ought to be terminated on this ground alone.
- h. Domestic Industry has presented wrong data in terms of increase in value of imports of PUC. Increase in imports in 2017-18 has been 15% from 2016-17 which cannot be said to be sharp, sudden and significant, compared to previous years.
- i. DI has mentioned various circumstances as unforeseen developments. TPVIA vehemently opposes that these circumstances were not unexpected at the time of incurring such obligations under GATT and DI provides no credible factual or legal basis for these submissions that unforeseen developments.
- j. Data relied upon by DI itself suggests that China PR's capacity is not export oriented as its domestic consumption of Solar Cells is more than exports.
- k. Though exports of Solar Modules were higher as compared to domestic consumption in 2014, the scenario gradually changed in 2016 when domestic consumption was higher. DI has completely misunderstood China's solar market and the allegation that its capacity for producing the PUC is export oriented is baseless.
- l. Arguments made by DI on support extended to Chinese producers by their government are relevant for a Subsidy investigation, not Safeguard. Reasons and justifications by DI are grounds to establish existence of subsidies and not unforeseen developments.
- m. Requirement of unforeseen developments is supplemented by condition of being an effect of obligations undertaken under the WTO Agreement to justify increased import. By no stretch of imagination can achieving economies of scale by China PR in solar sector can be said to be an effect of obligation incurred under the WTO.
- n. Imports have not only increased from China PR but from other countries as well on account of increased demand and incapacity of DI. However, there is no whisper in DI's submissions about increasing imports from other countries. Global safeguard cannot be initiated when injury is caused

due to one specific country. SGD is aimed at providing emergency protection from imports and in principle, cannot be targeted at imports from a particular country.

- o. It cannot be ignored that DCR requirement was always at the risk of running afoul of the WTO Obligations and the Government of India kept on pushing to protect domestic manufacturers.
- p. DI's contention that change in pattern of trade was pursuant to removal of DCR is misplaced as DCR affected only a small amount of production in India as noted by the Panel in India - Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules vide WT/DS456/R. Imports were equally high with DCR in place.
- q. Standard to determine existence of unforeseen development is "*not what the specific negotiators had in mind but rather what they could (reasonably) have had in mind*" as observed by the Panel in United States - Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products vide WT/DS248, 249, 251, 252, 253, 254, 258, 259/AB/R. Paris Agreement, being an agreement within the UNFCCC, came into force in 1994 and as such, cannot be said to be unforeseen but a culmination of efforts of two decades of reducing greenhouse gas emissions and taking care of global warming amongst WTO Members.
- r. In view of Preamble to ITA:1, it can be inferred that it was not unforeseen by the Government, of India at the time of granting concession under ITA-1 that certain developments may arise to encourage continued technological development of information technology industry on a world-wide basis. Circumstances must be unforeseen by Government while undertaking an obligation and not by DI as held by Panel in Dominican Republic - Polypropylene Bags (WT/DS415, 416, 417, 418/R).
- s. DI failed to demonstrate as a matter of fact how imports of the PUC being made free under ITA-1 led to unexpected increase in imports only during the POI when India became a signatory to ITA-1 in 1997 and tariffs were eliminated by 2000.
- t. If injury analysis in Anti-Dumping Investigation was not sufficient to establish injury, it would not suffice the requirement to show serious injury in a Safeguard investigation as "*the word 'serious' connotes a much higher standard of injury than the word 'material'*" as observed by the Appellate Body in the US - Lamb (WT/DS 177, 178/AB/R).
- u. According to Mercom's 2017 Q-4 and Annual India Solar Market Update, average selling price of modules imported from China PR saw an increase from 22.80/W in Q-3 2017 to ₹23.45/W in Q-4 2017. Increase of module price by 4% shows picture of injury presented by DI to be tainted.
- v. DI failed to demonstrate causal link between increased imports and serious injury by failing to consider non-attribution from other sources of injury such as inefficiency and incapacity of domestic producers, lower quality of domestically manufactured PUC, commencement of production by Mundra Solar only in May, 2017, Increasing demand due to ambitious target of Government to make India one of the largest green energy producers in the world, Government support through various schemes to build up manufacturing capacity of the PUC in India, such as Central Public-Sector Undertakings Scheme, fiscal incentives in the form of exemption from Customs Duty on import of capital good, creation of Technology Up-gradation Fund (TUF) for solar sector, etc., Compulsory registration of the PUC under the Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Component Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2017, and Capital and technology intensive nature of solar industry.
- w. DI blandly mentions that even with levy of 70% ad valorem duty, increase in power tariffs will be negligible. According to Mr. Subodh Rai, Senior Director, CRISIL Ratings, imposition of SGD would inflate project costs by 25% and increase viable tariff to ₹3.75 per unit from around ₹3 per unit, making solar power less attractive to discoms.
- x. Levy of Safeguard Duty would burden the ultimate end-consumer.
- y. DI assertion that addition of capacity announced by overseas manufacturers would never be realised if SGD is not levied is baseless as companies have already put investment plans in place which will support domestic producers achieve economies of scale. The DI is aiming to seek dual-protection in form of investment and loans for its operations from all sources and other in guise of protectionism from the Government to cover up for inefficiencies.
- z. Safeguard Duty should be proposed only to offset injury caused by increased imports and not for other causes as held in Appellate Body Report in United States - Definitive Safeguard Measures on Imports of Circular Welded Carbon Quality Line Pipe from Korea (WT/DS202/AB/R).

(iii) M/s First Solar Inc., USA; M/s First Solar FE Holding Pte. Ltd. & M/s First Solar Malaysia SDN. BHD.

- a. Majority of the injury parameters relating to the domestic industry are showing improvement. Analysis of past SGD investigations has shown that existence of serious injury is made out only when majority of the parameters show deterioration. Rules also require the authority to examine whether performance of domestic industry has deteriorated, so in a situation where performance of the domestic industry is improving, the DG Safeguards must hold that the domestic industry has not suffered serious injury.
- b. Parameters such as production, sales, capacity utilisation, losses, market share, return on investment etc. have improved. Any deterioration in parameters such as capacity utilisation, profits and return on investment is a result of significant capacity addition by Mundra Solar from 653 MW to 1000MW. Losses incurred by the domestic industry have increased significantly on account of Mundra Solar. If the same is excluded, the losses suffered by the domestic industry have reduced significantly.
- c. Petitioners have relied upon the preliminary findings at various places, however, such reliance is grossly misplaced for the findings were made without consideration of the interested parties and based predominantly on the petitioners claims. No reliance can therefore be placed on the preliminary findings in support of their submissions.
- d. Petitioners are trying to lump c-Si and Thin-Film products by professing them to be the same products using different technology. However the products here are inherently different, not just in the type of raw material and technology used, but also, the physical and technical characteristics of the product.
- e. In light of inherent differences between the two products as well as the submissions of the respondents in relation to the different BOSs required for the two, c-Si photovoltaic and thin film products are not interchangeable but alternative products.
- f. End product substitutability can never be a criterion for holding that the products themselves are substitutable. Petitioners cannot include two different articles in the scope of PUC on the ground that the product produced out of these two different articles is interchangeable and competing with each other.
- g. Petitioners have not explained how the c-Si products produced by them are directly competitive with each other. These are merely baseless arguments made by the petitioners. The product produced by the petitioners is not like or directly competitive to thin film products, and accordingly, the latter must be excluded from the scope of product under consideration.
- h. Reliance of the petitioners on the previous findings of the Authority is misplaced. Since the duty itself was not imposed, the respondents could never avail the opportunity of filing an appeal against the decision and the previous order of the Designated Authority. The previous finding has also not attained finality and therefore should not be relied upon.
- i. In coming to a conclusion that c-Si photovoltaic products and thin film products are like article, the Authority had relied upon, amongst others, the following facts:
 1. Thin film imports were 25% of the total imports from the subject countries.
 2. There was a very insignificant price difference between the price per watt of less than 5% between the two products.
 3. The cost/pricing and competition (in market parlance) is also decided based on factors such as Watt per unit, efficiency of the cell/modules under both technologies.
- j. However, there has been a dramatic change in the position of thin film products vis-à-vis c-Si products, with regard to the above factors.
 1. As per data supplied by petitioners, the imports of thin films is only 0.15% of the total imports of the subject goods into India.
 2. Further, the price difference between the two products is not insignificant, as noted in the earlier case, but rather there is a difference of 15% in the price of thin film products and c-Si products.
 3. While the price per watt of thin film products has been increasing over the period, that of c-Si products has been declining.Therefore, clearly the two products are not competing with each other in the market insofar as the prices are concerned.
- k. Petitioners have claimed that the safeguard findings of the Canadian Authorities in relation to solar cells must be relied upon rather than the US and EU findings that have considered the two products not fall

within the scope of the same PUC without offering any reasons for the same. If at all any findings were to be referred, the findings of the USITC in the safeguard findings are most relevant to the present case.

- l. If the US and EU authorities did not include c-Si and Thin Film products within the scope of the PUC, it goes on to show that there is higher degree of justification that the present case also should not include the two under the same scope of the PUC.
- m. Piece-meal reliance by the petitioners on the same findings cannot and should not be accepted. Petitioners have failed to point to a single fact that must distinguish the findings of the USITC on the issue of thin film products and justify the exclusion thereof.
- n. When petitioners have themselves accepted and relied upon the findings of the USITC on the issue of inclusion of cells and modules, they cannot claim that the findings should not be followed on the issue of inclusion of thin film products.
- o. Data in the preliminary findings and the written submissions has undergone a change compared to the data as given in the petitioners' application. This change has not been explained in the preliminary findings or the written submissions.
- p. The issue of SEZ units as not forming part of the DI has attained finality in light of previous findings of the Authority and the same cannot be contended by the petitioners.
- q. The issue of Safeguard duty being applicable only if the input used for making the finished products attracted the SGD cleared to the DTA attracted the levy is irrelevant in determining whether SEZ units should be considered as DI or not.
- r. Unforeseen developments took place in 2016 and the increase in imports must be evaluated for periods thereafter and not before that. When compared with 2015-16 rather than 2014-15, the imports have increased only by 123% while the demand during this period had increased by 133%. Imports thus, increased only as a response to increase in demand.
- s. While the imports may appear to have increased in relation to production, the same is on account of the fact that the production is suppressed due to decline in imports.
- t. Petitioners arguments in relation to the increase in the volume and value of imports is misleading as it draws attention to the decline in prices in isolation of other reasons for the said decline that are part of the detailed submissions of the respondents.
- u. Imports increased after the removal of DCRs. the development leading to an increase in imports was therefore the removal of DCRs, pursuant to the decision of the Appellate Body of the WTO rather than the imposition of duties by the EU and USA.
- v. Inconsistency of DCR with the obligations incurred under GATT is not an unforeseen development as DCR was not in existence when obligations were incurred and was introduced recently.
- w. Petitioners have failed to bring to light any development which brought about an increase in imports as only prices of Chinese imports have declined. Imposition of SGD would serve no purpose.
- x. In relation to the petitioner's claim of unforeseen development, the law requires existence of unforeseen developments and not unknown facts. Merely because of benefits enjoyed by producers in China, duty cannot be imposed against all countries across the globe.
- y. Petitioners seem to believe that investigations are only against China as each of the unforeseen development mentioned by them pertains wholly and exclusively to China. It was very much foreseen that the measures to develop industries would be taken, which is why the Anti Subsidy Agreement was entered into. It would not be appropriate to subject all exporters of the subject goods to duty, and increase the cost of imports, merely due to developments taking place in China.
- z. The increase in share of imports is not significant, as they have increased by merely 4%. This can, under no circumstances, qualify as sudden, sharp, significant increase.
- aa. Despite the continued positive price undercutting, there appears to have been no impact thereof on the petitioners; as neither there has been a decline in their production, sales, capacity utilization, nor any price suppression or depression, decline in profits, and ROI (excluding the data for Mundra Solar).
- bb. No price undercutting has been provided for thin film products, which again establishes that neither cells nor modules can directly compete with such products.
- cc. The decline in selling price of the petitioners has been commensurate with the decline in costs. If raw materials costs have declined and total cost of production has increased, it is clearly indicative of the fact that the costs have increased because of addition of Mundra Solar.

- dd. Production of the companies increased even after excluding Mundra Solar. Under these circumstances, there can be no question of decline in employment due to alleged surge in imports.
- ee. Petitioners have not established that they have suffered serious injury, in accordance with the parameters laid down under the Safeguard Rules. Contentions that point to injury on account of loss due to striking down of DCR by the WTO-AB report are merely attempts at gaining sympathy in the absence of any case on merits.
- ff. Any new plant takes some time to become fully operational and the capacity utilization in the initial period is always low. Therefore, the production achieved is quite understandably going to be low at 365 MW even after the increase in installed capacity of 1000 MW on account of entry by MSPVL. Low levels of production also attributable to the decline in sales performance of the petitioners.
- gg. Claimed inability of the petitioners, if any, to sell as much as they produce must be only on account of their poor export performance since sales during the period have quadrupled.
- hh. Petitioners' submissions with regard to increase in losses on account of increased sales due to pricing the products lower than cost are devoid of merit as the loss per unit of the petitioners has actually declined. If losses have increased it is due to overhead costs of Mundra Solar.
- ii. Sales of petitioners have admittedly increased and not declined. The rules require the Authority to examine serious injury and therefore possible significant decline in various economic parameters. The Authority cannot hold that the domestic industry suffered serious injury as some parameters did not increase as much as it could have in the absence of increased imports.
- jj. Attributing decrease in productivity per employee to increased imports despite the addition of MSPVL is erroneous since, if the new entrant set up with a huge workforce, the productivity per employee would show a decline in the short run. However, there is no decrease in the productivity of the petitioners, and actually the productivity per day has increased.
- kk. Petitioners had been suffering losses much before the increase in imports. In fact, the losses decreased only in 2014-15. Therefore, 2014-15 may be an abnormal year. Historically, the petitioners have been making losses, and the same has no correlation with the increase in imports.
- ll. In relation to causal link the following submissions of the respondent have been relied upon:
 - 1. The increase in imports volumes is because of the demand supply gap in the country.
 - 2. The import prices declined due to decline in raw material cost.
 - 3. First Solar request the authority to kindly consider the changes in raw material and prices of the product.
 - 4. The claim of price suppression and depression is strongly refuted. The increase in cost of production has been reported by including data of Mundra Solar. If data of Mundra Solar is excluded, it would be seen that the decline in cost is more than decline in selling price. Thus, despite price undercutting, there is no price suppression or depression effects. If the data shows increase in cost, it is only because of the fact that Mundra Solar recently commenced its commercial production and was faced with significantly high overhead cost which remained unabsorbed due to low production.
 - 5. The domestic industry has been suffering financial losses for quite some time because of collapse of their export market and resultant underutilisation of production capacities. Even before the surge happened, the domestic industry was not able to get prices above their actual costs.
 - 6. The domestic industry has claimed that their sales and capacity utilisation suffered. The domestic industry has not claimed that these volumes have declined. In fact, sales volumes have increased significantly. If the sales volumes have increased, there is no basis to claim serious injury on this account.
 - 7. The market share of domestic industry has not declined. In fact, the market share of domestic industry in prior to surge was much lower.
 - 8. The decline in return on investment is due to inclusion of Mundra Solar data which commenced commercial production only in the recent period. If Mundra Solar data is excluded, it would be seen that ROI of the domestic industry has improved.
 - 9. As regards increase in inventories, the same is on account of commencement of commercial production by Mundra Solar. It is quite obvious that the capacity of the petitioning companies increased from ___ to ___, the inventories with the domestic industries would also increase over the period. However, what is required to be considered is the inventory in relation to production. The inventory in relation to production has not increased to an alarming level.

It is thus evident that the petitioners are not been able to establish any adverse effect of increased imports on the petitioning domestic industry.

- mm. The adjustment plan of the petitioners is too vague and superficial.
- nn. China, Malaysia and Taiwan have been exporting the PUC to Indian market for considerably long period. If imports are at fair price (which is why Safeguard Duty), there is no basis for the argument that the exporters from subject countries are trying to annihilate the domestic industry. By the very concept itself, while imports are at fair price, the Indian industry is not competitive.
- oo. The DI cannot cater to the demand and the DG Safeguards has declined to recommend duties in the past when there has been a substantial demand supply gap.
- pp. The petitioners have given no evidence to support their claim that increase in tariffs would be negligible. Further, they have not explained how the government revenue would increase on account of indigenization.
- qq. Petitioners have not established how non-levy of duty will be against public interest in India. It is purely presumptive that the local manufacturing will cease.
- rr. The production of the domestic industry has been increasing and the capacity utilisation would also show increase if production of Mundra Solar is excluded. It is therefore, without any basis that the imports are going to have adverse effect on the productions line in India.
- ss. The petitioners have conveniently ignored the fact that it had withdrawn its application for anti-dumping duty for the reason that the injury margin was either negligible or negative. Under these circumstances, it is not fathomable as to how the petitioners can claim a duty as high as 95% in case of safeguard measures.
- tt. The duty, if levied, should be based on injury margin on the basis of non-injurious price calculated after applying the same principles as are applied in an anti-dumping investigation.

(iv) M/s North India Module Manufacturer Association

- a. Solar cell produced by the petitioners is not sufficient to take care of their own module manufacturing.
- b. Petitioners have falsely argued that extra capacity is going to come up after the imposition of safeguard duty.
- c. Imposition of duties must be on solar modules and not on solar cells since there is a huge demand supply gap between the demand for the final product, being solar modules and the domestic industry's capacity of solar cells. Even at optimum capacity utilization, the capacity is available to meet only 15% of the total demand. Adani Power has been captively consuming their entire capacity and is a net importer of solar cells.
- d. The petition does not disclose extraordinary or emergency situation which warrants imposition of safeguard duty. The petition must be dismissed on this ground itself.
- e. There has been no unforeseen development. Basic problem of the petitioner is non availability of wafer which is a well known factor. Every increase in import or availability of materials at lower prices outside India should not be discouraged.
- f. No causal link between the increase in imports and the injury caused to the DI has been made out since the problem of the DI remains the non availability of wafer in India. DI has not given any material basis on which it can be demonstrated that the injury claimed by them is due to the increased import.
- g. DI has failed to provide a credible and viable adjustment plan. Unless Silicon Ingot and Silicon Wafer is manufactured in India, Indian cell manufacturers cannot compete with imports at all.
- h. Imposition of safeguards is against public interest.

(v) M/s Avaada Power Private Limited

- a. In terms of Rule 2(e) of the Safeguard Rules, the following articles should be excluded from the product scope as the same are not being manufactured by the domestic industry:
 - i. Solar cells using the "PERC" (Passivated Emitter Rear Cell) based technology
 - ii. Thin films & Bi-facial N-type solar cells;

- iii. High efficiency solar cells using 5 and 6 bus bar production terminology;
- iv. Solar modules of mono crystalline technology.
- b. DI has miserably failed to fulfil and/or prove their eligibility for imposition of safeguard duty under the legal requirements for imposition of safeguard duty.
- c. Standing should be examined separately for solar cells and solar modules. Petitioners do not have standing as domestic industry for solar modules in this investigation.
- d. Petitioners located in SEZ units should be excluded from the standing analysis as their primary goal is to cater to the export market.
- e. Import of the subject goods increased as a result of the Government of India's vision to promote solar power in India. This is the only reason behind increase in imports of the subject goods. Imports occurred only to fill the huge demand-supply gap.
- f. Petitioners have failed to identify any development that qualifies as unforeseen within the meaning of Article XIX(1)(a) of the GATT.
- g. Petitioners have failed to identify any specific GATT obligation that led to sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods in terms of Article XIX(1)(a) of the GATT.
- h. The Petitioners' claim of serious injury has no merit. This is reflected from the annual reports of the petitioners.
- i. Indo Solar and Websol's performance has improved significantly in the financial year 2016-17 while Jupiter Solar Power Limited registered a profit of Rs. 3,999 lakhs during the same period. Mundra Solar PV Limited has started commercial production only about a year ago and cannot be expected to operate at optimum capacity. Injury to this company is on account of high interest and depreciation costs. M/s Helios Photo Voltaic Limited was undergoing corporate debt restructuring for a long period and has accumulated very high liabilities in the balance sheet and that is the reason for this petitioners losses.
- j. Petitioners' adjustment plan is not feasible and practical, and shall not facilitate adjustment in terms of Article 7.1 of the Agreement on Safeguards read with Rule 11(3) of the Safeguard Rules.
- k. Ultimate purchasers of solar power, which are various DISCOM's have clearly stated that solar power shall be purchased at not more than INR 3/kWh. However, imposition of duties would make this rate unfeasible. Post-levy rates of solar power will not only become uncompetitive but the developers will also have to abandon the development of the ongoing projects.
- l. any duty that disturbs the solar power grid parity would adversely affect not only the project developers but also the end-customers
- m. Indians at the bottom of the pyramid, especially, in rural areas have been able to switch to solar power at the current prices. Imposition of safeguard duty will have an adverse effect on rural electrification too.
- n. As petitioners are not legally entitled for imposition safeguard duty, their request for imposition of 95% safeguard duty does not arise.

(vi) M/s China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products

- a. Applicant's claims regarding the scope of the PUC is misleading since differences between products manufactured from both technologies are significant in several aspects, such as raw materials, production processes, efficiency, flexibility and prices, etc.
- b. In the anti-dumping investigations initiated by other countries, crystalline products and thin films have been regarded as different products as evidenced by the USITC and EU's findings.

- c. Claims of the petitioner regarding solar cells and solar modules forming part of the same product are erroneous. Module manufacturers in India rely on the imports of solar cells from other countries like China. Solar cells are the raw materials of modules, several other materials and additional production processes are needed to manufacture modules from solar cells. They are different products, which are needed by different types of clients.
- d. Claims of the petitioners with respect to unforeseen circumstances are unreasonable since no causal relationship between the increase in imports and such claimed unforeseen circumstances is made out by them. Imports have only increased as a result of increase in demand and not because of any unforeseen circumstances.
- e. While concrete commitments under certain international agreements may be unforeseen, but it is indeed foreseen that certain international agreement may be signed and may cause influence and change to relevant market.
- f. Claim of the DI stating that the serious injury caused is due also to the fact that protective ambit of DCR can no longer be offered in light of the WTO Appellate Body decision cannot be allowed since the WTO-AB has held the DCR to be inconsistent with relevant WTO rules. To protect the domestic industry through DCR is by nature unfair and inconsistent with WTO rules.
- g. Alleged injury may be due to the domestic industry's incorrect operating decision to make excessive investment in increasing capacity and production not being proportionate to the increase in demand.
- h. Imposition of safeguard duties is against India's public interest since currently 80% of India's production capacity of photovoltaic products is based on the imported solar cells, among which half are from China. To impose safeguard measures on imports of solar products will harm the interests of India's downstream users like power station operators, investors and importers.
- i. The indigenous manufactures situated in SEZ will come under the ambit of any blanket duty that will be imposed on solar cells and modules which will make them uncompetitive.
- j. The investigating authority mentioned neither the interests of importers or end users nor the overall public interests, but only emphasized that the proposed provisional Safeguard Duty is to protect the interests of the Domestic Industry.
- k. Quantum of duty proposed by the DI at 95% is even higher than the duty rate proposed in the preliminary findings.

(vii) M/s Solar Power Developers Association

- a. In terms of Rule 2(e) of the Safeguard Rules, the following articles should be excluded from the product scope as the same are not being manufactured by the domestic industry:
 - i. Solar cells using the "PERC" (Passivated Emitter Rear Cell) based technology;
 - ii. Thin films & Bi-facial N-type solar cells;
 - iii. High efficiency solar cells using 5 and 6 bus bar production terminology; and
 - iv. Solar modules of mono crystalline technology.
- b. DI has miserably failed to fulfil and/or prove their eligibility for imposition of safeguard duty under the legal requirements for imposition of safeguard duty.
- c. Standing should be examined separately for solar cells and solar modules. Petitioners do not have standing as domestic industry for solar modules in this investigation.
- d. Petitioners located in SEZ units should be excluded from the standing analysis as their primary goal is to cater to the export market.

- e. Import of the subject goods increased as a result of the Government of India's vision to promote solar power in India. This is the only reason behind increase in imports of the subject goods. Imports occurred only to fill the huge demand-supply gap.
- f. Petitioners have failed to identify any development that qualifies as unforeseen within the meaning of Article XIX(1)(a) of the GATT.
- g. Petitioners have failed to identify any specific GATT obligation that led to sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods in terms of Article XIX(1)(a) of the GATT.
- h. The Petitioners' claim of serious injury has no merit. This is reflected from the annual reports of the petitioners.
- i. Indo Solar and Websol's performance has improved significantly in the financial year 2016-17 while Jupiter Solar Power Limited registered a profit of Rs. 3,999 lakhs during the same period. Mundra Solar PV Limited has started commercial production only about a year ago and cannot be expected to operate at optimum capacity. Injury to this company is on account of high interest and depreciation costs. M/s Helios Photo Voltaic Limited was undergoing corporate debt restructuring for a long period and has accumulated very high liabilities in the balance sheet and that is the reason for this petitioners losses.
- j. Petitioners' adjustment plan is not feasible and practical, and shall not facilitate adjustment in terms of Article 7.1 of the Agreement on Safeguards read with Rule 11(3) of the Safeguard Rules.
- k. Ultimate purchasers of solar power, which are various DISCOM's have clearly stated that solar power shall be purchased at not more than INR 3/kWh. However, imposition of duties would make this rate unfeasible. Post-levy rates of solar power will not only become uncompetitive but the developers will also have to abandon the development of the ongoing projects.
- l. any duty that disturbs the solar power grid parity would adversely affect not only the project developers but also the end-customers
- m. Indians at the bottom of the pyramid, especially, in rural areas have been able to switch to solar power at the current prices. Imposition of safeguard duty will have an adverse effect on rural electrification too. As petitioners are not legally entitled for imposition safeguard duty, their request for imposition of 95% safeguard duty does not arise.

(viii) M/s REC Solar

- a. Safeguard duty, if any, should not be imposed on imports of PUC that:
 - originates from Singapore, and
 - utilise high-efficiency CSPV cells manufactured in Singapore
- b. SEZ units should not be part of the domestic industry as these units fall outside the custom territory of India.

Section 26 of the Special Economic Zones Act, 2005 provide for special incentives in the form of duty free imports for SEZ units which are not available to a unit in the DTA.

- c. They relied on the final finding in Safeguards Investigation concerning imports of Electrical Insulators into India from People's Republic of China, which was further confirmed in Safeguard Investigation concerning imports of 'Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys) into India.
- d. The Domestic Industry for the same PUC and for the same POI and injury analysis period is claiming material injury in the anti-dumping investigation and serious injury in the safeguard investigation which in turn shows that Injury segregation has not been provided.
- e. If there are factors other than increase in imports which are causing injury to the domestic industry, those factors should not be attributed to increased imports and in such cases, the complaint may be referred for anti-dumping or countervailing duty investigation.
- f. The DI should be directed to provide a segregation of injury suffered on account of dumped imports from the injury suffered on account of increased imports. *Front Axle Beam, Steering Knuckle & Crankshaft of medium and heavy commercial vehicles*

- g. Where the applicants themselves are admitting and claiming '*market disruption*' on account of imports of the PUC, which is only applicable to the imports from China PR, the DI's present application for imposition of safeguard duty on all the imports of the PUC is devoid of merit and is liable to be terminated.
- h. There is insufficiency in showing increased imports and even though there has been an increase in the volume of imports, the rate of the increase in imports shows a declining trend.
- i. The Indian domestic industry for the PUC has improved its performance significantly throughout the POI.
- j. The imports of the PUC into India must be allowed to meet the domestic demand for the PUC in India.
- k. There is inherent deficiency in Indian solar manufacturing industry. A concept note dated 15 December 2017 was issued by Ministry of New and Renewable Energy which provides that the injury suffered by the Domestic Industry is not account of increased imports of the PUC, but on account of its inherent deficiencies.
- l. The causal link between the imports of the PUC and the alleged serious injury to the DI is broken due to the following:
 - (i) Decline in the rate of increase in imports of the PUC
 - (ii) Inability of the DI to meet the demand
 - (iii) Inherent weakness in the Indian solar manufacturing industry
- m. Injury suffered by the Domestic industry, if any, on account of factors other than increased imports should not be attributed to the increased imports of the PUC.
- n. The DI has failed to justify that India being a signatory to the ITA and the removal of DCR is an unforeseen or unexpected circumstance leading to the increase in imports.
- o. With respect to the removal of DCR policy, no evidence has been provided with respect to import trend from the time of the removal of DCR in December 2016 till the time of the finalization of the DI application in May 2017. The reason of removal of DCR as constituting unforeseen circumstances also cannot be accepted. Thus, in view of the arguments made above, the respondent respectfully submits that the DI has not been able to meet the requirements of GATT Article XIX.
- p. The adjustment plan provided by the applicants is highly speculative and devoid of concreteness. The DI has not provided any specifics of the adjustment plan with respect to timelines or details regarding its implementation and therefore, the same cannot be considered as a viable adjustment plan.
- q. The imposition of safeguard duty, if any, will have a negative impact on the overall solar user industry and the same will prove detrimental to the larger public interest.

(ix) M/s Vikram Solar Ltd.

- a. The inclusion of units set up in SEZs as domestic industry, as held by the DG (Safeguards) in his preliminary findings dated January 5, 2018. This inclusion of units set up in SEZs as domestic industry by the investigating authority and in support of this decision it is submitted that there is no bar under the Agreement on Safeguards or under the Indian Safeguard law against considering units set up in SEZs as domestic industry.
- b. The solar units set up in the SEZs are contributing to the socio-economic growth and development of the country by providing employment and adding to the national GDP and are an important tool in realising the Government's target of 100 GW of solar power by 2022.
- c. The domestic industry is not manufacturing the articles listed below, these articles should be excluded from product under consideration of the safeguard investigation.
 - (i) Solar Cell using Passivated Emitter Rear Cell (PERC) technology;
 - (ii) Thin Films and Bi-facial Solar cells;
 - (iii) High Efficiency Solar Cells using 5 and 6 bus bar production terminology;
 - (iv) High Efficiency Solar Cells based on Heterojunction Technology
- d. The injury faced by both the SEZ units and units set up in the DTA area can be remedied by imposing safeguard duty in the form of Tariff Rate Quotas (TRQ) and by allocating a substantial portion of the TRQ to units set up in the SEZs.
- e. The domestic production capacity of solar cells is far lesser than the domestic requirement for the production of solar modules or panels

(x) M/s Trina Solar science & technology (Vietnam)

- a. Imports of the subject goods from Vietnam do not exceed 3% individually and 9% collectively when taken along with imports from other developing countries (other than China and Malaysia). As such, no provisional safeguard duty was recommended on Vietnam.

(xi) Trina Solar science & technology (Thailand)

- a. Imports of the subject goods from Thailand do not exceed 3% individually and 9% collectively when taken along with imports from other developing countries (other than China and Malaysia). As such, no provisional safeguard duty was recommended on Thailand.

(xii) M/s Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc and Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc

- a. Since six months have passed from the initiation of investigation, the data for the year 2017-18 is now available for both imports as well as injury. However, the Petitioners do not seem to have brought any recent data on record (whether for import or injury) and have simply relied on the annualized POI in its analysis.
- b. The period of investigation and injury period in both investigations remains largely common, with the only three months differentiating the two investigation periods.
- c. Solar cells and modules differ from each other on account of end-use, technical and commercial substitutability, pricing, and product characteristics as follows:
 - (i) Product Characteristics: Solar cells are inputs for modules. A module is composed of several solar cells.
 - (ii) End-use: While both solar cells and modules have a similar basic property i.e., generation of electric energy from sunlight, a solar cell is not commercially substitutable with a module and they are different in terms of end-use/applications. A single solar cell cannot typically generate electricity which can be used for any commercial application. A module which is made up of several solar cells, on the other hand, can be used for commercial applications due to higher amount of electricity generation. Therefore, solar cells and modules are different from the perspective of an end-user.
 - (iii) Technically and Commercially Un-substitutable: The process of assembling solar cells into modules is a technical and sophisticated process that requires value addition of up to 30% to 35% of the cost of solar cells. The landed value of solar cells from the Subject Countries, in terms of the Petition itself, ranges from INR 13.71/Watt to INR 18.59/Watt and the landed value of modules ranges from INR 24.19/Watt to INR 36.58/Watt during the POI.
- d. Solar cells and modules do not compete with each other – one is an upstream product to the other. Imports of modules do not compete with products sold by cell manufacturers and vice versa.
- e. Given solar cells and modules are separate products (as already emphasized above), no data whatsoever has been provided with respect to % share of production split between solar cells and modules by the five Petitioning Companies (as against the total production of solar cells and modules respectively).
- f. Based on public domain information, the five Petitioning Companies together would constitute a mere 3.25% of the total domestic production of modules.
- g. Three of the Petitioning companies are SEZ, they should be excluded from the domestic industry pursuant to the final finding in *Safeguard Investigation concerning Imports of “Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)”*
- h. The Exporters agree with the position that the safeguard duties, if any, would “not” be applicable to the finished goods manufactured in the SEZ and moved to the DTA – but would apply to the inputs that are used to make the said finished goods (assuming the duty is imposed on inputs and the finished goods are like article to the inputs).
- i. Since both solar cells and modules are neither like article nor directly competitive (as elaborated herein at Section B above), the Hon’ble Designated Authority is requested to direct the Petitioners to provide data in respect of increased imports – separately for solar cells and modules so as to make an effective assessment of serious injury.
- j. The Petitioners have limited their averments in respect of unforeseen developments solely to China at paragraph no. 50 to 68 of their Written Submissions and have failed to illustrate any unforeseen developments in respect of other countries from which there have been alleged imports to India.
- k. The events qualifying as ‘unforeseen’ must have been so at the time when concession was negotiated. At the time of negotiation of Marrakesh package, the contracting parties also negotiated agreements pertaining to trade-remedy measures i.e. anti-dumping, anti-subsidy and safeguard. Adoption of trade remedy measures on certain products was not ‘unexpected’ as such at the time when concessions were negotiated

- l. Inconsistency with WTO law cannot be considered as “unforeseen”.
- m. The figures provided in this behalf seem unsubstantiated and require further authentication. These events are business decisions taken by Companies globally to make their businesses efficient. Such events would continue to exist in any industry irrespective of the imposition of the safeguard duty. Mere increase in volume of trade or export orientation of the Chinese exporters cannot be termed as ‘unforeseen development’.
- n. The incentives provided to the Chinese domestic producers remains irrelevant for the purpose of the present safeguard investigation. What remains relevant is the demand that grew globally including in India. The subsidy measures adopted by China cannot be termed as ‘unforeseen developments’ by India within the meaning of Article XIX:1(a) of the GATT 1994. The Petitioners are attempting to counteract China’s subsidy measures by requesting for a levy of safeguard duties.
- o. Paris Agreement is nothing but an extension of India’s commitments under the United Nations Framework Convention on Climate Change (“UNFCCC”) which India ratified on 1 November 1993 and therefore, India was always committed to reduce its carbon emissions and it had full knowledge about its ongoing commitments under the UNFCCC at the time even COP21 were to be seen as new development, it can never be termed as ‘unforeseen development’.
- p. The Petitioners have themselves admitted that injury suffered to the domestic industry is on account of dumped imports and since the relevant investigation to tackle dumped imports is anti-dumping investigation – the Hon’ble Designated Authority is requested to direct the Petitioners to relevant investigation pursuant to its obligation under Safeguard Rules and the WTO.
- q. The present investigation is currently proceeding on the basis of outdated and erroneously annualized data, which does not appear to have been updated. The Hon’ble Designated Authority is requested to not proceed with the investigation unless new and most recent injury data is made available to the interested parties.
- r. The Petitioners have conveniently ignored the fact that their capacities (until the inclusion of Mundra Solar PV Limited) could not even cover India’s demand in the period of investigation, and developers had no choice but to import cells and modules at reasonable prices to meet the lofty targets set by the Government of India.
- s. The demand for the PUC significantly increased throughout the POI, however, the Indian capacity did not increase at the same rate so as to meet the demand for PUC in India.
- t. The Hon’ble Designated Authority in the past have decided not to impose safeguard duty in respect of subject goods wherein there were increased imports in India on account of meeting with the growing domestic demand in India and for the purpose of filling the gap in demand – supply in India.
- u. The Petitioners have attempted to simulate fictitious injury as will be demonstrated on the basis of the facts below. In a parallel anti-dumping investigation against imports of subject goods originating in or exported from China PR, Taiwan and Malaysia (“subject countries”), price undercutting for solar modules during the POI (1 April 2016 to 30 June 2017) for subject countries was negative.
- v. The Petitioners herein have conveniently provided separate data for cells and modules in respect of price undercutting, whereas in respect of other injury parameters like suppression and depression, the Petitioners have chosen to provide the combined effect of the solar cells and modules imports on domestic industry (when the solar cells and module if individually determined may not show alleged injury).
- w. The Hon’ble Designated Authority is requested to make a separate analysis of alleged injury on account of imports of solar cells and modules separately as cells and modules are not like and directly competitive.
- x. There is no price suppression/depression in the present facts as the selling price has been maintained at the same rate as that of the cost of sales. There is only one year in the entire injury period where the price has not moved in tandem with the cost of the Petitioners i.e. 2015-16. There were bound to be inflated costs for the new producer (as is the case for any new plant) due to high depreciation, high interest cost, higher fixed cost and slow ramping up of capacity utilization.
- y. Sales made by the Petitioners have improved throughout the POI and serious injury, if any, to the Petitioners is on account of various non-attributable factors discussed at relevant section below.
- z. The capacity has increased and capacity utilization of the Domestic Industry seems to have decreased. The Petitioners herein are conveniently seeking to provide the capacity data of the other producers of the PUC when they have consciously excluded the said producers from the ambit of “domestic industry”.

- aa. Surana Solar Ltd.- the Petitioners are seeking to rely on its injury analysis at paragraph 113, it is evident that the company has been consistently making profits from the year 2013.
- bb. XL Energy at page 43 of their Annual Report 2016-2017 has stated that capacities were unutilized due to the industry downturn and resultant fall in demand.
- cc. The Exporters submit that the averment made by the Petitioners in respect of Euro Multivision must be rejected as alleged injury to Euro Multivision was self-inflicted and was not on account of imports.
- dd. Alleged declining trend in the productivity of the domestic industry is clearly on account of the Petitioners' own inefficiencies.
- ee. It is reiterated that since Mundra is a newly established company – it should have certainly incurred certain setup costs, production costs and overheads (which ought to have been higher than any other established company) – consequently affecting the overall performance of the domestic industry in respect of the PUC.
- ff. The Hon'ble Designated Authority should determine if the exports of the said Petitioners have decreased and thereby, have led to the alleged increase in inventory.
- gg. The serious injury, if any, suffered by the Domestic Industry is self-inflicted. The steep decline in tariff was, in part, result of decline in international price of solar modules. For Petitioners to compete in this market, they needed to drop its prices in line with the lower bid made by the solar power developers and the declining international prices.
- hh. The decrease in auction activity can be attributed to factors such as weak financial condition of DISCOM, inefficient transmission, less power demand and increase in captive generation by commercial and industrial companies, and the WTO ruling against India's DCR in its renewable energy policy.
- ii. The Solar Energy Corporation of India and the NTPC have set a maximum capacity for a single bidder at 1800 MW and 2000MW and the same is being protested by leading developers in the solar market.
- jj. One of the Petitioning Companies, Indosolar Limited vide their "Statement of Audited Financial for the Quarter and Year ended on 31 March 2018" have reported exceptional items losses on account of impairment of plant and machinery under installation during the end of 2017.
- kk. The company lost over 300 crores in this period, for reason completely unrelated to the impugned imports.
- ll. Helios Photo Voltaic Limited (in short "Helios") - the operations of the company were affected due to stoppage of work for a period of 34 days.
- mm. Helios vide the:
 - (i) liquidity constraints faced by the company have critically impacted their ability to enhance their manufacturing operations and capacity utilization levels.
 - (ii) concern of inability to be cost effective due to lack of consistent demand because of intermittent release of tenders.
- nn. Websol Energy System - there was no full production for the quarter that ended March 2018.
- oo. Indosolar Limited at page 16 of the Annual Report 2014-15 has stated that capacities were unutilized due to the industry downturn and resultant fall in demand.
- pp. The petitioners reduce their costs by reducing the raw material prices in pursuance to renegotiation by entering into long-term contracts – it is respectfully submitted that such a practice should have been followed regardless of safeguard duties being levied.
- qq. If the Petitioners are taking up forward and backward integration projects for reducing their costs – it is submitted that the profit-making Petitioning companies like Mundra Solar PV Ltd (Adani Group) cannot be short of any resources to enter into such long-term projects and thereafter can effectively be successful in reducing their costs as part of the adjustment plan. Petitioners plan to reduce financing cost by converting Rupee borrowings into USD borrowings – the Exporters submit that the Petitioners have failed to explain how they plan to convert Rupee loans to USD loans and what would be the basis and commercial terms of such conversion, if possible at all.
- rr. The levy of safeguard duty on PUC would be against public interest of India as it would have a huge negative impact on solar market in India for the following reasons.
 - (i) The Designated Authority should not recommend any safeguard duties on the PUC and terminate the investigation as the ultimate impact would be on the users of the PUC in the solar market due to imposition of duties.

- (ii) If safeguard duty is levied on the PUC which will in turn effect the entry of advance technology imports – the domestic market would not be able to meet the increasing demand in Indian solar market.
- (iii) If safeguard duty is imposed it will lead to a situation of loss of jobs.

SS. There are no unforeseen developments that could have caused increase in imports in India, there is no serious injury to the domestic industry on account of imports and existence of break in causal link between increased imports and injury on account of self-inflicted injury to domestic industry – the averment of the Petitioners that 95% of safeguard duty be imposed is ought to be rejected by the Hon'ble Designated Authority in public interest.

(xiii) M/s ACME Solar Holdings Ltd. (“Acme Solar”) and M/s ACME Cleantech solutions Private Ltd. (“ACME Cleantech”)

- a. Section 2(e) of the Safeguard Duty Rules define ‘like articles’ as, “an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation”.
- b. Differences in c-Si & thin film
 - (i) Solar cells made from thin film technology and Solar cells made from c-Si technology cannot be substituted or mixed with each other.
 - (ii) Solar cells manufactured using c-Si technology are made through a process involving growth of crystals from crystalline silicon, production of wafers and thereafter conversion of wafers into cells, while under the thin film technology, thin PV material are placed onto dye sensitized substrates such as glass or stainless steel.
 - (iii) Solar cells manufactured using c-Si technology have higher wattage output and higher conversion efficiencies in comparison to solar cells manufactured using thin film technology.
 - (iv) Solar cells made from c-Si technology are space efficient but costly and they are mostly used for residential and small areas while solar cells made from thin film technology are opposite in terms of space and price from the latter and they are used for areas having high temperatures and larger space.
- c. Domestic Industry in its written submissions have admitted that they don't manufacture solar cells using thin film technology.
- d. The Domestic industry, whose total production by their own admission is 381 MW, constitute a mere 7.5% of the total production of the PUC in the country. The MNRE is annexed as Annexure “A” in the rejoinder submission.
- e. Balance sheet of two of the companies included in the DI, who were operational during the POI viz. Jupiter solar and Websol shows a clear considerable increase in revenues.
- f. Domestic Industry has contended that the imposition of Safeguard duty would result in increase of tariff by INR/kWh 0.70 which would lead to a meagre increase of tariff to INR/kWh 3.14. The rate of safeguard duty as proposed by the DI (i.e. 95%) is hypothetical and not based on any empirical study of data and other factors involved therein.
- g. The tariff would increase from INR 2.87/kWh to INR 3.56/kWh, if safeguard duty is levied @25% to INR 3.67/kWh, if safeguard duty is levied @30% and to INR 4.54/kWh if safeguard duty is levied @70% thereby resulting in a considerable increase in tariff corresponding to the rate at which safeguard duty is levied.
- h. Levying safeguard duty on the product will be contrary to public interest because the gap between demand and supply of PUC will increase manifold due to weak capacity utilization by the DI and it would delay the plans stipulated under the NSM.

D. EXAMINATION & FINDINGS OF DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)

- 17. Based on the submissions made by various interested parties in response to Initiation, preliminary finding and Public hearing, various primary and secondary records available, Domestic verification undertaken, I have examined concerns on various aspects and record my final finding as under:
- 18. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of safeguard duty on imports. Its sub-section (1) provides for imposition of safeguard duty by the Central Government on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.
- 19. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provide the manner and principles governing investigation.
- 20. The investigation has been conducted in accordance with the said rules and the final findings are recorded through this notification.

a) The Product Under Consideration (PUC)

21. In the preliminary finding, the following was held regarding PUC:

- (i) *“The PUC is “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” classifiable under Tariff Heading 8541 and Tariff Item 85414011 of the Customs Tariff Act, 1975. Solar Cells are also known as Photovoltaic Cells in the market parlance. Photovoltaic technology enables direct conversion of sunlight into electricity at the atomic level and Solar Cells are solid state electrical devices that convert sunlight directly into electricity by the photovoltaic effect. For practical use, Solar Cells are packaged and connected into an assembly and such an assembly of Solar Cells is referred to as a Solar Panel or Solar Module. The electrical connections are made to the Solar Cells in series to achieve desired output wattage and / or in parallel to provide a desired current capability.*
 - (ii) *The PUC is being manufactured using either of the two major technologies: (1) Crystalline Silicon (c-Si) based Solar Cell technology, also known as Silicon Wafer based technology, and (2) Thin Film technology. The c-Si technology may use n-type and p-type Silicon, and also mono crystalline and multi crystalline Silicon materials. The Thin Film technology may use Amorphous Silicon, Cadmium Tellurium (CdTe) or Copper Indium Gallium Selenium as semi-conductor materials. Solar Cells based on both c-Si technology and Thin Film technology are imported into India.*
 - (iii) *The applicants manufacture Solar Cells / modules / panels using only c-Si technology and not Thin Film technology. The applicants have claimed that Solar Cells based on both c-Si and Thin Film technologies are used in Solar power plants. According to the applicants, the Central Government projects such as Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM) or projects of various State Governments neither differentiate the technologies nor award separate auction price for projects based on different technologies. Moreover, there are no material differences between Solar Cells based on either of these technologies and these are all meant for the same end uses. Therefore, the applicants contend that the domestically produced PUC based on c-Si technology are like and directly competitive products to the imported PUC based on either c-Si technology or Thin Film technology.”*
22. Some interested parties have submitted that DI does not possess Thin-film technology and “PERC” (Passivated Emitter Rear Cell) based technology, & Bi-facial N-type solar cells; High efficiency solar cells using 5 and 6 bus bar production terminology; and Solar modules of mono crystalline technology and therefore PUC should be restricted only to the scope of production capability/ production by the DI. I have carefully examined this aspect and noted that Solar cells of various types produced by different technologies vary in terms of efficiency, price, physical characteristics, like size and weight etc. These variations though lead to trade off in price and efficiency, the final usage of the PUC is only to produce power.
23. The Safeguard duty rules (Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 – Notification No. 35/97-NT-Customs dated 29.07.1997(hereinafter called as Safeguard Rules) hold a domestic producer as “a producer of the like article or directly competitive article in India or a trade or business association, a majority of members of which produce or trade the like article or directly competitive article in India” and “like article” defined as “like article means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation.” The common and overlapping applications of PUC establishes that imported and domestically produced subject goods are directly competitive. This therefore does not warrant any exclusion from the scope of PUC as stated in initiation notification. I therefore uphold and confirm the scope of PUC as considered and mentioned in para 5.1 of the preliminary finding dated 5.01.2018.

b) Scope and Standing of Domestic Industry (DI)

24. Clause (b) of sub-section (6) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 defines Domestic Industry (hereinafter also referred to as the “DI”), as follows:

‘(b) “Domestic industry” means the producers -

- i. as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
- ii. whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.’

25. As regards scope and standing of the DI, in the initiation dated 19.12.2017 and the preliminary finding dated 5.01.2018, the applicant considered included SEZ units as well in the scope of the DI. The justification in the preliminary finding for this scoping was as under:

“The SEZ scheme, an export promotion scheme of the Ministry of Commerce and Industry, Government of India extends certain fiscal and non-fiscal benefits to the units operating thereunder with a view to encourage exports and that by creating a legal fiction, the SEZ units are treated as if these are outside India. However, the SEZ units are physically very much in India and in like manner of other domestic manufacturing units, these units adhere to domestic laws (though at times with some relaxations), generate employment, make domestic sales etc. Thus, increase in imports of any item also impacts SEZ units in like manner as it does any other domestic producer operating outside

the SEZs. Therefore, the applicant SEZ units qualify as part of the DI (indeed, by virtue of the quantum of production of the applicants, as the DI itself). All other SEZ units that are similarly engaged in production of like or directly competitive products would also be treated as a part of the DI".

26. However, post initiation and preliminary finding and further in response to the Public hearing (both submissions and rejoinders) many interested parties have argued for exclusion of SEZ units from the scope of DI on the following grounds.

Submissions by Interested parties other than Domestic Industry.

- a. Three out of five applicant domestic producers are located in SEZ and cannot be treated as domestic industry as SEZ area is deemed to be territory outside India and all governing legislations for import or export goods will apply to them. Goods produced by an SEZ unit cannot be said to be domestically manufactured. Initiation is therefore bad in law in view of Section 53 of Special Economic Zone Act, 2005 (SEZ Act) which provides that SEZ is deemed to be a territory outside the custom territory of India
 - b. As per Section 30 of SEZ Act and para 6.08 of Foreign Trade Policy, units located in SEZs and EOU are deemed to be situated outside India, and therefore cannot be considered as DI.
 - c. The fundamental objective of establishing of SEZ units is promotion of exports. Areas of the SEZ are excluded from the definition of Domestic Tariff Area and removals therefrom are subject to duties of customs. DTA sale of goods manufactured by a SEZ unit can be made only on submission of import license. The contentions for treating the SEZ unit as part of the DI are not acceptable.
 - d. The term used in the safeguard law is 'producers in India' and SEZ unit are deemed to be a territory outside the customs territory of India. SEZ or EOU units focus is on export market and do not compete primarily in domestic market whereas purpose of safeguard law is to protect the Domestic Industry from import competition in domestic market. Therefore, EOU and SEZ may form DI only to the extent of their entitlement permitted under the extant laws. Developers and Co-developer units in the SEZ's are given various exemptions and concessions under the SEZ Act, 2005 in the form of tax and fiscal benefits with a view to increase exports and therefore operate in a different sphere.
 - e. DA has made findings on a principle of law w.r.t. SEZ's not being part of the DI and the same should be followed since DA is a quasi-judicial body and must maintain uniformity in decision making process. In final findings of DG Safeguards dated 27 September 2012 in Electrical Insulators case, WSI Industries (located in SEZ) was also excluded from the scope of the domestic industry.
 - f. Increase in imports do not result in impact on units in SEZ. There are number of cases where the Authority has regarded SEZ to not be a part of DI. Resultantly, these three complainants cannot be considered to be a part of the domestic industry (DI) and the remaining complainants do not cross the threshold of 'collective output constituting a major share of total article in India', which results in such a standing requirement not being satisfied.
 - g. In the "Safeguard investigation concerning Imports of 'Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)' into India", DG-Safeguards has not considered SEZ units as part of DI.
 - h. 5 DI Companies would constitute only 3.25% of the domestic production of modules. In PF, DG has not examined standing of 5 DI Companies with respect to modules and instead, assessed their standing by taking solar cells and modules together.
 - i. As a result of such exclusion, the installed capacity and other economic data with respect to Mundra and Helios are to be excluded (specifically Mundra's 2400 MW installed capacity), which would render the contribution of DI in production of PUC to a mere 5.73% and would effectively disqualify remaining applicants as DI.
27. I have carefully gone through the arguments of both sides. The past decisions of DG Safeguards in Safeguard finding of **"Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)" and "Electrical Insulators" have been recalled. The following aspects regarding the SEZ units are underscored in this regard:**
- a) **The SEZ Act, 2005 was enacted to provide for the establishment, development and management of the Special Economic Zones for the promotion of exports and for matters connected therewith or incidental thereto.**
 - b) **Domestic Tariff Area in section 2(i) of the SEZ Act, 2005 means** the whole of India (including the territorial waters and continental shelf) but does not include the areas of the Special Economic Zones.
 - c) As per Section 2(m) (ii) of the SEZ Act, 2005 "export" means "supplying goods, or providing services, from the Domestic Tariff Area to a Unit or Developer.
 - d) Section 30 of the SEZ Act, 2005 provides that:

“Subject to the conditions specified in the rules made by the Central Government in this behalf:-

- (a) any goods removed from a Special Economic Zone to the Domestic Tariff Area shall be chargeable to duties of customs including anti-dumping, countervailing and safeguard duties under the Customs Tariff Act, 1975, where applicable, as leviable on such goods when imported; and
- (b) the rate of duty and tariff valuation, if any, applicable to goods removed from a Special Economic Zone shall be at the rate and tariff valuation in force as on the date of such removal, and where such date is not ascertainable, on the date of payment of duty.”

e) Section 53 of the SEZ Act, 2005 further provides that:-

“(1) A Special Economic Zone shall, on and from the appointed day, be deemed to be a territory outside the customs territory of India for the purposes of undertaking the authorized operations.

(2) A Special Economic Zone shall, with effect from such date as Central Government may notify, be deemed to be a port, inland container depot, land station and land customs stations, as the case may be, under section 7 of the Customs Act, 1962:

Provided that for the purposes of this section, the Central Government may notify different dates for different Special Economic Zones.”

f) Rule 47 of the Special Economic Zones Rules, 2006 states as under:

“Sales in Domestic Tariff Area — (1) A Unit may sell goods and services including rejects or wastes or scraps or remnants or broken diamonds or by-products arising during the manufacturing process or in connection therewith, in the Domestic Tariff Area on payment of customs duties under section 30, subject to the following conditions, namely:

Domestic Tariff Area sale under sub-rule (1), of goods manufactured by a Unit shall be on submission of import licence, as applicable to the import of similar goods into India, under the provisions of the Foreign Trade Policy”

g) As per Section 2(o) of SEZ act, 2005 “import” means-

- (i) bringing goods or receiving services, in a Special Economic Zone, by a Unit or Developer from a place outside India by land, sea or air or by any other mode, whether physical or otherwise; or
- (ii) receiving goods, or services by, Unit or Developer from another Unit or Developer of the same Special Economic Zone or a different Special Economic Zone;

h) Section 53, Sub-rule (1) and (2) provides for considering certain DTA clearances towards counting of NFE. SEZ is deemed to be a territory outside the customs territory of India and is also deemed to be a port, inland container depot, land station and land customs stations, as the case may be, under section 7 of the Customs Act, 1962.

i) The above provisions and features of SEZ Act and SEZ units therein establish that though SEZ units are a part of India in terms of territorial sovereignty considerations but they have been economically delineated from the DTA to attain a specified objective of exports ‘DTA sales’ though permitted under the SEZ Act/Rules thereof are only exceptions and not a business as usual model like a domestic producer in DTA primarily focussing on home market sales. There could be instances where in, the conditions of DTA clearances may be quite conducive and liberal for a SEZ unit but it in no way alters or modifies the prime objective of SEZ unit to remain export oriented.

j) Though section 2(i) of SEZ Act does not specifically mention about DTA clearances by a SEZ unit as an import in the DTA, but such clearances are subjected to duties like Anti-dumping duty, Countervailing duty and Safeguard duty as applicable in accordance with section 9A and section 8B of the Custom tariff Act, 1975. Section 30 of SEZ Act, 2005 stipulating collection of applicable Anti-dumping, Countervailing and Safeguard duties requires filing of a bill of entry which validates the fact that such DTA clearances are infact to be treated as imports. Therefore the following is concluded:

- (i) The fundamental objective of establishing SEZ units is promotion of exports governed by a specific SEZ Act, 2005. The area of SEZ are excluded from the definition of DTA under section 2(i) of SEZ Act, 2005. Supply of goods from DTA to SEZ constitutes exports.
- (ii) DTA sale of goods manufactured by a SEZ unit can be made only on submission of import licence, as applicable to the import of similar goods into India. Sale or clearance of goods from SEZ to DTA is subject to various duties i.e. Anti-dumping duty, Countervailing duty and Safeguard duty imposed as per section 9 and 8B respectively as per Custom Tariff Act, 1975 and levied as per Section 30 of SEZ Act, 2005.
- (iii) EOU’s are governed by specific Foreign Trade Policy provisions and its sales to SEZ units are considered as export. The Foreign Trade Policy provisions also apply to DTA units as well as to those who wish to undertake

imports/exports. Further DTA clearances by an EOU are liable for payment of applicable Excise duties/taxes. They operate outside the SEZ territories quite analogous to normal DTA units in the same ecosystems

- (iv) Therefore, on the basis of the above, I hold that the provision of Sales to DTA by a SEZ unit as an exception with features varying in different cases, does not justify a SEZ unit to be considered as a domestic producer in the context of trade remedial measures keeping in view the context of the larger framework of SEZ Act, 2005. Therefore the scope of DI in this investigation is restricted only to the producers i. e. M/s Indosolar Limited (EOU) and M/s Jupiter Solar Power Limited, which includes the EOU unit also, since they are physically located in DTA governed by Foreign Trade Policies though with export orientation.
- (v) With the exclusion of 3 SEZ units, the DI is now restricted to M/s Indosolar Limited and M/s Jupiter Solar Power Limited which collectively account for 38% of the total domestic production in the DTA. The support of ISMA rendered through the resolution of its managing committee and with no opposition qualifies the 2 applicant units meeting the requirements of major share of Indian Industry.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (Upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Total Indian production	MW	170	206	587	421	842
Production of the DI (applicants)	MW	141	191	314	159	318
Share of production of the DI in total Indian production	%	83	93	53	38	38

- (vi) I notice that certain module manufacturers who have imported cells have made submissions for being considered part of the domestic industry. Since 'PUC' which itself being imported in entirety to be converted to modules, such entities qualify only as importers and not as part of DI. The two producers mentioned in para (v) above constitutes DI in terms of Clause (b) of the Sub Section (6) of Section 8B of the Custom Tariff Act, 1975.

c) Period of Investigation

28. The Customs Tariff Act, 1975 and the said Rules as well as the WTO Agreement on Safeguards and Article XIX of GATT neither define nor provide guidance regarding the period of investigation. However, it is evident that the investigation period should be adequately long and sufficiently recent in time to allow reasonable conclusions to be drawn on the basis of various relevant factors such as domestic market conditions, performance of DI etc., as to whether or not the increased imports are indeed causing serious injury or threatening to cause serious injury to the DI and therefore justify the need for imposition of Safeguard Duty. On this basis, in the present case, it is considered reasonable and just to determine the period of investigation (POI) as 2014-15 to 2017-18 (Annualized).

d) Source of Information

29. The DI at the time of initiation submitted transaction-wise import data for the PUC, which has been sourced from: (i) Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S), Department of Commerce, Government of India for the period from 2014-15 till the end of First Quarter of 2017-18; and (ii) M/s Infodrive India, New Delhi for the period of the second quarter (July, 2017 to September, 2017) of 2017-18. The corresponding data for the period 2014-15 to 2017-18 (upto September, 2017) in respect of the DI itself has been submitted by the applicants and the same was verified on the basis of their (i) cost audit reports; (ii) financial records; (iii) various other records pertaining to production, sales, inventory etc. at the time of initiation. In addition, the import data for the period July, 2017 to September, 2017 was separately obtained from DGCI&S, Ministry of Commerce, Kolkata at the stage of Preliminary Finding. This data was taken into consideration for analysis for the Preliminary Finding. Subsequently transaction wise data for entire injury period i.e. 2014-2015 to 2017-2018 was called for from DGCIS for the Final Finding and the same has been adopted for computation of landed value of PUC for determination of Injury Margin.

e) Confidentiality and information submitted

30. The DI have provided some information in their application on confidential basis and has requested that it be treated as confidential. The DI have also provided a non-confidential version (NCV) of their application, as required under Rule 7 of the said Rules read with Trade Notice dated 21.12.2009 issued by

Director General (Safeguards) under File No. D-22011/75/2009. Further, the DI have submitted reasons justifying their claim of confidentiality of this information.

31. In terms of Rule 7 of the said Rules, the applicant may choose not to disclose information which is by nature confidential and provide a non-confidential summary thereof. The DI have submitted reasons for claiming confidentiality of the information and furnished a non-confidential summary of the information filed on confidential basis. Upon a careful examination of the reasons advanced by the DI, I find that these reasons satisfy the requirements of Rule 7 of the said Rules. Accordingly, the confidentiality claimed by the applicants is hereby granted.

f) Nature and quantum of import

a) Absolute terms

The PUC is being imported into India from various countries including China PR, Malaysia, Singapore and Taiwan. The major quantity of the PUC is being imported from China PR. As seen, the import volumes of the PUC have increased from 1,275 MW in 2014-15 to 9,833 MW in 2017-18 (Annualized). As per the updated DGCIS for 2017-18 the total imports of PUC are 9790 MW. This is an increase of 671% in 2017-18 (Annualized) (668% as per actual) from the base year 2014-15. Thus, there is no doubt that the import volumes have increased significantly each year. Moreover, there has been a sudden surge in imports volumes during the first six months of 2017-18 which is 77% of the imports in 2016-17. The increasing import volumes of the PUC both in absolute terms and percentage. terms during the period 2014-15 to 2017-18 (Annualized) is indicated in the table below.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)	2017-18 Actual
Total imports	MW	1,275	4,186	6,375	4,917	9,833	9790
% increase in imports over previous year	%	-	228	52	-	54	54

b) Relative terms

Relative to domestic production, imports of the PUC are found to have consistently increased between 2014-15 and 2017-18 (Annualized). The growth rate of such imports as a percentage of the domestic production was a remarkable 2036% during the intervening year 2015-16. Even the overall growth rate of the imports of the PUC relative to its domestic production is very significant, rising from 750% in 2014-15 to 1169% in 2017-18 Thus, during the entire POI, the import volumes of the PUC relative to its domestic production have consistently increased significantly, as indicated in the table below.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (Upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Total imports	MW	1,275	4,186	6,375	4,917	9,833
Indian production	MW	170	206	587	421	842
Imports as a % of Indian production	%	750	2036	1086	1169	1169 (*)

***Based on the actual imports during the period 2017-18, the import as a% of Indian production comes to 1162.**

g) Unforeseen developments

32. I recall and reproduce the finding in the preliminary determination in this regard:

“5.8.1 Neither Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 nor the Rules made thereunder impose an obligation on the Director General (Safeguards) to analyse the unforeseen developments as a result of which the increased imports have occurred. The legal provisions neither contain any parameters that must be verified to identify the unforeseen developments nor do they specify any

methodology that must be followed in the analysis of such unforeseen developments. However, the WTO Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT obligates the national authorities to examine “unforeseen developments” that led to the increase in imports and the consequent serious injury to the DI. In view of this requirement, this Directorate has consistently been examining the issue of “unforeseen developments” in its investigations. Therefore, even in the present case, it is considered appropriate to examine the unforeseen developments or circumstances that have led to the sharp increase in the imports of the PUC during the period of investigation. However, in order to do so, it is necessary to first appreciate the import of the term “unforeseen developments or circumstances” and for this, a reference needs to be made to various rulings of the Appellate Body of WTO.

5.8.2 The Appellate Body of WTO in *Argentina–Footwear (EC)*³ case held that imports in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers, must have been ‘unexpected’. In that case it was also held that the development of increased imports must have been due to “unforeseen developments”. Similarly, the Appellate Body of WTO in *Korea–Dairy*⁴ case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation. In that case it was also recognized that unforeseen developments are circumstances which must be demonstrated as a matter of fact. In another case, the Panel on *US–Steel Safeguards*⁵ concluded that the confluence of several events can unite to form the basis of an unforeseen development. It was also noted that increased imports must be an outcome of unforeseen developments i.e., it is the unforeseen developments that resulted in increased imports.

5.8.3 Applying the aforementioned findings to the present case, it is clear that the temporal nature of the increase in imports of the PUC so as to cause serious injury to the DI or give rise to a threat of such serious injury must have been unforeseen or unexpected and factual. Whereas the event of increased imports itself must be demonstrable on the basis of data on imports, a finding on its unforeseen or unexpected nature must be contextual. In the present case, a relevant context for this would be the event or events that resulted in tariff concessions on the import of the PUC into India. In other words, the factum of increased imports of the PUC during the POI must have been unforeseen at the time of incurring the obligations i.e., accession to WTO, resolving to abide by the commitments under various WTO Agreements, providing tariff concessions and subsequently amending those tariff concessions through the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products (ITA-1) on 13th December, 1996.

5.8.4 In the context of determining if the present development of a significant and sharp increase in imports of the PUC during the POI was indeed an unforeseen or unexpected development, the evidence furnished by the applicants has been examined and the findings thereon are, as follows:

- (i) China⁶ has more than doubled its production capacity of Solar Cells from 11.12 GW in 2012 to 27.78 GW in 2016. Similarly, the production capacity of Solar Modules increased from 12.46 GW in 2012 to 35.47 GW in 2016. Further, data of 35 producers who collectively account for 57% of Solar Cells and 67% of Solar Modules production in China reveals excess capacity, as indicated in the table below. This aspect of having a huge production base coupled with excess capacity have a bearing on the applicants' case that there has been a surge in imports of the PUC from China.

Solar Cells					
In GW	2012	2013	2014	2015	2016
Capacity (Cells)	16.70	19.30	22.19	26.46	33.13
Production (Cells)	11.12	14.03	18.54	22.72	27.78
Domestic consumption	10.68	13.06	17.31	22.26	26.76
Exports	0.40	0.81	0.87	0.52	0.50

³ Appellate Body Report, *Argentina – Footwear (EC)*, para. 91
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds121_e.htm;

⁴ Appellate Body Reports, *Korea – Dairy*, para. 85 and 89
[\[https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds98_e.htm\]](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds98_e.htm).

⁵ Appellate Body Report, *US – Steel Safeguards*, para. 315
[\[https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/248_259_abr_e.pdf\]](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/248_259_abr_e.pdf).

⁶ Findings of the United States International Trade Commission [USITC] in Section 201 proceedings against Crystalline Silicon Photovoltaic Cells (Whether or not Partially or Fully Assembled into Other Products) - Publication No. 4739
[\[https://www.usitc.gov/trade_remedy/731_ad_701_cvd/investigations/pub4739-vol_i_and_vol_ii_0.pdf\]](https://www.usitc.gov/trade_remedy/731_ad_701_cvd/investigations/pub4739-vol_i_and_vol_ii_0.pdf)

Idle capacity	33.41%	27.31%	16.49%	14.13%	16.15%
Solar Modules					
Capacity (Solar Modules)	20.13	22.77	27.99	34.71	46.40
Production (Solar Modules)	12.46	16.32	22.07	28.79	35.47
Domestic consumption	2.46	5.94	7.73	12.86	20.69
Exports	9.61	10.39	13.64	15.62	13.93
Idle capacity	38.10%	28.32%	21.15%	17.05%	23.99%
Exports share in production	77.12%	63.66%	61.80%	54.25%	39.27%

- (ii) China's export orientation in respect of the PUC is unquestionable, but a material fact that emerges is that during the past two years, both its direction and volume of export trade changed in a significant manner towards India, as is established from the table below. To illustrate, while China's exports to India constituted a paltry 1.52% of its total global exports during 2012, this increased to 21.58% during 2016.

Chinese Exports To (USD 000')⁷	2012	2013	2014	2015	2016
World	12,775,263	10,150,759	12,319,183	12,938,427	11,347,462
Japan	892,923	2,794,236	4,394,922	3,341,833	2,558,724
India	193,756	510,278	488,619	1,356,754	2,448,216
USA	1,416,963	1,208,074	1,818,175	1,634,799	1,368,664
EU	8,283,128	2,914,197	2,352,842	2,054,177	1,288,605
Share of India	1.52%	5.03%	3.97%	10.49%	21.58%
Share of EU + USA	75.93%	40.61%	33.86%	28.51%	23.42%

- (iii) The aforementioned shift in direction of Chinese exports of the PUC to India gets re-confirmed from the data of more current times. As indicated in the table below, during the first half of 2016 (H1 2016) Chinese exports to India were 18.51% of its total exports, as compared to which its combined exports to EU and USA were 30.65% (of its total exports). The situation turned dramatically during the succeeding two half yearly periods. In the second half of 2016 (H2 2016), China's exports to India constituted 25.09% while its exports to EU & USA fell to 15.12%. Again, in the first half of 2017 (H1 2017), China's exports to India increased to a staggering 38.77% of its total exports while its exports to EU and USA shrunk to just 5% (of its total exports). Such a significant shift in pattern of trade in which China started targeting the Indian market more vigorously as compared to developed countries / markets like EU and USA etc. could not have been foreseen.

Chinese Exports To (USD 000')⁸	H1 2016	H2 2016	H1 2017
World	6,062,679	5,284,783	5,350,966
India	1,122,083	1,326,133	2,074,573
Japan	1,219,493	1,339,231	1,095,773

⁷ www.trademap.org

⁸ www.trademap.org

EU	838,606	450,002	233,481
USA	1,019,870	348,793	34,268
Share of India	18.51%	25.09%	38.77%
Share of EU + USA	30.65%	15.12%	5.00%

5.8.5 Another unforeseen development that contributed in the surge in imports of the PUC in India and a shift away from other foreign markets was the imposition of trade remedy measures by the EU and USA on imports from China. The Anti-dumping and Countervailing duty orders in the USA associated with (i) the Crystalline Silicon Photovoltaic (CSPV 1) investigations became effective on 07.12.2012 and (ii) the CSPV 2 investigations became effective on 18.02.2015. Also, in the EU, the provisional measure came into effect on 05.06.2013 [Commission Regulation (EU) No. 513/2013 of 04.06.2013] and the final measure was imposed on 05.12.2013 [Commission Regulation (EU) No. 1238/2013 of 02.12.2013]. The immediate impact of these measures was not visible in India because of the requirement of Domestic Content Requirements (DCR) under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM). Thus, the DI had the assurance of a captive domestic market to the extent dictated by the DCR. However, in 2013, the USA challenged the DCR under JNNSM before the WTO Dispute Settlement Body and the outcome was that in October 2016, the WTO Appellate Body held the DCR to be inconsistent with Article III:4 of the GATT 1994 and Article 2.1 of the TRIMs Agreement. Hence, India withdrew the DCR. Pursuant to the withdrawal of DCR, the changes in the pattern of trade became more pronounced with imports of the PUC increasing substantially. As afore stated, these developments could not have been foreseen.

5.8.6 In 2015, India committed to the Paris Agreement on climate change for reduction of CO₂ emissions by 33-35% from 2005 levels, to address global warming. In line with this commitment, India established a target of achieving 100 GW of Solar power generation by the year 2022. This commitment pushed up the demand for Solar power generation projects in India. It is clear that the commitment given by India under the Paris Agreement that was signed by 197 countries (as on date ratified by 172 countries) was unforeseen at the time the import tariff concession for the PUC was agreed to under ITA-1 on 13th December, 1996. Similarly, the huge increase in the demand for the PUC in India in a short period of time which has in part fuelled the surge in imports was also unforeseen.

5.8.7 Another relevant factor that has emerged is that the imports of the PUC are taking place at very low prices; there has been a sudden and appreciable drop in the landed value of the imported PUC, as evident from the table below. The immediate impact of this has been that the Domestic Industry faced a drop in sales realisation of their products. Thus, the surge in imports at consistently falling landed price changed the competitive relationship between imports and domestic production, to the disadvantage of the latter. This has hampered the DI's ability to compete and make and sell the PUC. It is but evident that this change in the competitive relationship was entirely unforeseen.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Landed value of imports						
Solar Cells	Rs./Watt	18.78	18.81	15.42	14.04	14.04
Solar Modules	Rs./Watt	36.95	36.18	29.20	24.77	24.77
Net sales realisation of Domestic Industry						
Solar Cells (Indexed)	Rs./Watt	100	94	88	62	62
Solar Modules (Indexed)	Rs./Watt	100	103	82	92	92

5.8.8 India's import tariff on the PUC falling under Customs Tariff Item 85414011 of the Customs Tariff Act, 1975 is 'Free'. This 'Free' tariff was introduced pursuant to the obligations on India under GATT 1994, including the tariff concessions thereunder read with the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products dated 13th December, 1996 (hereinafter also referred to as the "ITA-1"). The PUC is covered under Attachment A, Section 1 of the ITA-1. The ITA-1 mandated elimination of Customs duties and other duties / charges of any kind within the meaning of Article II:1(b) of GATT 1994 on the products listed

therein. Since India is a signatory to ITA-1, the imports of PUC are free of Customs duties. Thus, ITA-1 binds India's "freedom of action"⁹ with respect to the imported PUC and prevents it from taking other WTO-consistent measures, such as increasing the Customs duties. It merits mention that India truly believed that its DCR under JNNSM was consistent with the exceptions contained in Article XX of GATT 1994, but after the rejection of this measure by the WTO Appellate Body in 2016, the Indian market for the PUC became open for unrestricted imports from all countries. Thus, India's obligation under GATT 1994 and ITA-1 to allow unrestricted tariff free imports of the PUC without giving preference to domestic production has led to a significant and unforeseen increase in the import volumes of the PUC into India.

5.8.9 The conclusion is that the sudden and sharp increase in imports of the PUC during the POI is an outcome of a combination of various global and domestic events, all of them unforeseen and unexpected. For purposes of clarity, these unforeseen and unexpected developments are briefly reiterated, as follows:

- (i) When faced with hindrances in exports to the EU and USA, China's huge production and excess capacities of the PUC which even otherwise is export oriented, had to find an alternative outlet, which they found in India;
- (ii) The imposition of protective measures on the PUC imported from China into the EU and USA shifted China's export focus towards India;
- (iii) The USA challenge to India's DCR under JNNSM resulting in the WTO Dispute Settlement Body holding the DCR to be inconsistent with Article III:4 of the GATT 1994 and Article 2.1 of the TRIMs Agreement, led to its withdrawal and consequential surge in imports to fill the space lost by the DI;
- (iv) India's commitment to the 2015 Paris Agreement paved the way for a domestic commitment to enhance the use of the PUC, which coupled with other events led to a surge in imports;
- (v) Declining landed price of the increasing imports of the PUC combined with other factors to change the competitive equation and place the DI at a disadvantage which was manifested in them i.e., the DI losing its share of the domestic market of the PUC to the imports; and
- (vi) India's obligations under GATT 1994 and the ITA-1 led to its Customs tariff on the imports of the PUC being made 'Free'.

5.8.10 As a result of the various aforementioned global and domestic unforeseen and unexpected developments, there has been an unquestionable verified surge in imports of the PUC into India. This surge in imports has significantly modified the competitive relationship between the imported and domestically produced PUC to the disadvantage of the DI."

33. **Post preliminary finding and public hearing:-** a number of interested parties have made submissions that the development reported of unforeseen are indeed foreseen nature. For the sake of clarity, these issues have been examined though there could be some repetition of analysis which has been done to emphasize and clarify contentions.
34. I have examined the provisions of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 and the Indian Safeguard Rules. Neither of the two obligates me to analyse the (i) unforeseen developments; and (ii) the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, as a result of which the increased imports have occurred. The legal provisions neither contain any parameters that must be verified to identify the unforeseen developments nor do they specify any methodology that must be followed in the analysis of such unforeseen developments. However, I recognise that the WTO Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT obligates the national authorities to examine both factors that led to the increase in imports and the consequent serious injury to the Domestic Industry. In view of this requirement, the DG Safeguards has consistently been examining the issue of "unforeseen developments" and "obligations incurred under GATT" in its investigations. Therefore, even in the present case, I consider it appropriate to examine both factors that have led to the sharp increase in the imports of the PUC during the period of investigation.
35. The Preliminary Findings record the legal standard laid down in the various WTO Appellate Body Reports and Panel Reports. I have examined the same in detail and various contentions made by the interested party. I observe that the legal test has been correctly outlined. For ease of reference, the same is explained again. The Preliminary Findings relied on the Appellate Body of WTO in *Argentina–Footwear (EC)*¹⁰ case in which it was held that imports in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause

⁹ Panel Report, *Ukraine – Passenger Cars*, para. 7.96. [[http://www.worldtradelaw.net/reports/wtopanels/ukraine-passengercars\(panel\).pdf.download](http://www.worldtradelaw.net/reports/wtopanels/ukraine-passengercars(panel).pdf.download)]

¹⁰ Appellate Body Report, *Argentina – Footwear (EC)*, para. 91
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds121_e.htm;

serious injury to domestic producers, must have been unexpected. In that case it was also held that the development of increased imports must have been due to “unforeseen developments”. Similarly, the Appellate Body of WTO in Korea-Dairy¹¹ case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation. It was also recognized by the Appellate Body that unforeseen developments are circumstances which must be demonstrated as a matter of fact.

36. The interested parties have argued that unforeseen development is *not what the specific negotiators had in mind but rather what they could (reasonably) have had in mind*. There is no doubt that such a consideration must be an integral part of the analysis. Attention has been drawn to the Appellate Body Report in US-Steel Safeguards¹² and the Panel Report¹³ in which it was concluded that the confluence of several events can unite to form the basis of an unforeseen development. It was also noted that increased imports must be an outcome of unforeseen developments i.e., it is the unforeseen developments that resulted in increased imports. For ease of reference, the observations are reproduced below:

10.99 Article XIX does not preclude consideration of the confluence of a number of developments as "unforeseen developments". Accordingly, the Panel believes that confluence of developments can form the basis of "unforeseen developments" for the purposes of Article XIX of GATT 1994. The Panel is of the view, therefore, that it is for each Member to demonstrate that a confluence of circumstances that it considers were unforeseen at the time it concluded its tariff negotiations resulted in increased imports causing serious injury.

37. In view of the aforesaid, I am of the view that it is the confluence of a number of developments, explained in detail in Preliminary Finding, which constitute the unforeseen developments. At this juncture, I observe that the interested parties have individually addressed each factor which was outlined in the Preliminary Finding. However, no submission has been made how the confluence of events could have been foreseen. For instance, the interested parties have argued that imposition of trade remedy measures and reduction in carbon emissions were foreseen the moment India signed various international agreements. However, India could not have expected that both EU and the United States would simultaneously levy trade remedy measures against China and certain other countries which would also coincide with the increase in demand due to commitments undertaken under COP21 (Paris Agreement).
38. Applying the aforementioned findings to the present case, it is clear and that the temporal nature of the increase in imports of the PUC so as to cause serious injury to the DI or give rise to a threat of such serious injury must have been unforeseen or unexpected and factual. Whereas the event of increased imports itself must be demonstrable on the basis of data on imports, a finding on its unforeseen or unexpected nature can only be contextual. I reiterate that, a relevant context for this would be the event or events that resulted in tariff concessions on the import of the PUC into India. In other words, the factum of increased imports of the PUC during the POI must have been unforeseen at the time of incurring the obligations i.e., accession to WTO, resolving to abide by the commitments under various WTO Agreements, providing tariff concessions and subsequently amending those tariff concessions through the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products (ITA-1) on 13th December, 1996. While the reference to ITA-1 is not an unforeseen development, the obligation which was incurred under GATT is an unforeseen development.
39. In the Preliminary Findings it was observed that China has more than doubled its production capacity of Solar Cells from 11.12 GW in 2012 to 27.78 GW in 2016. Similarly, the production capacity of Solar Modules increased from 12.46 GW in 2012 to 35.47 GW in 2016.
40. The interested parties have not questioned the data. They have only argued that domestic consumption in China is more than its exports in the year 2017. However, such submissions fails to address the idle capacity in China and the shift in pattern of trade.
41. In the Preliminary Findings, it was observed that during the past two years, both its direction and volume of export trade changed in a significant manner towards India.
42. It is clear that while China's exports to India constituted a paltry 1.52% of its total global exports during 2012, this increased to 29.8% during 2017 (updated).
43. In the preliminary findings I had observed that another unforeseen development that contributed to the surge in imports of the PUC in India and a shift away from other foreign markets was the imposition of trade remedy measures by EU and USA on imports from China in 2012 and 2013.

¹¹ Appellate Body Reports, *Korea – Dairy*, para. 85 and 89
[https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds98_e.htm].

¹² Appellate Body Report, *US – Steel Safeguards*, para. 315
[https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/248_259_abr_e.pdf].

¹³ Panel Report, *US – Steel Safeguards*, para. 10.99 [https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/248_259_abr_e.pdf].

44. One of the interested parties has contended that unforeseen developments cannot relate to the remote past. They have also contended that the developments that led to the imports must have been unforeseeable and it must be explained as to why the developments in question were unforeseeable. In this regard, the respondents have claimed that resorting to trade remedy measures by a contracting member, such as the EU and the US in the context of the present case, cannot be said to be unforeseeable at the time of India incurring the obligations under the GATT and the multilateral agreements under the WTO. The observation of the WTO Appellate Body in its Report in Argentina – Footwear (EC) clarifying that the development leading to import surge must have been unexpected is relevant in this regard.
45. I reiterate the conclusions/considerations in the Preliminary Findings that the immediate impact of these measures was not visible in India because of the requirement of Domestic Content Requirements (DCR) under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM). Thus, the DI had the assurance of a captive domestic market to the extent dictated by the DCR. However, in 2013, the USA challenged the DCR under JNNSM before the WTO Dispute Settlement Body and the outcome was that in October 2016, the WTO Appellate Body held the DCR to be inconsistent with Article III:4 of the GATT 1994 and Article 2.1 of the TRIMs Agreement. Hence, India withdrew the DCR. Pursuant to the withdrawal of DCR, the changes in the pattern of trade became more pronounced with imports of the PUC increasing substantially. As afore stated, these developments could not have been foreseen.
46. In 2015, India committed to the Paris Agreement on climate change for reduction of CO₂ emissions by 33-35% from 2005 levels, to address global warming. In line with this commitment, India established a target of achieving 100 GW of Solar power generation by the year 2022. This commitment pushed up the demand for Solar power generation projects in India. It is clear that the commitment given by India under the Paris Agreement that was signed by 197 countries (as on date ratified by 172 countries) was unforeseen at the time the import tariff concession for the PUC was agreed to under ITA-1 on 13th December, 1996. Similarly, the huge increase in the demand for the PUC in India in a short period of time which has in part fueled the surge in imports was also unforeseen.
47. I note that the imports of the PUC are taking place at very low prices; there has been a sudden and appreciable drop in the landed value of the imported PUC, as evident from the table below. This fact has not been contested by any interested party. The immediate impact of this has been that the Domestic Industry faced a drop in sales realisation of their products. Thus, the surge in imports at consistently falling landed price changed the competitive relationship between imports and domestic production, to the disadvantage of the latter. This has hampered the DI's ability to compete and make and sell the PUC. It is but evident that this change in the competitive relationship was entirely unforeseen. This data trend was highlighted in the preliminary finding as well.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Landed value of imports						
Solar Cells	Rs./Watt	18.96	18.99	15.58	13.61	13.61
Solar Modules	Rs./Watt	36.18	36.53	29.49	22.63	22.63
Net sales realisation of Domestic Industry						
Solar Cells (Indexed)	Rs./Watt	100	87	82	60	60

48. India's import tariff on the PUC falling under Customs Tariff Item 85414011 of the Customs Tariff Act, 1975 is 'Free'. This 'Free' tariff was introduced pursuant to the obligations on India under GATT 1994, including the tariff concessions thereunder read with the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products dated 13th December, 1996 (hereinafter also referred to as the "ITA-1"). The PUC is covered under Attachment A, Section 1 of the ITA-1. The ITA-1 mandated elimination of Customs duties and other duties / charges of any kind within the meaning of Article II:1(b) of GATT 1994 on the products listed therein. Since India is a signatory to ITA-1, the imports of PUC are free of Customs duties. Thus, ITA-1 binds India's "freedom of action"¹⁴ with respect to the imported PUC and prevents it from taking other WTO-consistent measures, such as increasing the Customs duties. India believed that its DCR under JNNSM was consistent with

¹⁴ Panel Report, *Ukraine – Passenger Cars*, para.7.96.[[http://www.worldtradelaw.net/reports/wtopanels/ukraine-passengercars\(panel\).pdf.download](http://www.worldtradelaw.net/reports/wtopanels/ukraine-passengercars(panel).pdf.download)]

the exceptions contained in Article XX of GATT 1994, but after the rejection of this measure by the WTO Appellate Body in 2016, the Indian market for the PUC became open for unrestricted imports from all countries. Thus, India's obligation under GATT 1994 and ITA-1 to allow unrestricted tariff free imports of the PUC without giving preference to domestic production has led to a significant and unforeseen increase in the import volumes of the PUC into India.

Therefore, I reiterate that the developments reported as unforeseen in the preliminary finding stand the scrutiny of analysis being unexpected, and unforeseen in the context of these being appreciated as a confluence of a number of developments and provision of Article XIX of GATT and relevant panel reports of WTO.

h) Serious injury and/or threat of serious injury

49. The next matter for determination is whether the substantially increased imports of the PUC have caused and / or are threatening to cause serious injury to the Domestic Industry of like or directly competitive products. By its very nature this is a complex exercise as injury to the DI of the PUC is a function of various parameters like its share in the domestic market viz. a viz. imports; sales; production; capacity utilization, to name a few. Moreover, it is important that any negative parameter must not be a one-off event but it must display a consistent trend. Accordingly, various relevant parameters, as indicated below, are being examined to assess whether or not the increased imports of the PUC during the POI have caused and / or are threatening to cause serious injury to the Domestic Industry of like or directly competitive products.

- (i) **Share of domestic market:** Despite the rapid expansion in domestic demand, the market share of the DI has decreased; the DI had a market share of 8% in 2014-15 which declined to 3% during 2017-18 (A). During the same period, the market share of imports increased from 90% to 93%.

Market Share	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Imports	MW	1,275 (90%)	4,186 (96%)	6,375 (92%)	4,917 (93%)	9,833 (93%)
Domestic sales by the applicants / DI	MW	115 (8%)	178 (4%)	299 (4%)	157 (3%)	314 (3%)
Domestic sales by other Indian producers	MW	28 (2%)	15 (0.3%)	244 (4%)	235 (4%)	471 (4%)
Total domestic sales	MW	143 (10%)	193 (4%)	543 (8%)	392 (7%)	785 (7%)
Domestic Demand	MW	1419 (100%)	4381 (100%)	6918 (100%)	5309 (100%)	10618 (100%)

- (ii) **Sales:** The above table also reveals that sales of the domestic producers increased from 115 MW to 314 MW i.e. by 199 MW. However, it is material to note that while domestic sales increased by 199 MW, imports increased by 8,558 MW. Thus, the increase in imports was more than that of the increase in sales of the DI. Also, as the domestic demand increased from 1,419 MW in 2014-15 to 10,618 MW in 2017-18 (Annualized), it is clear that the increased imports of the PUC have substituted for the domestic production in meeting the domestic demand for the PUC.

- (iii) **Production:** Production of the DI increased from 141 MW in 2014-15 to 318 MW in 2017-18 (Annualized). Also, while the import volumes of the PUC have increased from 1,275 MW in 2014-15 to 9,833 MW in 2017-18 (Annualized) i.e., an increase of 671%, in comparison the production of DI increased 126% during the same period. This conclusion is based on the data in the table below.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (Upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Total imports	MW	1,275	4,186	6,375	4,917	9,833
Production of DI	MW	141	191	314	159	318

- (iv) **Capacity utilisation** The capacity utilisation of the DI increased from 48% in 2014-15 to 85% in 2017-18 (Annualized).

When compared with the growth in demand which increased to 10618 MW in 2017-18, the DI's total capacity should have got utilised. The capacity remaining below 100% even in such a enhanced demand indicates a clear preference for the imported PUC.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Installed Capacity	MW	292	373	373	185	373
Production of DI	MW	141	191	314	159	318
Capacity Utilisation	%	48	51	84	86	85

- (v) **Employment:** The employment generated by the DI has slightly declined in 2017-18, but by and large remained stable.

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)
No. of employees (Indexed)	100	108	106	99

- (vi) The productivity per employee showed increasing trend similar to the production trend which is also rising. This is expected in a scenario where there is a huge demand supply gap.

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Production of DI (MW)	141	191	314	159	318
Productivity per employee (MW)	0.290	0.365	0.607	0.329	0.660

- (vii) **Profit / Loss –** The profitability per watt was severely impacted during (April 17-Sept17) period as compared to previous year and even the base year of injury period.

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)
Loss in Rs. Watt (Indexed)	-100	-143	-22	-107

- (viii) **Inventory:** The inventory carried by the DI increased by more than 2 times during the POI, as indicated in the table below.

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)
Closing Inventory (Indexed)	100	114	243	251

- (ix) **Price Undercutting:** There was a significant price undercutting by the imported goods throughout the POI, as borne out from the table below. It is evident that the high level of price undercutting prevented the DI from increasing their prices as a result of which they suffered losses.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (April - Sept. 2017)	2017-18 (Oct. – March-2018)
Landed value of imports						
Solar Cells	Rs./Watt	18.96	18.99	15.58	13.61	13.96
Solar Modules	Rs./Watt	36.18	36.53	29.49	22.63	22.96
Net sales realisation of Domestic Industry						
Solar Cells (Indexed)	Rs./Watt	100	87	82	60	48
Price Undercutting						
Solar Cells (Indexed)	Rs./Watt	100	61	83	36	-4

i) **Injury Margin and Threat of Injury**

For the purpose of quantifying the level of protection, the Cost of Production of the domestic industry has been computed for PUC (Cells) manufactured by them during 1/4/2017 to 30/9/2017. A reasonable return on Cost of Production minus interest has been added to Cost of Production to determine the Fair selling price (FSP). The injury margin has been computed as difference of landed value of imported cells and the FSP. The analysis of post POI data indicates that as compared to the landed value the Cost of Production (COP) in the post POI and Net Sales Realisation (NSR) shows continued price suppression. The continued price undercutting has finally led to a situation where the domestic industry is not able to raise prices above the landed value. The threat of serious injury is established.

j) **Causal link**

50. The WTO Panel on *Korea-Dairy*¹⁵ set forth the basic approach for determining “causation”, as follows:

“In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports. To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors.”

51. The analysis of data for the period 2014-15 to 2017-18 (upto Sept., 2017) indicates that imports of the PUC have remained at significantly higher levels and also the import prices of the PUC have come down drastically. This has led to the DI revising their own prices downwards shows a clear bootstrapping phenomena. As a result, the net sales realization of the DI has sharply declined when compared to the base year. As a result of significant price undercutting by the imports, domestic selling prices depicts significant price depression, as shown in the table below.

Particulars (Indexed)		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (H1)
Sales realisation	Rs./watt	100	87	82	60
Price Depression (Y-o-Y)	Rs./watt		100	37	173

¹⁵WTO Panel on *Korea-Dairy*. Para VII.887

[https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds98_e.htm]

Price Depression (Cumulative)	Rs./watt		100	137	309
Cost of sales	Rs./watt	100	95	74	86
Cost increase (Y-o-Y)	Rs./watt		100	437	(248)
Price Suppression (Y-o-Y)	Rs./watt		100	(283)	509
Extent of Prevention of Price Increase	Rs./watt	100	142	22	238

52. The following factors are also relevant in regard to determining the cause and effect relationship of increased imports and the serious injury during the POI and the threat of serious injury in the future, to the DI:

- (i) The volume of imports has increased significantly from 1275 MW in base year to 9833 MW in POI in absolute terms;
- (ii) The market share of imports has increased from 90% to 93% and, consequently, market share of the DI has declined from 8% to 3%;
- (iii) As the imports are available at prices lower than the selling price of the DI and are also decreasing over the time, the consumers are switching over to imported PUC with the effect that the DI are unable to not only sustain their prices but also have to face rising inventories (of the PUC);
- (iv) Another impact of the increased imports at low prices is that the DI are unable to increase their production and sales as compared to the rate of increase in demand / consumption of the PUC in India;
- (v) Though the Indian industry including the DI established capacities to contribute towards meeting the growing demand for the PUC, the substantially increased imports at consistently reducing landed prices have led to idle production capacities, falling sales realization etc.; and
- (vi) The DI is incurring significant losses.

53. To sum up, a comprehensive evaluation of parameters enumerated above demonstrates that serious injury is being caused to the DI and is likely to continue in future by the significantly increased and continually increasing imports of the PUC. It is also relevant to note that while arriving at this conclusion, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on determining the causation of serious injury to the DI have been evaluated.

k) Adjustment plan

54. One of the core features of the WTO Agreement on Safeguards is emphasis on adjustment by the domestic industry. In this regard, the Preamble to the Agreement on Safeguards provides as follows:

Recognizing the importance of structural adjustment and the need to enhance rather than limit competition in international markets; and

55. Further, Article 5.1 of the Agreement on Safeguards provides that *[a] Member shall apply safeguard measures only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment*. Article 7.1 of the Agreement on Safeguards mandates a WTO member country to *apply safeguard measures only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment*. Article 7.4 mandates that *[i]n order to facilitate adjustment in a situation where the expected duration of a safeguard measure as notified under the provisions of paragraph 1 of Article 12 is over one year, the Member applying the measure shall progressively liberalize it at regular intervals during the period of application*. The provisions are pari-materia with Safeguard Rules 4(4)(ii), 11(2), proviso to 11(3), 12(1), 16(1) and proviso to 16(2). In addition Rule 5(2) of the Safeguard Rules provides as under:

(2) An application under sub-rule (1) shall be in the form as may be specified by the Director General in this behalf and such application shall be supported by, -

(b) a statement on the efforts being taken, or planned to be taken, or both, to make a positive adjustment to import competition.

56. The interested parties opposing the levy of safeguard duty have argued that the adjustment plan provided by the DI is highly speculative and does not provide concrete steps or real significant measures for adjustment. They have also argued that renegotiations or long term contract with suppliers cannot be adopted as adjustment plan. The interested parties opposing the levy of safeguard duty have also submitted that the Domestic Industry has not provided specific

timelines and other details regarding implementation and hence adjustment plan does not meet the requirement of the Rules.

57. I observe that Rule 5(2) of the Safeguard Rules does not provide a format for the statement of adjustment referred to as adjustment planned. No guidance is provided in the Agreement on Safeguards also. I have examined the statement of the efforts planned to be taken by the Domestic Industry enclosed by each of the producers constituting the Domestic Industry with their individual questionnaire response. The salient features of the statement are summarised below:
- a) The domestic industry has provided a forecast of future performance for the next 3 years in the form of concrete steps such as (i) long term procurement of raw material, rate and volume discounts if better cash flow is achieved; (ii) higher utilisation of capacity leading to better conversion cost; (iii) better apportionment of semi-fixed and fixed costs; (iv) better credit ratings would lower the cost of borrowing and better servicing of debt; (v) efforts towards backward integration and developing an entire eco-system; (vi) technology development and R&D.
 - b) The domestic industry has quantified the impact of each step and the timeframe within which such impact could be visible.
 - c) The adjustment plan therefore covers efforts on cost reduction, efficiency improvement, forward and backward integration of value chain, in terms of technology and production.
58. I observe that raw material is a significant proportion (about 45%) of the cost of the finished solar module, with the wafer component roughly being half of this cost. Therefore, long term price negotiation with major suppliers is a credible and realistic effort. The domestic industry's projection is credible that a better demand outlook will aid targeted negotiations with wafer suppliers. The depreciation costs are a significant component of the cost structure and better utilization of capacity would aid in recovery of depreciation.
59. I note that the panel report in Korea-Dairy case (WT/D598) held the following regarding adjustment plan "*We wish to make it clear that we do not interpret Article 5.1 as requiring the consideration of an adjustment plan by the Authorities, as the European Communities asserts. The panel finds no specific requirement that an adjustment plan as such must be requested and considered in the text of the Agreement on Safeguards. Although there are references to industry adjustment in two of its provisions, nothing in the text of the Agreement on Safeguards suggests that consideration of a specific adjustment plan is required before a measure can be adopted. Rather, we believe that the question of adjustment, along with the question of preventing or remedying serious injury, must be a part of the Authorities' reasoned explanation of the measure it has chosen to apply. Nonetheless, we note that examination of an adjustment plan, within the context of the application of a Safeguard measure, would be strong evidence that the Authorities considered whether the measure was commensurate with the objective of preventing or remedying serious injury and facilitating adjustment.*"
60. Therefore, in view of the aforesaid and the adjustment plan submitted by the Domestic Industry, I hold that the adjustment plan contemplated by industry in the given ecosystem is quite pragmatic. Needless to mention that since relief under a safeguard measure is only for a limited period of time as an emergency measure, industry's adjustment efforts to withstand the surge in imports needs to be seen primarily during this time span.

I) Public Interest

61. Article 3.1 of the Agreement on Safeguards states as follows:

"A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law.

62. Though Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, do not require an examination of public interest, public interest, has been consistently evaluated before recommending levy of a safeguard duty. Various interested parties have made submissions on public interest, as detailed in the paras under submissions.
63. In view of the aforesaid, even though Article 3.1 also does not provide any guidance on evaluation of public interest, public interest evaluation, inter alia requires evaluating impact of a safeguard measure comprehensively on various stakeholders, and taking a balanced view keeping in view competing interests of different interested parties. There are various interested parties in the present case - (i) the domestic producers of solar cells, (ii) the domestic manufacturers of solar modules who do not manufacture cells themselves and rely upon domestic and imported cells,

and (iii) the power developers and (iv) the consumer of electricity who may bear the brunt of safeguard measures in form of increased electricity tariff

64. Undoubtedly levy of Safeguard duty would not only lead to mitigation of serious injury to the DI but would also improve viability of the upstream and downstream industry associated in the value chain of the manufacturing of solar cells /modules. The prices of cells/modules which would no doubt increase, would also have some adverse impact on the user industry i.e. module manufacturers using imported cells or domestic cells, module importers, power developers and consumers.
65. The interested parties opposing domestic industry have also claimed that when the Domestic Industry does not have sufficient capacity to meet the demand of the PUC in India, levy of safeguard duty will not be in public interest. In this regard, the interested parties have drawn my notice to the Final Findings in Safeguard investigation concerning imports of White/Yellow Phosphorus into India. On perusal of the Final Findings, we observed that in addition to insufficient capacity, levy of safeguard duty was held not to be in public interest due to inability of the domestic industry to achieve cost competitiveness, captive requirements of the domestic industry, imports under export promotion schemes and competition in the downstream markets. On the other hand, the Domestic Industry has drawn our attention to safeguard investigations where duty has been levied despite the Domestic Industry not having sufficient capacity to meet the entire demand in the domestic market – (i) Safeguard investigation concerning imports of Industrial Sewing Machine Needles, (ii) Safeguard investigation concerning imports of Oxo Alcohols, (iii) Safeguard investigation concerning imports of Sodium Nitrite; On perusal of the submissions made by the interested parties, I am of the view that capacity demand gap, though an important aspect, it cannot be considered in isolation. The public interest needs to be determined in every case based on the relevant facts and circumstances.
66. In the facts of the present case, when the Domestic Industry has made significant investments to cater to the domestic market and for backward integration, it must be protected against the sudden and sharp surge in imports. Further, the safeguard duty is not a quantitative restriction. Therefore, there is no embargo on procurement of the PUC by way of imports. Even in a situation where the Domestic Industry has the capability to meet the demand of the PUC, the effect of safeguard duty is that the domestic producers raise their prices to recover their cost, earn a reasonable return and to implement their adjustment plan.
67. As far as the interest of the power developers are concerned, the domestic industry has raised certain arguments. Power developers could be sub-divided into three categories i.e. (a) developers who entered into PPAs with DISCOMS and have already imported the product under consideration; (b) developers who entered into PPAs with DISCOMS but have not yet imported the product under consideration, and (c) developers which may bid on future projects and are hoping to import the product under consideration would incorporate the enhanced import price into their tariff quotations and may become uncompetitive. The power developers who would be presently affected are those that have entered into PPAs with DISCOMS and quoted the tariff based on prevailing import prices of product under consideration but have not yet imported the product under consideration. However, as Central Government has already taken steps to balance the interests of such affected power developers with the Ministry of New and Renewable Energy having notified a pass-through facility through a clarification on “change in law” clause of the agreements and therefore, I feel that the imposition of safeguard duty is covered under the ‘change in law’ clause and the impact of duty will be passed on to the DISCOMs.
68. It is clear that while on one hand, the Solar Manufacturing Industry in India needs to be strengthened, at the same time an equally important objective of achieving a 100 GW target from Solar power requires Solar Cells/Modules to be imported as the domestic supply base in the country is extremely low at present juncture.
69. I have examined the simulations on various levels of Safeguard duty protection submitted by the DI and also by one of the power developers i.e. M/S ACME. Both simulations are based on certain set of assumptions. I notice that broad conclusions from M/S ACME’s simulations are that 25% Safeguard duty on PUC will lead to 23% increase in tariff while the projection of DI is that in case of 30% levy of Safeguard, tariff increase will only be 5%, which will further get dampened by a lower weight of solar power in overall energy mix of the country. The domestic industry has made such optimistic submissions based on the assumption that developers who may bid on future projects and are hoping to import the product under consideration could receive viability gap funding. However, they have been unable to provide any evidence that such a scheme exists. Therefore, I have not considered such submissions in the analysis. As cost of module in the project cost is estimated as about 60%, the dimension of impact, projected in the simulation by M/S ACME seems unrealistic being quantified on the higher side. On the other hand projection of domestic industry on tariff increase is much on the lower side. As simulations are assumptions based, and two extremes have been presented, it can be reasonably concluded that increase in power tariff would lie somewhere between the two extremes.
70. The aforesaid considerations establish that it is in public interest to recommend imposition of a Safeguard measure of quantum and tenure which will balance the two competing concerns. Also while ensuring a reasonable level of safeguard measure, it is important to apply same quantum (advalorem %) of measure to solar cells as stand alone or

in assembled in modules/panels, so as to avoid any situation of duty inversion which may be counter-productive to the spirit of the measure compromising the envisaged balancing of public interest.

m) Developing nations

71. Proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975 provides that Safeguard Duty shall not be imposed on article originating from a developing country so long as its share of imports does not exceed 3% of the total imports of that article or, where the article is originating from more than one developing country, then, so long as the aggregate of the imports from all such developing countries, each with less than 3% import share taken together, does not exceed 9% of the total imports of that article. Further, Notification No.19/2016-Customs (NT), dated 5th February, 2016 specifies the developing countries for the purposes of this provision. Upon applying this legal provision read with the said notification to the available data in the present case, the finding is that import of the PUC is originating from more than one specified developing country including China PR and Malaysia. However, as a percentage of the total imports of the PUC into India, the imports from China PR and Malaysia individually account for more than 3% while the share of every other developing country is individually less than 3%. Also, the collective share of the developing countries whose individual share is less than 3% does not exceed 9% of the total imports of the PUC into India. Therefore, the import of the PUC originating from developing countries except China PR and Malaysia, need not be subjected to levy of Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975.

n) Other issues and Coverage of Safeguard measures

72. I recall para G of the preliminary finding where it was stated that “*the application of Section 30 of the SEZ Act, 2005 would negate the imposition of Safeguard measures under Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 and be counter-productive. The remedy to this could be a duty exemption to the extent of the Safeguard measure when the PUC is cleared by a SEZ unit into the domestic market. This would maintain the relevance of the Safeguard measures in the interest of the DI. This would also satisfy the canon of equity by placing all domestic producers or all constituents of the DI at par with regard to the applicability of the Safeguard measures on the imported PUC. However, this matter falls outside the ambit of the present proceedings which are governed strictly by the provisions of the Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 read with its Rules and is, therefore, left for the consideration of the Government. Needless to state, the provisions of Section 8B(2A)(ii) of the Customs Tariff Act, 1975 dealing with the levy of Safeguard Duty, if an article subjected to a Safeguard Duty on import is cleared as such from the SEZ into the domestic market or is used in the manufacture of any goods that are cleared by the SEZ unit into the domestic tariff area would apply.*”
73. The DI has also made detailed submissions related to this aspect as under:
- The petitioners constitute a major proportion of the total Indian production of the subject goods and therefore, constitute Domestic Industry within the meaning of 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act, 1975 as the collective production of the petitioners accounts for more than 50% of the total production of the PUC in India. Therefore, they represent a major proportion of the total Indian production and therefore, constitute Domestic Industry of the like article in India. The Ld. DG Safeguards also confirmed in the Preliminary Findings dated 05.01.2018 that the petitioners accounted for a major share of production of the subject goods in India and therefore, constituted Domestic Industry.
 - The Ld. DG Safeguards observed that M/s Mundra Solar PV Limited, M/s Websol Energy Systems Limited and M/s Helios Photo Voltaic Limited are based in Special Economic Zones (SEZ) and therefore, while imposing the safeguard duty, the same may be exempted from its levy by means of an adequate measure. However, clearance of subject goods from an SEZ to the DTA will not attract any safeguard duty in the event that the same is levied. This is clear from a combined reading of Section 8B(2A) and Section 30 of the SEZ Act, 2005. For ease of reference, Section 30(a) of the SEZ Act, 2005.
 - The levy of the ADD, CVD and SGD under Section 30 of the SEZ Act, 2005 are qualified by the words ‘where applicable’. Therefore, one needs to ascertain as to when anti-dumping duty, countervailing duty or safeguard duty is applicable in any given case.
 - The language of Section 9A pertaining to the levy of anti-dumping duty, Section 9 with respect to countervailing duty and Section 8B pertaining to the levy of safeguard duty all state, in no uncertain terms, that the same are applicable on imports of an article into India. Therefore, if an article is not imported into India, none of the aforesaid duties are payable. Though by a deeming provision, a legal fiction is created whereby SEZ’s are considered to be outside the customs territory of India, there is no provision under any extant law in India which deems the clearance of goods manufactured in an SEZ to the DTA as an import. The fact that clearance of goods manufactured in an SEZ to the DTA does not amount to import into the territory of India has also been reiterated in a catena of judgments including *Essar Steel v. Union of India* [2010 GLH (1) 52], *India Exports v. State of U.P. & Ors* [(2012) 47 VST 126], *Tirupathi Udyog Limited rep. by its Manager-Administration Shri D.V. Saradhy v. Union of India (UOI) through the Secretary, Ministry of Finance and Ors.* [2011 (272) ELT 209(A.P.)]. Therefore, without the factum of import, there can be no levy of anti-dumping duty, countervailing duty or safeguard duty.

- e. Anti-dumping duties and countervailing duties are country specific and therefore, even if the aforesaid duties are levied on the description of a like article which is manufactured in an SEZ and eventually cleared into the DTA, the same can never attract the aforesaid duties as there can never be an anti-dumping or countervailing investigation alleging dumping or subsidies against an SEZ in the territory of India itself and consequently, the question of levying any such duty would not arise. Therefore, to give effect to the meaning of the words in section 30 of the SEZ Act, 2005, the mention of levy of anti-dumping duty and countervailing duty mentioned therein during DTA clearance has to mean duty payable on the value of the inputs (*in the event that the inputs imported from specified countries attract anti-dumping duty or countervailing duty*) used on the finished product and not on the finished product itself, the latter being an impossibility.
 - f. The same principle is also applicable to safeguard duties levied against any like article that is also manufactured in an SEZ and cleared into the DTA. Unless safeguard duty has been imposed on the description of the inputs which have been imported and used in the manufacture of the finished product that is eventually cleared into the DTA, in which case the safeguard duty will be levied only to the extent of the value of the input (*assuming the input attracts safeguard duty*) employed in the manufacture of the finished article, no safeguard duty will be attracted on the finished product itself even though the same may be a like article against which India has imposed safeguard duties. This is also evident from Section 8B (2A) of the Customs Tariff Act, 1975. Therefore, Section 30 of the SEZ Act, 2005 read with Section 8B(2A) of the Customs Tariff Act, 1975 make it abundantly clear that safeguard duty is only payable on the inputs used in the finished products and not the finished product itself that is manufactured in the SEZ and cleared into the DTA.
 - g. Safeguard Duty would not be payable on the finished product manufactured in an SEZ and cleared into the DTA for one additional reason i.e. in a situation where safeguard duty has been levied by India on the description of inputs used in the manufacture of a finished product in the DTA as well as on the description of the finished product as well, then while clearance into the DTA, both the inputs used as well as the finished product will attract safeguard duty which will amount to double taxation. Such a levy being illegal, the reference to anti-dumping duties, countervailing duties and safeguard duties in section 30 of the SEZ Act, 2005 will always have to mean on the value of inputs as otherwise, the duty will be unworkable.
74. I have gone through the observations made in the preliminary finding and submissions of domestic industry. Since the scope of DI has been modified with exclusion of the three SEZ units, the issue of levy of Safeguards duty on DTA sales/clearances by SEZ units through interpretation of section 30 of SEZ Act and Section 8 B of the Custom Tariff Act, 1975 are required to be dealt by the relevant competent authorities and are outside the purview of this investigation.

o) Conclusions

75. On the basis of the above examination and analysis, it is concluded that:
- i. There has been a significant increase in imports of the PUC in absolute terms as well as in relation to total Indian domestic production over the entire POI.
 - ii. The domestic industry has suffered serious injury, considering overall performance, on the basis of listed economic parameters such as market share and profitability, which have sharply declined over the injury period 2014-2015 to 2017-2018 (Annualised) whereas market share of imports have increased during the same period. This has caused significant overall impairment to the domestic industry. The rise in imports and coinciding serious injury caused to the domestic industry during the injury period, establishes causality.
 - iii. The domestic industry has been able to demonstrate that the developments in the market on surge in imports of the PUC were unforeseen in the context of Article XIX of GATT.
 - iv. There will be some impact on the Solar Power Developers and also ultimate consumer as a result of safeguard duty on the PUC.
 - v. It is however concluded that imposition of safeguard duty in this case would be in public interest because it will prevent complete erosion of manufacturing base of Solar industry in the country which is upcoming and holds promise for a stronger manufacturing base in the country in future, at the same time, it is also in the public interest, to prevent undue escalation of Solar power cost, tariff to the final customer and that attainment of the target of 100 GW of Solar Power Deployment by 2022 is not derailed. The consideration of two competing interests require a balanced view.
 - vi. From the analysis of post POI data, it has been observed that the position of domestic industry further deteriorated on account of continued low price of import of PUC which continued price injury to the domestic industry, thereby establishing the threat of injury as well.

p) Recommendations

76. The increased imports of 'PUC' into India, have caused serious injury and threaten to cause serious injury to the domestic producers of "PUC" and it will be in the public interest to impose safeguard duty on imports of "PUC" into India in terms of Rule 12 of the Customs Tariff (Identification And Assessment of Safeguard Duty) Rules'97, for a period of two years. Considering the average cost of production of "PUC" of the domestic producers after allowing a reasonable return on cost of production minus interest, safeguard duty as indicated below, which is considered to be adequate to protect the interest of domestic industry on PUC being imported falling under sub-heading 85414011 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975, is recommended to be imposed. The Tariff Item mentioned herein is indicative only and the description of the imported goods will determine the applicability of the recommended Safeguard Duty.

Year	Safeguard duty recommended
First Year	Safeguard duty @ 25% ad valorem
Second Year (for first 6 months)	Safeguard duty @ 20% ad valorem
Second Year (For next 6-months)	Safeguard duty @ 15% ad valorem

77. As the imports from developing nations, as listed in Notification No.19/2016-custom(NT) dated 5th February,2016, except China PR and Malaysia do not exceed 3% individually and 9% collectively, the import of product under consideration originating from developing nations except China PR , and Malaysia will not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B (1) of the Customs Tariff Act, 1975.

SUNIL KUMAR, Director General (Safeguard)